

**DUE DATE SLIP****GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj.)**

Students can retain library books only for two weeks at the most.

<i>BORROWER'S No.</i>	<i>DUE DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>

# भारतीय संविधान तथा नागरिकता

(माध्यमिक शिक्षा परिषद्, यू० पी० द्वारा स्वीकृत)

अष्टम् सशोधित संस्करण



लेखक

अम्बादत्त पत एम० ए०  
राजनीति विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय।

१९५६

मूल्य ४ ५० रुपया

प्रकाशक

सेन्ट्रल बुक डिपो

इलाहाबाद

प्रकाशक :  
सैन्ट्रल बुक डिपो,  
इलाहाबाद ।

प्रथम संस्करण	१९५१
द्वितीय संस्करण	१९५३
तृतीय संस्करण	१९५४
चतुर्थ संस्करण	१९५५
पंचम संस्करण	१९५६
षष्ठ संस्करण	१९५७
सप्तम संस्करण	१९५८
अष्टम संस्करण	१९५९

मुद्रक :  
वैनगाडे प्रेस,  
इलाहाबाद ।

## अष्टम् संस्करण की भूमिका

इस पुस्तक में अनेक स्वयं पर परिवर्तन तथा सुधार कर दिये गये हैं। महापॉन्डा अधिनियम (१९५०) के अनुसार उत्तर प्रदेश में जिन महापॉन्डाओं की स्थापना होगी उनके संगठन आदि का वर्णन विस्तारपूर्वक कर दिया गया है। राजनैतिक क्षेत्र में भी जा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं उनका समावेश कर दिया गया है। आशा है अध्यापक तथा विद्यार्थी पूरव की ही भाँति पुस्तक का स्वागत करेंगे।

३० जून १९५९

अम्बादत्त पंत

## प्रथम संस्करण की भूमिका

पुस्तक मुख्यतः इंटरमीडिएट बाड के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए लिखी गई है परंतु यह आशा है कि जन साधारण के लिए भी सविधान विषयक मुख्य मुख्य बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

सविधान में जुलाई १९५१ तक जो कुछ परिवर्तन तथा संशोधन हुए हैं और निर्वाचन सम्बन्धी जिन नियमों की रचना हुई है उनका पुस्तक में समावेश किया गया है। इसके पश्चात् जो कुछ नये नियम बनेंगे, विद्याधिका के लाभ के लिए उनका भी यथासंभव तथा यथाशीघ्र परिशिष्ट रूप में अलग प्रकाशित करने का विचार है। राष्ट्रपति के अधिकारों की विवचना करते हुये उनके अस्थायी अधिकारों का वर्णन इस कारण कर दिया गया है जिससे यह ज्ञात हो जाय कि सविधान आरम्भ होते समय संघीय कार्यकारिणी का क्या-क्या अधिकार दिये गये थे।



सविधान के प्रतिरिक्त भारतीय नागरिक जीवन की मुख्य समस्याओं का भी संक्षिप्त वर्णन किया गया है।

इस पुस्तक को लिखने में कई प्रामाणिक ग्रन्थों से सहायता ली गई है। उन सबके लेखकों तथा प्रकाशकों का लेखक अत्यन्त आभारी है। मुख्य-मुख्य ग्रन्थ जिनके सहायता ली गई है, निम्नोक्त हैं—G. N. Singh: Landmarks in Indian Constitutional and National Development; Punnaiah Constitutional History of India; Sitarammaya: History of the Indian National Congress; Smith, W. C.: Modern Islam in India; Joshi G. N.: Constitution of India; M. P. Sharma: Constitution of the Indian Republic; D. D. Basu: A Commentary on the Constitution of India; Amar Nandi: The Constitution of India; Farquhar: Modern Religious Movements in India; Yusuf Ali: A Cultural History of India; Nurullah and Naik: A Student's History of Education in India तथा India and Pakistan Year Book 1950.

इस बात का पूरा भयल किया गया है कि पुस्तक में किसी प्रकार की असुविधा न रहे, अगर कोई असुविधा रह गई हो तो लेखक पाठकों से क्षमा प्रार्थना करता है। अगर कोई पाठक किसी दोष अथवा त्रुटि की ओर लेखक का ध्यान आकर्षित करे तो वह उनका अत्यन्त कृतज्ञ होगा।

## विषय-सूची

अध्याय १ भारत का संविधानिक विकास—अंग्रेजी साम्राज्य का प्रारम्भ—  
पार्लियामेन्ट के नियंत्रण का प्रारम्भ—१८५७ का विद्रोह—गवर्नमेन्ट  
ऑफ इंडिया ऐक्ट—अंग्रेजी शासन का द्वितीय काल—सन् १८६१ का  
ऐक्ट—१८९२ का इन्डियन कोसिल ऐक्ट—१९०९ का इन्डियन  
कोसिल ऐक्ट—सन् १९१७ की घोषणा—मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड  
योजना—अंग्रेजी शासन का तृतीय काल—साइमन कमीशन—१९३५  
का गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया ऐक्ट—सच निर्माण—अधिकार विभाजन—  
सच सरकार—प्रान्तीय सरकार—गृह सरकार—ऐक्ट का कार्यान्वित  
होना—१९३५ के ऐक्ट के दोष—अंग्रेजी शासन का अन्तिम  
काल—८ अगस्त १९४० की घोषणा—क्रिप्स योजना—भारत छोड़ो  
आन्दोलन—वैबेल योजना—नये चुनाव—कैबिनेट मिशन—  
अन्तर्वालीन सरकार की स्थापना—लीग का प्रसहयोग—१९४७ का  
स्वतन्त्रता कानून । पृष्ठ १

अध्याय २ संविधान निर्मात्री सभा तथा इसका कार्य—संविधान सभा—  
भारत में संविधान सभा की माँग—कैबिनेट मिशन के संविधान  
सभा के ऊपर गुस्सा—१५ जुलाई १९४७ का ऐक्ट—संविधान सभा  
का कार्य । पृष्ठ ३०

अध्याय ३ भारत के संविधान की विशेषताएँ—संविधान के स्रोत—  
लिखित तथा निमित्त विधान—विशाल स्वरूप—लोकतन्त्रात्मक  
संविधान—संघात्मक सरकार तथा शक्तिशाली केन्द्र—सासद पद्धति  
—संशोधन की विधि—धर्म निरपेक्ष शासन की स्थापना—मूल  
अधिकार—स्वतन्त्र न्यायपालिका—उदार संविधान—भारत तथा  
राष्ट्र मण्डल की सदस्यता । पृष्ठ ३८

**अध्याय ४ : भारत-संघ तथा इसका राज्य-क्षेत्र—संघ की परिभाषा—संघ सरकार के लक्षण—संघ सरकार के लिये आवश्यक दानाएँ—भारत में सघात्मक सरकार के लक्षण—भारत संघ के विशेष लक्षण—क्या भारत का विधान सघात्मक है—क्या भारत में संघ सरकार की स्थापना उपयुक्त है—संविधान में संशोधन की व्यवस्था—भारत का राज्य होना—राज्य-पुनर्गठन के पूर्व व्यवस्था—‘क’, ‘ख’, ‘ग’, ‘घ’, ‘ङ’ के राज्य—रियासतें तथा सत्ताट—रियासतों में शासन प्रबंध—देशी रियासतें तथा भारत संघ—रियासतों में स्वतन्त्रता आन्दोलन—१९४७ के पश्चात् रियासतों की स्थिति—नरेशों का प्रिन्सीपस-गवर्नर के राज्य—राज्यपुनर्गठन—कांग्रेस तथा पुनर्गठन का प्रश्न—आयोग की रिपोर्ट—इकाइयों का मूल रूप—राज्य पुनर्गठन विधेयक—भारत संघ के राज्य। पृष्ठ ५७**

**अध्याय ५ : भारतीय नागरिकता—नागरिकता का अर्थ—भारतीय नागरिकता—नागरिक कौन है—नागरिकता पर प्रतिबन्ध—नागरिकता अधिनियम (१९५५)—नागरिकता का लोप। पृष्ठ ९७**

**अध्याय ६ : नागरिकों के मूल अधिकार—मूल अधिकारों का अर्थ तथा प्रयोजन—समता का अधिकार—स्वातन्त्र्य अधिकार—शोषण के विरुद्ध अधिकार—धर्म स्वातन्त्र्य का अधिकार—सांस्कृतिक और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार—सम्मति का अधिकार—संविधानिक उपचारों के अधिकार—मूल अधिकारों का निरुन्मूलन—मूल अधिकारों पर झालोचनात्मक दृष्टि। पृष्ठ १०४**

**अध्याय ७ : राज्य की नीति के निर्देशक तत्व पृष्ठ ११८**

**अध्याय ८ : संघीय कार्यपालिका: राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति—राष्ट्रपति का निर्वाचन—राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएँ—पदाविधि—रिक्त-स्थान पूर्ति—महामन्त्रिण—राष्ट्रपति के अधिकार—अस्थायी अधिकार**

—साधारण कालीन अधिकार—सकट कालीन अधिकार—भारतीय राष्ट्रपति की कुछ अन्य देश के प्रधानों से तुलना—संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति—वैधानिक प्रधान की आवश्यकता—उपराष्ट्रपति ।

पृष्ठ १२६

अध्याय ६ संघीय कार्यपालिका मन्त्रिपरिषद्—मन्त्रिपरिषद् का निर्माण—वर्तमान मन्त्रिपरिषद्—मन्त्रिपरिषद् का काम—प्रधान मन्त्री के काम तथा उसका महत्व—मन्त्रिपरिषद् तथा लोक सभा—मन्त्रिपरिषद् तथा राष्ट्रपति—मन्त्रिपरिषद् में विभिन्न विभाग—भारत का महान्यायवादी ।

पृष्ठ १५३

अध्याय १० संघीय व्यवस्थापिका—संविधान के अनुसार ससद का संगठन राज्य-परिषद्—सदस्यता के लिए योग्यताएँ—अवधि—सभापति तथा उप सभापति—लोक सभा—निर्वाचन की विशेषताएँ—निर्वाचन के लिये प्रबन्ध—सदस्यता की योग्यता—अवधि—लोक सभा के पदाधिकारी—गणपूर्ति—ससद की कार्यवाही—ससद के अधिकार—विधान प्रक्रिया—ससद पर आलोचनात्मक दृष्टि—परिशिष्ट ।

पृष्ठ १७०

अध्याय ११ राज्यों का शासन—स्वामित्त राज्यों का शासन—राज्यपाल—नियुक्ति—पद की योग्यताएँ—अधिकार—मन्त्रिपरिषद्—मन्त्रिपरिषद् का काम—राज्यपाल तथा मन्त्रिपरिषद् में सम्बन्ध—महाधिवक्ता—व्यवस्थापिका—विधान परिषद्—पदाधिकारी—विधान सभा—पदाधिकारी—राज्यों में विधान सभाओं की सदस्य संख्या—वैधानिक व्यवस्था—संघीय क्षेत्रों की शासन व्यवस्था ।

पृष्ठ १९८

अध्याय १२ न्यायपालिका—उच्चतम न्यायालय—योग्यताएँ—वेतन—शपथ—स्वतन्त्रता—स्थान—अभिलेख न्यायालय—अधिकार—राज्यों की न्यायपालिका—उच्च न्यायालय—क्षेत्राधिकार—दंड न्यायालय—

व्यवहार न्यायालय—माल की मदान्त—पंचायती मदान्त । पृष्ठ २२३

अध्याय १३ : जिले का शासन प्रबन्ध—जिलाधीश—जिलाधीश के अधिकार—जिलाधीश के अधिकारों की सीमा—जिले के भाग—दिवीजन—पुलिस का प्रबन्ध—जेल विभाग । पृष्ठ २३६

अध्याय १४ : स्थानीय संस्थाएँ—महत्व—ऐतिहासिक पृष्ठभूमि—अंग्रेजी काल—स्थानीय संस्थाओं के रूप—नगर निगम—गाँव पञ्चायत—समिति—मुख्य नगर अधिकारी—महापालिका के वर्तमान तथा अधिकार—महापालिका की भाग के साधन—मुनिसिपैलिटी बोर्ड—संगठन—पदाधिकारी—समितियाँ—कार्य—आय-व्यय—सरकारी निरीक्षण—समस्याएँ—टाउन एरिया बोर्ड—इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट—कैम्पूमेंट बोर्ड—पोर्ट ट्रस्ट—जिला बोर्ड—जिला बोर्डों का संगठन—जिला बोर्डों के कार्य—पार्ष पद्धति—बोर्डों की भाग तथा व्यय—सरकारी नियन्त्रण—जिला-परिषद—गाँव पञ्चायत—गाँव मुन्ना—पञ्चायत के कार्य—अधिकार—गाँव बोर्ड—ग्राम पञ्चायत—सरकारी दिव्यन—भारतीय स्थानीय संस्थाओं पर एक दृष्टि । पृष्ठ २४५

अध्याय १५ : सरकारी नौकरियों—भारतीय नौकरियों का अंग्रेजी काल में विकास—लोक सेवा आयोग—सेवा आयोग के कर्तव्य—अंग्रेजी काल में सेना का संगठन—वर्तमान सैनिक संगठन—सैनिक शिक्षा की व्यवस्था । पृष्ठ २८३

अध्याय १६ : संघ तथा राज्यों में अधिकार विभाजन तथा सम्बन्ध—विधायनी सम्बन्ध—संघ सूची—राज्य सूची—समवर्ती सूची—संघ तथा राज्यों में प्रशासन सम्बन्ध—संघ तथा राज्यों में वित्तीय सम्बन्ध—संविधान द्वारा स्थापित वित्त-स्वरूपा—राज्य सरकारों को संघ की सहायता—संघ द्वारा राज्यों को अनुदान—वित्त आयोग—संघ तथा राज्यों में कर वितरण आदि का वर्तमान प्रबन्ध—विद्यमान आयोग की सिफारिशों—‘ख’ भाग के राज्यों के कुछ वित्तीय विषयों में, कराह—संज्ञित, निर्दिष्ट । पृष्ठ २९९

अध्याय १७ अनुसूचित क्षेत्रों तथा जन-जातियों के लिये विशेष प्रबन्ध—

इनका शासन—जन-जाति मन्त्रणा परिषद्—आसाम के जनजाति क्षेत्र—राज्यों के जन जाति क्षेत्रों का शासन—परिषद् के अधिकार—जांच आयोग—सविधान में जन जातियों तथा जन-जाति क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबन्ध—कुछ वर्गों के लिये विशेष उपबन्ध—पिछड़े वर्गों के लिये कमीशन । पृष्ठ ३१५

अध्याय १८ राजभाषा—हिन्दी भाषा के लिये आयोग—प्रादेशिक भाषाएँ—

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा । पृष्ठ ३२६

अध्याय १९ : राष्ट्रीय जागृति—अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव—देश में एकता

की स्थापना—आर्थिक कारण—समाचार पत्र—साहित्य-अंग्रेजों की भारत व प्रति घृणा—लाड' लिटन का शासन—इलवर्ट विल—राजनैतिक आन्दोलन का विकास—मुसलमानों का संगठन—मिन्दो-माले सुधार तथा प्रथम महायुद्ध—गांधी युग तथा जन आन्दोलन—असहयोग आन्दोलन—साम्प्रदायिक दंगे—स्वराज्य पार्टी—साईमन कमीशन—नेहरू रिपोर्ट—सविनय अवज्ञा आन्दोलन—गोलमेज सभा तथा गांधी इरविन समझौता—मैकडोनेल्ड एवाडें तथा पूना पैक्ट—तीसरी गोलमेज सभा—आन्दोलन का अन्त और कौंसिल प्रवेश—१९३५ का ऐक्ट—कांग्रेस में मतभेद—द्वितीय महायुद्ध—आजाद हिन्द सेना—नेताओं की रिहाई तथा बंबेले प्रस्ताव—कैबिनेट मिशन तथा अन्तर्वालीन सरकार की स्थापना—लन्दन कांग्रेस तथा १९४५ का ऐक्ट—परिशिष्ट—देशी राज्यों में राष्ट्रीय जागृति—साम्यवाद का जन्म । पृष्ठ ३२९

अध्याय २० भारत में राजनैतिक दल—राजनैतिक दलों का महत्व—प्रखिल

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस—कांग्रेस के उद्देश्य—प्रजा-समाजवादी दल—समाजवादी दल—वायपक्षी—समाजवादी—साम्यवादी दल—अन्य

दामरशी दल—लिबरल पार्टी—साम्प्रदायिक दल—हिन्दू महासभा—  
सिखों के दल—मुस्लिम लीग तथा अन्य मुस्लिम दल । पृष्ठ ३६१

अध्याय २१ : धर्म तथा धार्मिक आन्दोलन—धर्म तथा जीवन में इसका  
महत्व—भारतीय जीवन में धर्म—हिन्दू धर्म—जैन धर्म—बौद्ध धर्म—  
इस्लाम धर्म—मिक्ल धर्म—ईसाई धर्म—पारसी धर्म—धार्मिक सुधार  
आन्दोलन—ब्रह्म समाज—प्रायश्चात समाज—धर्म समाज—विद्योत्तो-  
किकल समाज—रोनडूपन मिशन—अन्य आन्दोलन—मुस्लिम सुधार  
आन्दोलन । पृष्ठ १७९

अध्याय २२ : भारतीय समाज की समस्याएँ तथा उनके सुधार—  
वर्ण व्यवस्था—प्रदूषित की समस्या—हरिजन सुधार आन्दोलन—  
संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली—संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली के लाभ तथा  
हानि—स्त्रियों की समस्या—बाल-विवाह—दहेज-विवाह—दहेज प्रथा—  
विधवा विवाह—बुढ़ा विवाह—समाज में नारी का स्थान—सुधार  
आन्दोलन—स्त्रियों की प्रमुख समस्याएँ—स्त्रियों की मार्ग—हिन्दू कोड  
बिल—अन्य सम्प्रदायों का सामाजिक जीवन । पृष्ठ ४०२

२३ : भारत की आर्थिक अवस्था—गरीबी—भारत के प्राकृतिक  
साधन—भारत की निर्धनता के कारण—कृषि—ऊँच उन्नति के कारण  
गाँव का जीवन तथा उनकी समस्याएँ—सुधार के उपाय—भू-दान  
आन्दोलन—उद्योग-धंधे—भारत में उद्योग-धंधों का विकास—गृह-  
उद्योग—कुछ मुख्य गृह-उद्योग—गृह उद्योगों के मार्ग में कठिनाइयाँ  
तथा उनकी उन्नति के उपाय—द्वितीय योजना तथा गृह उद्योग—बड़े  
उद्योग-धंधे—औद्योगीकरण से लाभ—देश में प्रमुख बड़े उद्योग धंधे—  
औद्योगिक विकास की योजना—राष्ट्रीयकरण—भारतीय श्रमिक तथा  
उनकी समस्याएँ—व्यापार—यातायात—भारत में बेकारी—ग्रामीण  
क्षेत्र में बेकारी—भगरो में बेकारी—बेकारी दूर करने के उपाय—  
पंचवर्षीय योजनाएँ तथा बेकारी की समस्या का हल—विभाजन का

आर्थिक परिणाम—प्रथम पंचवर्षीय योजना—द्वितीय पंचवर्षीय योजना—सामूहिक योजनाएँ । पृष्ठ ४२८

पृष्ठ २४ शिक्षा समस्याएँ तथा सुधार—शिक्षा का जीवन में स्थान—भारत में शिक्षा का इतिहास—शिक्षा विभाग का संगठन—वर्तमान शिक्षा व्यवस्था—विश्वविद्यालय—विश्वविद्यालय का संगठन—अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड—उच्च शिक्षा में दोष तथा सुधार के उपाय—विश्वविद्यालय आयोग—टेकनिकल तथा औद्योगिक शिक्षा—अन्य समस्याएँ—हमारी शिक्षा समस्याएँ—जन शिक्षा—वर्धा योजना—सार्जेंट योजना—स्त्री शिक्षा—महू शिक्षा । पृष्ठ ४८८

पृष्ठ २५ : भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ—संयुक्त राष्ट्र सच—उद्देश्य—साधारण सभा—सुरक्षा परिषद्—अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय—सचिवालय—आर्थिक तथा सामाजिक परिषद—सुरक्षण परिषद्—विशेष एजेन्सियाँ—भारत तथा संयुक्त राष्ट्र सच—भारत की पर-राष्ट्र नीति के आधार—भारत का अन्य देशों से सम्बन्ध—यूरोपीय देश—संयुक्त राष्ट्र अमेरिका—भारत का एशिया के देशों से सम्बन्ध । पृष्ठ ५१२



## अध्याय १

### भारत का संविधानिक विकास

यह कथन अत्यन्त ही सत्य है कि इतिहास राज्या तथा शासन-तन्त्र का स्रष्टा है। संविधान का निर्माण भी वास्तव में इतिहास के द्वारा ही होता है। इससे यह सातत्य है कि प्रत्येक संविधान कुछ विशेष परिस्थितियों का फल होता है और इन परिस्थितियों का जन्म इतिहास का फल है। अतएव यह आवश्यक है कि हम अपने देश के वर्तमान संविधान को उचित रूप से समझने के लिये उस विकास-क्रम का अध्ययन करें जिसका यह फल है। भारत के नवीन संविधान का जन्म २६ जनवरी १९५० में हुआ। परन्तु प्रत्येक देश का इतिहास एक इकाई होता है। इसलिये इस संविधान का पूर्णरूपेण समझने के लिये हम भारत के इतिहास पर प्रारम्भ से ही दृष्टिपात करना चाहिये। यह उचित ही होगा कि हम प्राचीन काल में ही भारतीय राजनैतिक संगठन के विविध रूपों के ऊपर दृष्टिपात करें और इस प्रकार वर्तमान का भूत-मेमन्त्र स्थापित करें। परन्तु विस्तार-मय से ऐसा करना सम्भव नहीं। हम केवल अत्यन्त संक्षेप में प्राथमिक काल में भारत के संविधानिक विकास का वर्णन करेंगे।

प्राधुनिक काल का प्रारम्भ भारतीय इतिहास में ईस्ट इण्डिया कम्पनी तथा अंग्रेजी शासन की स्थापना से होता है। अंग्रेज भारत में व्यापार के हेतु आये थे और इसी उद्देश्य से सन् १६०० में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की गई थी। अंग्रेज व्यापारियों ने सतहवी शताब्दी में मराठे, मुसलीम, हरिहर-पुर, मद्रास तथा बम्बई और बंगाल में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। अंग्रेजों का भारत में पुनर्गठन तथा उच्च व्यापारियों के द्वारा विग्राह किया गया।

प्रारम्भ में अंग्रेजों का उद्देश्य केवल व्यापार था। परन्तु सतहवी शताब्दी के अन्तिम वर्षों में उनकी नीति में परिवर्तन होने लगा। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अभि-विजय की नीति अपनाई। इसका यह फल हुआ कि कालान्तर में कम्पनी एक व्यापारिक संगठन न रहकर एक प्रशासकीय शक्ति हो गई।

अंग्रेजी साम्राज्य का प्रारम्भ — अठारहवीं शताब्दी में अनेक कारणों से अंग्रेजी शक्ति के अत्युदय में सहायता पहुँचाई। पुर्तगाल तथा हालैण्ड की

शक्ति क्षीण हो गई थी, इसलिए भारत में वे अंग्रेजों का सामना नहीं कर सके। फ्रान्स से भी भारत में व्यापारिक कम्पनी स्थापित कर ली थी तथा अंग्रेजों की ही भांति फ्रेन्च कम्पनी भी साम्राज्य स्थापना के स्वप्न देख रही थी। परन्तु मठारहवीं शताब्दी में फ्रान्स का राजतन्त्र अस्तित्व हो गया था, इसलिए भारत में फ्रांसीसी कम्पनी को पूर्ण सहायता नहीं मिल सकी। भारत में मुगल साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया था। देश में ज़िम्-नज़िम् नवाब तथा राजा की व्यवस्था मिली वह स्वाधीन होता चला गया। अराजकता फैलने लगी तथा इन राज्यों में डच, बमनस्य तथा लोभ के कारण युद्ध होने लगे।

इन राज्यों ने साधारण जनता की स्थिति सोचनीय थी। अंग्रेज व्यापारियों ने इस अवसर में पूरा लाभ उठाया। भारतीय नरेशों का मैनिज-मैंगलन तथा मुद्रबला पिछड़ी अवस्था में थी।<sup>1</sup> उपर्युक्त कारणों ने अंग्रेजों को साम्राज्य स्थापना में गफलता मिली।

१७५७ ई० में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब के ऊपर सफलता प्राप्त की। १७६३ ई० के पश्चात् फ्रान्स को भारत में साम्राज्य के मधुर-स्वप्न त्याग देने पड़े। अंग्रेजों ने इस समय तक कई ज़ामकों पर, जैसे तमोर, कर्नाटक, हैदराबाद, बंगाल आदि, अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था तथा कुछ भू-भाग पर अपना अधिकार जमा लिया था। इसके दूसरे वर्ष ही अंग्रेजों ने मुगल-साम्राट् तथा नवाब अवध की बक्सर की लड़ाई में हराया तथा इस विजय के फलस्वरूप बंगाल, बिहार व मिदनापुर की दीवानी मिली। इस प्रकार भारत में अंग्रेजी शासन का आरम्भ हुआ।<sup>2</sup>

1. Clive ने लिखा है "The Moors and the Hindoos are indolent, luxurious, ignorant and cowardly beyond all conception. .... The soldiers, if they deserve that name, have not the least attachment to their Prince, he only can expect service who can pay them best, but it is a matter of indifference whom they serve."

2. "The beginning of our Indian rule dates from the second Governorship of Clive, as our military supremacy had dated from his victory at Plassey. Clive's main object was to obtain the substance, though not the name, of territorial power, under the fiction of a grant from the Mogul Emperor. This object was obtained by the grant from Shah Alam of the Diwani or fiscal administration of Bengal, Bihar and Orissa." Ilbert, Government of India, pp. 37-38.

**पार्लियामेंट के नियन्त्रण का प्रारम्भ (१७७३-१८५८)** —कम्पनी के शासन के प्रारम्भिक वर्षों में जनता का निदयतापूर्वक शोषण हुआ जिसके फलस्वरूप समाज में दुःखित पड़ा। इन दावा के कारण इंग्लैंड में यह माँग उठने लगी कि पार्लियामेंट कम्पनी के कामों में हस्तक्षेप करे। सर्वप्रथम सन १७६७ में पार्लियामेंट ने पाँच बानून बनाये परन्तु इनसे कम्पनी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ आपत्तु यह विगडनी ही चली गई। सन १७७३ में कम्पनी ने पार्लियामेंट से ऋण-माफ़ना की। इस अवसर पर ग़म उठाकर पार्लियामेंट ने कम्पनी के प्रबन्ध में सधार की दृष्टि से सर्वोत्तम पाव किया। प्रथम ऐक्ट के द्वारा पार्लियामेंट ने कम्पनी का १,६००,००० पौंड का ऋण ४% व्याज की दर से दिया। दूसरे ऐक्ट के द्वारा पार्लियामेंट ने भारत में कम्पनी के संगठन तथा शासन-व्यवस्था में परिवर्तन किये। इस ऐक्ट का नाम रैग्युलैटिंग ऐक्ट है। इसका बहुत वैधानिक महत्व है।

रैग्युलैटिंग ऐक्ट का उद्देश्य अच्छा या बुरा व्यवहार में यह नज़र न हो सका क्योंकि इसके द्वारा एक दायरी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई थी। इनके दावा का दूर करने के लिये सन १७८१ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक सशोधन फ़ानून पार किया। पिट के प्रधानमन्त्रित्व काल में सन् १७८४ में इन्डिया ऐक्ट पार किया गया। इस विधेय का उद्देश्य कम्पनी को ब्रिटिश सरकार के पणतया अधीन करने का था।<sup>१</sup>

कम्पनी एक व्यापारिक संस्था के साथ साथ एक प्रशासकीय शक्ति भी हाँ गई थी। भारत तथा चीन में कम्पनी का व्यापारिक एकाधिकार था। सन १८१३ में भारत तथा सन १८३३ में चीन में इस एकाधिकार का ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा अन्त कर दिया गया। इस प्रकार कम्पनी पूर्णतः एक शासन

---

1 "The Act of 1773 is of great constitutional importance because it definitely recognised the political functions of the Company, because it asserted for the first time the right of Parliament to dictate the form of government in what were considered till then the private possessions of the company and because it is the first of the long series of Parliamentary  
" G N  
National

सत्था हो गई। सन् १८३३ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने यह घोषित किया कि भारत में जो कुछ कम्पनी के अधिकार हैं उन्हें यथापर्व स्थानी ब्रिटिश नज़्मात तथा उसके उत्तराधिकारी हैं। सन् १८५३ के धाजानन में यह कहा गया कि भारत की भूमि तथा धाम तब तक के लिये कम्पनी को प्रदान किये जाते हैं जब तक कि पार्लियामेंट कोई अन्य आदेश न दे। इसने यह स्पष्ट था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत में कम्पनी के शानन को अन्त करने का नाँव रहीं थी।<sup>१</sup>

**१८५७ का विद्रोह:**—कम्पनी का राज्य भारत में स्थापित हो गया था। कई भारतीय श्रेणियों को पर-विशेष कर दिया गया था। भारतीय जनता की भावनाओं का कोई धादर नहीं था और न यह जानने की कोई चेष्टा की गई थी कि भारतीय जनता कम्पनी के राज्य से मन्तुष्ट है अथवा मन्तुष्ट। इन सब बातों का फल यह हुआ कि अन्तर्तीय बड़ने लगा और सन् १८५७ में विद्रोह फूट पड़ा। इसने एक समय तो विदेशी शासन की जड़ हिला दी थी पर अन्त में भारतीयों की आपसी फूट के कारण यह अन्त रहा।

**गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ऐक्ट:**—इन विद्रोह के पश्चात् अंग्रेजी सरकार ने कम्पनी के हाथ से समस्त शक्ति छीन लेने का निश्चय किया और इस प्रकार द्वैध-शासन का, जिसका प्रारम्भ सन् १७७३ में हुआ था, अन्त हुआ। कम्पनी ने पूरा प्रयत्न किया कि उसकी शक्ति न छीनी जावे और इस उद्देश्य से पार्लियामेंट के दोनों भवनों का भावेदन-गत्र भी दिया, परन्तु इनका कोई परिणाम नहीं निकला। सन् १८५८ में पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ऐक्ट पान किया। इसके द्वारा कम्पनी के राजनीतिक अधिकारों का अन्त हो गया। भारत का शासन सीधा सम्राट् (Crown) को दे दिया गया। इसके लिए एक राज्य-मंत्री नियुक्त किया गया जो कि भारत-मंत्री कहलाया। उसके महापठार्य एक १५ सदस्यों की भारत कौन्सिल की नियुक्ति की गई। इसमें ८ ती सम्राट् द्वारा नियुक्त तथा ७ का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा निर्वाचन हुए। इस प्रकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ से सब शक्ति छीन ली गई। भारत-कौन्सिल के प्रत्येक सदस्य का १२०० पाँड प्रति वर्ष, वेतन निश्चित हुआ। इस कौन्सिल का भारत-मंत्री अध्यक्ष था। कौन्सिल का कार्य उसको नज़्माह देना था। वह कौन्सिल की राय के विरुद्ध भी निर्णय कर सकता था।

भारत-मंत्री, कौन्सिल के सदस्य तथा उनके कार्यालय (India office) का ज्यय भारत को देना पड़ा। भारत-मंत्री को प्रतिवर्ष पार्लियामेंट के सम्मुख

भारतीय आय-व्यय तथा भाग की उन्नति पर एक वक्तव्य रखने को कहा गया।

भारत में गवर्नर-जनरल अब सम्राट् का प्रतिनिधि हो गया। इस कारण वह वाइसराय कहलाने लगा। भारत का शासन गवर्नर-जनरल तथा उसकी कौन्सिल को सौंपा गया। उसकी तथा गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार सम्राट् को दिया गया। इसके कौन्सिल के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार भारत-मंत्री तथा कौन्सिल को दिया गया। कम्पनी की सेना तथा जहाजी-बेड़ा भी सम्राट् के अधीन हो गये। इस प्रकार भारत में कम्पनी के राज्य का अन्त हुआ। १ मितम्बर, १८५८ को क्रांति आँख डायरेक्टरों की अन्तिम ममा हुई और उनमें भारतीय साम्राज्य सम्राट् को अर्पित कर दिया।

इस ऐक्ट के पास होने के पश्चात् महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा द्वारा भारत के प्रति इंग्लैंड की नीति का बखान किया। इस घोषणा में यह कहा गया कि देशी नरेशों को अपने अधिकार से ध्युत नहीं किया जावेगा तथा उनके साथ हुई सन्धियों का पालन किया जावेगा। भारतीय जनता को यह आश्वासन दिया गया कि अनेक धर्म में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जावेगा तथा सरकारी पदा में शिक्षा तथा योग्यतानुसार, बिना किसी धर्म-जाति भेद के सबों को समान अवसर दिया जावेगा।

अंगरेजी शासन का द्वितीय काल (१८५८-१९१८) — इस युग में शासन के विकास में दो मुख्य बाने दृष्टिगोचर होती हैं। भारत में धारा सभाधा का विकास होने लगा तथा इसके अनिवार्य इस काल में भारतीयों को भी शासन में कुछ भाग लेने का अवसर दिया जाने लगा। परन्तु यह बहुत कम था। इस समय ही भारत में कांग्रेस की नीव पड़ी तथा भारतीयों ने शासन में सुधार के लिए आन्दोलन का प्रारम्भ किया। आन्दोलन का प्रारम्भ तो इस माँग से हुआ कि भारतीयों को शासन में भाग मिलना चाहिये परन्तु २०वीं शताब्दी में दगभग आन्दोलन के बाद स्वराज्य की भावना उदित हुई। तिलक तथा ऐनी बेसेन्ट ने होमरूल लीग की स्थापना की। तिलक ने कहा कि "स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है"। यह वाक्य सब प्रगतिशील भारतीयों का नारा हो गया।

उन ६० वर्षों में भारत के शासन के लिए अंग्रेजी पार्लियामेंट ने तीन नियम बनाये जो क्रमशः १८६१, १८९२ तथा १९०९ में पास हुए। इनके अनिवार्य १९१७ में भारत मंत्री ने भारतीय शासन सम्बन्धी नीति की घोषणा की। हम इनमें से प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन करेंगे।

सन् १८६१ का ऐक्ट—यह ऐक्ट एक भारतीय विद्वान् के अनुसार दो कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो इसके द्वारा भागीदारों को शासन में भाग देने का प्रयत्न मिला और दूसरा प्रांतों को सरकारों को कानून बनाने का अधिकार वापस मिल गया। यह अधिकार उसने १८३३ में छीन लिया गया था।

इस ऐक्ट से गवर्नर-जनरल के कांसिल के सदस्यों की संख्या ४ में ५ बढ़ दी गई। गवर्नर-जनरल की कांसिल में कानून बनाने के लिए कुछ सदस्य और जोड़े दिये, जिनकी संख्या ६ से १२ तक हो सकती थी। इनमें में कम से कम आधे गैर-सरकारी सदस्य होने चाहिए थे। इनमें में कुछ भारतीय भी हो सकते थे। इसकी नियुक्ति २ वर्ष के लिए की जाती थी। परन्तु इस सभा का कानून बनाने का अधिकार संपन्न नक़्शित था। बरबई तथा मद्रास की सरकारों को एक निश्चित सीमा के अन्दर कानून बनाने का अधिकार मिल गया। गवर्नर-जनरल को बंगाल के लिए भी एक धारा-सभा बनाने का आदेश दिया गया। वह अन्य प्रांतों में भी ऐसी सभा की स्थापना कर सकता था। इसके फलस्वरूप बंगाल में १८६२ ई० तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत में १८८६ ई० तथा पंजाब में १८९७ ई० में धारा-सभाओं की स्थापना हुई। इन सभाओं के सदस्य गवर्नर द्वारा मनोनीत होते थे। इनकी संख्या ४ में ८ तक हो सकती थी।

इस ऐक्ट के द्वारा भारतीयों को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। केन्द्र तथा प्रांत में जो धारा-सभाएं बनीं थीं उनकी शक्ति अत्यन्त सीमित थी तथा उनका काम बस धारा में सरकार की आज्ञाओं को ही व्यक्त करना था।<sup>1</sup> जो भारतीय सदस्य मनोनीत होते थे वे या तो कोई राजा, या किसी राज्य के दीवान या कोई जमींदार आदि होते थे। इसलिए इनमें भारतीयता के सन्तुष्ट नहीं हुआ। इस समय धीरे-धीरे देश में एक नया वर्ग पैदा हो रहा था जो कि अंग्रेज शासन के अन्तर्गत प्रजातन्त्र तथा उत्तरदायी-शासन-व्यवस्था का पक्षधारी था। देश में बड़े संस्थाओं का जन्म होने लगा। सन् १८८५ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। देश में इस लहर के कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट ने १८९२ में एक नया नियम पास किया। इसकी इंडियन कॉनिंग ऐक्ट कहते हैं।

1. G. N. Singh, Ibid. p. 77.

2. Neither at the centre nor in the provinces was it intended to set up "legislatures" as the term is usually understood. The new legislative councils were limited in their functions to considering legislative projects alone." Sharma, Ibid. p. 5.

१८६२ का इण्डियन कौंसिल ऐक्ट — इसका द्वारा केन्द्रीय धारा-सभा (Supreme Legislative Council) के सदस्यों की संख्या कम से कम १० तथा अधिक से अधिक १६ कर दी गई। प्रांतीय कौंसिल में भी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। बम्बई तथा मद्रास में यह कम से कम ८ तथा अधिक से अधिक २० कर दी गई। बंगाल के लिए अधिक से अधिक सदस्य २० तथा उत्तर-पश्चिम प्रान्त और अवध के लिए १५ कर दी गई। इस ऐक्ट के द्वारा कौंसिलों को वार्षिक-वित्तीय विवरण पर सीमित रहने का अधिकार तथा प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। इस कौंसिल में कुछ गैर-सरकारी सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होने लगा। इसमें तात्पर्य यह है कि कुछ समस्याओं, जैसे म्युनिसिपल तथा ट्रिस्ट्रिब्यूट वाइड, जमींदार, विश्वविद्यालय चेम्बर ऑफ कामर्स, का सरकार के सम्मुख नाम उपस्थित करने का अवसर मिला। यद्यपि यह आवश्यक नहीं था कि उनकी सिफारिश मानी ही जाय परन्तु कार्यक्रम में यह कभी भी सम्वीकृत नहीं की गई।<sup>1</sup>

१८८६ का इण्डियन कौंसिल ऐक्ट — इस अधार में भी जागरूक भारतीयों को मनोप नहीं हुआ क्योंकि यद्यपि उनका कोई भी भाग नहीं दिया गया था इसलिए असन्तोष बढ़ता ही गया। शिक्षित-वर्ग इनमें स्वयंसेवा था। वर्जन के द्वारा बग-भग न इस आन्दोलन को भड़काया। सरकार ने एक्ट में इस आन्दोलन को दबाने की चेष्टा की। इसके उत्तर में बंगाल में आतङ्काद का जन्म हुआ। इस आन्दोलन के कारण ब्रिटिश सरकार का नये सधार करने की बाध्य होता पड़ा। इसने परिणामस्वरूप १९०९ में एक नया नियम पास हुआ जिसको मोर्ले-मिण्टो सुधार कहा जाता है। मॉर्ले भारत मंत्री था तथा मिण्टो भारत का वाइसराय। इस अधिनियम ने केन्द्रीय तथा प्रांतीय धारा सभाओं में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। उदाहरणार्थ केन्द्रीय धारा सभा में अधिक से अधिक ६० सदस्य, मद्रास बम्बई बंगाल संयुक्त प्रान्त बिहार तथा उड़ीसा में ५० और पंजाब वर्मा तथा आसाम में ३० हो सकते थे। इनके प्रतिनिधित्व इन सब राजसभाओं में पदेन (ex-officio) सदस्य भी थे। धारा-सभाओं में मनोनीत तथा निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य रहे गये। निर्वाचित प्रणाली अप्रत्यक्ष थी। ये सदस्य म्युनिसिपल तथा ट्रिस्ट्रिब्यूट वाइड विश्वविद्यालय, चेम्बर ऑफ कामर्स व्यापारिक संस्थाएँ जमींदार वर्ग आदि के द्वारा निर्वाचित होते थे। मुसलमानों को अलग मताधिकार दिया गया। इस प्रकार साम्प्रदायिक निर्वाचन का आरम्भ हुआ। सभाओं में मनोनीत सदस्य दो प्रकार के थे—

सरकारी तथा गैरसरकारी। केन्द्रीय धारा नम्बर में सरकारी सदस्यों का ही बहमन रखा गया। धारा-नम्बरों के अधिकारों में कुछ वृद्धि हुई। उनको प्रस्ताव रखने का अधिकार मिला परन्तु ये प्रस्ताव केवल मिशनरियों से दिये जा सकेंगे। उनको बजट पर बहस करने तथा परत प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला। इन सुधार द्वारा भारत मंत्री की कौन्सिल तथा वाइसराय की कौन्सिल में एक-एक भारतीय सदस्य रखा गया।

इन सुधारों से देश में बड़ी निराशा हुई। यद्यपि शुरू में कुछ लोगों में समझा कि ये उत्तरदायी शासन की दिशा में प्रथम पद है। परन्तु शीघ्र ही यह स्पष्ट हो गया कि इनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। भारतीयों के हाथ में कोई सार्थक अधिकार नहीं आया और न वे शासन की नीति पर ही किसी प्रकार का दबाव डाल सकने पें। गवर्नर ने इन सुधारों में असन्तोष प्रकट किया।<sup>१</sup> भारत मंत्री मार्ग में लार्ड मन्साफेन ने कहा था (दिसम्बर, १९०८) कि इन सुधारों का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना नहीं है।<sup>२</sup> इन सुधारों का एक दोष यह भी था कि प्रत्येक निर्वाचन प्रणाली का आरम्भ करके इन्होंने देश की एकता को बहुत घटा पहुँचाया।

**सन् १९१७ की घोषणा :—**भारत में असन्तोष बढ़ता गया। ब्रिटिश सरकार की महामोग नीति भारत में असहयोग की भावना को बढ़ा रही थी। भारतीय शासन में सार्थक अधिकार पाने की इच्छा थी। देश में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही थी। निश्चित रूप से लया प्रथम वर्ग अंग्रेजी नीति ने बहुत अधिक असन्तोष पैदा किया। जब यह प्रारम्भिक अवस्था थी, उस समय कांग्रेस में प्रथम महाभूट का आरम्भ हुआ। अंग्रेजों की ओर से कहा गया कि इन भूट का उद्देश्य प्रजातन्त्र तथा स्वतन्त्रता की रक्षा है। भारतीयों ने भूट में अंग्रेजी सरकार की हृदय से सहायता की। इनके दमले यह स्वभाविक था कि भारतीय यह माँग करें कि भूट के पश्चात् उनको भी स्वतन्त्रता-पूर्वक अपनी नीति निर्धारित

१. उन्होंने कहा "That once the Government had made up their mind to adopt a particular course, nothing that the non-official members may say in the council is practically of any avail in bringing about a change in that course."

२. "If it could be said that this chapter of reforms led directly or necessarily up to the establishment of a Parliamentary system in India, I, for one, would have nothing at all to do with it..."



भारत का अधिकार है। दाम हामरुत आन्धीन धार्मिक प्रान पहन ता सरकार न नका नवान की चर की परन्त कुछ का वार भारतीया को आवागमन निया गया कि यह व पचात उनकी मागा का ध्यान म गया जायगा नकागीन भारत म न २० अगस्त १९१७ का ब्रिटिश ममद म य घापणा का कि मम्रा की सरकार की नाति जिमम कि भारत की सरकार पूणतया मन्मत ह यह कि नामन व प्रयव भास म भारताय जनता का मस्याग वन्ता जाय तथा न म स्वायत्त मस्याआ का विकास हा जिमम कि भारत म ब्रिटिश माआय व अन्तगत वमन उत्तरनायिवपुण नामन स्थापित हा तब नम उत्तरनाय व निया माअ ही वन्म उठान का भा वचन निया गया। नम माय-माय य भी वन्ता गया कि नम नीति म वमन प्रगति हागी ब्रिटिश सरकार तथा भारत सरकार ही जिनर ऊपर भारतीय जनता की उत्पति तथा भर्ग का उत्तर नायिक ह नमका निणय करन कि वन्ता तथा रिन्ता आग वन्ता जाय। इस घापणा म ही य भी वन्ता गया था कि भारत मत्री भारत म आकर वामराय न परामन वन्ता

मन १०१७ की घापणा भारत व शानिक विकास म नर मन्त्रपण स्थान गन्ती ह कयाकि हमर द्वाग ब्रिटिश सरकार न प्रथम बार य स्वाकार दिया कि ब्रिटिश नीति का उ न्य भारत म उत्तरनायिवपुण नामन की स्थापना ह। नर कायक म न घापणा का फर आगाजनक नगी निरन।

मा म्यू चेम्सफोर्ड यो नाना — भारत मत्री मि० माण्डलू नवम्बर १०१७ म भारत आदि तदा मर्न व वागगाय नर चम्फा व माय नान भारताय की आरी नाता तथा गजननिर परिस्थिति म भरी प्रसार परिचित हान व निया न का नीर निया इस मय्यव न व आधार पर उठान भारतीय विधान व म नर व उपर नर याजना प्रन्त का जा कि नम निमाणनर्ताता व नाम म मों म्यू चेम्सफोर्ड योजना या मोंफोर्ड योजना वन्गती ह य याजना जन् १०११ म ली थी नम निम्नगित मय्य थान था —

(१) जर्न तन मम्भव हो म्यानाय मस्याआ को जनता व प्रति उत्तरनायि यनाया जाय तथा न स्वतन्त्रता प्रान की जाय।

(२) प्राना म मरप्रथम उत्तरनायिपण नामन क गि कन्म उठान नायि।

(३) भारतीय मरा-मभा व मस्या की मया वन्ती चाणि तथा इस जनता का अधिक प्रतिनिधिक करना चाणि।

(४) जैसे-जैसे ऊपर वर्णित न्याय होने जावे, भारतीय गानन के ऊपर पार्लियामेंट तथा भारत-सूत्री की शक्ति कम होनी जावे।

इसी योजना के ऊपर १९१९ का गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट बना।

अंगरेजी शासन का तृतीय काल (१९१६ से १९३५ के ऐक्ट तक)

१९३५ का गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ऐक्ट:—१९१९ के निपट की निम्न-लिखित विशेषताएँ थीं:—

(१) केन्द्र में इन ऐक्ट द्वारा एक भवन वाली शासन-सभा (Imperial Legislative Council) के स्थान पर दो भवनों वाली व्यवस्थापिका स्थापित की गई। उच्च भवन को राज्य-परिषद् (Council of States) एवं निचले भवन को विधान-सभा (Legislative Assembly) कहा गया। राज्य-परिषद् में ६० तथा विधान-सभा में १४३ सदस्य सम्मिलित थे, जो कि प्रथम ४ वर्षों के लिये गवर्नर-जनरल द्वारा नियुक्त किये जाने वाला था, रहते थे। राज्य-परिषद् में ३४ सदस्य निर्वाचित तथा शेष मनोनीत रहते थे। मनोनीत सदस्यों में २० में अधिक सरकारी नहीं हो सकते थे। निर्वाचित सदस्यों में १५ विशेष क्षेत्रों में चुने जाते थे। निर्वाचित की प्रथा प्रथम रली गई परन्तु यह अधिकार केवल थोड़े से व्यक्तियों को मिला क्योंकि बहुत ऊँची सम्पत्ति की योग्यता रली गयी थी। विधान सभा में २९ सरकारी १४ मनोनीत और सरकारी, तथा १०३ निर्वाचित सदस्य थे। परिषद् की आय पाँच वर्ष तथा विधान-सभा की तीन वर्ष रखी गई।

केन्द्रीय व्यवस्थापिका ने अधिकारों में भी कुछ वृद्धि हुई। इसको धन-व्यय, बजट पर एक निश्चित सीमा के अन्दर मत देने, प्रस्ताव पेश करने तथा प्रस्ताव राखने का अधिकार मिला। परन्तु इन अधिकार में कई रोकें लगा दी गईं। गवर्नर-जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी बिल को जो कि दोनों भवनों द्वारा पास हो गया हो पुनः उनके विचारण लौटा दे। इस प्रकार व्यवस्थापिका की कोई अधिक शक्ति नहीं दी गई थी।

केन्द्रीय कार्यकारिणी (Executive) भारत-सूत्री तथा पार्लियामेंट के प्रति ही पूर्णतया उत्तरदायी रखी गयी न कि भारतीय व्यवस्थापिका के प्रति। गवर्नर-जनरल के कौन्सिल के सदस्यों की संख्या ८ कर दी गई। उनको अधिकार दिया गया था कि वह कुछ विशेष मामलों पर अपनी कौन्सिल के सम्मति को अस्वीकृत कर दें।

(०) दूग सेक्ट के द्वारा प्राणीय तथा केन्द्राय विषया का अलग-अलग कर दिया गया।

प्राणीय की विधान परिषदा के सदस्य ११ मस्य म भी वृद्धि की गई। यह निश्चित हुआ कि इनमें कम से कम ५० प्रतिशत निर्वाचित सदस्य होंगे २० प्रतिशत से अधिक सदस्य मस्यारी नहीं होंगे। उमाठ में १३०, वार्ड में १११ मद्रास में १०५ मस्यवन प्रांत में १०५ पञ्जाब में ०६ सिंधु तथा उड़ीसा में १०५ मस्य प्रांत में १० तथा आगाम में ०३ सदस्य थे। प्रत्यक्ष निवाचन विधि रही मद्र। साम्प्रदायिक निवाचन भी रखा गया। इन परिषदा की आयु ३ वर्ष रही गई। उनसे अधिकार भी दृष्ट कर दिया गया थे।

प्राणीय विषया का २५ भाग में बांटा दिया गया। एक भाग का रक्षित (Reserved) तथा दूसरे का हस्तांतरित (Transferred) कहा गया। रक्षित विषय मस्यन की कोमिट के हाथ में थे। इनके लिये यह विधान परिषद् के प्रति नागमात्र का भी उत्तरदायी मस्य की मस्य, उमका उत्तरदायित्व मस्यन के प्रति था। दूग भाग में राजून राजस्व (Revenue) बाणि कागदाग, औद्योगिक मामले, पत्त, मसिदर दसिदा निवारण आदि रक्ते मये। हस्तांतरित भाग में स्थानीय मस्यमस्य जन-मस्यमस्य शिक्षा, उमि मस्यारी मसिमि, उद्योगधन्धा का विकास आदि रक्ते मये। दूग भाग का प्रबन्ध मस्यन अपने मसिमिदा की मस्य में करवा था। ये मस्री विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। मस्यन द्वारा निर्वाचित सदस्य में से मस्री मारीय मिये जाते थे। दूग कांठ-विभाज का दूध नाग (Dyarchy) कहा जाता है।

(३) दूग सेक्ट के द्वारा मस्य-मस्यन में भी परिवर्तन मिये मये। भारत-कोमिट के सदस्य की मस्य घटा दी गई। पहले यह १० और १६ के बीच थी। दूग सेक्ट द्वारा यह ८ और १२ के बीच रखी मयी। इन सदस्य की नियुक्ति ५ वर्ष के लिये की जाती थी। भारत मनी तथा उनसे उममस्री का केन्दा असेत्री मस्यन में देना निश्चित था।

उप मये मस्यमारी की नियुक्ति दूई जमको कि हाई कमिशनर (High Commissioner) कहा गया। दूसरा काम उमसेक्ट में भारत मस्यन

1. "The division of the sphere of Government between two authorities, one amenable to Parliament and the other responsible to the electorates is known as Dyarchy" Supre, Indian Constitution and Administration, p 321

के एजेंट का था। इनको स्टोर-विभाग, भारतीय विद्यार्थी विभाग, भारतीय व्यापार-व्यवसाय के कार्यों का निरीक्षण नीचे गये। इन प्रकार भारत-राजी के हाथ में एजेंसी कार्य ले लिया गया।

(४) इसी साल एक रियासती परिषद (Chamber of Princes) की भी योजना बनी। इसका विधान १९१९ के नियम में नहीं था। इसकी स्थापना सम्राट की एक घोषणा द्वारा हुई।

(५) इस ऐक्ट में यह भी कहा गया कि १० वर्ष के पश्चात् एक कमीशन भारत भेजा जायगा। वह इस बात की जांच-पड़ताल करेगा कि भारत में १९१९ के ऐक्ट द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था कहा तक सफल रही है।

इस ऐक्ट से भारत को सन्तोष नहीं रहा। यह धारणा थी कि इस विधम के द्वारा उत्तरदायी-शासन व्यवस्था स्थापित होगी। इसी समय मैहता, अन्ना-बेण्ट तथा भारतीय मुसलमानों के तर्कों के मूलतः के प्रति बिरे हुए निर-राष्ट्रों के व्यवहार के लिये अनसुनो ने, अंग्रेजों के प्रति अनमत्तता को और बढ़ाया। रौलट ऐक्ट तथा जलियानवाला बाग ने माय में धी बर काम किया।<sup>१</sup> गांधी जी के नेतृत्व तथा अमीर-खानों के सहयोग ने एक देशव्यापी आन्दोलन फैला। इन आन्दोलन का उद्देश्य अहिंसात्मक उपायों से देश की स्वतंत्रता प्राप्त करना था। सरकार का इसमें पक पुरे जोरों के साथ चला। १९२० में जब नये ऐक्ट के अनुसार चुनाव हुए कांग्रेस ने उनका विरोध किया। आन्दोलन अग्रसर रहा। इसके बाद कांग्रेस के अन्दर एक अनेकवर्ती पार्टी बनी और इस दल के सदस्य अनेकवर्तियों में गये। इन समय देश में कई स्थानों में नागरिक दंगे हुए।

साइमन कमीशन—सन् १९२७ में साइमन कमीशन भारत आया। परन्तु इसका भारतीयों ने सर्वत्र बहिष्कार किया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इस कमीशन की रिपोर्ट १९३० में प्रकाशित हुई परन्तु राष्ट्रीय भारत ने इसको प्रतिनिध्यावादी बनलाया। इन समय बिलायत में मजदूर दल की सरकार बन गई थी। इसने भारतीय समस्या को मूलतः के लिए एक गोलमेज सभा बुलवाई। यद्यपि वे गोलमेज सभा की मांग कुछ वर्ष पूर्व पं० मोतीलाल ने की थी। लेकिन उन समय अंग्रेजों ने उसे नहीं माना। इस प्रथम गोलमेज सभा में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। इसके पश्चात् एक दूसरी

१. इन सब बातों का विस्तारपूर्वक वर्णन 'राष्ट्रीय आन्दोलन' वाले अध्याय में किया गया है।

सभा पुनर्वाइ गई। इसमें कायम न भाग लिया परन्तु कोई फल न निकला। इससे बाद एक तीसरी मालमज सभा बुलवाइ गई। इन सभाओं के परस्पर, यह धारणा मवमाय हो गई कि भारत में एकात्मक सरकार के स्थान में एक संघात्मक सरकार होनी चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने भारत की समस्या के ऊपर एक श्वेतपत्र प्रकाशित किया। इस श्वेतपत्र का ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों भवनों की एक संयुक्त प्रचरमिति (Joint Select Committee) ने सम्मूल रखा गया। इस कमेटी के अध्यक्ष लार्ड लिन्लिथगो थे। इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी उसके ऊपर १९३५ का एक्ट आधारित किया गया।

१९३५ का गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट — इस एक्ट का राष्ट्रीय भारतीयों ने स्वागत नहीं किया। क्याकि इसका उद्देश्य भारतीयों को बंधन देने का नहीं था। सर० सी० वार्ड० चिन्तामणि जैम नरमदगी ने इसको 'अभारतीय एक्ट' कहा। इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित थीं।<sup>१</sup>

(१) एक अखिल भारतीय मध्य की स्थापना जिसमें की ब्रिटिश भारत के प्रांत तथा दक्षिण गज्य दोनों सम्मिलित हों।

(२) प्रान्तों का स्वायत्त शासनाधिकार।

(३) प्रान्तों में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना परन्तु इसके साथ साथ गवर्नर का कई विषयों में विशेषाधिकार।

(४) मद्रास वगैरह मयनत प्रान्त बंगाल बिहार तथा आसाम में विधान परिषद (Upper Chambers) की स्थापना।

(५) धर्म तथा अदन का भारत में सम्बन्ध विच्छेद।

(६) दो नये प्रान्त—मिन्ध तथा उड़ीसा—का निर्माण तथा पश्चिमात्तर सीमा प्रांत का गवर्नर का प्रांत बनाया जाना।

(७) केन्द्र में द्वैध शासन प्रबन्ध की स्थापना अर्थात् आंशिक उत्तरदायित्वपूर्ण शासन प्रबन्ध।

(८) एक मधीय न्यायालय की स्थापना।

(९) एक रिजर्व बैंक की स्थापना।

संघ निर्माण — भारत संघ का निर्माण मन्त्रालय की एक घोषणा द्वारा हुआ था। परन्तु इसके लिये एक सत्र आवश्यक थी और वह यह कि उनसे देशी

<sup>१</sup> P. R. Rao, A Survey of Indian Constitutionalism,

राज्य मध्य में धारों को प्रस्तुत हो जायें जो कि कम से कम राज्य परिषद् में ५२ सदस्य भेजें तथा जिनकी जनसंख्या नमस्त देशी राज्यों की जनसंख्या की प्राची हो। भारत में मध्य शासन स्थापित न हो सका क्योंकि देश के मध्य मुख्य-मुख्य राजनैतिक दल इसके विरुद्ध थे। इसका कारण यह था कि केन्द्र में गवर्नर-जनरल को इतने अधिक अधिकार दिये गये थे कि उत्तरदायी शासन अशुभव था। इसके अतिरिक्त देशी राज्यों ने भी इसमें सम्मिलित होना स्वीकार नहीं किया।

**अधिकार विभाजन**—इस ऐक्ट द्वारा अधिकारों का विभाजन मध्य सरकार तथा प्रान्त की सरकारों के बीच निम्न प्रकार किया गया था —

**संघ-सूची में ५९ विषय थे।** उदाहरणार्थ, सेना, मनुष्यी तथा हवाई सेवा, परराष्ट्रनीति, धार्मिक विषय, डाक, तार, टेलीफोन, रेल, नौसेना सेवाएं आदि आदि।

**प्रान्तीय-सूची में ५४ विषय थे।** उदाहरणार्थ, पुलिस, जेल, स्वास्थ्य, प्रान्तीय सेवाएं, स्थानीय-स्वशासन, जन-स्वशासन, शिक्षा, रास्ते, नहर तथा सिंचाई, इति, जगजात आदि।

**सम्मिलित-सूची में ३६ विषय थे।** जैसे विवाह, तलाक, मनाचार पत्र, मजदूर-समाई आदि। इन विषयों पर संघ-सरकार तथा प्रान्तीय सरकार दोनों का कानून बनाने का अधिकार था।

इसके अतिरिक्त अवशिष्ट-शक्तियां (residuary powers) को सरकार को दी गई थी।

**संघ सरकार**—केन्द्र में इस ऐक्ट के द्वारा ईश्वर-नरनर स्थापित होने वाली थी। इस प्रकार कुछ विषय तो रक्षित थे और इसमें गवर्नर-जनरल, बिना अपने सचिवों के काम कर सकता था। ये विषय रक्षा, परराष्ट्रनीति, कबोला क्षेत्रों में सम्मत्य तथा ईमाई धर्म थे। इन विषयों के लिए वह अधिक से अधिक ३ कौमिलर नियुक्त कर सकता था। अन्य विषयों में (हस्तान्तरित विषय) उसकी सचिवों की सहायता से काम करना था। परन्तु उसको इतने अधिकार दिये गये थे कि उनकी वह राय के विरुद्ध काम कर सकता था। कुछ अन्य विषयों में वह केवल सम्राट के प्रति उत्तरदायी था। ये उनके विरोध-उत्तरदायित्व के विषय थे—जैसे की शांति, अन्तर्देशीय के हित, देशी राज्यों का हित, सरकारों के अधिकारों के अतिरिक्त आदि को रखा। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनको इतने अधिकार दिये गये थे कि वह देश का सर्वमूर्त था।<sup>१</sup>

१. गांधीजी ने उनके विषय में कहा "a personage possessing unheard of powers."

मध्यम व्यवस्थापिका व दो भवन हान वा १५। एक का नाम राज्य परिषद (Council of States) तथा दूसरा का नाम मध्यमभा (Federal Assembly)। राज्य परिषद में १५६ प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत में न तथा अंग्रेजों में अंग्रेज १०६ दत्ता गया म हान। देशी राज्य अपने प्रतिनिधियों का किसी प्रकार चुन सकते थे परन्तु ब्रिटिश भाग में १५० सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता ६ गवर्नर जनरल द्वारा मनानीय विषयों पर परन्तु मन २० का अधिकार सम्पूर्ण ब्रिटिश भाग में केवल १५० ००० व्यक्तियों का मित्ता। राज्य परिषद स्थायी मस्या होती। इसके एक तिहाई सदस्य प्रति सात वर्ष अवकाश प्राप्त करते।

मध्यमभा में अधिकाधिक ३३५ सदस्य हान। २५० ब्रिटिश भाग में तथा १०५ रियासतों में। ब्रिटिश भारत में २४६ सदस्य विभिन्न प्रान्ता स अध्याक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते। उनका चुनाव प्रान्तीय विधान मभाओं द्वारा होता। १५४ सदस्यों में तीन व्यवस्थापिका व व्यापारिका के तथा एक मजदूरों का प्रतिनिधि हाना। राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन का प्रवच दत्ता राज्य स्वयं करते। मध्यमभा की अवधि ५ वर्ष रखी गयी थी अगर यह उमक पूर्ण ही भग न कर दी गई हो।

मधीय व्यवस्थापिका का मधीय-मूची में वर्णित सब विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हाना। यह सम्मिलित मूची में वर्णित विषयों पर भी तथा प्रान्ता की स्वीकृति से प्रांतीय मूची के विषयों पर कानून बना सकती। सकट में यह सम्पूर्ण भारत के लिए कानून बना सकती। देखने में तो इसका सार अधिकार था परन्तु मयाथ में इसके अधिकार नामपात्र थे। क्याकि कानून विषयों पर यह दिना गवर्नर जनरल की अनुमति के न कानून बना सकती न कोई मन्त्राधन कर सकती। गवर्नर जनरल के कई कानून सम्बंधी अधिकार हान जैसे उसका आर्थिक न जागी करने का अधिकार होता। वह अपना इच्छा में कानून भी बना सकती था। गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका द्वारा पाम किये गये कानूनों का अमलीजामा करने का अधिकार होता। यह धन में अत्यन्त न होगी कि इस प्रकार के अनुसार सर्वोच्च कानून बनाने वाले मस्या व्यवस्थापिका न हाकर गवर्नर जनरल ही होता।

१) व्यवस्थापिका के वित्त अधिकार भी अत्यन्त यून थे। मधीय बजट का इरादा तीन चौथाई इसके अधिकार के बाहर था। १५ बजट में भी गवर्नर जनरल को कई अधिकार थे। वह अपने विष्णु दायित्व को पूरा करने के हेतु

व्यवस्थापिका द्वारा कितों भी अस्वीकृत व्यय का अधिष्टान व्यय की मूर्ती में डाल सकता था।

**प्रान्तीय सरकार** —इन ऐक्ट द्वारा प्रान्तों को स्वराज तथा उत्तरदायित्वपूर्ण शासन दिया गया था। प्रान्तों में द्वैध शासन का अन्त कर दिया गया। गवर्नर के हाथ में कोई रक्षित विषय नहीं रहे गये। सभी विषय प्रान्तीय व्यवस्थापिका तथा मन्त्रिमण्डल के आधीन कर दिये गये। मन्त्रिमण्डल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। परन्तु इतना होते हुए भी प्रान्तीय सरकारों पर गवर्नर-जनरल तथा भारतमन्त्री का नियन्त्रण बना रहा। गवर्नर को भी कई विशेषाधिकार दिये गये थे। वह मन्त्रियों के कामों में हस्तक्षेप कर सकता था। उनको अवहेलना कर सकता था तथा विधान को स्विकृत कर सकता था।

कुछ प्रान्तों में दो सदन वाली तथा कुछ में एक सदन वाली व्यवस्थापिका स्थापित की गई थी। इन व्यवस्थापिकाओं के अधिकारों पर कई प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे। इसलिए प्रान्तों में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन नाममात्र को ही स्थापित हुआ क्योंकि पृष्ठभूमि में गवर्नर की मूर्ति नभंश दृष्टिगोचर होती रही।

**गृह-सरकार** —इन ऐक्ट द्वारा गृह-सरकार में बदलाव किया गया। इंडिया-कौमिल को हटा दिया गया तथा उसके स्थान में एक परामर्श-दाताओं की समिति की स्थापना की गई। भारत-मन्त्री को यह अधिकार रहा कि वह इनकी राय माने या न माने। भारत-मन्त्री के परामर्शदाताओं की संख्या सघ बनने तक ८ में १२ तक रखी गई तथा सघ बनने के बाद इसमें तीन में छः तक सदस्य होना निर्दिष्ट किया गया। इनका वेतन १३५० पाँड वार्षिक तथा भारत के निवासी को ६०० पाँड वार्षिक भत्ता भी मिलता था। गृह-सरकार की शक्तियों में यद्यपि इन ऐक्ट द्वारा कुछ कमी की गई थी तथापि इसके पश्चात् भी वे कानूनी व्यापक थी।

**ऐक्ट का कार्यान्विन होना** —इस नये ऐक्ट के अनुसार प्रान्तों में चुनाव हुये। कांग्रेस ने इसमें भाग लिया तथा मद्रास, बम्बई, मद्रास प्रान्त, मध्य प्रान्त, बिहार और उड़ीसा में इसका बहुमत रहा। सामान तथा पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त में भी व्यवस्थापिका में कांग्रेस दल बहुत शक्तिशाली था। जब मन्त्रिमण्डल बनने का प्रश्न उठा तो कांग्रेस ने पहले तो गवर्नर के विशेषाधिकार के कारण मन्त्रिमण्डल बनाना अस्वीकार कर दिया। परन्तु कुछ काल पश्चात् उनको यह आश्वासन मिला कि गवर्नर अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग साधारणतः



मन्त्रिमंडल के कामों में राडा अटकाने का नहीं करेंगे। इसके बाद कांग्रेस ने ८ प्रान्ता में मन्त्रिमंडल बनाया। इस ऐक्ट का मधीय भाग लागू नहीं किया गया। भारतीय राजनीतिक दलों ने सघीय व्यवस्था का नितान्त असंतोषजनक बह्ना और वे इसमें भाग लेने को किसी भी दशा में प्रस्तुत नहीं थे। देशी राज्य भी मध में सम्मिश्रित होने के लिए तैयार नहीं हुए।

१९३५ के ऐक्ट के दोष — इस ऐक्ट में कई दोष थे। सबसे मुख्य निम्न-लिखित थे —

(१) इस ऐक्ट द्वारा जिस मध का निर्माण हुआ, उनमें देशी राजाओं के हित सुरक्षित रहते और इस प्रकार दम के एक बड़े भाग में प्रजातन्त्र शासन-व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकनी थी। देशी राज्यों को बहुत अधिक महत्व दिया गया था।<sup>१</sup>

(२) भारतीय मध न तो परराष्ट्र नीति में और न आन्तरिक नीति में ही स्वतंत्र होता। सरकारों में ऐक्ट का उद्देश्य स्वतन्त्र मध बनाना था ही नहीं। इस प्रकार मध स्थापित होने पर भी भारत अपने भाग्य का निर्माता नहीं हो सकता था।

(३) केंद्रीय कार्यवाहिकी का इतना अधिक अधिकार द दिये गये थे कि वह नृण स्वहरेण अनियन्त्रित थी। गवर्नर जनरल अपने मन्त्रियों को राय के विरुद्ध जो चाहें तो कर सकता था। मन्त्रिमंडल के हाथों में एक प्रकार से कुछ भी शक्ति नहीं थी और यह केवल शोभाय था। इस ऐक्ट ने मन्त्रिमंडल को समुक्त उत्तरदायित्व सिद्धान्त पर भी आधारित नहीं किया।

(४) केंद्रीय व्यवस्थापिका को भी बहुत सीमित अधिकार दिये गये थे। गवर्नर जनरल इसके अलावे किसी भी कानून का अम्भीकार कर सकता था। इसके लिये जो निर्वाचित प्रथा बनाई गई थी वह भी अत्यन्त दूषित थी। मध सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन अनहानी बात थी। साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व देश के लिए घातक सिद्ध हुआ। देशी राज्यों की व्यवस्थापिका में करीबन ४० प्रतिशत सदस्य होते जब कि उनकी जनसंख्या देश की जनसंख्या की एक-

१ "I am satisfied that the system of construction of the Federation under which the nominees of autocratic rulers are to have a powerful voice in both Houses of the Federation, in order to counteract Indian democracy, is quite indefensible" A. B. Keith quoted in H. N. Banerjee, New Constitution of India, p 41. f n.

निहाई में भी कम थी। इन राज्यों के प्रतिनिधि विदेशी सरकार के पिट्ट होने, अतएव प्रगति के अनु।

(५) प्रान्तीय-स्वराज्य केवल नाममात्र को था। गवर्नर व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। उनका मर्यादित उत्तरदायित्व मन्त्रि-परिषद् के प्रति था। वे अपने मन्त्रिमण्डल की राय को मानना असंभव कर सकते थे। इसलिए प्रान्तीय-स्वराज्य द्वारा कोई भी उपाय नकित भारतीयानियों के हाथ में नहीं दी गई।<sup>१</sup>

ब्रिटीश शासन का अन्तिम काल (१९३७-४०) — १९३७ में प्रान्तों में मन्त्रिमण्डल बने। इस प्रकार १९३५ के ऐक्ट का प्रान्तीय शासन सम्बन्धी भाग लागू हो गया। परन्तु इस ऐक्ट का मध्य-शासन वाला भाग केन्द्र में लागू नहीं हुआ।

इस समय यूरोप में राज्यों के मध्य वैमनस्य तथा विरोध बढ़ता जा रहा था। इसका परिणाम यह हुआ कि १९३९ में द्वितीय महायुद्ध का प्रारम्भ हुआ। इस युद्ध में भारत भी सम्मिलित कर दिया गया। परन्तु अंग्रेजी शासकों ने यह कार्य बिना भारतीयों की इच्छा के किया था। इस पर कांग्रेस ने यह माँग की कि ब्रिटिश सरकार यह घोषणा करे कि युद्धोपरान्त भारत स्वतन्त्र कर दिया जावेगा। परन्तु अंग्रेजी सरकार के यह माँग स्वीकार न करने पर, कांग्रेस मन्त्रिमण्डलों ने ८ प्रान्तों में विरोध स्वरूप त्यागपत्र दे दिया। परन्तु सिन्ध, पंजाब तथा बंगाल में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल कार्य करते रहे दोष प्रान्तों में गवर्नरों ने अपने हाथ में शासन ९३ धारा के अनुसार ले लिया।<sup>२</sup>

१. K. T. Shah : "It (Provincial Autonomy) is a cloak for the refusal on the part of British Imperialism to part with any substance of power to the people of India in the management of their own concerns."

२. "If at any time the Governor of a province is satisfied that a situation has arisen in which the Government of the Province cannot be carried on in accordance with the provisions of this Act, he may, by Proclamation :—

- (a) declare that his functions shall be exercised by him in his discretion ;
- (b) assume to himself all or any of the powers vested in or exercised by any Provincial body or authority.....'

Sec. 93 of 1935 Act.

८ अगस्त १९४० की घोषणा —युद्ध में इंग्लैंड के सहायक समस्त पश्चिमी यूरोप में परास्त हो गये थे और बचल इंग्लैंड अकेला ही आत्मी सेनाओं का मुकाबिला करने का रह गया था। उस समय भारत के गवर्नर-जनरल ने ब्रिटिश सरकार की ओर संवैधानिकता की (अगस्त ८ १९४०)। इसमें निम्न उल्लिखित मुख्य बातें थी —

(१) गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति में नया सदस्य नियुक्त किया जावेगा तथा परामर्श देने के लिये एक युद्ध समिति नियुक्त की जावेगी।

(२) युद्ध के पश्चात् भारतीयों को एक प्रतिनिधि मण्डल द्वारा ही भारत का नया विधान बनाया जावेगा। युद्धकाल में ऐसा पग उठाना सम्भव नहीं।

(३) ब्रिटिश सरकार इस बात की चेष्टा करेगी कि विभिन्न राजनैतिक दलों में आपस में समझौता हो जावे।

इस घोषणा से कोई मस्ताफ नहीं हुआ। क्योंकि इसके द्वारा जो कुछ भी प्रतिज्ञा की गई थी वह यद्वातर्क थी। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट नहीं किया गया था कि औपनिवेशिक-स्वराज्य स्थापित ही कर दिया जावेगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह थी कि अंग्रेज सरकार ने यह बात मान ली थी कि भारत का नया विधान भारतीयों द्वारा ही निर्मित होगा। किसी भी राजनैतिक दल ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति में अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे। मित-म्बर १९४० में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार की नीति के प्रति विरोध प्रकट करने को व्यक्तिगत मर्यादाग्रह आरम्भ किया। गांधीजी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे इंग्लैंड की कठिनाई में लाभ नहीं उठाना चाहते हैं। इसीलिए इस मर्यादाग्रह को सीमित रखा गया। जुलाई १९४१ में वाइसराय ने अपनी कार्यकारिणी समिति में पाँच और सदस्यों की नियुक्ति की। ये सब भारतीय थे।

क्रिप्स योजना —— इस समय युद्ध पक्ष में भी फैटने लगा था। दिसम्बर १९४१ में जापान ने पल हावर पर आक्रमण किया। दक्षिण-पूर्वी एशिया में जापान की प्रगति आश्चर्यजनक गति से हुई। भारत में जापानी आक्रमण का भय बढ़ा। देश में अंग्रेज विरोधी भावना भी प्रतिदिन बढ़ रही थी। इस कारण अंग्रेजी सरकार ने जापान के विरुद्ध भली प्रकार से युद्ध चलाने के लिए भारत का सहयोग प्राप्त करना आवश्यक समझा। इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए ब्रिटेन के युद्धकालीन मन्त्रिमण्डल ने सर स्टाफर्ड क्रिप्स का भारत भेजा। उन्होंने भारतीय नेताओं से वार्तालाप के पश्चात् मार्च २९, १९४२ को ब्रिटिश सरकार की ओर से एक योजना की घोषणा की जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं —

(१) भारत में स्वराज्य (Self-government) स्थापित करने की दृष्टि से, युद्ध के उपरान्त एक नवीन प्रांतीय मंच की स्थापना की जावेगी, जिसका पद उपनिवेश (Dominion) का होगा। यह ब्रिटिश-मण्डल का सदस्य होगा, परन्तु इसको इस राष्ट्र-मंडल में सम्बन्ध विच्छेद करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(२) युद्ध के समाप्त होने ही एक निर्वाचित विधान-निर्मात्री मंच बुलाई जावेगी, इसके निर्वाचन के लिये सर्वप्रथम, प्रान्तों में १९३५ के ऐक्ट के अनुसार नए चुनाव किये जावेंगे। इन प्रांतीय विधान मण्डलों (Lower Houses) के संसद, प्रांतुपातिक प्रतिनिधित्व विधि से संविधान मंच के सदस्य चुनेंगे। उनकी मर्यादा अपने निर्वाचकों की मर्यादा का  $\frac{1}{10}$  होगी।

इनके प्रतिरिक्त वेही राज्य भी अपनी जनमर्यादा के अनुसार इन विधान निर्मात्री मंच में प्रतिनिधि भेजेंगे।

(३) अगर कोई प्रान्त अथवा राज्य इस संविधान मंच द्वारा निर्मित नये विधान को स्वीकार न करे तो उसे यह अधिकार होगा कि वह भारतीय मंच में अलग हो जाय। ऐसे प्रान्त तथा राज्य अपना स्वतन्त्र मंच बना सकेंगे, जिसको वही अधिकार होंगे जो कि भारतीय मंच को।

(४) ब्रिटिश सरकार तथा विधान-निर्मात्री मंच के मध्य सल्लसल्लकों के हितों के रक्षार्थ तथा नागरिक-परिवर्तन में उत्पन्न अन्य बातों के लिये, एक मंच होगी।

(५) युद्ध काल में तथा नये संविधान के लागू होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व तथा उसके लिए शक्ति तथा अधिकार गवर्नर-जनरल की होंगी तथा वह ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा। परन्तु सैनिक, नैतिक तथा भौतिक (military, moral and material) मापनों को संयोजित करने का उत्तरदायित्व, भारतीय जनता के सहयोग में भारतीय सरकार पर होगा।

इस योजना के दो भाग थे। एक तो युद्धोत्तर, दूसरा युद्धकालीन। युद्ध के बाद भारत को उपनिवेश का पद दिया जाता। इस प्रकार स्वराज्य का मिदान्त मान लिया गया था। परन्तु इसमें दो दोष थे। पहला यह कि प्रान्त अथवा राज्यों को भारत मंच से अलग होने का अधिकार प्रदान किया गया था। इससे भारत की एकता भंग हो जाती। यह बयान में मुस्लिम लीग तथा कुछ देशी राज्यों को प्रसन्न करने के लिये किया गया था। दूसरा दोष यह था कि

विधान-निर्मात्री सभा में देशी-राज्या के जो सदस्य होते वे इन राज्या की ९ करोड़ जनता के प्रतिनिधि न होते अपितु वे राजाओं द्वारा मनोनीत सदस्य होते। इस प्रकार वे विधान निर्मात्री सभा के अन्दर एक प्रतिक्रिया-वादी शक्ति होते।

युद्धकालीन भाग में दोष यह था कि भारतीयों को अपने देश की रक्षा का उत्तरदायित्व नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त वाइसराय की कार्यकारिणी समिति न तो कैबिनेट के रूप में काम करने वाली थी और न वाइसराय ही एक प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में। इन्हीं कारणों से कांग्रेस ने इस योजना को प्रस्वीकार कर दिया। इस योजना का तत्कालीन फल कुछ नहीं होता। केवल युद्धापरान्त ही इससे कुछ फल निकलता। इसी कारण गांधीजी ने इसको "Post dated cheque" कहा था। अन्य भारतीय दलों ने भी इस योजना को स्वीकार नहीं किया।

"भारत छोड़ो" आन्दोलन —विष्म-योजना की असफलता पर भारत में अत्यन्त निराशा हुई अंग्रेजों के प्रति घृणा तथा क्षोभ का भाव बढ़ा। यह आशा नहीं रही कि समझौता सम्भव है। कांग्रेस ने अंग्रेजों के सम्मुख यह प्रस्ताव रखा कि वे भारत छोड़ें। इसमें तात्पर्य यह था कि अंग्रेजी राज्य का भारत में अन्त हो। यह प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यसमिति ने १४ जलाई १९४२ को पास किया था। इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कम्बोई में अखिल-भारतीय कांग्रेस कमेटी की सभा हुई। ८ अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारा हुआ गांधीजी ने कहा कि यह उनका अंग्रेजों का विरुद्ध अन्तिम स्टैंड है। ९ अगस्त के प्रातःकाल कांग्रेस के सब बड़े बड़े नेता अंग्रेजी सरकार ने पकड़ लिए। इससे देश में और क्षोभ बढ़ा। १० अगस्त का भागत-मनी एमरी का एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ जिसमें यह कहा गया कि कांग्रेस का काम देश में तार काटना, रेल उखाड़ना आदि था। इसके पश्चात् कुछ समय तक देश में देश-भक्तों ने इसी कार्यक्रम को अपना कर काम किया। अंग्रेजी सरकार ने पार्श्विक अत्याचार किए। गाली चलाना, गांव जला देना सामूहिक जुर्मानी तथा अन्य प्रकार के अत्याचार किए गए। कुछ समय तक ता जनता ने इसका प्रत्युत्तर दिया परन्तु करीबन दो मास पश्चात् देश में यद्यपि अमनतोष बना रहा तथापि आन्दोलन का एक प्रकार से अन्त हो गया।

१० फरवरी १९४३ को गांधीजी ने २१ दिन का व्रत रखा। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की नीति में परिवर्तन करना था। मई १९४४ में गांधी जी जेल में बीमार पड़े। सरकार ने उन्हें मुक्त कर दिया। जेल के बाहर गांधीजी ने फिर स्वच्छता प्राप्ति के प्रयत्न में लीग के नेता श्री जिन्ना से बातें की ताकि

हिन्दू-मुस्लिम एकता प्राप्त हो जावे। परन्तु इनमें उन्हें कोई मरुतता नहीं मिली। श्री जिन्ना का दावा कि मुसलमान एक अलग राष्ट्र हैं गांधीजी मानने को प्रसन्न न थे। इसमें कम से श्री जिन्ना मानने को तैयार न थे।

**चैबेल-योजना**—अगस्त १९४४ में लार्ड चैबेल भारत के नये वाइसराय होकर आये। उन्होंने देश में गत्यवरोध को दूर करने के लिए ब्रिटिश सरकार से मनवा कर (१४ जून १९४५) एक सूझाव रखा। इसको "चैबेल सुझाव" कहा जाता है। इसमें यह कहा गया था कि ब्रिटिश सरकार भारत के स्वराज्य प्राप्ति में सहायता करना चाहती है। भारत में विभिन्न सम्प्रदायों के बीच सम-सीने के लिए एक सभा बुलाई जावेगी। इस सभा का तत्कालीन उद्देश्य वाइसराय की एक नई कार्य-कारिणी समिति बनाना होगा, जिसमें सर्व हिन्दू तथा मुसलमानों के बराबर प्रतिनिधि होंगे। भारतीयों की परासष्ट विभाग भी दिया जावेगा, परन्तु मेतावर्ति अंग्रेज ही रहेगा। यह कार्य-कारिणी समिति वाइसराय के प्रति उत्तरदायी होगी। भारत में ब्रिटिश सरकार एक हार्ड-बमिन्टर भिन्न करने की जैसा कि अन्य उपनिवेशों में है।

१५ जून १९४५ को कांग्रेस के नेता मुक्त कर दिये गये तथा २५ जून को गिमला में सब दलों का नेताओं का सम्मेलन बुलाया गया। कांग्रेस ने इसमें भाग लिया। कोई समझौता न हो सका। क्योंकि मुस्लिम लीग ने यह नांग की कि कार्य-कारिणी समिति में सब मुसलमान सदस्य लीग के ही द्वारा मनोनीत होंगे। इसका अर्थ यह होगा कि कांग्रेस हिन्दुओं पर गंगडन है। कांग्रेस ने इसे मानना अस्वीकार कर दिया। क्योंकि लीग तथा कांग्रेस में समझौता न हो सका इसलिए वाइसराय ने इस सम्मेलन को भंग कर दिया।

**नये चुनाव**—जब इंग्लैंड में १९४५ में चुनाव हुए, चर्चिल के अनुदार दल की विजय नहीं हुई। इनके स्थान में सज्जूर दल की सरकार बनो तथा एटली नये प्रधान मंत्री हुए। इस समय पूर्व में जापान में युद्ध समाप्त हो गया था। इस समय भारत में आजाद-हिन्द-सेना के पक्षों को लेकर एक कौने से दूसरे कौने तक झुलबल मची हुई थी। इंग्लैंड की नई सरकार ने वाइसराय को बुलाना। इंग्लैंड ने वापसी पर १९ सितम्बर १९४५ को लार्ड चैबेल से एक घोषणा की। इसमें मुख्य बातें निम्नलिखित थी—

(१) १९४५-४६ के बीचकाल में भारत में केन्द्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के लिए चुनाव होंगे।

१. इसका वर्णन राष्ट्रीय सम्मोहन वाले अध्याय में देखिये।

(२) चुनाव के पश्चात् ब्रिटिश सरकार एक विधान-निर्मात्री सभा को बुलावेगी। इस उद्देश्य में वाइसराय भारतीय नेताओं से बात कर यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि रिप्प योजना उन्हें मान्य है अथवा वे उनमें कोई परिवर्तन चाहते हैं।

(३) देशी-राज्या के प्रतिनिधियों में इस विषय पर वार्तालाप होगा कि वे किस प्रकार आयोजित विधान-निर्मात्री सभा में भाग ले सकेंगे।

कांग्रेस ने इस घोषणा को अपूर्ण तथा अस्पष्ट बतलाया और यह कहा कि उसका उद्देश्य पूर्ण स्वतन्त्रता है। देश में चुनाव का फल यह हुआ कि छाठ प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बनें। बंगाल तथा मिथ, में सीपी मन्त्रिमण्डल बना। राजा में कांग्रेस, अकार्गी तथा यनियनिस्ट दल का मन्त्रिमण्डल विश्व हयात का के नेतृत्व में बना।

कैबिनेट मिशन — इस समय देश में एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का मिश्ट-मण्डल भ्रमण कर रहा था। इसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार ने दिसम्बर १९४५ में की थी। फरवरी १९४६ में इसने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को दी। इसी बीच में भारतीय नीति-नीति की जानकारी हड़ताल तथा सवर्ण आरम्भ हो गया था। इस घटना का ब्रिटिश सरकार की नीति पर काफी प्रभाव पड़ा। १९४६ में ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने यह घोषणा की कि एक तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा जायगा। इसका काम भारतीय नेताओं से मिल कर दीर्घनिर्णय भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करवाने का था।<sup>१</sup> इसके सदस्य लार्ड पैथिक लारेन्स (भारत मंत्री), सर स्टैफोर्ड क्रिप्स (बोर्ड ऑव ट्रेड के अध्यक्ष), तथा ए० बी० एलेक्जेंडर (फ़स्ट लार्ड ऑफ एडमिरैलिटी), थे। १५ मार्च १९४६ को ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने कामन्स सभा में एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि (१) ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतन्त्रता की मांग को स्वीकार करती है। (२) किसी भी

---

१ श्री एटली ने मिशन के भारत रवाना होने के विषय में कहा "My colleagues are going to India with the intention of using their utmost endeavours to help her to attain her freedom as speedily as possible. What form of Government is to replace the present regime is for India to decide, but our desire is to help her to set-up forthwith the machinery for making that decision. I hope the Indian people may elect to remain within the British Commonwealth. But if she does so elect, it must be by her own free will."

अल्पसंख्यक जाति का बहुसंख्यकों की प्रगति रोकने का अधिकार (veto) नहीं माना जा सकता है। (We cannot allow a minority to place a veto on the advance of the majority)

कैबिनेट मिशन २३ मार्च को करांची तथा एक दिन पञ्चात् दिल्ली पहुँचा। उन्होंने वाइसराय तथा प्रान्तों के बवनेरों में मिलने के पञ्चात् भारतीय नेताओं से वार्तालाप की। एक महीने में उन्होंने १८२ बैठकों में ४७२ नेताओं से मृदाकात की परन्तु फल कुछ न निकला। फिर कांग्रेस तथा लीग का संयुक्त सम्मेलन शिमला में बुलाया गया (५ मई)। परन्तु इसमें भी कोई समझौता न हो सका।

इसके पश्चात् १६ मई १९४६ को कैबिनेट मिशन ने एक योजना भारतीय नेताओं के सामने रखी। इसमें यह कहा गया था कि—

(१) कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारत के राजनैतिक दलों में समझौता करके भारत की स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सहायता करना था और इस दृष्टि से मिशन ने भरमक कोशिश की, परन्तु इसमें सफलता प्राप्त न हो सकी।

(२) मुस्लिम लीग भारत के विभाजन पर दृढ़ है और इसलिए पाकिस्तान की माँग रखती है। लीग के अनुसार इसके दो भाग होंगे : एक तो उत्तर-पश्चिम में, जिसमें पंजाब, सिंध, ब्रिटिश बल्खिस्तान तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त होंगे। दूसरा भाग उत्तर-पूर्व में होगा, जिसमें बंगाल तथा आसाम होंगे। परन्तु इन भागों में गैर मुसलमानों की संख्या इतनी अधिक है कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उत्तर-पश्चिमी भाग में ३८ प्रतिशत तथा उत्तर-पूर्वी भाग में ४८ प्रतिशत से कुछ अधिक गैर मुसलमान होंगे। अगर इन दो भागों में केवल उन्हीं क्षेत्रों को पाकिस्तान में रखा जावे जिनमें कि मुसलमानों का बहुमत है तो वह भी ठीक नहीं होगा। उन प्रान्तों की जनता का एक बड़ा भाग ऐसे विभाजन के पक्ष में नहीं है।

इसके अतिरिक्त कई आवश्यक सामनीय, आर्थिक तथा नैतिक प्रश्न भी देश के विभाजन के विरुद्ध हैं।

(३) कैबिनेट मिशन कांग्रेस की योजना से भी सहमत नहीं था। योजना थी कि प्रान्तों को पूर्ण स्वायत्त शासन का अधिकार हो और केन्द्र के पास केवल तीन विषय हों—परराष्ट्रनीति, वायव्यात तथा रक्षा। इसके अतिरिक्त अगर कोई प्रान्त चाहे तो वह कुछ अन्य विषय भी केन्द्र को माँग सकता था। परन्तु इसमें कोई बाध्यता नहीं थी। दस योजना को मिशन ने कई प्रकार की कठिनाइयों से पूर्ण कहा।



(४) दशो राज्या की समस्या का भी मिशन ने अध्ययन किया था तथा इस परिणाम पर पहुँचा कि सर्वोच्चाधिकार (Paramountcy) नई स्थिति में न तो सम्राट् के पास रह सकता था और न भारत की नई सरकार का परिचित किया जा सकता था।

इन कारणों से मिशन ने नए विधान के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये —

(अ) एक अखिल भारतीय मध्य जिनमें ब्रिटिश भारत तथा दशो राज्या दोनों सम्मिलित हों। हाना चाहिए। इनके अधीन पर राष्ट्र-नीति रक्षा तथा यातायात विषय रहने चाहिये तथा इस अपने व्यय के लिए धन उगाहने का अधिकार होना चाहिए।

(ब) मध्य में एक कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका हानी चाहिये जिनमें कि ब्रिटिश भारत तथा दशो राज्या के प्रतिनिधि हाने चाहिये। अगर व्यवस्थापिका में कोई बड़ा साम्प्रदायिक प्रश्न प्रस्तुत हो तो उसके निणय के लिये दो प्रमुख सम्प्रदायों के उपस्थिति प्रतिनिधियों का अलग अलग तथा समस्त उपस्थित सदस्यों का बहुमत हाना चाहिए।

(स) मध्य विषयों के अतिरिक्त अथवा सब विषय तथा शेष अधिकार प्रान्तों का हाने चाहिये।

(द) दशो राज्या का केन्द्र का दिये गये विषयों के अतिरिक्त अथवा सब विषयों पर अधिकार हाना चाहिये।

(ध) प्रान्तों को अपने समूह बनाने का अधिकार हाना चाहिये। प्रत्येक समूह की अपने कार्यकारिणी तथा व्यवस्थापिका होगी।

(ह) विधान में यह धारा हानी चाहिए कि प्रत्येक प्रान्त अपने अपने धारा-सभा के बहुमत हाने पर प्रथम दम बप पश्चात् तथा फिर प्रत्येक दम बप बाद, विधान की धाराओं पर पुनर्विचार करने का कह सकता है।

कॉन्फिरेट मिशन ने विधान निमात्री सभा बनाने के लिये भी सुझाव दिये। इस सभा का चुनाव प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं द्वारा पृथक् निर्वाचन मिष्ठान्त के अनुसार सुझाया गया था।

इस योजना में कई दोष थे। सबसे प्रथम तो यह था कि केन्द्रीय सरकार का केवल तीन विषयों पर ही अधिकार दिया गया था। इस प्रकार एक शक्तिहीन केन्द्र की व्यवस्था की गई थी। दूसरा दोष यह था कि प्रान्तों को अपने समूह

यनान का अधिकार दिया गया था। इसका उद्देश्य मुस्लिम लीग को मृग करने का था।

इस दीर्घकालीन प्रोजेक्ट के अतिरिक्त कॅबिनेट मिशन ने एक अन्तर्कालीन सरकार बनाने के लिये भी मुझाव रखा था। इसी को कार्यरूप में परिणत करने के लिये १६ जून १९४६ को एक घोषणा की गई। इसके अनुसार १४ सदस्यों की एक अन्तर्कालीन सरकार का प्रस्ताव रखा गया जिसमें ६ काँग्रेस के, ५ मुस्लिम लीग के तथा ३ अल्पसंख्यकों के सदस्य होंगे। लीग ने इसको स्वीकार किया, परन्तु काँग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। काँग्रेस की अस्वीकृति के कारण यह सरकार नहीं बनाई गई। काँग्रेस की अस्वीकृति का कारण यह था कि लीग इस बात को मानने को तैयार न हुई कि काँग्रेस अपने सदस्यों में किसी मुसलमान को भी रखे।

**विधाननिर्मात्री सभा का चुनाव तथा अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना**—जुलाई में विधान निर्मात्री सभा के लिए चुनाव के फलस्वरूप काँग्रेस को २०५ सीटें मुस्लिम लीग को ७३ सीटें तथा स्वतन्त्र उम्मीदवारों को १८ सीटें प्राप्त हुईं। देशी-राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं हुआ।

इसके पश्चात् वाइसरॉय ने ५० बैठक में अन्तर्कालीन-सरकार बनाने को कहा। एक १२ सदस्यों की सरकार बनी मन् (१९४६)। इसमें ५ हिन्दू, ३ मुसलमान, १ हरिजन, १ पारसी, १ सिख, तथा १ ईसाई थे। लीग ने इसके विरोध स्वरूप देश भर में टाईरेट-एवसान-डे मनाया। इसके फलस्वरूप स्थान स्थान पर साम्प्रदायिक दंगे हुए। अन्त में, अक्टूबर माह में लीग ने या सरकार में प्रवेश किया। अन्तर्कालीन सरकार के तीन सदस्यों को हटाना पड़ा और उनके स्थान पर लीग के ५ सदस्य नियुक्त हुए।

**लीग का असहयोग तथा १६४७ का स्वतन्त्रता कानून**—अन्तर्कालीन सरकार में लीग काँग्रेस के साथ सहयोगपूर्वक काम करने के लिए नहीं आई थी। लीग के सदस्यों का काँग्रेस के साथ एक कॅबिनेट की तरह काम करना उद्देश्य नहीं था। श्री जिन्ना के लिये अन्तर्कालीन-सरकार केवल वाइसरॉय कोमिल थी उसमें अधिक कुछ नहीं। लीग देश में पाकिस्तान पाने के लिये अपनी कार्य-वाही करती रही। लीग ने यह भी कह दिया कि उनके सदस्य विधान-निर्मात्री सभा में भाग नहीं लेंगे। क्योंकि लीग के अनुसार एक के स्थान पर दो विधान-निर्मात्री सभाओं की नियुक्ति होनी चाहिये थी।

ब्रिटिश कैबिनेट ने वाइसराय प० नेहरू मरदार पटेल, श्री जिन्ना तथा श्री लियासन अली खा का लन्दन बुलाया। मरदार पटेल न जा सके। प० नेहरू के साथ मरदार बलदेव सिंह गये। इस कार्यक्रम का फल यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने अपने बसतव्य में यह कहा कि प्रान्ता का समझा में सम्मिलित होने तथा विधान बनाने का स्वतन्त्रता नहीं होगी। उनके विधान का निर्णय समूह द्वारा ही किया जावेगा। यह लीग की विजय थी। इससे अतिरिक्त यह भी कहा गया कि अगर कोई दल विधान निर्मात्री सभा में भाग नहीं लेगा तो उसकी श्रुतपुस्थिति में बना विधान उसके ऊपर बाध्य नहीं होगा। यह भी लीग के पक्ष में था।

२० फरवरी १९४७ का ब्रिटिश प्रान्त मन्त्री ने एक घोषणा की इसमें यह कहा गया कि जून १९४८ तक ब्रिटिश सरकार भारत में सत्ता भारतीयों के ही हाथों में सौंप देगी। परन्तु घोषणा में यह भाषा तीर पर नहीं कहा गया कि भारत एक ही रहेगा अर्थात् इसका विभाजन किया जावेगा। इसी दिन यह भी ऐलान किया गया कि लाहौर पैबल के स्थान पर नई माउन्टबैटन भारत के नये वाइसराय नियुक्त होंगे।

यह वाइसराय ने भारत में आए गार्वाजी तथा श्री जिन्ना से विचार-विनिमय किया। इससे यह तब स्पष्ट हो गया कि मुस्लिम लीग बिना पाकिस्तान के मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए दस का विभाजन आवश्यक हो गया। परन्तु लीग का यह स्वाकार करना बड़ा कि उत्तर-पश्चिमी प्रदेश में वे क्षेत्र जिनमें हिन्दू बहुमत हैं पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। इस प्रकार दोना दला की सम्मति प्राप्त कर, माउन्टबैटन ने ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति से ३ जून १९४७ का योजना प्रस्तुत की। यह योजना महत्वपूर्ण है।

शर्तों में, इस योजना का अन्तर्गत यह था कि भारत के दो भाग कर दिये जायें। दूसरे शब्दों में लीग की मांग मान ली गई। ये भाग क्रमशः भारत तथा पाकिस्तान थे। पूर्वी पाकिस्तान में पूरा बंगाल और न पूरा असम ही रहा। बंगाल के वे जिले जिनमें मुसलमान बहुमत था अर्थात् पूर्वी बंगाल तथा असम के सिलहट जिले का अधिकांश भाग पूर्वी पाकिस्तान में रहे। पश्चिम में पाकिस्तान

× १ मुस्लिम बहुमत जिले निम्नलिखित हैं — चटगांव नोआखली नियरा, राकमगं, ढाका, फरीदपुर मेमनगिह जैमोर, मुंशिदाबाद, नदिया, बांगरा, दीनाजपुर, मातदा, पाना, राजशाही, रंगपुर।

में पश्चिमोन्मज्जा<sup>१</sup> सिन्ध, बलूचिस्तान तथा उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त रहे। बंगाल तथा पंजाब ने वहाँ की धारा-नमाओं ने प्रान्त के विभाजन के पक्ष में क्रमशः २० जून तथा २३ जून को मत दिया। सिन्ध की धारा-नमा ने पाकिस्तान में सम्मिलित होने के पक्ष में २६ जून को मत दिया। बंगाल के मिरहट जिले में जनता ने पाकिस्तान में रहने के पक्ष में मत दिया। उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त में भी पाकिस्तान के पक्ष में ही जनमत रहा। कांग्रेस ने वहाँ इन मत का बहिष्कार किया था क्योंकि कांग्रेस के मतदान प्रश्न यह होना था कि इन प्रान्त की जनता पाकिस्तान में रहना चाहती है अथवा स्वतंत्र पठानिस्तान बनाना चाहती है। परन्तु मतदानियों के सम्मुख यह प्रश्न रखा गया कि वे पाकिस्तान में रहना चाहते हैं अथवा हिन्दुस्तान में। बलूचिस्तान ने भी पाकिस्तान में ही रहने का निश्चय किया।

इन योजना में देशी राज्य दिपयक नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

इन योजना को कांग्रेस, मींग तथा मिर्खों ने स्वीकार कर लिया। ४ जुलाई १९४७ को ब्रिटिश पार्लियामेंट में माउन्टबेटेन योजना को बार्नेलन में परिष्कृत करने के लिए एक बिल पेश किया गया। यह बिल २८ जुलाई को पार हुआ। इसमें निम्नलिखित मुख्य बातें थी—

(१) १५ अगस्त १९४७ ने दो नये उपनिवेश—भारत तथा पाकिस्तान का जन्म होगा।

(२) इन उपनिवेशों को यह अधिकार दिया गया कि वे ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल में रहे अथवा अपने सम्बन्ध-विक्षेप कर दें।

(३) जब तक नया विधान नहीं बन जाना इन उपनिवेशों का शासन १९३५ के ऐक्ट के अनुसार होगा। परन्तु इस ऐक्ट में कुछ परिष्कार कर दिए गये। गवर्नर-जनरल तथा प्रान्तीय गवर्नरों के विरोधापिकाओं का पक्ष हो गया तथा वे वैधानिक शासन बना दिये गये, जिन्हें अपने मन्त्रियों की राय से शासन करना होगा। ये मन्त्री व्यसम्पादित के प्रति उत्तरदायी होंगे।

१. मुस्लिम बहुमत जिले—गुजरातवादा, गुरुदामपुर, राहौर, शेखपुरा, म्यालकोट, झटक, गुजरात, जेहलम, मिनावली, रावलपिंडी, रेवागढ़ी खां, मन, कामलपुर, मिटगुमरी, मुल्तान तथा मुजफ्फरगंज।

(६) प्रत्येक उपनिवेश में मखानिक डेटा का अना गवर्नर-जनरल मखाना बनने का अधिकार दिया गया। भारत में माउन्टेड हो रहा। पाकिस्तान में जिन्ना प्रथम गवर्नर-जनरल हुए।

(५) देनी राज्या के मखान में यह कहा गया कि मखान के सर्वोच्च अधिकारों का अन्त हो गया है तथा के किमी भी उपनिवेश में मखान होने को मखान है।

१७ अगस्त १९६७ का भारत तथा पाकिस्तान, इन दो उपनिवेशों का जन्म हुआ। भारत की गणधानी दिल्ली रही तथा पाकिस्तान की राजधानी कराची बनाई गई। इस विभाजन के फलस्वरूप सरकार की समस्त मखान को जैम रेल, टाक, नार, पोज का मामान, कागमाने गिजव रैक का धन आदि, दो हिस्सा में बाँट दिया गया। परन्तु इस विभाजन के बाद भी हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य के फलस्वरूप, लावा निरपराध, बाक, बूढ़े युवा स्त्री, तथा पुत्र मीन के घाट उतारे गये। इस माप्रदायिक पाकिस्तान का जिनता भी कामा जाय उतना कम है। मखान की आँखा में हम गिर गये। इसका फल यह हुआ कि लावा हिन्दू तथा मुसलमानों को अपना घरवार छाटना पडा और सरकार के बास्त मरणाधिकारी की समस्या उठ खड़ी हुई, जो अभी तक पूरा प्रकार में हल नहीं हो सकी है।

विधान-निर्मात्री मखान ने भारत का तथा मखान बनाया तथा वह २६ जनवरी १९५७ में लागू कर दिया गया। इस निधि से भारत एक गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्र हो गया, परन्तु वह ब्रिटिश गण-मण्डल का मदस्य बना रहा।

### प्रश्न

(१) मन् १८५८ से मन् १९१९ तक भारत में मखानिक विकास का मखान में वर्णन कीजिये।

(२) मन् १९१९ के ऐक्ट की क्या प्रमुख विशेषताएँ थीं?

(३) मन् १९३५ के ऐक्ट के अनुसार भारत में शासन व्यवस्था का क्या रूप था?

(४) मन् १९३९ से मन् १९४७ तक ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत विभिन्न योजनाओं का मखान में वर्णन कीजिए।

## संविधान-निर्मात्रों सभा तथा इसका कार्य

**संविधान सभा** — संविधानों का बड़े दृष्टियों में वर्गीकरण किया गया है। कुछ संविधान ऐसे होते हैं जिनका निर्माण किसी निश्चित तिथि को हुआ है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी संविधान हैं जिनका निर्माण किसी निश्चित समय में न होकर जनता विधान द्वारा हुआ है। शान्त-विधान को बनाने में कई सदस्य लगती हैं। उदाहरणार्थ भारत के संविधान का एक निश्चित समय में निर्माण हुआ है। परन्तु इंग्लैंड का शान्त-विधान कई सदस्यों के विकास का फल है। अमेरिका का संविधान भी एक निश्चित समय में निर्मित हुआ था। इन दृष्टि में संविधान निर्मित तथा निर्मित कहलाते हैं। नाधारणतः यह कहा जा सकता है कि विधायन-विधान अनिवार्य होता है तथा निमित्त-विधान निमित्त होता है।

निमित्त-विधान बड़े प्रकार में बन सकता है। यह जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाया जा सकता है या राजा और उनके परामर्शदाताओं द्वारा। नाथो-मथः धर्मरूपिका भी विधान का निर्माण कर सकती है। प्रथम महायुद्ध के पूर्व आस्ट्रेलिया का विधान इसी प्रकार बनाया गया था। विधान को बनाने के लिये एक विशेष संविधान सभा का प्रावधान भी किया जा सकता है। उदाहरणार्थ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का विधान, या हंगरी देश का संविधान इसी प्रकार की संविधान सभाओं द्वारा निर्मित हुए हैं।

संविधान-सभा में तात्पर्य उन विशेष सभा में है जो कि संविधान के निर्माण हेतु बनाई जाती हैं। यह सभा या तो जनता द्वारा निर्वाचित होती है, या यह भी हो सकता है, कि यह किसी राजा, नानाग्राह अथवा मुख्य कार्यवाहियों द्वारा स्थापित हो। सर्वप्रथम, अमेरिकन स्वतन्त्रता युद्ध के पश्चात् उत्तरी अमेरिका के निवासियों ने अपने देश का संविधान बनाने के लिए एक ऐसी सभा बुलाई। इसके पश्चात् फ्रांस में राज्यक्रान्ति के बाद ऐसी सभा बुलाई गई। उन्नीसवीं शताब्दी में भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं। बीन्की शताब्दी में रूस का संविधान ऐसी ही सभा द्वारा बनाया गया। हमारा संविधान भी ऐसे ही बना है। हमारी संविधान-सभा के विषय में अग्रेष्ट बात यह है कि इसका जन्म विदेशी सरकार

ढाग बनाये हुये कानून के कारण हुआ। इसका निर्वाचन किस प्रकार होगा ? इसमें बित्तन मदद हमारे ' आदिवासी ब्रिटिश सरकार द्वारा ही निश्चय की गई थी।

अठारहवीं सताब्दी के उत्तरार्ध में प्रजातन्त्रवाद का विकास होना लगा और मजबूत जनता ने यह माँग रखनी आरम्भ की कि राज्य का कार्य जनता के प्रति-निधियों द्वारा ही चलाया जाय। इस कारण यह स्वाभाविक था कि सविधान भी जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित हो। इस पद्धति में यह लाभ है कि जनता का विश्वास रहता है कि सविधान में उसकी हिता की उपेक्षा नहीं की जावेगी। इसी कारण आधुनिक काल में मंत्र निरवृत्त शासन में मुक्ति पाने के पश्चात् जनता के प्रतिनिधियों द्वारा सविधान का निर्माण हुआ है। इन सब सविधानों में जनता के अधिकारों का ध्यान रखा गया है। अधिकतर सविधानों में मूल अधिकारों का ब्यवधान भी कर दिया गया है।

**भारत में सविधानसभा की माँग**—यद्यपि कांग्रेस का जन्म उत्प्रेमकी सताब्दी में ही हो गया तथा बीसवीं सताब्दी के आरम्भिक वर्षों में विदेशी शासन के विरुद्ध भारता तथा आन्दोलन बढ़ने लग गए थे और स्वराज्य की माँग उठने लगी थी। तथापि यह नितांत मंथ है कि गाँधीजी के भारत आगमन के पश्चात् ही स्वतन्त्रता आन्दोलन जन-आन्दोलन हुआ। गाँधी जी ने ही एक प्रकार से सर्वप्रथम सविधान सभा का विचार भी भारत को दिया। उस समय यह स्पष्ट नहीं था और कदाएँ एक संकेत मात्र था। सन् १९२२ में गाँधीजी ने कहा था कि भारतीय-विधान भारतीयों की इच्छा का फल होगा न कि विदेशी सरकार द्वारा दिया हुआ दान। इस प्रकार हम देखते हैं कि गाँधी जी का यह विचार आरम्भ में ही था भारत का विधान भारतीयों द्वारा ही बनाया जायगा। परन्तु इस विचार को गाँधीजी ने उस समय इससे अधिक स्पष्ट रूप में नहीं रखा। सन् १९२४ में ५० मोतीलाल नेहरू ने भी एक सविधान-सभा की माँग रखी थी। परन्तु यह कहने में कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि कई वर्षों तक इस प्रश्न पर ऊपर गभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया। सन् १९३६ में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें स्वतन्त्र भारत का विधान बनाने के लिये एक सविधान सभा की माँग रखी गई थी। सन् १९५३८ में जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि स्वतन्त्र भारत के सविधान का निर्माण जनता की जनता द्वारा ही होगा। इसके लिये उन्होंने यह सुझाया कि एक सवि-

1 The Congress stands for a genuine democratic State in India where political power has been transferred to the

धान सभा होनी चाहिये। इनका निर्वाचन जनता द्वारा वयस्क-मतदाताधिकार के सिद्धान्त के अनुसार होना चाहिये। सन् १९३९ में कांग्रेस की कार्यसमिति ने संविधान-सभा की मांग रखते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था।

ब्रिटिश सरकार का विचार उस समय भारत को स्वतन्त्र करने का नहीं था और न भारत में पूर्ण उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित करना ही। इसलिये संविधान सभा की माँग केवल माँग ही रही। परन्तु १९३९ में द्वितीय महायुद्ध का आरम्भ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारत की राय के उसे युद्ध में सम्मिलित कर दिया। देश में युद्ध के प्रति कोई उत्साह नहीं था। इस समय पूर्व में जापान ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध आरम्भ कर दिया। धर्मा इनके हाथ में निकल गया। ऐसे समय में भारत का हार्दिक सहयोग प्राप्त करने के लिये अंग्रेजी सरकार ने श्रम योजना प्रस्तुत की परन्तु इसने भारत को सन्तोष न हुआ। १९४२ के आन्दोलन के पश्चात् पुनः समझौते की चेष्टा की गई। इंग्लैंड में जब मजदूर दल की सरकार बनी तब वहाँ के नये प्रधान मंत्री ने इस बात को स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत की शासन व्यवस्था कैसी हो, इसका निर्णय वहाँ की जनता स्वयं करेगी। इसके पश्चात् ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत आया और इसकी वार्ताओं के फलस्वरूप संविधान सभा का जन्म हुआ।

कैबिनेट मिशन के संविधान सभा के उपर सुझाव.—कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना में यह तो स्वीकार किया कि समस्त जनता का अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिये यह सबसे अच्छा होता कि संविधान सभा का निर्वाचन वयस्क मतदाताधिकार के आधार पर हो। परन्तु इस प्रकार के निर्वाचन के पश्चात् संविधान सभा के निर्माण करने में बहुत समय लगता और इससे विधान के बनने में भी बहुत विलम्ब हो जाता। इस कारण कैबिनेट मिशन ने यह सुझाव रखा था कि संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतीय-व्यवस्थापिका सभा द्वारा हो।

इन दो कठिनाइयों के कारण कैबिनेट मिशन ने सुझाव रखा कि—

(१) प्रत्येक प्रान्त के सदस्यों की संख्या वहाँ की जनसंख्या के आधार पर निर्दिष्ट होगी। इसके लिए प्रति दस लाख व्यक्ति पीछे एक सदस्य दिया जायगा।

people as a whole and the Government is under their effective control. Such a State can come into existence only through a Constituent Assembly, elected by adult suffrage and having the power to determine finally the constitution of the country."



(२) इस प्रकार जो बुरा सदस्य सख्या होगी उसको विभिन्न सम्प्रदायो के बीच उनकी सख्या के अनुपात में बाँटा जावेगा।

(३) प्रत्येक सम्प्रदाय के प्रतिनिधि व्यवस्थापिका सभा में उसी सम्प्रदाय के सदस्या द्वारा निर्वाचित ह्य, जैसे हिन्दू प्रतिनिधि हिन्दू सदस्यो द्वारा, मुसलमान प्रतिनिधि मुसलमान सदस्यो द्वारा, आदि।

(४) इस चुनाव के लिये भारत में केवल तीन बडे सम्प्रदाय माने जायें साधारण—इसमें हिन्दू, ईसाई, पारसी, दलित-वर्ग आदि रखे जायें मुस्लिम तथा सिख।

(५) भारत के प्रान्ता को तीन भाग में बाँटा जाय। इसमें स 'क' भाग में वे प्रान्त हागे जिनमें हिन्दू-बहुमत होगा। 'ख' तथा 'ग' भाग में वे प्रान्त हागे जिनमें मुस्लिम बहुमत होगा।

इस योजना के अनुसार प्रत्येक भाग के सदस्यो की मख्या निम्नलिखित प्रकार से निर्दिष्ट की गई थी —

### 'क' भाग

प्रान्त	साधारण सदस्य	मुस्लिम सदस्य	योग
मद्रास	४५	४	४९
उम्बई	१९	२	२१
संयुक्त प्रान्त	४७	८	५५
बिहार	३१	५	३६
मध्य-प्रान्त	१६	१	१७
उड़ीसा	९	०	९
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
योग	१६७	२०	१८७

### 'ख' भाग

प्रान्त	साधारण सदस्य	मुस्लिम सदस्य	सिख	योग
पंजाब	८	१६	४	२८
सिंध	१	३	०	४
पश्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त	०	३	०	३
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
योग	९	२२	४	३५

'ग' भाग

प्रान्त	साधारण सदस्य	मुस्लिम सदस्य	योग
बंगाल	२७	३३	६०
धानाम	७	३	१०
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
योग	३४	३६	७०

इसके प्रतिरिक्त इस मुसताब में यह था कि 'क' भाग में कुछ सदस्य और जोड़े जायेंगे। एक बंग से तथा एक-एक दिल्ली और पंजाब से। इसी प्रकार 'ख' भाग में एक सदस्य ब्रिटिश बलूचिस्तान का जोड़ा जायगा। हमारे समस्त ब्रिटिश-भारत के सदस्यों की संख्या २९६ होगी।

जहाँ तक देशी राज्यों के सदस्यों का प्रश्न है उसके लिए यह मुसताब था कि उनके प्रतिनिधियों की संख्या १३ होगी। परन्तु इन सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होगा यह बाद को निश्चित होगा।

इस योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करने को वाइस-राय ने सब प्रान्तों से कहा। इस निर्वाचन के फलस्वरूप ब्रिटिश भारत से कांग्रेस को २०५, मुस्लिम लीग को ७३, तथा १८ स्थान स्वतन्त्र उम्मीदवारों को प्राप्त हुए। इन स्वतन्त्र उम्मीदवारों में ११ हिन्दू, ४ सिख तथा ३ मुसलमान थे। देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन नहीं हुआ।

इस संविधान-सभा में लीग के सदस्यों ने भाग नहीं लिया। क्योंकि लीग के अनुसार हिन्दू तथा मुसलमान दो राष्ट्र थे। इन दो राष्ट्रों के लिए यह भाव-द्वक था कि दो संविधान सभाएँ होनी चाहिए न कि एक।

१५ जुलाई १९४७ का ऐक्ट :—इस ऐक्ट द्वारा भारत का विभाजन कर दिया गया तथा दो स्वतन्त्र राष्ट्रों का जन्म हुआ—भारत तथा पाकिस्तान। इन दो देशों में भलग भलग संविधान सभाओं का निर्माण हुआ। पाकिस्तान के निर्माण में भारत की संविधान सभा के सभ्य में कुछ बदलाव हो गये। इसके सदस्यों की संख्या ३१० ही रही। इनमें से २३१ ब्रिटिश भारत तथा दोष ७९ राज्यों के सदस्य थे। दो सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण संविधान सभा के कार्य में केवल ३०८ सदस्यों ने ही सक्रिय भाग लिया।

१५ जुलाई १९४७ के ऐक्ट में यह था कि १५ अगस्त १९४७ को भारत तथा पाकिस्तान स्वतन्त्र उपनिवेश हो जायेंगे। इसके फलस्वरूप उपर्युक्त विधि

का भारत की सविधान सभा एक स्वतन्त्र सविधान सभा (Sovereign Constituent Assembly) हो गई। यहाँ पर यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार निर्मित सविधान सभा स्वतन्त्र (Sovereign) नहीं थी। क्योंकि इस योजना के अनुसार जो सविधान इस सभा द्वारा बनाया जाता उसके लागू होने के पहले उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट की स्वीकृति प्राप्त करनी होती। परन्तु १५ अगस्त १९४७ को यह बन्धन दूर हो गया।

**सविधान सभा का कार्य**—इस सभा की प्रथम बैठक ९ दिसम्बर १९४६ को हुई। इस बैठक में डा० सच्चिदानन्द सिन्हा अस्थायी सभापति चुने गये। ११ दिसम्बर को डा० राजेन्द्र प्रसाद सविधान-सभा के स्थायी सभापति चुने गये। अपने भाषण में डा० राजेन्द्र प्रसाद ने भारत में एक ऐसे समाज की स्थापना पर जोर दिया जिसमें विध्वंस न हो। ५० महक ने सविधान-सभा में एक प्रस्ताव रखा जिसमें वि. इसके उद्देश्य स्पष्ट कर दिए गये थे। इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि भारत एक स्वतन्त्र राज्य होगा। यह एक सत्य होगा। इस सत्य के प्रदेशों को वे सब अधिकार दिए जायेंगे जो कि सत्य को नहीं मिलेंगे।<sup>1</sup> इस सत्य में समस्त शक्ति का स्रोत जनता होगी। यहाँ के नागरिकों को कई अधिकार दिये जायेंगे, जैसे समता का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार, आदि। इसके साथ-साथ यह भी कहा गया था कि अल्पसंख्यक, पिछड़ी हुई जातियों तथा कबायली क्षेत्र के निवासियों के हितों की रक्षा की जावेगी। यह प्रस्ताव २२ जनवरी १९४७ को स्वीकृत हुआ।

सविधान सभा ने कई समितियाँ स्थापित कीं। सरदार पटेल की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों के ऊपर परामर्श देने के लिए एक समिति नियुक्ति की गई। इस समिति के नीचे चार उपसमितियाँ नियुक्त की गईं। इसका कार्य

---

1 इस प्रस्ताव में कहा गया था कि The territories shall possess and retain the status of autonomous units together with residuary powers ” परन्तु सविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ सत्य को दी गई हैं न कि प्रदेशों को। यह परिवर्तन देश के विभाजन के कारण आवश्यक समझा गया।

प्रत्येक स्थानों, आदिवासियों, आदि की समस्या पर परामर्श देना था। इन्हीं में से एक समिति नागरिकों के मूल अधिकारों के लिए स्थापित की गई।<sup>1</sup>

संविधान-सभा ने एक समिति विधान का मसविदा (शालूप प्रपत्रा draft) बनाने के लिए २९ अगस्त १९४७ को बनाई। इसमें ८ सदस्य थे।

- (१) डा० ब्रम्हदेकर, सभापति
- (२) श्री गोपाल स्वामी भायगर
- (३) श्री अल्लादी कृष्ण स्वामी भायगर
- (४) श्री कन्हैया लाल एम० मुन्शी
- (५) श्री एस० एम० साभाडुल्ला
- (६) श्री माधवराव
- (७) श्री बी० एल० मिश्र
- (८) श्री डी० पी० खेतान

इस समिति ने जो मसविदा प्रस्तुत किया उसमें ३१५ धाराएँ और ८ अनुसूचियाँ थीं। यह मसविदा ५ नवम्बर १९४८ को संविधान-सभा के सम्मुख रखा गया। संविधान-सभा ने इस पर विचार करके २६ नवम्बर १९४९ को संविधान को पास किया। इस अन्तिम रूप में स्वीकृत संविधान में ३९५ धाराएँ तथा ८ अनुसूचियाँ हैं। यह विधान २६ जनवरी १९४९ से लागू हुआ। परन्तु कुछ धाराएँ २६ नवम्बर १९४९ से लागू हो गई थीं। उस दिन भारत-उपनिवेश सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न लोकतन्त्रात्मक-गणराज्य हो गया। परन्तु यह ब्रिटिश-राष्ट्र-मण्डल का सदस्य बना रहा।

#### १. कुछ मुख्य समितियों के नाम :—

- (१) Union Constitution Committee.
- (२) Union Powers Committee.
- (३) The Provincial Constitution Committee.
- (४) Advisory Committee on Minorities.

इसके अन्तर्गत चार उपसमितियाँ थीं—

अ—Minorities Sub-Committee.

ब—Fundamental Rights Sub-Committee.

स—North East Tribal and Excluded Area Sub-Committee.

द—Tribal and Excluded Areas Sub-Committee.

सविधान के निर्माण में २ वर्ष ११ महीने १८ दिन का समय लगा। अमरीका का विधान बनने में ४ मास का समय, कनाडा का २ वर्ष ५ महीने, आस्ट्रेलिया का ९ वर्ष तथा दक्षिण अफ्रीका का १ वर्ष का समय लगा था। भारतीय सविधान सभा ने ६,३९६,७२९ रुपये व्यय किये।

### प्रश्न

(१) सविधान सभा से आप क्या समझते हैं? भारत में सविधान सभा की माँग क्यों तथा कैसे प्रारम्भ हुई?

(२) भारतीय सविधान सभा की उत्पत्ति, संगठन तथा कार्य पर एक छोटा निबन्ध लिखिए।

## भारत के संविधान की विशेषताएँ

**संविधान के स्रोत :—**प्रत्येक देश के संविधान की कुछ विशेषताएँ होती हैं। वे उस देश के विशेष-परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होती हैं। हमारे संविधान के विषय में यह कहा जाता है कि संसार के सब मुख्य संविधानों के गुणों को यहाँ एकत्रित कर दिया है। इन्हें जो कुछ भी समता हो, इतना स्पष्ट है कि भारत के संविधान के निर्माण का कार्य जिन लोगों को सौंपा गया था उन्होंने कई देशों के संविधानों से इसके निर्माण में सहायता ली है। इन प्रकार हमारे संविधान में अन्य देशों के संविधानों का प्रभाव है। एक लेखक के अनुसार 'यह एक अनूठा संविधान है जिसके कि कोई स्रोत है'।<sup>1</sup>

इंग्लैंड की तरह, इन संविधान द्वारा भारत में संसद-प्रणाली की सरकार (Parliamentary Form of Government) स्थापित की गई है तथा केन्द्र को शक्तिशाली बनाया गया है। इसके लिये अवशिष्ट अधिकार (Residuary powers) केन्द्र को दिये हैं। समान राष्ट्र अमेरिका की तरह संविधान में नागरिक के मूल-अधिकारों का वर्णन है तथा एक स्वतन्त्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। आयरलैंड के संविधान का प्रभाव भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। वहाँ की तरह हमारे संविधान में राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रखा गया है तथा राज्यपरिषद् और विधान परिषदों में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का प्रवन्ध रखा गया है।

हमारे संविधान में १९३५ के ऐक्ट का भी बहुत अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होगा। यह कहने में असुविधा नहीं होगी कि बहुत सी बातों के लिये १९३५ का ऐक्ट ही नये संविधान का स्रोत है। एक लेखक के अनुसार संविधान में करीबन ७५ प्रतिशत बातें १९३५ के ऐक्ट से ली गई हैं।<sup>2</sup> उदाहरणार्थ केन्द्र तथा

1. "It is a unique document drawn from many sources."

2. Basu : The Constitution of India, p. 4.

Jennings says, "The constitution derives directly from the Government of India Act, 1935, from which in fact many of

राज्या के बीच वैधानिक सम्बन्ध निर्दिष्ट करने वाली धाराओं में अथवा राष्ट्र-पति को मस्टवाउ म अमाउगण अधिकार देने वाली धाराओं में १९३५ के ऐक्ट का प्रभाव स्पष्ट है। इसी प्रकार मय तथा राज्या के बीच अधिकार विभाजन के लिए जा मधीय राज्या की तथा ममवर्ती सूचियाँ हैं व भी इसी एक्ट पर आधारित हैं। इसके अतिरिक्त १९३५ के ऐक्ट का उद्देश्य भी भारत में समदम्यद्वि की स्थापना करना था न कि अध्यात्मिक पद्धति की। कुछ मात्रा तक यह स्वाभाविक था कि १९३५ के ऐक्ट का इतना अधिक प्रभाव हो। क्योंकि जिन मनुष्या का संविधान का प्रारूप बनाने का काम सोपा गया था उनका इस ऐक्ट का अनुभव था। इससे साथ-साथ प्रशासनात्मक प्रक्रिया की दृष्टि से भी १९३५ के ऐक्ट से बहुत कुछ लिया गया। क्योंकि अगर इससे पूर्णतया भिन्न संविधान बनाया जाता तो ब्रिटिश का म म प्रशासनिक प्रबंध चला आ रहा था उसमें बहुत कुछ हेर-फेर करना होता।

(१) लिखित तथा निर्मित विधान—हमारा संविधान लिखित तथा निर्मित है। हम पहले अध्याय में बतला चुके हैं कि इस प्रकार के संविधान में क्या तात्पर्य है। संक्षेप में लिखित संविधान वह संविधान है जिसके कि अधिकतर भाग लिखित हैं। निर्मित संविधान वह है जिसका कि एक निश्चित समय में निर्माण किया गया हो। इस दृष्टि में भारतीय संविधान इंग्लैंड के संविधान से पूर्णतया भिन्न है। क्योंकि इंग्लैंड का संविधान अलिखित तथा विकसित संविधान का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण कहा जाता है। इंग्लैंड का संविधान इतिहास का फल है। इसका प्रमाण विमान हुआ है। एक समय यह राजतन्त्रीय था परन्तु अब यह प्रजातन्त्रीय है।

परार्थ में प्रत्येक संविधान कुछ मात्रा तक लिखित तथा कुछ मात्रा तक अलिखित होता है। इसी प्रकार प्रत्येक संविधान कुछ मात्रा तक निर्मित तथा कुछ मात्रा तक विकसित होता है। इंग्लैंड के संविधान में कई बातें लिखित हैं। उदाहरणार्थ, १८३२ का सुधार विध, अथवा १९११ का पार्लियामेंट ऐक्ट। समस्त राष्ट्र अमेरिका के विधान में जो कि लिखित तथा निर्मित हैं कई बातें अलिखित हैं तथा विकास के फलस्वरूप हैं। भारत के संविधान में भी कालांतर में कई बातें ऐसी आ जावेंगी जिनका कि विधान में कहीं भी उल्लेख नहीं

is provisions are copied textually" Some characteristics of the Indian Constitution, p 17

Also see Malhotra, The Constitution of India, p 1 and Ramvasan, Ibid p 143

मिलेगा। ऐसा प्रत्येक लिखित विधान में हुआ है। अमेरिका के विधान में केवल ४००० शब्द हैं। इसको भाषे-घटे में पढ़ा जा सकता है। परन्तु केवल इसकी पढ़ने से ही अमेरिका का शासनतन्त्र समझ में नहीं आ सकता है।<sup>१</sup>

(२) विशाल लेख्य — भारत का संविधान एक विशाल लेख्य (document) है। इस संविधान में ३९५ धाराएँ तथा ८ अनुसूचियाँ हैं। अगर हम इसकी संसार के अन्य लिखित संविधानों से तुलना करें तो हम देखेंगे कि यह संसार के समस्त लिखित संविधानों में सबसे बड़ा है। संयुक्त-राष्ट्र-अमेरिका के संविधान में केवल ७ धाराएँ हैं, आस्ट्रेलिया के संविधान में १२० धाराएँ हैं। कनाडा के संविधान में १४७ धाराएँ हैं। परन्तु १९३५ के ऐक्ट से यह छोटा है। उसमें ४५१ धाराएँ (clauses) तथा १५ अनुसूचियाँ थीं। यह कहना असत्य नहीं होगा कि नये विधान की विशालता बहुत कुछ मात्रा तक १९३५ के ऐक्ट के प्रभाव के फलस्वरूप भी है। ऐसा प्रतीत होता है कि विधान निर्माताओं ने इस ऐक्ट को ही मूल्यतः ध्यान में रखकर नये संविधान का निर्माण किया है।

भारतीय संविधान में बहुत सी ऐसी बातों का समावेश कर दिया गया है जो कि दपार्श्व में शासन-सम्बन्धी (administrative) हैं तथा जिनका संविधान में वर्णन नहीं होना चाहिए था।<sup>२</sup> प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान डा० जेनिंग्स (Jennings) ने भी इसी प्रकार के विचार प्रकट किये हैं।<sup>३</sup> अगर इस

१. अमेरिका के विधान के विषय में एक लेखक लिखता है:—

"A model of conciseness it certainly is, for there are only 4,000 words in it, occupying ten or twelve pages of print, which can be read in half an hour. But let no one make the error of supposing that these ten or twelve pages can be understood merely by reading them, or that they contain all the constitutional rules which govern the American People today."

Munro : The Government of the United States, p. 53.

२. "Many of these matters relate to the details of the administration, and strictly speaking, should have no place in a Constitution."—Dr. M. P. Sharma, The Government of the Indian Republic, p. 28.

३. "The constitution is long and complicated, because the Government of India Act, 1935, on which it was in large measure



प्रकार का ढाना का संविधान में बहुत अधिक समावेश कर दिया जावे तो विधान का लचीलापन बहुत मात्रा तक चला जाता है। यह उचित नहीं क्योंकि इसमें संविधान को प्रत्येक नयी परिस्थिति के हल करने में अनुविधा का सामना करना पड़ेगा।

संविधान में केवल सघ सरकार तथा इसके तीन प्रमुख तत्वों—कार्य, पालिका व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका—का ही वर्णन नहीं है अपितु सघ के अन्तर्गत विभिन्न राज्या तथा इनके विधान का भी वर्णन किया गया है। अमेरिका में संघीय राज्या को अपना विधान बनाने तथा बदलने का अधिकार है। परन्तु हमारे संविधान द्वारा यह अधिकार राज्या को नहीं दिया गया है। इसका कारण यह है कि सघ का रूप निश्चित करने में विधान निर्माताओं ने कनेडा के संविधान का अनुसरण किया न कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के। उनका उद्देश्य एक शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना करना था क्योंकि यह देश की एकता बनाये रखने के लिए आवश्यक था।

इसके अतिरिक्त संविधान में नागरिकता तथा नागरिक के मूल अधिकारों का वर्णन है। इन मूल अधिकारों के पदचात राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का भी वर्णन है। संविधान में संपत्ति, वित्त व्यापार निवाहन, अल्पसंख्यकों की स्थिति सरकारी सेवाएँ आदि का वर्णन किया गया है। इसके साथ-साथ अतर्कालीन व्यवस्था के लिए भी जो विशेष उपबन्ध हैं उनका संविधान में स्थान दिया गया है। इनमें से बहुत सी बातें ऐसी थी जिनका वर्णन संविधान में आवश्यक नहीं था तथा जिनके लिए भारतीय संसद साधारण विधि बना सकती थी।

प्रदान यह है कि इन सब बातों का संविधान में वर्णन क्या किया गया है। कुछ लेखकों का कहना है कि भारत की परिस्थिति ऐसी थी, तथा वहाँ ऐसी समस्याएँ थी कि इन सब बातों का संविधान में समावेश देश के ब्यापक हित में है। अगर नहीं होता तो हमें बहुत सी कठिनाइयाँ उठानी पड़ती। डा० अम्बेदेकर ने जो कि संविधान प्राल्प समिति के अध्यक्ष थे इन सब बातों को सम्बन्धी बनाना का संविधान में समावेश उचित बताया। उनके अनुसार भारत में

founded, was long and complicated That Act had to distribute powers, formerly exercised under the authority of the Government of India, among various Indian Agencies and therefore went into great detail often more appropriate to a written Constitution" Jennings and Young, Constitutional Law of the Commonwealth, p 364 (1957 ed) Also see Jennings' Some Characteristics of the Indian Const pp 13 14

प्रजातन्त्र की तर्हें इतनी मजबूत नहीं हैं कि व्यवस्थापिका को शासन के रूप में उपयोग निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया जावे। क्योंकि वह इनको उचित भाँति से नहीं करेगी।

(३) लोकतन्त्रात्मक संविधान — भारतीय नवविधान इस सिद्धान्त पर आधारित है कि राज्य की शक्ति का स्रोत जनता है। इनको नार्वेजिक संश्रुति (Popular Sovereignty) का निदान कहा जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार राजा अपना सरकार राज्य की भस्ती नहीं। वे तो केवल जनता के लोकर अपना प्रतिनिधि हैं। जनता उता जनता है। यह निदान यूरोप में आधुनिक काल में आरम्भ हुआ। इंग्लैंड में लोक में इसका आना मिलता है। फ्रांस में स्मो तथा फ्रेंच-क्रांतिकारियों ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया। अमेरिका का संविधान भी इसी सिद्धान्त पर आधारित है। भारतीय नवविधान की प्रस्तावना में यह बात स्पष्ट रूप में बही गई है कि जनता ही राज्य की शक्ति का स्रोत है। संघ में तथा राज्यों में नारी शक्ति जनता के नाम मानी गई है। जब पं० नेहरू ने संविधान-सभा के प्रथम अधिवेशन में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, उसमें भी यही कहा गया था कि जनता शक्ति का स्रोत जनता है। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर नवविधान की प्रस्तावना का निर्माण हुआ। इस प्रस्तावना में कहा गया है:—

हम, भारत के लोग, भारत की एक सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न-लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिये, तथा उसके समस्त नागरिकों को:—

सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक भ्रष्टाचार,

विचार, अनिष्पत्ति, विस्वास, धर्म

और उपासना की स्वतन्त्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिये तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की

एकता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता, बढ़ाने के लिए,

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख २६ नवम्बर

१९४९ ई० (मिति भाग्यदीप शुक्ला सप्तमी संवत् दो हजार विंशती) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने हैं।

१. "Democracy in India is only a top dressing on the Indian soil which is essentially undemocratic. In the circumstances it is wiser not to trust the legislatures to prescribe forms of administration. This is the justification for incorporating them in the Constitution."—Dr. Ambedkar.

इस प्रस्तावना में यह व्यक्त किया गया है कि संविधान का निर्माण भारत के लोग कर रहे हैं तथा इन्हीं की इच्छा राज्य की सर्वोपनि इच्छा होगी। जनता अगर चाहे तो विधान में परिवर्तन कर सकती है। दूसरे शब्दों में सत्ता का स्रोत जनता है। इसी के लिये कहा गया है कि भारत 'लोकतन्त्रात्मक' राज्य है। लोकतन्त्र (democracy) से तात्पर्य है कि राज्य का कार्य, जनता के हित में जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जावेगा तथा जब जनता समझेगी कि प्रतिनिधि उचित रूप से काम नहीं कर रहे हैं तो वह इनको हटाकर उनके स्थान में नये प्रतिनिधि नियुक्त करेगी। प्रतिनिधि जनता के स्वामी नहीं अपितु मेवक है। इसमें यह ग्रह लाना चाहिये कि लोकतन्त्रात्मक प्रणाली इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक को अपने हितों को पहचानने की शक्ति है एतदर्थ उसे अपनी स्वतन्त्र इच्छा के अनुसार काम करने की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। हमारे संविधान की प्रस्तावना बहुत कुछ अमेरिकन संविधान की प्रस्तावना से मिलती है उसमें भी कहा गया है कि हम संयुक्त राष्ट्र के लोग इस संविधान को निर्मित तथा स्थापित करते हैं।

अमेरिकन लेखक मनरो (Munro) लिखता है कि यह सत्य है कि अमेरिका की संविधान सभा के सदस्य न तो जनता द्वारा निर्वाचित हुए थे और न उनके द्वारा निर्मित विधान जनता के सम्मुख उमरी स्वीकृति प्राप्त करने को रखा गया। तथापि विधान में यह बात घोषित की गई है कि वह जनता की इच्छा का फल है तथा इस बात को सब मानते चले आ रहे हैं। इसी प्रकार भारतीय संविधान-सभा का निर्वाचन भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से तथा वयस्क मताधिकार के ऊपर नहीं हुआ। संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानमण्डलों द्वारा हुआ। इन विधान मण्डलों का निर्वाचन १९३५ के ऐक्ट के अनुसार हुआ था। इस ऐक्ट के अनुसार इन चुनावों में केवल १३ प्रतिशत भारतीयों को मत देने का अधिकार था। इस कारण कई आलोचकों का कहना है कि संविधान सभा सम्पूर्ण भारतीय जनता की नहीं, परन्तु इस १३ प्रतिशत की प्रतिनिधि थी। इसलिये इसे समस्त भारतीय जनता के नाम में संविधान बनाने का

1 "We, the people of the United States, in order to form a more perfect Union, establish, justice insure democratic tranquility, provide for the common defence, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America"

2 Munro - Government of the United States, p 54

कोई अधिकार नहीं था। और इसी कारण यद्यपि संविधान में लोकतन्त्र का नाम लिखा गया है परन्तु प्रामाण्य में यह विधान लोकतन्त्रात्मक नहीं है।

इस प्रालोचना के विरुद्ध यह तर्क दिया जाता है कि जिस समय संविधान सभा का निर्माण हुआ उस समय ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि इसका वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन हो सकता। एक तो इस प्रकार के निर्वाचन के लिए बहुत अधिक समय चाहिए था और उस समय इतना भयंकर नहीं था। दूसरे देश में हिन्दू-मुस्लिम समस्या ने इतना गम्भीर रूप धारण कर रखा था कि चुनाव करने का प्रयत्न देश भर को शान्ति को सतरे में डालना होता। तीसरे, देश में कांग्रेस का इतना अधिक प्रभाव था कि अगर वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन भी होता तो भी संविधान-सभा में कांग्रेस दल का ही निरान्त बहुमत होता।

संविधान की प्रस्तावना में लोकतन्त्रात्मक शासन पद्धति के प्रतिरिक्त यह भी कहा गया है कि भारत एक सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न (Sovereign) गणराज्य (Republic) है। सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न होने से यह तात्पर्य है कि भारत पूर्णतया स्वतन्त्र है। राज्य की प्रभुता के दो पहलू हैं—आन्तरिक तथा बाह्य। आन्तरिक रूप में प्रभुता से यह तात्पर्य है कि राज्य के अन्तर्गत राज्य की इच्छा ही सर्वोपरि है तथा अपने अन्दर रहने वाले ममस्त व्यक्तियों तथा संस्थाओं को अपनी इच्छा मानने को बाध्य कर सकता है। बाह्य रूप में प्रभुता से यह तात्पर्य है कि राज्य किसी अन्य देश के अधीन नहीं है और न किसी रूप में इसकी परराष्ट्र-नीति किसी अन्य राष्ट्र द्वारा निर्धारित या प्रभावित होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों पहलुओं में प्रभुता का अर्थ स्वतन्त्रता है। संविधान में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि भारत अपने आन्तरिक तथा बाह्य दोनों क्षेत्रों में पूर्णतया स्वतन्त्र है।

भारत गणराज्य है। गणराज्य का अर्थ है कि भारत, में शासन का रूप राजतन्त्र नहीं होगा। राजतन्त्र से तात्पर्य है कि जब देश का प्रधान वंशावली-

1. परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये जैसा कि एक विद्वान ने कहा है कि "In India as in every free country with a written constitution, there are constitutional limitations which restrict the sovereignty. The Constitution prescribes its limits; it is restricted by the fundamental rights in several respects, and is controlled or regulated by an independent judiciary in the larger interests of liberty."—Sri K. M. Munshi.

क्रम से कोई राजा है। गणराज्य की परिभाषा करते हुए गानेर लिखता है कि यह राज्य का वह रूप है जिनमें राज्य की सर्वोपरि-इच्छा एक मनुष्य के हाथ में न होकर कई मनुष्यों के हाथ में हो। भारत में संविधान द्वारा गणराज्य स्थापित किया गया है न कि राजतन्त्र। जनता के प्रतिनिधियों को समस्त शक्ति दी गई है। वैसे तो देश का प्रधान एक राष्ट्रपति रखा गया है परन्तु यह केवल नाम-मात्र का प्रधान है।

इसके अतिरिक्त भारत को हम गणराज्य एवं दूसरे अर्थ में भी वह सकते हैं। स्वयं लेखक ग्लेन्टली लिखता है कि गणराज्य वह है जहाँ शासन समस्त जनता के हित में होता है। इस दृष्टि में भी भारत गणराज्य है। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संविधान का उद्देश्य समस्त नागरिकों का उत्थान करना है। इसीलिए इसमें गण्य, स्वतन्त्रता तथा समता को आधार-भूत सिद्धान्तों के रूप में रखा गया है। इससे यह तात्पर्य है कि शासन किसी वग विशेष के हित में नहीं होगा। धनी तथा निर्धनो में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जावेगा। कानून प्रत्येक को समान दृष्टि से देखेगा। प्रत्येक शक्ति को बिना भेद के विराम के लिए समान अवसर दिये जायेंगे। सरकारी सेवाएँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए खुली हैं। गरीब से गरीब मनुष्य योग्यता होने पर ऊँचे पद पर पहुँच सकता है। इसी प्रकार सामाजिक क्षेत्र में भी कोई भेद-भाव नहीं रखा गया है। साम्प्रदायिकता, छुआ-छूत आदि के लिए संविधान में कोई स्थान नहीं है। स्त्री तथा पुरुषों को समान समता गया है। इसके साथ साथ वयस्क मताधिकार का सिद्धान्त भी माना गया है।

(४) सघात्मक सरकार तथा शक्तिशाली केन्द्र — संविधान द्वारा भारत में एक सघात्मक सरकार की स्थापना की गई है।<sup>1</sup> इस सघ की स्थापना कई स्वतन्त्र राज्यों के आपस में मिलकर रहने की इच्छा के फलस्वरूप नहीं हुई है, अपितु एक एकात्मक सरकार सघात्मक सरकार में परिवर्तित कर दी गई है। साधारणतः सघ स्वतन्त्र राज्यों के बीच एक समझौते के फलस्वरूप बनते हैं। इस दृष्टि से भारत-सघ अनूठा है।

भारत-सघ कई दृष्टियों से अन्य सघों से भिन्न है। संक्षेप में यह कह सकते हैं कि इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि केन्द्र को बहुत अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। इसका कारण यह था कि संविधान के निर्माताओं के सम्मुख देश की एकता को अक्षुण्ण रखने का प्रश्न था। इस एकता को अक्षुण्ण रखने के लिए उन्होंने सोचा कि एक शक्तिशाली केन्द्र आवश्यक है। यहाँ पर केन्द्र

1 विस्तृत वर्णन के लिए चौथा अध्याय देखिये।

के संविधान का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। यहाँ तक कि संघ (Union) शब्द ही ब्रिटिश नॉर्थ अटलांटिक ऐक्ट की प्रस्तावना में से लिया गया है। डा० ग्रन्थेदकर ने संविधान सभा में कहा कि संघ (Union) शब्द से यह तात्पर्य है कि संघ इकाइयों के बीच किसी प्रकार के समझौता का फल नहीं है तथा इन इकाइयों को संघ को त्यागने का अधिकार नहीं है। यह बात तो प्रस्तावना में ही स्पष्ट हो जाती है कि इकाइयों को संघ त्यागने का अधिकार नहीं है। क्योंकि उसमें यह कहा गया है कि संविधान की रचना समस्त भारत की जनता द्वारा की गई है। इसलिए किसी राज्य-विशेष के इसकी छोड़ने का प्रश्न उठता ही नहीं है।

क्योंकि संविधान द्वारा अत्यन्त शक्तिशाली केन्द्र वाले संघ की स्थापना की गई है, इसलिए भारत-संघ अन्य संघों से कई बातों में भिन्न है। इस पर पूरा प्रकाश तो भागे के अध्याय में डाला जायगा। यहाँ पर इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि :

( १ ) संविधान द्वारा अवशिष्ट अधिकार संघ को दिए गये हैं न कि राज्यों को।

( २ ) संविधान द्वारा समस्त देश के लिए एक ही नागरिकता रखी गई है न कि द्वैध। अर्थात् संघ और राज्यों की भलग नागरिकता नहीं है।

( ३ ) राज्यों को अपना विधान बनाने का अधिकार उसमें किसी प्रकार के परिवर्तन करने का अधिकार नहीं दिया गया है।

( ४ ) समस्त देश के लिए एक ही न्यायपालिका की स्थापना की गई है अर्थात् संघ और राज्यों की न्यायपालिका भलग-भलग नहीं है।

( ५ ) समस्त देश के लिए एक ही विधि (Law) की स्थापना की गई है।

( ६ ) संविधान द्वारा संघ तथा प्रदेशों के अधिकार विभाजनार्थ तीन सूचियों का निर्माण किया गया है—संघ-सूची, राज्य-सूची तथा समवर्ती-सूची। संघ-सूची में दिए गए विषयों में केवल संसद ही कानून बना सकता है। राज्य सूची के विषयों पर राज्यों के विधान-मण्डलों को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती-सूची के अन्तर्गत विषयों पर संसद तथा राज्यों के विधान-मण्डल दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। परन्तु यहाँ पर भी संघ संसद द्वारा निर्मित कानूनों को प्राथमिकता तथा प्रधानता दी गई है। कनेडा के विधान में भी इसी प्रकार तीन सूचियाँ हैं। संघ तथा इकाइयों के मध्य इस प्रकार विस्तार-पूर्वक अधिकार विभाजन का फल यह हुआ है कि संविधान में कानूनीपन (legalism) का अभाव है।

(३) मकट काग में राष्ट्रपति का अगाधारण अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगर राष्ट्रपति सव (आपति) की घोषणा कर दे ता सध के हाथ में इनन अधिसार धा जान है कि सध के स्थान में एर एनात्मर सगका स्थापित हा जायगी। कपारि एर अवसर पर राज्या का मविधान द्वारा प्रन्न अधिकार का अन्त हा जायगा। अय सभा में इय प्रकार की बाई व्यवस्था नही है। मे उपबध १०,३५ व एक् मलिये गय है।

इन मव विशेषताधा व होने व कारण भारत-मध का रवका न quasi federal पहा है।

(४) सामर पद्धति—यद्यपि भारत का प्रधान एर राष्ट्रपति है तथापि वहाँ की सरकार अध्यात्मर न हाकर सांघद-पद्धति का है।

भारतीय मविधान में यद्यपि राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है तथापि उमे अपन मन्त्रिधा के परामदा व अनुगार काम करना पड़ेगा। मन्त्रिपरिषद् के सदस्यो के लिए मन्त्र का सदस्य हाता आवश्यक है। मन्त्रिपरिषद् लोकसभा व प्रति मामूहिर रूप म उत्तरदायी है। यह तभी तब अपन पद पर रह सता है जब तब दूसरो लोक-मभा का विवाग प्राप्त है, अथवा इम पदत्याग करना पड़ेगा। इन मर कारण ता हा यन् कहा गया है कि भारतीय मविधान सांघदीय-पद्धति की सरकार की स्थापना करता है। परन्तु इमर साथ-साथ इममें कुछ बातें होती हैं ता नि सांघद-पद्धति में नही हानी चाहिय जंग—

(१) राष्ट्रपति अथवा राज्यपाठ द्वारा दिए हुए बिन्ही आदेशो के लिये यह मान्यव नही कि उनमें किसी मन्त्री द्वारा हस्तागर किय जावें।

(२) राष्ट्रपति या राज्यपाठ मन्त्र या विधान मन्त्र द्वारा पास किसी विन् को फिर म उनके विचाराध बापिम भेज सकत हैं। सांघदीय विधि का

1 'The Union is not strictly a federal polity but a quasi-federal polity with some vital and important elements of unitariness'—G N Joshi: The Constitution of India, p 34

K C Wheare says 'The new Constitution establishes, indeed, a system of government which is at most quasi federal, almost devolutionary in character, a unitary State with subsidiary federal features rather than a federal State with subsidiary unitary features'

2 सांघद पद्धति तथा अध्यात्मर पद्धति व रिय ग्रेव की पुस्तक नागरिक शास्त्र व आधार देखिये।

आधारभूत मिदान्त वैधानिक प्रधान का उत्तरदायित्वहीन होना है। परन्तु भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ऐसी नहीं है।

भारतीय विधान में नागरिक-मदति को इसलिए अपनाया गया है क्योंकि इसमें सरकार जनता के प्रांत भली प्रकार उत्तरदायी रहती है। दूसरे, क्योंकि भारत में ब्रिटिश काल में वैधानिक विकास अल्प-संसादीय-सरकार की तरफ ही हो रहा था। विद्वानों का यह मत है सांनदविधि अल्पसंसादीय पद्धति में अच्छी है। इस विषय में प्रो० लास्की का एक उद्धरण दिया जाता है :—

“सांनदविधि में कई लाभ हैं। कार्यकारिणी तभी तक पदाङ्क रह सकती है जब तक इसको व्यवस्थापिका का विश्वास प्राप्त है। इस प्रकार इसकी नीति में एक लचीलापन रहता है जिसके कारण कोई गति अवरोध नहीं होने पाता जैसा कि जब कभी राष्ट्रपति तथा कांग्रेस एक दूसरे से सहमत न हों, अमेरिका में हो जाता है। व्यवस्थापिका में कार्यकारिणी के सदस्यों की उपस्थिति इसे अपनी नीति को उचित प्रकार समझाने का अवसर देती है। यह इस प्रकार उन लोगों का ध्यान आकर्षित करती है तथा आलोचना को चुनती है जो कि इसके स्थान में पदाङ्क होना चाहते हैं। इस प्रकार यह उत्तरदायित्व की स्थापना करती है। यह व्यवस्थापिका को मनमाने कानून बनाने से रोकती है क्योंकि इसका शासन में भी प्रभाव रहता है। और दूसरी तरफ यह कार्यकारिणी को भी पतित होने से बचाती है जैसा बहुधा होता है जब कि एक मन्त्रिमण्डल की नीति यथार्थ में अपनी नहीं होती है। इस प्रकार यह व्यवस्था उन दो अंगों को संयोजित करती है जिनका मानस में घनिष्ठ सम्बन्ध अच्छे शासन के लिये आवश्यक है।”

(६) संशोधन की विधि.—प्रत्येक संघात्मक विधान अपरिवर्तनशील होता है। अपरिवर्तनशीलता ने यह तात्पर्य नहीं है कि यह कभी भी बदला नहीं जा सकता है। परन्तु इसका यह अर्थ है कि विधान में परिवर्तन एक विशेष विधि से ही हो सकता है। परिवर्तनशील विधान में तो व्यवस्थापिका ही विधान परिवर्तन करती है। परन्तु अपरिवर्तनशील विधान में साधारण कानून तथा वैधानिक कानूनों में अन्तर रहता है। इस कारण इसमें परिवर्तन के लिये एक विशेष सभा होती है। इसलिए यह कहा जाता है कि अपरिवर्तनशील विधान में परिवर्तन भासानी से नहीं होते हैं। परन्तु भारतीय संविधान में संशोधन की व्यवस्था सरल है। यह कहा जाता है कि संघात्मक सरकार में अपरिवर्तनशील विधान का होना आवश्यक है, अन्यथा सदा यह भय लगा रहेगा कि



नम्र-मरकार राज्या की सरकारों के अधिकारों को हलचल न कर जाय। दूसरे शब्दों में मध्यम रूप के बने रहने के कारण संविधान में परिवर्तनशीलता आवश्यक गुण माना गया है। यह कहा जा सकता है कि भारत का संविधान 'अपरिवर्तनशीलता तथा परिवर्तनशीलता का मेल है।

संविधान की उन धाराओं में, जो कि मध्य तथा राज्या के मध्य अधिकारों का विभाजन करती हैं किसी भी संशोधन के लिए यह आवश्यक है कि उनका भारतीय संसद तथा राज्य में अधिक राज्यों के विधान मण्डलों की स्वीकृति प्राप्त हो। परन्तु संविधान के अन्य भागों में किसी भी संशोधन के लिए केवल भारतीय संसद की स्वीकृति को ही आवश्यकता है। परन्तु यहाँ पर यह कह दिया गया है कि उस संशोधन को संसद के प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम दो तिहाई बहुमत प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार साधारण विधि रचना तथा संशोधन में केवल यही अन्तर रह जाता है कि साधारण विधि के लिए उपस्थित सदस्यों का बहुमत ही पर्याप्त है। परन्तु इन उपबंधों की मर्यादा अधिक नहीं है।<sup>1</sup> परन्तु भारतीय संविधान की कठोरता उसकी संशोधन विधि के कारण न होकर उसके आधार के के कारण है।<sup>2</sup>

(७) धर्म निरपेक्ष शासन की स्थापना — संविधान धर्म निरपेक्ष (Secular) शासन की स्थापना करता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य यह है कि राज्य का क्षेत्र तथा धर्म का क्षेत्र अलग अलग हैं। आधुनिक काल में पूर्व ऐसा नहीं होता था। प्रत्येक राज्य का अपना एक विशिष्ट धर्म होता था। उस धर्म के अनुयायियों को राज्य की ओर से कई सुविधाएँ प्रदान की जाती थी। परन्तु अन्य धर्मावलम्बियों को वे सब सुविधाएँ नहीं थी। बहुधा यह भी हुआ है कि अल्प धर्मावलम्बियों के विरुद्ध कानून बना दिए जाते थे।

1 विस्तृत वर्णन के लिये पृष्ठ ६४ देखिये

2 Jennings लिखता है—In a Constitution "the degree of rigidity depends upon two factors First it depends on the degree of difficulty in the amending process Secondly, it depends upon the content of the Constitution What makes the Indian Constitution so rigid is that, in addition to a somewhat complicated process of amendment it is so detailed and covers so vast a field of law that the problem of constitutional validity must often arise" Jennings—Some Characteristics of the Indian Constitution, pp 9-10 Also see p 66

यूरोप में कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेण्ट देशों में इस प्रकार के कई उदाहरण मिल जायेंगे। परन्तु आधुनिक काल में सर्वत्र इस बात को माना जाने लगा है कि धर्म का क्षेत्र तथा राज्य का क्षेत्र सर्वथा भिन्न-भिन्न है। यद्यपि हमारे संविधान में वही पर लौकिक (Secular) शब्द व्यवहृत नहीं हुआ है तथापि स्पष्ट है कि संविधान ऐसे राज्य की स्थापना कर रहा है। दूसरे शब्दों में संविधान के अनुसार धर्म प्रत्येक मनुष्य का वैयक्तिक प्रश्न है। राज्य इसमें किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो मनुष्य चाहे जिस धर्म को मान सकता है। राज्य प्रत्येक धर्म के लिये बराबर सुविधायें देगा। ऐसा नहीं कि किसी को सुविधायें दी जावे तथा अन्य धर्मों को, वह न दी जावे। प्रत्येक धर्म वाले अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इनमें कोई बाधा नहीं पहुँचाई जावेगी। वे अपने पूजार्थ पूजागृह, मन्दिर, मस्जिद, गिर्जे आदि स्थापित कर सकते हैं। सरकार उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकेगी। परन्तु यह अधिकार सीमित नहीं हो सकता है। धर्म की स्वतन्त्रता वही तक दी जा सकती है जहाँ तक वह समाज की शक्ति, सुरक्षा तथा नैतिक-भावना के विरुद्ध न हो।

इसी कारण से धर्म के मामले में सरकार पूर्णतया निर्वैश है। सरकारी शिक्षा सरथाओं में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। उन संस्थाओं में जिनको सरकारी सहायता प्राप्त है किसी को किसी विशेष प्रकार के धार्मिक कृत्य में भाग लेने को बाध्य किया जा सकता है। धर्म के कारण राज्य किसी संस्था को सहायता प्रादि नहीं देगा। धर्म के कारण किसी व्यक्ति को सरकारी सेवा से वंचित नहीं किया जावेगा। संक्षेप में धर्म से राज्य का कोई प्रयोजन नहीं है। इससे यह तात्पर्य नहीं कि संविधान एक नास्तिक राज्य की स्थापना करता है, न यही अर्थ है कि नास्तिकों को विशेष सुविधायें प्रदान की जावेगी। परन्तु इससे यह तात्पर्य अवश्य लेना चाहिए कि मनुष्य चाहे धार्मिक हो चाहे नास्तिक, चाहे हिन्दू हो चाहे मुसलमान, वह राज्य के लिये समान है।

इसी लौकिकता का एक पहलू यह भी है कि संविधान द्वारा अस्पृश्यता भ्रंश पोषित कर दी गई है। अब सर्वत्र हिन्दू हरिजनों को मन्दिरों के अन्दर जाने से नहीं रोक सकते हैं न वे उन्हें कुओं से पानी भरने से रोक सकते हैं। अस्पृश्यता के साथ-साथ साम्प्रदायिकता को भी हटा दिया गया है। इसी उद्देश्य से पृथक निर्वाचन-प्रणाली का अन्त कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ अब पहले की तरह अल्पसंख्यकों के लिये सीटें सुरक्षित नहीं रखी जाती हैं। सशुद्ध-निर्वाचन प्रणाली मान ली गई है। परन्तु अब भी हरिजन तथा

प्रादिम जातियों के लिये कुछ ध्यान सुरक्षित रखने के लिए संविधान में उपबन्ध है। परन्तु कुछ काल पश्चात् ये भी हटा दिये जायेंगे।

धर्म-निर्देशना तथा अस्पृश्यता एवं साम्प्रदायिकता का अन्त इसलिए आवश्यक था कि देश की एकता दृढ़ की जाय तथा भारत का एक राष्ट्र हो जावे। इसी कारण संविधान निर्माताओं ने सोचा कि समस्त देश के लिए एक भाषा का होना भी आवश्यक है। राष्ट्रीयता के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहाँ भाषा की एकता व राष्ट्रीयता की भावना को सुदृढ़ करने में बहुत सहायता प्रदान की है। इसी कारण भारत में संविधान द्वारा समस्त देश के लिये एक ही राष्ट्र-भाषा स्वीकार की गई। यह हिन्दी है संविधान लागू होने के १५ वर्ष पश्चात् सब काम उसी भाषा में करना होगा। कुछ विद्वानों की राय में हिन्दी को इस प्रकार राष्ट्र-भाषा बनाना उचित नहीं हुआ है। क्योंकि भारत में कम से कम १४ अन्य ऐसी भाषाएँ हैं जिनका साहित्य है तथा जो उन्नत अवस्था में हैं। उत्तर भारत की भाषाओं में तो कुछ साम्य है। परन्तु दक्षिण भारत की भाषाएँ उत्तर भारत से सवधा भिन्न हैं। इन लोगों के मतानुसार किसी भाषा को इस प्रकार राष्ट्र भाषा नहीं बनाया जा सकता है। राष्ट्र-भाषा का तो धीरे धीरे विकास होगा। यह सत्य है कि भाषा की एकता राष्ट्रीयता के लिए नितान्त आवश्यक नहीं। उदाहरणार्थ, स्विटजरलैण्ड में तीन भाषाएँ हैं। परन्तु एक भाषा ऐसी होनी ही चाहिये जिसमें कि समस्त देश का काम हो सके। साधारण शब्दा में भारत में अंग्रेजी का स्थान लेने के लिए एक अन्य भाषा की आवश्यकता अवश्य है।

(८) मूल-अधिकार—भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कई अधिकार दिये गये हैं। इसका संविधान में वर्णन किया गया है। इनको नागरिकों के मूल अधिकार कहा गया है। इनसे यह तात्पर्य है कि राज्य व्यक्तित्व के विकास के लिये नागरिकों के कुछ अधिकारों को प्राप्त करने में कोई अड़बट डाले या सरकार किसी कानून द्वारा नागरिकों को उनका उपयोग करने से रोके तो नागरिक इनकी रक्षा न्यायालय की शरण ले सकते हैं। आधुनिक काम में अधिकतर लिखित विधानों में इस प्रकार के अधिकारों का वर्णन रहता है। संविधान द्वारा निम्नलिखित अधिकार मूल अधिकार कहे गये हैं

- (१) समता अधिकार,
- (२) स्वातन्त्र्य अधिकार,
- (३) शोषण के विरुद्ध अधिकार,
- (४) धर्म स्वातन्त्र्य अधिकार,
- (५) संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार

(६) न्यायिक अधिकार,

(७) न्यायिक अधिकारों के अधिकार।

इन मूल अधिकारों के अतिरिक्त संविधान में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि राज्य अपनी नीति निर्धारित करने तथा विधि बनाने में कुछ विशेष तत्वों का प्रयोग करेगा। परन्तु इन तत्वों की विशेषता यह है कि इनको किसी न्यायालय द्वारा बाधता न दी जा सकेगी। नविधान में यह कहा गया है कि ये तत्व देश के शासन में मूलभूत हों। राज्य का उद्देश्य, एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना बढ़ा गया है, जिसमें कि सबों को सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक न्याय प्राप्त हो। इसलिए राज्य की नीति का सम्बालन इस प्रकार करने को कहा गया है जिसमें सभी नागरिकों की जीविका के पर्याप्त साधन हों; धार्मिक व्यवस्था सभी के लिए हितकर हो; पुरुषों तथा स्त्रियों को समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जाय, आदि। इसी उद्देश्य के लिए राज्य कई कार्य करेगा। ये कार्य निम्नलिखित बतलाये गये हैं :

(१) ग्राम पंचायतों का संगठन,

(२) कुछ व्यवस्थाओं में नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।

(३) अमियों के लिये निर्वाह-मजदूरी,

(४) नागरिकों के लिए एक समान व्यवहार-संहिता,

(५) बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबन्ध; धार्मिक जातियों, अनुमार्जित जातियों तथा अन्य दुर्बल विभागों की शिक्षा और अन्य सम्बन्धी हितों की उन्नति,

(६) जीवन-स्तर को ऊँचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयत्न,

(७) कृषि और पशुपालन का संयोजन,

(८) राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और चीजों का संरक्षण,

(९) कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण,

(१०) अन्तर्राष्ट्रीय, शान्ति और सुरक्षा की उन्नति।

इन राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में तथा नागरिक के मूल अधिकारों में यह मुख्य भेद है कि इनको किसी भी न्यायालय द्वारा बाधता नहीं दी जा सकती है।

(६) स्वतन्त्र न्यायपालिका—संविधान द्वारा एक स्वतन्त्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। प्रत्येक स्वतन्त्र-राज्य में एक ऐसी सत्ता का होना

आवश्यक है जिसका निर्णय अन्तिम होगा तथा जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है। एकात्मक सरकार जिन देशों में है वहाँ यह सत्ता व्यवस्थापिका के पास होती है। उदाहरणार्थ, इंग्लैण्ड में पार्लियामेंट सर्वोच्च सत्ता है। पार्लियामेंट द्वारा बनाये हुये कानून की कोई अवहेलना नहीं कर सकता है। डायरी के अनुसार यह जो कुछ चाहे वह कर सकती है तथा किसी भी कानूनी-बन्धन से नहीं बंधी है। इसको पार्लियामेंट की सर्वोच्चता (Parliamentary Supremacy) कहा जाता है। परन्तु संघात्मक सरकार में सर्वोच्च-सत्ता न्यायपालिका है। क्योंकि संघ-राज्य, कई राज्यों के आपस में एक समझौता करने से बनता है। अथवा, एक एकात्मक-राज्य अपने को संघात्मक राज्य में परिवर्तित कर सकता है। दोनों दशाओं में संविधान द्वारा संघ तथा इसकी इकाइयों के मध्य अधिकार-विभाजन हा जाता है। कुछ अधिकार संघ-सरकार को दिये जाते हैं तथा कुछ इसकी इकाइयों को। इस अधिकार-विभाजन में कोई परिवर्तन बिना इन दोनों दलों की स्वीकृति से नहीं हो सकता है। इस कारण यह स्वाभाविक है कि अगर केन्द्रीय व्यवस्थापिका को सर्वोच्च सत्ता बना दिया जावे तो इकाइयों के अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसलिए यह सत्ता एक तटस्थ-शक्ति के हाथों में होनी चाहिये और यह शक्ति न्यायपालिका है।

संघ-राज्य में न्यायपालिका संविधान का संरक्षण करती है। इसको संविधान का संरक्षक (Guardian of the Constitution) कहा जाता है। इस प्रकार यह संघ तथा राज्य दोनों को अपने निश्चित क्षेत्र के अन्दर रखती है। इससे अतिरिक्त अगर इकाइयों का आपस में कोई झगडा हो तो इसका निर्णय भी यही करती है। अन्त में व्यक्ति के अधिकारों की भी यही रक्षा है।

भारतीय संविधान द्वारा भी, इन बातों के लिए एक स्वतन्त्र न्यायपालिका स्थापित की गई। इसकी स्वतन्त्रता तथा तटस्थता अक्षुण्ण रखने के लिए कई उपबन्ध बनाये गये हैं। इनका वर्णन आगे किया गया है।

(१०) उदार संविधान—भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि यह एक 'उदार संविधान' है। जैसा पहले लिखा जा चुका है इस संविधान का उद्देश्य भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतन्त्रता, समानता तथा ग्रातत्व की प्राप्ति है। ये ही उदारवाद के लक्ष्य हैं। इसी कारण जैसा हम अगला चुके हैं कि संविधान द्वारा, नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किये गये हैं और यह इसी उदारवादी विचारधारा का परिणाम है कि एक स्वतन्त्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है जो कि नागरिकों के मूल अधिकारों की संरक्षक है।

उदारवादी विचारधारा का मूल सिद्धान्त यह है कि व्यक्ति माधन नहीं है अपितु वह साध्य है। यह मत है कि यदि इस सिद्धान्त को यदि दूर तक ले जाया जाय तो यह समष्टि के लिये घातक होगा। परन्तु यह भी नितान्त मत्त है कि केवल समष्टि में ही प्रज्ञान केन्द्रित करने से व्यक्ति की सत्ता का पूर्णतः लोप हो जाता है।

(११) भारत तथा राष्ट्र-मण्डल की सदस्यता.—संविधान द्वारा भारत एक सम्पूर्ण-अभुत्व-सम्पन्न गणराज्य स्थापित हुआ है। हम बतला चुके हैं कि इतना क्या प्रयत्न है। परन्तु भारत इतके साथ-साथ राष्ट्र-मण्डल (Commonwealth of Nations) का भी सदस्य है। प्रश्न यह है कि क्या राष्ट्र-मण्डल की सदस्यता से भारत की स्वतन्त्रता में किसी प्रकार की कमी हुई है तथा क्या एक गणराज्य के लिए उचित है कि वह एक ऐसे मंडल का सदस्य हो जिसका प्रधान एक राजा है।

इन प्रश्नों का उत्तर मली-भांति नवसत्रे के लिये हमें यह देखना चाहिये कि राष्ट्र-मण्डल से क्या समझा जाता है। राष्ट्र-मण्डल का अर्थ उन देशों का मंडल है जो कि एक समय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। धीरे धीरे इनमें से कई भागों ने इंग्लैण्ड से कई प्रकार के अधिकार प्राप्त कर लिये और वे अपने प्रान्तरिक मामलों से परमत्ता स्वतन्त्र हो गये। सन् १९२१ में Statute of Westminster पास हुआ। इसमें यह स्पष्ट रूप से कह दिया कि ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल के सब सदस्य आपन में बराबर हैं कोई किसी के अधीन नहीं है तथा सबों ने स्वेच्छा से सम्राट को अपनी एकता का प्रतीक मान रखा है। इस प्रकार प्रान्तरिक विषयों में तथा बाह्य विषयों में राष्ट्र-मण्डल के सदस्यों को स्वतन्त्रता प्रदान की गई। परन्तु इसके साथ-साथ यह भी नहीं भूलना चाहिये कि राष्ट्र-मण्डल में १९४७ में पूर्व केवल वे ही राष्ट्र थे जहाँ कि गोरों की आबादी थी या उनके हाथ में प्रभुता थी। उदाहरणार्थ कॅनेडा, न्यूजीलैण्ड, साउथ अफ्रीका। इसी कारण अंग्रेज लेखकों ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि राष्ट्रमण्डल केवल एक राजनीतिक या आर्थिक एकता का ही फल नहीं है, परन्तु यह एक सांस्कृतिक एकता भी प्रदर्शित करता है।

राजिन्सान ने ना राष्ट्रमण्डल का सदस्य रहना आरम्भ में ही निश्चित कर लिया था। परन्तु भारत में इसमें उलट बदलाव हो गया। १९५० नेहरू तथा कांग्रेस के अन्य नेतागण तो इसमें ही रहना चाहते थे। परन्तु इस में कुछ अन्य ऐसी लोग थे जिनसे विचार में उलट नहीं रहना चाहिये था। जब ५० नेहरू अप्रैल १९४९ में ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल के प्रधान मन्त्रियों के सम्मेलन में गये तो वहाँ यह प्रश्न उठा। ५० नेहरू ने भारत की ओर से यह निश्चय किया किया भारत इसका सदस्य नगा। इसलिए ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के अन्य सदस्यों ने इसमें नाम के आगे से ब्रिटिश हटा दिया। अब यह बसल राष्ट्र मण्डल कहलाने लगा।

इस राष्ट्र मण्डल की एकता का प्रतीक सम्राट् है। परन्तु भारत एक गणराज्य है। एक गणराज्य इसका सदस्य कैसे हो गया? इसके समर्थकों का कहना है कि सम्राट् ना केवल प्रतीक है और भारत सम्राट् को केवल प्रतीक मानता है इसमें अधिक कुछ नहीं। भारत इसकी सदस्यता के सम्बन्ध में सम्राट् के प्रति कोई अधीनता नहीं प्रदर्शित करता है। सर एनस्ट जेकर ने लिखा है कि सम्राट् (King) तथा राष्ट्र मण्डल के सदस्य सम्राट् के अधीन हैं। दूसरी ओर सम्राट् केवल स्वेच्छा से रचित एगना का प्रतीक है। परन्तु भारत के साथ एक ही सम्बन्ध है। भारत सम्राट् को केवल एगना का प्रतीक मानता है। भारत सम्राट् के अधीन नहीं है।<sup>1</sup>

मविधान में राष्ट्र मण्डल की सदस्यता के ऊपर कोई धारा नहीं है। यह सम्बन्ध मविधान के बाहर का है। इस सम्बन्ध का अगली आधारा कानून न होकर संसद की राजनैतिक स्थिति है हमारे देश में शासक ने समझा कि हमारे राजनैतिक अधिकार तथा हिता का संरक्षण राष्ट्र मण्डल में रहने से होगा।

and the same attitude to sports—Sir, Ernest Barker *Parliamentary Affairs*, p 13, Vol IV No 1

1. "The relation of the King to the unity of the Commonwealth was double in its nature. On the one hand the King was the recipient of a common allegiance from all the individual members of all the countries of the Commonwealth. On the other hand he was a symbol. But in India, the King is not a recipient of allegiance. But (he) is acknowledged as the symbol of the free association of the independent member nations and as such the Head of the Commonwealth."

मतएव उन्होंने इसकी सदस्यता स्वीकार की। अगर कोई दूसरा दल कभी सरकार बनाने में सफल हुआ जिसकी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में इनटैन्ट के साथ सहानु-भूति नहीं है तो यह सम्भव है कि भारत राष्ट्र-मण्डल में निकल जावे।

### प्रश्न

- (१) भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ बताइये। (यू० पी० १९५९)
- (२) "राष्ट्रमण्डल" से आप क्या समझते हैं? भारत सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य होने हुए भी राष्ट्र-मण्डल का सदस्य क्या है?
- (३) भारत के नवीन संविधान की क्या विशेषताएँ हैं?  
(यू० पी० १९५२)
- (४) घमें निर्पेक्ष राज्य से क्या अर्थ है? हमारे संविधान द्वारा कहीं तक ऐसे राज्य की स्थापना हुई है?  
(यू० पी० १९५३)

At this place it will be interesting to note that Mr. Gordon Walker (who was Secretary of State in the Labour Government) said on February 20th 1953, that Shri Nehru's message to Queen Elizabeth "welcoming Your Majesty as the new head of the Commonwealth" had helped clearly and formally to enunciate that the Crown is the symbol of the free association of all members of the Commonwealth whether they be monarchies or republic."—*Amrit Bazar Patrika*, 1, 1953.

The statement issued after a Conference of Prime Ministers, attended by Pt. Nehru in London, stated, "The Government of India, have declared and affirmed India's desire to her full membership of the Commonwealth of Nations and her acceptance of the King as the symbol of the free association of the independent nations as the head of the Commonwealth"



## भारत-संघ तथा उसका राज्य-क्षेत्र

### I भारत संघ

मंत्रिदान ही प्रथम धारा में लिखा है कि भारत अर्थात् इण्डिया राज्या का मध्य होगा। इसमें हम इस अध्याय में मध्य-प्रथम यह देवना चाहिये कि संघ-राज्य की क्या परिभाषा है? इसने क्या लक्षण है? इसकी क्या आवश्यकता दशाएँ हैं? इसका पञ्चांग हम यह देखें कि भारत संघ में ये लक्षण कहीं तक वर्तमान हैं। इसके क्या विशेष लक्षण हैं जो अन्य मध्य सरकारों में भिन्न हैं, क्या हम इसको संघ कह सकते हैं तथा क्या भारत के लिये संघात्मक विधान उपयुक्त है?

**संघ की परिभाषा** — प्रा० स्ट्रांग संघात्मक सरकार की परिभाषा करते हुए लिखते हैं मध्य राज्य में कई रियासतें कुछ समान उद्देश्या के लिए एक हो जाती हैं। केंद्राध्य सरकार की शक्तियाँ रियासतों की शक्तियों के द्वारा सीमित हो जाती हैं। इसलिए एक ऐसी शक्ति होती है जो कि इस अधिकार-विभाजन का निश्चित करती है। विधान ही स्वयं यह शक्ति होता है। इस विधान का स्वरूप एक मध्य की तरह होता है।

मध्य राज्य का प्रकार संघ संघ संघ है एक ठग तो यह है कि जब कई स्वतन्त्र रियासतें कई बारणा में मिलकर एक राज्य बना लेती हैं। इस ठग से संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका का संघ बना था। दूसरा ठग यह है कि जब एक एकात्मक सरकार संघात्मक सरकार में परिवर्तित हो जाती है उदाहरणार्थ १८८९ में ब्राजील का संघ इसी प्रकार बना था। हमारा विधान भी इसी प्रकार बना है।

**संघ सरकार के लक्षण** — विद्वानों के अनुसार मध्य-सरकार में निम्न लिखित लक्षण होने चाहिये —

(१) संघात्मक सरकार में एक लिखित विधान होना चाहिए। ऐसा विधान निश्चित तथा स्पष्ट होना है।

(२) यह विधान अपरिवर्तनशील (rigid) होना चाहिये। नही तो रियासतों की सरकारों का सबदा अपने अधिकारों के छोड़े जाने का भय लगा रहेगा।

(३) संघ-सरकार में विधान की ही प्रधानता (Supremacy of the Constitution) रहती है।

(४) संघ-सरकार तथा रियासतों की सरकारों के बीच अधिकारों का विभाजन होना चाहिये। यह विभाजन संविधान द्वारा ही किया जाता है।

(५) संघ-सरकार में एक स्वतन्त्र न्यायाधिका का होना आवश्यक है। यह विधान की सरक्षक है। इसका काम संघ-राज्य तथा रियासतों के बीच झगड़ों का सुलझाना होता है।

संघ-सरकार के लिए आवश्यक दशाएँ — ये निम्नलिखित हैं:—

(१) कई छोटे राज्य हों, यथवा एक बड़ा राज्य हो जिसके विभिन्न भागों को संघ-इकाइयों में बदल लिया जाये।

(२) इन भागों को संस्कृति, सम्पत्ता, धर्म आदि में अधिक असमानता तथा भेद न हो।

(३) इन भागों में इतिहास की एकता होनी चाहिये।

(४) भौगोलिक दृष्टि से विभिन्न भाग मिले होने चाहिये। अगर एक रियासत हिन्द-महासागर में तथा दूसरी अटलांटिक-महासागर में हो तो संघ-राज्य की स्थापना नहीं हो सकती है।

(५) इन राज्यों के राजनैतिक तथा धार्मिक हित परस्पर-विरोधी न हों।

भारत संघ में संघात्मक सरकार के लक्षण:—भारत संघ में संघ-राज्य के प्रायः सभी लक्षण वर्तमान हैं:—

(१) भारत का संविधान लिखित है। इसकी रचना संविधान सभा द्वारा की गई है।

(२) यह विधान अपरिवर्तनीय है। वैधानिक कानून तथा माधारण कानून में अन्तर है। विधान में संशोधन के लिये विशेष विधि है।

(३) भारत में भी संविधान की प्रधानता है।

(४) संघ तथा राज्यों के बीच इस संविधान द्वारा अधिकारों का विभाजन किया गया है तथा दोनों के क्षेत्र निर्दिष्ट कर दिये गये हैं।

(५) भारत में एक स्वतन्त्र न्यायाधिका की स्थापना की गई है। यह विधान की सरक्षक है तथा इसका काम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और संघ तथा इकाइयों के बीच झगड़ों का निर्णय करना है।

**भारत सच के विशेष लक्षण** — उपराक्त वर्णित लक्षणा के होने हुए भी जो कि भारतीय संविधान तथा अन्य संविधानों में समान रूप से पाये जाते हैं, हैं, हमारे संविधान के कुछ विशेष लक्षण हैं। ये निम्नलिखित हैं —

(१) भारत-सच, जैसा कि साधारणतः अन्य सच राज्यों के बनने में हुआ है, बहुत से स्वतन्त्र राज्यों के आपस में एक समझौता का फल नहीं है। सन् १९३७ में जब कि १९३५ का ऐक्ट लागू किया गया था भारत के प्रान्तों को स्वायत्त-शासन का अधिकार दे दिया गया था। इस प्रकार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एकात्मक सरकार के स्थान में एक संघात्मक-सरकार की स्थापना की। परन्तु इसने द्वारा ये प्रान्त स्वतन्त्र राज्य नहीं हो गये थे। इसलिये जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ उस समय भी भारत में कई स्वतन्त्र राज्य नहीं थे, जो कि कुछ राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिये एक होना चाहते थे। अतः केन्द्र में एक सरकार थी जो कि भारत को एकान्ति, सुरक्षा तथा व्यवस्था के लिये उत्तर-दायी थी।

इसने अतिरिक्त यह भी ध्यान में रक्खना चाहिये कि जब संविधान-सभा में भारत के नये संविधान का निर्माण किया, उसमें विविध प्रान्तों का कोई भाग नहीं था। संविधान भारत की जनता ने, जिसने प्रतिनिधि संविधान-सभा में एनट्रिन दे बनाया न कि विविध प्रान्तों के प्रतिनिधियों ने।

(२) साधारणतः सच-राज्यों में द्वैध नागरिकता होती है—सच की तथा राज्यों की। उदाहरणार्थ, संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका में ऐसा है। वहाँ प्रत्येक नागरिक, सच का नागरिक है तथा साथ ही साथ अपने राज्य का भी। प्रत्येक राज्य (इपार्ट) अपने नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार देता है, जैसे नौकरी, व्यापार, शिक्षा आदि नियमों में कुछ गुंथिपाएँ प्रदान करता है। पर भारतीय संविधान द्वारा द्वैध नागरिकता नहीं स्थापित की गई है। भारत में एकही नागरिकता है प्रत्येक व्यक्ति सच का नागरिक है। राज्यों की अपनी अलग नागरिकता नहीं है। इस कारण कोई भी राज्य अपने नागरिकों को कोई ऐसी सुविधा व्यापार, शिक्षा, आदि की नहीं प्रदान कर सकता है जा कि अन्य नागरिकों को उपलब्ध न हो। ब्रिटेन के संविधान में भी एकही नागरिकता है। सन् १९३५ के ऐक्ट ने द्वारा एकही नागरिकता स्थापित हुई थी।

(३) साधारणतः सच-राज्यों के इकाइयों को यह अधिकार रहता है कि वे सच के अन्तर्गत अपने संविधान का स्वयं ही निर्माण करें। उदाहरणार्थ, संयुक्त-राष्ट्र में संविधान सभा ने केवल सच के संविधान की ही रचना की थी कि इकाइयों की भी। उनको यह अधिकार दे दिया गया था कि वे जिस प्रकार का

चाहे लोकतन्त्रात्मक विधान बनाये। आस्ट्रेलिया में भी इकाइयों को इस प्रकार का अधिकार है। परन्तु भारत में कनाडा की तरह संविधान द्वारा राज्यों का संविधान का भी निश्चय कर दिया गया है। राज्यों को इन उपबन्धों में किसी प्रकार के परिवर्तन का भी अधिकार नहीं है।

(४) साधारणतः सभ राज्यों में सम्पूर्ण सरकार की व्यवस्था ही दोहरी होती है—सभ की व्यवस्था तथा राज्यों की व्यवस्था। इस कारण सभ राज्यों में दोहरी व्यवस्थापिका, दोहरी कार्यपालिका, तथा दोहरी न्यायपालिका होती है। परन्तु भारतीय संविधान में कई ऐसे उपबन्ध हैं जिनके द्वारा यह दोहरापन बहुत कम कर दिया गया है। सर्वप्रथम संविधान द्वारा सम्पूर्ण सभ के लिए एक ही न्यायपालिका की स्थापना की गई है। अमेरिका में नयीय न्यायपालिका तथा राज्यों की न्यायपालिकाएं भिन्न-भिन्न होती हैं। परन्तु भारतीय संविधान में ऐसा नहीं किया गया है। कनाडा के संविधान में भी ऐसा ही है। इसके अतिरिक्त समस्त देश के लिये एक ही दीवानी व फौजदारी कानून है। इसी कारण दीवानी व फौजदारी कानून को समवर्ती सूची में रखा गया है। इसके साथ-साथ धामन की एकता के लिए समस्त देश के लिए अखिल-भारतव्यापी सेवाओं का प्रवन्ध किया गया है। इस सेवा (Service) के सदस्य सभी राज्यों में उच्च स्थानों में नियुक्त किये जाते हैं। सभ तथा राज्यों की अपनी-अपनी सेनाएँ हैं, परन्तु ये दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र के अन्दर सभ राज्य के कानूनों को कार्यान्वित कर सकती हैं।

(५) भारत में एक अत्यन्त शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना की गई है। साधारण समय में भी केन्द्र के पास कई ऐसी शक्तियाँ हैं जो साधारणतः अन्य संघात्मक संविधानों में नहीं पाई जाती हैं। राष्ट्रपति को राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति का अधिकार है। सभ सरकार कुछ विषयों में राज्य की सरकारों को आदेश दे सकती है और अगर कोई राज्य इन आदेशों का पालन न करे तो सभ सरकार स्वल्पकाल के लिये उस राज्य की शक्ति अपने हाथ में ले सकती है। सभ सरकार को राज्य-सूची में दिए हुए किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, यदि राज्यपरिषद् (Council of States) दो-तिहाई मत से यह पाम कर दे कि वह विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। संविधान में यह भी कहा गया है कि अगर राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनाया हुआ कोई कानून राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित कर लिया गया है, तो वह बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के लागू नहीं हो सकता है।

उपर्युक्त उपर्युक्त आधारणकालीन है। मकट-काल में वो मध-मरकार के पास इतनी शक्ति आ जाती है कि यह वस्तुन एकात्मक मरकार में परिणत हो जाती है। अन्य मविधान में ऐसी कोई विधि नहीं जिनके द्वारा कि सघात्मक सरकार के स्थान में एकात्मक सरकार स्थापित हो जाये। इस विषय में भारत का विधान अलूटा है। मकटकाल में इस प्रकार मध के अधिकारों की वृद्धि मन् १९३५ के ऐक्ट से ली गई है।

(३) साधारणतः मध राज्या में यह व्यवस्था है कि सघ मन् के ऊपरी भवन में प्रत्येक इकाई के बराबर सदस्य होते हैं। डूमेरे शब्दा में राज्यों की जन-संख्या के आधार पर ऊपरी-भवन के लिये सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता है। उदाहरणार्थ, अमेरिका में प्रत्येक राज्य सीनेट में दो सदस्य भेजता है। इस प्रकार के प्रतिनिधित्व का आधार यह सिद्धान्त है कि मध के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य बराबर है। निचले-भवन के लिये प्रतिनिधि जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित होते हैं। भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है। ऊपरी-भवन (राज्य-परिषद्) में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर रखा गया है। कुछ राज्यों को केवल एक ही प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है जब कि उत्तर प्रदेश से ३१ प्रतिनिधि भेजे जायेंगे। कनाडा में भी राज्यों की बराबरी का सिद्धान्त नहीं माना गया है। वहाँ की ऊपरी भवन में इकाइयों के बराबर प्रतिनिधि नहीं है। अधिक से अधिक २४ तथा कम से कम ४ है।

(७) भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है वह भी अन्य सघात्मक संविधानों से भिन्न है। उदाहरणार्थ, संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन व्यवहार में जनता द्वारा ही होता है। आस्ट्रेलिया अथवा कनाडा के गवर्नर-जनरल की नियुक्ति कैबिनेट की राय के अनुसार सम्राट् द्वारा की जाती है। भारत अगर उपनिवेश ही रहता तो यही विधि यहाँ भी लागू होती। भारत के स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद यह विधि सम्भव नहीं थी। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों भवनों के सदस्य तथा राज्यों की विधान-सभाओं के सदस्यों द्वारा एक-परिवर्तनीय-मत-विधि (Single Transferable Vote) द्वारा होगा।

(८) भारतीय संविधान में कानूनीपन (legalism) को बहुत कमी है। साधारणतः सघात्मक संविधानों में कानूनीपन अधिक होता है। इसका कारण यह होता है कि सघात्मक संविधान का स्वरूप एक सन्धि की तरह होता है। जिसके द्वारा सघ सरकार तथा राज्यों की सरकारों के मध्य अधिकार विभाजन किया जाता है। इस अधिकार विभाजन के फलस्वरूप इन दो दलों में

कठिनाईयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। उन समय फैमले के लिये न्यायालय की जरूरत लेनी पड़ती है। परन्तु भारतीय संविधान में ऐसे सगडों के लिये कम स्थान है क्योंकि मध्य तथा राज्यों की सरकारों के बीच अधिकार-विभाजन अधिक स्पष्ट रूप से किया गया है। इसके लिए तो सुविधा बनावी गई है। एक तो सच-मूची है। इसमें १७ विषय हैं। राज्य-मूची में ६६ विषय रखे गए हैं तथा समवर्ती मूची में दिए गए विषयों में भी मध्य सरकार को प्राथमिकता तथा प्रधानता दी गई है। अवशिष्ट अधिकार भी मध्य को दिए गए हैं।

(९) भारतीय संविधान में यद्यपि संशोधन की व्यवस्था सरल रखी गयी है तथापि इसके विस्तार के कारण इसमें संशोधन कठिन होगा। इसलिए विद्वानों के अनुसार भारतीय संविधान में अपरिवर्तनशीलता विशेष रूप से है।

क्या भारत का संविधान संघात्मक है?—भारतीय संविधान के उपर्युक्त वर्णित लक्षणों से यह स्पष्ट हो गया होगा कि विधान निर्माताओं का उद्देश्य एक शक्तिशाली केन्द्र स्थापना था। इसी कारण मध्य सरकार को कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिनके द्वारा यह राज्यों के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती है तथा संकटकाल में सब राज्यों के सब अधिकार अपने हाथ में ले सकती है तथा इसका कारण यह कहा है कि यही एक रास्ता था जिसके द्वारा भारत की एकता को अभ्युन्नत रखा जा सकता था। भूतकाल में भारत की एकता कई बार भंग हुई है। परन्तु भविष्य में ऐसा न हो इस कारण शक्तिशाली केन्द्र स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त कई समस्याएँ ऐसी हैं जो सावंदेरीय हैं। इस कारण भी मध्य-सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया गया।

परन्तु प्रश्न यह नहीं है कि शक्तिशाली केन्द्र भारत के हित में है या नहीं। प्रश्न वैधानिक (Constitutional) है और वह यह है कि क्या हम भारत को मध्य-राज्य कह सकते हैं? विद्वानों के अनुसार भारत संघ-राज्य तो है परन्तु इसमें एकात्मक सरकार के भी कई लक्षण वर्तमान हैं। डा० अम्बेदकर ने संविधान-सभा में स्वयं इस बात को स्वीकार किया संघात्मक-सरकार के साथ साथ एकात्मक सरकार के लक्षण भी भारतीय संविधान में वर्तमान हैं। लेखकों के अनुसार भारतीय संविधान में एकात्मक-सरकार के लक्षण मुख्य हैं

1. देखिये Jennings का Characteristics of the Constitution.

2. "It may be correctly described as a quasi-federation with many elements of unitariness."—G. N. Joshi, Ibid, p. 136r (1952 ed).

तथा सघात्मक के लक्षण मौन। एक अन्य लेखक के अनुसार यह एक नवीन प्रकार का मध है।<sup>1</sup>

क्या भारत में सघ सरकार की स्थापना उपयुक्त है?—इस प्रश्न का उत्तर देते समय हमें सघ-सरकार की आवश्यक दशाओं का ध्यान रखना चाहिये इनका हम पहले वषन कर चके हैं।

(१) भारतवर्ष एक विशाल देश है। इसके अन्तर्गत कई प्रदेश हैं जो कि जनसंख्या तथा क्षेत्र-विस्तार की दृष्टि से ससार के कई राष्ट्र से भी बडे हैं। उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, करीबन इंग्लैंड के बराबर है। इसकी जनसंख्या करीबन ५ करोड ६३ लाख ४६ हजार है। इसी प्रकार अन्य प्रदेश भी हैं। सम्पूर्ण भारतवर्ष की आबादी ३१ करोड ८७ लाख ७६ हजार है। इसका क्षेत्रफल १२ लाख १८ हजार ३२७ बर्गमील है। यह स्पष्ट है कि इतने बडे देश का शासन एक केन्द्रीय सरकार द्वारा सचारु रूपसे सम्पन्न नहीं हो सकता है।

(२) सघात्मक सरकार में ब्राइस (Bryce) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के ऊपर इतना अधिक काम नहीं रहता है कि वह काय-भार के कारण दब जाय। अपितु राज्यों की एक निश्चित-सीमा के अन्दर अपनी समस्याएँ अपने आप हल करने का अधिकार रहता है। इसका फल यह होता है कि दैनिक जीवन के मामलों में केन्द्रीय सरकार को अपना समय बर्बाद नहीं करना पडता परन्तु वह राष्ट्रीय महत्व के मामों में अपना समय लगा सकती है।

(३) भारत में भाषा, धर्म, तथा कुछ मात्रा में संस्कृति की विभिन्नता है। इसकी स्वीकारन करना केवल हठधर्मी ही हो सकता है। इसलिए विभिन्न

Prof K. C. Wheare writes, But just as in Canada the federal principle was modified by unitary elements in the form of control by the general government of principal governments, so also in the Indian Constitution—but much more so—the central government is given powers of intervention on the conduct of affairs of the state governments which modifies the federal principle. The Constitution does not indeed claim to establish a federal union, but the federal principle has been introduced into its terms to such an extent that it is justifiable to describe it as a quasi federation"—Federal Government, p. 28 (2nd ed)

1 Durga Das Basu, A Commentary on the Constitution of India, p. 31.

भाषा-भाषी प्रांतों को कुछ मात्रा तक स्वायत्त शासन देना आवश्यक है। इन प्रकार वे उत्साहपूर्वक काम करेंगे तथा अपनी समस्याओं को भली भाँति सुलझाने की चेष्टा करेंगे। केन्द्र से यह ध्याना करना कि वह प्रादेशिक समस्याओं को उतनी ही अच्छी प्रकार समझ सकता है तथा हल कर सकता है जितना कि उन प्रदेश की सरकार, उचित नहीं है।

(४) संपात्मक सरकार एकात्मक सरकार में अधिक प्रजातन्त्रात्मक कही जाती है। क्योंकि इसमें जनता को शासन-प्रवर्ण्य में भाग लेने का अधिक अवसर मिलता है। संपात्मक सरकार में मधीय सनद् के द्वारा तथा राज्यों के विधान-मण्डलों द्वारा भी, जनता शासन के नाम में नियन्त्रण रखती है।

(५) हमारे देश में प्रादेशिक विभिन्नताओं के साथ-साथ इतिहास तथा संस्कृति की एक व्यापक धारा में एकता रही है। विभिन्न प्रदेशों के राजनैतिक तथा आर्थिक हित एक दूसरे के विरुद्ध नहीं हैं। इनमें आपस में भौगोलिक एकता भी है।

उपर्युक्त कारणों से यह कहा जा सकता है कि भारत के लिए संपात्मक संविधान ही उपयुक्त था।

## II. संविधान में संशोधन की व्यवस्था

इस स्थान पर यह अनुचित नहीं होगा कि संशोधन व्यवस्था का भी वर्णन कर दिया जावे। हम पहले लिख चुके हैं कि यद्यपि भारत का संविधान कठोर है तथापि इसकी संशोधन व्यवस्था अन्य कठोर संविधानों की तुलना में मरल है। संपात्मक विधानों में कठोरता का होना आवश्यक माना गया है, क्योंकि अगर विधान में संशोधन की प्रथा तथा साधारण कानून निर्माण करने की प्रथा में कोई अन्तर न हो, दूसरे शब्दों में अगर संसद साधारण-विधि से ही संविधान में संशोधन कर ले, तो सभ के राज्यों को सदा यह भय लगा रहेगा कि उनके अधिकार सुरक्षित नहीं हैं। इस कारण संपात्मक विधान कठोर रखा जाता है।

भारतीय संविधान के संशोधन के लिये विशेष व्यवस्था है। परन्तु यह अत्यन्त मरल रखी गयी है। इसका कारण यह है कि पं० नेहरू ने कहा था, "हम यह चाहते हैं कि यह संविधान स्थायी हो, परन्तु संविधानों में स्थायित्व नहीं होता है। उनमें परिवर्तनशीलता होनी चाहिए। अगर आप किसी वस्तु को कठोर तथा स्थायी बनायें तो आप राष्ट्र की प्रगति को रोक रहे हैं..."



प्रत्येक दशा में, हमें इस सविधान को इतना कठोर नहीं बनाना चाहिये कि यह बदलती हुई अवस्थाओं के अनुसार न बदल सके।<sup>1</sup>

(घ) भारतीय सविधान के कुछ भाग ऐसे हैं जिसमें कि किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद को दिया गया है। अर्थात्, संसद साधारण बहुमत से उनको बदल सकती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इन उपबन्धों में कोई बदलाव सविधान का मसौदा नहीं माना गया है। इस प्रकार के उपबन्ध निम्नलिखित हैं —

(१) नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का बदलना;

(२) राज्यों में विधान-परिषद् का उत्सादन (abolition) या सृजन (creation),

(३) केन्द्रीय सरकार द्वारा शासित भागों का विधान बनाना;

(४) अनुसूचित क्षेत्रों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों का शासन-प्रबन्ध;

(व) इन उपबन्धों के प्रतिरिक्त सविधान में जो उपबन्ध हैं उनको बदलने को सशोधन कहा जायगा। इन उपबन्धों को भी दो भागों में बाँटा जा सकता है :—

(a) सविधान में कुछ उपबन्ध ऐसे हैं जिनमें सशोधन के लिये संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्य सख्या का बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत के अनिवार्य यह भी आवश्यक है कि स्थायित्व राज्यों के विधान-मंडलों, में से कम से कम आधे राज्यों के विधान-मंडलों की स्वीकृति प्राप्त हो। केवल इसके पश्चात् ही राष्ट्रपति के समक्ष उसकी अनुमति के लिये रखा जावेगा। इस कोटि के उपबन्ध निम्नलिखित हैं :—

1. "While we want this Constitution to be as solid and permanent as we can make it, there is no permanence in Constitution. There should be a certain flexibility. If you make anything rigid and permanent, you stop the nation's growth ...

In any event, we could not make this Constitution so rigid that it cannot be adapted to changing conditions "

- (१) राष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्ध रखने वाले (पारा ५४);
- (२) राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि (Manner of Election) से सम्बन्ध रखने वाले (पारा ५५);
- (३) संघीय कार्यपालिका की शक्ति की सीमा से सम्बन्ध रखने वाले, (पारा ७३);
- (४) स्वायत्त राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति की सीमा से सम्बन्ध रखने वाले (पारा १६२);
- (५) केन्द्रीय शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालय से सम्बन्ध रखने वाले (पारा २४१);
- (६) संघीय न्यायपालिका से सम्बन्ध रखने वाले (भाग ५ का अध्याय ४)
- (७) स्वायत्त राज्यों के उच्च-न्यायालय से सम्बन्ध रखने वाले (भाग ६ का अध्याय ५);
- (८) संघ तथा राज्यों के विधानीय सम्बन्धों (Legislative relations) से सम्बन्ध रखने वाले (भाग ११ का अध्याय १);
- (९) संघ तथा राज्यों की विधानीय-सूची ( Legislative Lists ) से सम्बन्ध रखने वाले (सातवीं अनुसूची);
- (१०) संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्ध रखने वाले;
- (११) संशोधन प्रथा से सम्बन्ध रखने वाले (पारा ३६८)।

(b) इन उपर्युक्त उपबन्धों के अतिरिक्त संविधान के अन्य उपबन्धों में संशोधन के लिए संसद के किसी सदन में इस उद्देश्य से एक प्रस्ताव उपस्थित किया जायेगा। यदि उस प्रस्ताव को प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत प्राप्त हो जावे तथा उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जावे तो वह संविधान में संशोधन हो जावेगा।

संशोधन के प्रस्ताव के कानून होने के लिए भी राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। इसलिए संसद द्वारा ऐसे किसी भी प्रस्ताव के पारित होने पर उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जायगा। परन्तु संविधान द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह किसी ऐसे प्रस्ताव पर अपनी अनुमति न दे।

एक बात संशोधन-व्यवस्था के सम्बन्ध में याद रखनी चाहिये कि संशोधन का प्रस्ताव उपस्थित करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। राज्यों

को यह अधिकार नहीं है कि वे अपने आन्तरिक विधान में किसी प्रकार का संशोधन करें। अमेरिका में राज्यों को यह अधिकार प्रदान किया गया है।

### III भारत का राज्य-क्षेत्र

संविधान द्वारा भारत को एक संघ बनाया गया है। इस संघ की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी इकाइयों को इससे निकलने (secede) का अधिकार नहीं है। भारत के अन्तर्गत राज्यों को प्रारम्भ में संविधान द्वारा चार श्रेणियों में बांटा गया था। इनका गणविधान की प्रथम अनुमूची में क्रमशः क, ख, ग, तथा घ वर्गों के राज्य कहा गया था। इस प्रकार से राज्यों का विभाजन इन विभिन्न प्रकार की कोटियों में किया गया था क्योंकि भारत के विभिन्न भाग राजनैतिक तथा आर्थिक दृष्टि में विभिन्न स्तरों में थे। उदाहरणार्थ, जो पहले ब्रिटिश भारत के प्रान्त थे वे भाग देशी रियासत वाले भाग से अधिक उन्नत थे। इन अलग-अलग वर्गों में प्रशासनीय व्यवस्था आदि में अन्तर रखा गया था। संक्षेप में इन चार वर्गों का वर्णन किया जायगा।

#### राज्य-पुनर्गठन के पूर्व व्यवस्था

‘क’ वर्ग के राज्य—इस वर्ग में वे राज्य थे जो कि ब्रिटिश काल में प्रान्त कहलाते थे। इनकी संख्या १० थी। ये निम्नलिखित थे—आसाम, उड़ीसा, पंजाब, पश्चिमी बंगाल, मद्रास, मध्य प्रदेश बम्बई, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा आंध्र।

इन राज्यों को स्वायत्त शासन का अधिकार था। इनका मुखिया राज्य-पाल (Governor) कहलाता था। इनमें से प्रत्येक में विधान-मंडल था। किन्हीं में दो सदन तथा किन्हीं में एक सदन था। इनका शासन प्रबन्ध वही था जो वर्तमान स्वायत्त राज्यों का है।

‘ख’ वर्ग के राज्य—इस वर्ग के राज्य पहले की देशी रियासतें थे। स्वतन्त्रता के पश्चात् देशी रियासतों का प्रश्न एक अत्यन्त ही जटिल प्रश्न के रूप में उपस्थित हुआ। स्वर्गीय सरदार बल्लभ भाई पटेल ने अत्यन्त ही योग्यता पूर्वक इसका समाधान किया। यह आवश्यक प्रतीत होता है कि यहीं पर इन देशी रियासतों की समस्या का वर्णन किया जाय।

अंग्रेजों के शासन-काल में भारत दो भागों में बँटा हुआ था यद्यपि इन दोनों भागों के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार पूर्णरूपेण स्थापित था। एक भाग तो ब्रिटिश भारत कहलाता था। इसमें ११ प्रान्त तथा ६ चीफ कमिश्नर के प्रान्त थे। दूसरा भाग भारतीय रियासतों का था। इनका शासन भारतीय राजाओं या नवाबों द्वारा होता था। इनका कुल क्षेत्रफल ७१२,५०८ वर्गमील था। यह समस्त भारत के क्षेत्रफल का ४५ प्रतिशत था। इन सब राज्यों की जनसंख्या लगभग ९३,२००,००० थी। यह भारत की जनसंख्या का लगभग चौथाई भाग थी। सब मिलाकर ५६२ रियासतें थी। इनमें से २३५ को राज्य कहा जाता था, शेष को रियासत, जागीर, झाड़ि। अगर हम रियासत की परिभाषा करें तो यह कहा जायगा कि यह भारत की भूमि का टुकड़ा था जो कि ब्रिटिश भारत के अन्तर्गत नहीं था, जिसका शासन एक भारतीय नरेश के हाथ में था, परन्तु यह स्वतन्त्र नहीं था, क्योंकि सर्वोच्च-सत्ता (Paramount Power) इंग्लैंड के सम्राट के हाथ में थी।

ये रियासतें विभिन्न प्रकार की थीं। कुछ रियासतें तो इतनी बड़ी थीं जितनी कि ब्रिटिश भारत के प्रान्त जैसे हैदराबाद, काश्मीर आदि। कुछ अन्य रियासतें भी काफी बड़ी थीं, जैसे ट्रावन्कोर, कोचीन, बड़ीश, मैसूर आदि। दूसरी ओर ऐसी भी रियासतें थीं जिनका क्षेत्रफल केवल कुछ एकड़ था। शिमला में पहाड़ों में एक रियासत की आबादी केवल २७ थी। इसकी वार्षिक आय करीबन ९०० रुपया थी। गुजरात तथा काठियावाड़ में कई छोटी रियासतें थी। इनकी संख्या करीबन २०६ थी। वार्षिक आय की दृष्टि से कुछ रियासतें ऐसी थी जिनकी आय १ करोड़ रुपये से अधिक थी जैसे हैदराबाद, मैसूर, आदि। कुछ रियासतें ऐसी थीं, जिनकी आय ५० लाख से ७० लाख के बीच में थी। परन्तु इनकी संख्या भी बहुत अधिक नहीं थी। अधिकतर रियासतों की आय बहुत कम थी।

**रियासतें तथा सम्राट :-** देशी रियासतें ब्रिटिश भारत से अलग थीं। उनकी प्रजा ब्रिटिश प्रजा नहीं थी परन्तु इन नरेशों की प्रजा थी। वे अंग्रेजी पार्लियामेंट के कानून से भी बाहर थे। इन देशी रियासतों तथा ब्रिटिश सरकार के बीच सम्बन्ध कानून की दृष्टि से इनके तथा सम्राट के बीच सम्बन्ध था। सम्राट ही सर्वोच्च सत्ता थी। सम्राट इन रियासतों के प्रति अपने कार्य भारत-मन्त्री या वाइसरॉय के द्वारा करता था।

प्रश्न यह है कि सर्वोच्च-सत्ता का इन देशी रियासतों से क्या सम्बन्ध था? इस प्रश्न का उत्तर बहुत कठिन है क्योंकि इस सम्बन्ध का कभी भी स्पष्ट रूप से

वर्णन नहीं किया गया। ब्रिटिश सरकार तथा इन रियासतों के बीच जो संधियाँ हुई थी वे सब एक प्रकार की न थी, परन्तु उनमें आपस में बहुत मतभेद था। सन् १९२७ ई० में जो भारतीय रियासतों के मामले में कमेटी नियुक्त की गई थी वह भी इस बात का सतोषजनक उत्तर नहीं दे सकी कि इन देशी रियासतों की वैधानिक स्थिति क्या थी। इस कमेटी ने यह कहा कि "सर्वोच्च-सत्ता सर्वोच्च है" (*Paramountcy is Paramount*)। इस प्रकार हम देखते हैं कि देशी रियासतों की वैधानिक-स्थिति कभी भी स्पष्ट नहीं की गई। इसलिये इन विषय पर मत-विभिन्नता होना स्वाभाविक है। कुछ लोगों का यह विचार था कि ये रियासतें स्वतन्त्र राज्य थे तथा इनके और ब्रिटिश सरकार के आपस में सम्बन्ध सन्धि द्वारा निर्धारित थे। परन्तु यह धारणा ठीक नहीं है क्योंकि वास्तव में देशी-रियासतें स्वतन्त्र राज्य नहीं थे। ब्रिटिश सरकार न केवल इनके बाह्य मामलों पर ही नियन्त्रण रखती थी अपितु इनके आन्तरिक मामलों में भी अन्तः-संगतवा ब्रिटिश सरकार का शब्द ही कानून था।

इन देशी रियासतों को यह अधिकार नहीं था कि वे किसी विदेशी राज्य से सम्बन्ध स्थापित कर सकें। उन्हें न केवल राजनैतिक परन्तु व्यापारिक सबंध स्थापित करने का भी अधिकार नहीं था। देशी रियासतों को यह अधिकार नहीं था कि वे किसी अन्य राज्य से युद्ध की घोषणा कर सकें अथवा सन्धि कर सकें। बिना सर्वोच्च सत्ता की अनुमति के वे अपनी भूमि का कोई भाग न बेच सकते थे और न किसी रियासत को दे सकते थे।

इस प्रकार बाह्य मामलों में इन रियासतों के हाथों में कोई अधिकार नहीं था। अगर हम आन्तरिक मामलों में दृष्टिपात करें तो वहाँ भी वस्तुतः वही स्थिति पायेंगे। अधिकतर देशी राज्यों में नरेशा की इच्छा ही कानून थी। अपने अपने क्षेत्र के अन्दर प्रत्येक रियासत दीक्षानी तथा फौजदारी दोनों मामलों में कानून बनाती थी तथा फैसला करती थी। राज्य के उच्चतम न्यायालय में निर्णय के विरुद्ध वही अपील नहीं हो सकती थी। वे अपने सामान्य प्रबंध के लक्ष्य के लिए करोड़ों का खर्चा करते थे। कुछ रियासतें जिनके पास समुद्रीतट था बाहर जाने वाले तथा भीतर आने वाले माल पर चुगी लगाती थी। १५ देशी रियासतों में अपना डाक-विभाग था और लगभग २० रियासतों में अपने मित्रों के चलते थे।<sup>१</sup> परन्तु इन सब बातों के होते हुए भी देशी रियासतें आन्तरिक क्षेत्र में भी स्वतन्त्र नहीं थीं। ब्रिटिश सरकार इनके आन्तरिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती थी तथा इनके कई बार हस्तक्षेप किया। कई राजाओं को विभिन्न कारणों

गद्दी से उतार दिया गया तथा उनके स्थान में उनके छटके को गद्दी पर बिठलाया गया। अगर रियासत की गद्दी के लिये उत्तराधिकार का कोई झगड़ा हो तो ब्रिटिश सरकार ही उसको तय करती थी। इसी प्रकार उत्तराधिकार नाबालिन (minor) होता था तो देशी रियासत का शासन-प्रबन्ध ब्रिटिश-सरकार द्वारा ही किया जाता था। अगर उन रियासतों में आपस कोई झगड़ा उठ खड़ा होता तो ब्रिटिश सरकार ही उसका निपटारा करती थी। इन रियासतों की सेना की संस्था निश्चित थी और वह बड़ाई नहीं जा सकती थी। इन राजानों को यहाँ तक अधिकार नहीं था कि वे अपनी रियासतों में कितना दना नकें। पुराने किले की मरम्मत भी वे बिना गवर्नर-जनरल की अनुमति के नहीं कर सकते थे।

ये रियासतें किसी विदेशी को अपनी रियासत में बिना भारत-सरकार की अनुमति के नौकर नहीं रख सकती थी। कोई भारतीय नरेश अपनी अपनी प्रजा बिना भारत सरकार के पासपोर्ट के विदेश नहीं जा सकते थे। यद्यपि देशी रियासतों में उनके ही कानून लागू थे तथापि छावनी, रेजीडेंसी, रेल की भूमि, तथा रियासत के अन्दर ब्रिटिश-प्रजा पर ब्रिटिश सरकार का ही कानून चलता था। इन रियासतों को अंग्रेजों को फाँसी देने का अधिकार भी नहीं था।

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि ये रियासतें कितनी भी भर्ष में स्वतन्त्र नहीं थी। किसी भी भारतीय नरेश के लिए अंग्रेज सरकार के विरुद्ध कोई काम कर अपनी गद्दी में दाग भर बैठे रहना असम्भव था। ब्रिटिश सरकार इन राज्यों के मामलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करती थी जब तक यह देखती थी कि यह नरेश कोई इस प्रकार का काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि अंग्रेजों के हितों को हानि पहुँचे। परन्तु ऐसा अगर कभी हुआ तो राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी।

**रियासतों में शासन-प्रबन्धः—**कुछ छोटी-सी रियासतों को छोड़ कर देश में प्राधुनिक भर्ष में कोई शासन-प्रबन्ध न था। नरेश की इच्छानुसार सब कुछ होता था। कानून आए दिन बदलते थे। कुछ भी निश्चित नहीं था। छोटी रियासतों में तो दया और भी खराब थी। कुछ राज्यों में तो एक प्रधान मंत्री तथा कुछ सहायक मंत्री होते थे। ये सब विषयों में नरेशों का मुँह ताकते थे क्योंकि वे तभी तक अपने पदों में थे जब तक कि ये इन नरेशों को प्रसन्न कर सकें। इसलिए यह स्वाभाविक था कि प्रजा की अधिक चिन्ता न कर ये नरेशों को प्रसन्न रखने की अधिक चिन्ता रखते थे। शासन में भ्रष्टचार बहुत अधिक था। पदाधिकारी अधिकतर अयोग्य थे। बड़े-बड़े पदों में आपलज नरे थे।

जनता का कानून बनाने में कोई भाग नहीं था। क्योंकि जनता के प्रतिनिधि कभी भी शासन-प्रबन्ध में शामिल नहीं किये गये। अधिकतर राज्यों में निरक्षर तथा स्वेच्छाचारी शासन था। कुछ राज्यों में विधान-मण्डल स्थापित हुये थे। परन्तु इनमें अधिकतर सदस्य सरकारी होते थे। गैरसरकारी सदस्य या तो मनांनीत किये जाते थे या उनका म्युनिसिपैलिटी आदि द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव होता था। इन विधान-मंडलों के पास यथार्थ में कुछ शक्ति नहीं थी। उनको न राज्य के कानून बनाने का अधिकार था और न आय-व्यय निश्चित करने का। अधिकतर ये विधान-मंडल केवल परामर्श देने के लिये थे। नरेश के पास यह अधिकार था कि इनकी बात माने या न माने।

करीबन ४० रियासतों में हाईकोर्ट थे तथा इनका संगठन ब्रिटिश भारत की तरह किया गया था। ३४ रियासतों में न्याय-विभाग तथा शासन विभाग प्रलग-प्रलग थे। करीबन ३० रियासतों में विधान मंडल थे। जहाँ तक स्थानीय स्वराज्य का प्रश्न है बहुत थोड़ी-सी रियासतों में इस ओर बढस उठाया गया था। वही वही म्युनिसिपैलिटी स्थापित की गई थी, परन्तु सरकारी सदस्य अधिक थे।

इन राज्यों में आय-व्यय का प्रबन्ध भी आधुनिक ढंग से नहीं होता था। करों के लगाने में आधुनिक कर-प्रणाली के किमी भी सिद्धान्त का पालन शायद ही किमी रियासत में किया गया हो। अधिकतर रियासतों में करों का लगाना, घटाना-बढ़ाना नरेश की इच्छा पर निर्भर था। हर साल नए कर लग जाते थे। इनसे जो आय होती थी उसका एक बड़ा भाग तो राजाओं के निजी खर्च के लिये खला जाता था। दूसरा बड़ा भाग राज्य कर्मचारियों के वेतन आदि में लग जाता था। केवल एक छोटा-सा भाग शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई के ऊपर खर्च होता था।

अधिकतर राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। केवल कुछ बड़ी रियासतों को छोड़कर शेष में उद्योग-धन्धों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था। इस कारण प्रमुख व्यवसाय खेती था। खेती भी पुराने ढंग से की जाती थी। इसलिए पैदावार कम थी। म्यान बहुत अधिक थे। जागीरदार, जमींदार, महाजन आदि उपज का एक बड़ा भाग हथिया लेते थे। इन सब कारणों से किसानों की दशा अत्यन्त शोचनीय थी। कुछ राज्यों में कल-कारखाने खुल गये थे। परन्तु इसका मुख्य कारण यह था कि यहाँ मजूरी बहुत सस्ती थी। इसलिये इनके खुलने से जनता को लाभ नहीं हुआ। मजदूरों की दशा भी अत्यन्त खराब थी।

सांस्कृतिक दृष्टि से भी रियासतें अत्यन्त पिछड़ी थीं। अधिकतर रियासतों में शिक्षा आदि का कोई भी प्रदत्त नहीं था। इन नये रियासतों में सब मिलाकर केवल दो विश्वविद्यालय थे। इतने दूर तक के स्कूलों की कुल संख्या ४०० से अधिक न थी। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय, मनोविनोदशालाएँ आदि का भी अभाव था। अधिकांश राज्यों में पत्र तथा पत्रिकाओं का भी अभाव था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन रियासतों की जनता अत्येक दृष्टि से पिछड़ी हुई थी।

**देशी रियासतें तथा भारतीय संघ :—**सन् १८५७ के विद्रोह के समय भारतीय रियासतों में अंग्रेजों रियासतों की बहुत अधिक सहायता की थी। इसके कारण १८५८ से ब्रिटिश सरकार ने इनके साथ उदार वर्तान करना शुरू कर दिया और यह भारतवासन दिया कि उनके क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप नहीं होगा। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने यह देखा लिया था कि भारतीय नरेश संकट-काल में सदा सहायक होंगे।

ब्रिटिश सरकार ने १९१७ के पश्चात् कुछ बड़ी रियासतों में रेजीडेन्स नियुक्त किये। अग्रे कई रियासतों के लिए एक रेजीडेन्ट होता था। छोटी रियासतों के लिये रिजिडेन्ट के नीचे पोलिटिकल एजेन्ट्स होते थे। इन सबका काम ब्रिटिश-हितों को देखना तथा इन नरेशों पर नियन्त्रण रखना था। नरेशों का प्रयत्न रहता था कि वे इन रेजीडेन्ट्स को प्रसन्न रखें। बहुत अनुचित नहीं होगा कि ये अधिकारी ही रियासतों में सर्वोच्च थे। नरेश इसके हाथों में केवल कठपुतली-भाग थे।

अब दोसवीं महायुद्ध में ब्रिटिश भारत में स्थित्यवस्था की जायना बढ़ने लगी तथा राष्ट्रीय आन्दोलन बढ़ने लगा, तो अंग्रेजों ने इन रियासतों को सम्पूर्ण भारत की राजनैतिक व्यवस्था के अन्दर लाने की सोचा। इसका फल यह हुआ कि जो कुछ सुधार अंग्रेजों को करने पड़ते उनका अन्तर सतत हो जाता। इसी-लिए अब १९१९ के ऐक्ट द्वारा कुछ सुधार किए गए, रियासतों का एक मंडल बनाया गया जिसको नरेश-मंडल (Chamber of Princes) कहा गया। इसकी स्थापना सन् १९२१ में सम्राट की घोषणा द्वारा हुई। इसमें १२० सदस्य थे। १०८ सदस्य तो १०८ बड़ी रियासतों के थे बाकी १२ सदस्य बाकी १२६ रियासतों के थे। बाकी १२६ रियासतों को इसमें प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया क्योंकि वे केवल जागीरें थीं। इस नरेश मंडल की सदस्यता कुछ बड़ी रियासतों ने स्वीकार नहीं की, जैसे हैदराबाद, भैसूर, बड़ौदा।

नरेश-मंडल स्थापित करने का उद्देश्य यह था कि सब विषयों पर जो कि ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों दोनों से सम्बन्धित थे, वाद-समाप रियासतों का मत जान सके।



इस समय भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन जोरा पर था। भारतीय नरेशों को यह चिन्ता हुई कि अगर ब्रिटिश भारत में लोकतन्त्रात्मक भावना बढ़ी तो वह शीघ्र ही इन रियासतों में भी पहुँचेगी और इसका परिणाम यह होगा कि उनके स्वच्छाचारी शासन का अन्त हो जायगा। दूसरी तरफ नरेशों ने यह देखा कि भारत की सरकार उनके ऊपर अपनी प्रधानता की मांग बढ़ाती जा रही है।<sup>1</sup> इसीलिए इन नरेशों ने यह माँग की कि रियासतों की समस्या पर एक कमेटी की स्थापना की जावे। इस कमेटी को बटलर कमेटी कहते हैं। इस कमेटी ने यह कहा कि सर्वोच्च शक्ति (Paramountcy) भारत की सरकार के हाथ में न होकर सम्राट के पास है। सम्राट यह शक्ति किसी भी भारत में स्थापित उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार को बिना नरेशों की सहमति के नहीं सौपेगा। इसका फल हुआ कि जब १०३५ का ऐक्ट बना उसमें देशी रियासतों की स्थिति बहुत अच्छी रही। उनको यह अधिकार रहा कि वे भारतीय सभ में आवे या न आवे। परन्तु १९३६ का ऐक्ट केन्द्र में लागू नहीं हुआ।

जब ३ जून १९४७ को भारत की वैधानिक समस्या पर ब्रिटिश सरकार ने सुझाव रखा तो भारतीय रियासतों के बारे में उसमें यह कहा गया है कि वे भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हो सकती हैं या स्वतन्त्र हो सकती हैं। यह उनकी इच्छा पर निर्भर है। जहाँ तक सम्राट की सर्वप्रधानता का प्रश्न था भारतीयों को शक्ति हस्तांतरित करते समय उसका अन्त हो जावेगा।<sup>2</sup> इस प्रकार भारत की नई सरकार के सामने समस्या उठ खड़ी हुई कि किस प्रकार इन रियासतों को भारत-सभ में लाया जावे।

**रियासतों में स्वतन्त्रता आन्दोलन** — यद्यपि रियासतों में जनता का अधिकांश भाग अशिक्षित था तथा आधुनिक सामाजिक तथा राजनैतिक शक्तियों के प्रति उदासीन था तथापि क्रमशः वहाँ भी चेतना का संचार होना प्रारम्भ हुआ। देशी रियासतों में भी नरेशों के स्वच्छाचारी तथा धर्म शासन का अन्त कर लोकतन्त्रात्मक प्रणाली की स्थापना के लिये आन्दोलन प्रारम्भ हुआ।

1 Punnaiah Constitutional History of India ■ 324

2 जुलाई १९४७ के भारतीय स्वतन्त्रता ऐक्ट में यह उपबन्ध था। कि 'एक निश्चित तिथि से "The suzerainty of His Majesty over the Indian states lapses, and with it all treaties and agreements in force at the date of the passing of this Act between His Majesty and the Rulers of the Indian States" Sec 7 (1) 6

परन्तु प्रत्येक रियासत में जहाँ इस प्रकार का आन्दोलन हुआ, नरेशों तथा उनकी सरकारों ने इसको दबाने में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। इन रियासतों की जनता को उसी प्रकार की—कभी कभी उनसे भी अधिक—शर्करा तथा नृशंसता का सामना करना पड़ा, जैसा कि ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आन्दोलन-कारियों को। रियासतों की जनता ने स्टेट्स कांग्रेस की स्थापना की। इनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महानभूति प्राप्त थी परन्तु यह उसका एक भाग नहीं था। रियासतों में आन्दोलन के विरुद्ध जो दमन हुआ उसका कारण एक ही यह था कि रियासतों के नरेश, सामन्त तथा अधिकारी वर्ग सभी लोक-तन्त्रात्मक प्रणाली से भयभीत थे, क्योंकि ऐसी प्रणाली में उनके लिए कोई स्थान नहीं था। दूसरी बात यह थी कि इन रियासतों में अंग्रेजी-सरकार के प्रतिनिधि गर्वशः आन्दोलन को भली-भाँति कुचलने के पक्ष में थे।

१९४७ के पश्चात् रियासतों की स्थिति — हम कह चुके हैं कि जुलाई १९४७ के ऐक्ट के द्वारा रियासतों के नामने तीन भाग खुले थे : (१) वे भारत में सम्मिलित हों; (२) वे पाकिस्तान में सम्मिलित हों; (३) वे स्वतन्त्र हो जावें। यद्यपि तीसरा मार्ग बचने बचिने था तथापि कुछ रियासतें इसका ही प्रबलम्बन करना चाहती थीं। परन्तु इन रियासतों की कठिन समस्या यह थी कि न इनकी रक्षा के लिये भारत में ब्रिटिश-सत्ता ही थी, और न इनको अपनी प्रजा का ही सहयोग प्राप्त था। इस कारण जिन रियासतों ने इस प्रकार का प्रयत्न किया भी उनको सफलता नहीं मिली। बावकोर, जुनागढ़ तथा हैदराबाद—इन तीनों को अन्त में भारत के ही अन्तर्गत माना पड़ा।

राज्यों की समस्या को सुलझाने के लिए ५ जुलाई १९४७ को भारत सरकार ने राज्य-विभाग की स्थापना की। इसका कार्य यह था कि यह सब रियासतों को भारत में सम्मिलित करे। सर्वप्रथम तो भारत की सरकार ने रियासतों से केवल यही माँग की कि वे तीन गृहलपूर्ण विषयों को—शांतायत, सुरक्षा, तथा परराष्ट्र विभाग—भारत को सौंप दें। यह कार्य करीबन १५ अगस्त १९४७ तक पूरा हो गया।

यह केवल पहला कदम था। इसके पश्चात् यह आवश्यक था कि वे छोटी-छोटी रियासतें जो कि भारत में सर्वत्र बिखरी हुई थीं, जिनके पास सुशासन के लिए न पैसा था और न कर्मचारी, अपने पड़ोसी प्रान्तों में विलीन हो जावें। रियासतें इसके लिए तत्पर हो गईं। क्योंकि इनमें से कई में इन समय जन-आन्दोलन ज़ोरों पर था और ये रियासतें उसे सँभाल सकने में असमर्थ थीं। इसलिए अपने ही हित में इन नरेशों ने अपनी रियासतों को प्रान्तों में विलीन करना स्वीकार

कर लिया। इसके फलस्वरूप २१६ रियासतें, जिनका क्षेत्रफल १०८,७३९ वर्गमील तथा जनसंख्या १,९१,५८,००० थी प्रान्तों में विलीन हो गई। इस प्रकार इनकी अलग सत्ता का अन्त हो गया तथा सब विषयों में ये प्रान्तों का ही भाग हो गई।

इनके अतिरिक्त अन्य रियासतें थी जो कि शासन की स्वावलम्बी इकाइयाँ होने के योग्य न थी। उनका क्षेत्र-विस्तार बहुत अधिक नहीं था, उनकी आय भी कम थी। इसलिए उन रियासतों को जो कि भौगोलिक दृष्टि से एक थी, प्राप्त में समुक्त कर, उनके सघ बना दिये गए। इसके फलस्वरूप निम्नलिखित रियासती सघ बने —

- (१) सौराष्ट्र सघ,
- (२) पटियाला और पूर्वी पंजाब रियासती सघ,
- (३) मध्य-भारत सघ,
- (४) त्रावणकोर-कोचीन सघ,
- (५) समुद्रन राजस्थान सघ।

इन सघों में 'ख' वर्ग के राज्यों का निर्माण हुआ। इनका मुखिया राज-प्रमुख कहलाता था। इसके अतिरिक्त उपराजप्रमुख भी नियुक्त हुए। किसी सघ में सम्मिलित रियासतों में से सबसे मुख्य का राजा राजप्रमुख बनाया गया। इस वर्ग में पहले विन्ध्यप्रदेश भी था। परन्तु वहाँ शासन-प्रबन्ध ठीक न होने के कारण बाद में वह 'ग' वर्ग के राज्यों की कोटि में रख दिया गया। इन ५ रियासती सघों का क्षेत्रफल १,१५,४५० वर्ग मील तथा जनसंख्या ३,४६९९,००० थी। इन सघों के अन्तर्गत २७५ रियासतें सम्मिलित थी।

शेष रियासतों में से ६१ रियासतें 'ग' वर्ग में रखी गई थी। उनको ७ राज्यों में संगठित किया गया है। ये राज्य निम्नलिखित थे —

- (१) हिमाचल प्रदेश,
- (२) वरुछ,
- (३) बिलासपुर,
- (४) भोपाल,
- (५) त्रिपुरा,
- (६) मनीपुर,
- (७) विन्ध्य-प्रदेश।

इनका कुल क्षेत्रफल ६३,७०४ वर्गमील तथा जनसंख्या ६९ लाख थी ये राज्य केन्द्र द्वारा शासित थे।

तीन रियासतों जो कि क्षेत्रफल तथा आय दोनों दृष्टियों से काफी बड़ी थी भारत सभ की डकाइयाँ बना ली गई। वे मैसूर, हैदराबाद तथा काश्मीर की रियासत थी। मैसूर के भारत में सम्मिलित होने में कोई विशेष बात नहीं हुई। हैदराबाद में रजाकारों के उपद्रव के कारण तथा वहाँ के शासन की पड़-पड़ोसी नीति के कारण भारत की सेना वहाँ प्रवेश कर गई और १९४९ के अंत में यह भारत का भाग हो गया था। काश्मीर नरेश भी अपने राज्य को स्वतंत्र बनाना चाहता था, परन्तु वह इसलिये भारत में सम्मिलित होने को बाध्य हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने उस क्षेत्र में कबायली इलाके वालों को आक्रमण करने भेज दिया। इस प्रकार काश्मीर भी भारत में सम्मिलित हो गया। (काश्मीर की स्थिति पर आगे अधिक विस्तारपूर्वक विचार किया गया है।)

**नरेशों का प्रिवी पस :-** जब तक इन रियासतों का शासन भारत से अलग था इसके नरेश रियासतों की आय का एक बड़ा भाग अपने ऊपर या अपने रिश्तेदारों, आदि के ऊपर खर्च कर देते थे। राजाओं के खर्च के विविध मद ये—नाक-बाना, विदेश, यात्रा, मोटरकारें, महल बनवाना, या अन्य भोग विलास की वस्तुएं। परन्तु स्वतन्त्र भारत में सम्मिलित होने के बाद उनका व्यक्तिगत व्यय निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक नरेश का प्रिवी-पस उसके भारत सरकार से हुए समझौते में वर्णित कर दिया गया। इसका निश्चय इस प्रकार किया गया। प्रत्येक नरेश को अपनी रियासत की वार्षिक आय के प्रथम १ लाख पर १५ प्रतिशत, इसके पश्चात् दूसरे लाख से ५ लाख तक १० प्रतिशत तथा इसके बाद की आय पर ७½ प्रतिशत दिया गया। परन्तु किसी भी दशा में यह १० लाख वार्षिक से अधिक नहीं रखा गया। परन्तु कुछ रियासतें ऐसी थी जिनके नरेशों को इससे अधिक दिया गया। जैसे, हैदराबाद के निजाम को ५० लाख वार्षिक या बढ़ोदा को २६ लाख वार्षिक वेना निश्चित हुआ। इसके अतिरिक्त जयपुर जोधपुर, बीकानेर, गटियाला, भावनकोर, इन्दौर, मैसूर के नरेशों को भी १० लाख से अधिक दिया गया। परन्तु यह प्रबन्ध केवल वर्तमान शासकों के साथ ही किया गया था। उनके उत्तराधिकारियों को १० लाख की सीमा के अन्दर ही दिया जायगा।

**'ग' वर्ग के राज्य—**इस वर्ग में १० राज्य थे। इनमें से तीन सविधान के प्रारम्भ होने के पूर्व चीफ-कमिश्नर के प्रान्त कहलाते थे। ये दिल्ली, भजनेर तथा कोङ्ग थे। इनके अतिरिक्त इस वर्ग में कुछ देशी रियासतें भी रक्ती गई

थी। गविवधान में यह कहा गया था कि इनका शासन केन्द्र द्वारा होगा। परन्तु सितम्बर सन् १९५१ के 'ग' राज्य सम्बन्धी विधेयन द्वारा इनमें से छह राज्यों को सीमित स्वायत्त शासन का अधिकार दिया गया था। इस वर्ग में निम्नलिखित राज्य थे

अजमेर, कच्छ, कोडग, त्रिपुरा, दिल्ली विलासपुर, भोपाल, मनीपुर, हिमाचल प्रदेश, विन्ध्य प्रदेश।

सविधान की धारा २३९ (सप्तम् सशोधन के पूर्व) के अनुसार 'ग' भाग के राज्यों के शासन के लिये राष्ट्रपति उत्तरदायी था। उसे इनके शासन के लिये चीफ-कमिशनर या लेफ्टिनेन्ट गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। ससद् को इन राज्यों के शासन के लिये विधान-मंडल बनाने का अधिकार सविधान द्वारा दिया गया था। ससद् को इन राज्यों में परामर्शदाताओं अथवा मन्त्रियों की कौंसिल बनाने का भी अधिकार दिया गया था।

ससद् ने सितम्बर १९५१ में 'ग' वर्ग के राज्यों के लिये एक ऐक्ट पास किया था, जो Part C States Act 1951 कहलाता था। इस ऐक्ट के द्वारा कुछ राज्यों में विधान-मंडल तथा कुछ राज्यों में परामर्श समिति की स्थापना की गई थी। परन्तु यह नहीं सोचना चाहिये कि इस ऐक्ट द्वारा 'ग' वर्ग के राज्यों में संघीय शासन का अर्थ है कि राज्य का शासन संघ द्वारा किया जाता है।

(१) दिल्ली, अजमेर, कोडग, भोपाल, हिमाचल प्रदेश तथा विन्ध्य प्रदेश में एक निर्वाचित विधान सभा की स्थापना की गई थी। इनके सदस्यों की संख्या इस प्रकार रखी गई थी दिल्ली-४८; अजमेर-३०, कोडग-२४, भोपाल-३०; हिमाचल प्रदेश-३६ तथा विन्ध्य प्रदेश-६०। इनमें से कुछ स्थान हर्जिनो के लिये तथा भोपाल, वाटग और विन्ध्य प्रदेश में कुछ स्थान जन जातियों के लिये सुरक्षित रखे गये थे।

इन विधान-सभाओं का कार्यालय सामान्यतः ५ वर्ष का था परन्तु आयात उद्घाषणा काल में बढ़ाया भी जा सकता था। प्रत्येक विधान सभा में एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता था। प्रत्येक सदस्य को स्थान ग्रहण करने के पूर्व एक शपथ लेनी पड़ती थी।

इन विधान-मंडलों को राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर विधि-निर्माण का अधिकार दिया गया था। परन्तु यदि इनका कोई कानून

संसद् के कानून का विरोधी हो तो संसद् के कानून को ही प्राथमिकता तथा प्रधानता दी गई थी। क्योंकि दिल्ली सभ की राजधानी है, इसलिये दिल्ली के विधान-मंडल के अधिकार अन्य विधान मंडलों से अधिक संकुचित रखे गये थे। जैसे सुरक्षा, सशस्त्र, पुलिस तथा रेलवे पुलिस, नगरपालिका तथा अन्य स्थानीय शक्तियों और मद्रास सम्बन्धी कानून बनाने का अधिकार इसको नहीं था।

'ग' वर्ग के राज्यों के विधान मंडल कई विषयों जैसे, राज्य सेवा आयोग, जजिसियल कमिश्नर की मद्रास का विधान तथा गवर्नर, आदि, पर चीफ कमिश्नर (या लेफ्टिनेंट गवर्नर) की आज्ञा के बिना विधेयक नहीं पास कर सकते थे। इसी प्रकार वित्तीय विधेयक भी कामकारिणी के ही उत्तरदायित्व पर पेश हो सकते थे। प्रत्येक विधेयक को विधान मंडल द्वारा पारित हो जाने पर चीफ कमिश्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर राष्ट्रपति के विचाराधीन प्रस्तुत करता था।

(२) इन राज्यों में चीफ कमिश्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को मन्त्रिणा देने के लिये एक मन्त्रिमंडल होता था। परन्तु चीफ कमिश्नर केवल नाम मात्र का ही प्रधान नहीं था। वह मन्त्रिमंडल की बैठकों में सभापति का आसन ग्रहण करता था। उसकी अनुपस्थिति में मुख्य मंत्री यह स्थान ग्रहण करता था। यदि चीफ कमिश्नर का किसी विषय में मन्त्रिमंडल से मतभेद हो जाय तो यह प्रवृत्त था कि वह राष्ट्रपति के विचारार्थ उसके द्वारा भेजा जाता और राष्ट्रपति का निर्णय मन्त्रिमंडल निर्णय था। दिल्ली में चीफ कमिश्नर का मन्त्रिमंडल के ऊपर और भी अधिक अधिकार थे। कुछ विशेष परिस्थितियों में वह बिना मन्त्रिमंडल के राज्य के ही निर्णय ले सकता था।

चीफ कमिश्नर (लेफ्टिनेंट गवर्नर) तथा उसका मन्त्रिमंडल राष्ट्रपति के सामान्य नियन्त्रण में रखे गये थे।

(३) कुछ 'ग' वर्ग के राज्यों में विधान सभा की स्थापना नहीं की गई थी परन्तु इनके स्थान पर परामर्शदात्री समितियों को नियुक्त की प्रवृत्त किया गया था। इस समिति की स्थापना का अधिकार राष्ट्रपति को था तथा उसके सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पदों में रहते थे। मनीपुर में इस प्रकार की समिति की स्थापना की गई थी।

'घ' वर्ग के राज्य :-—उस वर्ग में अन्धमान तथा निकोबार द्वीप रखे गये थे। इन क्षेत्रों का शासन राष्ट्रपति चीफ कमिश्नर या किसी अन्य अधिकारी द्वारा करता था। इन राज्यों के लिये संसद् द्वारा निर्मित किसी भी कानून को राष्ट्रपति रद्द कर सकता था। उसको इनके लिये नियम (Regulations) बनाने का अधिकार था।



कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी इस प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण था।

**राष्ट्रीय कांग्रेस तथा पुनर्गठन का प्रश्न :—**राज्यों के पुनर्गठन के प्रश्न पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति बहुत पहले से ही स्पष्ट थी। कांग्रेस का यह मत था कि ब्रिटिश शासन ने भारत का घनेकोँ प्रान्तों तथा प्रदेशों में विभाजन किसी वैज्ञानिक आधार पर नहीं किया था। यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि ब्रिटिश शासन ने इन प्रान्तों के निर्माण में अपनी सामाजिक, राजनैतिक, तथा प्रशासकीय आवश्यकताओं तथा सुविधाओं को ध्यान में रखा न कि देश के हित को। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि "The existing structure of the states of the Indian Union is partly the result of accident and the circumstances attending the growth of the British power in India and partly a by-product of the historic process of the integration of former Indian states. The division of the states into British provinces and princely states had no basis in Indian history. It was the result of that, as a result of the abandonment, after the upheaval of 1857, of the objective of extending the British dominion by absorbing princely territories, the surviving states escaped annexation. The map of the territories annexed and directly administered by the British was also not shaped by any rational or scientific planning but by the military, political or administrative exigencies or conveniences of the moment."

कांग्रेस ने भाषा-सिद्धान्त को सन् १९०२ से ही अपना समर्थन प्रदान किया है जब कि इसने बंगाल-विभाजन का विरोध किया। इसी सिद्धान्त के आधार पर सन् १९०८ में कांग्रेस का बिहार प्रान्त तथा १९१७ में धान्य तथा सिन्ध के कांग्रेस प्रान्तों का निर्माण हुआ। परन्तु यह सत्य है कि १९१७ के कांग्रेस अधिवेशन में डा० ऐनी बेसेन्ट के नेतृत्व में कुछ लोगो ने इस सिद्धान्त का घोर विरोध किया। परन्तु सन् १९२० में नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के सिद्धान्त को स्वीकार किया। सन् १९२७ में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वारा यह घोषणा की कि प्रान्तों का भाषा के आधार पर निर्माण होना चाहिये।

प्रान्तों के पुनर्गठन के प्रश्न पर नेहरू कमेटी का भी यही विचार था कि यह भाषा के आधार पर होना चाहिये। इसके अनुसार, "यह सत्य है



वाञ्छनीय है कि प्रान्तों का पुनर्संगठन भाषा के आधार पर हो। भाषा सामान्यतः एक विशिष्ट मस्कृति, परम्परा तथा साहित्य की सूचक है। एक भाषा-क्षेत्र में ये सब कारण प्रान्त की उत्पत्ति में सहयोग देते हैं।”

कांग्रेस ने सन् १९३७ में कलकत्ता अधिवेशन में तथा सन् १९३८ में वाघा में इसकी कार्यकारिणी समिति ने इस सिद्धान्तों का समर्थन किया। १९४५-४६ में अपने चुनाव-घोषणा में भी कांग्रेस ने इस मत को दुहराया कि प्रान्तों का निर्माण भाषा के आधार पर होना चाहिये।

सन् १९४७ में मविधान सभा की स्थापना हुई और इसने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक आयोग को नियुक्ति की जिसे दर आयोग (Dar Commission) कहा जाता है। इस आयोग ने दिसम्बर, १९४८ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा यह कहा कि केवल भाषा के आधार पर प्रान्तों का पुनर्गठन अनुपयुक्त है, मुख्यतः ध्यान प्रशासनीय सुविधा पर रखना चाहिये।

इसके पश्चात् दिसम्बर १९४८ में कांग्रेस ने एक समिति का निर्माण किया, जिसको जे० वी० पी० ( J. V. P. ) समिति कहा जाता है। इसके सदस्य श्री नहरू, सरदार पटेल तथा डा० पट्टाभि सीतारमैया थे। इस समिति के अनुसार प्रान्तों का पुनर्संगठन देश की एकता के अहित में नहीं किया जा सकता। अतएव भारत की सुरक्षा, एकता तथा आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखते हुये ही यह किया जा सकता है। भाषावार प्रान्तों के निर्माण में अत्यन्त ही सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए इस समिति का यह मत था कि यह प्रश्न स्थगित कर दिया जाय परन्तु यह आन्ध्र प्रदेश के निर्माण के पक्ष में थी।

आन्ध्र का निर्माण जैसा हम देख चके हैं १ अक्टूबर, १९५३ में किया गया। इसके पश्चात् ही राज्य पुनर्संगठन आयोग की स्थापना की गई।

आयोग की रिपोर्ट — राज्य पुनर्संगठन आयोग की रिपोर्ट ३० सितंबर १९५५ को भारत सरकार को पेश की गई थी और सरकार द्वारा इसका प्रकाशन १० अक्टूबर को किया गया।

भारत सरकार ने जिस प्रस्ताव द्वारा राज्य पुनर्संगठन आयोग की स्थापना की गई थी उसमें यह भी कहा गया था इस समस्या पर विचार करने समय आयोग को निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिये।

- (१) भारत की एकता तथा सुरक्षा;
- (२) भाषा तथा मस्कृति की समानता;

- (३) वित्तीय, आर्थिक तथा प्रशासकीय सुविधा; तथा  
(४) राष्ट्रीय योजना की सफलता।

राज्य-पुनर्संगठन आयोग इस विषय में एहमदन था कि देश के अन्दर गणराज्य का निर्माण एक वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिये। अंग्रेजों ने प्रान्तों का निर्माण इस प्रकार नहीं किया था। विदेशी शक्तों के सम्मुख देश का हित तथा देश की उन्नति शेष विषय थे। उनके लिये तो प्रमुख विषय यह था कि उनके प्रशासन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। जहाँ तक भारत का ब्रिटिश प्रान्तों तथा देशों राज्यो में विभाजन का यह भी केवल पञ्चापराय ही गया था। यह विभाजन देश के हित में नहीं था। इसके फलस्वरूप देश का समग्र भाग भाग (४५%) क्षेत्र) उन्नति नहीं कर सका और यहाँ की जनता अत्यन्त ही पिछड़ी स्थिति में रह गई। यद्यपि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् इस विषय में सुधार हुआ परन्तु मूलस्थिति में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ।

आयोग के अनुसार पुनर्संगठन की किसी भी योजना को निम्नलिखित तत्वों पर पूरा ध्यान देना चाहिये :—

(१) पुनर्संगठन की किसी भी योजना को यह सदा ध्यान में रखना चाहिये कि इसका उद्देश्य भारत की एकता तथा सुरक्षा है। यदि देश की एकता की बिना भी प्रकार धन्य पहुँचता है तो यह योजना देश की एकता के हित में नहीं हो सकती। यह नहीं भूलना चाहिये कि देश के विभिन्न भागों का स्थिति इसी में है कि भारत की एकता प्रबल रहे। विभिन्न भाषा-भाषी प्रदेशों को भारत के अन्दर समाविष्ट करने की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिये। परन्तु देश की एकता देश की सुरक्षा के लिये आवश्यक है।

(२) केवल भाषा समवा संस्कृति के आधार पर ही राज्यों का पुनर्संगठन न सम्भव है और न वांछनीय ही है। इन समस्याओं के उचित प्रकार समाधान के लिये एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है ताकि देश की एकता को भंग न उत्पन्न हो। इन प्रकार के संतुलित दृष्टिकोण के लिये निम्नोक्त बातें आवश्यक हैं। —

(अ) यह मानना चाहिये कि भाषा की एकता एक महत्वपूर्ण बात है, जिससे प्रशासकीय सुविधा तथा कुशलता में वृद्धि होगी, परन्तु केवल इस निदान को इतना अधिक धनिकार्य नहीं मानना कि चरता कि प्रशासकीय विधाय तथा राजनीतिक बातों पर ध्यान ही न दिया जाय।

(ब) इस बात का ध्यान रखना होगा कि विभिन्न भाषा-भाषी समूहों की सभार शिक्षा तथा संस्कृति सम्बन्धी आवश्यकताओं की उचित प्रकार पूर्ति हो, चाहे वे एक भाषा-भाषी राज्य में हो अथवा मिश्रित राज्य में।

(म) जहाँ सन्तोषजनक परिस्थितियाँ हैं तदा आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक, सुविधाएँ वर्तमान हो वहाँ मिश्रित (Composite) राज्य बने रहने चाहिये, परन्तु इस बात की व्यवस्था होनी चाहिये कि इनमें सभी वर्गों को समान अधिकार तथा अवसर प्राप्त हो।

(द) निवास-स्थान सिद्धान्त (Homeland concept) का स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह भारतीय सुविधान के इस आधारभूत सिद्धान्त के प्रतिकूल है कि सभ के अन्तर्गत समस्त नागरिकों का समान अवसर तथा अधिकार प्राप्त है।

(य) एक भाषा एक राज्य का सिद्धान्त स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह भाषा की समानता के आधार पर उचित नहीं है क्योंकि बिना भाषा-निदान्त का उल्लंघन किये एक ही भाषा बोलने वालों के एक से अधिक राज्य हो सकते हैं। यह सिद्धान्त व्यावहारिक भी नहीं है क्योंकि यह सदैव सम्भव नहीं कि एक ही भाषा बोलने वालों को, जैसे देश की हिन्दी भाषी विशाल जनसंख्या, एक-भाषी राज्य में ही समाहित किया जा सके।

(र) अन्त में यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि एक भाषा-भाषी राज्यों निर्माण ने जो पृथक्ता तथा प्रांतीयता की भावना जागृत होगी उसके नकारण के लिये यह आवश्यक है कि भारतीय राष्ट्रवाद को अनेक प्रकार से अधिक गहन तथा मज्झीर बनाया जाय।

(३) राज्यों के पुनर्गठन में आर्थिक तथा वित्तीय बातों पर भी ध्यान देना चाहिये। राज्यों को आर्थिक दृष्टि से इतना सम्पन्न तो होना चाहिये कि माधारणतः वे अपना व्यय-भार स्वयं वहन कर सकें। यह सत्य है कि केन्द्रीय सहायता आवश्यक हो जाती है परन्तु इसका उपयोग विकास-कार्यों के लिये हो जाना चाहिये।

(४) यद्यपि यह सत्य है कि राज्यों का इस प्रकार पुनर्गठन नहीं हो सकता कि वे आर्थिक क्षेत्रों के अनुरूप हो। न आर्थिक निर्भरता का सिद्धान्त ही स्पष्ट मान्य है। परन्तु यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिये कि विकास कार्य के लिये जो साधन आवश्यक हैं उनका कुछ भाग वे अवश्य ही जुटा सकें। यह वांछनीय ही होगा कि राज्यों के मध्य मयासम्भव आर्थिक साधनों में अधिक भेद नहीं हो।

(५) राज्य इतने बड़े हों कि उनमें प्रशासकीय कुशलता हो तथा मार्षिक विकास और लोक-कल्याण कार्यवाहियों के मध्य संयोजन हो सके।

(६) पुनर्गठन के प्रश्न पर अन्य बातों के साथ जनता की इच्छा को भी महत्व देना चाहिये।

(७) वर्तमान स्थिति के तथ्यों को मार्षिक महत्व देना चाहिये न कि ऐतिहासिक तर्कों को।

(८) प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से केवल भौगोलिक समीपता पर ध्यान देना चाहिये।

(९) पुनर्गठन के प्रस्ताव केवल किसी एक ही बात पर निर्भर नहीं हो सकते। किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के पूर्व उपर्युक्त सभी बातों पर ध्यान देना आवश्यक है।

इकाइयों का मूल रूप :—पुनर्गठन आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यों का विभिन्न वर्गों में वर्तमान विभाजन उचित नहीं है। 'ख' वर्ग तथा 'क' वर्ग के मध्य भेद मिटाने के लिये राजप्रमुख के पद को समाप्त कर देना चाहिये और राज्यपालों की नियुक्ति होनी चाहिये। 'ग' वर्ग के राज्यों को अपने समीपस्थ बड़े राज्यों में समाश्लिष्ट कर देना चाहिये। केवल हिमाचल प्रदेश, कच्छ तथा अजमेर के ऊपर केन्द्रीय सरकार के कुछ नियोजन के अधिकार रहेंगे। वे 'ग' वर्गीय राज्य जिनका किसी कारणों से विलय नहीं हो सकता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा शासित होंगे। इस प्रकार भारत संघ में केवल दो प्रकार की इकाइयाँ होंगी। संघ की प्राथमिक इकाइयाँ तथा केन्द्रीय शासित क्षेत्र।

आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सोलह प्राथमिक इकाइयाँ तथा तीन केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्र होंगे। ये निम्नलिखित हैं :—

### संघ की प्राथमिक इकाइयाँ

राज्यों के नाम	क्षेत्रफल	जन-संख्या
मद्रास	५०,१७० वर्ग मील	३ करोड़
केरल	१४,९८० "	१ करोड़ ३६ लाख
कर्नाटक	७२,७३० "	१ करोड़ ९० लाख
हैदराबाद	४५,३०० "	१ करोड़ १३ लाख
गोवा	६४,९१० "	२ करोड़ ९ लाख

राज्यों के नाम	क्षेत्रफल	जनसंख्या
बम्बई	१५१,३६० वर्ग मील	४ करोड २ लाख
बिदभ	३६,८८० "	७६ लाख
मध्य प्रदेश	१७१,२०० ,	२ करोड ६१ लाख
राजस्थान	१३२,३०० "	१ करोड ६ लाख
पंजाब	५८,१४२ "	१ करोड ७२ लाख
उत्तर प्रदेश	११३,४७० ,	६ करोड ३२ लाख
बिहार	६६,१२० ,	३ करोड ८५ लाख
पश्चिमी बंगाल	३६,१९० ,	२ करोड ६५ लाख
आसाम	८०,०४० ,	९७ लाख
उड़ीसा	६०,१४० ,	१ करोड ४६ लाख
जम्मू तथा काश्मीर	२२,७८० ,	४४ लाख

### केन्द्रीय शासित क्षेत्र

क्षेत्र	क्षेत्रफल	जनसंख्या
दिल्ली	५७८ वर्ग मील	१,७४४,०७२
मणिपुर	८,६२८ ,	५७७,६०५
अण्डमन तथा निकोबार	३,२११ "	३०,९७१

राज्यपुनर्गठन ऐक्ट —अयोग की इसी रिपोर्ट पर आधारित कर भारत सरकार ने ससद् में एक विधेयक प्रस्तुत किया और यह विधेयक ससद् द्वारा पारित होकर राज्य पुनर्गठन ऐक्ट कहलाया। ३१ अगस्त १९५६ को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इसे प्रभावी करने के लिए सविधान में संशोधन की आवश्यकता हुई। यह सविधान का सप्तम् संशोधन अधिनियम कहलाता है।

इस राज्य पुनर्गठन ऐक्ट की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं —

(१) इस अधिनियम द्वारा स्वायत्त राज्यों का 'क' तथा 'ख' वर्ग में विभाजन समाप्त कर दिया गया। सम्पूर्ण भारत क्षेत्र को दो प्रकार की इकाइयों में बाँटा गया है। इनको क्रमशः राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्र कहा गया है। 'ख' वर्ग के राज्यों के लुप्त हो जाने के कारण राजप्रमुख के पद का भी लोप हो गया है। इन तवीन स्वायत्त राज्यों की जिनका शासन उत्तरदायित्वपूर्ण है सख्या १४ है। ये निम्नलिखित हैं —

राज्यों के नाम	क्षेत्रफल	जनसंख्या
(१) आंध्र	१०५,९६२	३१,२६०,१३३
(२) आसाम	७५,०१२	९,०४३,७०७
(३) बिहार	६७,१४६	३८,७०९,४६२
(४) बम्बई	१९०,९१९	४८,२६५,२२१
(५) केरल	१५,०३५	१३,५४९,११८
(६) मध्य भारत	१७१,२०१	२६,०७१,६३७
(७) मद्रास	५०,११०	२९,९७४,९३६
(८) मसूर	७४,३६७	१९,४०१,१९३
(९) उड़ीसा	६०,१३६	१४,६४५,९४६
(१०) पंजाब	४७,४२६	१६,१३५,८९०
(११) राजस्थान	१३२,०७८	१५,९७०,७७४
(१२) उत्तर-प्रदेश	११३,४०९	६६,२१५,७४२
(१३) पश्चिमी बंगाल	३३,९५८	२६,३०६,६०२
(१४) जम्मू तथा काश्मीर	९२,७८०	४,१००,०००

उपर्युक्त राज्यों के प्रधान, जम्मू तथा काश्मीर के अतिरिक्त, राज्यपाल कहलाते हैं तथा इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। काश्मीर राज्य का प्रधान सदर-ई-रियासत कहलाता है। इसी नियुक्ति राष्ट्रपति वहाँ पर अध्यक्षतापिका की सिफारिश पर करता है। परन्तु इन सब राज्यों की संविधान के अन्तर्गत एक ही स्थिति है। ये सब स्वायत्त राज्य हैं। परन्तु काश्मीर की स्थिति अभी भी कुछ मात्रा तक विशेष है।

चार राज्यों में हुए अधिनियम द्वारा कोई क्षेत्रीय तथा सीमा-सम्बन्धी परिवर्तन नहीं हुए। ये राज्य जम्मू तथा काश्मीर, उत्तर प्रदेश, आसाम तथा उड़ीसा हैं। बिहार के दो छोटे टुकड़े पश्चिमी बंगाल में मिला दिये गये हैं। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद रियासत का तेलंगाना क्षेत्र मिला दिया गया है। बम्बई राज्य में पुराने हैदराबाद रियासत का मरमवाड़ा क्षेत्र, राजस्थान का एक छोटा टुकड़ा तथा पुराने मध्य प्रदेश का विद्वर क्षेत्र मिला दिये गये हैं। नवीन मसूर राज्य में करनाटक क्षेत्र, कोडग, मद्रास का दक्षिणी कन्नड़ जिला तथा कोलेगन तालुक मिला दिये हैं। मद्रास का मलवार प्रदेश केरल में मिला दिया गया है। मध्य प्रदेश में पुराना मध्य भारत, भोपाल, विन्ध्य प्रदेश तथा राजस्थान का एक छोटा सा भाग मिला दिये गये हैं। पेप्पू को पंजाब में विलीन कर दिया गया है।

इन मन्त्रीय राज्या का आधार भाषा है। इसी कारण दक्षिण भारत में विशेषतः राज्य-पुनर्गठन की माग बहुत बलवती थी। परन्तु दो राज्यों के निर्माण में यह गिद्दान लागू नहीं हो सका है—जम्मू तथा पञ्जाब। इस कारण जम्मू में काफी असन्तोष है।

इन स्वायत्त राज्या के अतिरिक्त ६ संघीय क्षेत्रों का निर्माण किया गया है। 'ग' तथा 'घ' वर्ग के मध्य भेद समाप्त हो गया है।

संघीय क्षेत्र	क्षेत्रफल	जनसंख्या
हिमाचल प्रदेश	१०,९०४	१,१०९,६६६
मनीपुर	८,६२८	४७७,६३४
त्रिपुरा	१,०३८	६३०,०२९
दिल्ली	१३८	३४४,०७२
अण्डमान तथा निकोबार	३,७१४	३०,९७१
लक्षद्वीप समूह	१०	२१,०३५

इन मन्त्रीय क्षेत्रों में स्वायत्त शासन नहीं है। राष्ट्रपति इनका शासन एक शासन के द्वारा करेगा।

(२) राज्य का पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पाँच मण्डलीय परिषदों (Zonal Councils) की स्थापना की गई है। निम्नलिखित प्रत्येक मंडल में एक ऐसा परिषद् होगी—

(१) उत्तरी मण्डल—इसमें पञ्जाब, राजस्थान, जम्मू तथा काश्मीर, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश रखे गये हैं।

(२) केन्द्रीय मण्डल—इमें उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश हैं।

(३) पूर्वी मण्डल—इसमें बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आसाम, मनीपुर तथा त्रिपुरा रखे गये हैं।

(४) पश्चिमी मण्डल—जम्मू तथा मैसूर राज्य इसके अन्तर्गत हैं।

(५) दक्षिणी मण्डल—आंध्र, मद्रास तथा केरल के राज्य इसमें आते हैं। प्रत्येक मंडल की मंडलीय परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे—

- (१) राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक सचिव;
- (२) इसके अन्तर्गत प्रत्येक राज्य का मुख्य मन्त्री तथा प्रत्येक ऐसे राज्य में दो अन्य मन्त्री जो कि काश्मीर में सदर-इ-रियासत द्वारा तथा अन्य राज्यों में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जायेंगे। परन्तु यदि किसी राज्य में मन्त्रिपरिषद् न हो तो उस राज्य से तीन सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।
- (३) यदि किसी मण्डल में कोई सच द्वारा शासित क्षेत्र सम्मिलित है तो ऐसे प्रत्येक क्षेत्र से राष्ट्रपति द्वारा दो सदस्य मनोनीत किये जायेंगे।
- (४) अनुमूर्चन क्षेत्र के निम्न नाम के राज्यपाल का परामर्शदाता भी पूर्वी मंडल की परिषद् का एक सदस्य होगा।

राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सहाय मन्त्री मंडलीय परिषद् का सभापति होगा। राष्ट्रपति द्वारा केन्द्रीय गृह मन्त्री प० गोविन्दवल्लभ पन्त को पाँचों मंडलीय परिषदों का सभापति नियुक्त किया गया है। प्रत्येक मंडल में सम्मिलित राज्यों के मुख्य मन्त्री नामानुसार इनकी परिषद् के उपसभापति होंगे। प्रत्येक का कार्य-काल एक वर्ष होगा। परन्तु यदि इस समय किसी राज्य में मन्त्रिमंडल न हो तो राष्ट्रपति वहाँ के किसी सदस्य को मंडलीय परिषद् का उपसभापति मनोनीत कर सकता है।

प्रत्येक मंडलीय परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति परिषद् को इसके कार्य में सहायता देने के लिये परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्त किये जायेंगे।

- (अ) एक व्यक्ति योजना आयोग द्वारा नियुक्त किया जाएगा;
- (ब) उस मंडल के अन्तर्गत प्रत्येक सम्मिलित राज्य की सरकार का मुख्य सचिव (Chief-Secretary);
- (क) उन मंडल के अन्तर्गत प्रत्येक सम्मिलित राज्य का विकास आयुक्त अथवा राज्यपाल द्वारा मनोनीत कोई अन्य पदाधिकारी।

उपयुक्त प्रत्येक परामर्शदाता को परिषद् के वादाविवाद अथवा किसी कमेटी के, जिसका वह सदस्य बनाया गया हो, वादाविवाद में भाग लेने का अधिकार होगा परन्तु उसे परिषद् अथवा कमेटी में मतदान का अधिकार नहीं होगा।

मंडलीय परिषद की बैठक कब हो इसकी तिथि इसके सभापति द्वारा निर्दिष्ट की जावेगी। इसकी बैठकों में ऐसे प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का पालन किया



जायगा जा कि सभापति केन्द्रीय सरकार ने मन्त्रणा कर समय समय पर निर्दिष्ट करे।

परिषद् की बैठके उस मण्डल के अन्तर्गत राज्यों में सम्पन्न होगी। यदि

इन बैठकों में प्रत्येक प्रश्न का निणय बहुमत द्वारा होगा। परन्तु यदि किसी प्रश्न में मत बराबर हो तो सभापति का एक मत और प्रदान करने का अधिकार होगा। परिषद् की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही का विवरण केन्द्रीय सरकार तथा सदस्य राज्य सरकारों को भेजा जायगा।

मण्डलीय परिषद् समय समय पर प्रस्ताव पारित कर अपने सदस्यों तथा परामर्शदाताओं की कमेटीया नियुक्त कर सकती है। ये कमेटीया ऐसे कार्य सम्पादन करेंगी जैसा करने का अधिकार इन्हें मण्डलीय परिषद् द्वारा प्रदान किया जायगा।

प्रत्येक मण्डलीय परिषद् का एक सचिवालय कर्मचारीवर्ग (Secretariat Staff) होगा। इसमें एक सचिव, एक सयक-सचिव तथा ऐसे अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी होंगे जिनकी नियुक्ति सभापति करना आवश्यक समझे। प्रत्येक परिषद् के अन्तर्गत सम्मिलित प्रत्येक राज्य का मुख्य सचिव बारी-बारी से उस परिषद् का एक एक वर्ष के लिये सचिव नियुक्ति किया जायगा। सयक-सचिव की नियुक्ति ऐसे पदाधिकारियों में से की जावेगी जा कि उस मण्डलीय परिषद् के सदस्य राज्यों की सेवा में नहीं है।

प्रत्येक मण्डलीय परिषद् का दफ्तर उस मण्डल के अन्दर जिस स्थान पर हा इसका निश्चय उस परिषद् द्वारा किया जायगा। इस प्रसंग में जो भी व्यय होगा उसको केन्द्रीय सरकार देगी।

### इन परिषदों के कार्य

- (घ) प्रत्येक मण्डलीय परिषद् एक परामर्शदात्री परिषद् है। यह ऐसे विषयों पर विचार-विमर्श करेगी जिनमें उस मण्डल के सब या कुछ राज्यों का अथवा सब तथा उस मण्डल के किसी सदस्य राज्य का समान हित हो।<sup>1</sup>

1. प० गोविन्द वल्लभ पन्त ने केन्द्रीय मण्डल परिषद् की अध्यक्षता करते हुये (मई, १९५०) कहा कि इन मण्डलीय परिषदों का काम केवल परामर्शदात्री है। यदि ये इस कार्य को ठीक प्रकार से कर सकें तो इन्हें अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफलता समझनी चाहिये।

(४) विशेषतः ये परिषदें निम्नलिखित विषयों पर विचार करेंगी :

- (१) सीमान्त सम्बन्धी विवाद;
- (२) घल्पभाषी समूहों से सम्बन्धित प्रश्न,
- (३) अन्तर राज्य परिवहन;
- (४) आर्थिक योजना से सम्बन्धित प्रश्न;
- (५) सामाजिक योजना क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न प्रश्न ।

इन मण्डलीय परिषदों की संयुक्त बैठकें भी हो सकती हैं । यदि किसी एक मण्डल के राज्य तथा दूसरे मण्डल के किसी राज्य अथवा राज्यों के मध्य ऐसे विषय हों जिन पर उनका समान हित हो तो ऐसे अवसरों पर संयुक्त बैठक हो सकती है ।

अभी तक केवल दो उत्तरी परिषद तथा केन्द्रीय-परिषद् की बैठकें हुई हैं । इस बैठक में समापति—पं० गोविन्द वल्लभ पन्त—ने इन परिषदों के कार्य और महत्त्व पर प्रकाश डाला । यदि ये परिषदें ठीक प्रकार से काम कर सकीं तो इसमें शन्देह नहीं है कि ये देश की उन्नति तथा एकता में अत्यन्त ही गह्रा-यक भिन्न होंगी ।

**राज्य पुनर्गठन-एक समीक्षा :**—राज्य पुनर्गठन यद्यपि अब समाप्त हो चुका है तथा इसके आधार पर नये राज्यों का निर्माण और व्यवस्थापिका का संगठन हो चुका है तथापि अभी भी देश में इस प्रश्न का महत्त्व बना है । इसका कारण यह है कि राज्यों के पुनर्गठन के समय देश में यह दृष्टिगोचर हुआ कि प्रान्तीयता की भावना बहुत प्रबल है । गुजरात तथा बम्बई में जो फाण्ड हुये उसने देश में सभी विचारशील व्यक्तियों की आंखें खोल दी और यह स्पष्ट हो गया कि देश की एकता को, यदि इस प्रकार की प्रवृत्तियों को अनियंत्रित बढ़ने दिया जाय तो, कभी भी मर्य उन्नत हो सकता है । इसलिये यद्यपि राज्यों का पुनर्गठन देश की सांस्कृतिक उन्नति के लिये आवश्यक था तथापि इसे इतना अधिक प्राण नहीं ले जाना चाहिये कि हम देश को अराकत कर दें ।

**भारत संघ के राज्यों तथा क्षेत्रों का संक्षिप्त परिचय**

(१) **आन्ध्र प्रदेश :**—इसका क्षेत्रफल १०५,९६२ वर्गमील तथा जन-संख्या ३१,२६०,९३३ है । इसके अन्तर्गत २० जिले हैं । भाषा यहाँ की तेलगु है । आंध्र प्रदेश में खेती योग्य उजाड़ भूमि तथा कपास की खेती के लिये काली

मिट्टी है। यहाँ की पैदावार में तम्बाकू, गन्ना, अरारोट, कपास, जूट आदि मुख्य हैं। यहाँ १२ कपड़े की मिलें हैं। इसके अतिरिक्त चीनी तथा कागज की मिलें भी हैं। यहाँ की राजधानी हैदराबाद है।

(२) आसाम — यह भारत का सबसे पूर्वी प्रदेश है। इसका क्षेत्रफल ८५,०१० वर्ग मील तथा जनसंख्या ९,०४३,७०७ है। इसके अन्तर्गत १२ जिले हैं। इसकी राजधानी शिलांग है। यहाँ का सबसे मुख्य उद्योग चाय है। इसमें लगभग ५ लाख व्यक्ति लगे हैं। आसाम में जूट की पैदावार मुख्य है। भारत में यही सबसे मुख्य स्थान है जहाँ मिट्टी का तेल पाया जाता है।

(३) पश्चिमी बंगाल — इसका निर्माण १९४७ में विभाजन के फलस्वरूप हुआ। पूर्वी बंगाल, जहाँ कि मुस्लिम बहुमत था, पाकिस्तान में चला गया। पश्चिमी बंगाल भारत में रहा। जनवरी १, १९५० में कुछ बिहार रिहासत तथा प्रकटबर ५, १९५० को पन्द्रहवें पश्चिमी बंगाल में विलीन कर दिये गये। राज्य पुनर्गठन के फलस्वरूप बिहार से कुछ भाग बंगाल में मिला दिये गये। अब इसका क्षेत्रफल ७३,९५८ वर्गमील तथा इसकी जनसंख्या २६,३०६, ९०२ है। इसकी राजधानी कलकत्ता है। बंगाल भारत सभ का एक अत्यन्त घना बसा हुआ भाग है। यहाँ प्रति वर्गमील ८०६ जनसंख्या है। बंगाल की मुख्य पैदावार चावल, गन्ना चाय है। इनके अतिरिक्त धान, जौ, सरसो, कपास तम्बाकू आदि भी यहाँ पैदा होने हैं। बंगाल में कई उद्योग भी हैं। भारत में पजीवित उद्योगों का २३% यहाँ है। यहाँ की जूट मिला में लगभग ३१०,००० लाख बाम करते हैं। कपड़े की बगाट में २२ मिल हैं। उत्तरप्रांश में बिड़ला का मोटर बनाने का कारखाना है। बंगाल भारत के मुख्य प्रदेशों में एक है। स्वतन्त्रता संग्राम तथा माहिग्यिक और सांस्कृतिक आन्दोलन में इस प्रदेश का महत्वपूर्ण दान रहा है।

(४) बिहार — इसका क्षेत्रफल ६७,१६४ वर्ग मील तथा जनसंख्या ३८,७७९,१६२ है। राज्य पुनर्गठन के द्वारा बिहार में ३,१६५ वर्गमील भूमि तथा १,४४९,०८७ जनसंख्या बंगाल को हस्तान्तरित कर दिये गये। पहले बिहार लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन था। सन् १९१९ के ऐक्ट द्वारा गवर्नर के अधीन किया गया। सन् १९३७ में इसे स्वायत्त शासन की स्थापना हुई। राज्य पुनर्गठन के पूर्व यह 'क' वर्ग का राज्य था।

बिहार मुख्यत एक कृषि प्रधान प्रदेश है। इसकी जनसंख्या का ८२% भाग पूर्णत कृषि पर निर्भर है। केवल ७-८% भाग खदान कार्य तथा उद्योगों

में लगे हैं। बिहार की मुख्य पैदावार धान, गन्ना, गेहूँ, जौ, जूट, तम्बाकू, तिलहन, मटर आदि हैं। उत्तरी बिहार दक्षिणी बिहार से अधिक उपजाऊ है।

(५) बम्बई :—नवीन बम्बई राज्य का निर्माण पुराने बम्बई प्रदेश में कच्छ सोराष्ट्र, हंढराबाद का मराठी भाषी क्षेत्र, तथा मध्य प्रदेश का विदर्भ क्षेत्र मिलाने से हुआ है। परन्तु पुराने बम्बई से कुछ क्षेत्र वर्तमान मैसूर तथा एक छोटा भाग वर्तमान राजस्थान को चले गये हैं। वर्तमान बम्बई राज्य द्विभाषीय है। यहाँ लगभग २ करोड़ ६० लाख मराठी भाषी, १ करोड़ ६० लाख गुजराती भाषी तथा १५ लाख भारत की अन्य भाषा बोलने वाले हैं। बम्बई का क्षेत्रफल १९०,९१९ वर्ग मील तथा जनसंख्या ४८,२६५,००१ है। यद्यपि बम्बई वाणिज्य व्यापार तथा उद्योगों की दृष्टि से बहुत महावपूर्ण है तथापि कृषि यहाँ की जनसंख्या के बहुसंख्यक भाग का पेशा है। यहाँ की मुख्य पैदावार ज्वार, बाजरा, कपास, तम्बाकू, मरारोट, चावल, गेहूँ, जौ,चना, आदि है।

(६) मध्य प्रदेश :—यह राज्य भौगोलिक दृष्टि से भारत का केन्द्रीय राज्य है। इसका क्षेत्रफल १७१,२०१ वर्गमील तथा जनसंख्या २६,०७१,६३७ है। वर्तमान मध्य प्रदेश का निर्माण पहले के मध्य भारत, विन्ध्य प्रदेश, भोपाल पुराने मध्य प्रदेश के १७ जिले तथा कोटा रियासत का एक छोटा भाग मिलने से हुआ है।

इस राज्य की अर्थ-व्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है। इसकी जनसंख्या का ७८% भाग कृषि पर निर्भर है। यहाँ की मुख्य पैदावार चावल, गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा, दाल, तिलहन, कपास है। खनिज पदार्थों की दृष्टि से यह राज्य सम्पन्न है। इस राज्य की मुख्य भाषा हिन्दी है। परन्तु इसके अतिरिक्त अनेक स्थानीय तथा क्षेत्रीय बोलियाँ यहाँ हैं।

(७) मद्रास :—यहाँ का क्षेत्रफल ६०,११० वर्ग मील तथा जनसंख्या २९,११४,९३६ है। यहाँ की भाषा तमिल है। भाषा की दृष्टि से यह एक-भाषीय राज्य है। यहाँ की मुख्य पैदावार मूँगफली, कपास, गन्ना, नारियल, धान, दाल, आलू, प्याज, केला आदि है। मद्रास में खनिज पदार्थ भी पाये जाते हैं। यहाँ के मुख्य उद्योग कपड़ा, चीनी, तम्बाकू, दियासलाई, तेल, सिमेन्ट आदि हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ रेशम, लोहा, दस्पात, चाय, काप्री आदि के भी कारखाने हैं।

(८) उड़ीसा :—यहाँ की जनसंख्या १,४६,४५,३४६ तथा क्षेत्रफल ६०,१३६ वर्ग मील है। उड़ीसा की जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या लगभग पुरुषों से २ लाख अधिक है। उड़ीसा मुख्यतः गाँवों का बना है। यहाँ जनसंख्या का केवल

४.०६ भाग नगरो में रहता है। उद्योग धंधों की दृष्टि से यह पिछड़ा हुआ है। यहाँ परेल उद्योग काफी बढे हुए हैं।

(६) पंजाब :—यह भारत का सबसे पश्चिमी प्रदेश है तथा पाकिस्तान से इसकी सीमा मिली हुई है। यहाँ की जनसंख्या लगभग १६,४३५,८९० तथा क्षेत्रफल १७,९५७ वर्ग मील है। राज्य पुनर्गठन द्वारा पुराने पंजाब तथा वेम् के मिलने से वर्तमान पंजाब राज्य का निर्माण हुआ है। पंजाब में १९४ शहर तथा २१,५१६ गांव हैं। पंजाब भी एक द्विभाषीय राज्य है। अतएव यहाँ हिन्दी और पंजाबी दोनों राज्य-भाषाएँ मानी गई हैं। जनसंख्या का ६६.५% भाग कृषि पर निर्भर है। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूँ, चना, जौ, मक्का, बाजारा, गन्ना, ज्वार, कपास, मरसो हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ थोड़ी बहुत मात्रा में चाय, तम्बाकू, मूँगफली तथा अलसी भी पैदा होती हैं। यहाँ के मुख्य उद्योग कपड़ा कढ़ी कपड़ा, तथा खेलबूद का सामान हैं।

(१०) उत्तर-प्रदेश — इसका क्षेत्रफल ११३,४०९ वर्गमील तथा जनसंख्या ६३,२११,७४२ है। राज्यपुनर्गठन का इस प्रदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इस प्रदेश को सबसे पहले उत्तर-पश्चिमी सूबा कहा जाता था। सन् १९०२ में इसका नाम आगरा तथा अवध का संयुक्त प्रान्त कर दिया गया। जब यहाँ १९३५ के ऐक्ट के अनुसार स्वायत्त शासन की स्थापना हुई तब १ अप्रैल १९३७ से इसका नाम केवल संयुक्त-प्रान्त रखा गया। नये संविधान के प्रारम्भ से दो दिन पूर्व २४ जनवरी १९५० से इसका नाम बदल कर उत्तर-प्रदेश रख दिया गया। उत्तर प्रदेश कृषि तथा उद्योग दोनों ही दृष्टियों से भारत के उन्नतिशील भागों में से है। यहाँ गेहूँ, चावल, जौ, दाल, चाय, तम्बाकू, कपास पैदा होती है। यहाँ के उद्योगों में कपड़ा तथा चीनी मुख्य हैं।

(११) राजस्थान :—राजपूताना की अनेक रियासतों के मिलने से इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। इसका क्षेत्रफल १३२,०७६ वर्ग मील तथा जनसंख्या १५,९७०,७७४ है। यह राज्य अधिक उन्नत नहीं है। यहाँ की मुख्य फसलें ज्वार, बाजारा, गेहूँ, मक्का, जौ तथा चना हैं। यहाँ थोड़ी बहुत कपास भी पैदा होती है। शिखा की दृष्टि से यह अत्यन्त ही पिछड़ा प्रदेश है।

(१२) मैसूर — नवीन मैसूर राज्य का क्षेत्रफल ७४,३४७ तथा जनसंख्या १,९९,००,००० है। यहाँ की मुख्य भाषा कन्नड है जो कि लगभग ६६% जनसंख्या की भाषा है। परन्तु इसके अतिरिक्त ६४ और भाषाएँ यहाँ बोली जाती हैं। मैसूर भारत में केवल ऐसा प्रदेश है जहाँ सोना निकाला जाता

है तथा चदन का तेल बनता है। इसके प्रतिरिक्त यहाँ स्थात, माबुन के उद्योग भी हैं।

(१३) केरल — यह राज्य मसार का प्रथम राज्य है जहाँ प्रज्ञानात्मक रीति से साम्यवादी दल ने शासन हस्तगत किया है। यहाँ का क्षेत्रफल १५,०३५ वर्ग मील तथा जनसंख्या १३,५८९,११० है। निम्ना दृष्टि से भारत का मार्वाधिक उन्नत प्रदेश है। यहाँ की मुख्य पैदावार चावल, नारियल, गन्ना, खर, चाय, काफी इत्यादि हैं। उद्योग धंधों की दृष्टि से भी यह उन्नत है।

(१४) जम्मू तथा काश्मीर राज्य — राज्य पुनर्गठन के पश्चात् यह प्रवेला 'स' वर्ग का राज्य है जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। २६ जनवरी सन् १९५७ में काश्मीर में एक नया संविधान लागू हो गया है जिसके द्वारा यह भारत का एक अविभाज्य अंग घोषित किया गया है। भारत मध्य के अन्तर्गत काश्मीर का स्थिति विरोध है। यहाँ का राज्य-प्रधान सदर-इ-रियासत कहलाता है। इसका अपना झंडा है परन्तु भारत का झंडा यहाँ का भी राष्ट्रीय झंडा है।

संघ तथा काश्मीर राज्य के मध्य सम्बन्ध १९५० के संविधान प्रादेश तथा राष्ट्रपति द्वारा घोषित अन्व आदेशों और १९५२ के काश्मीर तथा भारतीय सरकार के मध्य गमझोते पर आधारित थे। इनके अनुसार केवल तीन विषयों में ही काश्मीर ने भारत मध्य में प्रवेश किया था। ये विषय निम्नोक्त थे—रक्षा, मातायात तथा वैदेशिक सम्बन्ध। भारत संघ की प्रशासकीय तथा न्यायिक शक्तियाँ भी काश्मीर में सीमित थी। १९५२ के समझौते के अनुसार काश्मीर द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया था कि राष्ट्रपति के सख्त कालीन अधिकार काश्मीर पर लागू होंगे। परन्तु आन्तरिक संकट के विषय में कार्यवाही राज्य की विधान-सभा की सहमति बिना नहीं की जायगी। इसी प्रकार नागरिकों के मूल अधिकारों को भी काश्मीर ने कुछ संशोधन के साथ स्वीकार किया। काश्मीर ने बिना प्रतिकार दिये ही जमाशर उन्मूलन कर दिया।

जम्मू-काश्मीर राज्य का क्षेत्रफल ९२,७८० तथा जनसंख्या ४,४१०,००० है। यह राज्य मुख्यतः पहाड़ी है। अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिये काश्मीर मसार प्रसिद्ध है। प्रतिवर्ष हजारों यात्री इसकी प्राकृतिक सुषमा का पान करने के लिये दूर दूर से आते हैं। काश्मीर में मुख्य उद्योग ऊनी कपड़ा, रेशम, तथा लकड़ी का पान है। काश्मीर में कई खनिज पदार्थ भी पाये जाते हैं। परन्तु पार्थिक दृष्टि से यह पिछड़ा हुआ है जनसंख्या का अधिकांश भाग निर्धन है। जनसंख्या की दृष्टि से काश्मीर मुख्यतः एक मुस्लिम प्रदेश है। जनसंख्या का ७५% भाग मुस्लिम है।

जम्मू काश्मीर राज्य का १९ भाग पाकिस्तान के अधीन है। काश्मीर प्रदेश पर भारत तथा पाकिस्तान के मध्य कोई समझौता अभी तक सम्भव नहीं हो सका है। गत राष्‍ट्र मन्‍त्र के सम्‍मुख यह प्रश्‍न है। परन्‍तु इससे द्‍वारा भी इसको सुलझाया नहीं जा सक्‍ता है। हमारी सरकार का यह कहना है और यही काश्‍मीर सरकार का भी मत है कि काश्‍मीर भारत का अविच्छिन्‍न अंग हो गया है। इस स्‍थिति का मार का प्रश्‍न बेज्‍वज यह है कि पाकिस्‍तान अपनी सेनाओं का वहां स ह्‍टा कर परन्‍तु पाकिस्‍तानी सरकार इससे स्‍विकृति नहीं देती।

### केन्द्रीय क्षय का संचित वजन

(१) दिल्ली - यह भारत की राजधानी है। यहाँ का क्षेत्रफल ५१३ वर्गमीटर है तथा जनसंख्या १,७४४,०७ है। भारत के इतिहास में दिल्ली का बड़ा ही महत्त्व है। राज्य-पुनर्गठन के पश्चात् दिल्ली के लिये राष्‍ट्रपति ने एक परामर्शदात्री समिति का निर्माण किया है। यह समिती केन्द्रीय गृहमन्‍त्री के अधीन कार्य करेगी। इसके सम्‍मुख निम्‍नोक्त हैं—दिल्ली से मस्‍द के न्‍य सदस्य चीफ कमिश्‍नर विधायिकाय का उप कुम्‍पति दिल्ली नगरपालिका का अध्यक्ष तथा नई दिल्ली नगरपालिका का उपाध्यक्ष। यहाँ एक नगर निगम की स्‍थापना कर दी गई है।

(२) हिमाचल प्रदेश - राज्य पुनर्गठन के पूर्व यह नववां राज्य था। इसका क्षेत्रफल १०,९०४ वर्ग मील तथा जनसंख्या १,०९,४६९ है। यहाँ की जनसंख्या का ९४% भाग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। यहाँ की मुख्य वस्तुएँ गन्‍धक, जौ, चन्‍दन, चाय, गन्‍धक, धातु आदि हैं।

हिमाचल प्रदेश हिमाचल की तराई में स्थित है। छोटे छोटे राज्यों और जिलासपुर राज्य के मिलन से बना है। इस समय यहाँ का प्रधान एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है। यह स्वायत्‍त राज्यों की श्रेणी में नहीं है।

(३) मनीपुर - आसाम के दक्षिण पूर्वी कोन में स्थित है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ८,९२८ वर्ग मील तथा जनसंख्या २,७७,६३१ है। क्योंकि चतुर्दिक् जल से घिरा हुआ है इसी कारण इसे केन्द्रीय शासन में रखा गया है। मनीपुर की मुख्य वस्तु धान है। यहाँ चाय की भी खेती होती है। वस्‍तु उद्योग यहाँ का मुख्य उद्योग है।

राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा राष्‍ट्रपति ने यहाँ के लिये एक परामर्शदात्री समिति का निर्माण किया है। इसमें ५ सदस्य हैं तथा चीफ कमिश्‍नर इसका सभापति है।

(४) त्रिपुरा — इनका क्षेत्रफल ४,०३२ वर्गमील तथा जनसंख्या ६३९,०२९ है। यह तमिल पदमों तथा जंगल में सम्पन्न है। यहाँ की मुख्य फसल जूट, चाय, गन्ना, कपास तथा तिलहन है। यह राज्य पुनर्गठन के पूर्व एक 'ग' वर्ग का राज्य था तथा यहाँ की परामर्शदात्री समिति १९५१ में स्थापित हुई थी। उद्योग-धर्मों में यह राज्य बहुत गिद्धा है।

(५) लक्षद्वीप, मीनीकाय तथा अमीनीद्वीप द्वीप :— इनका क्षेत्र १० वर्गमील तथा जनसंख्या २१,०३५ है। राज्य पुनर्गठन के पूर्व यह प्रशासन के लिये मद्रास राज्य में सम्मिलित थे परन्तु अब इनका शासन केन्द्र द्वारा ले लिया गया है। इन द्वीप समूह में कुल १९ द्वीप हैं जिनमें से १० में जनसंख्या निवास करती है। यहाँ का शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा होता है। इन द्वीप समूहों के सब निवासी मुसलमान हैं।

(६) अण्डमान तथा निकोबार द्वीप :— यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। इनका क्षेत्रफल ३,२१५ तथा जनसंख्या ३०,९७१। इन समूह में २०४ द्वीप हैं। राज्य पुनर्गठन के पूर्व यह 'घ' वर्ग का राज्य था। अब इसका शासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के अधीन है।

### प्रश्न

(१) "भारतीय संविधान सप्तात्मक भी है और एकात्मक भी।" इस कथन की व्याख्या कीजिये। (यू० पी० १९५२)✓

(२) भारतीय संविधान के सप्तात्मक लक्षणों का वर्णन कीजिये।

(यू० पी० १९५४)

(३) भारतीय संविधान में केन्द्र की शक्तिशाली बनाने के लिये किन किन नियमों का प्रयोग किया गया है? भारत के लिये सशक्त केन्द्रीय सरकार की क्यों आवश्यकता है?

(यू० पी० १९५४)

(४) "भारतीय संविधान देशने में सप्तात्मक है, पर वास्तव में एकात्मक है।" इस कथन की व्याख्या कीजिये।

(यू० पी० १९५८)



## भारतीय-नागरिकता

नागरिकता का अर्थ — नागरिकता का अर्थ किसी देश के नागरिक होने का है। इसका नागरिकता उस देश के कानून के अन्तर्गत कि किसी व्यक्ति को राज्य की ओर से नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार प्राप्त हों। इन अधिकारों के अन्तर्गत नागरिकता राज्य के प्रति बंधन संबंध निग्राहक रहते हैं। इनका पालन आवश्यक है।

नागरिकता दो प्रकार के होते हैं — स्वाभाविक नागरिकता तथा राज्यदत्त नागरिकता। स्वाभाविक नागरिकता के सम्बन्ध में तीन सिद्धान्त हैं। पहला तात्त्विक सिद्धान्त है। किसी मनुष्य की नागरिकता का निर्णय उसके पिता की नागरिकता से किया जाता है। दूसरा जन्मस्थान से किया जाता है। तीसरा सिद्धान्त इन दोनों सिद्धान्तों से मिलकर बनता है।

राज्यदत्त नागरिकता से तात्पर्य उनमें है जो जन्म से ही किसी अन्य राज्य के नागरिक थे परन्तु जिस देश में अब वे राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली हैं। प्रत्येक राज्य का अधिकार है कि वह विदेशियों की कुछ शर्तों पर पत्र पत्रपत्रों नागरिकता प्रदान करे।

भारतीय नागरिकता — हम पहले यह पूछें हैं कि भारत में क्या नागरिकता है? इसका जवाब भी है कि नागरिकता नहीं स्थापित की गई है। भारत में एक भारत का नागरिकता है, राज्य की नहीं। क्योंकि भारत राष्ट्र मण्डल का सदस्य है इस कारण भारत की नागरिकता राष्ट्र मण्डल की नागरिकता से भी उद्भासित है।

भारतीय मंत्रिपरिषद् ने एक बार बताया गया है कि इस मंत्रिपरिषद् ने लागू होने वाले अधिनियम १९५० के अन्तर्गत भारत के नागरिक थे। परन्तु मंत्रिपरिषद् ने यह नहीं बताया कि भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है तथा किस प्रकार उसकी समाप्ति हो सकती है। इस विषय में मंत्रिपरिषद् ने बताया है कि मनुष्य को उपर्युक्त बताने का अधिकार है। इस प्रकार भविष्य में नागरिकता सम्बन्धी विषयों की रचना का अधिकार मनुष्य को दिया गया है। इस विषय में मनुष्य का अधिकार मंत्रिपरिषद् में दिये हुये

उपबन्धों में सीमित नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर ससद् चाहे तो वह किसी भी व्यक्ति को नागरिकता की (जिसकी संविधान के लागू होने पर, उसमें बंशिन उपबन्धों के अनुसार नागरिकता मिली हो) ममाप्ति कर सकती है तथा उनको किसी अन्य प्रकार में संकुचित कर सकती है।

**नागरिक कानून है** — संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकता तीन श्रेणियों के लोगों को दी गई है

(१) वे जो कि संविधान के लागू होते समय भारत के निवासी थे।

(२) वे व्यक्ति जो कि पाकिस्तान से भारत को प्रवजन (migrate) कर आये हैं, अर्थात् पाकिस्तान से आये शरणार्थी।

(३) भारत के बाहर रहने वाले भारतीय, अर्थात् वे भारतीय जो कि विदेशों में रहे रहे हैं।

इनमें से प्रत्येक श्रेणी को हम क्रमशः लेंगे।

(१) वे लोग जो कि संविधान के लागू होते समय भारत के निवासी थे, यहाँ के नागरिक समझे जायेंगे, अगर वे नीचे लिखी तीन शर्तों को पूरा करते हों।

(अ) उनका जन्म भारत-राज्य क्षेत्र में हुआ हो;

(ब) या, उनके माता-पिता में से कोई भारत-राज्य में जन्मा हो;

(स) या, जो कि संविधान के प्रारम्भ के ठीक पहले कम से कम पाँच वर्षों से भारत राज्य-क्षेत्र में साधारणतः रहे हों।

(२) पाकिस्तान से आये शरणार्थी भारत के नागरिक समझे जायेंगे अगर वे नीचे लिखी शर्तों को पूरा करते हों:

(अ) वे शरणार्थी जो कि १९ जुलाई १९४८ के पूर्व भारत में आ गये थे, भारत के नागरिक समझे जायेंगे, यदि वे, उनके माता-पिता या महाजनकों में से कोई, अविभाजित भारत में (अर्थात् जैसा कि पाकिस्तान बनने के पूर्व था) जन्मा हो। इसके अतिरिक्त यह शर्त भी थी कि भारत में आने की तारीख से सामान्यतः भारत के निवासी रहे हों।

(ब) वे शरणार्थी जो कि १९ जुलाई १९४८ के बाद में आये, भारत के नागरिक समझे जायेंगे, यदि वे, उनके माता-पिता या महाजनकों में से कोई, अविभाजित भारत में जन्मा हो। इसके अतिरिक्त यह शर्त भी थी कि वे भारत-सरकार द्वारा नियुक्त किये हुए पदाधिकारी को आवेदन-पत्र देकर अपना नाम

मविधान लागू होने की तिथि (२६ जनवरी १९५०) म पञ्च पञ्जीबद्ध (register) करा ले। परन्तु उनका नाम पञ्जीबद्ध तभी होगा जब वे आवेदन-पत्र देने की तिथि से कम से कम ६ मास पूर्व से भारत में रह रहे हों। इसका तात्पर्य यह हुआ कि केवल वे ही शरणार्थी इस प्रकार से नागरिक हो सकते थे जो कि भारत में २५ जुलाई १९४९ के बाद न आये हों।

(स) मविधान में यह कहा गया है कि वे व्यक्ति जो १ मार्च सन् १९४७ के पश्चात् भारत-राज्य क्षेत्र में उस राज्य को चले गये थे जो अब पाकिस्तान कहलाता है, भारत के नागरिक नहीं होंगे। परन्तु यह प्रतिबन्ध उन लोगों पर लागू नहीं होगा जो कि भारत को फिर से लौट आए हैं तथा जिन्हें फिर से भारत में निवास करने के लिए भारत सरकार की अनुमति मिल गई हो। ऐसे मय व्यक्तिओं पर वे ही उपबन्ध लागू होंगे जो कि १९ जुलाई १९४८ के बाद आए शरणार्थियों पर लागू होते हैं। अर्थात् यह समझा जायगा कि ये सब व्यक्ति १९ जुलाई १९४८ के बाद भारत आये। यह उपबन्ध उन मुसलमानों की मविधा के लिए बनाया गया जो कि भारत में ही रहना चाहते थे, जैसे राष्ट्रीय मुसलमान, या सरकारी नौकर, परन्तु जो साम्प्रदायिक स्थिति के कारण अपने परिवार को पाकिस्तान पहुँचा आए थे परन्तु मिति सुधर जाने पर फिर से भारत में आना चाहते थे। ऐसे लोगों की मस्या बहुत कम थी। ५० नेहरू ने मविधान मभा में कहा कि (अगस्त १२, १९४२) इनकी मस्या दो या तीन हजार से अधिक नहीं होगी।

(३) भारत से बाहर विदेशों में रहने वाले भारतीय जिनका या जिनके माता-पिता का या महाजनकों में से किसी का अविभाजित भारत में जन्म हुआ हो, भारत के नागरिक समझे जायेंगे अगर उन्होंने भारत के राजनीतिक (diplomatic) या वाणिज्यिक (consular) प्रतिनिधि को, इस मविधान में लागू होने से पहले या बाद, आवेदन-पत्र देकर अपने का पञ्जीबद्ध करा लिया है।

**नागरिकता पर प्रतिबन्ध** —मविधान में यह कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर ली है तो वह भारत का नागरिक नहीं समझा जायगा।

नागरिकता सम्बन्धी उपरोक्त उपबन्धों को देखने से ज्ञात होता है कि भारतीय मविधान द्वारा वंश-सिद्धान्त तथा जन्म-स्थान-सिद्धान्त दोनों नागरिकता निर्धारित करने के लिए मान लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त भारत में

कुछ काल का निवास भी भारत की नागरिकता निर्धारित करने के लिये कारी माना गया है।

यह स्पष्ट है कि नागरिकता सम्बन्धी उपबन्ध अपूर्ण हैं। उदाहरणार्थ अगर कोई विदेशी अभिवासी भारत का नागरिक होना चाहे तो किस प्रकार होगा, इस विषय में संविधान में कुछ नहीं है। इसका कारण यह है कि भारतीय संसद को नागरिकता सम्बन्धी उपबन्ध बनाने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। इसलिए इस प्रकार की जो बातें संविधान में छूट गई हैं वे सब संसद साधारण विधि (law) द्वारा पूरी कर देगी।

## भारतीय नागरिकता अधिनियम

जैसा ऊपर लिखा जा चुका है भारतीय संविधान संसद को नागरिकता सम्बन्धी उपबन्ध बनाने का पूर्ण अधिकार देता है। संविधान में नागरिकता के विषय में जो उपबन्ध हैं वे पूर्ण नहीं थे क्योंकि उनमें केवल यही बताया गया था कि २६ जनवरी १९५० को भारत के नागरिक कौन थे परन्तु इस तिथि के पश्चात् भारतीय नागरिकता का निर्णय कैसे किया जायगा इस विषय में विधिनियम आवश्यक था। इसीलिए गृह-मंत्री पं० गोविन्द वल्लभ पंत ने संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जो पारित होने पर "भारतीय नागरिकता अधिनियम" (Indian Citizenship Act of 1955) कहलाया। इस अधिनियम के मुख्य उपबन्ध निम्नोक्त हैं:

### नागरिकता प्राप्ति

(१) जन्मजात नागरिक—भारत में २६ जनवरी १९५० को या इस तिथि के पश्चात् उत्पन्न प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात भारतीय नागरिक होगा यदि वह विदेशी दूत अथवा विदेशी शत्रु की सन्तान न हो।

(२) वंशाधिकार से नागरिकता की प्राप्ति:—कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म २६ जनवरी १९५० या इस तिथि के पश्चात् भारत के बाहर हुआ हो भारत का वंशाधिकार के आधार पर (by descent) नागरिक माना जायगा यदि उसका पिता उसके जन्म के समय भारत का नागरिक था।

(३) रजिस्ट्री के द्वारा नागरिकता:—कोई व्यक्ति जो कि संविधान के उपबन्धों द्वारा या इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों द्वारा भारतीय नागरिक नहीं है, प्रायश्चित्त देने पर इस देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, यदि वह निम्नलिखित वर्गों (categories) में से किसी एक वर्ग में हो:

(अ) वे भारतीय (Persons of Indian origin) जो माघारणत भारत में ही निवास करने हैं तथा रजिस्ट्री के प्रायनापत्र देने में ६ महीने पूर्व में भारत में ही निवास कर रहे हो ,

(ब) वे भारतीय (Persons of Indian origin) जो माघारणत अविभाजित भारत में बाहर किसी स्थान में निवास कर रहे हैं ,

(स) वे स्त्रियाँ जिनका विवाह भारत के नागरिक से हुआ हो

(द) भारतीय नागरिक के अल्पवयस्क (minor) बच्चे, ।

(ध) निम्नलिखित देश के नागरिक—संयुक्त राज्य (United Kingdom), कनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, दक्षिणी अफ्रीका में, पाकिस्तान मीलान स्लोवेनिया तथा न्यामालैण्ड में तथा आयरलैण्ड का गणतन्त्र ।

किसी व्यक्ति का रजिस्ट्री के द्वारा नागरिकता प्राप्ति तभी हो सकती है यदि वह नागरिकता की शपथ ग्रहण करे ।

केन्द्रीय सरकार विशेष परिस्थितियों में किसी अल्पवयस्क का भी भारतीय नागरिक रजिस्टर (register) कर सकती है ।

ऊपर के उपबन्धों में भारतीय (Person Indian of origin) से यह तात्पर्य है कि वह व्यक्ति अथवा उसका माता-पिता में से एक या दादा-दादी में से एक, अविभाजित भारत में जन्मा हो ।

(४) नागरिककरण द्वारा नागरिकता प्राप्त होना —कोई विदेशी (राष्ट्र मण्डल के सदस्य देशों अथवा आयरलैण्ड-गणतन्त्र के नागरिक के प्रतिस्वतः) प्रायनापत्र देने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नागरिककरण (Naturalisation) द्वारा भारत का नागरिक बनाया जा सकता है यदि वह निम्नांकित शर्तों को पूरा करता हो ।

(१) वह किसी ऐसे देश का नागरिक न हो जहाँ कि भारत के नागरिक के नागरिककरण पर विधि या व्यवहार द्वारा रोक हो ,

(२) उसने अपनी पहली नागरिकता का परित्याग कर दिया हो तथा केन्द्रीय सरकार को इसकी सूचना दी हो ।

१. यह शपथ है "I, AB do solemnly affirm (or swear) that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully observe the laws of India and fulfil my duties as a citizen of India."

(३) वह प्रार्थना-पत्र देने के पूर्व भारत में लगातार १२ माह रहा हो या सरकार की नौकरी में भारत में १२ माह लगातार रहा हो,

(४) इन १२ मास की अवधि में पूर्व ३ वर्षों के समय में वह कम से कम ४ वर्ष तक कुल मिलाकर (in the aggregate) भारत में रहा हो,

(५) वह मन्चरित्र हो,

(६) भारतीय संविधान में छाठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भारतीय भाषा का उसे पर्याप्त ज्ञान हो,

(७) नागरिककरण प्राप्त हो जाने पर उसके विचार भारत में निवास करने का हो या भारत सरकार की नौकरी या किसी ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की नौकरी करने का हो जिसका भारत सदस्य हो।

इन उपर्युक्त बातों की भारत सरकार किसी ऐसे व्यक्ति-विशेष के सम्बन्ध में जिसने विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन, विद्वत्-शान्ति अथवा मानव-उन्नति के दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया हो, हटा भी सकती है।

(५) क्षेत्र-विस्तार द्वारा:—यदि कोई भू-भाग (territory) भारत राज्य में सम्मिलित होता है तो भारत-सरकार उसके निवासियों की भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकती है।

## नागरिकता का लोप

(१) कोई भारतीय वयस्क नागरिक, जो कि किसी अन्य देश का भी नागरिक है, एक घोषणा द्वारा भारत की नागरिकता त्याग सकता है।

(२) यदि कोई पुरुष भारत का नागरिक नहीं रह जाता तो उसके अवयस्क बच्चे भी भारतीय नागरिकता से संचित हो जायेंगे।

(३) यदि भारत का कोई नागरिक, किसी प्रकार स्वेच्छतया, २६ जनवरी १९५० तथा इस नागरिकता अधिनियम के लागू होने के मध्य काल में अन्य किसी देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का लोप हो जायगा।

(४) भारत-सरकार किसी ऐसे व्यक्ति की नागरिकता का अन्त कर सकती है जिसने नागरिककरण या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने में किसी प्रकार की बेइमानी की हो।

(५) यदि कोई ऐसा नागरिक भारतीय संविधान के प्रति विश्वासघातक होता है, सरकार उसकी नागरिकता का अन्त कर देगी।

(६) यदि युद्धकाल, में उसने अवैध रूप में किसी शत्रु देश के साथ सम्बन्ध रखा हो या व्यापार किया हो तो उसकी नागरिकता छिन जायेगी।

(७) यदि नागरिककरण अथवा रजिस्ट्रीकरण के ५ वर्ष के भीतर उसे किसी देश में कम से कम २ वर्ष का वागवास दण्ड मिला हो तो उसकी नागरिकता का अन्त हो जायेगा।

(८) यदि ऐसा नागरिक ७ वर्ष तक लगातार भारत के बाहर निवास करता रहा हो तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जायेगी।

परन्तु उपर्युक्त सभी दशाओं में भारत सरकार तभी नागरिकता का अन्त करेगी यदि उसे ऐसा विश्वास हो कि ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक रखना सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को यह अधिकार दिया जायेगा कि वह सरकार के सम्मुख अपने पक्ष का प्रतिनिधित्व करे।

इस अधिनियम द्वारा नागरिकता प्राप्ति तथा र्दोष के नियमों को जो कि संविधान में पूरे नहीं थे पूरा कर दिया गया है। इस अधिनियम के द्वारा नागरिकता प्राप्ति के सभी सिद्धान्तों को गान्वता प्रदान की गई है।

### प्रश्न

१. (१) भारतीय संविधान में नागरिकता सम्बन्धी उपबन्धों का वर्णन कीजिये।

## नागरिकों के मूल-अधिकार

**मूल अधिकारों का अर्थ तथा प्रयोजन** — प्राधुनिक काल में कई लिखित विधानों में नागरिकों के कुछ अधिकारों का वर्णन कर दिया गया है। इन अधिकारों को मूल-अधिकार कहते हैं, अर्थात् वे अधिकार जो कि स्वयं मविधान द्वारा प्रदान किए गये हैं। प्रत्येक राज्य द्वारा अपने नागरिकों को कुछ सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं, क्योंकि इन सुविधाओं के बिना व्यक्तित्व का विकास सम्भव नहीं है। लोकतन्त्रात्मक शासन-प्रणाली का आधार ही व्यक्ति का विकास है। परन्तु लोकतन्त्रात्मक प्रणाली में बहुमत की सरकार होती है। भय है कि बहुमध्यक मूल-समूहों के हितों का ध्यान ही न रखें तथा इस प्रकार उन्हें वे सुविधाएँ न प्रदान करें जो कि व्यक्तित्व के विकास की आवश्यक दशाएँ हैं। इसलिए इन सुविधाओं का अर्थात् अधिकारों का विधान में समावेश कर दिया जाता है और इस प्रकार मूलमत-दल उनके उपभोग में वचित रहता है।

मविधान में कुछ अधिकारों का इस प्रकार वर्णन करने का परिणाम यह होता है कि सरकार नागरिकों की इन सुविधाओं को आसानी से हटा नहीं सकती है। ये अधिकार चाहे कोई भी दल शासनारूढ क्यों न हो बने रहते हैं।<sup>1</sup> बहुमतीय दल इनको अपनी इच्छानुसार आसानी से बदल नहीं सकता क्योंकि मविधान में उनका वर्णन होने के कारण वे अद्वितीय की दृष्टि से देखे जाते हैं। परन्तु अगर बहुमत दल चाहे तो इनमें परिवर्तन कर ही सकता है। उदाहरणार्थ हमारे देश में, मूल-अधिकारों में अभी कुछ संशोधन किया गया है। देश में संगठित जनमत का एक बड़ा भाग इन संशोधनों के विरुद्ध था परन्तु तब भी ये संशोधन संसद द्वारा पारित कर दिए गये क्योंकि मसद में सरकार का ही बहुमत था।

---

1. अमेरिकन उच्चतम न्यायालय के एक मुख्य-न्यायाधीश ने इन अधिकारों की निम्नलिखित परिभाषा की है "The very purpose of fundamental rights was to withdraw certain subjects from the reach of majority-principles to be



एक बात नहीं बलनी चाहिये कि मूल-अधिकार भी असीमित नहीं हो सकते हैं। कोई भी अधिकार अगर समाज के हितों के विरुद्ध है तो अधिकार नहीं रह सकता है। इसलिए प्रत्येक अधिकार की एक निश्चित सीमा है। वह यह है कि वह समाज से अहित न करे। इसलिए, उदाहरणार्थ, स्वतन्त्रता का अधिकार मजे लगा करने या किसी की हानि करने का अधिकार नहीं देता है। धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार मजे दूसरे धर्मों के विरुद्ध लोगों का भड़काने का अधिकार या कुछ ऐसे काम करने का अधिकार जो कि हमारे मानिक भावना के विरुद्ध हो नहीं देता। इसी प्रकार प्रत्येक अधिकार सीमित है।

फ्रेच शानिबार्गिया ने सन् १७८९ में "मनुष्य के अधिकारों की घोषणा" में कुछ मौलिक अधिकारों का बणन किया। अमेरिकन संविधान में भी एक अधिकार-पत्र (Bill of Rights) का समावेश किया गया है। आजकल तो कई विधान हैं जिनमें कि नागरिकों के मूल अधिकारों का बणन है। उदाहरणार्थ, आयरलैण्ड, रूस, आदि के। परन्तु कुछ विधान ऐसे भी हैं जहाँ कि विधान में मूल-अधिकारों का बणन नहीं है, उदाहरणार्थ इंग्लैण्ड का। वहाँ तो संविधान अलिखित है। इसमें मूल-अधिकारों के संविधान में बणन का प्रश्न उठता ही नहीं परन्तु इसमें यह नहीं समझना चाहिये कि वहाँ नागरिकों के अधिकार धरमिन हैं, वहाँ उनकी रक्षा साधारण विधि द्वारा होती है। परन्तु वहाँ क्योंकि पार्लियामेण्ट की सर्वप्रधानता है, इसलिए अगर पार्लियामेण्ट किसी विधि द्वारा किसी अधिकार का अन्त कर दे तो न्यायालय इसके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते हैं। परन्तु उन देशों में जहाँ कि न्यायालिका की सर्वप्रधानता है वहाँ नागरिक किसी भी कानून को जो कि उसके मूल-अधिकार में कटारघात करते हैं, न्यायालय के सामने ला सकता है तथा न्यायालय अगर यह समझे कि वह कानून नागरिक के मूल अधिकारों का अन्तिममण करता है तो वह अवैध घोषित कर दिया जावेगा। इसलिए यह कहा जाता है कि मूल अधिकारों की रक्षा के लिये न्यायालिका की सर्वप्रधानता (Judicial supremacy) आवश्यक है। क्योंकि अगर इन अधिकारों को मनवाने (enforce) का कोई साधन न हो तो वे अर्थ हैं तथा उनमें कोई लाभ नहीं।

भारतीय संविधान में मूल-अधिकार — संविधान में निम्नलिखित अधिकारों का बणन है, समता अधिकार, स्वतन्त्र-अधिकार, घोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म-स्वातन्त्र्य का अधिकार, सम्पत्ति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार, तथा संविधानिक उपचारों के अधिकार। इन अधिकारों को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है। उनमें से कुछ अधिकार तो ऐसे हैं जो कि केवल नागरिकों को ही प्रदान किये गये हैं। उदाहरणार्थ स्वतन्त्रता का अधिकार

केवल नागरिकों को ही प्रदान किये गये हैं। परन्तु जीवन-सम्पत्ति, रक्षा आदि अधिकार सबों को प्रदान किये गये हैं।

इन अधिकारों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो वे हैं जो कि राज्य की शक्ति के ऊपर एक संविधानिक नियन्त्रण स्थापित करते हैं। दूसरे वे हैं जो कि व्यक्ति की स्वतन्त्रताओं की रक्षा करते हैं। पहले प्रकार के अधिकारों पर व्यवस्थापिका विनी प्रकार का भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यदि यह ऐसा करेगी तो न्यायपालिका ऐसे किसी भी विधान को अवैध घोषित कर देगी। परन्तु दूसरी श्रेणी के अधिकारों का राज्य कुछ सीमा तक नियन्त्रण कर सकता है।<sup>1</sup>

संविधान में यह कहा गया है कि वे सब कानून जो कि नये संविधान के प्रावधान होने से ठीक पहले भारत में लागू थे उन भाषा तक लागू होंगे जिन तक वे मूल-अधिकारों से अलग हैं।<sup>2</sup> इसके अतिरिक्त राज्य को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह कोई ऐसा कानून बनावे जो कि इन अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। राज्य शब्द में यहाँ पर संघ, राज्य सरकार, राज्यों की सरकारें तथा भारत के अन्दर का बाहर-भारत-सरकार के अधीन सब अधिकारियों में हैं। इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि मूल अधिकार इन सब अधिकारियों को नियन्त्रित करते हैं।

**समता का अधिकार:**—प्रत्येक नागरिक राज्य की दृष्टि में समान है—राज्य ऊँच-नीच, गरीब-अमीर, आदि का भेद नहीं करेगा। सबों को राज्य की ओर से समान अवसर दिए जाएंगे। यह अधिकार लोक-तन्त्रात्मक प्रणाली में अत्यन्त महत्वपूर्ण है। बिना इसके हम लोक-तन्त्रात्मक सरकार की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। संविधान द्वारा इसके अन्तर्गत निम्नलिखित बातें रखी गई हैं:—

(१) **विधि के समक्ष समता**—इसका अर्थ यह है कि भारत-राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत कानून के मामले में सब बराबर हैं तथा सब को समान रूप में कानूनों का मरतब प्राप्त होगा। इसमें किसी प्रकार का भी भेद-भाव नहीं दिया जावेगा।

(२) **धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, या जन्म-स्थान के आधार पर या इनमें से किसी एक के आधार पर राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध कोई विवेद नहीं करेगा।** इसमें यह उल्लेख है कि ऊपर वर्णित बातों के आधार पर राज्य द्वारा

नागरिका में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जायगा। राज्य द्वारा प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह दुबाना मावजनिन भोजनालया होटला तथा मावजनिन मनोरंजन के स्थाना में जेम पाव मिनमा आदि में बिना किसी बाधा के प्रवेश कर सकता है। इसमें अतिरिक्त मविधान यह भी कहा गया है कि उन सब नुआ, नाशना स्नान घाटा मडका तथा मावजनिन समागम के स्थाना (public resorts) में जिनको कि राज्य में किसी प्रकार की महायना मिस्री है या जो मावगण जनना के उपयोग के लिए समर्पित किए गए हैं उपयोग का बिना किसी भेदभाव के सब नागरिका को अधिकार होगा।

(३) राज्य में सब नीतरिया या पदा पर नियुक्ति के लिये सब नागरिका को बराबर अवसर दिया जावेगा। घम जाति लिंग आदि के आधार पर नीतरिया में कोई भेद-भाव नहीं किया जावेगा। स्त्री तथा पुरुषों में भी इस बात में कोई फरक नहीं किया जावेगा। दोनों को समान अवसर प्रदान किया जावेगा।

(४) मविधान द्वारा अस्पृश्यता का अन्त कर दिया गया है। इस धारा द्वारा हिन्दू समज में जो बडा भार (कलह था उसका दूर करने की चेष्टा की गई है। छुपाछत के कोड को जिसने हमारे समाज की दुदशा कर दी थी हम अन्तर हटाने का प्रयत्न किया है। राज्य की दृष्टि में सब व्यक्ति समान है। अगर कोई मनुष्य किसी दूसरे पर अस्पृश्यता के आधार पर कोई रोक-टोक लगावे तो वह राज्य द्वारा दण्डित होगा।

(५) राज्य द्वारा सेना या रिद्या सम्बन्धी उपाधिया के अतिरिक्त और किसी प्रकार का खिताब प्रदान नहीं किया जावेगा। इस प्रकार सामाजिक समानता स्थापित करने की चेष्टा की गई है। यह भी मविधान में कहा गया है कि भारतीयों को विदेशी सरकार से भी कोई खिताब स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। परन्तु अगर कोई विदेशी भारत-भरकार को सेवा में है तो वह राष्ट्रपति की सम्मति से किसी राष्ट्र से खिताब स्वीकार कर सकता है।

मविधान में उपरोक्त उपबन्धा के साथ साथ यह भी स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि समता का अधिकार राज्य को निम्नलिखित काम करने में नहीं रोक मवेगा।

(१) सार्वजनिक स्थानों में हर एक को प्रवेश करने का बराबर अधिकार है परन्तु राज्य को यह अधिकार हागा कि वह स्त्रियों तथा बच्चों की मुविधा के लिए विशेष उपबन्ध बनावे।

(२) राज्य को यह भी अधिकार है कि वह नागरिक दृष्टि में तथा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए किसी वर्ग के लिये या जनसूचित-जातियों अथवा जन-जातियों के लिये कोई विशेष उपबन्ध बनावे ।

(३) यद्यपि नौकरियों में सबको समान अवसर दिया जावेगा परन्तु राज्य को यह अधिकार है कि वह पिछड़े हुये किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिसका राज्य की नौकरियों में प्रतिनिधित्व कम है, कुछ स्थान सुरक्षित कर सकेगा है ।

(४) राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी नौकरी के लिये अगर चाहें तो निवास सम्बन्धी योग्यता निर्धारित कर सकेगा है ।

(५) अगर किसी कानून के द्वारा यह प्रबन्ध है कि किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक सत्ता के पदाधिकारी किसी विशेष धर्म या सम्प्रदाय के हों तो ऐसा समता के अधिकार का विरोधी नहीं माना जावेगा ।

**स्वातन्त्र्य अधिकार** — “स्वतंत्रता ही जीवन है।” यह आधुनिक काल में प्रत्येक लोकतन्त्रात्मक दल का नारा रहा है। व्यक्ति का विकास बिना स्वतन्त्रता के असम्भव है। बिना स्वतन्त्रता के हम अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यथार्थ में जो राष्ट्र परतन्त्र रहे हैं उनका सांस्कृतिक, नैतिक तथा बौद्धिक ह्रास हुआ है। किसी प्रकार की भी उन्नति बिना स्वतन्त्रता के सम्भव नहीं है। आधुनिक काल में सभी सम्य देशों में नागरिकों को यह अधिकार दिला गया है। भारतीय-संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार मूल-अधिकारों की कोटि में रखा गया है। इनके अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकार नागरिकों को दिये गये हैं :—

(१) भाषण तथा लेखन की स्वतंत्रता इनके अन्तर्गत प्रेत की स्वतन्त्रता भी सम्मिलित है ।

यह अधिकार असीमित नहीं है। संविधान-संशोधक बिल (१९५१) द्वारा यह पास किया गया कि यह अधिकार राज्य को कोई ऐसा कानून पार करके से नहीं रोक सकेगा जो राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, शिष्टाचार या सदाचार के हित में भाषण तथा लेखन की स्वतन्त्रता पर रोक लगाते हों। इन संशोधन का बहुत विरोध किया गया था। परन्तु ५० मेहर ने इसे अत्यन्त आवश्यक बताया तथा यह संसद द्वारा पार हो गया ।

१. गंगूली द्वारा जो प्रथम संशोधक-बिल पास हुआ है उसके द्वारा यह उप-बन्ध बढ़ा दिया गया है ।

(२) शान्तिपूर्वक तथा बिना श्रयिष्यर मभा करने का स्वतन्त्रता । परन्तु इस प्रकार की स्वतन्त्रता पर भी राज्य मावजनिक व्यवस्था क हित म पकिन प्रकन राक लगा सकता ।

(३) सम्था या मध बनान की स्वतन्त्रता । यहाँ भी राज्य की मावजनिक व्यवस्था क हित में यकिनयसन राक लगाने का अधिकार है ।

(४) भारत क राज्य मध में सब जगह रे राक-टार नूमन (मराध मचाण) की स्वतन्त्रता ।

(५) भारत क राज्य मध र किसी भाग म निवास करने और इस जाने की स्वतन्त्रता ।

(६) सम्पति क अजन, धारण तथा व्यय करने की स्वतन्त्रता ।

परन्तु राज्य को माधारण जनता क हित में या किसी कानून-द्वारा ४५, ९ में वर्णित स्वतन्त्रता में युक्तियुक्त रोक लगाने का अधिकार है ।

(७) किसी भी प्रकार कृति उपजीविका व्यापार कारबार करने की स्वतन्त्रता ।

परन्तु यह अधिकार भी असीमित नहीं है । राज्य जनहित म इस प्रकार की स्वतन्त्रता पर भी राक लगा सकता है ।

(८) बिना अपराध किसी मनुष्य को दण्ड नहीं दिया जायगा और कोई व्यक्ति एक ही अपराध क लिए एक बार म अधिक दण्डित नहीं किया जायगा । किसी व्यक्ति का अपने ही विरुद्ध गवाही देने का बाध्य नहीं किया जावेगा ।

(९) बिना कानून क किसी व्यक्ति का अपन प्राण या शारीरिक स्वतन्त्रता मे वचिन नहीं किया जावेगा । परन्तु इस सम्बन्ध में समद को यह अधिकार है कि अगर वह प्राण या शारीरिक-स्वतन्त्रता मे वचिन करने का कोई कानून बनावे तो न्यायालय उसकी अवहेलना नहीं कर सकता है । न्यायालय यह नहीं कह सकते हैं कि यह कानून अवैध है । इस प्रकार इस विषय में व्यवस्थापिका के हाथ में शक्ति है न कि न्यायपालिका के ।

इस अधिकार म यह अर्थ है कि सरकार मनमानी न करे और बिना किसी अपराध क कोई मनुष्य अपराधी न करार दिया जावे तथा जेल में न ठूस दिया जावे । इस प्रकार की व्यवस्था आवश्यक है । अन्यथा सरकार अपने विरोधिया को मनमाना व्यवहार कर सकती है ।

(१०) बन्दीकरण और निरोध मे सरक्षण — इसक अन्तगत मविधान मे यह कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो बन्दी किया गया है बिना बन्दीकरण

के कारणों को बनाये हवालात में नहीं रखा जायगा। बन्दीकरण के बाद यह २४ घण्टे के भन्दर किसी मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जायगा तथा बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के आगे हवालात में नहीं रखा जायगा। उसको यह अधिकार होगा कि वह अपने पसन्द के वकील से सलाह करे तथा उसे अपनी रक्षा के लिए नियुक्त करे।

परन्तु अगर कोई व्यक्ति उस समय भारत का विदेशी-वादी है या कोई व्यक्ति जो कि नजरबन्दी कानून में परकटा गया है, उनके मामले में ऊपर वर्णित उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

इस स्थल पर हमें नजरबन्दी कानून (निवारक-निरोध-विधियाँ preventive detention) पर विचार करना चाहिए। मंत्रिपरिषद् द्वारा राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाये तीन महीने के लिये नजरबन्द कर सकता है। परन्तु यह अवधि दो प्रकार से बढ़ायी भी जा सकती है। (१) अगर नजरबन्दी के मामले में राय देने वाली समिति यह समझे कि यह अवधि बढ़ा ऐसी चाहिये। इस समिति के सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि उच्चतम-न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हों या न्यायाधीश होने की योग्यता रखते हों। (२) अगर संसद कोई कानून बनाकर यह निश्चय करे कि कितने काल के लिए किसी व्यक्ति को नजरबन्द किया जा सकता है। मन्त्र को यह अधिकार भी है कि वह यह निश्चित करदे कि अधिक से अधिक कितने बाल के लिए किसी व्यक्ति को नजरबन्द किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को जो कि नजरबन्द किया जावेगा सरकार सीधे यह बतावेगी कि वह क्यों नजरबन्द किया गया है। परन्तु अगर सरकार यह नोवे कि कुछ बातें जन-हित के विरुद्ध हैं तो वह उन्हें बतलाने की वाध्य नहीं है। नजरबन्द व्यक्ति को अपनी नजरबन्दी के विरुद्ध अपील करने के लिये प्रवृत्त किया जावेगा। (भारतीय संसद ने २५ फरवरी १९५० को एक कानून बनाया जिसने द्वारा किसी भी व्यक्ति को देश की सुरक्षा अथवा शान्ति के लिये १ वर्ष के लिए नजरबन्द किया जा सकता है। १९५१ में यह कानून कुछ परिवर्तनों से साफ किर पान किया गया। नजरबन्दी कानून भारतीय संसद द्वारा पुनः पान कर दिया गया है। इसको देश की शान्ति के लिये आवश्यक बतलाया गया है। प्रतिवर्ष इस कानून की एक वर्ष के लिये पारित किया जाता है।)

इस कानून की मंत्रिपरिषद् तथा में बहुत अधिक आलोचना की गई थी। कुछ सदस्यों ने इसे नागरिक-स्वतन्त्रता का पाउक कहा है। ऐसे उक्तियों में

मवेश अधिकार भय इस बात का रहता ॥ कि अगर सरकार चाहें तो वह इन अपने विराधियों की बायबाही को रोकने के लिए प्रयत्न कर सकती है।

**शोषण के विरुद्ध-अधिकार** —संविधान द्वारा इस अधिकार का प्रभाव करने में भारत राज्य क्षेत्र में मनुष्यों का पण्य अर्थात् खरीदना और बचन बेगार तथा विगो अथवा प्रकार का जबरदस्ती लिया हुआ अथवा अपराध बना दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता तो उसको राज्य द्वारा दण्ड दिया जावेगा। हमारे गाँवों में तथा पहिले की देशी रियासतों में दास की प्रथा थी। जमींदार तथा तालुकेदार अपने खाने में अन्न जातियाँ या गाँव में बगल पाल अथवा लागा में बेगार करवाने थे। अगर वह प्रथम अथवा है जिसका मेहनताना नहीं दिया जाता है। यह बहुत अनुचित प्रथा थी। संविधान ने इसे बन्द कर बहुत अच्छा किया है। आवश्यकता इस बात की है कि इसका पूर्णतया पालन करवाया जाय।

ऊपर दिए हुए अधिकार में राज्य के इस अधिकार में कोई कमी नहीं आती कि वह किसी सयोजना प्रयोजन के लिए बाध्य सेवा लागू करे। उदाहरणार्थ, राज्य देश की रक्षा के लिए सब योग्य व्यक्तियों को सेना में भर्तियाँ भर्ती करता है।

संविधान में यह भी कहा गया है कि १४ वर्ष से कम आयु वाले बालकों को पारखाना, खाना अथवा किसी अन्य मकदमय नौकरी में नहीं लगाया जायगा। इस उपबन्ध का उद्देश्य यह है कि भारत के भावी नागरिकों का स्वास्थ्य न बिगड़ जावे। परन्तु इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह आवश्यक था कि १४ वर्ष के बच्चे १६ वर्ष रह जायें तथा बालकों के साथ साथ स्त्रियों का भी खाना आदि में काम करना बन्द कर दिया जाय। क्योंकि खाना आदि में काम करना स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक है। विशेषकर हमारे जैसे देश में जहाँ कि पूँजीपतियों ने मजदूरों की दशा सुधारने का बहुत ही कम प्रयास किया है।

**धर्म स्वातन्त्र्य का अधिकार** —इसके अन्तर्गत संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अन्तःकरण की स्वतन्त्रता तथा अपने धर्म का बिना किसी छत्रोछत्र के मानने प्रचार करने तथा आचरण करने का अधिकार दिया गया है। परन्तु इस प्रकार का अधिकार असीमित नहीं है। इसलिए यह अधिकार आवश्यक अवस्था, गदाचार तथा स्वास्थ्य के विरुद्ध नहीं हो सकता है।

धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार इसलिए आवश्यक है क्योंकि अन्यथा जो दल शक्ति में होता है वह अपने धार्मिक विचारों को और सबों से मनवाने की

भी चेष्टा करता है। यह उचित नहीं है। ऐसे उदाहरण इतिहास में मिलते हैं।<sup>१</sup> सभी समय राज्य आजकल धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं। भारत भी धर्म के विषय में निष्पक्ष है। अर्थात्, राज्य स्वयं किसी धर्म-विरोध को ऐसी सुविधाएँ प्रदान नहीं करेगा जोकि धन्य धर्मावलम्बियों को न दी गई हो।

निर्वाणों को कृपाण धारण करने का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक धार्मिक सम्प्रदाय को धार्मिक समस्याओं की स्थापना तथा उनके पोषण का अधिकार दिया गया है। उनको धार्मिक-न्यायों के प्रवन्ध की स्वतन्त्रता दी गई है। वह इस उद्देश्य से जगम तथा स्थावर सम्पत्ति खरीद तथा रख सकता है।

राज्य ने अपने हाथ में यह अधिकार रखा है कि किसी धर्म में सम्बन्धित किसी प्रकार की आर्थिक या राजनैतिक क्रियाओं के लिए निषेध बना सके या उन्हें रोक सके। राज्य को समाज-न्याय के उद्देश्य में या हिन्दू-समाज के सब वर्गों के लिए हिन्दू सामंजसिक समस्याओं को खोलने के लिए, बानन बनाने का भी अधिकार है। हिन्दुओं में भिन्न, बौद्ध तथा जैन भी शामिल हैं।

किसी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की उत्पत्ति के लिए करो को देने की स्वतन्त्रता दी गई है। उसको इनके लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है। राज्य की शिक्षा-संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक-शिक्षा नहीं दी जावेगी। उन शिक्षा-संस्थाओं में जिनको इस उद्देश्य से ही स्थापित किया गया है वे उपबन्ध लागू नहीं होंगे। परन्तु उन शिक्षा-संस्थाओं में भी धार्मिक शिक्षा के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जावेगा।<sup>२</sup>

**संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार:**—भारत एक विनाश देश है। इसमें विभिन्न भाषा-भाषी लोग हैं। यद्यपि यह सत्य है कि व्यापक दृष्टि में भारत में संस्कृति की एकता है तथापि यह भी सच है कि प्रत्येक भाषा की अपनी-अपनी भाषा तथा संस्कृति है। भारत में १४ ज्ञात भाषाएँ हैं जिनका अपना साहित्य तथा इतिहास है। इसलिए सांस्कृतिक-स्वतन्त्रता ऐसे देश में प्राप्यम्भक है। हम में भी जहाँ कि कई विभिन्न संस्कृतियाँ पाई जाती हैं सांस्कृतिक स्वतन्त्रता प्रदान की गई है।

भारतीय नैविद्यान में इस विषय पर निम्नलिखित उपबन्धों की रचना की गई है —

1. G.N. Joshi, Ibid, p. 85.

2. इस विषय में भारतीय-अध की विवेकताएँ चान्दा अध्याय देखिये।



(१) प्रत्येक अल्प-संख्यक वर्ग का जिसकी अपनी भाषा लिपि या मस्कृति है उसको बनाये रखने का अधिकार है।

(२) ऐसी शिक्षा-संस्थाओं में जो राज्य द्वारा चलाई जाती हैं या जिनको राज्य आर्थिक सहायता देता है प्रत्येक नागरिक को प्रवेश करने का अधिकार है। अथवा धर्म भाषा जाति या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी नागरिक ऐसी संस्थाओं में प्रवेश पाने में वंचित नहीं किया जावेगा। परन्तु प्रथम संशोधन बिल (१९५१) द्वारा राज्य को यह अधिकार है कि वह पिछड़ी हुई जातियों के लिए इनमें कुछ स्थान सुरक्षित कर दे।

(३) धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्प-संख्यक वर्गों को अपनी हवि की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना तथा उनके प्रबन्ध का अधिकार है।

(४) राज्य द्वारा शिक्षा-संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने में इस आधार पर कोई भेद नहीं किया जावेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्प संख्यक वर्ग के प्रबन्ध में हैं।

**सम्पत्ति का अधिकार**—सत्रहवीं शताब्दी में अंग्रेज दाशनिक लॉक ने कहा था कि जीवन स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति प्राकृतिक अधिकार हैं। तब से वह सिद्धान्त लोकतन्त्रात्मक सरकारों ने (साम्यवादी-श्रोकतन्त्र को छोड़कर) माना है कि नागरिकों की सम्पत्ति में उनकी संपत्ति के बिना हस्तक्षेप नहीं किया जायगा। नागरिका की संपत्ति व्यवस्थापिका में उनके प्रतिनिधियों द्वारा दी जाती है। यह वही सिद्धान्त है कि बिना प्रतिनिधित्व के कर लागू नहीं होंगे।

भारतीय संविधान में भी इस प्रकार के उपबन्ध हैं। कहा गया है कि कोई भी मनुष्य कानून के अधिकार के बिना अपनी सम्पत्ति में वंचित नहीं किया जावेगा। परन्तु राज्य को ध्वस्तगत सम्पत्ति सार्वजनिक कार्य के लिये हस्तगत करने का अधिकार है और इसके लिए यह व्यवस्था की गई है कि अगर इस प्रकार कोई किसी की सम्पत्ति देगा तो उसको प्रतिकार (मुआवजा) देगा।<sup>12</sup> अगर राज्यों के विधान-मण्डल कोई इस प्रकार का कानून बनावे तो उनके प्रभावी होने के लिये राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है।

1 Under this (provision for compensation) the British interest in India will be protected Moreover, however great may be the urgency for social control the vested interests cannot generally be disturbed" S K Sen—Salient Features of Our New Constitution, p 9

न्यायालयों द्वारा जमींदारी-उन्मूलन-कानून को अवैध घोषित कर उसे लागू होने से रोकना न जाय इसलिए प्रथम संसोधन बिल (१९५१) में एक विशेष उपबन्ध की रचना की गई जो सम्पत्ति अधिकार को कृत्रिम में अधिक सीमित कर देता है। इस संसोधन की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि बिहार के हाईकोर्ट द्वारा जमींदारी उन्मूलन कानून व्यक्तिगत के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कहकर अवैध करार दे दिया गया था।

संविधान के चतुर्थ संसोधन अधिनियम (अप्रैल, १९५५) द्वारा प्रतिकार निश्चित करने में न्यायालयों की शक्ति और अधिक नकुचित कर दी गई है।

**संविधानिक उपचारों के अधिकार** — इनमें तात्पर्य उन अधिकारों से है जो कि नागरिकों को अपने मूल अधिकारों के रक्षार्थ दिये गये हैं। क्योंकि केवल मूल-अधिकारों के वर्णन मात्र से ही उनका नागरिक उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि अगर कोई नागरिक या स्वयं राज्य ही किसी नागरिक के मूल अधिकारों में हस्तक्षेप करे तो उसके अधिकारों की रक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये।

संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपने मूल अधिकारों के रक्षार्थ उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की सहायता ले सकता है।<sup>1</sup> यह न्यायालय इन मूल अधिकारों को प्रदत्त करने के हेतु निर्देश (directions), आदेश (orders) या लेख (writs) निकाल सकता है।<sup>2</sup> इसी प्रकार राज्यों के उच्च-न्यायालयों (High Courts) को भी अपने क्षेत्र के अन्दर इस प्रकार के निर्देश, आदेश तथा लेख निकालने का अधिकार दिया गया है। परन्तु नागरिक सीधा उच्चतम-

१. उच्चतम न्यायालय ने एक मुकदमे में निर्णय देते हुए कहा कि "उच्चतम न्यायालय संविधान द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों का गारन्टी बनाया गया है।

२. संविधान द्वारा न्यायालयों को मूल अधिकारों के रक्षार्थ विभिन्न प्रकार के लेख निकालने की शक्ति दी गई है। संक्षेप में उन लेखों का वर्णन किया गया है।

(अ) वन्दरी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) — यह लेख कई प्रकार का होता है। परन्तु सबसे मुख्य वह है जिसके द्वारा न्यायालय को यह अधिकार है कि वह किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को अपने सम्मुख उपस्थित करवाने

यायालय के पास आवदन न जा सकता है। इसका प्रतिनिधित्व मगदूम किमी क्षम यायालय को भा कानून द्वारा इस प्रकार का अधिकार प्रदान कर सकती है।

क्या मूल अधिकार निलम्बित अथवा सकुचित (suspended and restricted) किया जा सकता है — इस प्रश्न का उत्तर है कि व अधिकार ज्य द्वारा निम्बित तथा सकुचित किया जा सकता है —

(१) विधान सभापति द्वारा इन मूल-अधिकारों का संकुचित किया जा सकता है। प्रथम विधान-सभापति विन (१०५१) द्वारा इन मूल-अधिकारों में कुछ परिवर्तन किया गया है। इसका हम यथावधान वर्णन कर चुके हैं।

का आदेश दे सकता है। इस प्रकार यायालय इस बात की जांच कर सकता है कि वह व्यक्ति कानून के अनुसार गिरफ्तार किया गया है या नहीं। यह लेख नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका द्वारा काय-यायिका में नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। इसका सर्वप्रथम आरम्भ (१६६१) में इंग्लैण्ड में हुआ था।

(घ) परमादेश (Mandamus) — यह लेख एक आदेश है जिसके द्वारा एक उच्च यायालय किसी व्यक्ति से या निचले यायालय का काम करने का आदेश देता है जिसका करना उसका कर्तव्य है। यह नागरिकों के नागरिक हृदय तथा मानवजाति के मर्यादा के लिए प्रयत्न किया जाता है। इसका प्रयोग बना होता है जहां कि अधिकार तो है परन्तु उसका प्रवर्तन के लिये उपचार नहीं है।

(स) प्रतिषेध (prohibition) — यह लेख उच्च यायालय द्वारा अपने में निम्न यायालय के लिये निरस्त जाता है और इसका उद्देश्य निम्न यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जान से रोकना है।

(द) अधिकार पृच्छा (Quo warranto) — इस लेख द्वारा यायालय किसी भी व्यक्ति को जिससे गैर-कानूनी तरीके से किसी पद अधिकार आदि को प्राप्त किया हो उस पद पर या अधिकार का उपयोग करने से रोक सकता है।

(न) उत्प्रेक्षण (Certiorary) — इस लेख द्वारा एक उच्च यायालय अपने अधीनस्थ निम्न न्यायालय में किसी मुकदमे के कागजात आदि यह लेख की मांग सकता है कि वही वह अपने निश्चित क्षेत्र से बाहर तो नहीं जा रहा है।

(२) संसद् को यह शक्ति है कि वह यह निर्धारित करे कि सेना में या सार्वजनिक शान्ति को रक्षावाले सेनाओं में ये मूल-अधिकार जित्त आवश्यक तक कम या समाप्त किये जा सकते हैं, ताकि उनमें अनुशासन बनाये रखने तथा उनमें कर्तव्य पालन करवाने में कठिनाई न हो।

(३) संसद् को शक्ति है कि वह सेना-विधि (Court martial) के लगे हुए क्षेत्र में काम को मान्य कर सकती है। कार्य रूप में इसका अर्थ यह हुआ कि सेना-विधि लगे हुये क्षेत्र में मूल अधिकार निलम्बित रहेंगे।

(४) अगर राष्ट्रपति सकट-काल की घोषणा कर दे तो भाषण-नेशन की स्वतन्त्रता, संप्र तथा सभा की स्वतन्त्रता, आदि अधिकार उस काल के लिये निलम्बित हो जायेंगे। इसके साथ-साथ अन्य मूल-अधिकार भी अगर राष्ट्रपति आदेश दे दे तो सकट-काल की घोषणा जब तक लागू रहेगी तब तक के लिये निलम्बित हो जायेंगे।

**मूल-अधिकारों पर एक आलोचनात्मक दृष्टि**—कूट लेखकों के अनुसार भारतीय मविधान द्वारा जितने अधिकार प्रदान किये गये हैं उतने किसी भी अन्य देश के मविधान में उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए इनके विचार में भारत-वर्ष का मविधान लोक-तन्त्रात्मक मणराज्य का आदर्श उपरिपत करता है।

यह सत्य है कि मविधान में कई मूल-अधिकारों का वर्णन है तथा इस प्रकार नागरिक को मुविधाएँ प्रदान की गई हैं जो उसके व्यक्तित्व के विरुद्ध सहायक होंगी। समता तथा स्वतन्त्रता के अधिकार भी प्रदान किये गये हैं। परन्तु इसमें कमी यह है कि विधान में इन अधिकारों को निलम्बित तथा संकुचित करने के लिये इतने उपबन्ध दिये गये हैं जिनसे यह भय होता है कि ये अधिकार कार्य-रूप में अधिक काम नहीं करेंगे। मविधान के मूल अधिकारों से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्धों में संशोधन किया जा सकता है। इसलिए यह भय है कि सरकार किसी भी समय संशोधन द्वारा इनको संकुचित कर सकती है। इसके अतिरिक्त इन अधिकारों का उद्देश्य राजनैतिक प्रजातन्त्र स्थापित करना तो है परन्तु आर्थिक प्रजातन्त्र का इस भाग में कोई वर्णन नहीं। यह सच है कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व वाले भाग में कुछ इस प्रकार के उपबन्ध हैं। वे यथार्थ में व्यर्थ से हैं क्योंकि न्यायालय द्वारा उनका प्रवर्तन नहीं कराया जा सकता है। हमारे विचार में इन अधिकारों में इस प्रकार के अधिकार अवश्य सम्मिलित होने चाहिए जिनसे देश में आर्थिक प्रजातन्त्र स्थापित करने की ओर कदम उठाया जा सकता है। मविधान द्वारा राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि यह सकट काल की घोषणा द्वारा इन अधिकारों को निलम्बित कर सकता

६। राष्ट्रपति का आदेश ससद् के सम्मुख उपस्थित किया जाएगा। परन्तु संविधान में यह कही पर नहीं दिया हुआ है कि सफट जारी होने के कितने दिन के भीतर, राष्ट्रपति या इन मूल-अधिकारों का निलम्बित करने वाला आदेश ससद् के सम्मुख रखा जाय और न ससद् की आज्ञा ऐसे आदेश के जारी रहने के लिये आवश्यक की गई है। यह उचित नहीं है। यह कार्य-पालिका को बहुत अधिक शक्ति देती है। इस प्रकार के उपबन्ध भयपूर्ण है क्योंकि कार्यपालिका सफट के नाम में नागरिकों के अधिकारों का अपहरण कर सकती है। एक लेखर के अनुसार इन उपबन्धों में नागरिकों की स्वतन्त्रता के हित में भीष्मातिशीघ्र संशोधन होना चाहिये।<sup>१</sup>

### प्रश्न

- (१) मूल अधिकारों से क्या तात्पर्य है? भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को क्या क्या मूल अधिकार प्रदान किये गये हैं? (यू० पी० १९५६)
- (२) मूल अधिकारों का नागरिकों के जीवन पर क्या महत्व है? भारतीय संविधान को ध्यान में रखते हुए लिखिये।
- (३) भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार क्या हैं? इनकी क्या किंग प्रकार हो सकती हैं? (यू० पी० १९५६)

## राज्य की नीति के निदेशक तत्व

पिछले अध्याय में हमने नागरिक के मूल अधिकारों का वर्णन किया था। इन अधिकारों की विशेषता यह है कि स्वायत्तता की उन्हें प्रवर्धित करने की उचित संविधान द्वारा प्रदान की गई है। इसलिए अगर राज्य उनकी अवहेलना करे तो स्वायत्त नागरिक की रक्षा कर सके है। इन अधिकारों के प्रतिरूप संविधान के धर्म भाग में कुछ उदाहरण दिये जाते हैं। ये उदाहरण भी कुछ ऐसी सुविधाओं का वर्णन करते हैं जिनको प्राप्ति से नागरिकों का जीवन अच्छा हो सकता है। इनको राज्य की नीति के निदेशक तत्व कहा गया है। इन निदेशक तत्वों को विधान में क्या स्थान दिया गया है इसका जवाब यही उत्तर हो सकता है कि भारत सरकार इन तत्वों की प्राप्ति का नैतिक ध्यान रखे अपात्र कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका दोनों का यह कर्तव्य है कि वे इन तत्वों-प्राप्ति की चेष्टा करें। परन्तु कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका अगर इन तत्वों पर ध्यान न रखे तो क्या होगा? इसका उत्तर यह है कि उनको कोई बाध्य नहीं कर सकता है कि वे इन तत्वों का ध्यान रखें हो। क्योंकि इन तत्वों को किसी स्वायत्तता द्वारा बाध्यता न दी जा सकेगी। इन प्रकार ये स्वायत्तता के संरक्षण में नहीं हैं। कोई नागरिक सदा अपना स्वायत्तता को यह धारित नहीं दे सकता है कि राज्य इन तत्वों की अवहेलना कर रहा है और इसको बाध्य किया जाये कि धारित करे। संक्षेप में यह राज्य का नैतिक कर्तव्य कहा जा सकता है कि वह इन तत्वों का अपनी नीति निर्धारित करने में ध्यान रखे। परन्तु नैतिक कर्तव्य के पीछे वैयक्तिक एक ही शक्ति है जो कि उनका पालन करवा सकती और वह जनमत है। इसलिए देश में आगस्त्य जनमत होगा जो कि प्रत्येक रूप में सरकार के कार्यों का मूल-आति निरीक्षण कर रहा है तथा जब सरकार ने गलत कदम उठाया उसकी धारित करना कर रहा है, तब तो कुछ मात्रा तक धारित आशा की जा सकती है कि इन निदेशक तत्वों का राज्य की नीति के धारित में ध्यान रखा जायगा, अन्यथा ये केवल शीमार्य रह जायेंगे। इतिहास यह बतलाता है कि सरकार सभी तक ठीक काम करती है जब तक उनका यह मन रहता है कि

अगर यह और प्रकार में शासन न करेगा तो वह स्थान खूब कर देता जावेगी। क्याकि जमा प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासिक डॉ. एक्स्टन (Action) ने कहा है All power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely

जब मविधान मन्त्रा के इन शक्ति निदेशक तत्वों का उपयोग के ऊपर विचार हो रहा था तब यह मन्त्रा न यह विचार प्रस्तुत किया था क्याकि इनके पीछे कोई सानुनी शक्ति नहीं है इमार्ग में यह सही है। उद्देश्य इनका केवल परिणाम इच्छार्थ है। इस प्रकार का शासन करना व उल्टा में विधान समिति ने अग्रिम १० अम्बेदकर ने कहा था कि यद्यपि यह सच है कि इन निदेशक तत्वों के पीछे शक्ति का घल नहीं है तथापि यह कहना कि उनमें पीछे कोई भी शक्ति नहीं है उचित नहीं। इनको हमें उन आदेश पत्रा (Instrument of Instructions) की तरह समझना चाहिए जो कि १९३५ के एक्ट के अनुगमन ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल तथा गवर्नरों का दिया जाते थे। यद्यपि डॉ० अम्बेदकर यह मानने का प्रयत्न नहीं हुए कि ये निदेशक तत्व शक्ति हीन हैं तथापि यह भी स्पष्ट है कि ये कथन कुछ आदेशमय हैं।

कुछ ऐश्वर्या के अनुसार इन तत्वों के इस प्रकार मविधान में वर्णन में एक अर्थ है कि चाहे कोई भी इन चुनावों में जीत के फलस्वरूप शासन का कार्य सम्भाले राज्य की नीति में एक प्रकार की स्थिरता रहेगी। क्याकि लोकतन्त्रात्मक प्रणाली में यह सम्भव है कभी तो अनुदार दल की सरकार हो तथा कभी कोई ऐसा दल शक्ति में आ जाय जिसका कि शासिकारी भावनात्मक है। इन निदेशक तत्वों के द्वारा अनुदार दल प्रतिक्रियावादी नीति के अनुसार न कर सकेगा तथा इसी प्रकार शान्तिकारी दल को भी अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा।

इन तत्वों के मविधान में वर्णन से यह मचित किया गया कि राज्य अपनी आन्तरिक नीति का एक प्रकार चलाएगा जिससे कि नागरिकों का जीवन आर्थिक वृद्धि आदि में स्थिर रहेगा। पर गणतन्त्र नीति में राज्य शान्ति की नीति ग्रहण करेगा। ऐसा कि एक ऐश्वर्य ने कहा है कि राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों के लिए अच्छे जीवन की सम्पत्ति दोगले उपस्थित करे और अच्छे जीवन के लिए आपुनित काल में ये सब करने आवश्यक है जो कि निदेशक तत्व यात्रे भाग में वर्णित हैं। परन्तु इन सब बातों के दण्डन के लिए मविधान उपयुक्त स्थान नहीं है।

हमारे विचार में इनका नवविधान में वर्णन तभी उचित था अगर इनके पीछे बानूत की शक्ति होती अन्यथा इनका वर्णन बेकार है।

नवविधान में कहा गया है कि ये तत्त्व देश के शान्त में मलभूत हैं तथा बानूत बनाने में इनका प्रयोग करना राज्य का वर्तमान होगा। स्वार्थ में तत्त्व देश के शान्त में मूढभूत हैं इसलिए सरकार के प्रत्येक अंग का वर्तमान इनका प्रयोग करना होगा।

ये तत्त्व निम्नलिखित हैं :—इनका प्रयोग करने दिया जावेगा।

(१) राज्य लोक-व्यवस्था की उन्नति के लिये ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना तथा रक्षा करेगा जिसमें कि सर्वो को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय प्राप्त हो सके। इन उपबन्ध में प्रयुक्त सामाजिक आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय शब्द नवविधान की प्रस्तावना में भी पाये जाते हैं। जब कि प्रस्तावना में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि नवविधान को बनाने का उद्देश्य ही समाज में न्याय की स्थापना है, तो फिर ये उसको सिद्ध करने में अधिक लाभ नहीं प्रतीत होता है। इनके अतिरिक्त प्रश्न यह उठता है कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक न्याय की प्राप्ति कैसे होगी? अबतक यह न बनलाया जावे कि इन भावों का प्राप्त करने का मार्ग क्या है, केवल भावों को स्तित देने में अधिक लाभ नहीं हो सकता है। नवविधान में यह कहाँ पर नहीं कहा गया है कि इन उद्देश्य के लिए उन्नति के माधनों का राष्ट्रीयकरण किया जावेगा। जब तक कि इन माधनों का राष्ट्रीयकरण नहीं होता है, तब तक देश में आर्थिक प्रजातन्त्र के स्थापित होने की आशा करना केवल व्यर्थता है। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यह उपबन्ध अस्वाभाविक है।

(२) राज्य की नीति का उद्देश्य निम्नलिखित बातों को प्राप्त करना बनलाया गया है :—

(क) भारत के सब नागरिकों को—मर नया नारी—समान रूप में जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। इसका अर्थ यह होगा कि भारत में बेकारी उठ जावेगी। आज तो देश में एक बहुत बड़ी संख्या बेकारों की है। प्रश्न यह है कि किस प्रकार राज्य बेकारी को दूर करेगा? इसका उत्तर हमें कही नहीं मिलता है। कुछ अन्य विधानों में भी यह कहा गया है कि बेकारी

१. एक विद्वान के अनुसार 'As these principles cannot be enforced in any court they amount to little more than a manifesto of aims and of aspirations.' Prof. K. C. Wheare.



को नष्ट किया जायगा। परन्तु इसके लिए उनमें यह उपबन्ध है कि प्रत्येक नागरिक को उसकी योग्यता अनुसार काम करने का अधिकार (right to work) दिया गया है। जब तक ऐसा नहीं होगा बेकारी नहीं हट सकती है।

(ख) समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बाँटा हो जिससे समस्त समाज का हित हो।

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चल जिससे कि धन तथा उत्पादन के साधन छोड़ स लोगो के हाथों में ही न केन्द्रित हों जायें और इस प्रकार सर्वसाधारण का अहित हो।

(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन मिले।

(ङ) सुकुमार बालकों की व्यवस्था का तथा श्रमिक पुरुषों तथा स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा शक्ति का दुरुपयोग न हो। इसके अतिरिक्त ऐसा न हो कि आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर लोग ऐसे काम करें जो कि उनका आयु या शक्ति के अनुसार न हो।

(च) शोष तथा विचार व्यवस्था का शोषण और आर्थिक तथा नैतिक परित्याग (abandonment) से बचाव हो।

इस भाग में वर्णित उपबंधों का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब कि उत्पादन साधनों पर बाँटे स व्यक्तियों का अधिकार न हो कर सम्पूर्ण समाज का हो। बिना ऐसा किए हुए न तो बेकारी दूर की जा सकती है और न धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के हित में केन्द्रीयकरण।

(३) ग्राम पंचायत का संगठन—महात्मा गांधी का यह विचार था कि स्वतन्त्र भारत की प्रशंसनीय इकाई ग्राम ही है। भारत में जन-संख्या का बड़ा भाग गाँवों में ही रहता है तथा खेती ही हमारे आर्थिक जीवन का आधार है। इसी कारणों से गाँधी जी के स्वनात्मक कार्यक्रम में ग्राम-सुधार बहुत महत्वपूर्ण था। इसी के प्रभाव स्वरूप सविधान में भी यह कहा गया है कि राज्य ग्राम-पंचायतों का संगठन करेगा। इन पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ तथा अधिकार दिये जायेंगे ताकि वे स्वायत्त-शासन (Self-Government) की इकाइयों के रूप में काम कर सकें।

कई राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि में इस प्रकार के संगठन स्थापित किये गये हैं। इन्हें सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब कि ये स्वार्थी

मनुष्यों के हाथों में न पहुँच जावे। इनके अधिकारों का विस्तृत वर्णन भी किया गया है।

(४) राज्य अपनी धार्मिक नीति के अनुसार इन बातों का प्रयत्न करेगा कि सब मनुष्य काम या नके तथा शिक्षा या नके। इनके अनिवार्य राज्य इन बातों का भी प्रयत्न करेगा कि वेकरी वृद्धता जवहानि तथा अन्य अनहंभमाय (undeserved want) की दशाओं में नावृजनिव नटापना या नके। आजकल कई अन्य राज्यों में इन उद्देश्यों के लिये कानून बनाये गये हैं। १९वीं शताब्दी तक यह राज्य का काम नहीं समझा जाता था कि वह इन प्रकार के काम करे। परन्तु २०वीं शताब्दी में सभी विचारक इन बातों को मानने लगे हैं कि राज्य को इन प्रकार के काम करने चाहिये।

(५) राज्य इन बातों का उन्वय करेगा कि काम करने की दशाएँ उचित हों। वे ऐसी हों जो कि मनुष्यों के लायक हों, इसमें यह तात्पर्य है कि काम की दशाएँ ऐसी न हों जहाँ कि जीवन को खतरा हो, अपवा किमी अन्य प्रकार से शरीर की हानि पहुँचावे या आदमी के मान के प्रतिभूल हों। इनके साथ साथ राज्य इन बातों का भी प्रयत्न करेगा कि प्रवृत्ति अवस्था में स्त्रियों को सहायता मिले। प्रत्येक मनुष्य देश में इन उद्देश्यों के लिये कुछ कानून बनाए हैं।

(६) राज्य कानूनों के द्वारा (या धार्मिक-मगडन द्वारा) या अन्य किसी प्रकार में इन बातों का प्रयत्न करेगा कि सब अधिकारों चाहे वे हानि के हों या उद्योग के या अन्य किसी प्रकार के काम, निवाह, मजूरी आदि मिले। अधिक अपना जीवन ठीक प्रकार में यापन कर सकें इसलिये उनके जीवन-स्तर को ऊँचा करने का प्रयत्न किया जावेगा। वे अपने अवकाश का उचित रीति में उन्वय करें तथा उनको सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर मिलें, इनका भी राज्य प्रयत्न करेगा। इनके साथ-साथ गाँवों में अवस्था सुधारने के लिए राज्य कुटीर-उद्योगों की स्थापना करेगा।

(७) भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए राज्य एक समान व्यवहार-निति (Civil Code) प्राप्त कराने का प्रयत्न करेगा। इसका यह उद्देश्य है कि समस्त राज्य में एक ही कानून (Law) हो। इसका अर्थ यह है कि सब नागरिकों को समान अधिकार मिलें चाहिये। भारत में आज का उद्देश्य इन प्रकार के विभिन्न कानूनों को हटाने का प्रयत्न करना है।

(८) राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि मांशान के प्राप्ति में दस वर्ष के अंदर सब जाति का १८ वर्ष का समानि तक निर्यात तथा अनिर्यात शिक्षा दी जावे। हमारे विचार में यह उपर्युक्त सूचक-चिह्न का भाग में जाना चाहिये था। हमारे देश में ऐसी अनिर्यात है कि बिना अनिर्यात तथा निर्यात का यह न था कि नही किया जा सकता है। यह राज्य का कर्तव्य है कि यह अनिर्यात का समान न करे।

(९) परंपि राज्य अपने शेष के अनिर्यात समी की शिक्षा तथा शेष सम्पत्ति शिक्षा की अनिर्यात प्रयत्न करेगा तथापि विनियमन जनता के विरुद्ध हा भागा—आदिम जातियों तथा शिक्षा-व शिक्षा तथा शेष सम्पत्ति शिक्षा का विनियमन करना। उनमें करेगा तथा सामाजिक अनिर्यात और अनिर्यात शेष का उनका न करेगा। यह अनिर्यात है कि राज्य जनता के विरुद्ध भागा की अनिर्यात की और अनिर्यात न करेगा। अनिर्यात के अनिर्यात में भी इस प्रकार का उपकरण है।

(१०) राज्य इस बात का प्रयत्न करेगा कि इसका अपने मुख्य कर्तव्य में मान की लागा का स्वास्थ्य नृणा का राज्य तथा उनका अनिर्यात पुष्टि-क (Level of Nutrition) और जीवन स्तर का ऊंचा किया जावे। हमारे देशवासियों का स्वास्थ्य समान तथा अनिर्यात पुष्टि-क और जीवन-स्तर का ऊंचा करने के लिये यह अनिर्यात है कि देश में गरीबी तथा बकारी का दूर किया जावे। जब तक राज्य इस दिशा में कोई बदल नहीं उठता है तब तक यह उपर्युक्त व्यर्थ है। हमारे देश में पनि व्यक्ति पीछे जीवनन अनिर्यात इतनी कम है कि पूरा पेट भोजन ही सम्भव नहीं है अल्प भोजन का ता प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य अपने जाति का स्वास्थ्य गरीबी के लिये अनिर्यात मादक-पदार्थों तथा अनिर्यातों के उपभाग पर निवारण दवा के लिये अनिर्यात नृणा का प्रयास करेगा। अर्थात् राज्य गरीबी तथा गरीबी पीन का बीजा पर राक्ष लगावेगा। यह बहुत अच्छा है कि राज्य मादक पदार्थों पर अनिर्यात लगावेगा। यह समाज के गरीब वर्गों के अनिर्यात किया जायगा। परन्तु प्रश्न यह है कि लोग गरीबी वस्तु का व्यवहार क्या करते हैं? इसका उत्तर यह है कि निम्न शर्तों का जीवन इतना नीरस तथा दुष्प है कि दिन भर के बर्तन पश्चिम के पश्चान् मनोरंजन का कोई अर्थ मारन न हान के कारण के अनिर्यात गरीबी यकात का देश में मिटाना चाहते हैं। यद्यपि यह सत्य है कि इन वस्तुओं का सेवन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है तथा उनको अनिर्यात व्यवस्था को और भी गरीब कर देता है तथापि यह भी सत्य है कि यह उनके मनोरंजन का मुख्य साधन भी

है। इसलिए केवल 'शराब मत पिओ' कहने से न तो शराब पीना बन्द हो जावेगा और न सरकार का कर्तव्य ही पूरा होया। सरकार को चाहिये कि वह इन निम्न वर्गों के लिये कोई मनोरंजन के माधन प्रस्तुत करे, उनके जीवन की दशाओं को सुधारने की कोशिश करे तथा उनके शिक्षा का प्रचार करे। तब तो इन और सफलता मिल सकती है नहीं तो पहले लोग खुलकर पीने से धब छिपकर पियेंगे।

(११) राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि कृषि तथा पशु-पालन आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि के हों। यह गाँवों, बछड़ों तथा अन्य दुधार और बाहक टारों की नस्ल को बचाने तथा सुधारने की चेष्टा करेगा। भारत जैसे कृषिप्रधान देश में यह आवश्यक है कि हमारे खेती के टण को सुधारा जाय। आज भी भारत में अधिकतर किसान बाबापारम के जमाने से चलें घाये तरीकों में खेती करते हैं। इसका फल यह है कि प्रति एकड़ उपज हमारे यहाँ अन्य सम्य देशों की तुलना में अत्यन्त कम है। हम दूसरे देशों का खाने के लिए मुह साकते हैं। टारों की नस्ल सुधारना भी अत्यन्त आवश्यक है।

(१२) राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐतिहासिक या कलात्मक महत्व के प्रत्येक स्मारक या वस्तु को नष्ट होने से बचावे। इसके लिये मन्द द्वारा कानून बनाया जावेगा। भारत में इस प्रकार के कई स्थान हैं। उनकी रक्षा कार्यपालिका को करनी चाहिये क्योंकि वे हमारी महानता के चिह्न हैं।

(१३) राज्य अपनी लोक सेवाओं को न्यायपालिका से पृथक् करने के लिये प्रयत्न होगा। भारत में इसकी बहुत आवश्यकता है कि इन दोनों का पूर्ण पृथक्करण कर दिया जावे। इनका इस प्रकार पृथक्करण निम्न न्याय के लिये बाधनीय है। इस विषय में थोड़ा-सा कदम उठाया गया है। परन्तु यह आवश्यक है कि शीघ्र ही यह पूर्ण रूप से कर दिया जावे।

(१४) भन्त में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी राज्य कुछ धाद्यों को लेकर चलने का प्रयत्न करेगा। ये निम्नलिखित हैं :—

- (क) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति, तथा सुरक्षा की उन्नति,
- (ख) राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धों को स्थापित करना,
- (ग) राष्ट्रों के आपस के व्यवहारों में, अन्तर्राष्ट्रीय कानून तथा सन्धियों के प्रति आदर-भाव बनाना,
- (घ) अन्तर्राष्ट्रीय-विवादों को मध्यस्थता (arbitration) द्वारा निवटारे के लिए प्रोत्साहित करना। अर्थात् अन्तर्राष्ट्रीय विवाद शान्तिपूर्ण उपाय से हल किये जायें।

उपर्युक्त नीति निदेशक-तत्वा में उन सब बातों का वर्णन किया गया है—  
यद्यपि उनको बाध्यता नहीं दी गई है—जो कि एक सम्य राज्य की आन्तरिक  
सथा बाह्य नीति को निर्धारित करते हैं।

### प्रश्न

- (१) राज्य के निदेशक सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिये। संविधान में इन  
का क्या महत्त्व है ? (यू० पी० १९५२)
- (२) राज्य की नीति के भारतीय संविधान के अनुसार क्या निदेशक  
सत्त्व हैं ?
- (३) संविधान में दिये गये नीति निदेशक तत्वा का उल्लेख कीजिये।  
इनका क्या महत्त्व है ? पिछले दस वर्षों में इन तत्वों की कहीं तक पूर्ति हुई है ?  
(यू० पी० १९५७)

## संघीय कार्यपालिका : राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति

संविधान के द्वारा हमारे देश में साम्य पद्धति के शासन की स्थापना की गई है। इन प्रकार के शासन की मुख्य विशेषता यह होती है कि इसमें एक नाम मात्र का प्रधान होता है जिसके नाम से शासन-कार्य चलाया जाता है। परन्तु शासन की यथार्थ-शक्ति मंत्रिमण्डल के हाथ में होती है। यह यथार्थ-कार्यपालिका मण्डल के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत में राष्ट्र के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। संविधान की ५२वीं तथा ५३वीं धाराओं में कहा गया है कि "भारत का एक राष्ट्रपति होगा। गण की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इनका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा।" राष्ट्रपति वास्तव में केवल कार्यपालिका का ही प्रधान नहीं है वह राज्य का प्रधान (Head of the State) है। भारत का राष्ट्रपति संविधान द्वारा कुछ ऐसे अधिकारों में विभूषित किया गया है कि नाममात्र का प्रधान होने हुए भी उनकी शक्तियाँ यथार्थ हैं।

**राष्ट्रपति का निर्वाचन** — भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति मन्त्र के समस्त अन्य देशों में भिन्न है। उदाहरणार्थ, फ्रान्स का राष्ट्रपति मन्त्र द्वारा निर्वाचित होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति एक निर्वाचक मण्डल (electoral college) द्वारा चुना जाता है जिनके सदस्य प्रत्येक राज्य से जनता द्वारा चुने जाते हैं। परन्तु भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति इसमें भिन्न है। साम्यता केवल यहाँ है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया जायगा परन्तु अप्रत्यक्ष होगा। फ्रान्स तथा अमेरिका में भी ऐसा ही है।

भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक-गण स्थापना की जायेगी। भारतीय-संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचन-गण के सदस्य होंगे। अर्थात्, इसमें मन्त्रीय सदस्यों को स्थान नहीं दिया गया है। इस निर्वाचक-गण के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के

निर्वाचित सदस्यों की मतमसूचा तथा राज्य की विधान-सभा का निर्वाचित सदस्यों का जनसंख्या वगैरह होगी।

प्रथम प्रश्न यह है कि इस निर्वाचन-मण्डल की मत-संख्या किस प्रकार निर्दिष्ट की जावेगी? इसका जग निम्नलिखित आया है

(१) राज्या की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों में प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की मतमसूचा — किसी राज्य का जनसंख्या को उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या में भाग दिया जावेगा या भाग फट जावेगा उसका फिर से १००० द्वारा भाग दिया जावेगा। इस प्रकार जो भागफल आयेगा उस राज्य के विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का उनका ही मत दान का अधिकार होगा। इनको इस प्रकार रखा जा सकता है।<sup>१</sup>

राज्या की कुछ संख्या

राज्य की विधान-सभा के कुछ निर्वाचित सदस्यों की संख्या — १०००

१००० से भाग देने के बाद जो शेष बचेगा अगर वह ५०० से कम हुआ तो वह छोड़ दिया जावेगा परन्तु अगर वह ५०० से अधिक हुआ तो प्रत्येक सदस्य के मतमसूचा और जोड़ दिया जावेगा। उदाहरणार्थ मान लीजिये भारत में किसी राज्य की जनसंख्या ५१२१२६०० है। वहाँ की विधान-सभा में १०० निर्वाचित सदस्य हैं। प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की मत-संख्या उपरोक्त विधि से निश्चित करनी है। यह इस प्रकार होगा।

$$\frac{\text{प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत की संख्या}}{\text{संख्या की संख्या}} = \frac{५१२१२६००}{५००} = १०००$$

= १०२ तथा शेष ४२३ बचेगा। परन्तु यह ५०० से कम है इसलिये इसका छोड़ दिया जावेगा। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य की विधान-सभा के प्रत्येक निर्वाचित-सदस्य की मत-संख्या निश्चित की जावेगी।

1 This has been done "in order to ensure his dual responsibility as a federal officer to the State Assemblies and as a National officer to the Union parliament Banerjee B. १—New Constitution of India, p 72

इस विधि में यह स्पष्ट है कि जिन राज्यों की जनसंख्या अधिक होगी उनकी विधान-सभाओं के सदस्यों को कम जनसंख्या वाले राज्यों के सदस्यों से, राष्ट्रपति के निर्वाचन में अधिक मत देने का अधिकार होगा। इसी प्रकार अधिक जनसंख्या वाले राज्यों के कम जनसंख्या वाले राज्यों में अधिक मत होंगे अर्थात्, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों को बराबर मत नहीं दिए गए हैं क्योंकि मत निर्दिष्ट करने का आधार जनसंख्या को रखा गया है। इस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न-भिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व एक में मापमान से किया गया है।

(२) संसद् के दोनों सदनों के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य की मत-संख्या.—विधान में यह कहा गया है कि संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की मत-संख्या का योग सब राज्यों के विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत-संख्या के योग के बराबर होगा उदाहरणार्थ, अगर सब राज्य के विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्यों की मतसंख्या का योग तीन लाख है तो संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की मत-संख्या का योग भी इतना ही होगा।

इससे यह स्वाभाविक है कि प्रत्येक संसद् की निर्वाचित सदस्य की मत-संख्या निर्दिष्ट करने के लिए भारत के सब राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों के योग को, संसद् के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दे दिया जावे। जो भागफल आवेगा उसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जावेगा तथा अन्य भिन्नो की उपेक्षा की जावेगी।

उदाहरणार्थ, मान लीजिये सब राज्यों के विधान-सभाओं के निर्वाचित सदस्यों की मत-संख्या का योग ३००,००० (तीन लाख है)। भारतीय संसद् के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या ७०० है, प्रत्येक संसद् के

निर्वाचित सदस्य को  $\frac{300,000}{700}$  मत अर्थात्  $\frac{428}{7}$  देने का अधिकार होगा।

यहाँ पर  $\frac{428}{7}$  भापी भिन्न से अधिक है, इसलिए प्रत्येक संसद् का निर्वाचित-सदस्य ४२९ मत देगा।

१. यह प्रत्येक संख्या यथार्थ संख्या नहीं है, केवल समझाने के लिए मान रखी गई है।



इस निर्वाचन-गण के सदस्या व मता द्वारा राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। यह निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति (Proportional representation) के अनुसार एक परिवर्तनीय मत विधि (Single Transferable Vote) द्वारा होगा, अर्थात् मत इस विधि से गिन जायगे।<sup>१</sup> इस निर्वाचन में अपनदान गुप्त (Secret ballot) होगा।

विधाना के अनुसार एक-परिवर्तनीय मतविधि की यह आवश्यक दशा है कि बहुनिर्वाचन मंडल हो अर्थात् एक से अधिक प्रतिनिधि एक मंडल में से चुने जायें। परन्तु राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो केवल एक ही उम्मीदवार को चुनना है। अतएव इस विधि का प्रयोग कैसे होगा यह स्पष्ट नहीं है।<sup>२</sup>

राष्ट्रपति के लिये निर्वाचन पद्धति में तीन विरोध बातें दृष्टिगोचर होती हैं।

(१) अप्रत्यक्ष निर्वाचन—राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष-प्रणाली से व्यर्थ मताधिकार द्वारा नहीं रखा गया है। संविधान सभा में कुछ सदस्या का मत था कि प्रत्यक्ष प्रणाली से निर्वाचन हो। परन्तु इसके विरुद्ध निम्नलिखित सर्व दिये गए।

(अ) प्रत्यक्ष-प्रणाली का व्यवहार करने में बहुत अधिक समय तथा शक्ति की हानि होगी।

(ब) मनदाताओं की संख्या बरीबत अठारह करोड़ ५० लाख होगी। इतनी बड़ी संख्या के लिये उचित प्रकार की निर्वाचन व्यवस्था करना अत्यन्त कठिन है।

(स) संविधान द्वारा यथाय शक्ति मन्त्रिमंडल तथा व्यवस्थापिका का दी गई है न की राष्ट्रपति को। इसलिये यह अनावश्यक है कि राष्ट्रपति का व्यक्त मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष प्रणाली से निर्वाचन हो।<sup>३</sup>

(द) भारत व अधिकांश व्यक्ति अशिक्षित हैं। अतएव अपन उत्तर-दायित्व को ठीक प्रकार नहीं पूरा कर सकेंगे।

१ संविधान में इसके लिये 'एकल सक्रमणीय मत' शब्द प्रयुक्त हुये हैं। इनका अर्थ समझने के लिए लेखक की 'नागरिक शास्त्र के आधार' पुस्तक देखिये।

२ एक व लेखक अनुसार "Possibly what the Constitution intends is election of the President by the alternative of the preferential vote" Dr. Sharma, Ibid, p. 105

३ पंडित नेहरू ने संविधान निर्मात्री सभा में कहा था, "If we had the President elected on adult franchise and did not give him any power it might become a 'little anomalous'"

(२) मसद् के सदस्यों की मत मर्यादा का योग सब राज्यों के विधान-सभा के सदस्यों की मत-मर्यादा के बराबर रखा गया है। इसका कारण यह है कि मसद् के सदस्य भी सम्पूर्ण भारत की जनमर्यादा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तथा विधान सभाओं के सदस्य भी सम्पूर्ण भारत की जनमर्यादा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए दोनों की राष्ट्रपति के निर्वाचन में समान होना चाहिए।

(३) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। इसका कारण यह बनलाया गया है कि मसद् में नागरिकता एक ही दल का बहुमत होगा तथा वही दल गवर्नर-इल का भी निर्वाचन करेगा। इसलिए अगर केवल मसद् को ही राष्ट्रपति के निर्वाचन का अधिकार होता तो यह भय था कि बहुत दल विरुद्ध ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति चुनता जो कि उनका ही समर्थक होता। परन्तु यह उचित नहीं होता। इसलिए विधान-निर्माताओं ने राज्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया है।

राष्ट्रपति के लिए योग्यताएँ—राष्ट्रपति होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिये।

- (घ) भारत का नागरिक हो।
- (ब) पैंतीस की आयु पूरी कर चुका हो।
- (ग) लोक सभा के लिए नदस्य निर्वाचित होने की योग्यता अ. ५१। १

(द) भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन या इन सरकारों में नियुक्ति किसी स्थानीय या अन्य अधिकारी के अधीन कोई नाम का पद न धारण किया हुआ हो। परन्तु तान के पद के अन्तर्गत, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राज्यपाल अथवा सचिव या राज्यों के मंत्रियों का पद नहीं निभाना जावेगा। इसमें यह तात्पर्य है कि ये लोग सरकारी नौकरी में होते हुए भी राष्ट्रपति-पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं।

(ध) जो व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण कर रहा है अथवा कर चुका है वह पुनः अगर उन्हीं उपरोक्त योग्यताएँ बतलाना है राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। अमेरिका में पहले एक अधिनियम बन गया था कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए दो बार से अधिक नहीं चुना जावेगा। परन्तु रूजवेल्ट (एफ० डी०) ने चार बार निर्वाचित होकर इन अधिनियम को भंग कर दिया। परन्तु अब अमेरिका में नविधान में ही यह

मनामन हो गया है कि कोई व्यक्ति दो बार में अधिक इस पद के लिये निर्वाचित नहीं होगा।

) अन्य शर्तें — (अ) राष्ट्रपति न तो मसद के किसी मदन का और न किसी राज्य के विधान-मण्डल के मदन का सदस्य होगा। अगर मसद के किसी मदन का, अथवा किसी राज्य के विधान-मण्डल के मदन का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जावे, तो राष्ट्रपति के रूप में पद-ग्रहण की तारीख में उसी उमर मदन की सदस्यता का अपने आप अन्त हो जावेगा।

(ब) राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण न करेगा। यह उपबन्ध इसलिए रखा गया है ताकि राष्ट्रपति अपना सम्पूर्ण समय अपने पद के कर्तव्यों के निवाहने में ही लगावे तथा वह अन्य किसी उद्देश्य में प्रभावित न होगा। जो मनुष्य कोई अन्य आर्थिक लाभ का पद धारण किये होगा वह स्वभावतः ही अपनी राष्ट्रपति पद की शक्ति का उस समस्या अथवा व्यक्ति के हितार्थ उपयोग करने की चेष्टा करेगा जिसके नीचे वह आर्थिक-लाभ का पद ग्रहण किये हुये है।

पदावधि — राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से ५ वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। परन्तु यह अवधि कुछ दशाब्दों में कम हो सकती है —

(क) अगर राष्ट्रपति ५ वर्ष से पूर्व ही त्यागपत्र दे दे। इनमें उसका स्नाक्षर होने चाहिये। यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सम्बोधित किया जावेगा। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना एकदम लोक-सभा के अध्यक्ष को देगा।

(ख) अगर राष्ट्रपति नविवान का अतिक्रमण करे तो वह मसद द्वारा महाभियोग से अपने पद से हटाया जा सकेगा।

रिक्त स्थान पूर्ति — नये राष्ट्रपति का निर्वाचन पहले राष्ट्रपति की पदावधि पूरी होने से पूर्व ही कर दिया जावेगा। राष्ट्रपति अपने पद की समाप्ति हो जाने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद-धारण किये रहेगा। यदि किसी राष्ट्रपति का पद पूरी अवधि में पहिले ही रिक्त हो जावे, अथवा उसकी मृत्यु हो जावे या वह पद त्याग दे, या वह महाभियोग द्वारा हटाया जावे, तो उस दशा में पद रिक्त होने के ६ मास बीतने के पहिले ही नये राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जावेगा। नया राष्ट्रपति पद-ग्रहण की तारीख से ५ वर्ष

तक अपने पद पर रहेगा। ऐसे अवसरों पर नये राष्ट्रपति के चुनाव तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा।

**राष्ट्रपति का वेतन आदि.**—राष्ट्रपति के लिये, संविधान द्वारा १०,००० रु० मासिक वेतन निश्चित किया गया है। इसके अतिरिक्त उसको रहने के लिये एक निवास-स्थान दिया जायगा। उसको इसका किराया नहीं देना होगा। राष्ट्रपति को अन्य भत्ते आदि भी दिये जायेंगे। जब तक इनका निश्चय संसद नहीं करेगी तब तक राष्ट्रपति प्रति वर्ष लगभग १५,२६,००० रुपये यात्रा, उत्कार, भत्ते, अनुदान, आदि पर व्यय कर सकता है। उसके कार्यकाल में उसके भत्ते, आदि नहीं घटाये जायेंगे। यद्यपि पहले के गवर्नर-जनरलों की तुलना में राष्ट्रपति का वेतन भत्ते आदि बहुत कम है, तथापि यह भी सत्य है कि हमारी आर्थिक-अवस्था को देखते हुये यह काफी ठीके रहे गये हैं।

**महाभियोग**—राष्ट्रपति अपने पद से ५ वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व भी हटाया जा सकता है। इसके लिये संविधान में महाभियोग का उपबन्ध है। अगर कोई राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण कर रहा है तो संसद का कोई भी सदन उसके विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव रख सकता है। ऐसे प्रस्ताव को उन सदन के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर प्राप्त होने चाहिये। यह दिखायावेगा कि इन सदस्यों का समर्थन उसे प्राप्त है। इस प्रस्ताव की सूचना कम से कम १४ दिन पूर्व देनी चाहिये। अगर यह प्रस्ताव उस सदन के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पास हो गया तो वह दूसरे सदन को भेजा जावेगा। यह दूसरा सदन राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण का अनुसंधान करेगा या फरावेगा। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह इस अनुसंधान में उपस्थित हो सकता है, या अपना प्रतिनिधि भेज सकता है। अगर अनुसंधान के फल-स्वरूप दूसरा सदन दो तिहाई बहुमत से दोषारोपण को मान ले तो प्रस्ताव पास हो जावेगा। इसका फल होगा कि राष्ट्रपति को उस तारीख से पद-त्याग करना होगा। राष्ट्रपति इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं कर सकता है।

इस महाभियोग की व्यवस्था संविधान में इस कारण की गई है जिससे राष्ट्रपति अपनी शक्तियों तथा अधिकारों का दुरुपयोग न करे। क्योंकि संविधान ने कही पर ऐसा उपबन्ध नहीं है कि राष्ट्रपति अपने मन्त्रिमण्डल की राय माने ही।

अमेरिका के संविधान में भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की व्यवस्था है। परन्तु अन्तर यह है कि भारत में संसद का कोई भी सदन दोषारोपण पर दिखाई देना निषेध कर सकता है जबकि दूसरे सदन से दोषारोपण लाना

हो परन्तु अमेरिका में केवल सीनेट ही इसका निर्णय करती है। व्यवस्थापिका (कांग्रेस) के निचले भवन को इसके निर्णय का अधिकार नहीं है।

३. ) राष्ट्रपति द्वारा शपथ — प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्र-पति के रूप में काम कर रहा है, अपने पद-ग्रहण से पूर्व भारत के मुख्य न्याया-धिपति के समक्ष निम्न-रूप में शपथ करेगा तथा उसमें हस्ताक्षर करेगा —

“मैं ... अमुक, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अद्यावत् भारत के राष्ट्रपति पद का कार्य पालन (अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन) करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से सविधान और विधि का परिपालन, संरक्षण और प्रतिरण करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा।

अन्तर्कालीन व्यवस्था — ऊपर राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि तथा ग्रन्थ उससे सम्बन्धित बातों पर वर्णन किया गया है। इस प्रकार राष्ट्रपति की निर्वाचन सर्वप्रथम मई १९५२ में, जब कि सभ तथा राज्यों में ग्राम-निर्वाचनों के पश्चात् नई व्यवस्थापिका का निर्माण हो गया था तब हुआ। परन्तु भारतीय सविधान २६ जनवरी १९५० से लागू हो गया था। अन्तर्काल के किये राष्ट्रपति चाहिये था। इसलिये सविधान सभा को ही सविधान के अनुसार यह प्रकार दे दिया गया था कि वह एक अन्तर्कालीन राष्ट्रपति का निर्वाचन कर दे। उस समय डा० राजेन्द्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति सर्वमम्मति से चुने गये थे। (२५ जनवरी, १९५०)।

मई १९५२ का राष्ट्रपति का चुनाव — राष्ट्रपति के लिये ससद् के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या ४,०५७ थी। इसमें ४९५ लोक सभा के २०४ राज्य परिषद के तथा ३,३५८ क, ख तथा ग वर्ग के राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य थे। इनमें काश्मीर की सविधान-सभा के ८५ सदस्य भी शामिल हैं। काश्मीर के ससद् के १० सदस्यों को भी निर्वाचन में मत प्रदान का अधिकार मिला। काश्मीर के सदस्यों को इस अधिकार को प्रदान करने के लिये राष्ट्रपति ने “The Constitution (Applicable to Jammu and Kashmir) (Amendment) Order, 1952” की घोषणा की।

राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों को निम्न संख्या में भूतधिकार प्राप्त हुआ।

राज्य का नाम	निर्वाचित सदस्यों की संख्या	प्रत्येक सदस्य की मत-संख्या	राज्य का नाम	निर्वाचित सदस्यों की संख्या	प्रत्येक सदस्य की मत-संख्या
आसाम	१०८	७९	मैसूर	९९	८२
बिहार	३३०	११९	पटियाला तथा पूर्वी	६०	४४
बम्बई	३१४	१०४	गज्य		
मध्य प्रदेश	२३२	९०	राजस्थान	१६०	९२
मद्रास	३७५	१०५	सौराष्ट्र	९०	६६
उड़ीसा	१४०	१०३	निवाकुर-कोचीन	१०८	७९
पंजाब	१२६	१००	अजमेर	३०	२४
उत्तर-प्रदेश	४३०	१४३	भोपाल	३०	२८
पश्चिमी बंगाल	२३८	१०२	कोइंग	२४	७
हैदराबाद	१७५	१०१	दिल्ली	६८	३२
काश्मीर	७५	५९	विध्य प्रदेश	६०	१५
मध्य भारत	९९	७९	हिमाचल प्रदेश	३६	३०

विधान सभाओं के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या ३,३५८ थी तथा उनके मतों का योग ३,४५,२९१ था। इसलिये संसद् के दोनों भवनों के निर्वाचित सदस्यों की भी कुल मत संख्या ३,४५,२९१ ही हुई और प्रत्येक मत कीमत।

$$\frac{\text{संख्या } ३,४५,२९१}{४९५ + २०४} = ४९५ \text{ हुई।}$$

इस निर्वाचन में डा० राजेन्द्र प्रसाद के प्रतिस्वित थी के० टी० साहू, श्री एल० जी घट्टे, श्री हरी राम तथा श्री के० के० चटर्जी भी उम्मीदवार थे, परन्तु डा० राजेन्द्र प्रसाद को ८४ प्रतिशत, श्री साहू को १५ प्रतिशत तथा शेष उम्मीदवारों को १ प्रतिशत मत मिले। अतएव डा० राजेन्द्र प्रसाद निर्वाचित हुए और २३ मई सन् १९५२ को उन्होंने अपने पद की शपथ ली।

मई १९५७ का राष्ट्रपति का निर्वाचन — क्योंकि राष्ट्रपति की पदावधि ५ वर्ष है इसलिए १० मई १९५७ को पुनः इस पद के लिए निर्वाचन हुआ। डा० राजेन्द्र प्रसाद पुनः भारी बहुमत से निर्वाचित हुए। उनके उत्तराधिकारी

उसकी पदावधि में उसके विरुद्ध उसे बन्दी बनाने के लिये कोई प्रादेशिका (वारंट) नहीं निवाली जा सकेगी। राष्ट्रपति के विरुद्ध, अपने वैयक्तिक रूप में किये गये निजी कार्य के दाने में, चाहे वह पदग्रहण करने के पूर्व या बाद में किया गया हो, कोई दोषाती कार्यवाही तब तक नहीं की जा सकेगी, जब तक कि उसे दो मात पूर्व लिखित सूचना न दी गई हो। इस सूचना में कार्यवाहियों का स्वरूप, दाद का कारण (cause of action), तथा ऐसी कार्यवाहियों की सम्पित करने वाले पक्षकार का नाम, विवरण, निधान-स्थान, आदि दिया होना चाहिये।

इन प्रकार के उपर्युक्त अन्य देशों के संविधानों में भी है। उदाहरणार्थ, अमेरिका का राष्ट्रपति भी अपने पद के कर्मों के लिए किसी न्यायालय के सम्मुख उत्तरदायी नहीं।

राष्ट्रपति के अधिकारों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है :

(१) साधारण कालीन अधिकार :—इनका प्रयोग वह देश की प्रतिदिन की समस्याओं तथा शान्त में करेगा।

(२) संकटकालीन अधिकार :—इनका प्रयोग वह संकटकाल की घोषणा होने पर करेगा तथा मरुट का शान्त होते ही इनका प्रयोग भी बन्द हो जावेगा।

(१) साधारण कालीन अधिकार :—इनके अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकार हैं : कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार, विधायिका-वर्षित सम्बन्धी अधिकार तथा न्याय सम्बन्धी अधिकार। इनका क्रमशः वर्णन किया जावेगा।

**कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार (Executive Powers) :—**वह कार्यपालिका का मुखिया है। ये सब विषय दितके विषय में संसद् की आज्ञा बनाने का अधिकार है, कार्यपालिका के क्षेत्र के अन्तर्गत है। इनके प्रतिरिक्त वे अधिकार जो कि भारत सरकार को विनी सन्धि द्वारा प्राप्त होंगे इन्हीं के क्षेत्र के अन्तर्गत होंगे। राष्ट्रपति के नाम में ही नमस्त देश का प्रशासन होता है। भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किये जाने के लिये तथा मन्त्रियों में उक्त कार्य के उद्धार के लिये राष्ट्रपति को नियुक्त बनाने का अधिकार है। वह देश की रक्षा-दलों (defence forces) का प्रधान है। उसे युद्ध तथा संधि करने का अधिकार है। उसे अन्य देशों को राजदूत भेजने का अधिकार है। बाहर के राजदूत उनी को घणना प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।

राष्ट्रपति को मुख्य-मुख्य सरकारी कर्मचारी, जैसे प्रधान मंत्री तथा उसकी राय में अन्य मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाईकोर्टों के न्यायाधीश, राज्यपाल, निर्वाचन आयोग (Election Commissioners), संघीय सेवा

भाषा के सदस्य आदीनर जनरल, एटर्नी जनरल दित्त-भाषा तथा भाषा भाषा के सदस्य आदि का नियुक्ति का अधिकार है। वह सुप्रीम-कोर्ट तथा हाइकोर्ट के न्यायाधीश मन्त्री तथा राज्या के न्यायाधीश के सदस्य की नियुक्ति प्रक्रिया द्वारा हटा भी सकता है।

राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राज्या का सरकार को कुछ निश्चित विषयों में आदेश दे सकता है। कानून तथा न्याय के अन्तर्गत विषय उन पर है।

विधायी शक्ति सम्बन्धी अधिकार — विधायी शक्ति सम्बन्धी अधिकार को भारत के राष्ट्रपति का राष्ट्र नियमित शक्ति सम्बन्धी अधिकार नहीं है। वह राज्य पद में १० सदस्य मनोनाम करेगा तथा लोक सभा में एक शक्ति सम्बन्धी दो प्रतिनिधि मनोनीत कर सकता है। उस मनव के अधिकार बलाने का तथा स्थिति बरत और न करन का अधिकार है। राष्ट्रपति को मनव के किन्ती एक मनव प्रपक्ष इच्छा दोना सदना को सरोधित करन का अधिकार है। वह मनव के किन्ती भी मनव का मनव नो मनव सकता है। उस मनव पर वह मनव विचार करेगा। यदि नाविल बिना उसका स्वाकृति के कानून नह हो सकता है। वह किन्ती भी मनव द्वारा पाल बिना को निवृत्त वन-विपन्नता (money bills) के स्वाकृति दना मनव सकता है और उहकि ने मनव के विचारप लैव सकता है। एल्ल अगर मनव उते फिर पस करदे तो राष्ट्रपति का अपना स्वाकृति दनी हुंगी। कुछ विशेष बिल को दिना उहकी सिकरिस के मनव में पेश नहा बिना जा सकता है जेने वनविषयक या को बिना जो किन्ती राज्य की सीमा नम दानि बदलना चाहता हो।

उनको राज्या के लक्ष्य में नो का निवृत्ति शक्ति है। वह नव-राज्य को पेशगा से राया के निवृत्त-मन्त्रालय अधिकार मनव को सौंन सकता है। राज्या में बर्त स्थिति पर दिना बिना उसकी पूर स्वाकृति के विधान मन्त्रालय प्रस्तुत नहीं हो सकते हैं जेन कि राज्य के अन्दर या बाहर राज्या के लक्ष्य सार केनिक हिन न व्यापार आदि पर निवृत्त लाने वाल बिना। कुछ विषय ऐसे हैं जेन पर राज्या के विधान मन्त्र द्वारा स्वाकृति दित बिना राष्ट्रपति की स्थिति नही हो सकता है। जेने नागरिक के जीवन के लिये आवश्यक वस्तुओं के निवृत्त पर कर लगाने वाल बिना, या सम्पत्ति की प्राप्ति के लिये बनाने वाल बिना या समन्ती सूची में वर्तित विषय पर बनाने वाल बिना यदि वे मनव द्वारा निवृत्त कानून के विरुद्ध हों।



राष्ट्रपति को अन्दमान तथा लक्ष द्वीप के लिये नियम बनाने का अधिकार है। उन सब विषयों पर जिन पर संसद् को कानून बनाने का अधिकार है। राष्ट्रपति अगर संसद् अधिवेशन में न हो तो अध्यादेश (Ordinances) जारी कर सकता है। इन अध्यादेशों का प्रभाव बिल्कुल ही होता जैसा कि संसद् द्वारा पारित अधिनियमों का होता है। ये अध्यादेश संसद् के फिर प्रारम्भ होने पर उससे सामने रखे जायेंगे तथा उस प्रारम्भ होने की तारीख में केवल ६ महीने तक जारी रहेंगे। परन्तु संसद् इन अध्यादेशों के पूर्व भी उनको रद्द कर सकती है।

वित्त-सम्बन्धी अधिकार :—राष्ट्रपति के वित्त-सम्बन्धी अधिकार भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। संसद् में कोई भी धन-विषयक विना उनकी स्तिफारिता के नहीं रखा जा सकता है। प्रत्येक वित्तीय-वर्ष के प्रारम्भ में वह संसद् के सम्मुख एक वित्तीय-विवरण (Financial Statement) रखता है। इसमें सभ के उस वर्ष के अनुमानित आय-व्यय का विवरण होता है। उसके हाथ में भारत की आर्थिक-स्थिति निहित है और इसमें से वह संसद् को आशा में पूर्व आर्थिक-व्यय के लिये धन दे सकता है। आय-कर से जो रकम प्राप्त होगी उसका सभ तथा राज्यों के बीच विभाजन का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। जूट के निर्यात कर से हुई आय के हिस्से के बदले में, राष्ट्रपति को सामान, परिचमी-धन, बिहार तथा उड़ीसा को महारक-सन्तुष्टि (Grants-in-aid) को देने का अधिकार है। उनको मविधान लागू होने के दो वर्ष के अन्दर एक वित्त आयोग (Finance Commission) की नियुक्ति का अधिकार है। यह आयोग इस बात का निर्णय करेगा कि संघ तथा राज्यों के बीच कितनी नई हुई आय का बँटवारा किन प्रकार हो तथा राज्यों की आर्थिक-महायत्ता के लिए सुझाव रखेगा। इसके पश्चात् प्रति पाँचवें वर्ष या उससे पहिले राष्ट्रपति इसी प्रकार के आयोग की स्थापना करेगा। आयोग की स्थापना १० वर्षों के लिए है।

न्याय सम्बन्धी अधिकार :—मविधान की ७२ की धारा द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह दण्ड पाये हुये व्यक्ति को क्षमा कर दे। वह दण्ड को कम कर सकता है, कुछ काल के लिए रद्द कर सकता है या दण्डित-व्यक्ति को पूर्णतया क्षमा कर सकता है। वह मृत्यु-दण्ड को भी स्थगित कर सकता है। वह मृत्यु-दण्ड को क्षमा कर सकता है या प्राज्ञम करवास्त में परिणत कर सकता है।

उन सब अवस्थाओं में भी जहाँ की दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो उनको यह अधिकार है। परन्तु इसका प्रभाव किसी सैनिक अधिकारी के सैनिक-न्यायालय द्वारा दिये गए दंड को कम करने या छोड़ने या स्थगित करने



इस संबन्धनाल की घोषणा का प्रभाव बड़ा व्यापक होता है। इसके द्वारा राष्ट्रपति सारे देश का शासन प्रबन्ध अपने हाथ में ले सकता है। संसद में, सहायक विधान के स्थान में एकात्मक व्यवस्था स्थापित हो जाती है। सभ की कार्यपालिका शक्ति किसी राज्य को इन विषय में आदेश दे सकती है कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का दिन रीति से उपयोग करे। मतद-राज्यों की सूची में वर्णित विषयों पर भी कानून बना सकता है और अगर कोई राज्य का कानून इस समय संसद के कानून के विरुद्ध हो तो वह नहीं माना जाएगा। संवत्साल में, नागरिकों के कई मूल अधिकार जैसे, भाषण तथा छेड़न की स्वतन्त्रता, सभ तथा सभा की स्वतन्त्रता आदि (इनका हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं) रक्षित हो जाते हैं। राष्ट्रपति नागरिकों के मूल अधिकारों के रक्षण किसी न्यायालय की तरफ से जाने में भी रोक सकता है। राष्ट्रपति को यह अधिकार भी है कि वह सभ तथा राज्यों के बीच राजस्व-विभाजन (Revenue Distribution) सम्बन्धी सब उपबन्धों को निलम्बित (suspend) कर सकता है।

(२) राज्यों में नविधान सभ की विफलता के कारण होने वाला संकट—अगर राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल या राज्यमन्त्र से रिपोर्ट मिलने पर या किसी अन्य प्रकार यह मन्नाया हो जावे कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो वह संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा करने के लिये यह जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति को राज्य के प्रधान से सूचना मिले ही। वह अपने आप भी ऐसी घोषणा कर सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यों को कुछ आदेश देने का अधिकार है। अगर किसी राज्य में उसके द्वारा दिये गये आदेश का पालन नहीं तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि राज्यों में संविधान सर्व विफल हो गया है और वह संकट की घोषणा कर सकता है।

इस घोषणा का प्रभाव यह होगा कि राष्ट्रपति उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति को अपने हाथ में ले सकता है। राज्य के विधान मण्डल की शक्तियाँ संसद को दे सकता है। यद्यपि राष्ट्रपति राज्य के विधान मण्डल या उच्च न्यायालय की शक्तियाँ अपने हाथ में नहीं ले सकता है तथापि संसद को यह अधिकार है कि वह विधान मण्डल की शक्तियाँ राष्ट्रपति या अन्य किसी अधिकारी को दे दे। उसको यह अधिकार भी है कि इस दशा में अगर लोक सभा

1. ३० अप्रैल १९५३ को लोकसभा द्वारा Patiala and East Punjab States Union Legislature (Delegation of Powers Bill) पास किया गया था जिसने द्वारा इस प्रदेश की विधायिका शक्ति राष्ट्रपति को दे दी गई थी।

अधिवेशन में न हों तो वह किसी राज्य की मन्त्रिमण्डल में न व्यय करने की आज्ञा भी दे सकता है।

इस प्रकार की घोषणा का राष्ट्रपति दूसरी घोषणा द्वारा रद्द कर सकता है। इस घोषणा को सदन के दोनों भवनों का स्वीकृति दो मास के अन्दर मिलनी चाहिये अन्यथा दो महीने पश्चात् यह लागू नहीं रहेगी। सदन की स्वीकृति के बाद यह ६ महीने तक लागू रह सकती है। इसके बाद फिर से नई की जा सकती है। परन्तु किसी भी दशा में ऐसी घोषणा ३ वर्ष से अधिक लागू नहीं रह सकती और न एक समय में ६ महीने से अधिक के लिये सदन द्वारा स्वीकार की जा सकती है।

अगर ऐसी घोषणा उस समय की जावे जब कि लोक सभा भंग हो या बिना उस घोषणा की स्वीकार किये इसके लागू होने से २ महीने के अन्दर भंग हो जाय उस दशा में अगर यह घोषणा राज्य परिषद द्वारा स्वीकृत हो गई है तो लोकसभा के भी अधिवेशन की निधि में तीस दिन तक लागू रहेगी। अगर नई लोक सभा ने इन तीस दिनों के अन्दर इसे स्वीकार कर लिया तो यह उस तिथि से ६ महीने तक लागू रहेगी। उस दशा में भी जब ऐसी घोषणा को सदन की स्वीकृति मिलने के बाद ६ महीने के अन्दर लोक-सभा भंग हो जावे यही उपबन्ध काम में आयेंगे।

संविधान द्वारा इस प्रकार राष्ट्रपति का राज्यों के क्षेत्र में विस्तृत अधिकार दिये गये हैं। १९३५ के ऐक्ट में ( ९३ धारा के द्वारा ) संवैधानिक तन्त्र की विफलता पर गवर्नर अथवा हाय में सब अधिकार से सकता है। परन्तु नये संविधान में कानून बनाने का अधिकार सदन को दिया गया है क्योंकि सदन में सब राज्यों के प्रतिनिधि भी उपस्थित होंगे। परन्तु सदन यह शक्ति राष्ट्रपति को दे सकती है।

(३) वित्तीय सत्ता — अगर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जावे कि

राज्यों के सरकारी नौकरों के वेतन में कमी करने का अधिकार होगा। इसी

इसी प्रकार दिसम्बर १९५४ में आन प्रदेश की विधायिनी शक्ति राष्ट्रपति को दे दी गई थी।

प्रकार नय सरकार के नौकरी तथा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के स्थापनाधीन के बतन में भी कमी को जा सकेगा। राज्यों को उनके विधान-मंडलों के द्वारा याम किमी भी घन सम्बन्धी बिल या धर्म बिल को राष्ट्रपति को स्वीकृति के लिए पेश करने का आदेश किया जा सकेगा।

विनीय संकट की घोषणा दो मास तक लागू रहेगी। अगर ममद के दोनों सदनों की स्वीकृति इसे प्राप्त हो जाय तो चतुर्दश मास के बाद भी लागू रहेगी अगर ऐसी घोषणा उम समय की जावे जब कि लोक-सभा भंग हो अपवाद बिना इसको स्वीकार किए दो मास के भन्दर भंग हो जावे तो ऐसी अवस्था में राज्य परिषद् की स्वीकृति में यह घोषणा लागू रहेगी। परन्तु नई लोक सभा के मिलने के ३० दिन के भन्दर इसे उनकी स्वीकृति प्राप्त हो जानी चाहिए, अन्यथा यह ३० दिन के बाद लागू नहीं रहेगी। राष्ट्रपति संकट की घोषणा इनकी घोषणा द्वारा रह भी कर सकता है।

संकटकालीन अधिकारों की आलोचना:—इन अधिकारों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक तथा विस्तृत है। इनके द्वारा संगठनक सरकार एकात्मक हो जाती है। सब की कार्यपालिका के हाथ में अत्यन्त विस्तृत अधिकार आ जाते हैं। इन अधिकारों की कई राजनीतियों ने तथा विद्वानों ने आलोचना की है।

(१) राष्ट्रपति का मूल अधिकार को निलम्बित करने तथा न्यायालय को, उन्हें प्रवर्तित करने में रोकने का अधिकार नागरिकों की स्वतन्त्रता का धातक है। इससे देश में निरंकुश शासन की स्थापना का भय है।

(२) संविधान में यह कहीं पर वर्णित नहीं है कि राष्ट्रपति अपने संकट-कालीन अधिकारों का प्रयोग मन्त्रिमण्डल की राय से करेगा। इस प्रकार एक व्यक्ति के हाथ में इतनी अधिक शक्ति देना सर्वथा अनुचित है। उनके लिये अपने अधिकारों के दुरुपयोग करने का लोभ रोकना बहुत कठिन होगा।

इसके उत्तर में यह कहा गया है कि—

(१) मूल अधिकारों को केवल उनी समय निलम्बित किया जावेगा जब कि देश के लिये महान् संकट उपस्थित होना। यद्यपि यह सत्य है कि नागरिक के मूल अधिकार अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं तथापि यह नहीं भूलना चाहिए कि राज्य की सुरक्षा इसमें भी अधिक महत्वपूर्ण है। अगर राज्य ही नहीं रहेगा तो नागरिकों के मूल अधिकारों का क्या मूल्य रहेगा? बिना राज्य के इनकी कौन रक्षा करेगा?

(२) यद्यपि राष्ट्रपति से यह नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का प्रयोग मन्त्रिमंडल की राय से करेगा परन्तु यह स्वभावन आज्ञा की जाती है कि वह ऐसा करेगा क्योंकि मन्त्रिमंडल का लोक-मता में मजबूत बहुमत रहेगा और राष्ट्रपति इस कारण मन्त्रिमंडल से अप्रसन्न नहीं करेगा। इस स्थिति में यह होगा कि कुछ काल में इंग्लैंड की तरह भारत में भी यह अधिकार मर्यादित हो जावेगा कि मन्त्रिमंडल की राय से बिना कायपालिका का प्रधान कुछ नहीं करेगा।

(३) संसार के अन्य देशों में जो सब काल के लिये अधिकारों की निरन्तरता बरतने में उपयुक्त हैं। उदाहरणार्थ अमेरिका तथा इंग्लैंड में संसद का शरीर प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) को स्थगित करने का अधिकार है। परन्तु यहाँ पर नहीं भूयता चाहिये कि यह अधिकार संसद को है न कि कायपालिका का। अमेरिका में राष्ट्रपति केवल मुख्य मंत्रिमंडल की हस्तक्षेप से कुछ दशांश में इस अधिकार को स्थगित कर सकता है। भारत में यह अधिकार संसद के हाथ में न होकर कायपालिका के हाथ में है।

(४) राष्ट्रपति का ऐसा आदेश जिसके द्वारा नागरिक न्यायालयों का अपने अधिकारों से प्रवर्तित करने की प्रायत्ता नहीं कर सकते हैं संसद के सम्मुख रखा जायेगा। परन्तु इसमें भारी कमा यह है कि संविधान में यह कहीं पर नहीं कहा गया है कि कितने दिन के अन्दर ऐसा आदेश संसद के सम्मुख रखा जायेगा तथा संसद की आज्ञा (Authorization) इसके जारी रहने के लिए आवश्यक है।

संविधानिक-तन्त्र को विफलता पर राज्य के शासन में हस्तक्षेप का अधिकार भी अंगरवार-वार प्रयुक्त किया गया तो इसमें राज्यों के अधिकारों का विस्तृत घात हो जावेगा। इसके अतिरिक्त यह राज्य के नागरिकों को शासन के प्रति उत्तरदायित्व की भावना में विहीन कर देगा क्योंकि वे सोचेंगे कि कोई गड़बड़ होने पर सब सरकार सब ठीक कर देगी। संविधान सभा में इस आलाचना के विरुद्ध यह कहा गया था कि राष्ट्रपति इस प्रकार हस्तक्षेप केवल तभी करेगा जब कि वह देखेगा कि अन्य प्रकार से राज्य का शासन ठीक नहीं हो सकता है यह आज्ञा प्रकट की गई है कि पहले राष्ट्रपति उस राज्य को एक चेतावनी देगा इसका कोई फल न होने पर वही नए निर्वाचन करवायेगा। इसके पश्चात् भी अगर वहाँ शासन ठीक नहीं हुआ तब संविधानिक मजबूती की घोषणा करेगा। इसमें कोई शन्देह नहीं कि राष्ट्रपति के सकट-कालीन अधिकार बहुत व्यापक तथा विस्तृत हैं। इनका आधार १९३५ का ऐक्ट है। हम यह मन्ताप कर सकते

हैं कि तब भारत पराधीन था, जब स्वाधीन है इसलिये इन अधिकारों का प्रयोग राष्ट्रपति देश की मलाई को ही दृष्टि में रखते हुये करेगा। गवर्नर जनरल ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था परन्तु राष्ट्रपति भारत की जनता के प्रति उत्तरदायी है। परन्तु आलोचकों के इस तर्क में वाक़ी तथ्य है कि अगर कोई अधिकार ख़ाली तथा सिद्धान्तहीन व्यक्ति अगर इस पद पर आसबूढ़ हो जावे तो वह इन उपबन्धों के द्वारा तानाशाही स्थापित करने का प्रयास कर सकता है।

### भारतीय राष्ट्रपति का कुछ अन्य देशों के प्रधानों से तुलना

(१) भारत का राष्ट्रपति तथा इंग्लैण्ड का सम्राट् — इन दोनों में समानता यह है कि यह दोनों केवल नाम-मात्र के प्रधान हैं। केवल ऊपर से देखने से ऐसा लगता है कि जैसे इंग्लैण्ड के सम्राट् के हाथ में सब अधिकार हैं और वह जिस प्रकार चाहे उनका प्रयोग कर सकता है। परन्तु यथार्थ में इंग्लैण्ड में १७वीं शताब्दी से धीरे-धीरे ऐसे अधिसमयों की स्थापना हो गई है कि वहाँ का सम्राट् केवल मन्त्रिमण्डल के हाथ की कठपुतली है। भारत में भी राष्ट्रपति को वैधानिक प्रधान ही बनाया गया है—कम से कम ऐसी आशा की जाती है।

इंग्लैण्ड में सम्राट् लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधान मंत्री के पद के लिए चुनाता है। तब मन्त्रिमण यथार्थ में प्रधान मंत्री द्वारा ही छाटे जाते हैं और सम्राट् तब अपनी स्वीकृति दे देता है। ऐसा ही भारत में भी होगा। साधारणतः राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल में प्रधान मंत्री जिनको रखे उनको स्वीकार कर लेगा। सामंतीय-पद्धति वाले देशों में प्रधान मंत्री चुनने में केवल उस समय वैधानिक-प्रधान को कुछ स्वतन्त्रता रहती है जब कि लोकसभा में किसी दल का बहुमत न हो। ऐसे अवसर पर वह निर्णय करता है कि कौन से दल मन्त्रिमण्डल बनाने में सफल होगा। परन्तु ऐसा अवसर बहुत कम आता है। साधारणतः कुछ दल मन्त्रिमण्डल निर्माण हेतु संयुक्त हो जाते हैं।

सम्राट् तथा राष्ट्रपति में अन्तर यह है कि उसका पद पैंतूक है परन्तु राष्ट्रपति का प्रत्येक ५ वें वर्ष निर्वाचन होगा।

(२) भारत का राष्ट्रपति तथा अमेरिका राष्ट्रपति:—दोनों में साधारण बातों में कई समानताएँ हैं। दोनों का मप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। दोनों राष्ट्र के प्रधान हैं। दोनों कार्यपालिका के मुखिया हैं। दोनों को संविधान द्वारा धार्यन्त विस्तृत अधिकार दिए गए हैं। परन्तु यह सब समानता उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितना कि दोनों में अन्तर महत्वपूर्ण है। इस अन्तर का कारण यह

है कि भारत में सामंतीय पद्धति की स्थापना हुई जब कि अमेरिका में अध्यक्ष-त्मक पद्धति है। भारत का राष्ट्रपति वैधानिक प्रधान है। अमेरिका का राष्ट्रपति यथार्थ में राज्यपालिका का प्रधान है। वह मन्त्रिमण्डल का स्वामी है। उन्हीं मंत्री जमी के द्वारा नियुक्त होते हैं और वह उनको जब चाहे तब निकाल सकता है। वह उनकी शाय मान या न मान।<sup>१</sup> उसको अधिकार है कि वह उनकी शाय निगी महत्पूर्ण विषय में भी न ले। परन्तु भारत के राष्ट्रपति की स्थिति यह नहीं है।

(३) भारत का राष्ट्रपति तथा आयरलैंड का राष्ट्रपति — मन्त्रिमन्त्र सभा में यह कहा गया था कि भारत का राष्ट्रपति आयरलैंड के राष्ट्रपति की भाँति ही होगा। दोनों ही वैधानिक प्रधान हैं। परन्तु दोनों में अंतर भी है। आयरलैंड का राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यद्यपि वह वैधानिक प्रधान है परन्तु दो विषयों में उसको विशेष अधिकार है। एक तो, मन्त्रिमण्डल की प्राप्ति पर वह लोक-सभा (Dail) का भय करना नामजूर कर सकता है। दूसरा, वह कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद द्वारा स्वीकृति बिना की जनता के मत (Referendum) के लिए रण सकता है। भारत के राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि उसने मन्त्रिमन्त्र द्वारा दिए गए निणयों से सूचित किया जाय तथा और जो सूचना शासन-सम्बन्ध में वह सीमा उन्हीं दी जाय परन्तु आयरलैंड के राष्ट्रपति को कोई अधिकार नहीं दिया गया है।

(४) भारत का राष्ट्रपति तथा फ्रांस का राष्ट्रपति — दोनों ही वैधानिक प्रधान हैं क्योंकि दोनों देशों में सामंतीय पद्धति की सरकार है। फ्रांस का राष्ट्रपति के विषय में सर हनरी मेन ने कहा था 'The President of the French Republic neither reigns nor rules'। परन्तु यह सर्वथा प्रभावहीन नहीं है। क्योंकि वह मन्त्रिमण्डल की बैठक में सभापति का आसन ग्रहण करता है। उसका निर्वाचन सीमा की समद्वारा होता है। उसको

1. Lush: नृत्तिता है In the range of his powers, in the immensity of his influence, and in his special situation as at once the head of a great state, and his own Prime Minister, his position is unique

The President is the complete master of his Cabinet. He may consult with it before taking action, he may act against its advice, he may act without consulting it at all

२ फ्रांस के नवीन संविधान में (पंचम गणतंत्र में) राष्ट्रपति का शक्तियाँ तथा अधिकार बहुत बढ़ गए हैं।



बिल को अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है। उनके कोई संकटवालीन अधिकार नहीं है। उनका लोचनमा जग करने का अधिकार भी सीमित है।

**संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति** — संविधान सभा में डॉ० अम्बेडकर ने कहा था कि 'भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान नहीं परन्तु राज्य का प्रधान होगा।' इसमें यह निश्चय निकलता है कि भारतीय राष्ट्रपति केवल एक वैधानिक प्रधान है।' उसने नमि ने सब कानून बना जावेगा, परन्तु मर्यादा में उसके अधिकार, मन्त्रिमण्डल के अधिकार हैं। परन्तु संविधान में केवल इतना ही कहा गया है कि राष्ट्रपति को महानता और मन्त्रणा देने के लिये एक मन्त्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान प्रधान-मन्त्री होगा। वह मन्त्रिपरिषद लोक सभा के प्रति सानूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। इन उपबन्धों से यह कैसे कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति अपने मन्त्रिमण्डल की राय मानने को बाध्य है। अगर वह राम को न माने तो वह संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं करेगा। इस कारण विज्ञानी के अनुसार राष्ट्रपति सर्वथा अधिकार-शून्य नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री पटवर्ली शास्त्री के मतानुसार राष्ट्रपति की शक्ति का व्यवहार केवल उन्नी मात्रा तक सीमित हो सकता है। जितना कि संविधान में स्पष्ट उल्लेख है। इससे अधिक, दूसरे संविधानों के पूर्व दृष्टान्तों (precedents) के आधार पर, इसे सीमित नहीं किया जा सकता है।

परन्तु इसके साथ-साथ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत का राष्ट्रपति अमेरिकन राष्ट्रपति भी नहीं है। मन्त्रिमण्डल को राय राष्ट्रपति को दैनिक शासन से सम्बन्ध रखने वाली सभी बातों में माननी हो पड़ेगी क्योंकि मन्त्रिमण्डल का लोक सभा में बहुमत होगा। अगर राष्ट्रपति इनकी राय के विरुद्ध जावे और यह दृष्टीपा दे दे तो राष्ट्रपति को इनके स्थान में दूसरे मन्त्रिमण्डल की नियुक्ति करने में अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। अगर वह नया

1. संविधान-सभा में उन कारणों का भी उल्लेख किया गया था जिनके कारण भारत में सांसदीय पद्धति स्थापित की गई है। वे निम्नलिखित हैं :—

(अ) अध्यात्मिक सरकार का निदान स्थापित है तथा सांसदीय सरकार उत्तरदायित्व सिद्धान्त पर आधारित है। विधान निर्माताओं ने उत्तरदायित्व को अधिक महत्त्व दिया है।

(ब) अधिकार पृथक्करण के कारण अध्यात्मिक पद्धति में सरकार के तीन अंगों के बीच पुरा सहयोग नहीं रहता है।

मन्त्रिमण्डल जाना है ना उमसे लासमा म बहुमत रही होगा मतएव वह कुछ भी काम नहीं कर सकेगा। अगर राष्ट्रपति लासमा का भग कर नये चुनाव करे तो उमसे भी यह सम्भव है कि फिर स उमी दउ वा बहुमत हो जिये मन्त्रिमण्डल म पदत्याग किया वा। दगलिय दग कठिना से बाने के लिये राष्ट्रपति दैनिक गान्त में मन्त्रिमण्डल के परामश के अनुगार हो काम करेगा।

परन्तु असाधारण स्थिति में यह सम्भव है कि राष्ट्रपति उन मन्त्रिमण्डल के अनुगार काम न करे जब कि वह समझता है कि उसके परामश के अनुसार काम करने में वह जनता के हितों के विरुद्ध जा रहा है। बहुधा यह उदाहरण दिया जाता है कि यह मन्त्रिमण्डल की इच्छा के विरुद्ध लासमा का भग करन का प्रस्ताव न हो। परन्तु कुछ विद्वानों के अनुसार राष्ट्रपति को इस अवसर पर भी मन्त्रिमण्डल की राय मांगनी पड़ेगी।

इस दम निष्कर्ष पर पहुँचने है कि यद्यपि मन्त्रिमण्डल में यह स्पष्ट नहीं है, तथापि मन्त्रिमण्डल निर्माणाधीन का यह विचार था कि राष्ट्रपति प्रत्येक अवसर पर वैयक्त वैधानिक प्रभाव के रूप में काम करेगा तथा वास्तव में दम प्रकार के अधिकार भी स्थापित हो जायेंगे। राष्ट्रपति अपनी कस्तियों का दुरुपयोग करने का साहस नहीं करेगा क्योंकि मगर उमसे विरुद्ध महाभियोग की कार्यवाही कर सकेगी है।

दसलिये इंग्लैंड के सम्राट की तरह भारत के राष्ट्रपति के वक्ता तीन अधिकार रखे जायेंगे और युद्धिमा राष्ट्रपति इसमें अधिकार की मांग भी नहीं करेगा। मन्त्रिमण्डल उमसे महत्त्वपूर्ण विषयों में परामश करे (right to be consulted), मन्त्रिमण्डल को उत्साहित करने का अधिकार तथा सावधानी देना का अधिकार (right to encourage and right to warn) उमसे हैं। राष्ट्रपति कार्य के रूप में सामान्य के उपर बिलकुल प्रभाव डालेगा।

(ग) नायपालिका तथा व्यवस्थापिका में सीधा सम्बन्ध न होने के कारण अध्यक्षत्वमय सरकार भागदोय सरकार की अपेक्षा घटाने वाली है।

(द) भारत में स्वतन्त्रता की रक्षा करने के लिये यह आवश्यक था कि नयी सरकार स्थापित हो जिसमें आपस में सहयोग की कमी न हो।

1. Basu, India p 214

2. अमेज लेख Baghot ने वही के सम्राट के वही तीन अधिकार बताये हैं।

यह उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करेगा। अगर वह दृढ़चरित्र, बुद्धिमान, अनुभवी तथा लोक-प्रिय होगा तो मन्त्रिमंडल प्रत्येक विषय में उसके मत की आदरपूर्वक सुनेगा तथा उसके द्वारा स्वाभाविक ही प्रभावित होगा।' इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया तथा एडवर्ड तन्त्र ने कई बार अपने देश की नीति में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। परन्तु अगर राष्ट्रपति कोई साधारण व्यक्ति होगा तो उसका प्रभाव नगण्य होगा।

**वैधानिक-प्रधान की आवश्यकता :—**यद्यपि राष्ट्रपति केवल वैधानिक-प्रधान है तथापि उसका पद कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसलिये यह नहीं समझना चाहिए कि राष्ट्रपति का संविधान में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। इंग्लैंड में वहाँ का सम्राट केवल वैधानिक-प्रधान है, परन्तु उसके पद का महत्व है इसी कारण उसको हटाया नहीं गया है। इसी प्रकार फ्रांस में एक वैधानिक-प्रधान होता है। वहाँ के राष्ट्रपति के विषय में सर हेनरी मेन ने कहा था "वह न राज्य करता है न शासन"। परन्तु फिर भी संविधान में उसके लिए स्थान है। यह कहा जाता है कि सांसदीय-मदति की सरकार में एक वैधानिक प्रधान का होना आवश्यक है। उसी के नाम में सब शासन का काम किया जाता है, यद्यपि पदार्थ में उसके हाथ में कोई शक्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि मन्त्रिमंडल तो बनते तथा बिगाड़ते रहते हैं। वे शासन में स्थायित्व कैसे रख सकते हैं। फिर एक मन्त्रिमंडल में कई व्यक्ति होते हैं। साधारण मनुष्य यह नहीं समझ सकता कि किस प्रकार एक मन्त्रिमंडल देश का प्रधान हो सकता है। वह तो एक ऐसे व्यक्ति को समस्त शासन-तन्त्र के पीछे खोजता है जिसको वह राष्ट्र का प्रतीक समझे। सांसदीय पद्धति में वैधानिक प्रधान ही राष्ट्र

1. एक अंग्रेज विद्वान ने उचित ही लिखा है कि, "The power and influence which accrues to the Presidential office will depend in some degree on the personality and character of the President and Ministers in the early years of the Republic." A. Gladhill.

2. "The Prime Minister is not the titular chief executive in any country. It is impossible to conceive of a stable parliamentary government without there being at its head some one whose tenure of office is beyond the fickleness of a Parliament or a Congress. This tenure must be long enough to assure stability—be it four years as in America, seven as in France or for a life as in Great Britain." Munro, Government of Europe. p. 70.

का प्रतीक है। उसी को साधारण व्यक्ति राष्ट्र तथा राज्य का मुखिया मानते हैं। इस कारण वह राष्ट्र का नेता है। अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधि है। उसी के नाम में सब कुछ होता है। उसी के नाम में दूसरे देशों को जूझते भेजे जाते हैं। उसी के नाम में युद्ध तथा संधि की घोषणा होती है।

यद्यपि गणतन्त्र में राष्ट्र का मुखिया भी किसी न किसी राजनैतिक दल का ही उम्मीदवार होता है तथापि चुनाव के पश्चात् वह सोचा जाता है कि वह राजनैतिक-दलबन्दी से परे है। उसका कर्तव्य निष्पक्ष रूप से समस्त देश के हितों को सामने रखने हुये काम करना है। इसलिये वह किसी राजनैतिक दल के लाभ की दृष्टि में काम नहीं करेगा। मान लीजिए कि मन्त्रिमण्डल अपनी नीति के कारण देश में अग्रिय हो गया है परन्तु लोक सभा में उसका बहुमत है, उस समय राष्ट्रपति लोक सभा को भग वर मन्त्रिमण्डल की पदत्याग करने के लिये बाध्य कर सकता है। या, अगर मन्त्रिमण्डल लोक सभा में हार जाने पर यह इच्छा करे कि लोक सभा भंग कर दी जावे तथा नये निर्वाचन हो, तो राष्ट्रपति इस माँग को स्वीकार करने से मना कर सकता है, अगर वह यह देखता है कि लोक सभा का भंग करना देश के हित में नहीं है।

जिस समय एक मन्त्रिमण्डल पद त्याग करता है, यह हो सकता है कि दूसरे मन्त्रिमण्डल बनाने में कुछ समय लगे। इस काल में जब कि कोई मन्त्रिमण्डल नहीं है राष्ट्रपति ही देश का शासन चलावेगा। इस प्रकार वह देश में अस्थान्ति गृह-युद्ध की सम्भावना को नहीं उपजने देगा। लोक-तन्त्रात्मक पद्धति में ऐसे अवसर बहुधा हो सकते हैं जब कि मन्त्रिमण्डल पद-त्याग करे तथा उसके स्थान में दूसरे के बनाने में कुछ समय लगे।

### उपराष्ट्रपति

राष्ट्रपति के अतिरिक्त भारत का एक उपराष्ट्रपति भी होगा। साधारणतः वह राज्यपरिषद का सभापति होगा। वह कोई अन्य लाभ का पद नहीं धारण करेगा परन्तु जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तब वह उस काल के लिये राज्यपरिषद का सभापति नहीं रहेगा।

जब राष्ट्रपति का स्थान मृत्यु, पदत्याग, अथवा पद से हटाये जाने या किसी अन्य कारणों से खाली होगा तब उपराष्ट्रपति उस स्थान में राष्ट्रपति के रूप में सब तक काम करेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति चुनाव के पश्चात् अपने पद को ग्रहण न कर ले। संविधान के अनुमार ६ महीने के अन्दर ही नये राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिये।

जब राष्ट्रपति बीमारी या अन्य किसी कारण से अपना काम करने में अनमय हों तब भी उपराष्ट्रपति उनके स्थान में उन तारीख तक काम करेगा जब तक राष्ट्रपति अपने काम को न समाल ले।

जिन कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद में काम करेगा उसके राष्ट्रपति पद का ही वेतन, भत्ता तथा अन्य सुविधाएँ मिलेंगी। परन्तु उन काल में वह राज्यपरिषद् के सम्भाषित पद का वेतन आदि पाने का अधिकारी नहीं होगा।

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन ससद् के दोनों सदनों के द्वारा किया जायगा। इस अवसर पर भी अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एक परिवर्तनीय मतविधि द्वारा निर्वाचन होगा। मतदान गोपनीय होगा। इस पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहियें :—

(१) भारत का नागरिक हो तथा ३५ वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

(२) राज्य-परिषद् के लिये सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।

(३) भारत सरकार या राज्य सरकारी के अधीन या इनमें से किसी के द्वारा नियन्त्रित किसी स्थानीय या अन्य अधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद न धारण किये हो। परन्तु राष्ट्रपति, नए के मंत्री, राज्यपाल, राज्यमन्त्र तथा राज्यों के मंत्री लाभ का पद धारण किये हुये न मनसे आयेगे।

उपराष्ट्रपति न तो ससद् के किसी सदन का और न राज्यों के विधान-सदनों का सदस्य होगा। अगर वह किसी का सदस्य हो तो निर्वाचित होने की तिथि ने उसकी सदस्यता का अन्त हो जावेगा।

उपराष्ट्रपति को पदावधि पाँच वर्ष रखी गई। परन्तु वह इनके पूर्व अपने हस्ताक्षर किए हुए स्वामन्त्र द्वारा जो कि राष्ट्रपति को सम्बोधित होगा पर-त्याग कर सकता है। वह राज्य परिषद् के सदस्यों द्वारा बहुमत ने स्वीकृत प्रस्ताव से, जिसको लोकसभा ने मान लिया हो, हटाया जा सकता है। परन्तु ऐसे प्रस्ताव की गूचना कम से कम १४ दिन पहिले देनी होगी।

नए उपराष्ट्रपति का चुनाव पहिले उपराष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने के पहले ही कर लिया जावेगा। पदावधि के अन्दर ही उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर सीधेता ने नए उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जावेगा तथा वह पद-ग्रहण की तारीख से ५ वर्ष के लिए पद धारण करेगा। पद-ग्रहण ने पूर्व उप-

राष्ट्रपति को एक उपराष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के मामले लेनी पड़ेगी।

आम चुनाव के पश्चात् नई मसद् द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया। डा० राधाकृष्णन् इस पद के लिए निर्वाचित हुए।

भारतवर्ष के उपराष्ट्रपति तथा अमेरिका के उपराष्ट्रपति में यह समानता है कि दोनों ऊपरी सदन या सभापति के पद पर हैं। पर इसके अतिरिक्त अन्तर भी है। वह यह है कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन वहाँ की संसद् ऊपरी सदन (Senate) द्वारा होता है। राष्ट्रपति के कारणवश पदत्याग करने पर वह पद की शेष अवधि तक राष्ट्रपति रहता है। परन्तु भारत में अधिकाधिक ६ महीने राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। वहाँ के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल केवल ४ वर्ष है।

राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बन्धित विषय — उपराष्ट्रपति के चुनावों से सम्बन्धित मन्त्र सभाओं का फैसला उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जावेगा। अगर किसी व्यक्ति का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिये निर्वाचन शून्य (void) कर दिया जावे तो वह उस निर्णय के विरुद्ध कहीं पर अपील नहीं कर सकता है और उसे तत्काल पद-त्याग करना होगा। परन्तु इस निर्णय के पूर्व उसने अपने पद से जो कार्य किये हैं वे अमान्य नहीं माने जायेंगे।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के सम्बन्ध में, इन उपरोक्त वर्णन उपबन्धों के अधीन मसद् को नियम बनाने का अधिकार है।

### प्रश्न

- है? (१) भारत के राष्ट्रपति को संविधान द्वारा क्या अधिकार दिये गये (यू० पी० १९५२)
- (२) क्या यह कहना उचित है कि भारत का राष्ट्रपति केवल वैधानिक प्रधान है?
- (३) वैधानिक प्रधान की क्या आवश्यकता है। भारत का राष्ट्रपति इन आवश्यकताओं की किस मात्रा तक पूर्ति करता है?
- (४) मसौदे में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रथा का वर्णन कीजिए।

(५) भारत के राष्ट्रपति पर सक्षिप्त नोट लिखिए। (यू० पी० १९५३)

(६) भारत के राष्ट्रपति की सकटकालीन शक्तियाँ क्या हैं? उनका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। (यू० पी० १९५५)

(७) भारत के राष्ट्रपति के सकटकालीन अधिकारों की व्याख्या कीजिए और उनका महत्व बतलाइये। (य० पी० १९५९)

## संघीय कार्यपालिका—मन्त्रिपरिषद्

भारतीय संविधान सांसदीय होने के कारण भारत में यथार्थ कार्यपालिका मन्त्रिपरिषद् ही है। इस कारण संविधान में इसका अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वे सब अधिनार जो कि मन्त्रिषान द्वारा राष्ट्रपति का दिए गए हैं यथार्थ में मन्त्रिपरिषद् के ही अधिनार हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया होगा कि मन्त्रिपरिषद् के हाथ में साधारण काल में ही अधिनारण अधिनार हैं। फिर मकड़-काल का सा कहना ही क्या है।

**मन्त्रिपरिषद् का निर्माण** —संविधान की ७४ मया ३४ वीं पाराया में मन्त्रिपरिषद् सम्बन्धी उपबंध दिये गये हैं। इनके अनुसार मन्त्रिपरिषद् का कार्य राष्ट्रपति को उससे कामा के सम्पादन में सहायता तथा सन्तुष्टा देने का है। किसी न्यायालय में इस प्रश्न की जाँच न की जा सकेगी कि मन्त्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी या नहीं, तथा क्या सलाह दी।

प्रधान मन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान मन्त्री की सलाह से करेगा। मन्त्रीगण अपने पदों पर, राष्ट्रपति की जब तक इच्छा हो, तब तक रहेंगे। मन्त्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप में उत्तरदायी है। (सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ पिछड़े अध्याया में स्पष्ट कर दिया गया है।)

इस वर्णन से यह लभता है कि राष्ट्रपति जिसको चाहे प्रधान मन्त्री बना दे, अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति में भी उसका काफी हाथ होगा तथा जब वह चाहे इन मन्त्रियों को अपने पद से हटा दे। परन्तु यथार्थ में स्थिति पूर्णतया इससे भिन्न है क्योंकि मन्त्रिमण्डल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप में उत्तरदायी है, इसलिए मन्त्रिमण्डल केवल बड़ी दल निर्माण कर सकता है जिससे कि लोकसभा में बहुमत होगा। अतएव, प्रधान-मन्त्री निश्चय ही बहुमत दल का होगा। इसलिए, प्रधान-मन्त्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति के हाथ बंधे हैं। वह बहुमत पक्ष के नेता के अतिरिक्त अगर किसी अन्य व्यक्ति को प्रधान-मन्त्री बनावे तो उसका मन्त्रिमण्डल लोकसभा में एक दिन भी नहीं टिकेगा। इसलिये प्रधान मन्त्री सर्वदा ही बहुमत दल का नेता होता है।



परन्तु अगर देश में कई राजनैतिक दल हो जोर इनमें से किसी का भी लोक सभा में धजेय बहुमत न हो तो उन स्थिति में राष्ट्रपति को प्रधान मंत्री छांटने में कुछ स्वतन्त्रता होगी। वह यह निश्चय करेगा कि किस दल का नेता अन्य दलों की सहायता से एक स्थायी मन्त्रिमण्डल बना सकेगा। परन्तु ऐसे अवसरों की उन देशों में जहाँ कि छोटे-छोटे राजनैतिक दल नहीं होते हैं वहाँ आशा नहीं।

मन्त्रिपरिषद् में अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति वस्तुतः प्रधान मंत्री करता है। राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति को अयोग्य समझता है तो वह ऐसी राय दे सकता है। परन्तु वह प्रधान मंत्री को बाध्य नहीं कर सकता कि वह किसी विशेष व्यक्ति को मन्त्रिपरिषद् में रखे या न रखे। प्रधान मंत्री अपने मन्त्रिमण्डल को बनाने समय कई बातों का ध्यान रखेगा। सर्वप्रथम, वह अपने दल के विशिष्ट नेताओं को अपने मन्त्रिमण्डल में स्थान देगा। यह दल की एकता बनाये रखने के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वह यह देखेगा कि देश के विभिन्न भागों का मन्त्रिमण्डल में प्रतिनिधित्व है। भारत में विभिन्न सम्प्रदायों का प्रतिनिधित्व भी आवश्यक है। हम ऐसे मन्त्रिमण्डल की कल्पना नहीं कर सकते कि जिसमें केवल एक ही सम्प्रदाय के सदस्य हों। मन्त्रिमण्डल बनाने में प्रधान मंत्री को स्वाभाविक ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है क्योंकि स्थान इसमें निश्चित हैं, परन्तु उम्मीदवार अधिक हो जाते हैं। प्रत्येक सदस्य की यह इच्छा रहती है कि वह कभी न कभी मंत्री ही हो जावे। इंग्लैण्ड में भी इस प्रकार की कठिनाई होती है। प्रधान मंत्री अगर चाहे तो वह अपने दल के बाहर के व्यक्तियों को भी मन्त्रिमण्डल में ले सकता है, परन्तु ऐसा कम किया जाता है। इस प्रकार नामों की एक सूची बनाकर प्रधान मंत्री राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति उगको मान लेगा क्योंकि राष्ट्रपति यह जानता है कि बहुमत दल के नेता के अतिरिक्त अन्य कोई भी मन्त्रिमण्डल नहीं बना सकता है।

संविधान में कहा गया है कि मन्त्रियों में भारत-सरकार के कार्य के संचालन के लिये राष्ट्रपति नियम बनायेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह मन्त्रियों के बीच विभिन्न विभागों का वितरण करेगा। यह कार्य प्रधान मंत्री ही करता है। इसमें प्रधान मंत्री को यह ध्यान रखना पड़ता है कि इन प्रकार विभागों का वितरण करे कि उसके माथी मनुष्य रहें। इसके अतिरिक्त उसे उनकी रीति, अनुभव आदि का भी ध्यान रखना पड़ता है। परन्तु यह

न समझना चाहिये कि जिस मन्त्री का जो विभाग मिलता है उसका उसे पूरा ज्ञान होता है या प्रत्यक्ष मन्त्री अपने विषय में गारन्टी होता है। इंग्लैंड में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ कि मन्त्री का पद ग्रहण करते समय अपने विषय का विस्तृत भी ज्ञान नहीं था। उदाहरणार्थ एक वित्त मन्त्री को यह नहीं मालूम था कि दशमज्जम बिन्दु क्या होता है। उसने अपने सेक्रेटरी से, जो राज्य का आय-व्यय पत्र (Budget) उगल सामने आया पूछा कि ये बिन्दु क्या हैं, (What are these bloody dots?)। एवं उपनिवेश मन्त्री ने अपने सेक्रेटरी से कहा कि यह उस नक्शे में यतल द कि इंग्लैंड के उपनिवेश (colonies) कहाँ पड़े हैं।

अगर हम मन्त्रियों की पदावधि का क्या ना विधान में कुछ नहीं है। परन्तु क्योंकि लोकसभा का बायपास ५ वर्ष है इसलिए मन्त्रिमण्डल भी साधारणतः ५ वर्ष तक पद में रहेगा। अगर इसके पूर्व किसी कारण से वह लोकसभा का विस्तार या न ६ या ७ वर्षों तक लोकसभा भंग हुआ नये चुनाव में ऐसा एक बहुमत में नही। परन्तु नया राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल या किसी विशेष मन्त्री को हटा सकता है। क्या राष्ट्रपति प्रभार मन्त्री का हटा सकता है? इन प्रश्नों का उत्तर जगदलाल ज्ञाता। याकि अगर राष्ट्रपति एक मन्त्रिमण्डल को अवलोक्य कर उसने स्थान में दूसरे को नियोजित कर तो यह लोकसभा में बहुमत न होने के कारण एक दिन भी नहीं टिक सकेगा। केवल यही दल मन्त्रिमण्डल बना सकता है जिसका लोकसभा में बहुमत हो। अगर राष्ट्रपति लोकसभा का भंग कर दे तो यह सम्भव है कि नये निर्वाचन के फलस्वरूप फिर यही दल बहुमत में आ जाय किन्तु मन्त्रिमण्डल को राष्ट्रपति ने अवलोक्य लिया था। कोई भी समझदार राष्ट्रपति करने लिए इस प्रकार की कठिनाई नहीं पैदा करेगा। सब सामंतीय पद्धति वाले देशों में यह अधिसमय है कि मन्त्रिमण्डल तब तक पदस्थ रहता है जब तक इसका लोकसभा में बहुमत रहता है। वैधानिक प्रधान हमको अवलोक्य करने की चेष्टा नहीं करता। परन्तु यह सम्भव है कि मन्त्रिमण्डल देश में तो प्रिय हो गया है परन्तु लोकसभा में उसका बहुमत बना है तथा राष्ट्रपति का यह पूर्ण विश्वास हो कि नये निर्वाचन के फलस्वरूप वह दल फिर बहुमत में नहीं आवेगा तो वह देश के हित के लिये लोकसभा का भंग कर नये चुनाव कर सकता है।

प्रत्येक मन्त्री के लिये समझ का सदस्य होना आवश्यक है। अगर कोई मन्त्री ६ माह तक ससद के किसी मदन का सदस्य न रहे तो उसे उस का

की समाप्ति पर अपने पद में हटना पड़ेगा। इस प्रकार के उपबन्ध प्रत्येक शासकीय सविधान में पाये जायेंगे। इसका अर्थ यह है कि केवल वही व्यक्ति मन्त्री हो जिसकी जनता का समर्थन तथा विद्वान् प्राप्त हो। हमारे सविधान में राष्ट्रपति को राज्य परिषद् में २ सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है। यह सम्भव है कि एक व्यक्ति जो कि लोकप्रिय न हो राज्य परिषद् में मनोनीत करवा कर मन्त्रिमण्डल में लिया जावे। परन्तु ऐसी घाटा कम है क्योंकि प्रमाण मन्त्री साधारणतः अपने मन्त्रिमण्डल में ऐसे व्यक्ति को लेकर देश में अपनी लोकप्रियता कम नहीं करायेगा तथा इसके प्रतिरिक्त वह लोक सभा को भी इस प्रकार के काम कर अप्रसन्न नहीं करना चाहेगा।

मन्त्रियों के वेतन तथा मतों के विषय में संसद् को समय-समय पर कानून बनाने का अधिकार है। परन्तु जब तक संसद् इसको निर्धारित नहीं करती तब तक मन्त्रियों को १००० रु० मासिक वेतन तथा ५०० रु० भत्ता मिलेगा। प्रत्येक मन्त्री को अपनी पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति दो शपथें—एक पद की तथा दूसरी गोपनीयता की करवायेगा। पद की शपथ यह है “मैं.....

ईश्वर की शपथ लेता हूँ  
अमुक... सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के सविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, राष्ट्र के मन्त्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अन्तःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मम या पक्षपात, अनुयाय या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति सविधान के अनुसार न्याय करूंगा।”

गोपनीयता की शपथ यह है “मैं...अमुक...  
ईश्वर की शपथ लेता हूँ  
सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो विषय सभामन्त्री के रूप में मेरे विचार के लिये लाया जायगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उग अथवा को छोड़कर जब कि ऐसे मन्त्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिये ऐसा करना अपेक्षित हो अन्य अवस्था में, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सूचित या प्रकट नहीं करूंगा।”

वर्तमान मन्त्रिपरिषद् :-—ग्राम चुनावों के पूर्व का मन्त्रिमण्डल वास्तव में सविधान लागू होने से पूर्व ही बना था (सितम्बर, १९४६)। नए सविधान के लागू होने पर (२६ जनवरी १९५०) इसके सदस्यों ने (जो उस समय मन्त्री थे) राष्ट्रपति के सामुन पद की शपथ ली थी। ग्राम चुनावों से पूर्व के मन्त्रिपरिषद् का आधार सविधान की ३८१ धारा थी जिसमें कहा गया है कि

संविधान के लागू होने के पहले के मन्त्रा मन्त्रिपरिषद् के लागू होने पर राष्ट्रपति के मन्त्रिमण्डल के रूप में काम करेंगे।

आम चुनावों के पश्चात् १३ मई १९५२ का मन्त्रिमण्डल का पुनर्गठन हुआ। पुराने मन्त्रिमण्डल ने अपने पद से त्याग-पत्र दिया। परन्तु नये मन्त्र (नए मन्त्र) में कांग्रेस का ही बहुमत था। अतएव राष्ट्रपति ने पुन कांग्रेस दल के नेता का मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए आमन्त्रित किया। १३ मई, १९५२ का ५० नम्बर के नये मन्त्रिमण्डल ने अपने पद की शपथ ली।

इस समय मन्त्रिपरिषद् में प्रधान मन्त्री सहित १५ मन्त्री हैं। इनमें प्रतिनिधित्व कुछ राज्य उपमन्त्री तथा सामंतीय मन्त्रिपरिषद् है। इन मन्त्रों के मिश्रण से मन्त्रिमण्डल बनता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रिमण्डल में भेद है। मन्त्रिपरिषद् मन्त्रिमण्डल में छोटा है परन्तु देश की नीति का निर्धारण मन्त्रिपरिषद् करता है न कि मन्त्रिमण्डल। मन्त्रिपरिषद् से अर्थ Cabinet से है। मन्त्रिमण्डल में तात्पर्य Ministry है। इन दोनों में अंतर है। इस अंतर को सबदा ध्यान में रखना चाहिये।

मन्त्रिपरिषद् का काम — मन्त्रिपरिषद् का काम, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह तथा सहायता देना है। संविधान में यह नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति इस सलाह का मानने को बाध्य है। परन्तु मन्त्रिमण्डल में स्थिति पूर्णतया इससे भिन्न है। जैसा हम कह चुके हैं मन्त्रिपरिषद् ही मन्त्रिमण्डल का कार्यपालिका है। इसलिए इसका ही काम देश की शासन चलायाना है।

ब्रिटेन के राजा रामज म्मूर न इंग्लैंड के मन्त्रिपरिषद् (Cabinet) के विषय में लिखा है कि वह देश का पूर्णरूपेण स्वामी (Dictator) हो गया है। इसका कारण यह है कि मन्त्रिपरिषद् के हाथ में इतनी शक्ति है कि वह राष्ट्र का वस्तुतः स्वामी हो गया है। भारत में मन्त्रिपरिषद् के निम्नलिखित काम हैं —

( १ ) यह राष्ट्र की नीति का निर्धारण करता है। यह इस बात का निश्चय करता है कि आन्तरिक तथा वैदेशिक क्षेत्र में सरकार किस नीति का अवलम्बन करेगी।

( २ ) मन्त्रिपरिषद् देश के सामन के लिए उत्तरदायी है। इसके लिए सामन कार्य को कई विभागों में बाँट दिया जाता है तथा प्रत्येक विभाग का एक मन्त्री होता है। परन्तु जो कुछ प्रत्येक मन्त्री द्वारा किया जाता है उसके लिए सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद् उत्तरदायी है।

(३) मंत्रिपरिषद् विचारणीय-कार्यों (legislative activities) के लिए भी उत्तरदायी है। समद में सब महत्वपूर्ण बिल सरकार की ओर से ही पेश होते हैं। किन्ती गैरमन्त्रकारी बिल के पान होने की आशा बहुत कम होती है क्योंकि मंत्रिपरिषद् का लोकागना में बहुमत होने के कारण ऐसा बिल संभव ही असंभव हो जावेगा।

(४) मंत्रिपरिषद् ही राज्य के वित्त सम्बन्धी मामलों के लिए उत्तरदायी है। वार्षिक प्राय-व्यय-पत्र (Budget) इसी के द्वारा बनाया जाता है और वही उसको मंसद में पेश करता है। इसके अतिरिक्त अन्य सब वार्षिक तथा वन सम्बन्धी बिल भी इसी के द्वारा संसद में प्रस्तुत किये जाते हैं। इस प्रकार राज्य के वित्त के ऊपर मंत्रिपरिषद् का पूरा अधिकार है। यही इस बात का निश्चय करेगा कि क्या क्या कर लगाये जायें तथा किन किन विषयों पर खर्च बिना जावे।

(५) मंत्रिपरिषद् की ही राय से कई महत्वपूर्ण पदों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जावेगी, जैसे राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राजभूत आदि।

(६) मंत्रिपरिषद् बहुत अधिक जाना तक इस बात का भी निश्चय करता है कि मंसद में क्या-क्या मामले पेश किये जावेंगे तथा उनको कितने समय दिया जावेगा।

(७) संकट-काल में मंत्रिपरिषद् राज्यो के क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर सकता है।

इस सूची को देखने से ज्ञान हो गया होगा कि मंत्रिपरिषद् के हाथ में कितनी शक्ति है तथा यह कितना महत्वपूर्ण है।

**मंत्रिपरिषद् की बैठकें**—साधारणतः मंत्रिपरिषद् की प्रति सप्ताह एक बैठक होती है। इसमें प्रधान मंत्री सभापति का आसन ग्रहण करता है। अगर कोई विशेष बात हो आवे तो एक से अधिक बैठकें हो सकती हैं। प्रधान मंत्री जब चाहे तब बैठक बुला सकता है। इन बैठकों में दिन-प्रति-दिन के कामों

---

1. Marriot ने जो इंग्लैंड के मंत्रिपरिषद् के विषय में कहा है, वह हम भारत के बारे में भी कह सकते हैं—“It is the pivot round which the whole political machinery revolves.”

की आलाचना नहीं होती है। परन्तु इस सरकार की नीति निर्धारित होती है तथा महत्वपूर्ण मामला पर निर्णय लिया जाता है। जो कुछ इस बैठक में तय हो वह प्रत्यक्ष मन्त्रियों को मानना पड़ेगा। अगर कोई मन्त्री इसमें निर्णय में सहमत नहीं है तो उन्हें लिखे बैकल एव ही भाग है कि वह मन्त्रिपरिषद् से त्याग कर दे। परन्तु जब तक वह मन्त्रिपरिषद् का सदस्य है उसे इसमें निर्णय का मानना पड़ेगा।

साधारणतः मन्त्रिपरिषद् में किसी विषय पर मत नहीं लिखे जाते हैं तथा जहाँ तक संभव हो सके तब तक किसी भी कोर्ट की नीति निश्चय की जाती है। परन्तु अगर ऐसा सम्भव न हो सके तो उस स्थिति में बहुमत से निर्णय होता है। प्रधान मन्त्री अपने सचिवों को किसी विषय पर कोई नीति मानने को प्रभावित कर सकता है परन्तु वह उनको बाध्य नहीं कर सकता। अगर मन्त्रिपरिषद् में बहुमत उसकी नीति में विरुद्ध हो तो वह उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता है जैसा कि अमेरिका का राष्ट्रपति अपने मन्त्रिपरिषद् की कर सकता है।

मन्त्रिपरिषद् की बैठकों की सब बातें तथा विवाद गुप्त रखे जाते हैं और अतः साधारण को बैकल अन्तिम निर्णय ही मालूम हो सकता है। प्रत्येक मन्त्री यह कहता है कि यह मन्त्रिपरिषद् की वास्तविकता को गुप्त रखे।

मन्त्रिपरिषद् में काफी सदस्य होते हैं। भारत में इस समय १४ हैं। इतनी बड़ी सभा के द्वारा सब मामले ठीक से नहीं सुलझाये जा सकते हैं। इसलिए प्रत्येक मन्त्रिपरिषद् के अंदर एक छोटी सभा बन जाती है। कानून की दृष्टि में इसका कोई स्थान नहीं है परन्तु यह सत्य है कि अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय प्रधान मन्त्री तथा उसके एक-दो माधियों ही तय कर लेते हैं तथा मन्त्रिपरिषद् उसके निर्णय को मान लेता है। इंग्लैंड में इसको Inner Cabinet कहते हैं।

कैबिनेट का एक सेक्रेटरी भी होता है। इसमें एक सेक्रेटरी तथा उसके नीचे ज्यूनियर सेक्रेटरी ज्यूनियर सेक्रेटरी आदि होते हैं। इसका काम मन्त्रिपरिषद् के निर्णयों की रिपोर्ट करना, उनकी विभिन्न मामलों में सूचना देना आदि है।

1 अमेरिकन-राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक समय कहा था, "In a Cabinet meeting there are many arguments and opinions but only one vote—and that is the vote of the President"

प्रधान मन्त्री के काम तथा उसका महत्व — भारत में भी सार्वभौम-पद्धति होने के कारण वहाँ के प्रधान मन्त्री के विषय में यह कहा जा सकता है कि उसका वही स्थान है जो कि इंग्लैंड के प्रधान मन्त्री का। दूसरे शब्दों में, प्रधान मन्त्री मन्त्रिपरिषद् का मुखिया व्यक्ति है। उसके विषय में हम हिस्स लूके हैं कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा परन्तु समार्ष में इस नाम से ही साधारणतः राष्ट्रपति को कोई स्वतन्त्रता नहीं है। उसे बहुत दल के नेता की ही इस पद के लिये नियुक्ति करना होगा।

प्रधान मन्त्री के पद का महत्व जनमानस के लिये हमें सर्वप्रथम उसके कामों को देखना चाहिये। मंत्रिपरिषद् के अनुसार तो प्रधान मन्त्री के अधिकार यह हैं कि वह राष्ट्रपति को मन्त्रिपरिषद् के मातन सम्बन्धी तथा कानून निर्माण सम्बन्धी सब निर्णयों की सूचना दे। अगर राष्ट्रपति मातन के सम्बन्ध में या कानून बनाने के सम्बन्ध में कोई और सूचना जानना चाहे तो वह भी प्रधान मन्त्री उसको देगा। अगर राष्ट्रपति किसी विषय को, जिस पर किसी मन्त्री ने निर्णय कर दिया हो परन्तु मन्त्रिपरिषद् ने नहीं, पुनः मन्त्रिपरिषद् के सामने विचार के लिये रखने को कहे, तो प्रधान मन्त्री बँसा करेगा। परन्तु समार्ष में प्रधान मन्त्री के अधिकार इतने वहाँ अधिक हैं। वे निम्नलिखित हैं:—

(१) वह संसद् में बहुमत दल का नेता है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि संसद् के बाहर भी उस दल में उसकी स्थिति बहुत ऊँची हो और वही उसका नेता हो। जेनिंग ने इंग्लैंड के प्रधान मन्त्री के विषय में लिखते हुए कहा है कि एक नया चुनाव समार्ष में प्रधान मन्त्री का हो चुनाव है। क्योंकि अधिकांश मतदाता किसी दल को नहीं परन्तु किसी नेता के नाम से मत देते हैं। ऐसा ही भव्य होता है।

(२) वह मन्त्रियों की चुनता है तथा उनके बीच काम का बँटवारा करता है। इनमें उसके हाथ पूर्णतया स्वतन्त्र नहीं है। समार्ष उससे काफ़ी स्वतन्त्रता रहती है। इसके साथ-साथ अगर वह अपन किसी सहयोगी से असन्तुष्ट है तो वह उसको पदत्याग करने को कह सकता है। साधारणतः जिससे वह कामगा वह पद त्याग कर देगा परन्तु अगर वह ऐसा न करे तो प्रधान मन्त्री मन्त्रिपरिषद् को ही भंग कर देगा और जब नया परिषद् बनायेगा तब उसमें उस विशेष व्यक्ति को स्थान नहीं देगा।

(३) वह मन्त्रिपरिषद् की बैठकों में सभापति का मातन रहन करता है।

(४) विभिन्न विभागों में जो मनमोह हो जाता है उसका उही टीका करना है तथा सुधारना है। हमसे यह स्पष्ट है कि वह मन्त्रिपरिषद् का नेता है।

(५) राष्ट्र की नाति निर्धारित करने में उसका बहुत बड़ा हाथ रहता है। वह मन्त्रिपरिषद् के अन्य सदस्यों का अपनी बात मानने का बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित कर सकता है।

(६) वह राष्ट्रपति का मन्त्रिपरिषद् के निर्णयों की सूचना देता है। उसके अनिवार्य किसी अन्य मन्त्री का यह अधिकार नहीं है कि वह राष्ट्रपति को इस प्रकार की सूचना दे। अगर कोई मन्त्री ऐसा करता है तो उसका बलव्य है कि वह प्रधान मन्त्री का इस बात की सूचना दे।

(७) राज्य में बहुत से उच्च पदों में नियुक्ति राष्ट्रपति उनी के परामर्श के अनुरोध पर होगा। उदाहरणार्थ, राज्यपाल, राजदूत, पट्टिन मन्त्रि परिषद् के सदस्य, दूरवादि। इस विषय में अगर प्रधान मन्त्री चाहें तो वह बिना अपने मन्त्रियों के सूचना दिए राष्ट्रपति को किसी विशेष व्यक्ति का नाम देना सकता है।

(८) वह समय में मन्त्रिपरिषद् के विषय पर सरकार की नीति रखता है इस प्रकार वह मन्त्रिपरिषद् का नेता है।

(९) राजा वह मन्त्रिपरिषद् का नेता है, इसलिए सम्पूर्ण देश के शासन के ऊपर उसका अधिकार है। वह किसी भी मन्त्री से किसी भी विषय पर सूचना मांग सकता है। वह देश की वैदेशिक-नीति में भी मुख्य भूमिका लेगा। शासन-विभाग प्रधान मन्त्री के ही पास है।

प्रधान मन्त्री का अधिकार का इस सूत्र का हमसे ज्ञात हो गया होगा कि वह अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इस देश के प्रधान मन्त्री के विषय में एक ने कहा है कि 'वह मूल है जिसकी यह परिकल्पना करते हैं।' वास्तव में प्रधान-मन्त्री की ऐसी ही स्थिति है। प्रत्येक मन्त्री उसकी बगल में नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि प्रधान मन्त्री सबसे समान में पड़ता है (First among equals), वह इसमें अधिक है। परन्तु प्रधान मन्त्री की वास्तविक स्थिति क्या है, इन की आन्तरिक तथा वैदेशिक-नीति बनाने में उसका बिज्जा हाथ है, इन सब प्रश्नों का ठीक उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रधान मन्त्री का व्यक्तित्व क्या है। अगर कोई साधारण



प्रतिभा का व्यक्ति प्रधान-मन्त्री हो जावे तो स्वभावतः ही उसका प्रभाव कम होगा। परन्तु अगर कोई असाधारण प्रतिभा का व्यक्ति इस पद पर हो तो उसका प्रभाव अधिक होगा। सफल प्रधान-मन्त्री के लिए कई गुण आवश्यक हैं—प्रतिभा, नेतृत्व की योग्यता, निष्पक्षता, चारित्रिक-दृढ़ता। वह अपने सहयोगियों से थलम न रहते भी दूर हों अन्यथा उनकी छाँटों में वह गिर जावेगा। उसे प्रत्येक विभाग की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। उसके दल के सदस्यों की भक्ति उसके प्रति होनी चाहिए। इंग्लैंड के एक प्रधान मन्त्री ने कहा था कि "The office of the Prime Minister is what its holder wants to make it" यही बात भारत के प्रधान मन्त्री के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है।

**मन्त्रिपरिषद् तथा लोकसभा :—**संविधान में कहा गया है कि मन्त्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ यह हुआ कि मन्त्रिपरिषद् सभी तक अपने पद में रह सकता है जब तक लोकसभा में उसका बहुमत बना हुआ है। दूसरे शब्दों में जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। जिस रोज मन्त्रिपरिषद् यह विश्वास खो देगा उसे पदत्याग करना पड़ेगा।

सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ हम पहले समझ चुके हैं। संक्षेप में इससे तात्पर्य यह है कि अगर लोकसभा किसी एक मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास-प्रस्ताव पास कर दे तो समस्त मन्त्रिमण्डल को त्याग-पत्र देना पड़ेगा। अर्थात् एक का उत्तरदायित्व सभी का उत्तरदायित्व है। इसलिए समस्त मन्त्रिपरिषद् एक इकाई की तरह काम करता है। इस नियम को कोई भी भंग नहीं कर सकता है। इसकी भंग करने के परवाह उसके लिये मन्त्रिपरिषद् में कोई स्थान नहीं रह जाता है।

यहाँ पर यह देखना चाहिये कि लोकसभा किस प्रकार मन्त्रिमण्डल को पदत्याग करने के लिये बाध्य कर सकती है। यह कई प्रकार से किया जा सकता है।

(१) लोकसभा सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे यदि वह इसकी नीति से सहमत नहीं है।

(२) यह किसी एक विशेष मन्त्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे।

(३) वह, जब कि बजट पेश किया जाता है, यह प्रस्ताव पास कर दे कि किसी मन्त्री का वेतन कम कर दिया जावे।

(४) वह मन्त्रिपरिषद् द्वारा पेश किए हुए किसी महत्वपूर्ण विजि को पास न करे।

( ५ ) लाकम्भा किसी गैर मन्त्रिपरिषद् द्वारा पेश किए हुए विजि को मन्त्रिपरिषद् के विरोध करने पर भी पास कर दे। ऐसी अवस्था में मन्त्रिपरिषद् को पक्ष-त्याग करना पड़ेगा अगर वह इस विश्वास का प्रदान बना दे।

साधारणतः जब तक मन्त्रिपरिषद् का लाकम्भा में बहुमत रहता है ऐसी अवस्था उत्पन्न होने की बहुत कम सम्भावना रहती है। परन्तु अविश्वास के प्रस्ताव का हर सरकार का भवदा मतक सम्मान है और यह लोक-मभा को अप्रमत्त नहीं करनी है।

क्याकि मन्त्रिपरिषद् लाकम्भा के प्रति उत्तरदायी है इसलिए लाकम्भा स्वामिनी है तथा मन्त्रिपरिषद् उनका भवक और जब स्वामिनी चाहे तब भवक को उगवे पद में हटा सकती है।

परन्तु कार्य-रूप में स्थिति इसमें सर्वथा भिन्न है। यह स्थिति सब देशों में पाई जायगी जहाँ कि सामाजीय-पद्धति है तथा जहाँ अपने छोटे-छोटे दल न होकर बड़े बड़े गणित दल हैं। इंग्लैण्ड की Cabinet के बारे में कहा जाता कि वह लाकम्भा की स्वामिनी है और लाकम्भा उसकी प्रत्येक प्रस्ताव का गलन करती है। जब तक मन्त्रिपरिषद् का लाकम्भा में बहुमत है वह लोक-मभा का स्वामी है। उसे लाकम्भा में कोई हर नहीं क्याकि प्रत्येक विषय में उसके दल के सदस्य उसका समर्थन करेंगे। परन्तु मन्त्रिपरिषद् कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि उसके दल के सदस्य ही उसके विरुद्ध हो जायें। प्रश्न यह उठता है कि क्या कारण है कि मन्त्रिपरिषद् सर्वत्र भवक के स्थान पर स्वामी हो गया है। इसका उत्तर यह है —

(१) दल-पद्धति की प्रथा—इस प्रथा के कारण प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने दल का ही समर्थन करे। उसका मिथ्यात्व यह है कि मन्त्र या मंत्री, मैं अपने दल के पक्ष में हूँ। इसके कारण मन्त्रिपरिषद् को अपने दल में साधारणतः कोई हर नहीं है।

“It is one of the agreeable fictions of British Government that the Commons controls the Cabinet, but an assertion that the Cabinet controls the Commons would come closer to actualities”—Munro, Government of Europe, p 224

(२) यादकल वयस्क मताधिकार तथा निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार विस्तार होने के कारण किसी भी स्थान पर उम्मीदवार के लिये चुनाव में जीतने की आशा करना व्यर्थ है । इसके पास न उतना धन है और न साधन । इसलिए लोकसभा सदस्य दलों द्वारा निर्वाचित होते हैं ।

(३) अगर मंत्रिपरिषद् की किसी प्रस्ताव पर हार हो जावे तो वह लोकसभा को भंग करवा कर नये निर्वाचन करवा सकता है । तात्पर्यतः मंत्रिपरिषद् की प्रार्थना कि लोकसभा भंग कर दी जावे मान्य ली जावेगी । प्रत्येक निर्वाचन का भय है, धन का व्यय, परेशानी, समय की हानि आदि । जो लोग एक समय निर्वाचित हो चुके हैं वे फिर से इतनी परेशानी उठाने को साधारणतः प्रभुत नहीं होते ।

भारत में लोकसभा साधारणतः मंत्रिपरिषद् के इशारों पर चलती है । कुछ ऐसे उदाहरण अवश्य हैं जहाँ कि मंत्रिपरिषद् को अपनी नीति बदलनी पड़ी । एक लेखक ने लिखा है कि भारत में मंत्रिपरिषद् संसद के प्रति अन्य देशों की अपेक्षा अधिक आदर दिलाता है ।<sup>1</sup>

**मंत्रिपरिषद् तथा राष्ट्रपति** — यह बात नदा ध्यान में रखनी चाहिए । भारत में सांसदीय व्यवस्था है न कि अध्यक्षतात्मक । अतएव साधारणतः राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् के परामर्श अनुसार काम करेगा क्योंकि अगर वह ऐसा न करे और किसी मंत्रिपरिषद् को जिम्मा लोकसभा में बहुमत है, पदच्युत कर दे तो उसे अत्यन्त कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा । संविधान में यह कहा गया है कि मंत्रिपरिषद् राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए होगा तथा इसके सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर रहेंगे । परन्तु साथ साथ यह भी कहा गया है कि मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा । इस उपबन्ध से यह स्पष्ट हो जाता है कि मंत्रिपरिषद् का उत्तरदायित्व संसद के प्रति है न कि राष्ट्रपति के । संविधान के निर्माण के समय संविधान निर्मात्री मन्त्रों में यह स्पष्ट रूप से

1. "The Cabinet has been treating the legislature with greater consideration in India than is usual elsewhere." — Sharma, S. R., *Cabinet Government in India, Parliamentary Affairs* winter 1950, p. 120.

वहा गया था कि भारत का राष्ट्रपति केवल वैधानिक प्रधान मात्र है।<sup>१</sup> परन्तु कुछ विशेष दशाधा में राष्ट्रपति देश के हित का ध्यान में रखते हुये स्वतन्त्रता पूर्वक काम कर सकता है। जब मन्त्रिपरिषद् की सारसभा में हार हा जावे और प्रधान मन्त्री लोकसभा भंग करने की प्रावना करे राष्ट्रपति इसका प्रस्वीकृत कर सकता है अगर यह यह समझे कि इसकी कार्रवाई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार अगर किसी मन्त्रिपरिषद् का लोकसभा में ता बहुमत बना हा परन्तु दश में उसकी नीति व फलस्वरूप घससाण बढ़ जावे तो राष्ट्रपति देश के हित को ध्यान में रखते हुये लोक सभा का भंग कर नव निर्वाकन की घोषणा कर सकता है।

इंग्लैंड में यह प्रथा है कि सच्चाई का बोर्ड भी काय बैध होने व लिये उस विभाग में सम्बन्धित मन्त्री द्वारा उगम हरनाशर हुाना चाहिये। परन्तु भारतीय संविधान में ऐसा कार्र नियम नहीं है। भारतीय संविधान में ऐसा उपबन्ध नहीं है कि जिस मन्त्रिपरिषद् में इस्तीफा दे दिया हो वह तब तक काम करता रहेगा जब तक कि उसके स्थान में दूसरे का निर्माण न हा जावे। आयर्लैंड के विधान में ऐसा ही है। इस कारण भारत में यह सम्भव है कि जब एक मन्त्रिपरिषद् ने पदत्याग कर दिया हा राष्ट्रपति दूसरे का नियुक्त करने में देर लगा दे और इसी बीच में नव पाथ उनके द्वारा चलाया जाय। परन्तु यह बैध एक आशंका है।<sup>२</sup>

मन्त्रिपरिषद् में विभिन्न विभाग — शासन-काय सुचारु रूप से चलाने के लिए सरकार का काम अलग-अलग भागा में बाँट दिया जाता है। प्रत्येक विभाग या कभी-कभी दो दो विभाग एक मन्त्री के अधीन होते हैं। इस समय हमारे यहाँ निम्नलिखित मुख्य मुख्य विभाग हैं —

- (१) वैदेशिक विभाग, (२) शिक्षा विभाग, (३) यातायात विभाग  
(४) स्वास्थ्य विभाग (५) वित्त विभाग, (६) योजना विभाग, (७) सिंचा

१ डा० अर्चबेदकर ने संविधान सभा में ४ नवम्बर १९४८ को कहा था,  
"Under the presidential system of America, the President is the chief head of the executive. The administration is vested in him. Under the draft constitution (of India) the President occupies the same position as the King under the English constitution. He is the head of the state but not of the executive. He represents the nation but does not rule the nation. He is the symbol of the nation. His place in the administration is that of a ceremonial device on a seal by which the nation's decisions are made known."

२ इस विषय के लिये अध्याय ८ देखिये।

तथा सक्ति विभाग, (८) गृह विभाग, (९) रक्षा विभाग, (१०) व्यापार तथा उद्योग विभाग, (११) माद्य विभाग, (१२) कानून विभाग, (१३) रेलवे विभाग, (१४) परिवहन विभाग, (१५) निर्माण, मकान तथा रसद विभाग, (१६) श्रम विभाग, (१७) उत्पाति विभाग, (१८) पुनर्वासन विभाग, (१९) कृषि विभाग, (२०) रियासती विभाग, (२१) संसद् विषय विभाग (२२) रेडियो व सूचना विभाग, (२३) माल तथा अन्य विभाग, (२४) लौह तथा इस्पात विभाग ।

उपरोक्त विभाग निम्नलिखित मन्त्रियों के हाथों में हैं :—

(अ) वर्तमान मन्त्रिपरिषद् के सदस्य (Members of Cabinet) ।

- (१) जवाहर लाल नेहरू—प्रधान मंत्री तथा परराष्ट्र मंत्री एवं मनुष्यसिद्धि विभाग के मंत्री ।
- (२) श्री गोविन्द वल्लभ पंत—गृह मंत्री ।
- (३) श्री मयूरा जी रणछोड़ जी देसाई—वित्त मंत्री ।
- (४) श्री जगजीवनराम—रेल मंत्री ।
- (५) श्री गुलजारीलाल नदा—श्रम, रोजगार तथा नियोजन मंत्री ।
- (६) श्री लाल बहादुर शास्त्री—वाणिज्य तथा उद्योग ।
- (७) सरदार स्वर्णसिंह—इस्पात, खान तथा जलयान ।
- (८) श्री के० सी० रेड्डी—गृह निर्माण तथा पूर्ति मंत्री ।
- (९) श्री अजितप्रसाद जैन—खाद्य तथा कृषि मंत्री ।
- (१०) श्री वी० के० कृष्ण मेनन—प्रतिरक्षा मंत्री ।
- (११) श्री एस० के० पाटिल—यातायात तथा संचार ।
- (१२) श्री हाफिज इवाहीम—सिचाई तथा सक्ति ।
- (१३) श्री भगोक कुमार सेन—विधि मंत्री ।

(ब) राज्य मन्त्री

- (१) श्री सत्यनारायण सिंह—संसदीय विषय ।
- (२) डा० बालकृष्ण विश्वनाथ केसकर—सूचना तथा प्रसार ।
- (३) दत्तात्रेय परसुराम करपाकर—स्वास्थ्य ।
- (४) डा० पंजाबराव गूंस० देशमुख—खाद्य तथा कृषि ।
- (५) श्री केशवदेव मालवीय—इस्पात, खान तथा जलयान ।
- (६) मेहरचन्द खन्ना—पुनर्वासि मंत्री ।
- (७) श्री नित्यामन्द कानूनगो—वाणिज्य तथा उद्योग ।
- (८) श्री राजबहादुर—यातायात तथा संचार ।

- (१) श्री बलवन्त नागेश दातार—गृह ।
- (१०) श्री एम० एम० शाह—वाणिज्य तथा उद्योग ।
- (११) श्री मुरेन्द्रकुमार दे—सामदायिक विभाग ।
- (१२) डा० बालुलाल श्रीमाली—शिक्षा तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान ।
- (१३) श्री हुमायूँ कबीर—वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा संस्कृति ।
- (१४) श्री बी० गोपाद रेन्डी—आर्थिक विषय ।
- (म) उद्मन्त्री

- (१) सरदार मुरजीतसिंह मजोठिया—प्रतिरक्षा ।
- (२) श्री आदिदमली—यम ।
- (३) श्री अनिलकुमार धरा—गृह निर्माण तथा पूर्ति ।
- (४) श्री एम० बी० कृष्णा—वाद्य तथा कृषि ।
- (५) श्री जयसुख लाल हठी—विचारों तथा नियुक्ति ।
- (६) श्री गनीगचन्द्र—वाणिज्य तथा उद्योग ।
- (७) श्री इयामनन्दन मिश्र—नियोजन ।
- (८) श्री बलिराम भगत—वित्त ।
- (९) श्रीमती तारबेस्वरी मिश्रा—आर्थिक विषय ।
- (१०) श्री शाहनवाज खान—रेल ।
- (११) श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन—परराष्ट्र ।
- (१२) श्रीमती वायलेट ग्रन्वा—गृह ।
- (१३) श्री ग्रहमद मोहिन उद्दीन—सिविल एविएशन ।
- (१४) श्री ए० एम० बामन—वाद्य तथा कृषि ।
- (१५) श्री एम० बी० कृष्ण स्वामी—रेल ।
- (१६) श्री पी० एस० नरवर—जनसुखवस्थापन ।
- (१७) श्री आर० एम० हजरतबीम—विधि ।
- (१८) श्री के० रघुरमैया—प्रतिरक्षा ।

इन प्रकार हम देखते हैं कि वर्तमान मन्त्रिपरिषद् में केवल १३ सदस्य हैं । परन्तु इनके अनिश्चित १४ राज्य मन्त्री तथा १८ उपमन्त्री हैं । इनके अनिश्चित आठ सांसदीय सचिवों (Parliamentary Secretaries) की भी नियुक्ति की गई है । ये सचिव भी एक प्रकार के मन्त्री हैं क्योंकि इनका पद भी स्थायी नहीं होता है ।

उपरोक्त विवरण से यह ज्ञात हो जाता है कि मन्त्रिपरिषद् मन्त्रिमण्डल में घाटा होता है । मन्त्रिपरिषद् में वास्तव में उन समूह (body) सह जो कि

मन्त्रिमण्डल की नीति को निर्धारित करता है। मन्त्रिपरिषद् में केवल १३ मंत्री होते हैं। परन्तु मन्त्रिमण्डल से उत्पन्न उन सब कर्मचारियों से है जो कि लोक-सभा में जब तक उनके दल का बहुमत रहता है सरकार बनाते हैं और यह बहुमत न रहने पर उन्हें पदत्याग करना होता है। मन्त्रिमण्डल के मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों के प्रतिरिक्त राज्यमंत्री, उपमंत्री तथा सांख्यिक सचिव सभी सदस्य होते हैं। मन्त्रिपरिषद् (Cabinet) का पदत्याग करता मन्त्रिमण्डल (Ministry) का भी पदत्याग है।

इसके प्रतिरिक्त प्रत्येक विभाग में स्थायी कर्मचारी होते हैं। इनमें सबसे मुख्य सेक्रेटरी होता है, उसके नीचे ज्वाइन्ट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एसिस्टेंट सेक्रेटरी आदि होते हैं। इनका पद स्थायी होता है। मन्त्रिपरिषद् बनाते विभाग होते हैं, परन्तु इन पर कोई अन्तर नहीं होता है। इसी स्थायी कर्मचारी बृन्द को Bureaucracy कहा जाता है।

**भारत का महान्यायाधीश :—**इस पदाधिकारी का काम भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय देना तथा अन्य ऐसे कानूनी कर्तव्य को करना है जो कि राष्ट्रपति उसको समय-समय पर भेजे या सौंपे। इन कर्तव्यों के पालन में इस अधिकारी को भारत के सब न्यायालयों में सुनवाई (Audience) का अधिकार दिया गया है।

२६ जनवरी, १९५० को भारत द्वारा राष्ट्रपति ने महान्यायाधीश के पद के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम बनाये :—

उसको ₹००० २० प्रति मास वेतन तथा अन्य भत्ते मिलेंगे। सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के प्रतिरिक्त उसका काम भारत-सरकार की तरफ से उच्चतम न्यायालय, तथा उच्च न्यायालयों में उन मुकदमों में सहा होगा होगा जिनमें भारत सरकार सम्बन्धित है।

महान्यायाधीश अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त रहेंगे। इस पद पर वही व्यक्ति नियुक्ति किया जा सकता है जिनमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता हो।

### प्रश्न

(१) नवोन संविधान के अनुसार प्रधान मंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है? प्रधान मंत्री के कर्तव्यों तथा अधिकारों का उल्लेख कीजिये।

(पृ० पृ० १९५२)

(२) भारतीय संविधान में मन्त्रिपरिषद् का क्या स्थान है?

(३) मन्त्रिपरिषद् तथा राष्ट्रपति के मध्य क्या सम्बन्ध है ?

(४) "प्रधान मन्त्री मन्त्रिपरिषद् रूपी वृत्तखंड का मध्य प्रस्तर हैं।" यह कथन भारत के प्रधान मंत्री पर कहाँ तक लागू होता है ?

(यू० पी० १९५२)

(५) भारतीय मन्त्रिपरिषद् के संगठन तथा उसके अधिकारों का वर्णन कीजिये।

(यू० पी० १९५४)

(६) भारत में मन्त्रिपरिषद् के (१) राष्ट्रपति, तथा (२) राजसभा के सम्बन्धों का वर्णन कीजिये।

(यू० पी० १९५५)

(७) केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् संगठन एवं उसके कार्यों पर प्रकाश डालिये।

(यू० पी० १९५७)

(८) प्रधान मंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से होती है ? क्या राष्ट्रपति से नियुक्ति को बरन में स्वतन्त्र है ? प्रधानमंत्री के कर्तव्य और अधिकारों की परीक्षा कीजिये।

(यू० पी० १९५८)

(९) संघीय मन्त्रिमंडल में प्रधान मंत्री का क्या स्थान है ? उसके विशेषाधिकारों का वर्णन कीजिये।

(यू० पी० १९५९)



## संघीय व्यवस्थापिका

भारत की मधीय-व्यवस्थापिका को संसद (Parliament) कहा जाता है। संविधान द्वारा दो सदनों वाली व्यवस्थापिका की स्थापना की गई है। इसमें कहा गया है कि, "संघ के लिये एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम कमरा, राज्य-परिषद् और लोकसभा होंगे।" (धारा ७९)

राज्य-परिषद् ऊपरी सदन है। इसमें राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। भारत में अमेरिका की तरह प्रत्येक राज्य को ऊपरी सदन में बराबर प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। यह जनसंख्या के अनुसार कम या अधिक रखा गया है। तब भी राज्य-परिषद् राज्यों की प्रतिनिधि है और इनका काम उनके हितों का संरक्षण है। निचले सदन का नाम लोकसभा है। लोकसभा में भारत की जनता के प्रतिनिधि होंगे।

क्योंकि भारत ने ब्रिटेन की तरह संसद पद्धति को अपनाया गया है इसी कारण राष्ट्रपति को भी व्यवस्थापिका का अंग बना दिया गया है। ब्रिटेन में व्यवस्थापिका को King in Parliament कहा जाता है। अर्थात् राजा व्यवस्थापिका का आवश्यक अंग है। संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका में अध्यक्षतात्मक सरकार होने के कारण वहाँ का राष्ट्रपति (अध्यक्ष) व्यवस्थापिका का एक अंग नहीं है। वहाँ के संविधान में केवल कहा गया है कि संघ की व्यवस्थापिका शक्ति कांग्रेस (Congress) में होगी, जो कि सीनेट (Senate) तथा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (House of Representatives) से बनेगी।

संविधान के अनुसार संसद की संगठन :—संविधान के अनुसार संसद में दो सदन हैं।—राज्य-परिषद् तथा लोकसभा। संविधान के अनुसार संसद का संगठन सार्वजनिक निर्वाचनों के पदवात हुआ। २६ जनवरी १९५० को जब नया संविधान लागू हुआ भारत की संविधान गभा ही संसद में परिवर्तित कर दी गई थी तथा उसकी वे सब अधिकार दिये गये थे जो कि संविधान द्वारा संसद को दिये गये हैं। इस प्रकार सार्वजनिक निर्वाचनों के बाद संसद के संगठन तक भारत की संसद में केवल एक ही सदन था। द्विसदनात्मक संसद का निर्माण इस निर्वाचन के बाद हुआ।

## राज्य परिषद्

यह मसुदा का ऊपरी सदन है। इसमें राज्या के प्रतिनिधि आवेंगे। इसमें अधिक से अधिक २५० सदस्य होंगे। इसमें से २३६ सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। ये राज्या के प्रतिनिधि होंगे। १२ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किये जावेंगे। संविधान में कहा गया है कि ये "ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्न प्रकार के विषयों के बारे में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव है। धर्मार्थ साहित्य, विज्ञान, कला और माभाजिक सेवा।" आयरलैंड के संविधान में भी इस प्रकार का उपबन्ध है।

राज्य परिषद् में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों का विभाजन निम्नोक्त प्रकार से किया गया है

१—आंध्र प्रदेश	१८	१०—पंजाब	११
२—आसाम	७	११—राजस्थान	१०
३—बिहार	२१	१२—उत्तर प्रदेश	३८
४—बम्बई	२०	१३—गुजराती बंगाल	१६
५—केरल	१	१४—जम्मू तथा कश्मीर	४
६—मध्य प्रदेश	१६	१५—दिल्ली	३
७—मद्रास	१७	१६—हिमाचल प्रदेश	२
८—मैसूर	१२	१७—मणिपुर	१
९—उडिसा	१०	१८—त्रिपुरा	१

इन उपर्युक्त सदस्यों के अतिरिक्त १२ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं।

दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा मणिपुर-त्रिपुरा के अतिरिक्त अन्य राज्यों के सदस्य वहाँ की विधान मन्त्रालय के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एक परिवर्तनीय मतविधि द्वारा चुन जायेंगे। संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस प्रकार होगा, इसका निर्णय का अधिकार संविधान द्वारा संसद को प्रदान किया गया है। संसद की विधि द्वारा इसका निश्चय किया जाता है। मसुदा के द्वितीय सदन के लिये राज्या के प्रतिनिधियों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में भी पाया जाता है। गणतन्त्र राष्ट्र अमेरिका में सीनेट के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है।

सदस्यता के लिए योग्यताएँ — राज्यपरिषद् के सदस्य होने के लिये

निम्नलिखित योग्यताएँ हानी चाहिए —

- (१) वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो,
- (२) उसकी अवस्था ३० वर्ष की हो चुकी हो,

(३) (घ) कोई व्यक्ति किसी स्वायत्त राज्य से राज्यपरिषद् के लिये सदस्य नहीं चुना जायगा जब तक वह उस राज्य में किसी नागरिक निर्वाचन-क्षेत्र का निर्वाचक नहीं हो।

(ब) कोई व्यक्ति किसी केन्द्रीय शासित प्रदेश में राज्यपरिषद् की सदस्यता के लिये नहीं चुना जायगा जब तक वह वहाँ में किसी नागरिक निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचक न हो जहाँ कि ऐसे प्रतिनिधि का चुनाव होने वाला हो।

राज्य-परिषद् की सदस्यता के लिये वही अनिवार्यता है जो लोकसभा के लिए है। इनका वर्णन बाद में किया है।

अवधि :—राज्यपरिषद् भंग नहीं होगी। यह स्थायी संस्था है किन्तु इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अपना पद रिक्त कर देंगे।

सभापति तथा उप-सभापति :—भारत का उपराष्ट्रपति राज्यपरिषद् का पदेन (ex-officio) सभापति होता है। हम पहले लिख चुके हैं कि उनका निर्वाचन संसद के सदस्यों द्वारा किया जायगा। उसकी पदावधि ५ वर्ष है। वह अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, या राज्य-परिषद् द्वारा भ्रष्टाचार विचार जा सकता है। इन दोषांशों में वह सभापति नहीं रहेगा।

राज्य-परिषद् का एक उपसभापति भी होगा। वह सभापति की अनुपस्थिति में सभापति का आसन ग्रहण करेगा। उसका निर्वाचन राज्यपरिषद् द्वारा ही किया जाता है। उपसभापति को, अगर वह परिषद् का सदस्य न रहे, तो अपना पद छोड़ना पड़ेगा। वह अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। राज्यपरिषद् के समस्त वर्तमान सदस्यों के बहुमत से वह अपने पद से हटाया जा सकता है। परन्तु ऐसे प्रस्ताव को पेश करने के लिये १४ दिन पूर्व सूचना देनी होगी।

राज्य-परिषद् में एक सभापति या उपसभापति के हटाने के लिये प्रस्ताव होगा तब इसमें से जिनके विरुद्ध यह प्रस्ताव हो वह राज्य-परिषद् में उपस्थित रह सकता है परन्तु वह सभापति का आसन ग्रहण नहीं कर सकता और न वह इस अवसर पर मत ही दे सकता है।

राज्य-परिषद् का सभापति (भारत का उपराष्ट्रपति) दायर में राज्य-परिषद् का सदस्य नहीं है। उनकी साधारण अवस्था में मत देने का अधिकार नहीं है। वह केवल तभी मत देगा जब कि किसी प्रस्ताव पर पक्ष तथा विपक्ष में बराबर मत हो जायें। इसको निर्णायक-मत (Casting Vote) कहते हैं।

अगर सम्मानित तथा उप-सम्मानित राजा हों अनुपस्थित हों तो राज्य परिषद उन बातों के लिये अपने किसी सदस्य का सम्मानित पद के लिये नियुक्त कर सकती है।

सम्मानित तथा उपसम्मानित का जेहन तथा कुछ भस्ते मिलेंगे। अगर राज्य समुदाय बानून बनायेगी परन्तु जब तक समुदाय बानून द्वारा उनका निश्चय नहीं करती तब तक इनका वहाँ जेहन तथा जत्ते मिलेंगे जो मंत्रिपरामर्श जगु ज्ञान के पूर्व मंत्रिपरामर्श तथा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को मिलेंगे थे।

राज्य परिषद् का संवैधानिक आधार — राज्य परिषद् जनता की प्रतिनिधि न होकर राज्या की प्रतिनिधि है, इसी कारण इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रखा गया है। मधीय व्यवस्था में ऊपरी सदन राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करता है। मध्यम राज्य समिति में मोनेट भी इसी प्रकार राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। परन्तु समुदाय की ऊपरी सदन में मधीय राज्यों का प्रतिनिधित्व समान है। राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं रखा गया है।

राज्य परिषद् के द्वारा मंत्रिपरामर्श निर्माणा का यह भी उद्देश्य था कि राजा के कई विद्वान्, अनुमती तथा समामान्य व्यक्ति जो कि राजनीति में भाग लने में हिचकत हैं, व्यवस्थापन के कार्य में सहाय्य दे सकें। इसीलिए राज्य परिषद् में यह भी व्यवस्था की गई है कि राष्ट्राति कुछ व्यक्तियों का मतौदीय करता है।

ऊपरी सदन के विषय में यह भी जाता है कि यह निश्चय सदन की भांति जनता के भाव तथा उत्तजनाओं में प्रेरित नहीं होता है। यह निर्वाचन की क्षमता इच्छाओं तथा आदेशों में अपने का स्वतन्त्र रूप से व्यवस्थापन कार्य करता है। यह विधि निर्माण की शक्ति को सीमा तक देता है। इससे तदर्थ जो कि निश्चय सदन के सदस्यों में अधिक अनुमती तथा दलगत राजनीति में उत्तरे उल्लेख नहीं रहते, विधि निर्माण कार्य का अधिक विवेकपूर्ण ढंग से सम्पादित करने में सफल रहेंगे।

## लोक सभा

यह समुदाय का निचला तथा मुख्य सदन है। इसमें जनता के प्रतिनिधि रहेंगे। इस सदन को ऊपरी सदन (राज्य-परिषद्) की अपेक्षा अधिक शक्तिवाली बनाया गया है। मंत्रिपरामर्श की धारा ८१ में इसके मण्डल के विषय में यह उपबन्ध है कि इसके सदस्यों में से अधिकाधिक ५०० सदस्यों का मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन किया जायगा। इस उद्देश्य से भारत में राज्यों को

प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (territorial constituencies) में बांटा जायगा। यह विभाजन इस प्रकार किया जायगा कि प्रत्येक क्षेत्र की जनसंख्या तथा उसके सदस्यों की जनसंख्या के मध्य जो अनुपात हो वह सदस्य राज्य में यथा सम्भव समान रहे। इसके साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा जायगा कि प्रत्येक राज्य से लोकसभा के लिये सदस्यों की जो संख्या निर्दिष्ट की जायगी, उसके तथा उस राज्य की जनसंख्या के मध्य जो अनुपात हो वही यथासम्भव अन्य समस्त राज्यों में भी रहे। देश में अधिकांश निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय हैं, अर्थात् उनमें से केवल एक ही सदस्य का निर्वाचन किया जायगा। परन्तु कुछ निर्वाचन क्षेत्र द्वि-सदस्यीय भी हैं, अर्थात् उनमें से दो सदस्यों को चुन कर भेजा जायगा। स्वभावतः ही द्वि-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या एक-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या से अधिक होगी।

इन उपर्युक्त ५०० सदस्यों के अतिरिक्त संघीय क्षेत्रों से (Union territories) अधिकाधिक २० सदस्य लोकसभा में भेजे जायेंगे। इनका निर्वाचन किस प्रकार किया जायगा इसके निश्चय का अधिकार संसद् को दिया गया है। संसद् विधि द्वारा इसका निश्चय करेगी।

लोक सभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों की संख्या निम्नलिखित निर्दिष्ट की गई है —

राज्यों के नाम	सदस्य संख्या	राज्यों के नाम	सदस्य संख्या
आन्ध्र प्रदेश	४३	राजस्थान	२२
आन्ध्र प्रदेश	१२	उत्तर प्रदेश	८६
बिहार	५५	पश्चिमी बंगाल	३४
बम्बई	६६	जम्मू काश्मीर	६
केरल	१८	दिल्ली	५
मध्य प्रदेश	३६	हिमाचल प्रदेश	४
मद्रास	४१	मनीपुर	२
मंसूर	२६	त्रिपुरा	२
उड़ीसा	२०	बडमान	१
पञ्जाब	२२	लंकादीव तथा अमीनदीव	१

इसमें से जम्मू-काश्मीर तथा अहमदनिकोवार के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित न होकर राष्ट्रपति द्वारा मनानीत किये जाते हैं। जम्मू-काश्मीर की विधान-सभा जिन सदस्यों के नाम का सिफारिश करेगी राष्ट्रपति उन्हीं को नियुक्त करेगा। इनके अतिरिक्त धारा ३३१ के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दो गैरलो टर्निटियन सम्प्रदाय के प्रतिनिधि लोक सभा के सदस्य मनानीत किये जायेंगे। इनके अतिरिक्त ग्रामाम के जन-आति क्षत्रा (पाट वी) का प्रतिनिधित्व करने के लिये एक सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनानीत किया जाता है। अहमदनिकोवार तथा अमीनदीय का एक सदस्य भी राष्ट्रपति द्वारा मनानीत किया जाता है।

**निर्वाचन की विशेषताएँ —**ये निम्नलिखित हैं—

(१) प्रत्यक्ष चुनाव — लोकसभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष हागा परन्तु दो राज्या न प्रतिनिधि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से न चुने जाकर राष्ट्रपति द्वारा मनानीत किये जायेंगे। जम्मू-काश्मीर तथा अहमदन और निकोवार के प्रतिनिधि मनानीत होंगे।

(२) वयस्क मतदाधिकार — संविधान द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को जो कि २१ वर्ष की आयु पूरी कर चुका है मत देने का अधिकार दिया गया है। इसका फल यह हागा कि करीबन १८॥ करोड़ व्यक्ति चुनाव के अवसर पर मतदान करेंगे। इस संविधान के पूर्व १९३५ के अधिनियम द्वारा केवल १३ प्रतिशत व्यक्तियों को मत देने का अधिकार दिया गया था। उसके पूर्व तो यह और भी कम लोगों का मिला था। १९१९ के अधिनियम द्वारा केवल ३ प्रतिशत व्यक्तियों को यह अधिकार मिला था। इस संविधान के पूर्व निर्वाचक होने के लिए कई योग्यताएँ हानी चाहिये थी जैसे सम्पत्ति, ग्रामदनी, साक्षरता, पद, उपाधि आदि। परन्तु नये संविधान में ये कुछ नहीं रही हैं।

कोई व्यक्ति किसी निर्वाचनक्षेत्र (Constituency) में मत देने से इसक लिए उसमें केवल निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिये —

(अ) वह २१ वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

(ब) वह उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक-सूची में नाम लिखे जाने तक १८० दिन रह चुका हो।

निर्वाचक में निम्नलिखित शर्तोंमें से न होने चाहिये :

(अ) वह भारत का नागरिक न हो ।

(ब) वह किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया हो ।

(न) वह निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी अन्याय के लिये दण्डित न हो ।

(३) संयुक्त निर्वाचन—संविधान लागू होने के पूर्व भारत में पृथक् निर्वाचन प्रणाली थी । इसका आधार साम्प्रदायिकता थी । परन्तु संविधान द्वारा संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को स्थापना की गई है । इसके अन्तर्गत साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का अन्त कर दिया गया है ।

परन्तु संविधान द्वारा कुछ पिछड़ी हुई जातियों तथा कुछ अल्पसंख्यकों के लिये कुछ स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं । परन्तु यह व्यवस्था केवल १० वर्ष के लिये है । अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये उनके जनसंख्या के आधार पर कुछ स्थान सुरक्षित कर दिये गये हैं । इसी प्रकार एन्टी-डिस्क्रिपन समुदाय के लिये यह उचित है कि अगर राष्ट्रपति यह मनसे कि उनका लोकसभा में समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो वह उन समुदाय के दो सदस्यों को मनोनीत कर सकता है । यह व्यवस्था भी केवल दस वर्ष के लिये है ।

निर्वाचन के लिये प्रदण्ड :—संविधान में एक निर्वाचन-आयोग ( Election Commission ) की व्यवस्था है । इसकी नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है । इसमें एक मुख्य-निर्वाचन आयोग तथा उसके नातहत निर्वाचन आयोग और सहकारी निर्वाचन आयोग होंगे । निर्वाचन आयोग की स्थापना कर दी गई है ।

निर्वाचन-आयोग के निम्नलिखित काम हैं :—

(१) संसद के निर्वाचन के लिये निर्वाचकों की सूची तैयार करना;

(२) राज्य के विधानमंडलों के निर्वाचकों की सूची तैयार करना;

(३) देश में होने वाले अन्य निर्वाचनों का निरीक्षण एवं नियन्त्रण;

(४) राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का निरीक्षण एवं नियन्त्रण ।

(५) संसद तथा राज्यों के विधान-मंडलों के निर्वाचकों के देश हुए सर्व विवादों तथा संदेहों के निर्णय के लिये निर्वाचन न्यायाधिकरण ( Election Commission ) की नियुक्ति करेगा ।

इस आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य यह है कि निर्वाचन निष्पक्ष हो। निर्वाचन आयोगों की सेवा की शर्तों और पदावधि के लिये राष्ट्रपति द्वारा नियम बनाये गये। मुख्य निर्वाचन आयोग अपने पद के वैसे कारणों और नैतिकी नीति के बिना नहीं हटाया जा सकता जैसे कारणों और नीति से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता है अर्थात् वह अपने पद से केवल तभी हटाया जा सकता है जब कि कदाचार अथवा अयोग्यता के कारण समद के प्रत्येक सदस्य की समस्त सदस्य प्रकृति के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई के बहुमत द्वारा उसके विरुद्ध प्रस्ताव पाम होने पर वह राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हटा दिया जायगा। किसी अन्य निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक निर्वाचन आयोग को बिना मुख्य निर्वाचन-आयोग की सिफारिश के अपने पद से नहीं हटाया जा सकता है।

निर्वाचन के लिये समस्त देश को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया। संविधान में कहा गया था कि निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण इस प्रकार किया जायगा कि प्रति ७। लाख जनसंख्या के लिये एक से कम सदस्य नहीं होगा तथा प्रति ५००,००० जनसंख्या के लिये एक से अधिक सदस्य नहीं होगा। परन्तु संविधान में द्वितीय संशोधन ऐक्ट के द्वारा यह कहा गया कि निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण इस प्रकार होगा कि प्रति ५००,००० जनसंख्या के लिये एक से अधिक सदस्य न हो। इन क्षेत्रों का निर्माण निर्वाचन आयोग का काम है। इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। यह यह कि जनसंख्या तथा प्रतिनिधित्व के बीच जो अनुपात एक क्षेत्र में हो वही बरकरार अन्य सब क्षेत्रों में भी हो। प्रत्येक जनगणना के बाद यह निर्वाचन क्षेत्रों का फिर से सर्गाठन करेगा। परन्तु अगर किसी जनगणना का फल उस समय निकले जब कि एक लोक सभा बन चुकी हो तो नये निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत चुनाव तभी होगा जब कि यह ठान गमा भग हो जायेगी। समद ने इसी उद्देश्य में एन ऐक्ट के पास किया है जिसकी Delimitation Commission Act of 1952 कहते हैं।

निर्वाचन-आयोग का काम निर्वाचकों की सूची बनाना भी है। प्रत्येक क्षेत्र के निर्वाचकों की एक सूची होगी। इस सूची में केवल धर्म जाति या वर्ण के कारण किसी का नाम सम्मिलित होने से नहीं रोका जायेगा। एक व्यक्ति केवल एक ही क्षेत्र से निर्वाचक हो सकता है। अगर उसका नाम मूलतः से एक से अधिक जगह हो जाये तो इसका यह अर्थ नहीं कि वह उन सब क्षेत्रों से मतदान कर सकता है।



**सदस्यता की योग्यता** — किसी व्यक्ति में लोकसभा की सदस्यता के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिये —

(अ) भारत का नागरिक हो।

(ब) उसकी आयु कम से कम २५ वर्ष की हो।

(स) ससद् ने **The Representation of the People Act, 1951**, द्वारा अन्य योग्यताएँ रखी हैं। इस ऐक्ट के अनुसार जम्मू-काश्मीर राज्य तथा अण्डमान-निकोबार द्वीपों के स्थानों के प्रतिनिधित्व, लोकसभा में अन्य स्थानों के लिए कोई व्यक्ति तब तक योग्य नहीं समझा जावेगा जब तक कि वह—

(१) किसी राज्य में अनुसूचित जातियों (**Scheduled Castes**) के लिये सुरक्षित स्थान से चुने जाने को उस राज्य की या अन्य किसी राज्य की ऐसी जातियों का सदस्य न हो तथा किसी सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो।

(२) किसी राज्य में (आसाम के स्वायत्त जिलों के प्रतिनिधित्व) अनुसूचित जन जातियों (**Scheduled Tribes**) के लिये सुरक्षित किसी स्थान से चुने जाने को उस राज्य की या आसाम जनजाति क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व अन्य किसी राज्य की ऐसी जनजाति का सदस्य न हो तथा किसी सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक न हो।

(३) आसाम के स्वायत्त क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित किसी स्थान से चुने जाने को उनमें से किसी जनजाति का सदस्य न हो तथा किसी ऐसे सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक न हो जिसके अन्तर्गत कोई ऐसा जनजाति स्वायत्त क्षेत्र हो।

(४) किसी अन्य स्थान से चुने जाने के लिये किसी सांसदीय निर्वाचन क्षेत्र (**Parliamentary Constituency**) का निर्वाचक (**elector**) न हो।

निम्नलिखित प्रकार के व्यक्ति इसके सदस्य नहीं हो सकते हैं —

(१) अगर वे भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के नीचे कोई लाभ का पद धारण किए हों।

(२) किसी न्यायालय द्वारा पागल करार दे दिये गये हों।

(३) अगर दिवालिये हा ।

(४) अगर भारत के नागरिक न हा ।

(५) The Representation of the Peoples Act, 1951 नीचे लिखी अयोग्यतायें जोड़ दी गई हैं ।

(अ) अगर वे निर्वाचन सम्बन्धी किसी अपराध के अपराधी हो,

(ब) अगर किसी अपराध के लिए दो वर्ष से अधिक की सजा पाये हा तथा उनको छूटे हुए अभी ५ वर्ष का समय न हुआ हो;

(स) अगर सरकारी नौकरी में बेईमानी करने पर निलाले गए हो,

(द) अगर किसी सरकार सम्बन्धित ठेके में हिस्सेदार हो, या किसी सरकार से सम्बन्धित कारखाने में बोर्ड हित हो ।

(राज्य-परिषद् की सदस्यता के लिए भी वही अयोग्यताएँ हैं ।)

**लोकसभा की अवधि** —साधारणतया लोकसभा की अवधि ५ वर्ष है और इसकी समाप्ति पर पुनर्निर्वाचन होगा । परन्तु लोकसभा इसके पूर्व भी भंग की जा सकती है । (प्रधानमन्त्री के भाग करने पर राष्ट्रपति इसे भंग देगा ।) परन्तु यदि सकट-काल की घोषणा लागू हो तो उस दशा में लोकसभा की अवधि ५ वर्ष से अधिक बढ़ाई जा सकती है । इस दशा में सदैव विधि के द्वारा इसकी अवधि एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ा सकती है । परन्तु किसी भी दशा में सकट काल की घोषणा की समाप्ति के पश्चात् ६ माह से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकेगी ।

**लोकसभा के पदाधिकारी** —लोकसभा में दो पदाधिकारी होते हैं— अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष । इनका निर्वाचन लोकसभा अपने सदस्यों में से ही बहुमत द्वारा करती है । उपाध्यक्ष का काम अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसने स्थान पर काम करना है । ये अपने पद पर साधारणतः तब तक रहेंगे जब तक लोकसभा भंग न हा जावे । नयी लोक सभा अपने अध्यक्ष का फिर चुनाव करेगी । परन्तु अध्यक्ष नई लोकसभा के प्रथम अधिवेशन तक अपना स्थान नहीं छोड़ेगा ।

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अगर लोकसभा के सदस्य न रहे तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा । वे अपने पद में इस्तीफा भी दे सकते हैं । उनके विरुद्ध लोकसभा अविश्वास का प्रस्ताव भी पास कर सकती है । ऐसे प्रस्ताव की कम

में कम १४ दिन पूर्व सूचना देनी होगी। अगर यह प्रस्ताव बहुमत से पास हो जावे तो उन्हें अपना पद त्यागना पड़ेगा।

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को वेतन तथा भत्ते मिलेंगे। ये समय समय पर समद द्वारा निर्धारित किए जावेंगे। परन्तु जब तक संसद इस विषय में कानून नहीं बनाती, उनको वही वेतन तथा भत्ते मिलेंगे जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को मिलते थे।

लोकसभा के अध्यक्ष को केवल निर्णायक मत देने का अधिकार है। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव उपस्थित हो तो उसे सभा को कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। परन्तु वह पीठासीन (preside) नहीं होगा। उसे ऐसे प्रस्ताव पर मत देने का अधिकार है, परन्तु वह इस पर निर्णायक मत नहीं दे सकता है।

इंग्लैंड में यह अभिसमय (Convention) है कि अध्यक्ष निर्वाचन होने पर इलवन्दी से भ्रमण हो जाता है। श्री मावलाकर (भूतपूर्व अध्यक्ष) ने एक स्थल पर लिखा है कि भारत में यद्यपि अध्यक्ष निष्पक्षतापूर्वक अपना काम करता है, परन्तु वह इंग्लैंड की कामन्स सभा के अध्यक्ष की तरह इलवन्दी से पूर्णतया अलग नहीं है। ऐसा भारत में बर्न बर्न होगा।<sup>१</sup>

अध्यक्ष का काम लोकसभा की बैठकों में मभापति का भ्रमण करने, सभा के अन्दर नियमों का पालन करवाना, मत गिनना तथा उनका फल बतलाना आदि है। वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी मभापति का भ्रमण ग्रहण करेगा। उसे यह अधिकार है कि वह इस बात का निर्णय करे कि कोई बिल धन-विधेयक (Money Bill) है कि नहीं।

अगर लोकसभा की बैठक में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो सभा स्वयं अपने एक सदस्य को अध्यक्ष बन लेगी। अगर इन दोनों पदाधिकारियों के पद खाली हो जावें तो राष्ट्रपति अस्थायी काल के लिए लोकसभा के किसी सदस्य को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर देगा।

गरुपूति — लोकसभा तब तक अपना कार्य शुरू नहीं कर सकती है जब तक उसमें एक निर्दिष्ट सख्या में सदस्य उपस्थित न हों। यह संस्था, संविधान द्वारा, कुल सदस्य संख्या का दसवाँ हिस्सा रखी गयी है।

संसद के सदस्यों की उन्मुक्तियाँ तथा वेतन —संसद के सदस्य अपना कार्य ठीक प्रकार कर सके इसलिये उन्हें कई अधिकार तथा उन्मुक्तियाँ प्रदान की गई हैं। उन्हें भाषण की स्वतन्त्रता है। परन्तु उन्हें संसद द्वारा निर्मित कार्यवाही के नियमों का पालन करना पड़ेगा। उन पर संसद अथवा इसकी किसी समिति में दिये हुए किसी भाषण के ऊपर किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। समय-समय पर संसद उनके अधिकारों के सम्बन्ध में कानून बनावेगी। परन्तु जब तक ऐसे कानून नहीं बनते हैं सदस्यों को वह सब अधिकार दिए गए हैं जो कि इंग्लैंड में कामन्स-मैन के सदस्यों को प्राप्त हैं। संसद के सदस्य घोर अपराध (felony) तथा देशद्रोह को छोड़कर अन्य किसी अपराध के लिये संसद के अधिवेशन काल में पकड़े नहीं जा सकते हैं। संसद विधि द्वारा अपने सदस्यों के वेतन तथा भत्ते निश्चित करती है। संसद ने यह निश्चय किया है कि इनके सदस्यों को प्रति मास ६००) वेतन तथा अधिवेशन के समय २१) प्रतिदिन की उपस्थिति के अनुसार भत्ता मिला जाएगा इसके प्रतिरिक्त इनकी रेल के प्रथम श्रेणी का पान भी मिलेगा जिससे वे भारतवर्ष में कहीं भी जा सकते हैं।

संसद का सचिवालय —संसद के प्रत्येक सदन का एक-एक सचिवालय (Secretariat) होता है। इनका काम उनके दैनिक कार्य का संचालन है। इनके विषय में संसद को तब नियम निश्चित करने का अधिकार है।

संसद की कार्यवाही —किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह एक ही संसद के दोनों सदनों का सदस्य हो जावे। इसी प्रकार कोई व्यक्ति एक ही समय संसद का तथा किसी राज्य के विधान-मण्डल का सदस्य नहीं हो सकता है। यह केवल एक ही स्थान पर रह सकता है। इन विषय में संसद विधि निर्माण करेगी।

अगर कोई संसद का सदस्य ६० दिन तक बिना आज्ञा के संसद के अधिवेशन में अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता का अन्त हो जावेगा और दूसरे व्यक्ति का उस स्थान के लिये निर्वाचन होगा।

संसद के अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। वही उसको स्थगित तथा भग भी करता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन को बुलावेगा। केवल यह शर्त है कि पहले अधिवेशन की प्राथमरी तारीख तथा उसके अधिवेशन की पहली तारीख के बीच ६ महीने से अधिक समय व्यतीत न हो।

चुनाव के पश्चात् जब संसद के सदनों का प्रथम अधिवेशन होता है उस

दिन सत्र के प्रत्येक सदस्य को एक शपथ लेनी पड़ती है कि वह संविधान के प्रति श्रद्धा रखेगा तथा अपने पद के कर्तव्यों को ठीक प्रकार निभाएगा। यह शपथ इन प्रकार है।

मैं... प्रमुक्त... जो राज्य-परिषद् (अथवा लोकसभा) का सदस्य निर्वाचित (या नामजद) हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ (या सत्यनिष्ठा में प्रतिज्ञा करता हूँ) कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का ध्यापूर्वक पालन करूँगा। इसके बाद दूसरा वान लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन है। राज्य-परिषद् का सभापति भारत का उप-राष्ट्रपति होता है।

चुनाव के पश्चात् प्रथम अधिवेशन तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन में राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करेगा। राष्ट्रपति के भाषण में देश की परिस्थिति का अवलोकन होता है तथा सरकार की नीति पर प्रकाश डाला जाता है।

संसद का अधिवेशन माघारणतः १०-३० बजे सुबह से ५ बजे शाम तक रहता है। पहले घंटे में प्रश्नों के उत्तर दिये जाते हैं और फिर अन्य कार्य किया जाता है। संसद का अधिक समय सरकारी बिलों को दिया जाता है परन्तु कुछ दिन गैर-सरकारी बिलों को भी दिये जाते हैं। संसद् अपने समय में केवल दसमास गैर-सरकारी बिलों को देती है।

संसद के सदनों में प्रत्येक बात बहुमत से निश्चित होती है। माघारणतः किसी बिल के कानून बनने में दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है। परन्तु घन-विषेयक बिना राज्य परिषद की स्वीकृति के भी पास हो सकता है। जब संसद के दोनों सदनों में किसी बिल के ऊपर मतभेद होता है तो उनकी मंजूरी बैठक होती है। उसमें भी बहुमत से ही निर्णय होते हैं।

संसद् के किसी सदन की कार्यवाही तब तक आरम्भ नहीं हो सकती जब तक उसमें गण-पूर्ति ( Quorum ) न हो। यह सदस्य संख्या का दसवाँ हिस्सा है।

संविधान लागू होने से १५ वर्ष तक संसद में हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग हो सकता है। परन्तु सभापति या अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह किसी सदस्य को अपनी भाषा में ही बोलने का अधिकार दे दे अगर वह उपरोक्त दोनों भाषाओं में से किसी में भी नहीं बोल सकता है।

१५ वर्ष समाप्त होने पर सब कायवाही हिन्दी में ही हुया करेगी । समद की कायवाही में मन्त्री गण भाग लेने हैं तथा जिस मदन के सदस्य हा वहाँ मतदान भी करत हैं । महा-शायवादी की कायवाही में भाग लेने का अधिकार है परन्तु मत देने का नहा ।

समद के अधिकार —उन अधिकारों को निम्नलिखित श्रणियों में बाटा जा सकना है ।

- (१) कानून निर्माण सम्बन्धी अधिकार (Legislative)
- (२) सामन सम्बन्धी अधिकार (Administrative),
- (३) राजस्व सम्बन्धी अधिकार (Financial) ।
- (४) मविधान में मशोधन का अधिकार (Power of Amendment) ।

इनमें से प्रत्येक का प्रयोजन वर्णन किया जावेगा ।

(१) कानून निर्माण सम्बन्धी अधिकार —प्रत्येक लोकन्यायिक सरकार में जनता के प्रतिनिधि ही कानून बनाने हैं । अतएव समद का प्रथम काम कानून बनाना है । समद उन सब विषयों पर कानून बना सकती है जो कि मधीय सूची में वर्णित हैं । समदर्ता सूची में वर्णित विषयों पर भी समद को राज्यों की अपेक्षा प्राथमिकता तथा प्रधानता दी गई है । अवशिष्ट विषयों पर भी समद कानून बना सकती है ।

केन्द्रीय शासित प्रदेशों में विधि निर्माण का अधिकार समद को ही है । स्वायत्त राज्यों के विषय में भी यदि राज्य परिषद के दो तिहाई मत से प्रस्ताव पास करने पर समद इन राज्यों के लिए भी कानून बना सकती है । एम प्रस्ताव का प्रभाव एक समय में केवल एक बर रहता है । इस काल के अन्दर पाम कानूनों का प्रभाव इस एक वर्ष के समाप्त होने पर ६ मास और रहेगा ।

जब देश में राष्ट्रपति सकट की घोषणा कर दे उस अवसर पर समद राज्यों के सूची में वर्णित किसी विषय पर कानून बना सकती है । ऐसे कानूनों का प्रभाव सकट काल समाप्त होने के पश्चात् ६ महीने तक रहता है । यदि किसी समय दो या अधिक स्वायत्त राज्यों के विधान मंडल ऐसा प्रस्ताव पारित कर कि उनसे सम्बन्ध में, राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर समद ही कानून बनाये ता समद ऐसा करेगी । यदि किसी अन्य स्वायत्त राज्य का विधान मंडल बाद की उस कानून को स्वीकार कर ले तो वह कानून उस राज्य में भी लागू हो जायगा ।

संसद को यह भी अधिकार है कि किसी बाहरी देश से की हुई सन्धि अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किये हुये किसी निश्चय के पालनाथ भारत के किसी भी क्षेत्र के लिये विधि निर्माण कर सकती है ।

(२) शासन सम्बन्धी अधिकार — जनता के प्रतिनिधियों का काम सरकार की नीति निर्धारित करना है इसके साथ-साथ यह देखना भी है कि इस नीति का कार्यपालिका अनुसरण कर रही है । इसलिए व्यवस्थापिका कार्यपालिका को नियमित भी करती है । अगर ऐसा न हो तो कार्यपालिका मनमानी करने लगे । इसलिए जनता के प्रतिनिधियों का यह काम है कि कार्यपालिका को ऐसा काम करने से रोके जो कि जनता के हितों के विरुद्ध है । मासिक पत्रिका की सरकार में सभाय कार्यपालिका अपने पद पर तभी तक रह सकती है जब तक उस पर समझ का विश्वास है । अगर यह विश्वास उठ जावे तो मन्त्रिपरिषद् को इस्तीफा देना होगा । संसद शासन सम्बन्धी नीति पर नियन्त्रण, प्रश्न पूछ कर, प्रस्ताव पान कर तथा वादविवाद (debates) के द्वारा रखती है ।

प्रश्न :—हर एक बैठक के शुरू में कुछ समय प्रश्नों को दिया जाता है । इन प्रश्नों का उद्देश्य सरकार से विविध विषयों के ऊपर जानकारी प्राप्त करना है । सरकार का ध्यान जनता के कष्टों की ओर अथवा किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग की ओर आकर्षित करना भी हो सकता है । प्रश्नों की सूचना कुछ दिनों पूर्व देनी होती है । सरकार कभी-कभी प्रश्नों का उत्तर नहीं भी देती है । यह कहा जाता है कि उत्तर सार्वजनिक हित के विरुद्ध होगा । तबस्थो को अधिकार है कि प्रश्नों के उत्तर शासन अधिक स्पष्ट करने के हेतु वे पूरक-प्रश्न भी पूछ सकते हैं । पूरक-प्रश्नों की पहिले से सूचना नहीं देनी होती है ।

इन प्रश्नों का बहुत महत्व है । इसके कारण सरकार को सर्वदा चौकड़ा रहना पड़ता है । सरकारी अधिकारी मनमानी करने से डरते हैं तथा भ्रष्ट नहीं होते हैं । अप्रत्यक्ष रूप से इन प्रश्नों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है ।

प्रस्ताव :—प्रस्तावों तथा प्रश्नों में भेद है । प्रस्तावों का उद्देश्य सरकार से किसी विषय पर जानकारी प्राप्त करना नहीं परन्तु सरकार से कोई काम करने की सिफारिश करना है । प्रस्तावों के लिए भी पूर्व-सूचना आवश्यक होती है । पेश होने पर उनके ऊपर बहस होती है । अगर कोई प्रस्ताव पार भी हो जावे तो सरकार पर निर्भर है कि उसको माने या न माने । माघारणतः सरकार उसको कुछ न कुछ महत्व अवश्य देगी ।

इससे अतिरिक्त अन्य प्रकार के प्रस्ताव भी होते हैं। कभी-कभी सदन में काम स्थगित करने के लिए (Adjournment motion) प्रस्ताव रखा जाता है। ऐसा किसी महत्वपूर्ण प्रश्न, या किसी विषय घटना पर बहस करने के लिए किया जाता है। कभी-कभी जब सरकार का किसी प्रश्न का उत्तर न्यायजनक नहीं होता तब भी ऐसा प्रस्ताव पेश किया जाता है। एम प्रस्ताव प्रश्न के घट (Question hour) के पश्चात् रखे जाते हैं। सभापति या अध्यक्ष का अधिकार है कि वह अगर उस बात का महत्वपूर्ण नहीं समझता है तो प्रस्ताव का अस्वीकार कर दे। इस दशा में प्रस्ताव पेश नहीं होगा। अगर अध्यक्ष की स्वीकृति प्राप्त हो गयी तो बैठक के आखिरी समय में इस पर बहस होती है। अगर यह पास हो जावे तो सरकार के विरुद्ध निन्दा के प्रस्ताव (Vote of Censure) के समान हैं इसलिये सरकार की ओर में कोशिश रहती है कि इस प्रस्ताव पर बहस ही होती रहे और निश्चित समय के अन्दर इस पर मत लेने का अवसर न मिले। इस प्रकार प्रस्ताव talked out हो जाता है। साधारणतः सरकार का ओर से यह कहा जाता है कि वह बहस को दूर करने की चेष्टा करेगी और इस प्रकार प्रस्ताव पर मत लेने का अवसर नहीं उठता है।

तीसरे प्रकार का प्रस्ताव अविश्वास का प्रस्ताव (Vote of no-confidence) कहलाता है। अगर यह पास हो जावे तो मन्त्रिपरिषद् का इस्तीफा देना होगा। ऐसा प्रस्ताव तभी पेश हो सकता है कि जब कि सदस्यों की एक निश्चित संख्या उसके पक्ष में खड़ी हो। इसके लिए एक विशेष दिन निश्चित किया जाता है। परन्तु ऐसे प्रस्ताव का अवसर साधारणतः कभी नहीं आता है। मन्त्रिपरिषद् सदन के अविश्वास के कारण नहीं परन्तु जनता के अविश्वास के कारण त्यागपत्र देती है। इसलिये प्रस्ताव के फलस्वरूप ही मन्त्रिपरिषद् बदलने है।

यादविवाद -- इसमें तात्पर्य यह है कि सरकारी नीति सम्बन्धी किसी विशेष बात पर मतों में बहस होती है। ऐसी बहस का निश्चय याता सरकार ही स्वयं करती है या विरोधी दल इसकी माँग रखता है। इस पक्षपर सरकार की नीति की विरोधी दल विस्तृत मालोचना करते हैं और सरकारी पक्ष भी अपनी नीति की विस्तृत व्याख्या करते हैं। इन बहसों में यह लाभ है कि सरकार को यह मालूम हो जाता है कि जनता में उसकी नीति के लिये क्या भावना है।



(३) महाभियोग का अधिकार :—राज्य को, जैसा हम लिस चुके हैं, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का अधिकार भी संविधान द्वारा दिया गया है। इस अधिकार का अर्थ यह है कि यदि कोई राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे तो संसद, जो कि देश की पूर्ण जनता की प्रतिनिधि है, उसे अपदस्थ कर संविधान की रक्षा करे। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रारम्भ हो सकता है।

(४) राजस्व सम्बन्धी अधिकार :—सत्रहवीं शताब्दी में जब यूरोप में प्रजातन्त्रवादी विचार फैल रहे थे तब यह भाग उठी कि no taxation without representation। तब से यह बात सब मानते हैं कि राजस्व तथा वित्त के ऊपर जनता के प्रतिनिधियों का अधिकार है। इसी कारण सर्वत्र लोकतन्त्रात्मक पद्धति में इस विषय पर व्यवस्थापिका का ही अधिकार है। भारत में भी संसद को यह अधिकार दिया गया है। इन प्रकार देश का प्राथम्य संसद ही निश्चित करती है। बिना संसद की स्वीकृति के कोई नया कर नहीं लगाया जा सकता है, किसी प्रकार का खर्च (निर्वाह अथवा अन्य के) नहीं किया जा सकता है, न सरकार कोई ऋण ले सकती है। परन्तु एक बात नहीं भूलनी चाहिये कि मन्त्रिपरिषद् संसद में बहुमत बल का नेता होने के कारण जो कुछ चाहता है करवा लेता है। इसलिये यथार्थ में वित्त के ऊपर संसद का अधिकार नाममात्र का होता है। इन सम्बन्धी कोई भी विवाद केवल मन्त्रिपरिषद् की ओर से ही पैदा हो सकता है और इसके लिये राष्ट्रपति की सकारित आवश्यक है। अन्य कोई सदस्य इस प्रकार का विल पेश नहीं कर सकता।

(५) संशोधन का अधिकार :—जैसा कि पहिले बतलाया जा चुका है संशोधन का प्रस्ताव केवल संसद में ही प्रस्तुत हो सकता है। संसद के किसी भी सदन में ऐसा प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। केवल उन विषयों को छोड़कर जो कि राज्यों के अधिकारों से सम्बन्धित हैं, अन्य सब मामलों में संविधान में परिवर्तन संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत होने पर और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर ही जाता है। राज्यों के अधिकारों से सम्बन्धित विषयों पर संशोधन के लिये आधे से अधिक स्वायत्त राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी आवश्यक होती है। राज्यों को अपने विधान में भी परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है।

**विधान प्रक्रिया (Legislative Procedure) (१) साधारण बिल की प्रक्रिया** — जब किसी विषय में कोई कानून बनाना होना है, तो सर्वप्रथम उक्त विषय में सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद् का विभाग (गैर-सरकारी होने पर सदस्य स्वयं ही) एक प्रारूप (draft) बनाना है। इसको बिल कहते हैं।

कोई भी बिल, सिवाय धन सम्बन्धी तथा ग्रांथिक तथा विलो के, मसद के किसी भी सदन में प्रारम्भ हो सकता है। धन-सम्बन्धी तथा ग्रांथिक बिल केवल लोकसभा में ही प्रारम्भ हो सकते हैं। जब बिल एक सदन में पाम हो जाता है, तब वह दूसरे सदन में जाता है। अगर वहाँ भी पास हो गया तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर कानून बन जाता है।

दोनों सदनों में धारस में किसी बिल के ऊपर मतभेद हो सकता है। अगर कोई बिल एक सदन में तो पाम हो गया हो, परन्तु दूसरे सदन द्वारा प्रस्वीकृत कर दिया जावे, या दूसरा सदन उसमें कुछ संशोधन कर दे जो कि पहले सदन को मजूर न हो या दूसरा सदन उक्त बिल को छ महीने तक रोके रखे, तो इस मतभेद के होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलावेगा। इस बैठक में उपस्थित सदनों का बहुमत प्राप्त करने पर वह बिल दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत समझा जायगा। परन्तु धन-विषयको पर वह धान लागू नहीं होगी।

परन्तु संयुक्त बैठक में—(१) यदि बिल दूसरे सदन द्वारा बिना किसी संशोधन के उक्त सदन को लौटा दिया गया है, जिसमें कि वह पाम हो चुका है, तो सिवाय उन संशोधनों के जो कि बिल के पास होने में देरी के कारण आवश्यक हो गये हैं, और कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा,

(२) यदि बिल दूसरे सदन द्वारा कुछ संशोधनों सहित वापिस किया जाता है, जो कि पहले सदन को मान्य नहीं है, तो इन संशोधनों के तथा ऐसे संशोधनों के जो कि पाम होने में देरी के कारण आवश्यक हो गये हैं, अन्य विंगो संशोधन पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

जब कोई बिल सिवाय धन-विषयक के दोनों सदनों द्वारा पास होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिये भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि वह अपनी अनुमति दे अथवा न दे। बिना उसकी अनुमति के बिल कानून नहीं बन सकता है। वह बिल को अपनी सिफारिशों के सहित मसद के पुनर्विचारार्थ यथाशीघ्र वापिस भी कर सकता है। अगर बिल फिर से मसद द्वारा राष्ट्रपति की सिफारिशों सहित या उनके बिना पास किया जाता है तो

राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं रोकेगा। संविधान में यह स्पष्ट नहीं है कि राष्ट्रपति कितने समय के अन्दर बिल को संसद के पुनर्विचारार्थ लौटा दे। इस-लिये एक तीसरी सम्भावना भी है। राष्ट्रपति विधेयक को अनिश्चित समय के लिये अपने पास पड़ा रहने दे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की बीटी शक्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

परन्तु राष्ट्रपति की यह बीटी शक्ति (veto power) सामद-युक्ति के सिद्धान्तों से साम्य नहीं रखता है। इंग्लैंड में राजा को विशेषाधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति न दे परन्तु सन् १७०७ से लेकर आज तक ऐसा एक भी दृष्टान्त नहीं मिलता है जब कि उसने अपनी अनुमति न दी हो। यहाँ तक कि जब विद्वानों के अनुसार उसका अनुमति न देना अवैधानिक होगा।

(२) धन-विधेयक विषयक प्रक्रिया :—धन-विधेयकों से तात्पर्य निम्न-लिखित विषयों में सम्बन्ध रखने वाले बिलों से है :

(क) किसी कर का लगाना, हटाना, बदलना या उसमें कमी करना।

(ख) भारत सरकार के ऋण लेने या किसी आर्थिक आभार (Financial Obligation) से सम्बन्ध रखने वाले किसी कानून में, बदलाव करने सम्बन्धी कोई नियम।

(ग) भारत की संचित-निधि अथवा आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा (custody) या ऐसी किसी निधि में धन डालना या उसमें से निकालना।

(घ) भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग (appropriation)।

(ङ) किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना, अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि को बढ़ाना।

(च) भारत की संचित निधि के या भारत के लोक लेखे (public accounts) के मध्य धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या निष्ठा करनी अथवा सप-राज्य के लेखाओं (accounts) का लेखा परीक्षण (audit) करना।

(छ) ऊपर उल्लिखित विषयों में से किसी का धान्दलिक कोई विषय।

अगर नही यह सन्देह हो कि कोई बिल धन विधेयक है कि नही ना लाकसभा के अध्यास का निश्चय अन्तिम होगा ।

/ धन विधेयक बिल लोकसभा में ही आरम्भ हो सकते हैं । बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के ऐसा बिल पेश नही किया जा सकता है । ऐसा बिल लोकसभा में पाम होकर राज्य-परिषद् में जाता है । अगर राज्य परिषद् उसे १४ दिन के अन्दर अपनी सिफारिश सहित लाकसभा को वापिस कर देती है तो लाकसभा उन सिफारिशों पर विचार करेगी । इसको यह स्वतन्त्रता है कि यह उन सिफारिशों का माने या न मान । अगर नही मानती तो बिल बिना इन सिफारिशों के पास समझा जावेगा । अगर राज्य-परिषद् १४ दिन के अन्दर बिल को वापिस नही कर देती है तो बिल स्वयमेव पास समझा जायगा । इस प्रकार दोनों में धन विधेयक पर मतभेद होने की स्थिति में संयुक्त बैठक की व्यवस्था नही है । राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी अनुमति नही रोवेगा ।

राज्य परिषद् को धन-सम्बन्धी बिलों के सम्बन्ध में कोई भी अधिकार नही है । इंग्लैण्ड में लार्ड सभा को भी १०११ से धन सम्बन्धी बिलों में कोई अधिकार नही रह गया है । वह ऐसे बिलों को केवल ३० दिन तक रोक सकती है । भारत में केवल १४ दिन समय दिया गया है । इंग्लैण्ड में भी धन विधेयक कामन्स सभा में ही आरम्भ होते हैं । अमेरिका में धन-विधेयक निचले भवन में ही आरम्भ होते हैं परन्तु ऊपर भवन को उसमें सशोधन का अधिकार है । इस अधिकार का प्रयोग वह धुव खलकर करता है । ऐसे उदाहरण है जहाँ कि सिवाय बिल के नाम (title) के अन्य सब बातें ऊपरी भवन द्वारा बदल दी गई थी ।

(३) वित्तीय प्रक्रिया (Financial Procedure) — हर साल वित्तीय वर्ष के आरम्भ में राष्ट्रपति ससद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार का वार्षिक वित्त विवरण रखवायेगा । इसमें भारत सरकार के उस वर्ष के आय व्यय का अनुमान होगा । इस विवरण में दो तरह के व्यय का अनुमान होता है —

- (१) वह व्यय जो कि अनिवार्य है ।
- (२) वह व्यय जिसके लिए ससद की आज्ञा मांगी जानी है ।

अनिवार्य व्यय के ऊपर ससद में बहस हो सकती है, पर इसमें परिवर्तन नही किया जा सकता । दूसरे प्रकार के व्यय को ससद चाहे तो पास करे या

कम कर दे, या माल्तीकार कर दे। अनिवार्य व्यय से तात्पर्य उस व्यय से है जो कि संविधान में भारत को मन्त्रित निधि (Consolidated Fund) पर हस्तलाया गया है। इसमें नीचे लिखे व्यय आते हैं।

(क) राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ, भत्ते तथा उसके पद से सम्बन्धित अन्य व्यय।

(ख) राज्य-परिषद के सभापति तथा उप-सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उप-अध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते।

(ग) भारत सरकार के ऋण पर दिया जाने वाला व्याज तथा अन्य व्यय।

(घ) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते तथा पेंशन फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन तथा संविधान लागू होने के पूर्व ब्रिटिश भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन।

(ङ) भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ते तथा पेंशन।

(च) किसी न्यायालय के निर्णय के कारण भुगतान के लिए प्रपेशित राशि।

(छ) सपीय लोक-सेवा-आयोग से सम्बन्धित खर्च।

(ज) राजाओं का प्रिबी-वर्स।

(झ) संसद से विधि द्वारा इस प्रकार अनिवार्य घोषित किया हुआ कोई और व्यय।

उपरोक्त व्ययों के प्रतिरिक्त अन्य व्ययों के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश से लोकसभा में मांगें रखी जावेंगी। लोकसभा के इन मांगों को स्वीकार कर लेने पर भारत सरकार के सब प्रकार के व्यय के लिए लोकसभा में एक विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) रखा जाता है। बिना इसके पास हुए संचित निधि में से खर्च नहीं किया जा सकता है।

भगर वर्ष के बीच में कोई खर्च का नया भद्र मा जावे जिसका कि बजट में उल्लेख नहीं है, या किसी विषय पर बजट में स्वीकृत राशि से अधिक खर्च हो जावे तो राष्ट्रपति अनुपूरक तथा प्रचिकाई मांग (Supplementary and additional grants) कर सकता है। इन मांगों की प्रक्रिया भी साधारण मांगों की तरह है।

लोक सभा को यह भी अधिार है कि वह वित्तीय प्रक्रिया के पूरे हान व पत्र ही सरकार का कुछ पेसगी धन अलग उसका काम चलाने के लिए स्वीकार कर ॥ । वित्त प्रक्रिया के सम्बन्ध में तीन बाने ध्यान में रानी चाहिए —

(१) कोई भी धन-विधेयक बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के पेस नहीं हो सकता है ।

(२) तेना विधेयक केवल लोकसभा में आरम्भ हो सकता है तथा राज्य परिषद का इसके उपर कुछ भी अधिार नहीं है ।

(३) लोकसभा का यह अधिार है कि वह बजट को स्वीकार करे अस्वाकार करे या किसी व्यव-राशि का काम करे । परन्तु वह न कोई नए कर का सुझाव रख सकती है और न कोई व्यय राशि का बड़ा सकती है । ऐस प्रस्ताव केवल किसी मन्त्री द्वारा राष्ट्रपति की सिफारिश ॥ पेस किए जा सकते हैं ।

जब बजट पास हो जाता है तब आय के लिए नगारों जनि बाने करा के प्रस्ताव वित्तीय विधेयक ( Financial Bill ) के रूप में पेस किए जाते हैं । ये केवल लोक सभा में ही आरम्भ हो सकते हैं ।

संसद पर एक आलोचनात्मक दृष्टि — भारत की संसद् एक स्वतन्त्र राज्य की संसद् है । इसलिए यह किसी प्रकार के बाहरी नियन्त्रण से बंधा नहीं है । परन्तु भारत में संसदमय सरकार है इस कारण राष्ट्रीय संसद् के अधिार राज्यों के अधिारों से सीमित है । परन्तु समकालीन मूषों में संसद् की प्रधानता है तथा संसदकाल की घोषणा होने पर यह राज्य-मूषों पर भी कानून बना सकती है । प्रवक्षित अधिार भी इसी की प्राप्त है । संसद् द्वारा बनाया हुआ कोई भी कानून अगर न्यायालया द्वारा धर्मध घोषित कर दिया जाय तो यह फिर लागू नहीं होगा । हम लिरा खुने हैं कि संसद सरकार में न्यायपालिका विधायी की सरसक होती है । एकारमय सरकार में न्यायपालिका की इस प्रकार का अधिार नहीं होता है उदाहरणार्थ इंग्लैंड ।

संसद में लोकसभा के लिए व्यवस्था मताधिार दिया गया है । इस आधार परीचन साके अठारह परोड व्यक्ति निराचक हैं । कुछ लोग के विचार । भारत की जनता अचक तथा मूल है । इसलिए यह अधिार संसद का ठाक नहीं है । परन्तु लोकतन्त्रमय सरकार का आधार हा यह सिद्धान्त है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने अकेले की पहचान है । राज्य-परिषद का निर्वाचन

अप्रत्यक्ष रखा गया है। सघातमक देशों में साधारणतः ऊपरी नदन में प्रत्येक राज्य के बराबर प्रतिनिधि होते हैं परन्तु भारत में ऐसा नहीं है।

लोकसभा के लिये आनुपातिक-प्रतिनिधित्व (Proportional Representation) को नहीं अपनाया गया है। इसके लिए यह कहा गया है कि इस प्रणाली का दोष यह है कि इससे देश में अनेक दल बन जाते हैं क्योंकि प्रत्येक का विश्वास तो रहता ही है कि उसके कुछ न कुछ प्रतिनिधि चुने जायेंगे। ऐसी अवस्था में स्थायी मन्त्रिपरिषद् निर्मित नहीं हो सकती है। परन्तु यह नहीं भूलना चाहिये कि बिना इस प्रणाली को अपनाने हुए जनता का वास्तविक-प्रतिनिधित्व अनम्बव है। कुछ लेखकों ने इंग्लैंड के लिए भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाने को लिया है, उदाहरणार्थ रामजे म्यूर।

निर्वाचन में साम्प्रदायिक-प्रतिनिधित्व तथा पृथक् निर्वाचन प्रणाली के लिये भी स्थान नहीं रखा गया है।

लोकसभा जनता की प्रतिनिधि है तथा राज्य-परिषद् राज्य की। सविधान द्वारा राज्य-परिषद् को पूर्णतया शक्तिहीन बनाया गया है। साधारण मितों के ऊपर अगर राज्य-परिषद् कोई संशोधन करे जिसे लोकसभा न माने तो संयुक्त बैठक की व्यवस्था है। परन्तु लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्य-परिषद् के दूनी है, इसलिए साधारणतः संयुक्त बैठक में भी लोकसभा की ही बात रहेगी। धन-विधेयकों पर तो राज्य-परिषद् का इना भी अधिकार नहीं है। अधिक न अधिक उन्हें १४ दिन तक रोक सकती है।<sup>१</sup>

संविधान द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति दे, या इसे संसद के विचारार्थ एक संदेश सहित फिर लौटा दे। इसको veto कहते हैं। परन्तु अगर संसद लौटाये हुए बिल को फिर से साधारण बहुमत से पास कर दे तो राष्ट्रपति अपनी अनुमति नहीं रोक सकता है। ऐसी शक्ति अन्य देशों में भी कार्यपालिका के मुखिया के पास है। इंग्लैंड में मन्त्रि को absolute veto का अधिकार है। परन्तु यह कभी प्रयुक्त नहीं होता है। कुछ लेखकों के मत में अब यह अधिकार रह नहीं गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति को भी veto का अधिकार है। परन्तु अगर वहाँ की कांग्रेस फिर से उस बिल को दो तिहाई बहुमत द्वारा पास

१. इस विषय पर आगे पूरी प्रकार से विचार किया गया है।

का दत्ता राष्ट्रपति अपना अनुमति नहीं रख सकता है। क्योंकि भारत में गणदीय-गणराज्य इसलिए राष्ट्रपति अपने veto का मन्त्रपरिषद् की राय से प्रयोग करता।

मन्त्र क दो मदना के मध्य मध्यस्थ — प्रधान मन्त्री ने ६ मई १९५३ को मन्त्र क दत्ता मन्त्रा की मन्त्र बैठक में कहा था कि मन्त्रिधान दोना दना का ममान मानता है बल्कि वितीय विषय मन्त्रिमत का ही अधिकार मन्त्र के अनुगत है। वितीय विषय के निम्नय करने में मन्त्रिमत का प्रधान है। अन्तिम निष्पादन है। परन्तु यह कहने में कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि भारतीय मन्त्रिधान में ऊपरी मदल में बल्कि वितीय मदल है अपितु मन्त्रिमन्त्र है तथा मन्त्रिधान निम्नता का उद्देश्य ही इस मन्त्र मदल बनाने का था।

राज्य परिषद् यद्यपि राज्या की प्रतिनिधि सभा है तथापि इसकी यह स्थिति भी सुदृढ़ नहीं है। क्योंकि यह नहीं भूना चाहिए कि राज्य परिषद् में सभा का इकाइया का ममान प्रतिनिधित्व नहीं है जैसा कि हम अमरिषी द्वितीय मन्त्र (सीनेट) में पाते हैं। राज्य परिषद् में विभिन्न राज्या का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर रखा गया है। भारत की राज्य परिषद् में यह भावना दृष्टिगोचर नहीं होती कि यह सभाय इकाइया की मन्त्रक है जैसा कि अमरिषी मानट में होता है।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि मन्त्रिपरिषद् के मदल राज्य-परिषद् भी हो सकते हैं और प्रधान मन्त्री भी राज्य-परिषद् का ही सदस्य हो सकता है परन्तु मन्त्रिपरिषद् राजसभा के प्रति उत्तरदायी है न कि राज्य परिषद् के प्रति। इस कारण यह स्वाभाविक है कि राजसभा का महत्व अधिक हो जायगा। इनके साथ ही साथ लोकसभा का निष्पादन जनता द्वारा प्रयत्न रूप

१ कुछ लोगका न मिया है कि भारत के राष्ट्रपति का veto किसी विषय को बन्द स्थगित कर सकता है। परन्तु राष्ट्रपति की यह शक्ति इससे बड़ी अधिक है

The veto power of our President is a combination of the absolute suspensive and pocket vetoes Basu Ibid p 340

■ The Constitution treats the two Houses equally except in certain financial matters which are to be the sole purview of the House of the People In regard to what these are the speaker is the final authority Pt Nehru in May 6th 1953



से होता है और लोकसभा जनता की प्रतिनिधि है, इन कारण भी लोकसभा का महत्व बढ़ जाता है ।

राज्य-परिषद् को, जैसा बन्दोबस्त या चूका है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में तथा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्थापित करने में नाग सभे के अधिकार दिये गये हैं । परन्तु इनके अतिरिक्त राज्य-परिषद् के कोई कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार नहीं हैं ।

व्यवस्थापन के क्षेत्र में भी नब्बू के दोनों सदनों के समान अधिकार नहीं हैं । प्रत्येक व्यवस्थापन के सम्बन्ध में लोकसभा की स्थिति प्रधान है तथा राज्य सभा के अधिकार अत्यन्त ही सीमित हैं । विज्ञेय तथा घन सम्बन्धी विवेक केवल लोकसभा में ही प्रस्तापित किया जा सकता है । इन सदन में पारित होने पर यह द्वितीय सदन को भेजा जाता है । द्वितीय सदन इस विषयक को चौदह दिन के अन्दर अपनी निफारियों सहित लोकसभा को वापिस करदे । लोकसभा इन निफारियों को माने या न माने । यदि राज्य-परिषद् १४ दिन के भीतर इसे वापिस नहीं करती तो यह उपाय रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित नकल जायगा जिस रूप में यह लोकसभा में पाम हुआ था ।

साधारण विधेयकों के सम्बन्ध में यद्यपि दोनों सदनों के अधिकार समान रख गये हैं तथा मतभेद होने पर मजबूत बैठक में लोकसभा की मद्रस्व मंज्या, राज्य-परिषद् से लगभग दुगुनी होने के कारण यह स्थानाधिक है कि लोकसभा का ही दृष्टिकोण माना जायगा ।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि लोकसभा ही मद्रस का प्रभावी तथा प्रमुख सदन है । इन स्थिति में परिवर्तन सम्भव नहीं है । अमेरिका के संविधान निर्माताओं का भी यही विचार था कि यहाँ का विद्वत् मद्रस जो प्रतिनिधि सभा कहलाता है प्रमुख सदन होगा । किन्तु वहाँ कानान्तर में इसके विपरीत, अनेक कारणों से ऊपरी सदन प्रमुख सदन हो गया । परन्तु भारत में ऐसा होना असम्भव है । इसका कारण यह है कि यहाँ सांसदीय व्यवस्था है । फलस्वरूप कार्यपालिका का मुख्य उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति ही रहेगा ।

भारत का नियन्त्रक महालेखा परीक्षक :—इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है । उसका वेतन तथा सेवा की गारंटी संनद विधि द्वारा निश्चित करेगी । प्रत्येक व्यक्ति जो इस पद में नियुक्त किया जायगा राष्ट्रपति के सम्मुख अपने पद की शपथ लेगा । अपने पद से अवकाश ग्रहण करने के बाद नियन्त्रक महालेखा परीक्षक भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार

क अधीन जीर कोई पद नहीं ग्रहण कर सकता है। वह अपन पद में केवल उसी प्रकार हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय का जस्टिस यायाधिश अर्थात् जब संसद व दोनों सदन एक ही अधिवेशन में सब मदम्या व बहुमत तथा उपस्थित सदस्या के दो तिहाई बहुमत में राष्ट्रपति से उसका हटान की मना कर।

नियंत्रक महात्मा परीक्षक का काम बहुत महत्वपूर्ण है। वह यह देखता है कि प्रत्येक विभाग उतना ही खर्च करे तथा उही विषया पर खर्च कर जितना कि संसद ने निर्दिष्ट किया है। संविधान में यह कहा है कि वह सब राज्यों तथा अन्य अधिकारियों के ललाभा व सम्बन्ध में ऐस कृतव्या का पालन करेगा जैसा कि संसद निर्दिष्ट करे। परन्तु जब इस विषय में संसद कानून नहीं बनाती है तब तब उसके काम बड़ी हानि जो कि संविधान लागू होने के पूर्व भारत के महालेखा परीक्षक के काम में। सब तथा राज्यों के ललाभा को किस प्रकार रखा जावे इसका निर्दिष्ट वह राष्ट्रपति के अनुमोदन में करेगा। उसके सब लेखा सम्बन्धी रिपोर्टों को संसद में रखवावेगा। राज्य लेखा मंत्री रिपोर्टों को राज्यपाल उस राज्य में विधानमण्डल के सामने रखवावेगा।

नियंत्रक महात्मा परीक्षक को संसद में भाग लेने का अधिकार है परन्तु अनुदान का नहीं।

मई १९५३ के प्रारम्भ में संसद द्वारा एक विधेयक [The Comptroller and Auditor General (Condition of Service Bill) 1953] स्वीकृत किया गया है जिसके अनुसार इस पदाधिकारी का कार्यकाल ५ वर्ष का स्थान पर ६ वर्ष कर दिया गया है। यह भी इस विधेयक द्वारा निर्दिष्ट किया गया है कि अवकाश ग्रहण करने पर उसे ₹२००० प्रति वर्ष पेंशन मिलेगी।

## परिशिष्ट

(अ) भारत संसार में सबसे बड़ा लोकतन्त्रात्मक देश है। यहाँ निर्वाचकों की संख्या, गत निर्वाचन (१९५७) में १९२१ २९ ९२४ थी। पिछले निर्वाचन के समय इनकी संख्या केवल १७ करोड़ ३२ लाख थी। विभिन्न राज्यों में निर्वाचकों की संख्या इस प्रकार थी।

आंध्र	१,७६,६०,६६४	पंजाब	११,१२,७४२
आसाम	४३,७५,०८९	राजस्थान	८६,९३,०३१
बिहार	१,९५,६३,७४७	उत्तर-प्रदेश	३,४७,७०,४३४
बम्बई	२,४३,८६,५२५	पश्चिमी बंगाल	१,५१,८१,०६१
केरल	७५,५९,०४७	दिल्ली	९,७६,३६१
मध्य प्रदेश	१,३८,८०,२०९	हिमाचल प्रदेश	६,८४,६२८
मद्रास	१,७५,९९,०५६	मनीपुर	३,३०,१११
मैसूर	१,०१,२३,६१८	निपुरा	३,४५,८४९
उड़ीसा	७९,५१,८०५		

(ब) १९५७ के निर्वाचन में लगभग ४९\*२ प्रतिशत मतदाताओं ने मत दिया। गत निर्वाचन में केवल ४४\*२ प्रतिशत ने भाग लिया था।

लोक सभा के लिये समस्त देश में ३८५ एक सदस्यीय तथा ८ द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र स्थापित किये गये थे। ७४ स्थान परिगणित आतियों तथा २९ स्थान परिगणित जन-जातियों के लिये सुरक्षित रखे गये थे। इस चुनाव में कोई भी निर्वाचन क्षेत्र त्रिसदस्यीय क्षेत्र नहीं था।<sup>१</sup>

भारत की विद्याल जनसंख्या के कारण निर्वाचन अत्यन्त ही बड़ा काम है। निर्वाचन आयोग को इस बार लगभग २९,६०,००० लोहे की मतपेटियाँ बनवानी पड़ी और दस लाख से भी अधिक कर्मचारी को चुनाव कार्यों में लगाया गया।

इस बार निर्वाचन के लिये ३ लाख से कुछ अधिक निर्वाचन घरों (polling stations) की आवश्यकता हुई। गत चुनाव में केवल १,९६,०८४ निर्वाचन-घर थे।

(स) निर्देशन पत्र—निर्वाचन के लिये लड़े होने वाले प्रत्याशी (candidate) के लिये यह आवश्यक था कि वह निर्वाचन अधिकारी द्वारा घोषित नियत तिथि से पूर्व अपना निर्देशन पत्र दो मतदाताओं के हस्ताक्षर सहित, एक नाम प्रस्तुत करने वाला (proposer) तथा दूसरा अनुमोदन करने वाला (seconder) तथा जा पर अपनी लिखित सहमति के निर्वाचन अधिकारी को स्वयं भयवा इन उपर्युक्त दो व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा जमा करदे। यदि वह ससद के लिये प्रत्याशी था तो उसे ५००) अपने निवेदन पत्र के साथ जमा करना होता था।

१ ये आँकड़े Hindustan Year Book 1957, p. 630-631 में लिये गये हैं।

इन निवेदन पत्रों की निर्वाचन अधिनियमों द्वारा जाँच होती है और जो ठीक समझे जाते हैं वेचल वही प्रत्याशी निर्वाचन में खड़े हो सकते हैं। इसके पश्चात् इनको कुछ समय इसके लिये भी दिया जाता है कि यदि वे चाहें तो प्रपना नाम घोषित न करने हैं।

(द) मतदान पूर्णतः गुप्त होता है। प्रजातन्त्र की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि मतदाना स्वतन्त्रतापूर्वक तथा निर्भयता से मतदान करें। इस लिये गुप्त मतदान आवश्यक है।

निर्वाचन के पश्चात् मतगणना होने पर जिसे सर्वाधिक मत प्राप्त होने हैं वह निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है।

यदि कोई प्रत्याशी निर्वाचन से असन्तुष्ट है कि निर्वाचन ठीक प्रकार नहीं हुआ तो उसके लिये यह व्यवस्था की गई है कि वह निर्वाचन-पत्रिका (election petition) देकर निर्वाचन-न्यायालय के सम्मुख प्रपना मामला रख सकता है। इस निर्वाचन-न्यायालय का निर्णय अन्तिम होता है।

### प्रश्न

(१) मम ससद् के विरोधाधिकारों की व्यवस्था का वर्णन कीजिये। क्या ससद् मविधान में संशोधन कर सकती है? यदि कर सकती है तो किस प्रकार? (यू० पी० १९५१)

(२) लोकसभा के निर्माण का वर्णन कीजिये। इस सभा के अधिकारों की तुलना राज्यपरिषद के अधिकारों से कीजिये। (यू० पी० १९५२)

(३) नक्षेत्र में विधान-प्रक्रिया क्या है, इसको समझाइये।

(४) लोक सभा और राज्य-परिषद के पारस्परिक सम्बन्ध बतलाइये। (यू० पी० १९५४)

(५) भारतीय मसद के अधिनियम बनाने के अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिये। (यू० पी० १९५५)

(६) भारतीय लोकसभा की रचना और उसके अधिकारों का वर्णन कीजिये। (यू० पी० १९५६)

(७) भारतीय मसद के दोनों सदनों, लोक सभा और राज्य-सभा के पारस्परिक सम्बन्धों का वर्णन कीजिये। (यू० पी० १९५८)

## राज्यों का शासन

प्रत्येक संघ में एक संघ सरकार तथा कुछ राज्यों की सरकार होती है। भारत में ऐसा ही है। संघ सरकार का हम वर्णन कर चुके हैं। अब राज्यों के शासन-प्रबन्ध को देखना चाहिये। जैसा पहले बतलाया जा चुका है राज्य पुनर्गठन विधेयक के कारण, संविधान में जो संशोधन हुआ, उनके फलस्वरूप भारत संघ के अन्तर्गत राज्यों को दो कोटियों में रखा गया है। इनमें से प्रथम कोटि राज्य स्वायत्त राज्य हैं। इनके साथ ही साथ वहाँ उत्तरदायित्वपूर्ण शासन है। कार्यपालिका विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है। संघ की ही प्रकार यहाँ भी सांख्यिक पद्धति की सरकारें स्थापित की गई हैं। एतद्वय साधारण रूप से संघ सरकार तथा इन राज्यों की सरकारों में काफी साम्य है। कानून बनाने की पद्धति तथा विधान-सभाओं की कार्य-प्रणाली संघ की ही तरह है।

इन राज्यों के अन्तर्गत जम्मू-काश्मीर की विशेष स्थिति है। इस राज्य का शासन इसके द्वारा स्थापित मन्त्रिमण्डल निर्मात्री सभा के द्वारा निमित्त हुआ है। इसलिये हम इसका पुनः वर्णन करेंगे।

उपर्युक्त राज्यों के अतिरिक्त ७ केन्द्र द्वारा शासित क्षेत्र हैं। ये स्वायत्त राज्य नहीं हैं और इनका शासन केन्द्र द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा होता है।

### स्वायत्त राज्यों का शासन - (१) कार्यपालिका

संविधान :—इन राज्यों का प्रधान राज्यपाल कहलाता है। संविधान में कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्यपाल में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। इसने यह न समझना चाहिये कि राज्यपाल समार्य शक्ति है। समार्य में शक्ति तो मन्त्रिपरिषद् के हाथ में है। राज्यपाल तो केवल वैधानिक प्रधान है। सब काम उसके नाम में किया जायगा, परन्तु सब मन्त्रिपरिषद् द्वारा किया जायगा। इसलिये हमने धारम्भ में कहा था कि संघ के राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की स्थिति में कोई अन्तर

नहीं है। परन्तु राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह परराष्ट्रनीति सम्बन्धी सैनिक तथा सशस्त्रबल अधिकार नहीं है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल कुछ विषयों में राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी भी है।

**नियुक्ति** — राज्यपाल की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति का है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि जब सभ के प्रधान का चुनाव होता है तो राज्य के प्रधान का चुनाव क्या न हो? अमेरिका में राज्या के गवर्नर का जनता द्वारा सीधा चुनाव होता है। भारत में यह पद्धति स्वीकार न कर ब्रिटिश उपनिवेशों में प्रचलित पद्धति का स्वीकार किया है। कनाडा तथा अन्य उपनिवेशों में गवर्नर की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है। संविधान सभा में कुछ सदस्यों का यह मत था कि राज्यपाल का जनता द्वारा निर्वाचन होना चाहिये। परन्तु इसके विरुद्ध निम्नलिखित तर्क दिए गए और अन्त में यही निश्चित हुआ कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जावेगा।

(१) राज्यपाल केवल वैधानिक प्रधान है इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि वह राज्य के समस्त मतदानांशों द्वारा निर्वाचित हो।

(२) अगर राज्यपाल का जनता द्वारा निर्वाचन हुआ तो उसमें तथा मन्त्रिपरिषद् में मधुरता की बहुत अधिक सम्भावना रहेगी। क्योंकि वह इस बात का नहीं भूल सकता कि मन्त्रियों की ही तरह वह भी जनता का प्रतिनिधि है।

(३) समस्त जनता द्वारा निर्वाचित होने में ध्येय ही समय तथा श्रम की हानि होती है।

(४) निर्वाचन में यह भी सम्भव था कि राज्य की सरकार की एकात्मता तथा स्थिरता नष्ट हो जाते। राज्यपाल भी दम्बन्दी में पड़ जाता।

(५) राष्ट्रपति द्वारा अगर राज्यपाल मनोनीत होता तो राज्या के ऊपर सभ सरकार की शक्ति और मजबूत हो जायेगी।

इन कारणों से यही उचित समझा गया कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हो तथा दूसरे राज्य का निवासी हो। इससे वह राज्य के अन्दर की दल बन्दी में ऊपर रहेगा।

राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपने पद पर रहेगा। परन्तु साधारणतः उसका कार्यकाल ५ वर्ष होगा। इससे पूर्व अगर वह अपना पद छोड़ना चाहे तो वह राष्ट्रपति का त्यागपत्र दे सकता है। अपना कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी राज्यपाल तब तक अपने पद पर काम करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले।

**पद के लिए योग्यताएँ तथा शर्तें** —राज्यपाल नियुक्त होने के लिए दो योग्यताएँ आवश्यक हैं वह व्यक्ति भ्रान्त का नागरिक होना चाहिये तथा उसकी आयु कम से कम पैंतीस वर्ष की पूरी होनी चाहिए ।

राज्यपाल न तो सत्तद् के किसी मदन का, और न के किसी राज्य के विधान-मण्डल के किसी सदन का सदस्य होना चाहिये । अगर वह इन दोनों में से किसी का सदस्य हुआ तो राज्यपाल के पद ग्रहण की तारीख से उसकी सदस्यता समाप्त हो जावेगी । राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद नहीं धारण कर सकता है ।

**वेतन** —राज्यपाल का वेतन, भत्ते आदि मंत्रि मन्त्र द्वारा निर्धारित करेगी । परन्तु जब तक मंत्रि इनके विषय में कानून नहीं बनाती तब तक राज्यपाल को ५,५०० रुपये मासिक वेतन तथा अन्य भत्ते आदि दिये जायेंगे । उसको बिना किराया दिये एक निवास-स्थान दिया जावेगा । उसके कार्यकाल में उसके वेतन, भत्ते आदि में कोई कमी नहीं की जावेगी ।

यदि दो या अधिक राज्यों के लिये एक ही राज्यपाल की नियुक्ति हो तो इन राज्यों के बीच उसके वेतन आदि का सब बित्त अनुपात में बाँटा जाय, इनका निश्चय राष्ट्रपति द्वारा किया जायगा ।

**शपथ** :—प्रत्येक राज्यपाल को अपने पद ग्रहण करने से पहले उस राज् के उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिशपति के सम्मुख निम्नलिखित प्रतिज्ञा करनी होगी तथा उन पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे ।

मैं...अमुक, ईदवर की शपथ लेता हूँ कि मैं अङ्गपूर्वक... (राज्य का नाम) के राज्यपाल का कार्यपालन (अथवा राज्य के कर्त्तों का निर्वाह) करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से सविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं... (राज्य का नाम) की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा ।

**अधिकार** :—राज्यपाल के अधिकारों की चार भागों में बाँट सकते हैं । इनमें से प्रत्येक का क्रमशः वर्णन किया जावेगा ।

(१) कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार :—सविधान में यह कहा गया है कि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है । इस शक्ति का प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा करेगा । राज्य की कार्यपालिका

शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके बारे में उस राज्य का विधान मण्डल बानून बना सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वे सब विषय जो कि राज्य सूची में वर्णित हैं इनके क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर क्योंकि सभ्य संसद को प्राथमिकता तथा प्रधानता दी गई है इसलिए इन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका अधिक राज्य की कार्यपालिका शक्ति के ऊपर है। राज्य के सरकार की सारी कार्यपालिका कायदाही राज्यपाल व ही नाम से की हुई वही जायेगी।

राज्यपाल मुख्य मंत्री की नियुक्ति करेगा तथा उसकी राय के अनुसार अन्य मन्त्रियों की। यह राज्य की सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिये तथा मन्त्रियों में उसका विभाजन करने के लिए नियम बना देगा। राज्य के राज्य मंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल का मन्त्रि परिषद के निर्णय की सूची देता रहे।

राज्यपाल को कुछ उच्च सरकारी कमचारियों की नियुक्ति का अधिकार है उदाहरणार्थ राज्य का महाधिवक्ता (Advocate General) पब्लिक सर्विस कमिशन के सदस्य आदि।

(२) कानूनी सम्बन्धी अधिकार -- राज्यपाल राज्य के विधान-मण्डल का एक भाग है। उसको राज्य के विधान मण्डल के एक सदन या दोनों सदनों के अधिवेशन को समय समय पर आमन्त्रित करने का अधिकार है। परन्तु पहले अधिवेशन की आखिरी तारीख तथा दूसरे अधिवेशन की पहली तारीख के बीच ६ महीने से अधिक समय नहीं होना चाहिये। उसे विधान मण्डल को स्थापित करने तथा भंग करने का भी अधिकार है। उस विधानमण्डल के एक सदन अथवा दोनों सदनों को सम्बोधन रूप से सम्बोधित (Address) करने तथा उन्हें लिखित सन्देश भेजने का अधिकार है। जिन राज्यों में विधान मण्डल में ऊपरी-सदन (राज्यपरिषद) है वहाँ राज्यपाल उसमें कुछ सदस्यों को मनोनीत करेगा जिनको साहित्य विज्ञान, कला, महत्त्वपूर्ण आन्दोलन तथा सामाजिक सेवा के बारे में विशेष ज्ञान या अनुभव है। वह अगर यह सोचे कि विधान सभा में ऐंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व समुचित रूप से नहीं हुआ है तो वह उस समुदाय के कुछ सदस्य विधान सभा में मनोनीत कर सकता है।

प्रत्येक विल जो कि राज्य के विधानमण्डल द्वारा पास हो गया हो राज्यपाल के सामने उसकी अनुमति के लिए उपस्थित किया जाएगा। बिना इस



अनुमति के वह कानून नहीं हो सकता है। राज्यपाल किसी ऐसे बिल को अनुमति दे या न दे। राज्यपाल किसी ऐसे बिल को जो कि धन विधेयक (Money Bill) नहीं है, अपनी सिफारिश के साथ फिर से विधान-मण्डल को लौटा सकता है। परन्तु अगर विधानमण्डल ने इस बार इस बिल को फिर से पास कर दिया तो राज्यपाल को अपनी अनुमति देनी ही पड़ेगी।

राज्यपाल किसी बिल को जो कि विधानमण्डल द्वारा पास हो गया हो, राष्ट्रपति के विचार के लिये रक्षित कर सकता है। अगर कोई बिल ऐसा है जो कि राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों को दम करता है तो राज्यपाल ऐसे बिल को मस्यदा राष्ट्रपति के विचारार्थ रोकता। राष्ट्रपति राज्य द्वारा उसके विचारार्थ रक्षित किसी बिल को अपनी स्वीकृति दे या न दे। धन-विधेयक के अनिश्चित, किन्तु अन्य विधेयक को राष्ट्रपति राज्य के विधान-मण्डल को अपने सन्देश सहित लौटा सकता है। राज्य के विधान-मण्डल को ऐसा सन्देश मिलने के ६ महीने के अन्दर उस पर फिर से विचार करना पड़ेगा। अगर वह बिल फिर से पास हो गया तो वह फिर से राष्ट्रपति के सम्मुख उसकी सम्मति के लिये भेजा जायगा। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह अपनी सम्मति दे या न दे। अगर उसकी सम्मति प्राप्त न हुई तो वह बिल रद्द हो जायगी।

अगर राज्य का विधान-मण्डल अधिवेशन में न हो तो राज्यपाल आवश्यकता होने पर उन सब विषयों पर अध्यादेश बना सकता है, जिन पर कि राज्य के विधान मण्डल को कानून बनाने का अधिकार है। ऐसे किसी अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो राज्य के विधान-मण्डल द्वारा बनाए हुए किसी कानून का, किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश राज्य के विधान-मण्डल के सम्मुख रखा जायगा। विधान-मण्डल के अधिवेशन आरम्भ होने के ६ मप्ताह बाद अध्यादेश रद्द हो जायगा। इसके पूर्व ही यह रद्द हो सकता है अगर, विधान-मण्डल इसको रद्द कर दे तो राज्यपाल भी इसको किसी समय लौटा सकता है।

कुछ विषयों पर राज्यपाल बिना राष्ट्रपति के अनुदेशों के अध्यादेश नहीं बना सकता है। ये निम्नलिखित हैं—

(१) उस राज्य के साथ या भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतन्त्रता पर लोकहित की दृष्टि से कोई व्यक्तिगत रोक लगाना चाहता हो। इस विषय का कोई बिल भी बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के राज्य विधान मण्डल में पेश नहीं किया जा सकता है।

(२) अगर अध्यादेश में ऐसे उपबन्ध हों जैसे कि किसी बिल में होने पर वह उसे राष्ट्रपति के विचाराय रक्षित करना आवश्यक समझता है। जैसे राज्य के उच्चन्यायालय की शक्ति कम करने वाले।

(३) अगर अध्यादेश में ऐसे उपबन्ध हों जैसे किसी बिल में होने पर उसके लिये संविधान के अधीन राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती। उदाहरणार्थ, राज्य के अन्तर्गत किसी सम्पत्ति पर वज्रा करने के लिये, उन वस्तुओं पर कर लगाने के लिये जो कि समद ने समुदाय के जीवन के लिये आवश्यक घोषित कर दी है जो समवर्ती सूची में वर्णित विषय पर है पर जो मसल द्वारा बनाए हुए किसी कानून के विरुद्ध पड़ते हैं या कुछ विशेष प्रवस्थाओं में पानी तथा बिजली पर कर लगाने के लिये [भाग २८८ (२)]।

(३) न्याय सम्बन्धी अधिकार — राज्यपाल का यह अधिकार है कि राज्य के किसी कानून के विरुद्ध किसी अपराध के लिये दण्डित व्यक्ति के दंड को वह क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है तथा कुछ समय के लिये रोक सकता है। परन्तु अगर कोई व्यक्ति सच-सरकार के कानून का उल्लंघन करने के अपराध में दण्डित हुआ है तो राज्यपाल उस अपराध में कुछ नहीं कर सकता है। उसे प्राणदण्ड क्षमा करने या कम करने का भी अधिकार नहीं है। आन्तरिक दोनों मामलों में जैसा पहले बताया जा चुका है राष्ट्रपति का ही अधिकार है।

(४) राज्य सम्बन्धी अधिकार — विधान सभा में कोई भी धन विधेयक उसकी मिकारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता है राज्य की आकस्मिकता विधि में में किसी आकस्मिक व्यय के लिये विधान मण्डल कि आज्ञा के पहले ही रूपया दे सकता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष (financial year) के प्रारम्भ में वह विधान मण्डल के सम्मुख उस वर्ष के अनुमानित आय तथा व्यय का विवरण प्रस्तुत करेगा। इनको वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual financial statement) कहते हैं।

मन्त्रिपरिषद् — राज्य के मन्त्रिपरिषद् का संक्षेप में ही वर्णन किया जायगा क्योंकि इसमें तथा संघीय मन्त्रिपरिषद् में सैद्धान्तिक दृष्टि से करीबन पूरी समानता है। संघ में तथा राज्यों में दोनों स्थलों में मासिक पद्धति प्रचलित की गई है। अतएव दोनों जगह मन्त्रिपरिषद् के ही हाथ में वास्तविक शक्ति है।

संविधान में कहा गया है कि राज्यपाल को अपना काम करने में (विशेष कुछ विशेष कृत्यों के) सहायता और सत्रा देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान मुख्य-मन्त्री होगा। सभ के मन्त्रिपरिषद् का प्रधान प्रधान-मन्त्री कहलता है। मुख्य-मन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति वह मुख्य-मन्त्री की राय से करेगा। मन्त्री अपने पदों पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त रहेंगे।

मन्त्रिपरिषद् विधान-सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। अतएव यह स्वाभाविक है कि मुख्य मन्त्री विधान-सभा में बहुसंख्यक दल का नेता होगा। अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति उनके द्वारा की जावेगी न कि राज्यपाल द्वारा जो उसके द्वारा दिए गए नामों को मान लेगा। मन्त्रिगण क्योंकि विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी है इसलिए जब तक विधान-सभा का उनमें विश्वास है वे अपने पदों पर रहेंगे। अगर राज्यपाल किसी ऐसे मन्त्रिपरिषद् को भंग कर दे जिसका विधान में बहुमत है तो उसको नए मन्त्रिपरिषद् का निर्माण करने में बाधित कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

संविधान में यह नहीं कहा गया है कि मन्त्रिपरिषद् में कितने सदस्य होंगे इसलिए उनकी संख्या का निर्देश मुख्य-मन्त्री सरकार के काम की उचित व्यवस्था तथा राज्य की भाषिक अवस्था ध्यान में रखते हुए करेगा। परन्तु संविधान में यह कहा गया है कि बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में मुख्यमन्त्री द्वारा एक मन्त्री की नियुक्ति पिछड़ी हुई जातियों तथा आदिम जातियों के हितों की रक्षा करने तथा उनकी उन्नति के लिए काम करने के लिए की जावेगी। इससे यह नहीं सोचना चाहिये कि अन्य राज्यों में सरकार का वह कर्तव्य नहीं है।

मन्त्रिपरिषद् की सदस्यता के लिए यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति विधान-मंडल का सदस्य हो। कोई मन्त्री जो ६ महीने तक विधान-मंडल का सदस्य न रहे, उस काल की समान्ति पर मन्त्री नहीं रहेगा।

मन्त्रियों का वेतन तथा भत्ते समय-समय पर राज्य का विधान-मंडल कानून द्वारा निर्धारित करेगा। परन्तु जब तक ऐसा नहीं होता उनकी वही वेतन मिलेगा जो कि संविधान आरम्भ होने के पहले मिलता था।

प्रत्येक मन्त्री को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल द्वारा पद की तथा गोपनीयता की शपथ ग्रहण करवाई जायेगी।

सविधान में कहा गया है कि सरकार व काम की सविधापूर्वक चयन के लिए राज्यपाल उनका मन्त्रिया व चांच विभाजन करने के लिए नियम बनायेगा। यथाय में मन्त्रिया व बीच काम का विभाजन मुख्य मन्त्री करता है। प्रत्येक मन्त्री के अधीन एक-दो विभाग होते हैं। मन्त्रिया व नीचे उपमन्त्री, सल्लियामेन्टरी सेक्रेटरीज भी हैं। इनके अतिरिक्त प्रत्येक विभाग में सचटरी डिप्टी सचटरी असिस्टेंट सेक्रेटरी आदि होते हैं। ये सरकारी नौकर होते हैं (Permanent Civil Servants) तथा इनकी नौकरी पर मन्त्रिमण्डल व बनने विगड़न का प्रसर नहीं होता है।

**मन्त्रिपरिषद् का काम** — इनका काम सविधान व अनुसार राज्यपाल का मन्त्रणा देना तथा सहायता देनी है। किसी ग्यामाग्य में यह नहीं पूछा जा सकेगा कि किस मन्त्री ने राज्यपाल का क्या सलाह दी।

मुख्य मन्त्री का काम राज्यपाल को उन सब निश्चया की सूचना देना है जो कि मन्त्रिपरिषद् ने सामान सम्बन्धी अथवा कानूनी सम्बन्धी मामला में लिए हैं। अगर राज्यपाल चाहे तो वह इन मामलों पर किसी और सूचना का मांग सकता है। वह किसी विषय को जिस पर एक मन्त्री ने निश्चय कर लिया है परन्तु मन्त्रिपरिषद् ने नहीं, फिर से मन्त्रिपरिषद् के सामने विचारार्थ रख सकता है।

मन्त्रिपरिषद् का काम मन्त्रणा देना ही नहीं अपितु यथाय में राज्यपाल के नाम में सब काम करना है। इसकी वही स्थिति है जो कि मधीय मन्त्रिपरिषद् की। परन्तु इसमें एक अन्तर है। सविधान द्वारा राज्यपाल का कुछ कार्यों को स्वविवेक से करने का अधिकार दिया गया है। इन सब मामलों में राज्यपाल बिना मन्त्रिमण्डल के परामर्श के काम करेगा। किन्तु विषयों में वह स्वविवेक से काम करेगा यह उसी के निश्चय में छोड़ दिया गया है। उनका निश्चय इस विषय में अनिश्चित होगा। सविधान में यह स्पष्ट नहीं है कि किन विषयों में राज्यपाल का स्वविवेक से काम करने का अधिकार है। तथापि ऐसा लगता है कि आमतौर पर अन्तर के अतिरिक्त अन्य किसी राज्यपाल को स्वविवेक से काम करने का अधिकार प्रयोग करने का अवसर नहीं मिलेगा। आमतौर में राज्यपाल कुछ आदिम जाति-अन्तर्गत का सामान प्रत्यक्ष राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की स्थिति में करता है। उसके लिए वह मन्त्रिपरिषद् की सलाह तथा मन्त्रणा नहीं लेगा।

मन्त्रिया का काम अपने अपने विभाग के दिन प्रतिदिन के कामों को देखना है। उनका करने में वे स्वतन्त्र हैं। परन्तु नीति सम्बन्धी विषयों का

निश्चय मन्त्रिपरिषद् द्वारा ही किया जावेगा। प्रत्येक मन्त्री का कर्तव्य है कि वह मन्त्रिपरिषद् के निर्णय को माने। अगर वह ऐसा करने में असमर्थ है तो उसे मन्त्रिपरिषद् से त्यागपत्र देना होगा। मन्त्रियों को विधान-मण्डल में अपने विभाग के कामों से सम्बन्ध रखने वाले बिलों को पेश करना, प्रश्नों का उत्तर देना तथा अपने विभाग के कामों को समझाना आदि काम करने पड़ते हैं।

राज्यपाल तथा मन्त्रिपरिषद् में सम्बन्ध — हम पहले कह चुके हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। राज्यपाल को मनीनीत करने के पक्ष में एक तर्क यह भी था कि वह सब शक्ति से हीन, केवल वैधानिक प्रधान है। इससे यह स्पष्ट हो जाना है कि राज्यपाल अपने मन्त्रिपरिषद् की राय से ही काम करेगा। दूसरे शब्दों में सब शक्ति मन्त्रिपरिषद् के ही हाथों में है तथा राज्यपाल जैसा मन्त्रिपरिषद् कहेगा वैसा करेगा। अर्थात्, राज्यपाल केवल वैधानिक प्रधान-मात्र है।

यद्यपि राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह मुख्य-मंत्री की नियुक्ति तथा उसकी सलाह से अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति करे और यह भी कहा गया है कि मन्त्रिपरिषद् उसके प्रसाद-पर्यन्त अपने पद पर रहेगा तथापि यथार्थ में राज्यपाल को मन्त्रियों की नियुक्ति तथा, उसको अपदस्थ करने में केवल नाममात्र की स्वतन्त्रता है। मन्त्रिपरिषद् के विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होने के कारण राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री का पद ग्रहण करने को आमन्त्रित करेगा। मुख्य-मंत्री अपने मन्त्रिपरिषद् के अन्य सदस्यों को चुनेगा। मन्त्रिमण्डल तब तक अपने स्थान में बना रहेगा जब तक इसका विधान सभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त है। अगर राज्यपाल किसी ऐसे मन्त्रिपरिषद् को अपदस्थ कर दे तो उसके लिए दूसरा मन्त्रिपरिषद् निर्माण करना असम्भव हो जावेगा।

इससे यह स्पष्ट हो गया कि राज्यपाल केवल वैधानिक प्रधान है। परन्तु इससे यह निर्णय नहीं निकलना चाहिये कि वह केवल शोभाय है और उसका कोई काम नहीं।<sup>1</sup> अगर राज्यपाल योग्य तथा अनुभवी व्यक्ति हुआ

1. संविधान सभा में एक सदस्य ने कहा था "The function of the Governor shall be to lubricate the machinery of Government, to see that all the wheels are going well by reason not of his interference, but of his friendly intervention."

ता वह राज्य के शासन की सुचारु रूप से चलायें में बहुत अधिक सहायता पहुँचा सकता है। दख्खन्दी के झगडा का दूर कर मन्त्रिपरिषद् का काफी सहायता दे सकता है। वह मन्त्रि-परिषद् को ऐसे काम करने से रोक सकता है जो कि अन्य दला को हचिकर नहीं है।

राज्यपाल का सबसे मुख्य काम यह देखना है कि मन्त्रि-परिषद् इतना अधिक दख्खन्दी की भावना से ओत-प्रात न हो कि जनता के हितों का ध्यान ही न रखे। अगर मुख्य-मन्त्री कभी विधान-सभा भंग करने की प्रार्थना करे तो राज्यापाल यह धनभव करे कि यह जनता के हित में नहीं होगा तो वह इस प्रार्थना का अस्वीकार कर सकता है। अथवा, अगर कभी मन्त्रि-परिषद् का विधान सभा में तो बहुतम हा परन्तु जनता में उसकी नीति में असन्तुष्टि उत्पन्न हो गया हो तो राज्यापाल विधान-सभा को भंग कर नये निर्वाचन करवा सकता है।

**महाधिवक्ता (Advocate General)** —जिस प्रकार मधीय सरकार में राष्ट्रपति अधि-सम्बन्धी मामला में सलाह के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है उसी प्रकार वैसे परामर्श के लिए राज्यापाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। इस पद के लिए वही व्यक्ति नियुक्ति हो सकता है जो कि उच्च न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है। उसकी जो वेतन तथा भत्ते मिलेंगे इनका निर्देश राज्यापाल करेगा। वह अपने पद पर राज्यापाल के प्रसादपर्यन्त रह सकता है।

## (२) व्यवस्थापिका

प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान-मंडल होता जो राज्यापाल तथा कुछ राज्या में दो सदना से तथा कुछ अन्य राज्या में एक सदन में मिलकर बनेगा। पंजाब, बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश, मैसूर तथा उत्तर प्रदेश में दो सदन हैं। निचला सदन विधान-सभा तथा ऊपरी सदन विधान-परिषद् कहलाता है। अन्य राज्या में केवल एक ही सदन है। यह सदन विधान-सभा कहलाता है। परन्तु जिस राज्या में दो सदन हैं वहाँ की विधान-सभा

परन्तु बंगाल के उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में राज्यापाल के विषय में कहा—“Under the present Constitution the power to act in his discretion or in his individual capacity has been taken away and the Governor, therefore must act on the advice of his minister”

सब सदस्यों के बहुमत से तथा उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से यह पास करे कि विधान-परिषद् हटा दी जावे तो मन्त्र-परिषद् द्वारा उस राज्य से विधान-परिषद् को हटा सकेगी। इसी प्रकार जिन राज्यों में एक ही सदन है वहाँ मन्त्र-परिषद् द्वारा दूसरे सदन का सृजन कर सकेगी।

कुछ राज्यों में द्वि-सदनीय विधान-मंडल की व्यवस्था है। इसका कारण यह है कि दूसरा सदन अनेक दृष्टियों से उपयोगी माना गया है। जैसे, यह निचले सदन से भेजे गये विधेयकों पर पुनर्विचार करता है, विरोध हितों की रक्षा करता है तथा उन्हें प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। इनमें अधिक अनुभवी व्यक्तियों की भाँति काम करने का व्यवसर मिलता है, आदि।<sup>1</sup>

**विधान-परिषद् :—**यह विधान-मंडल का ऊपरी सदन होगा। किसी राज्य के विधान-परिषद् में साधारणतः उन राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या के चौथाई भाग से अधिक सदस्य नहीं होंगे। परन्तु यह संख्या किसी भी तरह ४० से कम नहीं होगी। किसी राज्य के विधान-परिषद् की रचना, जब तक संसद कानून द्वारा कोई और प्रवन्ध न करे, निम्नलिखित प्रकार से होगी।

(क) कुल सदस्य संख्या का तीसरा भाग, उस राज्य की नगर-पालिकाओं, जिला-मंडलों तथा अन्य ऐसी स्थानीय संस्थाओं के, जैसा कि संसद विधि द्वारा निर्दिष्ट करे, सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचन-मंडलों द्वारा चुना जायगा।

(ख) कुल सदस्य संख्या का बाँहवाँ भाग उस राज्य में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बने हुए निर्वाचन-मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा, जो भारत के किसी विश्वविद्यालय के कम से कम तीन वर्ष से स्नातक (graduate) हैं या इसके बराबर की संसद द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य योग्यता धारण करते हों।

(ग) कुल सदस्य संख्या का बाँहवाँ भाग ऐसे निर्वाचन-मंडलों द्वारा चुना जायगा जो कि उस राज्य के भीतर रहने वाले ऐसे व्यक्तियों से बने होंगे जो कि उस राज्य में माध्यमिक शिक्षास्थलों या इससे उच्च शिक्षालयों में तीन साल से अधिक से अध्यापन कार्य कर रहे हों।

(घ) कुल सदस्य संख्या का तीसरा भाग राज्य की विधान-सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा जो कि सभा के सदस्य नहीं हैं।

1. इस विषय के विस्तार-पूर्वक वर्णन के लिये लेखक की पुस्तक 'नागरिक शास्त्र के आधार' देखिये।

(३) शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जायेंगे। ये ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें माहित्य विज्ञान उला, सहकारी आन्दोलन या सामाजिक सेवा के विषया में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो।

/ उपर्युक्त उपखण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन निर्वाचित होने वाले इससे ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुने जायेंगे जैसे कि सदन कानून बना कर तय करे। परिषद के सब सदस्यों का चुनाव अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एक परिवर्तनीय विधि द्वारा होगा।

विभिन्न राज्या के विधान परिषदा की महत्ता निम्नोक्त होगी।

विहार	७२	मंसूर	५२
बम्बई	८२	पंजाब	६०
मध्य प्रदेश	७२	उत्तर प्रदेश	७२
मद्रास	४८	पश्चिमी बंगाल	५१

राज्य पुनर्गठन के पूर्व मंसूर तथा मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका नहीं थी।

कार्य काल :—विधान परिषद स्थायी संस्था है। इसका कभी भी विघटन नहीं होगा। हर दूसरे साल बाद एक तिहाई सदस्य नये चुने जायेंगे। पहले चुनाव पर एक-तिहाई २ वर्ष के लिये, एक तिहाई ४ वर्ष के लिये तथा एक तिहाई ६ वर्ष के लिये चुने जायेंगे। इसके बाद प्रत्येक का कार्यकाल ३ वर्ष होगा।

सदस्यों के लिए योग्यता — निम्नलिखित योग्यताएँ आवश्यक हैं —

(१) वह भारत का नागरिक हो।

(२) वह ३० वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

(३) Peoples' Representation Act, 1951 द्वारा यह निश्चित हुआ है कि विधान-परिषद के निर्वाचित सदस्य होने के लिये यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति उस राज्य की विधान-सभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक हो। मनोनीत-सदस्य होने के लिये उसे साधारणतः उस राज्य का निवासी होना चाहिये।

सदस्य होने के लिये निम्नलिखित अयोग्यताएँ नहीं होनी चाहिये —

(१) वह सब-सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण किये हुये हो। मन्त्रियों का पद ऐसा नहीं समझा जाता है।



(२) वह पागल न हो।

(२) वह उनमूक दिवालिया हो।

(३) वह भारत का नागरिक न हो।

(५) वे अयोग्यताएँ जो कि सगद् की सदस्यता के सम्बन्ध में Peoples Representation Act, 1951 में दी हुई हैं।

अगर कभी यह प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति सदस्यता के लिये अयोग्य तो नहीं है तो राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया कि वह निर्वाचन-आयोग की राय से इस बात का निर्णय करे और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

**सदस्यों के स्थानों की रिक्तता :—**कोई भी मनुष्य एक ही समय में किसी राज्य के विधान-मण्डल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है और न एक समय में एक ही व्यक्ति दो राज्यों के विधान-मण्डलों का सदस्य हो सकता है। उसे एक से इस्तीफा देना होगा।

अगर कोई सदस्य अपने सदन के अधिवेशन से बिना उसकी आज्ञा के ६० दिन तक लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। सदस्य अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकते हैं।

**गणपूर्ति :—**कुल सदस्य संख्या का दसवाँ हिस्सा या १० सदस्य जो अधिक हों वही विधान-परिषद् का कोरम होगा।

**पदाधिकारी :—**एक सभापति तथा एक उपसभापति होना। इनका निर्वाचन परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से ही किया जाएगा। सभापति को केवल निर्णायक मत देने का अधिकार है। नको वेटन तथा भत्ते मिलेंगे। इनका काम वैसा ही है जैसा कि राज्य-परिषद् के सभापति तथा उपसभापति का। विधान-परिषद् इनकी अपने पद से बहुमत-प्रस्ताव द्वारा हटा सकती है। परन्तु ऐसे प्रस्ताव के लिये १४ दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी।

**विधान सभा :—**यह राज्यों में व्यवस्थापिका का निचला सदन है। सविधान में धारा १७० में कहा गया है कि इसमें अधिक से अधिक ५०० तय कम से कम ६० सदस्य होंगे। इनका राज्य के निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। परन्तु इसके अतिरिक्त जैसा नीचे बतलाया जाएगा विधान-

सभा में मनानान सदस्य भी हा मर्न है । यह उपबन्ध ऍला इन्धिन समझाव क हिन में रखा गया है ।

/ निवाचन सत्रा का बनान समम इस बात का ध्यान रखा जायगा कि समस्त में प्रतिनिधिया तथा जनना में एक हा अनुपात हा । साधारण भाषा म जहाँ तक सम्भव होगा प्रत्येक निवाचन क्षेत्र में बराबर जनसंख्या रखा जायेगी । प्रत्येक मतगणना के पश्चात प्रतिनिधिव के सम्बन्ध में जो कुछ आवश्यक परिवर्तन करने हाने उनका राज्य का विधान मण्डल कानून द्वारा तय करेगा ।

प्रत्येक राज्य के विधान-सभा में अनुसूचित जातियों तथा जन जातिया क लिये उनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान सुरक्षित रखे गये हैं । ग्रामान की विधान सभा में कुछ स्थान वहाँ के स्वायत्त जिला (Autonomous districts) क लिये उनकी जनसंख्या क आधार पर सुरक्षित रखे गए हैं । शिक्षाग क नगरपालिका क्षेत्र तथा वॉटोनमण्ट क प्रतिरिक्त इन स्वायत्त जिा से कोई भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं चुना जायगा जो कि अनुसूचित जनजाति का न हो ।

एंग्लो इण्डियन समुदाय के लिय भी विशेष उपबन्ध हैं । अगर राज्यपाल समझे कि इस समुदाय का विधानसभा में समुचित प्रतिनिधित्व नहा हुआ है ता वह इस समुदाय के जितने ठीक समझे उनन सदस्य मनोनीत कर सकता है ।

अल्पमत के सम्बन्ध में म सब विशेष उपबन्ध सविधान लागू होने क दम धप पश्चात समाप्त हो जावेंगे । परन्तु ग्रामान के स्वायत्त जिला सम्बन्धा उपबन्ध स्थायी रूप म रहेंगे ।

विधानसभा क लिये प्रत्येक चुनाव होगा । प्रत्येक वयस्क का (जा २१ वष की आयु पूरी कर चुका हो) मत देने का अधिकार हाया पर उमम निम्नलिखित बातें हानी चाहिए — वह भारत का नागरिक हो, पागल न हा, राज्य में निदिचत अवधि से निवास कर रहा हो, किसी अपराध भादि १५, ५ मताधिकार म वचित न कर दिया गया हो ।

विधानसभा की सदस्यता के लिये योग्यताएँ — इसके लिए निम्न-लिखित योग्यताएँ हानी चाहिए —

(१) भारत का नागरिक हूँ, तथा, २५ वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूँ।

(२) संसद ने Peoples' Representation Act, 1951 द्वारा यह निश्चित किया है कि—

(घ) राज्य के अन्दर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित किसी स्थान से चुने जाने को वह इन जातियों या जनजातियों का सदस्य होना चाहिए तथा उस राज्य की विधान-सभा के किसी निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचक होना चाहिए।

(ग) आसाम के स्वायत्त जिले के लिए सुरक्षित किसी स्थान के लिए (शिलोण की म्युनिसिपैलिटी तथा कैन्टोनमेन्ट के अतिरिक्त) चुने जाने को उसे उस जिले की किसी जनजाति का सदस्य होना चाहिए तथा ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचक होना चाहिये जिसमें कि उस जिले के लिये एक स्थान सुरक्षित हो।

(घ) किसी अन्य स्थान के लिए चुने जाने को उसे राज्य में किसी विधान-सभा के निर्वाचन-क्षेत्र (Assembly Constituency) में निर्वाचक (elector) होना चाहिए।

विधान-सभा के सदस्य पद के लिए वही अयोग्यताएँ हैं जो कि विधान परिषद् की सदस्यता के लिये। अगर अयोग्यता का प्रश्न उठा तो राज्यपाल निर्वाचन-आयोग की राय से उसको तय करेगा।

कार्यकाल.—विधान-सभा का कार्यकाल साधारणतः ५ वर्ष होगा। परन्तु इसके पूर्व भी यह राज्यपाल द्वारा भंग की जा सकती है। असाधारण काल में इसका कार्यकाल बढ़ सकता है। संकट की घोषणा होने पर संसद विधि द्वारा इसका कार्यकाल बढ़ा सकती है। परन्तु एक समय में केवल एक वर्ष के लिए ही होगा। संकटकाल के समाप्त होने के ६ महीने के अन्तर्गत ही इसका विघटन हो जायगा।

पदाधिकारी :—इसके दो पदाधिकारी होंगे—अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। इनको विधानसभा अपने ही सदस्यों में से चुनेगी। इनको पद से हटाया भी जा सकता है। इसके लिए वही प्रक्रिया है जो कि विधान-परिषद् के समानांतर अथवा उपसमापति को हटाने के लिए है। इसके बैसे ही अधिकार तथा कर्तव्य



हैं जैसे कि लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के। अध्यक्ष को केवल निर्णायक मत देने का अधिकार है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को वेतन तथा भत्ते मिलेंगे। विधान-मण्डल की मसुका बैठक में अध्यक्ष ही महापति का आसन ग्रहण करेंगे।

**गणिपूति** — विधानसभा का कोरम कम से कम १० तथा अधिक से अधिक कुल सदस्य सभा का दसवाँ हिस्सा, या इन दोनों में से जो अधिक हो वह रखा गया है।

**राज्यों में विधान सभाओं की सदस्य संख्या** — समझ ने विधि द्वारा विभिन्न राज्यों की विधान-सभाओं की सदस्य संख्या निश्चित कर दी है।

आंध्र	३०१	मद्रास	२०५
आसाम	१०८	मैसूर	२०८
बिहार	३३०	उड़ीसा	१४०
बम्बई	३०६	पंजाब	१५४
केरल	१०६	राजस्थान	१७६
मध्य प्रदेश	२८८	उत्तर प्रदेश	४३०
पश्चिमी बंगाल	२३८		

**विधान मंडलों के सदस्यों की उन्मुक्तियाँ तथा वेतन आदि** — विधान मंडल के सदस्यों को विधान के उद्भव तथा विधान-मंडल की प्रक्रिया के नियमों के अधीन रहते हुए वाक्-स्वातन्त्र्य का अधिकार दिया गया है। विधान-मंडल या उसकी समिति में कहीं हुई किसी बात या दिए हुए किसी मत के विषय में किसी सदस्य के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं चल सकेगी। विधान मंडल इन सब विषयों पर विधि बनायेगा। परन्तु जब तक इस विषय पर विधान-मंडल धातून बनाने है उनके तथा उनके सदस्यों की वही शक्तियाँ तथा उन्मुक्तियाँ रहेंगी जो कि इंग्लैंड में कामन्स सभा की हैं।

विधान-मंडल के सदस्यों की वेतन तथा भत्ते मिलेंगे। इनका निश्चय राज्य का विधान मंडल समय समय पर विधि द्वारा करेगा। जब तक इस विषय में विधि निर्माण नहीं होता है सदस्यों को वही वेतन तथा भत्ते मिलेंगे जैसा कि संवधान लागू होने के पूर्व प्रांतीय सभाओं के सदस्यों को मिलते थे।

विधान-मण्डल के प्रत्येक सदस्य को पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के सम्मुख एक शपथ लेनी होगी। बिना इस शपथ के लिए अगर वह मदन में बैठे तो वह दण्ड का भागी होगा।

**विधान-मंडल का अधिवेशन** — राज्यपाल समय-समय पर विधान-मंडल के सदस्यों या किसी भी सदस्य को, ऐसे स्थान और समय पर जैसा कि वह ठीक समझे बुलावेगा। परन्तु पहले अधिवेशन की आखिरी बैठक तथा नये अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच में ६ महीने से अधिक समय नहीं बीतना चाहिये। उनको यह भी अधिकार है कि वह किसी भी सदस्य या सदस्यों को स्थागित कर सकता है तथा विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल प्रत्येक नये चुनाव के पश्चात् प्रथम अधिवेशन में तथा प्रति वर्ष के प्रथम अधिवेशन में विधान-मण्डल के सदस्य अपना जहाँ दो सदस्य हैं, दोनों को चुन रूप से सम्बोधित करेगा और उनको बुलाने का वा कारण बतलावेगा। वह विधान-मण्डल को किसी बिल के सम्बन्ध में या किसी अन्य कारण में संदेश भेज सकता है। विधान-मण्डल इस संदेश पर यथाशीघ्र विचार करेगा।

विधान-मण्डल में प्रत्येक बात का निश्चय बहुमत द्वारा होगा। अगर किसी अवसर पर मत-साम्य हो जावे तो अध्यक्ष या समापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। किसी भी मशन की कार्यवाही तब तक नहीं हो सकती है जब तक गणपूर्ति न हो।

मन्त्रियों तथा महाधिवक्ता को सदस्यों की बैठक में भाग लेने का अधिकार है। परन्तु मंत्री मतदान केवल उसी सदस्य में कर सकेंगे जिसके वे सदस्य हैं। महाधिवक्ता को मत देने का अधिकार नहीं है।

विधान-मण्डलों में हिन्दी, अंग्रेजी तथा उस राज्य की भाषा का प्रयोग हो सकता है। १५ वर्ष पश्चात् अंग्रेजी का प्रयोग बन्द हो जावेगा। अगर कोई सदस्य इन तीनों में से कोई भी भाषा न जानता हो तो वह अध्यक्ष या समापति की आज्ञा से अपनी भाषा का प्रयोग कर सकता है।

विधान-मण्डल का प्रत्येक सदस्य, संविधान के उपबन्धों के अधीन, अपनी कार्यवाही के लिए नियम की रचना कर सकता है। जब तक ऐसे नियम नहीं बनाये जाते हैं वे ही नियम लागू होंगे जो कि संविधान के पूर्व थे।

प्रत्येक सदन का अपना मन्त्रिवालय होगा। इसके कमन्चाग्रियों की नियुक्ति सभा सेवा सम्बन्धी नियमों की रचना राज्य का विधान-मण्डल करेगा। परन्तु जब तक ऐसा नहीं होता है, राज्यपाल अध्यक्ष तथा सभापति में राय लेकर इनके लिये नियम बनावेगा।

**विधान-मण्डल के अधिकार** — इस विषय में इतना बताना पर्याप्त होगा कि इसका मुख्य काम राज्य सूची में तथा समवर्ती सूची में वर्णित विषयों के ऊपर कानून बनाना होगा। परन्तु समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर ससद् के बनाए हुए किसी कानून के विरुद्ध विधान-मण्डल कानून नहीं बना सकते हैं। विधि-निर्माण के अतिरिक्त दूसरे सामान-सम्बन्धी अधिकार हैं। यह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है। मन्त्रिपरिषद् विधान-सभा के प्रति उत्तरदायी है। इसके वित्त सम्बन्धी अधिकार हैं। राज्यों के क्षेत्र में विधान-मण्डल के वही अधिकार हैं जो कि संघ-क्षेत्र में ससद् के हैं।

**वैधानिक प्रक्रिया** — इसका भी संक्षेप में वर्णन किया जायगा। क्योंकि ससद् तथा विधान-मण्डलों की प्रक्रिया में कोई विशेष अंतर नहीं है।

(१) **साधारण विधेयक सम्बन्धी प्रक्रिया** — साधारण बिल जहाँ विधान-मण्डलों में दो सदन हैं किसी भी सदन में प्रारम्भ हो सकेगा। साधारणतः यह कानून तभी बनेगा जब कि यह दोनों सदनों द्वारा पारित हो जावे तथा इसका राज्यपाल की अनुमति मिल जावे। यदि कोई बिल विधान-सभा द्वारा पारित हो गया हो परन्तु विधान-परिषद् उसको अस्वीकार कर दे या परिषद् में ऐसे तीन मान में अधिक समय व्यतीत हो जाता है या परिषद् उसमें ऐसे संशोधन कर दे जा कि विधान सभा का स्वीकार नहीं है, तो वह बिल, विधान-सभा द्वारा दुबारा पास होकर फिर से परिषद् में भेजा जावेगा। अगर इस बार परिषद् उसको अस्वीकार कर दे, या एक माह तक न लीटावे या ऐसे संशोधन कर दे जा कि स्वीकार न हो तो बिल उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जावेगा जिसमें वह विधान द्वारा पारित किया गया था।

(२) **धन विधेयक की प्रक्रिया** — धन विधेयक केवल विधान-सभा में ही प्रारम्भ हो सकता है धन-विधेयक का अर्थ यहाँ पर भी वही है, जैसा कि ससद् के सम्बन्ध में बताया गया था। अगर केवल यही है कि वहाँ पर वे सब बातें सच सरकार से सम्बन्ध रखती थी, यहाँ पर राज्य सरकार से सम्बन्ध रहते हैं। इसलिए पुनः उन बातों को दोहराने से कोई लाभ नहीं। कोई

विधेयक धन-विधेयक है या नहीं इसका निर्णय विधान-मन्त्रालय का अधिकार होगा।

जब विधान सभा किसी धन-विधेयक को पास कर देती है तब वह विधान-परिषद् में भेजा जाता है। परिषद् उन विधेयक को चौरह दिन के भीतर अपनी सिफारिशों सहित विधान सभा को लौटा देगी। सभा को यह अधिकार है कि वह उन सिफारिशों को माने या न माने। अगर विधान-परिषद् उस विधेयक को १४ दिन के अन्दर वापिस नहीं करती है तो यह काल की समाप्ति पर दोनों सदनों द्वारा पास समझा जावेगा।

**राज्यपाल की अनुमति :—**अनेक विधेयक विधान-मण्डल में पास होने के बाद राज्यपाल की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जावेगा। राज्यपाल इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें कर सकता है—

(१) वह अपनी अनुमति दे दे।

(२) वह अपनी अनुमति न दे।

(३) धन-विधेयक के अतिरिक्त किसी अन्य बिल का वह अपनी सिफारिशों सहित विधान-मण्डल को वापिस भेज दे। अगर विधान-मण्डल इस बिल को उसकी सिफारिशों सहित वापिस भेजा इनके फिर पास कर दे तो राज्यपाल को अपनी अनुमति देनी पड़ेगी।

(४) राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के विचारार्थ रोक ले। सब विधेयक जो की संविधान द्वारा अर्पित राज्य के उच्चन्यायालय की शक्तियों को कम करते हैं, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए अवश्य रणित किये जावेंगे।

(५) इस प्रकार रणित किसी धन-विधेयक को राष्ट्रपति अपनी अनुमति दे या न दे। परन्तु अन्य विधेयकों को वह अपनी सिफारिशों सहित विधान-मण्डल के पुनर्विचारार्थ वापिस भेज देगा। विधान-मण्डल ६ महीने के अन्दर इस पर फिर विचार कर सकता है। अगर वह फिर से पास हो जावे तो उस दशा में राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने को बाध्य नहीं है।

**वित्तीय प्रक्रिया :—**विधान-मण्डलों की वित्तीय प्रक्रिया विष्णुल सदन की ही तरह है। अतएव उसका वर्णन नहीं किया जावेगा। जो काम वहाँ राष्ट्रपति करता है वह यहाँ राज्यपाल करेगा। जो कुछ वहाँ संघ सरकार के सम्बन्ध में कहा गया है वहाँ राज्य-सरकार से सम्बन्ध रहेगा।

## विधान-मण्डलों की विशेषताएँ

(१) जिन राज्यों में दो सदन हों वहाँ उपरी सदन अत्यन्त शक्तिहीन होगा। विधान सभा को महत्ता दी गई है। दोनों सदन में मतभेद होने पर प्रधान बैठक की व्यवस्था नहीं है। धन विधेयक पर उपरी सदन केवल १४ दिन की देर कर सकता है तथा अन्य विधेयक पर अधिक से अधिक ६ महीने की।

(२) विधान-मंडल में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा अपने कक्ष में पालनाय किये हुए कार्यों के विषय में कोई भी बहस नहीं हो सकती है।

(३) विधान-मंडल राज्य सूची के अन्तर्गत सब विषयों पर कानून बना सकते हैं। ससद साधारणकाल में इन विषयों पर कानून नहीं बना सकती है। परन्तु इनमें से किसी विषय पर भी अगर राज्य परिषद् दो तिहाई बहुमत से पास कर दे तो ससद कानून बना सकती है। सबट-काल में तो ससद राज्य सूची में वर्णित सभी विषयों पर कानून बना सकती है।

(४) विधान-मंडल द्वारा यान्त्रिक विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति उनके कानून बनाने के लिए आवश्यक है। इनका वर्णन राष्ट्रपति के अधिकारों के सम्बन्ध में कर चुके हैं। कुछ विषयों पर विधान मंडल में कोई विधेयक तब तक पेश नहीं किया जा सकता है, जब तक कि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति न हो। इनका उल्लेख भी पहले कर दिया गया है।

## जम्मू काश्मीर की शासन व्यवस्था

अभी तक हम भारत सब के स्वायत्त राज्यों के शासन प्रबन्ध का वर्णन कर रहे थे। मविधान में कहा गया है कि ये उपबन्ध जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू नहीं होंगे। जम्मू तथा काश्मीर की भारत-संघ में अनेक कारणों से विशेष स्थिति रखी गई है। वहाँ का मविधान एक मविधान निर्माण सभा द्वारा बनाया गया है। इस सभा की स्थापना काश्मीर सरकार द्वारा की गई थी। जनवरी २६, सन १९५७ में यह मविधान काश्मीर में लागू हुआ है।

राज्य पुनर्गठन के पूर्व काश्मीर 'संघ' का राज्य था। हम बतला चुके हैं कि 'संघ' के राज्य भूतपूर्व देशी राज्यों से बने थे। इन्हें भी स्वायत्त-शासन का अधिकार प्राप्त था। साधारणतः यह कहा जा सकता है कि इनके



शासन-प्रबन्ध तथा 'क' वर्ग के राज्यों के शासन-प्रबन्ध में बहुत साधारण अन्तर था। 'न' वर्ग के राज्यों में कार्यशालिका का मान्यता सम्पादन न कहलाकर राजप्रमुख रहता था। इनको स्थिति वैधानिक प्रधान की स्थिति थी। इसको नलाह देने के लिये मन्त्रिमण्डल होता था। इसका निर्माण उसी प्रकार होता था तथा इनके कर्तव्य व अधिकार वही थे जो कि 'क' वर्ग के राज्यों में मन्त्रिमण्डल के होते थे। इन राज्यों में दिनाम-मण्डल भी होते थे। मैसूर के अतिरिक्त अन्य 'स' वर्ग के राज्यों में एक सदनान्तक विधान-मण्डल था। मैसूर के अतिरिक्त अन्य 'ख' वर्ग के राज्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रथम ग्राम चुनावों (१९५०) के पश्चात् कुछ कौंसिलरों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी। इन कौंसिलरों का काम इन राज्य-सरकारों की नीति सम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयों पर परामर्श देना था। इनके अतिरिक्त यदि राज्य-सरकारें चाहें तो अन्य किसी विषय पर भी इनकी राय उपलब्ध हो सकती थी।

उपर्युक्त 'स' वर्ग के राज्यों में जम्मू तथा काश्मीर का विशेष स्थान था। राज्य पुनर्गठन के पश्चात् भी जम्मू तथा काश्मीर का संघ के अन्तर्गत एक विशेष स्थान है। इस राज्य ने अक्टूबर, १९४७ को भारत संघ में प्रवेश किया। प्रवेशपत्र द्वारा संघ को इस राज्य द्वारा केवल तीन विषय—सुरक्षा, यातायात तथा वैदेशिक सम्बन्ध दिये गये थे। केवल इन्हीं विषयों पर संघ की विधि बनाने का अधिकार था। परन्तु प्रदेश पत्र में यह भी उल्लिखित था कि अन्य विषयों पर भी मध्य सरकार विधि बना सकती थी जिनको राष्ट्रपति राज्य-सरकार से परामर्श करके अपने आदेश में वर्णन कर दे। सन् १९५१ में एक संविधान सभा की काश्मीर में स्थापना हुई। इसने अन्ततः राजतन्त्र का अन्त कर दिया। परन्तु महाराज करणसिंह को ही राज्य का प्रधान चुना गया। इनको सदर-इ-रियासत कहा गया। भारत तथा जम्मू काश्मीर के मध्य एक समझौता हुआ और सन् १९५४ में काश्मीर की संविधान सभा द्वारा इनको मान लिया गया। सन् १९५४ में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा यह प्रस्तावीत हुआ। संविधान सभा ने काश्मीर के लिये संविधान का निर्माण किया जो, जैसा चलाया जा चुका है, २६ जनवरी १९५७ से लागू हो गया है। इसके अनुसार वहाँ के शासन की निम्नोक्त मध्य विशेषताएँ हैं

इन संविधान द्वारा यह धारणा की गई है कि जम्मू-काश्मीर भारत का अविच्छिन्न (integral) अंग है तथा सदा रहेगा। संविधान द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा

मवना है। मविधान का उद्देश्य एक समाजवादी समाज की स्थापना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि काश्मीर तथा भारत का एक ही उद्देश्य है।

यहाँ के मविधान की मशाघन व्यम्था र विषय में यह उपबन्ध है कि राज्य की विधान मभा में ही एमा प्रस्ताव पेश किया जायगा। जब विधान भा व दाना सदना में दा निहाई बटुमन म यह प्रस्ताव पारित हा जाय तो उगरे पक्षान यह सदर इन्वियामत की म्बीवृति क लिये भेजा जायगा और म्बीवृति मिये पर यह त्रिधि रा रूप बहण कर लेगा। परन्तु कुछ वाता पर जम्मू-काश्मीर की विधान मभा का सजावन बग्ने का अधिकार नहीं है। उदाहरणार्थ, काश्मीर भारत का मविच्छिन एम है तथा भारतीय मविधान के उन उपबन्धों का जो कि इस राज्य में भी लागू हानी हैं।

जम्मू-काश्मीर में मागदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। इस लिये वहाँ का शासन उत्तरदायित्वपूर्ण शासन है। कार्यपालिका का मुखिया सदर-इन्वियामत कहलाता है। यह पद निर्वाचित पद है। इसका निवाचित काश्मीर की विधानमभा द्वारा किया जाता है। संविधान म कहा गया है कि राज्य का मुखिया यह व्यक्ति होगा जिसे राष्ट्रपति राज्य विधान मभा की सिफारिश पर मान्यता प्रदान करेगा। सदर इन्वियामत का कार्य बाल ५ वर्ष सदा गया है। इस समय वहाँ युवराज वणमिह सदर इन्वियामत है। इसी नियुक्ति नवम्बर १९५० में हुई थी।

क्योंकि शासन का स्वल्प मागदीय है इसलिए वास्तविक कार्यपालिका मन्त्रिमण्डल है जो कि विधानमभा के प्रति उत्तरदायी है। इस समय काश्मीर में प्रथमी गुलाम मोहम्मद प्रधान मन्त्री है।

काश्मीर की व्यम्थापित्रा द्वि-मदनात्मक है। निश्चय मदन वमर मता धिदार द्वारा निवाचित हाता है। इसकी मदत मग्था १०० सदी गई है। परन्तु इसमें से २१ स्थान उन सदम्था के लिये रिक्त करे गये हैं जो कि काश्मीर के उन भाग का प्रतिनिधि र करेंग जिन पर अभी पाकिस्तान का मैनिश अधिकार है। मन्त्रिमण्डल का निमाण दूम निक्के मदर--विधान-मभा--में जिस दल का बहुमत हागा उगना नेता करेगा। उपरी मदन में ३६ स्थान है। इनकी निर्वाचन प्रत्येक नहीं हागा।

राज्य का अरना एर उच्च-मायाग्य है। परन्तु इस न्यायालय म मपीके भारत के सर्वोच्च न्यायालय म आयेंगो।

काश्मीर के नागरिक भारत के नागरिक हैं तथा उन ममस्त मूक अधिकारों का प्रयोग करने हैं जो कि भारत का संविधान द्वारा प्रदान किए गये हैं।

### संघीय क्षेत्रों का शासन-प्रबन्ध

उपयुक्त वर्णित स्वायत्त राज्यों के अतिरिक्त भारत मध्य में कुछ संघीय क्षेत्र भी हैं। दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, त्रिपुरा, मण्डमान तथा लक्षद्वीप द्वीप-समूह इस श्रेणी में आते हैं। ये संघीय क्षेत्र, जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट हो जाता है, स्वायत्त राज्य नहीं हैं और इनका शासन केन्द्र के अधीन है। इनकी वही स्थिति है जो कि राज्य पुनर्गठन के पूर्व 'अ' वर्ग के राज्यों की थी।

संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक संघीय क्षेत्र (Union territory) का प्रशासन राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त एक प्रशासक के द्वारा करेगा। (पारा २३९) राष्ट्रपति इस उद्देश्य से यदि चाहें तो किसी राज्य के राज्यपाल को किसी अभिकृत संघीय-क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। परन्तु राज्यपाल इस प्रशासन के लिए अपने मन्त्रिमण्डल से स्वतन्त्र रूप से काम करेगा।

इन संघीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में संसद् को व्यवस्थापन का पूर्ण अधिकार दिया गया है। परन्तु इसके अतिरिक्त संविधान में यह भी कहा गया है कि मण्डमान-निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप-समूह में शांति, उन्नति तथा अच्छे शासन के हित में राष्ट्रपति नियम (regulations) निर्माण कर सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा निमित्त नियम उस समय लागू हुए किसी विधि को अप्रभावी कर देगा।

इन संघीय क्षेत्रों के लिए उच्च-न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संविधान द्वारा संसद को प्रदान किया गया है।

राज्य पुनर्गठन के पूर्व दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा में एक विधान सभा थी तथा चीफ कमिशनर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को मंत्रणा देने के लिए एक मन्त्रिमण्डल होता था। परन्तु अब यह व्यवस्था हटा दी गई है। इनमें न विधान सभा है और न मन्त्रिमण्डल ही।

**क्षेत्रीय परिषद् :**—दिनांक १९५६ में संसद द्वारा एक ऐक्ट पारित किया गया जिसे The Territorial Council Act, 1956 कहते हैं। इस ऐक्ट के द्वारा हिमाचल प्रदेश, मनीपुर, तथा त्रिपुरा में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई है। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में एक क्षेत्रीय परिषद् (Territorial Council) होगी। इन क्षेत्रीय परिषदों में सदस्यों की वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। हिमाचल प्रदेश में ४१, तथा त्रिपुरा और मनीपुर प्रत्येक में ३० निर्वाचित सदस्य होंगे। मनीपुर

में १२ स्थान प्रत्यक्षित जानिया व ग्रिय मुगलिन रख गये हैं। उन निवाचिन सदस्यो व प्रतिरिक्त व द्रीय सरकार प्रत्येक परिषद में दो सदस्य मनानीत कर सकनी हैं। निवाचन व ग्रिय उन छात्रा का निवाचन भन्ना म विभवन किया जायगा। यह कार्य व द्रीय सरकार व धानानुसार किया जायगा।

प्रत्येक व्यक्ति जो कि वस्यक हा तथा Peoples Representation Act, 19५0 व अनुसार मन प्रान की योग्यता रखता है इन क्षेत्रीय परिषदो के सदस्यता व योग्य है यदि वह किसी क्षेत्रीय परिषद के लिए निवाचन है।

प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद म एक अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होगा जिसका इत परिषद द्वारा निवाचन किया जायगा। इन अधिकारियो का क्षेत्रीय परिषद एक निश्चित मन मस्या द्वारा अपने पदा म हटा भी सकनी है।

इस एक द्वारा क्षेत्रीय-परिषदा व निम्नलिखित मुख्य कृत्य हैं

(१) एसी व तथा अचर सम्पत्ति और मस्याका का प्रबन्ध तथा रक्षा जो कि इस परिषद का हस्तान्तरित कर दिय जाय,

(२) उन मद्रका पूरा भवना तथा तालावा का निमाण रक्षा तथा सम्पूर्णकार ना इस हस्तान्तरित कर दिय जाय

(३) छात्रा का राशन तथा रक्षा

(४) प्राथमिक तथा माध्यमिक गिनालया का प्रबन्ध इनसे भवना का निर्माण तथा जणोद्वार तथा गिनालया की दृनिग यादि।

(५) औषवाच्य तथा अस्पताला की स्थापना तथा प्रबन्ध,

(६) बाजारा तथा मला की स्थापना और इसका प्रबन्ध,

(७) मराया तथा संगम मालिका पर नियन्त्रण,

(८) अल का प्रबन्ध

(९) भूमि मरधान,

(१०) जानवरों का रक्षा तथा उनका इलाज का प्रबन्ध

(११) पशुना की अत्याचार से रक्षा,

(१२) जन-स्वास्थ्य तथा सफाई

(१३) पचायत की दख रेख तथा उन पर नियन्त्रण

(१४) तथा कोई अन्य अथ विषय जो कि व द्रीय सरकार इस परिषद को हस्तान्तरित कर द।

उपयुक्त सूची को देखने से यह स्पष्ट है कि इन क्षेत्रीय परिषदों के अधिकार उस प्रकार के हैं जैसा कि सामान्यतः स्थानीय संस्थाओं (म्युनिसिपैलिटी या ट्रिब्युट बोर्ड्स) को दिए जाते हैं। इन विषयों में भी ये परिषदें प्रशासक के नियन्त्रण में काम करेंगी। केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार है कि वह यदि चाहे तो इन क्षेत्रीय परिषदों से समस्त अधिकार ले सकती है।

दिल्ली में एक निगम (Corporation) की स्थापना की गई है जो कि यहाँ के स्थानीय विषयों का प्रबन्ध करेगा। मन्डमान तथा लक्कादीव द्वीप समूह का शासन प्रशासक के द्वारा ही किया जाएगा।

### प्रश्न

(१) नये संविधान के अनुसार राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन कीजिए।  
(यू० पी० १९५१)

(२) नये संविधान के अनुसार राज्य की विधान सभा का निर्माण कैसे होता है? उसकी शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का वर्णन कीजिए।

(यू० पी० १९५२)

(३) उत्तर प्रदेश की विधान सभा और विधान परिषद् के संगठन और पारस्परिक सम्बन्धों का वर्णन कीजिए।  
(यू० पी० १९५४)

(४) उत्तर प्रदेश की सरकार में राज्यपाल का क्या स्थान है?

(५) उत्तर प्रदेश की विधान सभा के निर्वाचन प्रणाली का वर्णन कीजिए।  
(यू० पी० १९५५)

(६) उत्तर प्रदेश की व्यवस्थापिका सभा में कानून बनाने की क्या विधि है। समझाकर उदाहरण द्वारा बतलाइए।  
(यू० पी० १९५६)

(७) उत्तर प्रदेश में द्वि-भवन विधान मण्डल की व्यवस्था क्यों की गई है? इनके पारस्परिक सम्बन्धों का वर्णन कीजिए। यदि प्रदेश दूसरे भवन को तोड़ना चाहे तो यह किस प्रकार सम्भव है।  
(यू० पी० १९५७)

(८) उत्तर प्रदेश के राज्य शासन में राज्यपाल का क्या स्थान है। उसकी शक्तियों का उल्लेख कीजिए।  
(यू० पी० १९५८)

(९) उत्तर प्रदेश के विधान मण्डल के अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन कीजिए।  
(यू० पी० १९५९)

## न्यायपालिका

प्रत्येक सविधान में एक सशक्त न्यायपालिका का होना आवश्यक है । इसका काम व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है । अगर इन अधिकारों की रक्षा नहीं की जावेगी तो व्यक्तित्व का विकास सम्भव नहीं है क्योंकि अधिकारों से तात्पर्य ही व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक दशाओं में है । लार्ड ब्राह्मन एक स्थान पर कहता कि किसी सरकार की उत्तमता का सर्वोत्कृष्ट बिन्दु अच्छा न्याय विभाग है । क्योंकि साधारण नागरिक के हित तथा सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसके साथ उचित न्याय भीय किया जावता ।

सब सरकारें तो न्यायपालिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हैं । इसका काम सविधान की रक्षा करना हो जाना है । इसलिए इसका 'सविधान का संरक्षक' कहा जाता है । इसका काम यह देखना है कि व्यवस्थापिका कोई ऐसा कानून न बनाय जो कि सविधान के विरुद्ध हो इसलिए यह सविधान की रक्षा करती है । अगर कोई कानून इसके अनुसार सविधान के विरुद्ध हो तो यह अवैध घोषित कर दिया जाता है । इसके साथ ही साथ यह इस बात की भी देखती है कि सब सरकार तथा राज्यों की सरकारें अपने अपने क्षेत्र के बाहर नहीं जाती हैं । अगर सब सरकार तथा राज्यों की सरकारों में प्रत्येक राज्यों में प्रत्येक में कोई झगडा होता है तो उक्त नियम न्यायपालिका ही करती है ।

साधारणतः सशक्त सविधान में दो न्यायपालिकाएँ होती हैं—सब की तथा राज्यों की । अमेरिका में ऐसा ही है और वहाँ वे एक दूसरे में पूरक हैं । परन्तु भारत में ऐसा नहीं किया गया है । अंग्रेजी सामन काल में समस्त देश के लिए एक ही सुप्रीम न्यायपालिका का प्रबन्ध था । नये सविधान में भी ऐसा ही रखा गया है इसका कारण यह बतलाया गया है कि कानून तथा उसके शासन में समस्त देश में कोई विभिन्नता न रहे । भारत का सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय कहलाता है । राज्यों में उच्च न्यायालय हैं । परन्तु ये सब सब सरकार के अधीन हैं ।

उच्चतम न्यायालय — स्वतन्त्रता के पूर्व भारत के फैसलों की अन्तिम अपील इंग्लैंड के प्रिंसी कौन्सिल में होती थी। परन्तु अब उच्चतम न्यायालय ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। मविधान में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति तथा जब तक समझ विधि द्वारा इस संख्या को नहीं बढ़ाती अधिक से अधिक पात अन्य न्यायाधीश होंगे। परन्तु अब संसद द्वारा यह संख्या १० कर दी गई है। इन न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को है। मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों की सलाह लेगा, जिनसे राय लेना वह आवश्यक समझे। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में, इनके प्रतिरिक्त मुख्य न्यायाधिपति में गलाह लेना आवश्यक है।

इनके पलावा इस बात का प्रबन्ध किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर मुख्य न्यायाधिपति राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, तदर्थ न्यायाधीशों (ad hoc judges) को कुछ समय के लिये नियुक्त कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय तथा मविधान लागू होने के पूर्व के सपीय-न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की जा सकती है।

योग्यताएँ — सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिये यह आवश्यक है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, किसी राज्य के उच्च न्यायालय में कम से कम लगातार ५ वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या किसी उच्च न्यायालय में कम से कम लगातार दस वर्ष तक अधिवक्ता (advocate) रह चुका हो, या राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता (jurist) हो। प्रत्येक न्यायाधीश को ६५ वर्ष की आयु पूरी करने पर पद से अवकाश ग्रहण करना पड़ेगा।

वेतन :— मुख्य न्यायाधिपति को ५००० रुपया मासिक तथा अन्य न्यायाधीशों को ४००० रुपया मासिक वेतन मिलेगा। इसके प्रतिरिक्त उन्हें रहने के लिए बिना किराये का मकान तथा अन्य भत्ते मिलेंगे।

शपथ :— प्रत्येक न्यायाधीश पद-ग्रहण से पूर्व राष्ट्रपति के सम्मुख पद की शपथ लेगा कि वह मविधान के प्रति निष्ठा रखेगा तथा निष्पक्ष रूप से बिना भय या द्वेष के न्याय करेगा।

स्वतन्त्रता :— न्यायपालिका के लिये यह आवश्यक है कि वह स्वतन्त्र हो नही तो सच्चा न्याय असम्भव है। इस उद्देश्य से मविधान में कई उपबन्ध रखे गए हैं।

(अ) समद या किसी राज्य के विधान-मण्डल में उच्चतम न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा अपने वक्तव्य-ालाप्य किये गये किसी कार्य पर विचार नहीं हो सकता ।

(ब) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन तथा भत्ते आदि उनके बर्खास्त होने से घटाए नहीं जा सकते हैं । यह न्याय भारत की सचिव निधि में से दिया जावेगा । अतएव समद इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है ।

(स) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपनी पदावधि के पूर्व केवल दो पदों में हट सकते हैं । या तो त्यागपत्र दे दें या समद के दोनों सदन पृथक्-पृथक् या एक ही अधिवेशन में, अपने समस्त सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा राष्ट्रपति से यह प्रार्थना करें कि कोई न्यायाधीश अयोग्यता भ्रष्टाचार (misbehaviour) के कारण अपने पद से हटा दिया जाव ।

(द) अपने कर्मचारियों को नियुक्त करने तथा कार्य सम्बन्धी नियमों को बनाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को दिया गया है । मुख्य न्यायाधिपति ११ उसकी आज्ञा में कोई अन्य पदाधिकारी उस न्यायालय के कर्मचारियों को नियुक्त करेगा । परन्तु राष्ट्रपति यह नियम बना सकता है कि कोई व्यक्ति जो के पहले उच्चतम न्यायालय से लगा न हो बिना सचीव सेवा आयोग की राय के नियुक्त न किया जावे । कर्मचारियों की सेवा की शर्तें भी न्यायालय स्वयं तय करेगा । परन्तु बनाने छूटी भत्ते तथा पन्थान के नियमों के लिए राष्ट्रपति अनुमोदन चाहिये । उच्चतम न्यायालय को समद द्वारा बनाये हुए कानूना अधीन तथा राष्ट्रपति के अनुमोदन में अपने कार्यप्रणाली तथा प्रक्रिया सम्बन्धी नियम बनाने का अधिकार है । जैसे अपने कर्मचारियों के बारे में, या नवीतों चुनने के लिए प्रक्रिया के बारे में, या किसी मूल अधिकार को पूर्ण करने के लिये उस न्यायालय में कार्यवाही के बारे में या उस न्यायालय में कार्यवाही में सम्बन्धित गवर्नर या फीम के बारे में तथा इसी प्रकार के अन्य विषयों पर नियम बनाने का अधिकार है ।

(ध) भवनाश ग्रहण करने के पश्चात् भी न्यायाधीशों को किसी भी न्यायालय में बर्खास्त करने का अधिकार नहीं दिया गया है ।

(१) स्थान — उच्चतम न्यायालय दिल्ली में भवना ऐसे अन्य स्थान या स्थानों, जिन्हें भारत की मुख्य न्यायाधिपति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर निश्चित करे, बैठेगा ।



**अभिलेख न्यायालय** — उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। इसलिए इसे अपने प्रपमान (contempt) के लिए दण्ड देने की सब शक्तियाँ होंगी। अभिलेख न्यायालय (Court of Record) ने यह तात्पर्य है कि उनकी सब कार्यवाही तथा कृत्य प्रामाणिक माने जाते हैं और उसे प्रपमान के लिए दण्ड देने का अधिकार होता है।

**अधिकार** — संविधान द्वारा इसको निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं।

( १ ) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) :— प्रत्येक संघीय-संविधान में संघ तथा इसके राज्यों के बीच अधिकार विभाजन होता है। इनमें से प्रत्येक का क्षेत्र निश्चित है। परन्तु इन दोनों में आपस में अपने-अपने क्षेत्र विस्तार के सम्बन्ध में विवाद उठ सकते हैं। ऐसे अवसर पर यह आवश्यक हो जाता है कि कोई ऐसी मत्ता हो जो कि ऐसे विवादों का निर्णय करे। संघ सरकार में यह मत्ता न्यायपालिका होती है।

भारतीय संविधान में संघीय-न्यायालय का निम्नलिखित विवादों पर उक्त सीमा तक प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार होगा जहाँ तक उनका सम्बन्ध किसी वैध अधिकार से :—

( ५ ) भारत सरकार तथा किसी राज्य या राज्यों के बीच।

( ७ ) एक ओर भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्य और दूसरी ओर किसी राज्य या राज्यों के बीच।

परन्तु उच्चतम न्यायालय के प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार को संविधान की धारा १३१ के द्वारा कुछ सीमित किया गया है। उदाहरणार्थ इन क्षेत्राधिकार के अन्दर कोई ऐसा विवाद सम्मिलित नहीं होगा जो संविधान लागू होने के पूर्व की गई किसी संधि या समझौते के कारण उत्पन्न हुआ हो तथा वह संधि या समझौता संविधान लागू होने के बाद भी मान्य हो। इसी प्रकार यदि किसी राज्य के साथ यदि इस प्रकार की संधि हुई हो जिसके अनुसार किसी प्रकार का विवाद-विशेष उच्चतम न्यायालय के सम्मुख नहीं प्रस्तुत किया जाएगा, तो वह भी इसका क्षेत्राधिकार के बाहर हो जाएगा। इसके अतिरिक्त वित्त आपाग में संबंधित बातें (धारा २८०), राज्यों के मध्य जलपूर्ति सम्बन्धी मामले (inter state water supply), नागरिकों के बीच विवाद, राजदूत सम्बन्धी मामलों आदि भी इस क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

(२) मूल अधिकारों का मरना — उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का मरना है। मविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह इन अधिकारों के साथ उच्चतम न्यायालय के समक्ष जा सकता है। इस उद्देश्य का पूर्ति के लिये हम न्यायालय का विनाश करना केवल निवारण का अधिकार है जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार अन्य न्यायालयों का निषेधा का दुहरा करना है।

(३) अपील की श्रेणी — स्वाधीनता के पूर्व भारत के मूल न्यायालय में अपील इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल में होती थी। अतएव यह कौंसिल ही सर्वोच्च अपील का न्यायालय थी। परन्तु मिनस्टर १९४९ से भारत का सर्वोच्च अपील न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय बना रहा। इस उच्चतम न्यायालय ही सर्वोच्च न्यायालय है। इसके निषेध के विरुद्ध विनाश अन्य न्यायालय में अपील नहीं हो सकती है। परन्तु यह स्वयं अपने आदेशों तथा निषेधा का पुनर्विलोकन कर सकता है। उच्चतम न्यायालय में मापारणत उच्च न्यायालयों के निषेधा के विरुद्ध अपील होती है परन्तु इसका यह अधिकार है कि यह मौखिक न्यायालयों के अतिरिक्त भारत में अन्य किसी न्यायालय के निषेध के विरुद्ध अपील की शक्ति दे दे।

(४) उच्चतम न्यायालय में मविधानिक, अग्रहण-सम्बन्धी तथा दण्ड सम्बन्धी (Constitutional Civil and Criminal) विवादों को अपील हो सकता है। मविधानिक विवादों को अपील इस न्यायालय में तभी जानी जा सकती जब कि किसी राज्य का उच्च न्यायालय या प्रमाण दे कि इस विवाद में मविधान-सम्बन्धी कोई प्रश्न निहित है। अगर उच्च न्यायालय इस प्रकार का प्रमाणपत्र न दे तो उच्चतम न्यायालय स्वयं ही ऐसा प्रमाणपत्र दे सकता है।

अग्रहण-सम्बन्धी विवादों में उच्च न्यायालय के निषेध के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील तभी हो सकती है जब कि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित करे कि वाद विषय की गति या मूल्य बीम अग्रहण-सम्बन्धी है या नहीं। यह मामला उच्चतम न्यायालय में अपील के योग्य है।

दण्ड सम्बन्धी मामलों में उच्च न्यायालय के निषेध के विरुद्ध तब अपील हो सकती है यदि उच्च न्यायालय ने अपील में निषेध न्यायालय द्वारा मुक्त किया हुआ किसी अभियुक्त का मृत्यु-दण्ड दिया हो या निषेध न्यायालय में किसी मामले का अपने परीक्षण के लिए मसाले अभियुक्त का मृत्यु-दण्ड दिया हो, या उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने लायक है।

(४) राष्ट्रपति को परामर्श देना — राष्ट्रपति किसी विधि या तथ्य सम्बन्धी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न को उच्च न्यायालय के विचार के लिए नीप सकता है। उच्चतम न्यायालय ऐसे अवसरों पर उचित मुनवाई के बाद अपनी राय देगा। अभी राष्ट्रपति द्वारा केरल सरकार द्वारा पारित शिक्षा-विधेयक उच्चतम न्यायालय को परामर्श के लिए भेजा गया था और न्यायालय ने उसपर अपनी राय दी। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति को अवश्य ही मानना पड़ेगा ऐसा संविधान में नहीं कहा गया है और न यही कहा गया है कि राष्ट्रपति इस विषय में स्वतंत्र है।

(५) पुनरावृत्ति का अधिकार :— उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार भी है कि अपने द्वारा दिए गए किसी निर्णय का पुनः अवलोकन कर सके तथा उसकी त्रुटिप्रां हटा दे।

उच्चतम न्यायालय के अधिकारों में सुसूक्ष्म विधि द्वारा वृद्धि कर सकती है। इस न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के मन्दिर सब न्यायालयों पर बंधनकारी होगी।

संविधान में उच्चतम न्यायालय का स्थान :— भारतीय उच्चतम न्यायालय देश की न्यायपालिका का उत्तमार्ग है। संविधान के द्वारा इसको विशेष अधिकार सम्पन्न इसलिए किया गया है कि जिससे यह देश में संविधानिक व्यवस्था में अपनी भूमिका ठीक प्रकार से निभा सके।

न्यायपालिका के मुखिया के रूप में इसका कार्य यह देखना है कि कानून ठीक प्रकार लागू किए जाते हैं तथा कोई भी नागरिक न्याय से वंचित नहीं किया जाता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था का यह आधारभूत सिद्धान्त है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिये न्याय सुलभ हो तथा सभी के लिए न्याय समान हो। इसलिए यदि किसी को यह विश्वास हो कि उसके साथ न्याय नहीं किया गया है वह उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। तथा यह उसे किसी भी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील करने की अनुमति दे सकता है। उच्चतम न्यायालय नागरिक के मूल अधिकारों का रक्षक है।

इसके विषय में एक विद्वान ने कहा था कि यह संसार के सब उच्चतम न्यायालयों में अधिक शक्तिशाली है। इसी प्रकार भारत के महान्यायाधीश श्री सीतल-

1. The Indian Supreme Court was described as having "more power than any other supreme court in any part of the world" —A. K. Aiyer.

वाद ने एए अवसर पर कहा था कि दमक अधिकार राष्ट्रमण्डल के किसी भी देश के उच्चतम न्यायालय अथवा अमेरिका के उच्चतम न्यायालय में अधिक है।<sup>1</sup> अमेरिका के उच्चतम न्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार भारतीय उच्चतम न्यायालय के अधिक विस्तृत है। परन्तु अपीलीय क्षेत्राधिकार भारतीय उच्चतम न्यायालय का अधिक विस्तृत है।

अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के सम्बन्ध में कहा जाता है कि यह देश की व्यवस्थापिका का तीसरा गढ़न हो गया है इसके अंगन न्यायिक पुनर्विगठन के अधिकार का इस प्रकार प्रयोग किया है कि दमकी तेजी स्थिति हो गई है। भारतीय उच्चतम न्यायालय को भी न्यायिक पुनर्विगठन का अधिकार है। यदि देश में पार्टी व्यवस्थापिका तेजी विधि का निमाण कर जा संविधान का उच्छेदन करती हो या पार्टी कायपालिका का गंगा आदेश द जो संविधान का प्रतिफल करती हो इन दोनों दंगला में उच्चतम न्यायालय इस विधि अथवा आदेश का अवैध घोषित कर देगा। परन्तु भारतीय उच्चतम न्यायालय का यह अधिकार प्रत्यक्ष रूप में संविधान द्वारा नहीं दिया गया है।

भारत का उच्चतम न्यायालय किसी कानून का दमन्य अवैध घोषित कर सकता है कि यह संविधान की धारा 32 का उच्छेदन करता है परन्तु वह इस कारण उसका अवैध नहीं घोषित कर सकता है कि बुरावाद (bad) कानून है। भारतीय उच्चतम न्यायालय के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह प्राथमिक तथा सामाजिक नीति के निर्धारण में व्यवस्थापिका के काम में रोक अटक करे। भारत में न्यायपालिका की स्थिति दूसरे उ तथा अमेरिका के बीच है। इस न्यायिक पुनर्विगठन का अधिकार है परन्तु यह अधिकार उसना व्यापक नहीं है जितना अमेरिका में। उच्चतम न्यायालय ने स्वयं अपने पर निर्णय में कहा है कि भारत में न्यायपालिका की यह भूमिका (role) नहीं हो सकती जो कि अमेरिका में है। भारत में अनन्ततापिका व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता है न कि न्यायपालिका की। समस्त संविधान में स्थापित के द्वारा न्यायपालिका की शक्ति का अप्रभावी कर सकता है।

---

1. It can firmly be said that the jurisdiction and powers of this court in their nature and extent are wider than those exercised by the highest court of any country in the Commonwealth or by the Supreme Court of the U.S.A."

## राज्यों की न्यायपालिका

**उच्च न्यायालय** —नाधारणतः सब राज्यों में दोहरी न्यायपालिका होती है—प्रथम तथा राज्यों की। परन्तु जैना इन पहले लिख चुके हैं भारतीय संविधान द्वारा दोहरी न्यायपालिका की स्थापना नहीं की गई है। इसका कारण यह कहा गया है कि नमम्ब देश में एक न्याय व्यवस्था होनी चाहिये।

नविधान द्वारा प्रस्तावित राज्यों के लिये एक उच्च न्यायालय का उपबन्ध किया गया है। केन्द्र द्वारा प्रस्तावित राज्यों के लिये उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार सन्द् को दिया गया है। जिन राज्यों में नवीन संविधान लागू होने के पूर्व उच्च न्यायालय थे, इन नविधान के लागू होने पर वहाँ के उच्च न्यायालय मान लिये गए हैं। प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अनिलय न्यायालय है और इसको ऐसे न्यायालय के सब अधिकार दिए गए हैं। प्रथम न्यायालय इसके फैसलों को प्रामाणिक मानेगे।

प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति तथा कुछ अन्य न्यायाधीश होंगे। प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायाधीशों की अधिक से अधिक किन्तु नौ संख्या हो, इनको राष्ट्रपति आदेश द्वारा समय-समय पर नियत करेगा। इसलिए विभिन्न राज्यों में संख्या अलग-अलग होगी।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिये निम्नलिखित योग्यताएँ होनी चाहिए।

- (१) भारत का नागरिक होना,
- (२) भारत राज्य क्षेत्र के अन्दर कम से कम दस वर्षों तक कोई न्यायिक पद (Judicial Office) धारण किया होना,
- (३) भारत के किसी उच्च न्यायालय में कम से कम दस वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति तथा राज्य के राज्यपाल अथवा राजप्रमुख के परामर्श से करता है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधिपति तथा राज्य के मुख्य न्यायाधिपति की राय से करता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति उनकी बानूनी योग्यता तथा चरित्र आदि पर ध्यान रखता है। प्रत्येक न्यायाधीश ६० वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है।

गया व मुख्य न्यायविपत्ति का ८००० रुपया मासिक तथा ग्राम न्यायाधीश को २५०० रुपया मासिक वनतमिन्ता ह। अरुणाग्रण करन व पचात् नको पानन भी मिन्ता। गणप न भागन कमन्ता न्यायविपत्तिन पानन कर निमी न्यायाधीश का एक उत्र न्यायाध्य न म्पर उ व न्यायाध्य म म्पानान न्न कर नरन्ता न। प्रियर न्यायाधीश पन् ग्रन्थ म पूव रा यगा न म्पानन पद की नदय न्ता न।

न्यायाधीश अरु बा न्ता यन पन् म म्पाना न मरन्ता ह। अरु ममद क न्ता म्पान अरु ममम म्पाना क वन्तन म न्ता उरन्तिन म्पाना के दा निन्ता वन्तन न निमी न्यायाधीश क विन्त अरुपाना अरु वन्तन का अरुप वरन्ता राप्प न म उम हान की प्रायना करन ह ना गण्डपनि म्पान पन् म हन्ता मरन्ता न।

न्यायका प्रन्थ विपत्ति न्याय न वि न्यायाधीश स्वन्तन म्पाना कारण न्यायाधीश का पन् म हान न निन्ता म्पान विपत्ति अरुपाना का म्पान ह। उनक यन न्याय म्पान म विपत्ति म्पाना वार्ड म्पाना कर म्पाना न उनक म्पान न म्पाना न्यायविपत्ति म्पाना म्पाना म्पाना न। गया व विपत्ति म्पाना द्वारा पान का की विन्ता निन्ता निन्ता न्यायाध्य न अरुपाना पन् उरन्ता म्पाना न्याय न्याय राप्प न ना स्त्रीपुनि क वानन न्ता ह मरन्ता ह। पन् म अरुपाना ग्रहण करन क बा न्ता विपत्ति न्यायाध्य म वरन्तिन न्याय कर मरन्ता न।

न्यायधिकार — उरन्ता न्यायाध्य क अधिकार उरन्ता म्पानन पन्तिनना क अरुपाना म्पान न्याय न्याय म्पानन न्याय हान क पूव य। उरन्ता न्यायाध्य क अरुपाना का विन्तन ह। वरन्ता क अरुपाना न्याय न्याय पाननाना दाना प्रकार क म्पाना म्पाना की म्पान क्की अरुपाना ह। म्पानन न्याय हान क पूव पन्तिनता वार्ड न्याय म्पान क उ व न्यायाध्य क पान प्रारम्भिक न्याय अरुपाना दाना प्रकार क अधिकार य। वरन्ता म्पान म्पानन म्पान म्पान दा हान रुपय म्पान हाना या इनम अरुपाना कर मरन्ता व वरन्ता पाननाना क म्पान म्पान न्याय म्पाना द्वारा म्पान न्याय अरुपाना ह मरन्ता य। अरु उ व न्यायाध्य का प्रारम्भिक अधिकार न्याय य। वरन्ता अरुपाना न्यायाध्य य। न्याय विपत्तिन द्वारा इम अरुपाना म्पान पन्तिनन न्याय निन्ता गया ह। पन् नु इमक द्वारा उ व न्यायाध्य क अधिकार अरु म्पान वरन्ता ह। एक ना यह निन्ता अरु म्पान न्याय म्पाना म्पाना म्पाना म्पाना उ व न्यायाध्य क प्रारम्भिक अरुपाना क अरुपाना अ म्पान ह। म्पाना न्याय म्पान

होने के पूर्व यह अधिकार नहीं था। दूसरे यह कि अब नवीन संविधान द्वारा प्रत्येक उच्च न्यायालय को लेख निकालने का अधिकार दे दिया गया है। इससे पूर्व केवल कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास के उच्च न्यायालयों का यह अधिकार था। अन्य उच्च न्यायालय केवल बन्दी प्रत्यक्षीकरण लेख ही निकाल सकते थे। परन्तु अब सब उच्च न्यायालयों को यह अधिकार प्रदान किया गया है। यह अधिकार इसलिए प्रदान किया गया है ताकि व्यक्तियों के मूल अधिकारों का उचित प्रकारसे संरक्षण हो सके। उच्च न्यायालय किसी कानून को अगर संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध हो अवैध घोषित कर सकता है।

प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने राज्य क्षेत्र के अन्दर सब अन्य न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों (Tribunals) पर निरीक्षण का अधिकार है। परन्तु सैनिक न्यायालय इसके निरीक्षण में नहीं रहेंगे। अपने अधीन न्यायालयों के ऊपर उच्च न्यायालय के नीचे लिखे अधिकार हैं:—(क) अधीन न्यायालयों से विवरणी (Call for returns) मांग सकता है। (ख) अधीन न्यायालयों की कार्यप्रणाली तथा कार्यवाहियों को निश्चित करने के लिये नियम बना सकता है। (ग) अधीन न्यायालय के अधिकारियों द्वारा रखी जानेवाली पुस्तकें, प्रविष्टियाँ तथा लेखाओं के रखने का ढंग निश्चित कर सकता है। (घ) अधीन न्यायालयों के सौदाग, क्लर्क, अन्य कर्मचारी तथा वकील आदि की पीठ निश्चित कर सकता है, (ङ) किसी मुकदमे को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेज सकता है।

**हस्तान्तरण का अधिकार**—यदि उच्च न्यायालय यह समझे कि किसी अधीन न्यायालय में कोई ऐसा मामला है जिसमें कि संविधान के निर्वाचन (Interpretation) सम्बन्धी कोई प्रश्न अन्तर्गत है तथा जिसका निर्धारित होना मामलों के निबटाने को आवश्यक है तो वह उस मुकदमे को अपने पास भेज लेगा। या तो वह उस मामले को स्वयं निपटा देगा या उस विशेष प्रश्न को निर्धारित कर भागने को फिर से निचले न्यायालय में भेज देगा। दूसरी दशा में निचला न्यायालय उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यवाही करेगा।

**उच्च न्यायालय के पदाधिकारी आदि**—उच्च न्यायालय के पदाधिकारियों तथा सेवाओं को नियुक्तियाँ मुख्य न्यायाधिवक्ता या उसकी आज्ञा से उस न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश करता है। परन्तु राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के लिये जो कि पहले से न्यायालय में नहीं लगा है यह नियम बना

सकता है कि वह लोक सेवा के आयोग के परामर्श बिना नियुक्त न हो। इन पदाधि-  
कारियों की सेवा की शर्तें राज्य के विधान भण्डाल द्वारा इस सम्बन्ध में बनायी  
हुए कानूनों के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायाधीशपति द्वारा निश्चित की जाती  
हैं। वेतन भत्ता तथा छुट्टी आदि में सम्बन्धित नियमों के लिये राज्यपाल  
को अनुमोदन चाहिये। वेतन आदि का यह राज्य की सचिव निधि पर भारित  
है।

समझ लो यह अधिकार हैं कि वह उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का क्या  
सबनी है या उनके अधिकार को कम कर सकनी हैं।

राज्यों में अधीन न्यायालय — उच्च न्यायालय के अधीन जिन में कई  
न्यायालय होते हैं। फौजदारी तथा दोबानी के अलग अलग न्यायालय होते हैं।  
इनके अतिरिक्त माल की अदालतें (राजस्व न्यायालय) भी होती हैं।

दण्ड न्यायालय — जिले में सबसे बड़ा दण्ड न्यायालय सेशन कोर्ट कह-  
लाता है। इसके न्यायाधीश को सेशन जज कहते हैं। सेशन जज की महायतार्थ  
सहायकारी सेशन जज भी होते हैं। इन न्यायालयों में जज मुकदमों का निणय  
जुरी या असेसरो की सहायता में करते हैं। इन न्यायालयों के अधिकार फौज-  
दारी मामलों में उच्च न्यायालय के समान ही हैं। परन्तु इसके द्वारा दिए हुए  
न्यायदण्ड के लिए उच्च न्यायालय का अनुमोदन आवश्यक है। इसके अधिकार  
प्रारम्भिक तथा अपीलिय दोनों प्रकार के हैं।

सेशन जज के अधीन तीन श्रेणी के मजिस्ट्रेट होते हैं। प्रथम श्रेणी के  
मजिस्ट्रेट का २ वर्ष की सजा तथा १००० रुपया तक जुर्माना करने का अधि-  
कार है। द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट का ६ माह की सजा तथा ३०० रुपया तक  
जुर्माना करने का अधिकार है। तृतीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट १ माह की सजा तथा  
५० रुपया जुर्माना कर सकता है। मजिस्ट्रेट वैतनिक तथा अवेतनिक दोनों  
प्रकार के होते हैं। अवेतनिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्य की सरकार करती  
है। इनके पास साधारण मुकदमों हो जाते हैं।

वैतनिक मजिस्ट्रेटों में जिलाधीश (District Magistrate) का प्रथम  
श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकार होते हैं। इसके नीचे डिप्टी कलेक्टर तथा तह-  
सिलदार और नायब तहसिलदार की कचहरियाँ होती हैं। प्रेसीडेन्सी शहरों  
में प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट होते हैं। बड़े शहरों में मिटी मजिस्ट्रेट भी होते हैं।  
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कचहरी में उसके आतहत कचहरियों के निगमों की



अपील हो सकती है। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध सेशन जज की अदालत में तथा इसके निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील हो सकती है।

यानी तक जिला अधिकारियों के पान कार्याचारिणी और न्यायाधिकारी दोनों प्रकार के अधिकार समुचित रूप में हैं। परन्तु नागरिक की स्वतंत्रता के हित में यह कहा जाता है कि इनका पुनर्करण होना चाहिये। इन उद्देश्य में कुछ राज्यों ने पहला कदम उठाया है।

**व्यवहार न्यायालय :—**जिले में दीवानी की सबसे बड़ी अदालत जिला न्यायाधीश की अदालत होती है। साधारणतः एक ही व्यक्ति सेशन जज तथा जिला न्यायाधीश दोनों पद धारण किए रहता है। जिला न्यायाधीश को दीवानी मामलों में प्रारम्भिक तथा अपीलीय दोनों प्रकार के अधिकार हैं। इसमें केवल उन मुकदमों को अपील हो सकती है जिनका मूल्य ५०००) से कम होता है। इसके अधिक मूल्य के मुकदमों से उच्च न्यायालय में अपील किये जाते हैं।

जिला न्यायाधीश के मातहत अन्य अदालतें होती हैं जिनके ऊपर उसको निरीक्षण का अधिकार है। सिविल जज जिला न्यायाधीश के मातहत है। उसको लगभग वही अधिकार प्राप्त हैं जो कि जिला न्यायाधीश को। इसके नीचे मुन्सिफ की अदालत होती है। मुन्सिफ को साधारणतः २०००) मूल्य तक के मुकदमों और विशेष अधिकार दिए जाने पर ५०००) मूल्य तक मुकदमों का अधिकार रहता है। परन्तु इनको अपीलीय अधिकार नहीं हैं बड़े जिलों में इनके अतिरिक्त स्पेशल-कांज-कोर्ट (सफोफा अदालत) भी हैं। इनमें साधारणतः ५००) और विशेष अवसरों पर १०००) मूल्य तक के मुकदमों मुने जाते हैं। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में ये अदालतें २०००) मूल्य तक के मुकदमों मुन सकती हैं। इनके निर्णय की अपील नहीं होती है।

**जिला न्यायाधीश आदि की नियुक्ति :—**अधिवान में यह कहा गया है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद-स्थापना तथा पदोन्नति उस राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करके राज्यपाल या राजप्रमुख करेगा। कोई व्यक्ति जो संघ की या राज्य की सेवा में पहिले से नहीं लगा है, तभी जिला-न्यायाधीश हो सकता है जब कि वह कम से कम सात वर्षों तक अधिवक्ता या वकील रहे चुका है तथा उनकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की है। जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य पदों पर नियुक्ति के लिये राज्य-

पाल उस राज्य के लोकसेवा आयोग तथा उच्च न्यायालय में परामर्श करेगा। राज्य के अन्तर्गत सब अधीन न्यायालयों तथा उनके कम-पारियों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण तथा निर्गमन का अधिकार है।

**माल की अदालत** — राज्य में माल की सबसे बड़ी अदालत पाठ अर्थ रखे हुए है। इनके नीचे कमिश्नर की अदालत होती है। जिसे माल की सबसे बड़ी अदालत सिला मजिस्ट्रेट की होती है। इनके नीचे डिप्टी कमिश्नर तथा तहसीलदार की अदालतें हैं। इन अदालतों में मालगुजारी सम्बन्धी मामले सुने जाते हैं।

**न्याय-पंचायत** — जिन सूबों में पंचायत प्रथा स्थापित की गई है वहाँ पंचायती अदालतें भी हैं। इन अदालतों के सदस्यों का चुनाव गाँव की पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है गाँव के माधुरी मुख्तार—दीबानी तथा पीन-दारी—की मुनबार्द इन अदालतों में होती हैं।

### प्रश्न

उत्तम न्यायालय के कर्तव्य तथा अधिकारों का वर्णन कीजिये। इन न्यायालयों का भारतीय नविवान में क्या विशेष महत्व है? (यू० पी० १९५३)

(२) सही राज्य में न्यायपालिका का क्या महत्व है? भारत में न्याय-पालिका वहाँ तक इन कृतियों का पूरा करती है?

(३) उच्च न्यायालयों के मगटन तथा अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिये।

(४) जिन में न्याय का प्रवर्ग किन प्रकार होता है? समस्त कर लिखिये।

(५) भारत के उच्चतम न्यायालय के मगटन तथा अधिकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिये। (यू० पी० १९५६)

(६) हमारे नविवान में उच्चतम न्यायालय का क्या स्थान है? उसके अधिकारों का वर्णन कीजिये। (यू० पी० १९५७)

## जिले का शासन-प्रबन्ध

**जिलाधीश.**—प्रत्येक राज्य कई जिलों में बाँटा गया है; हमारे उत्तर प्रदेश में ५१ जिले हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सब जिलों में भाषाही बराबर हों या उनका क्षेत्रफल बराबर हों। कुछ जिले छोटे तथा कुछ बड़े हैं। इन्हीं प्रकार भाषाही की दृष्टि से भी उनमें काफी भिन्नता है। आर्थिक दृष्टि से भी उनमें असमानता है। परन्तु प्रत्येक जिले में शासन-बन्ध एक सा ही होता है। हर जिले में सरकार के कई विभाग होते हैं, जैसे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, पब्लिक वर्क्स आदि। इनमें से प्रत्येक का जिले में एक प्रधान होता है। जिले में सबसे मुख्य अधिकारी जिलाधीश कहलाता है। वह जिले में सरकार की शक्ति का प्रतीक है। वह प्रत्येक दृष्टि से जिले का मुख्य अधिकारी है। साधारण बोल-चाल में वह जिले का मालिक है। उसका मुख्य काम लगान वसूल करना तथा जिले में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखना है। साधारण जनता की भाँषी में वही सरकार है। उसके कई प्रकार के काम होते हैं। जिले का प्रत्येक विभाग कुछ भाँषा तक उससे निरीक्षण में रहता है। एक लेखक के अनुसार वह जिले में सरकार का मुख, कान, मुँह तथा हाथ है।

स्वराज्य प्राप्ति में पूर्व साधारणतः इण्डियन सिविल सर्विस के सदस्य जिलाधीश बनाये जाते थे। कुछ अवसरों पर प्रांतीय सिविल सर्विस के बहुत पुराने सदस्य भी कभी-कभी विनी जिले के जिलाधीश बना दिये जाते थे। परन्तु मुख्य जिलों के जिलाधीश सदैव इण्डियन सिविल सर्विस के ही सदस्य होते थे। ब्रिटिश सत्ता के ये जिलाधीश प्रतीक थे। अब जिलाधीश भारतीय एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के सदस्य होंगे। इस समय कई प्रांतीय सर्विस के सदस्य भी जिलाधीश पद पर नियुक्त हैं।

**जिलाधीश के अधिकार**—उसके अधिकार अनेक हैं। मृदुभाष्य उनको हम नीचे लिखे वर्गों में बाँट सकते हैं।

(१) जिले में शान्ति तथा सुव्यवस्था बनाय रखना—सामाजिक जीवन के लिए शान्ति आवश्यक है। सरकार के मुख्य कर्तव्यों में से एक यह है कि

नत्येक नागरिक को इस बात का विश्वास हो कि वह अपना काम बिना विघ्न बाधाओं के कर सकता है। इसके लिये शान्ति तथा व्यवस्था बनी रहनी चाहिये। जिले के अन्दर यह काम जिलाधीश का है। इस हेतु जिले की पुलिस को उसके साथ सहयोग करना पड़ता है। तथा उसके आज्ञानुसार काम करना होता है। पुलिस जिलाधीश का एक हाथ है। जिले में प्रत्येक पुलिस-अफसर इस दृष्टि से मातहत है। शान्ति तथा व्यवस्था का बनाये रखने के लिये थैलेटर को बहुत अधिकार दिये गए हैं। वह गंगा या जुलूमों पर रोक लगा सकता है। बरफू आइर तथा धारा १४४ लगा सकता है। वह समाचार पत्रों को भी देखभाल करता है। यह बन्दूक आदि के लाइसेन्स पर भी रोक रखता है। जिले में शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये यह जिले का दौरा करता है। जनता के प्रतिनिधियों से मिलता है। उनकी तबलीफा का मुनता है उन्हें दूर करने की चेष्टा करता है। आज्ञाकारी गणों को दंड तथा सजाओं की बर्गीकरण इन बातों का प्रबन्ध करने के लिए ओ राशनिंग तथा मण्डार विभागों से गए हैं वे भी जिलाधीश के अधीन हैं।

(२) मालगुजारी घसूल करने का अधिकार — बलेक्टर सार्व का कार्य ही घसूल करने वाला होता है। वह जिले की मालगुजारी घसूल करता है। यह भी उसके मुख्य कामों में से एक है। उसको यह अधिकार नहीं कि वह नटा या बड़ा सफे। परन्तु अकाल बाढ़ आदिके समय वह सरकार से यह सिफारिश कर सकता है कि इसमें बर्गीकरण छूट कर दी जावे। इसलिए जिले के अन्दर इस कार्य में सम्बन्धित सब अधिकारी उसके मातहत हैं। उसके नीचे काम को करने के लिये डिप्टी बलेक्टर, तहसीलदार नायब तहसीलदार, कानूनगो तथा पटवारी होते हैं। इस प्रकार जिलाधीश इस संगठन का मुखिया है। लगान घसूल करने के साथ साथ जिलाधीश किसानों के हिता तथा समस्याओं का भी ध्यान रखता है। अतिवृष्टि या अनावृष्टि या किसी और कारण से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने में वह किसानों की सहायता करता है। जिले का आव-कारी महकमा उनसे अधीन होता है। मादय-वस्तुओं के बिक्री का लाइसेन्स वही मजूर करता है। इसके साथ-साथ रजिस्ट्रेशन विभाग भी उसी के अधीन होता है। जिले का सजाना भी उसी की मातहत में होता है।

(३) न्याय सम्बन्धी अधिकार — हम पहले ही यह चुके हैं कि जिलाधीश प्रथम श्रेणी का मैजिस्ट्रेट होता है। उसे २ वर्षों तक की कैद तथा १००० रुपये तक जुर्माना करने का अधिकार है। द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के निणयों के विरुद्ध वह अपील मुनता है। मैजिस्ट्रेटों की अदालतें उसके अधीन हैं।

जिलाधीन जिले में मान के नुस्खों को नदमे बढ़ी बढ़ाकर है। नीचे को मान की बदलावों ने उन्हें मान धरीने पाती है। इनके निर्णय के विरुद्ध वनिस्तर को बदलन में अपील हो सकती है।

कई लोगों का कहना है कि जिला अधिकारियों के हाथ में इन प्रकार से शानन तथा न्याय दोनों अधिकार को मनुक्त रूप से नहीं होना चाहिए। इनका काम केवल शासन करना होना चाहिए, न कि न्याय करना भी। क्यों कि अगर शानन तथा न्याय सम्बन्धी अधिकार एक ही व्यक्ति के हाथ में होंगे तो सच्चा न्याय सम्भव नहीं है। इसी कारण बहुत मनन में नुस्खारकों ने इन बात की मांग की है कि कार्यकारी तथा न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाये। इनके अतिरिक्त अगर न्याय का काम पृथक कर दिया जाये तो ये अधिकारी शानन कार्य की ओर ध्यान दे सकते हैं। संविधान के नीति-निर्देशक तत्व वाले भाग में यह कहा गया है कि न्याय तथा शासन संबंधी कार्यों को सीधे-सीधे से अलग-पलग किया जावेगा। कुछ राज्यों में इन दिशा में कदम डाला गया है।

(४) निरीक्षण का अधिकार :—जिले में कई विभाग होते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, पुलिस, जंगल, पब्लिक वर्क्स आदि। इनमें से प्रत्येक का जिले में एक एक प्रधान होता है। ये प्रधान प्रदेस सरकार के अधीन हैं तथा जिलाधीन इनका प्रधान नहीं है और न ये विभाग उनकी अधीनता में हैं। तथापि ये सब विभाग जिलाधीन को अपने-अपने कार्यों की नुचता देते रहते हैं और इन विभागों के ऊपर उनका परीक्षण करने, कुछ न कुछ निरीक्षण रहता है। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जिलाधीन जिले में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिष्ठित है। अतएव यह स्वाभाविक है कि उनका यह सबने अधिक महत्वपूर्ण हो।

इन सरकारी विभागों के अतिरिक्त स्थानीय संस्थाओं, जैसे जिला-बोर्ड, नगरपालिका आदि के कामों पर भी जिलाधीन निरीक्षण रहता है। १९३९ तक तो जिलाधीन ही जिला-बोर्ड का नभापति होता था। परन्तु अब ऐसा नहीं होता है। अगर जिलाधीन इन संस्थाओं के कार्य में मनुष्ट नहीं है तो वह उसकी सूचना सरकार को दे सकता है। अब जिलाधीन तथा प्रादेशिक सरकार के मध्य सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया है। वनिस्तर के बहुत से अधिकार जिलाधीन को मिल गए हैं।

**जिलाधीश के अधिकारों की सीमा** — जिलाधीश अपने अधिकारों के सम्बन्ध में अपने ऊपर के अधिकारियों की अधीनता में काम करता है। वह राज्य सरकार के अधीन है और उसे अपने कामों की सूचना समय-समय पर भेजता है। दण्ड के मामलों में उसके निर्णय के विरुद्ध अपील जज के यहाँ अपील होती है। माल के मुकदमा की अपील उसके यहाँ में कमिश्नर की अदालत में होती है।

**जिले के भाग** — प्रत्येक जिला कई छोटे-छोटे भागों में बटा रहता है। इनको 'सब डिवीजन' कहते हैं। प्रत्येक सब डिवीजन एक सब-डिवीजनल-अफसर के अधीन होता है। यह अफसर साधारणतः प्रान्तीय सिविल सर्विस का सदस्य होता है। कुछ अक्सर पर भारतीय सर्विस का नया वर्ती हुआ सदस्य भी इस पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। इन सब-डिवीजनल अफसरों को प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के अधिकार होते हैं। इनमें से कुछ अफसर तो जिले के हेड-क्वार्टर में रहते हैं तथा कुछ अपने सब डिवीजन में रहते हैं। ये अधिकारी जिलाधीश के अधीन होते हैं। इनका काम अपने सब-डिवीजन में घट्टी है जो कि जिलाधीश का जिले में होता है, अर्थात् मालगुजारी वसूल करना, शान्ति व्यवस्था बनाये रखना तथा कचहरी करना। जिलाधीश समस्त जिले का प्रशासन इन अधिकारियों की सहायता से करता है।

— सब-डिवीजनल अफसर की अधीनता में तहसीलदार तथा नायब-तहसीलदार होते हैं। प्रत्येक जिला कुछ तहसीलों में बटा होता है। तहसील के अफसर को तहसीलदार कहते हैं। तहसील में तहसीलदार के वही काम हैं जो सब-डिवीजनल अफसर के सब-डिवीजन में होते हैं। वह तहसील की शान्ति तथा व्यवस्था के लिये उत्तरदायी है तथा उसका न्याय साबन्धी अधिकार और मालगुजारी वसूल करने के अधिकार होते हैं। तहसीलदारों को साधारणतः द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के अधिकार होते हैं। तहसीलदार की सहायता के लिये उसके नीचे नायब-तहसीलदार होता है। इसका काम मालगुजारी वसूल करने के काम में उसकी सहायता करना होता है।

प्रत्येक तहसील में कुछ परगने होते हैं। प्रत्येक परगना कुछ गांवों के मिलने से बनता है। परगने में मालगुजारी वसूल करने के लिये बानूनगो होता है। प्रत्येक गांव में एक पटवारी तथा एक मुखिया होता है। मुखिया गांव के प्रबन्ध के लिये उत्तरदायी है। पटवारी का काम मालगुजारी आदि का हिसाब रखना है। इससे अतिरिक्त गांव में एक चौकीदार भी होता है। इसका काम गांव के अपराध आदि की सूचना पुलिस थाने में देना है।

**टिबीजन** — बड़े जिलों के मिलने से टिबीजन बनता है। यह प्रशासकीय क्षेत्र एक कमिश्नर के अधीन होता है। इसीलिए इसे कमिश्नरी भी कहा जाता है। प्रायः सभी राज्यों में टिबीजन है। पञ्च बम्बई राज्य में सन् १९५० में कमिश्नरियों को हटा दिया गया है। मद्रास में भी कमिश्नर के पद को हटा दिया गया है। कुछ लोगों के मतानुसार कमिश्नर तथा कमिश्नरियों को हटाने से प्रशासन में कोई अमुविधा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इसीलिए कमिश्नरियों की संस्था बम कर दी थी तथा कमिश्नर के जिले के प्रशासन के ऊपर निगरानी सम्बन्धी अधिकारों में कमी कर दी थी। क्योंकि यह तर्क उपस्थित किया गया था कि राज्य सरकार तथा जिलाधीशों के मध्य इन कर्तों की कोई आवश्यकता नहीं है और उनके मध्य सीधा सम्बन्ध स्थापित होगा चाहिए। परन्तु अब पुनः उत्तर प्रदेश सरकार ने कमिश्नरियों की संस्था बम कर दी है तथा कमिश्नरों को उनके पुराने अधिकारों से विभूषित कर दिया है।

कमिश्नर प्रशासकीय सेवा का पुराना तथा अनुभवी कर्मचारी होता है। कमिश्नर का कार्य जिलाधीशों के कार्यों का निरीक्षण करना है। वह इन बातों को देखता है कि जिलाधीश राज्य सरकार की आज्ञाओं के अनुसार काम रहे हैं। जिले तथा राज्य सरकार के बीच वह सम्पर्क बनाता है। इसलिए राज्य सरकार की आज्ञाएँ उसी के द्वारा जिला अधिकारियों को पहुँचाई जाती हैं तथा जिले में राज्य सरकार के पान उसी की द्वारा पब आदि भेजे जाते हैं। वह जिलाधीश तथा पुलिस कप्तान के कार्यों के मध्य सम्बन्ध में महानक होता है। कमिश्नर की सरकार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आयोजना सम्बन्धी सभी विषयों की निगरानी का अधिकार प्रदान किया गया है। इनके अतिरिक्त कमिश्नर या प्रधान कार्य मालगुजारी सम्बन्धी है। वह इनकी बमूली का निरीक्षण करता है। उसे यह अधिकार है कि विशेष अवसरों पर मालगुजारी की बमूली रीकूरे या ठगने कमी कर दे। माल के मुकदमें उसकी मद्रालत में होते हैं। इस विषय में जिलाधीशों के निर्णय के विरुद्ध उसके यहाँ अपील होती है।

इन अधिकारों के अतिरिक्त कमिश्नर को स्थानीय संस्थानों के ऊपर देखभाल करने के अधिकार भी प्राप्त हैं। वह इनके बजट का निरीक्षण भी करता है। प्रतिवर्ष वह इनके काम के ऊपर एक रिपोर्ट देता है जिसमें उनके वार्षिक कार्य का सक्षिप्त विवरण तथा आलोचना रहती है।

**पुलिस का प्रबन्ध** :—राज्य का मुख्य कार्य प्राचीन-काल से ही आन्तरिक शान्ति को बनाये रखना तथा देश की सहाय्य आवश्यकता से रक्षा बनाना

गया है। आन्तरिक शान्ति के लिये प्रत्येक देश में पुलिस विभाग होना है। हमारे देश में पुलिस मरीच विषय नहीं है परन्तु राज्य सरकारों के अधीन है। जिन् में पुलिस विभाग का प्रधान कर्मचारी पुलिस-सुपरिन्टेन्डेंट कहलाता है। उसका मातारण राज्य पुलिस कप्तान कह कर सम्बोधित करने है। यह जिन् में आधारण पुलिस तथा स्थायी-पुलिस दाना का प्रधान है। माधारणतः यह ट्रिनि-यन पुलिस मरिय का मदम्य होता है। परन्तु कभी कभी प्रान्तीय पुलिस मरिय के अनुभवी कर्मचारी भी इस पद पर नियुक्त हो जाते हैं। पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट की शान्ति में उसका कार्य में महायता देने के लिये डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट होते हैं। ये प्रान्तीय पुलिस मरिय के मदम्य होते हैं।

ये जिन् के पुलिस अधिकाारी जिन्धीन की महायता के लिए हैं ताकि वह जिन् की शान्ति व्यवस्था बनाए रखे तथा जहाँ आवश्यकता प्रतीत हो इनकी महायता के अन्तर्गत जिन् में शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिये पुलिस का जिन्धीन की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट का यह कर्तव्य है कि वह जिन्धीन का जिन् की शान्ति व्यवस्था सम्बन्धी बातों की गवर दना है। परन्तु जहाँ नर आन्तरिक-अन्तर्भावन, प्रबन्ध आदि का सम्बन्ध है पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस विभाग के अन्तर्गत ग उँव कर्मचारियों के अधीन है। इनके आन्तरिक सामन में जिन्धीन का कर्तव्य अधिकाारी नहीं है।

प्रत्येक राज्य में एक पुलिस विभाग होता है। इसका प्रधान एक मंत्री होता है। पुलिस तथा जल विभाग एक ही मंत्री के अधीन होते हैं। यह आवश्यक विभागों में से एक है। मंत्री के नीचे पुलिस विभाग का मुख्य अफसर इन्स्पेक्टर जनरल कहलाता है। यह भारतीय पुलिस मरिय का पुराना तथा अनुभवी मदम्य होता है। यह राज्य के अन्दर पूरे पुलिस विभागों का मातृक है। मातारण पुलिस तथा स्थायी पुलिस दाना उसने अधीन है। मंत्री के अन्तर्गत कार्य के लिए राज्य विधान मन्त्र के प्रति उत्तरदायी है। इन्स्पेक्टर-जनरल मंत्री के प्रति उत्तरदायी है।

इन्स्पेक्टर जनरल के अधीन कुछ डिप्टी इन्स्पेक्टर-जनरल होते हैं। प्रत्येक डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल के अधीन एक-एक रेजिमेंट होती है। एक रेजिमेंट में कई जिन् होते हैं। माधारणतः एक रेजिमेंट में ८-१० जिन् होते हैं। एक डिप्टी इन्स्पेक्टर-जनरल हेड-क्वार्टर में होता है। एक स्थायी पुलिस के लिये नियुक्त होता है।



प्रत्येक जिला पुलिस के काम के लिये छोटे टुकड़ों में बाटा जाता है। इन क्षेत्रों को सर्किल कहा जाता है। एक जिले में करीबन ५ से ८ सर्किल तक होते हैं। प्रत्येक नविल एक पुलिस इन्स्पेक्टर के अधीन होता है। हर सर्किल में कई थाने होते हैं जो कि सब इन्स्पेक्टर की मातहत में होते हैं। इस के अतिरिक्त हर थाने में कुछ सिपाहों तथा रिपोर्ट लिखने के लिये मन्दी होते हैं। कई गांवों के बीच एक थाना होता है। गांव के चौकीदार का कर्तव्य है कि वह अपराध आदि की सूचना इन थानों में देता रहे। हर थाने के मातहत कुछ पुलिस चौकियां होती हैं। ये हेड-क्वार्टर के अधीन होती हैं।

नगरों में पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट की अधीनता में एक कोतवाल होता है। यह प्रांतीय पुलिस अधिनियम का मस्य होता है। छोटे नगरों में यह केवल इन्स्पेक्टर भी हो सकता है। प्रेसीडेन्सी नगरों के पुलिस प्रधान को पुलिस कमिश्नर कहते हैं। इस अधिकारी का सम्बन्ध सीधे राज्य सरकार में है। यह इन्स्पेक्टर जनरल के अधीन नहीं है। प्रत्येक नगर में सिटी-कोतवाल की अधीनता में कई थाने होते हैं। मुख्य थानों में इन्स्पेक्टर और बाकी में सब-इन्स्पेक्टर होते हैं।

**रिजर्व पुलिस :—**जिले के हेड-क्वार्टर में कुछ पुलिस सदा रखी जाती है। इसको रिजर्व पुलिस कहते हैं। जिले में किसी भी स्थान पर यदि वहाँ का पुलिस बल स्थिति पर काबू करने के लिये पर्याप्त न समझा जावे, तो रिजर्व पुलिस में से वहाँ भ्रादमी भेजे जाते हैं।

**रेलवे-पुलिस** —रेलवे-वर्माण अपने कार्यों के लिए अलग पुलिस रखता है। इसका काम गाड़ियों में, स्टेशनों में ज्ञान-माल की रक्षा करना है। इसका संगठन जिले के पुलिस मगटन में भिन्न होता है। इसके पास अपने अलग अधिकारी होते हैं।

**सुफिया-पुलिस** —भारत में इसकी व्यवस्था २०वीं सताब्दी के आरम्भ में की गई। इसका काम गुप्त अपराधों, पडव्यं, आदि का पता लगाना है। इसके संगठन के लिए एक डिप्टी-इन्स्पेक्टर जनरल होता है। प्रत्येक जिले में सुफिया पुलिस-सुपरिन्टेन्डेंट की अधीनता में होती है। उसके नीचे डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट तथा इन्स्पेक्टर और सब-इन्स्पेक्टर होते हैं।

भारत में पुलिस विभाग पर जनता की श्रद्धा कम है इसका मुख्य कारण यह है कि विदेशी शासन काल में पुलिस ने जनता का विश्वास प्राप्त करने की

चष्टा नहीं की है। इसका मुख्य काम जनता में आनक जमाना था। अब भी पुलिस को सब बुराइयाँ दूर नहीं हो गई परन्तु कश्मिस मन्त्रिमण्डल इन बुराइयों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

५. जेल विभाग — यह विभाग भी राज्य सरकार के अधीन है। इसका प्रधान एक मंत्री होता है। पुलिस तथा जेल विभाग एक ही मंत्री के अधीन होते हैं। इसमें नीचे एक इन्स्पेक्टर-जनरल होता है। यह अधिकारी मेडिकल सर्जिन का पुराना सरस्य होता है। जेल विभाग के अन्य सब कर्मचारी इसकी अधीनता में काम करते हैं।

जेल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं —

(१) केन्द्रीय जेल — इन जेलों में वे अपराधी रक्ते जाते हैं जो कि लम्बे काठ के लिये दंडित होते हैं। ये प्रत्येक जिला में नहीं होते हैं, परन्तु कुछ मुख्य-मुख्य स्थानों में स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक केन्द्रीय जेल में एक सुपरिन्टेन्डेंट, जेलर वाटर् आदि होते हैं।

(२) जिला जेल — हर जिले में अपराधियों को रक्ते के लिये जिला जेल होता है। मिडिल-क्वॉल्टी जेलों का नियोजन करता है। इसमें प्रतिरिक्न, लार् मेडिकल अफसर तथा वाटर् आदि होते हैं।

(३) हवालात — इनमें वे कैदी रक्ते जाते हैं जिनका मुकद्दमा चला रहा है तथा जिनका फैसला नहीं हुआ हो।

(४) कैम्प जेल — इनकी स्थापना तब की जाती जब कि कैदियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है।

जेल में स्त्री तथा पुरुषों को अलग-अलग रखा जाता है। स्त्रियों के भाग में वाटर् आदि कर्मचारी सब स्त्रियाँ ही होती हैं। बच्चे के लिए भी अलग प्रबन्ध है। उन्हें बड़े कैदियों के साथ नहीं रखा जाता है। बालक अपराधियों के सुधार के लिए भी अलग जेलों की व्यवस्था है, जिनका रिफॉर्मेटरी स्कूल कहा जाता है परन्तु इनकी संख्या नगण्य है।

हमारे देश में जेलों में बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है। विद्वानों सामानों ने इस ओर कभी भी ध्यान नहीं दिया। कश्मिस मन्त्रिमण्डल ने इस दिशा

में कुछ बदल उठाया जा परन्तु अधिक नहीं। यह आवश्यक है कि जेल के अन्दर कैदियों के साथ सिध्द तथा सम्य व्यवहार होना चाहिये; उनके शारीरिक तथा मानसिक आनन्द का प्रबन्ध होना चाहिये। खाना स्वास्थ्य-कर होना चाहिए। इन सब सुधारों के बिना हमारे जेलों की दशा अच्छी नहीं हो सकती।

### प्रश्न

- (१) जिले के प्रशासन के लिए किस प्रकार संगठन किया जाता है ?
- (२) जिलाधीश के क्या-क्या अधिकार हैं ?

## स्थानीय सस्थाएँ

**महत्त्व** — स्थानीय-सस्थाओं से तात्पर्य उन सस्थाओं से है जिनके द्वारा जनता के प्रतिनिधि अपने स्थानीय मामलों का प्रबन्ध करते हैं। इस प्रकार जनता को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है। इस प्रथा को स्थानीय स्वराज्य या स्थानीय स्वाशासन कहते हैं। स्थानीय स्वराज्य का बहुत महत्व है।

केन्द्रीय सरकार से यह आशा रखना कि वह समस्त देश का शासन ठीक प्रकार से कर सकेगी व्यर्थ है। क्योंकि सरकार के राष्ट्रीय महत्व के काम ही इतने अधिक बढ़ गए हैं तथा जटिल हो गए हैं कि वह छोटी छोटी स्थानीय समस्याओं पर ध्यान नहीं दे सकती हैं। स्थानीय सस्थाएँ ही मनुष्य के दैनिक जीवन के लिये आवश्यक सुविधाओं का प्रबन्ध कर सकती हैं।

केन्द्रीय सरकार वे सदस्य स्थानीय मामलों में बहुत दिलचस्पी नहीं लेती क्योंकि उनका ध्यान राष्ट्रीय मामलों में ही उलझा रहता है। वे अपने को राष्ट्र की सेवा करना समझते हैं, इसलिए स्थानीय मामलों के प्रति उनमें न काम करने की इच्छा रहती है और न उत्तरदायित्व का भावना।

अगर सब काम केन्द्रीय सरकार के ही हाथों में रहे तो पूरी सरकार एक नौकरशाही में परिणत हो जावेगी। ये सरकारी बर्मेंचारी अधिकतर मन माना काम करते हैं। नौकरशाही का सबसे बड़ा दोष लाल पीता (red tape) कहलाता है। सरकारी भ्रष्टाचार के अन्दर सहानुभूति कम रहती है। वे सब काम करने में देर लगाते हैं क्योंकि प्रत्येक काम कायदे के अनुसार होना चाहिए।

स्थानीय कामों को वे ही ठीक प्रकार समझ सकते हैं जो कि वहाँ के रहने वाले हों। बाहरी आदमी इन कामों को ठीक प्रकार नहीं कर सकता है।

स्थानीय सस्थाओं के द्वारा नागरिकों को राजनैतिक शिक्षा मिलती है। उनमें कई गुणों की वृद्धि होती है। वे यह समझते हैं कि उत्तरदायित्वपूर्वक काम करना चाहिए। प्रजातन्त्र में इन सस्थाओं का महान महत्व है। ये नागरिकों को शासन प्रबन्ध का ज्ञान देकर उन्हें देश के शासन में भाग लेने योग्य बनाती हैं।

**ऐतिहासिक पृष्ठभूमि** —नाथारपत यह समझा जाता है कि स्थानीय संस्थाओं का प्रारंभ अंग्रेजी काल में ही हुआ तथा प्राचीन और मध्यकालीन भारत में ऐसी संस्थाओं का कोई भी चिह्न नहीं था। यद्यपि यह सत्य है कि उस समय इनका स्वरूप आज से भिन्न था परन्तु यह कहना कि वे अंग्रेजी काल से पूर्व नहीं थी, प्रमत्त है।

प्राचीन भारत में नगर तथा गाँवों दोनों के प्रबन्ध के लिए संस्थाएँ थीं। इन संस्थाओं को इन क्षेत्रों का उचित प्रकार से प्रबन्ध करने के लिये आवश्यक अधिकार मिले थे। इनका प्रबन्ध सराहनीय था।

नगर के प्रबन्ध के लिये कई कमेटियाँ होती थीं। इनमें से एक कमेटी प्रधान होती थी। प्रत्येक कमेटी को किसी न किमी बात का प्रबन्ध करना पड़ता था, जैसे, रोशनी, सफाई, शिक्षा, दुकानों का प्रबन्ध इत्यादि। विदेशी यात्रियों ने इस प्रबन्ध की प्रशंसा की। उदाहरणार्थ, मेगस्थनीज जो कि चन्द्रगुप्त मौर्य के दामन काल में आया था, पाटलिपुत्र नगर के प्रबन्ध की प्रशंसा करता है।

गाँव में भी उनके प्रबन्ध के लिए संस्थाएँ थीं। इनको पंचायत कहते थे। प्रत्येक गाँव की पंचायत के नीचे कई कमेटियाँ होती थीं। ये गाँव की विभिन्न बातों का प्रबन्ध करती थीं। इन पंचायतों का अधिकार क्षेत्र वास्तव में बहुत व्यापक था। गाँव के सब प्रकार के मामले पंचायत ही निपटा देती थी। उक्त कारण यह था कि गाँवों का जीवन उन समय सामूहिक था तथा गाँव स्वावलम्बी (self-sufficient) थे। अपनी आवश्यकता की चीजें स्वयं ही पैदा कर लेते थे। गाँव की यह अवस्था उन्नीसवीं शताब्दी में आकर बदलने लगी। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के पश्चात् गाँव की स्थिति में परिवर्तन होना आरम्भ हुआ। पूँजीवादी व्यवस्था में गाँव स्वावलम्बी रह ही नहीं सकते थे। इसी कारण ब्रिटिश काल में ग्राम पंचायतें भूत हों गईं। मुगलमानी काल में भारत की ग्रामीण संस्थाएँ बनी रही।

**अंग्रेजी काल** :—अंग्रेजी काल में स्थानीय स्वराज्य का प्रारम्भ सन् १७८७ ई० से प्रारम्भ होता है। इन वर्षें मद्रास में एक कारपोरेशन (निगम) की स्थापना की गई। कुछ काल पश्चात् इसी प्रकार के निगम कलकत्ता तथा बम्बई में भी स्थापित किए गए। सन् १८४२ में स्थानीय स्वराज्य कुछ अन्य नगरों में स्थापित किया गया। परन्तु यह कहना प्रत्यक्षपूर्व नहीं होगा कि स्थानीय स्वराज्य का वास्तविक आरम्भ सन् १८७० से होता है। उन वर्षें भारत सरकार ने अपने एक प्रस्ताव में यह कहा था कि सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि

कामों से सम्बन्धित निधि के ऊपर स्थानीय मस्याओं का अधिकार होना चाहिए। सन १८८२ में भारत सरकार ने स्थानीय स्वराज्य के ऊपर एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया। उस साल लॉर्ड रिपन भारत के वाइसराय थे। इस प्रस्ताव में निम्नलिखित बात थी —

(१) इस समय तक स्थानीय स्वराज्य केवल नगरों तक ही सीमित था। इस प्रस्ताव द्वारा गांवों में भी इस प्रकार की मस्याओं की स्थापना करने को कहा गया। नगरों में भी स्थानीय मस्याओं की स्वाधीनता में वृद्धि की गई है।

(२) इन मस्याओं में सरकारी सदस्यों का बहुमत न हो। अधिक से अधिक उनकी मदद समस्त मदस्य सख्या की तिहाई होनी चाहिए।

(३) इन स्थानीय मस्याओं पर प्रान्तीय सरकार का नियंत्रण प्रत्यक्ष नहीं होकर बाहर से हो। इसका अध्यक्ष भी गैर-सरकारी ही हो।

इस एक्ट के द्वारा कुछ उन्नति तो अवश्य हुई परन्तु विशेष नहीं। क्योंकि इन मस्याओं में सरकार बहुत अधिक हस्तक्षेप करती थी। इनकी धार्मिक प्रवृत्तियाँ शोचनीय थीं। इनके जो मदस्य निर्वाचित होते थे वे बहुधा अधिभारियों के पिछे भावित हुए। इन मस्याओं का सभापति अक्सर गैर-सरकारी न हाकर जिज्ञाशील ही बना रहा। इस प्रकार ये मस्याएँ स्वतन्त्रतापूर्वक काम नहीं कर सकीं।

सन १९१८ में सरकार ने एक नए प्रस्ताव द्वारा स्थानीय मस्याओं के विषय में कई सधार किए। इनमें से मुख्य मुख्य निम्नलिखित थे।

(१) इन मस्याओं में गैर-सरकारी समस्या का बहुमत हो तथा सरकारी समस्याओं को सहायकार न हो।

(२) इन मस्याओं का सभापति गैर-सरकारी हो तथा उसका निर्वाचन हो।

(३) इन मस्याओं के निर्वाचकों की योग्यता में कमी कर दी जावे ताकि अधिक लोग चुनाव में भाग ले सकें।

(४) इन मस्याओं को कर घटाने-बढ़ाने तथा प्रान्तीय सरकार की सन मति में नए कर लगाने का अधिकार हो।

सन १९१९ में गामन-मुबार एक्ट पास होने पर स्थानीय स्वराज्य विभाग प्रान्तीय सरकार के एक मंत्री को मिला गया। स्थानीय स्वराज्य के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण काम था। इसने इन मस्याओं के अधिकार बढ़े तथा इनमें जनता के प्रतिनिधि आने लगे। सरकारी व्यय भी कम हो गया।

मयूक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में सन् १९१६ में एक म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट पाम हुआ था। इस ऐक्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वराज्य प्राप्ति के पदचार्त् स्थिति परिवर्तन को ध्यान रखते हुए कई संशोधन कर दिये हैं। जैसे साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व हटा दिया गया है। वररक मताधिकार की स्थापना की गई है। अध्यक्ष का जनता द्वारा सीधे चुनाव प्रथा की स्थापना की गई है। सन् १९२९ में हमारे प्रान्त में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट पाम हुआ था। सन् १९५० ई० में इसमें भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए।

**स्थानीय संस्थाओं के रूप —** नगरों के प्रबन्ध में सम्बन्धित संस्थाएँ निम्नान्त प्रकार की होती हैं —

कारपोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, टाउन एण्डा वमेटी, बोर्डिफाइड एण्डा वमेटी, इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट, कंन्ट्रोलमेण्ट बोर्ड तथा पोर्ट ट्रस्ट।

गाँवों के प्रबन्ध से निम्नलिखित संस्थाएँ सम्बन्धित हैं :—

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, सब-डिविजनल बोर्ड तथा ग्राम पंचायत। इनका क्रम वर्णन किया जायगा।

## नगर-निगम (Corporations)

अंग्रेजी काल में केवल तीन प्रेजीडेन्सी नगरों—कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में ही नगर निगम स्थापन किए गए थे। परन्तु अब कुछ अन्य नगरों में भी इनकी स्थापना हो गई है। पटना, जबलपुर, नागपुर में नगर निगमों की स्थापना हो चुकी है। उत्तरप्रदेश में इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, कासपुर तथा आगरा में भी नगर निगमों की स्थापना होने वाली है। इसके लिये एक अधिनियम बन गया है, जिसे उत्तरप्रदेश नगर महापालिका अधिनियम १९५९ कहा गया है। अक्टूबर, १९५९ में दस नगरों में इस हेतु निर्वाचन होये।

नगर निगम या नगर महापालिकाओं को एक उच्च कोटि का नगरपालिका कहा जा सकता है। इनके साधन-व्यय के साधन तथा इनकी शक्तियाँ साधारण नगरपालिकाओं से अधिक होती हैं अन्यथा दोनों के बीच कोई विशेष भेद नहीं है। नगरपालिकाएँ जो कार्य अपने क्षेत्र में करती हैं वही कार्य महापालिकाएँ बड़े बड़े नगरों में करती हैं। हम संक्षेप में महापालिका अधिनियम (१९५९) के अनुसार उत्तरप्रदेश में जो महापालिका का गठन होगा उसका संक्षिप्त

वर्णन करेंगे। अन्य स्थानों पर भी थोड़े बहुत क्षेत्रों के अन्तर्गत कार्यवाही का काम ही मगडन है।

उत्तर प्रदेश में महापालिका अधिनियम द्वारा दस पाँच नगरों में शब्दों के निर्वाचनों के पश्चात् महापालिकाओं का स्थापना हो जायगी। महापालिका एक निर्वाचित समिति होगी। प्रत्येक महापालिका में एक नगर प्रमुख, कुछ महासद (इनकी मस्या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जायगी), तथा कुछ विविष्ट सदस्य होंगे। विविष्ट सदस्यों की मस्या लगभग महासदों की मस्या का दवाँ भाग होगा। महासदों में से कुछ स्थान परिगणित जातियों (scheduled Caste) के लिये कुछ स्थान रक्षित रहेंगे। महापालिका का कार्यकाल ५ वर्ष निर्दिष्ट किया गया है। परन्तु राज्य सरकार यदि चाहे तो इसे अधिक से अधिक १ वर्ष और बढ़ा सकती है तथा किसी सम्मोचन मकद के कारण यह एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है।

महापालिका के सदस्यों का कार्यकाल भी ५ वर्ष रहा गया है। महासदों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। इसके लिये नगर का कई निर्वाचन क्षेत्रों में बाँट दिया जायगा। परन्तु विविष्ट सदस्यों का निर्वाचन मजानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल-मजमणीय मत द्वारा महासदों द्वारा किया जायगा। इन महासदों द्वारा तथा विविष्ट सदस्यों की योग्यताएँ अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट कर दी गई हैं। विविष्ट सदस्य होने के लिये यह आवश्यक है कि वह ध्वजित नगर में निर्वाचक हो तथा ३० वर्ष की आयु से कम न हो। महासद होने के लिये यह योग्यता आवश्यक है कि वह नगर में निर्वाचक हो तथा परिगणित जातियों के लिये रक्षित स्थान से नियुक्त होने के लिये यह आवश्यक है कि वह परिगणित जाति का सदस्य हो। वे व्यक्ति जो दिवालिया हों, ६ माह से अधिक के लिये मजा पाये हों और तब से ५ वर्ष का समय न बीत। हा, महापालिका में कोई लाभ का पद धारण किए हों, या सरकारी नौकरी आदि में हों, सरकारी नौकरी से छुट्टाचार आदि के लिये निकाले गये हों, या कोई हों, आदि योग्यताओं के होने पर महापालिका की सदस्यता के लिये निर्वाचित नहीं हो सकते हैं।

प्रत्येक महापालिका में एक नगर प्रमुख तथा एक उपनगर प्रमुख होगा। नगर प्रमुख की अनुपस्थिति में उप नगर प्रमुख उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। नगर प्रमुख तथा उप नगर प्रमुख के लिये निम्नलिखित योग्यताएँ आवश्यक हैं —



- (१) वह नगर में निर्वाचक हो,
- (२) तीन वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो,
- (३) उसमें मनासद तथा विविष्ट नदस्य पद के लिये उल्लिखित अयोग्यताएँ न हों,

तथा (४) यदि वह मनासद या विविष्ट नदस्य होने के लिये निर्वाचन में हारा हो, तो तब ने ६ माह का समय बीच चुका हो।

नगरप्रमुख का कार्यकाल १ वर्ष रखा गया है, परन्तु वह यदि चाहें तो पुनः निर्वाचन के लिये खड़ा हो सकता है। इनका निर्वाचन समानुपाती पद्धति से एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान द्वारा होगा। उप नगरप्रमुख का कार्यकाल महापालिका के बराबर ही रखा गया है।

नगरप्रमुख महापालिका की बैठकों में भाग्यति वा यासन ग्रहण करेगा। साधारण दस्तों में उसे मतदान का अधिकार नहीं है परन्तु किसी समय समान मत होने पर उसे निर्णायक मत (casting vote) का अधिकार दिया गया है। वह यदि महापालिका का अन्य प्रकार सदस्य न हो तो एवेन (ex officio) सदस्य होगा। उसे ऐसे भत्ते (allowances) दिये जायेंगे, जैसा कि महापालिका राज्य सरकार की पूर्ण सहमति में निर्दिष्ट करे। नगरप्रमुख तथा उप नगरप्रमुख का नागरिक जीवन में विविष्ट स्थान होगा परन्तु इन्हें प्रशासनिक अधिकार नहीं दिये गए हैं।

महापालिका की प्रतिवर्ष कम से कम ६ बैठकें होंगी तथा किन्तु दो बैठकों के बीच २ माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए।

**कार्यकारिणी समिति** — प्रत्येक महापालिका एक की कार्यकारिणी समिति (executive committee) होगी। इसके निम्नोक्त सदस्य होंगे।

उप नगर प्रमुख जो कि इस समिति का पदेन सभापति होगा तथा १२ नदस्य जिनका निर्वाचन महापालिका अपने मनासदों तथा विविष्ट नदस्यों में से करेगी।

इन १२ सदस्यों का निर्वाचन महापालिका अपने निर्वाचन के पश्चात् प्रथम बैठक में करेगी। प्रतिवर्ष इनमें से छह सदस्य अपने स्थान रिक्त कर देंगे। इनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन दिया जायगा। जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया हो वे पुनर्निर्वाचन के लिये खड़े हो सकते हैं। इन सदस्यों का निर्वाचन समानुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति से एवम् संक्रमणीय प्रणाली द्वारा किया जायगा।

वायवारिणी समिति का महापालिका व नगर में मुख्य स्थान होगा। यह इसरी सबसे प्रमुख समिति होगी।

इसके अतिरिक्त महापालिका में एक विकास समिति (development committee) होगी। यदि महापालिका विजयी, नगर ट्रामपोर्ट तथा अन्य जन हितकारी सेवा का संचालन करे तो उनके सम्बन्ध में अन्य समितियाँ स्थापित की जा सकती हैं। विकास समिति का सभापति उस नगर प्रमुख होगा तथा उसके अतिरिक्त महापालिका के सभासद तथा विशिष्ट सदस्यों में से निर्वाचित १० सदस्य तथा दो को-ऑप्टेड (co-opted) सदस्य होंगे। यदि महापालिका अन्य समितियों की स्थापना करना चाहे तो उसे राज्य सरकार से आज्ञा प्राप्त करनी होगी। इन समितियों में अधिक से अधिक १८ सदस्य होंगे तथा इनमें से ही एक सभापति तथा एक उप सभापति चुना जायगा। उपर्युक्त सभी समितियों की काम में काम प्रतियोग एक बैठक अवश्य होगी।

**मुख्य नगर अधिकारी** — वास्तव में यह महापालिका का मुख्य प्रशासकीय अधिकारी होगा। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायगी। परन्तु यदि राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करे जो कि सरकारी सेवा का सदस्य नहीं है तो उस दशा में इसकी नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा स्वीकृत होनी चाहिए। मुख्य नगर अधिकारी की नियुक्ति पहले समय राज्य सरकार तीन वर्षों से अधिक के लिये नहीं करेगी। परन्तु उसके पश्चात् इसकी नियुक्ति का पुनर्नवीकरण किया जा सकता है। परन्तु किसी भी समय एक समय में नियुक्ति तीन वर्षों से अधिक के लिये नहीं की जायगी। मुख्य नगर अधिकारी के विरुद्ध यदि महापालिका की कुछ सदस्य संख्या का ५१.८वां भाग यह प्रस्ताव पार करे कि सरकार उसे काफ़ी बुरा ले तो उस हटा दिया जायगा। उसको महापालिका कोष से धन दिया जायगा जो कि राज्य सरकार द्वारा निश्चित किया जाय। महापालिका की कार्यपालिका शक्ति मुख्य नगर अधिकारी को ही दी गई है। महापालिका के अन्य सब कर्मचारी (मुख्य लेखा परीक्षक के अतिरिक्त) उसके नियंत्रण में रहेंगे। किसी मस्य के समय जनता को सेवा अथवा सुरक्षा या महापालिका की सम्पत्ति की रक्षा के लिये वह कोई ऐसा काम कर सकता है जो उस आवश्यक प्रतीत हो। परन्तु वह इस कार्य की सूचना कार्यसमिति तथा महापालिका का सुरक्षित देगा। महापालिका या उसकी समितियाँ यदि चाहे तो मुख्य नगर अधिकारी को अपने कुछ कृत्य इस्तान्तरित भी कर सकती है। उसको महापालिका ने उन सब कर्मचारियों को जिनका वेतन दो सौ रुपए प्रति माह से अधिक नहीं है। (वेक उनके अतिरिक्त जो कि मुख्य लेखा परीक्षक के अन्तर्गत आते हैं) नियुक्ति का भी अधिकार है।

कलकत्ता नगर निगम में कार्यपालिका अधिकारी की नियुक्ति कारपोरेशन द्वारा ही की जाती है। परन्तु अन्य सब कारपोरेशनों में यह नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

मुख्य नगर अधिकारी के अतिरिक्त महापालिका में कई अन्य कर्मचारी होंगे। महापालिका निर्माणित पदों पर नियुक्ति कर सकती है। —उप नगर अधिकारी सहायक नगर अधिकारी, नगर अभियन्ता (engineer) नगर स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य नगर लेखा परीक्षक तथा अन्य ऐसे कर्मचारी जिनको आवश्यकता प्रतीत हो। इन पदों पर नियुक्ति नगर प्रमुख लोक सेवा आयोग की राय में करेगा। इन विभिन्न अधिकारियों का कार्यक्षेत्र इस अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट कर दिया गया है।

महापालिका के कर्तव्य तथा अधिकार.—साधारणतः यह कहा जा सकता है कि महापालिका के वे ही कर्तव्य हैं जो कि अन्य नगरों में नगर पालिकाओं द्वारा सम्पादित किए जाते हैं। परन्तु इनके अधिकार मुख्य क्षेत्रों में नगर-पालिकाओं से अधिक विस्तृत हैं। उत्तरप्रदेश में महापालिका अधिनियम के द्वारा इतने कुछ कर्तव्यों को अनिवार्य करिंट में रखा गया है। इनके अतिरिक्त कुछ कर्तव्य ऐच्छिक भी हैं।

मीमा-चिह्नों का निर्माण, मार्गों (streets) तथा गार्बेजिनिक ग्यानों का नामकरण, गन्दगी को हटवाना, रास्तों की गफाई, नालियों तथा गार्बेजिनिक खोबालों तथा मूत्रालयों का निर्माण, जल का प्रवण तथा वितरण, जल की गफाई का प्रवण, रास्तों में रोडनी का प्रवण, अस्पतालों का निर्माण, छूत की बीमारियों की रोक धाम, टीके लगाने का प्रवण, जन्म-मरण का हियाव, मौजन, पानी धादि की शुद्धता की ऑन वें लिये रसायनशालाओं की स्थापना, बेम्यावृति धादि पर प्रतिबन्ध, ध्मशान, म्दांघाट, कत्रगाहों का प्रवण, बाजार तथा बचडशालाओं (slaughter houses) का निर्माण, आग बुझाने के लिये पानी का प्रवण, टूटी फूटी इमारतों को तोडना, प्राथमिक शिक्षा तथा नर्सरी शिक्षा के लिये स्कूलों की स्थापना, स्वास्थ्य मस्याओं को अनुदान, पदार्थों के लिये चिकित्सालयों की स्थापना, कांजी हाउस बनाना, रास्तों, यलियों, पुलों धादि का निर्माण, रास्तों में वृक्षारोपण, नगर नियोजन तथा नगर सुधार महापालिका नर्सालय तथा गार्बेजिनिक इमारतों की देखभाल धादि।

उपर्युक्त कर्तव्यों के अतिरिक्त महापालिका यदि चाहे तो निम्नलिखित कर्तव्यों में से भी मनी या कुछ कर्तव्यों को कर सकती है। इनमें से मुख्यः

है पागलखाने, कोठी खाने, अनाथालया, आदि का स्थापना तथा प्रबन्ध, गर्भ-वती स्त्रियों, बच्चा तथा स्कूल के विद्यार्थियों के लिये दूध का प्रबन्ध, तैरन के तालाब तथा स्नान के लिये घाटों का निर्माण, डेयरी का प्रबन्ध, मनुष्यों तथा पशुओं के लिये सार्वजनिक स्थान पर पीने के पानी का प्रबन्ध, शिक्षालयों तथा सांस्कृतिक संस्थाओं का अनुदान, नुमाइश, दमल आदि का प्रबन्ध, थियेटर भवन आदि का निर्माण, महापालिका के कर्मचारियों के लिये भवन निर्माण तथा गैस आदि देने का प्रबन्ध, ट्रामवे या मोटर ट्रान्स्पोर्ट का प्रबन्ध करना, पुस्तकालय, म्यूजियम की स्थापना आदि, पशुओं के लिये अस्पताल, जानवरों तथा पक्षियों का विनाश, मान पत्र देना, चरागाह के मैदानों को रखना, भूमि तथा भवन का सर्वे, यात्री ब्यूरो का प्रबन्ध, महापालिका के काम के लिये छापाखाना तथा वर्क-शाप खोलना, कम्पोस्ट खाद बनाने का प्रबन्ध, व्यापार तथा उद्योग की उन्नति करना, महापालिका बैंक की स्थापना, अमिश कल्याण केन्द्रों की स्थापना, भोजन माँगने के विरुद्ध अभियान, परिणमित तथा पिछड़ी जातियों की सामाजिक अभिविधाओं को दूर करने में सहायता देना, इत्यादि, इत्यादि। यदि राज्य सरकार चाहे तो इनमें से किसी भी ऐच्छिक कृत्य को अनिवार्य कृत्य की कोटि में रख सकती है।

उपर्युक्त कृत्यों की सूची देखने से स्पष्ट हो जाता है कि महापालिकाओं को कितने विस्तृत अधिकार दिये गए हैं।

महापालिकाओं की आय के साधन—महापालिकाओं की आय के लिए इन्हें अनेक प्रकार के कर लगाने का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक महापालिका निम्नोक्त कर लगायेगी—सम्पत्ति पर कर, मशीन में चलने वाली गाड़ियों के अतिरिक्त अन्य गाड़ियों पर कर, रुवारी गाड़ियों पर कर, नावों पर कर, सवारी आदि के लिये पशुओं पर कर। इनके अतिरिक्त महापालिकाएँ निम्नलिखित कर भी लगा सकती हैं—यापार,वेशे आदि पर कर, शहर में आने वाले तथा बाहर जाने वाले गाँव पर चुगी, गाड़ियों तथा सवारियों पर चुगे, कुत्तों पर कर, अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कर, समाचार पत्रों में छपे विज्ञापनों के अतिरिक्त अन्य विज्ञापनों पर कर, थियेटर कर, तथा कोई अन्य प्रकार का कर जो कि राज्य के विधान मण्डल के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है।

इन उपर्युक्त करों के अतिरिक्त महापालिकाओं को इस अधिनियम के द्वारा यह भी अधिकार दिया गया है कि वे आवश्यकता होने पर ऋण भी ले सकती हैं। परन्तु इसके लिए उन्हें राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।

परन्तु श्रृण केवल स्थायी निर्माण कार्य (a permanent work) के लिये ही लिया जा सकता है। श्रृण कितना हो, व्याज की क्या दर हो आदि बातें राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जायेंगी। कोई भी श्रृण महापालिका ३० वर्षों में अधिक काल के लिये नहीं लेगी।

महापालिकाओं की कुछ धारा इनके द्वारा निर्मित भवनों, दुकानों, आदि में किराये के रूप में, बूचडसालों, मार्बलजिनिक टान्करोट, प्रदर्शनी, पिपेटर, आदि में भी होगी। समय समय पर इनको राज्य सरकार की ओर से भी आर्थिक सहायता मिलती रहेगी।

**राज्य सरकार का नियन्त्रण:**—महापालिकाओं की कर्मचारियों की नियुक्ति में तथा ऋण लेने में हम देख चुके हैं कि सरकार नियंत्रण रखती है। इनके प्रतिरिक्त सरकार अन्य कई प्रकार से महापालिकाओं पर नियंत्रण रखती है। अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित बातों पर राज्य सरकार का नियंत्रण रहेगा:—

(१) राज्य सरकार महापालिका प्रपवा इसकी किसी भी समिति की किसी कार्यवाही के विषय में सूचना मांग सकती है।

(२) यह मुख्य नगर अधिकारी से महापालिका प्रशासन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकती है।

(३) यह महापालिका के किसी भी विभाग प्रपवा कार्य के निरीक्षणार्थ कर्मचारी की नियुक्ति कर सकती है जो अपनी रिपोर्टें राज्य सरकार को देगा।

(४) यह महापालिका को किसी कार्य के करने का आदेश दे सकता है।

(५) यदि महापालिका राज्य सरकार की आज्ञानुसार किसी कार्य को करने में असमर्थ सिद्ध हो तो राज्य सरकार किसी व्यक्ति को नियुक्त कर वह काम करवा सकती है।

(६) राज्य सरकार इसी प्रकार किसी संकट (emergency) की स्थिति में अपने द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा काम करवा सकती है।

(७) महापालिका तथा इनकी समितियों के प्रस्ताव मुख्य अधिकारी द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित किये जायेंगे।

(८) यदि राज्य सरकार यह मोचे कि महापालिका का कोई प्रस्ताव या आदेश अनहित में नहीं है तो वह उसका लागू करना रोक सकती है।

(९) यदि बिना समय राज्य सरकार को यह विन्दाग हो जाय कि महाप्राप्ति अथवा इत्यादि का निवृत्ति कर में अग्रगण्य है अथवा यह अपनी गतिता का दुर्गमण कर रही है तो राज्य सरकार उस भग्न कर गवनी है तथा अग्रगण्य ६ मास व अन्तगत गए निर्वाचित करायगी

(१०) यदि त्वत्प्राप्तं महापात्रं दीनं प्रकारं न काम न कर मा  
राज्यं गन्तव्यं महापात्रं वा भगवत् इत्येव अधिकारं प्राप्तं प्रायः न ल  
भवीते । परं तु विष्णो श्री लिंगे में ४ वयं न अधिक समय तक महापात्रं  
भगवती स्तुति ।

उपयुक्त वणन से स्पष्ट है कि राज्य सरकार का महाप्राधिकाप पर नियंत्रण काफी विस्तृत तथा व्यापक है। यद्यपि यह सच है कि स्थानीय मन्त्रालयों को अपना कार्य क्षेत्र व आयतन प्रगतिवाधित स्वतंत्रता होती चाहिये जिससे उन्हें उन्हें उत्तरदायित्व का भावना बढ़ सके तथापि भारत की वर्तमान परिस्थितियों में वादका ह्रास यह रही वरा जा सकता कि मन्त्रालयों पर स्थानीय मन्त्रालयों पर अत्यधिक हस्तक्षेप है।

गामोय रूप न भारत न सभी वास्तवगत को गम्य धार बन  
प्रार व माध दुगी प्रार वा है। अतएव उक्त पक्ष वणत आवश्य नही  
है।

गंगा ब  
मात्रिका  
नी नगर  
म स्थितिगिरिगिरी की स्थापना करना राज्य सरकार का हाथ में है। यही  
नी प्रसार  
उपक  
ता काम  
करना का जिस एक अग्रसर नियुक्त कर ली है त्रिगुणी एडमिनिस्ट्रेटर कहते  
हैं उपायग्राह्य लगाने से इसका बिया गया है।

उत्तर प्रदेश में व्यक्तिगत-उद्योगों का विकास तथा उनका अधिष्ठापन मन्त्रालय द्वारा १९१३-१४ के बजट में प्राथमिक है। इसका मन्त्र १९६९ तथा मन्त्र १९५१ में मशीन विभाग में थे ? मन्त्र १९६९ के बजट में मशीन विभाग में विभिन्न मशीनों के उत्पादन के नियंत्रण के अधीन मशीन विभाग तथा मशीन विभाग का प्रत्यक्ष विभाग है। मन्त्रालय में मशीन विभाग के अधीन मशीन विभाग का प्रत्यक्ष विभाग है।

प्रतीत हुआ कि म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट में और संशोधन बिचे जाय। इस उद्देश्य में अक्टूबर मन् १९५२ में प्रादेशिक विधान मंडल में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया जो कि फरवरी मन् १९५२ में कानून हो गया। इसको The U. P. Municipalities (Amendment) Act, 1952 कहते हैं। एक प्रांत में भी प्रादेशिक सरकार ने निर्वाचन नामावली का तैयार करने तथा उसमें संशोधन करने को निकाला। इसको U. P. Municipalities Preparation and Revision of Electoral Rolls Order (1953) कहते हैं।

**संगठन** — म्यूनिसिपैलिटी में जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं। अलग-अलग म्यूनिसिपैलिटीजों में इनकी संख्या अलग-अलग है। पहले इन सदस्यों को निर्वाचित करने का अधिकार सब वर्गों को नहीं था। शिक्षा तथा सम्पत्ति की योग्यता रखी गई थी। परन्तु अब प्रत्येक व्यक्ति जिसका उस क्षेत्र में प्रादेशिक विधान-मंडल के निचे निर्वाचक नामावली में नाम है, निर्वाचक है। निर्वाचक होने के लिये वही योग्यता चाहिये जो विधान-मंडल के निर्वाचक होने के लिये है।

निर्वाचक को भारत का नागरिक होना चाहिये। उस पागल या दिवालिया न होना चाहिये। ऐसा व्यक्ति जिसको १ वर्ष से अधिक जेल हो गई हो, निर्वाचक नहीं हो सकता है। जेल जाने की उपयोगिता जेल में छूटने के ४ वर्ष बाद हट जायेगी। अगर सरकार चाहे तो इनमें पहले भी इसको दूर कर सकती है।

म्यूनिसिपैलिटीज का चुनाव साधारणतः ५ वर्ष के लिए होता है। परन्तु सरकार को यह अधिकार है कि वह चुनाव की म्पणित कर दे या अगर लोक हित में आवश्यक जान पड़े तो नियत समय से पहले ही चुनावों को करवा दे।

म्यूनिसिपैलिटी की सदस्यता के लिए प्रत्येक वह व्यक्ति खड़ा हो सकता है जिसका नाम निर्वाचक सूची में हो। परन्तु नीचे लिखे व्यक्ति सदस्यता के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं : कोडी, दीवालिये, वे लोग जिन्होंने म्यूनिसिपैलिटी का कर या श्रृण नहीं चुकाया है, सरकारी नौकरी, अवेतनिक मजिस्ट्रेट, मजिफ या मजिस्ट्रेट कलेक्टर।

जब म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव की घोषणा होती है तब एक निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है। इसमें सब बोटरी के नाम दर्ज किए जाते हैं। अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वह एक निश्चित तारीख तक इस मूल को १०) देकर सुधारवा सकता है। मारा नगर कुछ क्षेत्रों (wards) में बांटा

जाना है। प्रत्येक भूत म म म म म चुन जान है। यह प्राद्वित मन्थान निर्दिष्ट न केने। कि इन भूत का क्या मन्थान है तथा प्रत्येक में कितने मन्थान है।

एक निर्दिष्ट तारीख तक उम्मीदवारों को अपने निर्देशपत्र (Nomination Paper) प्रप्तान तथा अनुमोदन व हस्ताक्षर सहित जमा कर देना होता है। उसके साथ ५०) भा जमा करना पड़ता है। इन पत्रों की एक निर्दिष्ट दिन जांच की जाना है। अगर कोई गलती हुई या निर्देशपत्र गड़ कर दिया जाना है।

मन्थान न न मन्थान (चैप्टर) म होता है। बाट रिटनिंग प्रक्रम के सामन गिन तन है। जो अधिक मन पाना है वह निर्वाचित होता है। अगर चुनाव में कोई गलती होना इसकी रिपान जिम्मेदार के यहाँ होती है। इसके साथ एक निर्दिष्ट रकम भी जमा करनी होती है। अगर अपराध मिद हो जावे तो अपराधी ५ वष तक व लिय मन्थानता व अन्ते फिर खड़ा नहीं हो सकता है। अगर अपराध मिद न हुआ या जमा की हुई रकम दूसरे दू को दी जानी है। अगर मिद हो गया तो धिक्कार करने वाले का लोटा दी जाती है। अगर पूरा चुनाव ही ठीक प्रकार नहीं हुआ या द्वारा चुनाव जाना है। म्युनिसिपैलिटी म अपमरपका व मन्थान के लिये स्थान मरक्षित नहीं हाय। परन्तु इन्ति गों के मन्थान व रिट स्थान मरक्षित हाय। इसका म्युनिसिपैलिटी की कुछ मन्थान मन्थान म वही अनुपात होगा जो उम नगर में दन्ति वगों का जनमन्थान का वगों की कुल जनमन्थान म हागा।

प्रदाधिकारी — म्युनिसिपैलिटी का मुख्य अधिकारी प्रधान (Chairman) कहलाता है। उसका चुनाव मन्थान द्वारा होता है। वह चार वष के लिये चुना जाता है। वह चाह तो अपने पद में इस्तीफा दे सकता है। बाट उसके विरुद्ध अधिष्ठास या प्रस्ताव पास कर सकता है जिसको अगर राज्य सरकार मान ले तो प्रधान को पदत्याग करना पड़ेगा। प्रधान सरकार से एमे धक्कर पर वोट को भंग करने की प्राबल्य कर सकता है। अगर सरकार यह मान ले तो फिर नए चुनाव होंगे। सरकार भी प्रधान को उसका काम ठीक न होने पर हटा सकती है। प्रधान के अलावा एक या दो उप प्रधान भी होते हैं।

प्रधान धाटों की बैठकों म मभाषति का पद ग्रहण करता है। उसका नाम बोर्ड का शासन प्रबंध ठीक रहना है। उमे म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार है। कुछ अधिकारी बोर्ड की अनुमति से वह



निर्वाचन करता है। वह उनको हटा भी सकता है। प्रति वर्ष वह कमिशनर के पास बोर्ड की काम की रिपोर्ट भेजता है।

प्रधान के प्रतिरिक्त नगरपालिकाओं में उप-प्रधान भी होते हैं। इनका निर्वाचन सदस्यों द्वारा आपस में ही किया जाता है। साधारणतः दो उप-प्रधान होते हैं। एक को Senior Vice Chairman तथा दूसरे को Junior Vice Chairman कहते हैं।

जिन म्यूनिसिपैलिटीयों की आमदनी ५०,००० से अधिक है उनमें एक इन्जीनियरिंग ऑफिसर तथा एक मेडिकल ऑफिसर होता है। मेडिकल ऑफिसर प्रांतीय सचिव का होता है। कम आमदनी वाली म्यूनिसिपैलिटी में एक या दो प्रबैतनिक मंत्री रखे जाते हैं? इनके प्रतिरिक्त म्यूनिसिपैलिटी अन्य कर्मचारी जैसे इजीनियर, वाटर वर्क्स सुपरिन्टेन्डेन्ट, इलेक्ट्रिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, ओवर-मियर आदि भी नियुक्त कर सकती हैं। इनके प्रतिरिक्त कुछ अन्य कर्मचारी भी होते हैं जैसे मैनिटरो इन्स्पेक्टर, टोल इन्स्पेक्टर आदि।

**समितियाँ:**—म्यूनिसिपैलिटी अपना काम सुविधा-हेतु समितियों के द्वारा करती है। प्रत्येक समिति को कोई विभाग सौंप दिया जाता है। इनकी नियुक्ति बोर्ड करता है। इनमें कुछ को-ऑप्टेड (Co-opted) सदस्य भी हो सकते हैं। एक समिति में १० सदस्य तक होते हैं। प्रत्येक का एक सभापति भी होता है। मुख्य समितियाँ ये हैं। शिक्षा-समिति, स्वास्थ्य समिति, धर्म-समिति, वाटर-वर्क्स समिति, जुगी-समिति, वर्कम-समिति आदि। प्रत्येक समिति अपना काम बोर्ड के नियंत्रण तथा अनुमोदन में करती है।

**कार्य:**—म्यूनिसिपैलिटीयों के कामों को अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांट सकते हैं। मुख्य अनिवार्य कार्य निम्नलिखित हैं: (१) शहर के भीतर सड़कों का प्रबन्ध करना, उनकी सफाई तथा सफाई करवाना, उनमें रोशनी का प्रबन्ध करना। शहरों में जो गलियाँ होती हैं उनकी भी इसी तरह परवाह करनी होती है। (२) शहर में सफाई का प्रबन्ध करना, गन्दगी को हटवाने का इन्तजाम करना, नालियों की सफाई। औषधालय स्थापित करना तथा टीके लगवाना। (३) साफ पानी का प्रबन्ध तथा बाजार में सड़ी-गली चीजों को विक्रेता से रोकना। (४) शिक्षा का प्रबन्ध करना। (५) जन्म-मरण का हिमायत करना। (६) धर्म वृत्ताने का प्रबन्ध।

ऐच्छिक काम निम्नलिखित हैं— (१) जन साधारण के मनोरंजनार्थ पार्क, तान्दाव, आदि बनवाना। (२) पुस्तकालय, वाचनालय, ग्रन्थालय की स्थापना।

है। इन सब दुःराइयों को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि शिक्षा का अधिक प्रचार हो। चरित्रवान मनुष्य इन रास्चावों में आवें। मदस्य गण सेवा के लिये आवें न कि स्वार्थ-साधन के लिये। दलबन्दी की भावना भी दूर होनी चाहिये। इन झुंझावों की आर्थिक स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। उन्हें आमदनी बढ़ाने के नए साधन उपलब्ध होने चाहिये। उनके काम में अनावश्यक मरकाटों-हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिये।

**टाउन एरिया कमेटी**—उन नगरों में जिनकी आबादी २०,००० से कम तथा १०,००० से अधिक हो सरकार टाउन एरिया कमेटी स्थापित कर सकती है। इनके माधारणतः वही काम हैं जो कि बड़े नगरों में म्युनिसिपैलिटियों करती हैं। टाउन एरिया कमेटी में ५ से ७ सदस्य होते हैं। ये ४ वर्ष के लिये होते हैं। एक सभापति होता है जो या तो सदस्यों द्वारा चुना जाता है या सरकार द्वारा मनोनीत होता है। इन कमेटियों के अधिकार म्युनिसिपैलिटियों से कम हैं, इनके धाय के मापन भी कम हैं तथा इनमें सरकारी हस्तक्षेप है। इनका मुख्य काम सड़कों का निर्माण, मरम्मत, पानी रोखनी तथा स्वास्थ्य का प्रबन्ध है। इनको सरकार की ओर से तथा जिला बोर्डों से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। अन्य आय के साधन कर, नजूल भूमि से आमदनी तथा जुर्मानों से प्राप्त रहते हैं।

जिन नगरों की आबादी १०,००० से कम तथा ५,००० से अधिक हो बड़े सरकार नोटोफाइड एरिया कमेटी स्थापित कर सकती है। इस कमेटी में ३ या ४ सदस्य होते हैं जो या तो निर्वाचित या कमिशनर द्वारा मनोनीत या दोनों हो सकते हैं। एक सभापति होता है। इसके काम भी टाउन एरिया कमेटी की तरह होते हैं।

**इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट**—नगरों को एक योजना के अनुसार पुनर्निमित्त करने के लिए बड़े-बड़े नगरों में इसकी स्थापना की गई है। इसका काम सड़कों को चौड़ी करना, हवादार मकानों को बनवाने में सहायता देना, अत्यन्त घनी बसी हुई वस्तिर्यों का पुनर्निर्माण करना जिससे वहाँ हवा तथा सूर्य की रोशनी ठीक ढंग से आ सके इत्यादि बातों का प्रबन्ध करना है। इसके अतिरिक्त इसका काम गरीब जनता के रहने के लिये छोटे परन्तु सुले हुए मकानों का प्रबन्ध करना भी है। इन सब कामों के लिये यह राज्य सरकार के सम्मुख निर्माण सञ्चाली योजनाएँ रखती हैं।

इन ट्रस्टों का काम एक कमेटी द्वारा होता है। इसका एक प्रधान होता

हैं। कमेटियों के सदस्य मनोनीत होने हैं कुछ तो सरकार द्वारा तथा कुछ नगर की म्यूनिसिपैलिटी द्वारा। इनकी आय के मुख्य साधन ये हैं—भूमि बेचने में आमदनी, सहकारी सहायता तथा ऋण।

/ इन ट्रस्टों के काम में जनता में अधिक मतोप नहीं है क्योंकि इनकी योजनाओं को कार्यान्वित करने में बहुधा गरीबों की हानि हो जाती है। जो मकान तोड़ जाते हैं उनके ठिये बहुत कम पैसा मिलता है। मकान निर्माण के लिये भूमि बहुधा महगी बेची जाती है। इस प्रकार अमीर आदमी ही उस भूमि को खरीद सकते हैं। इसका फल यह होता है कि विराधेदारा की संख्या बढ़ती जाती है तथा मकान मालिकों की कम होती जाती है। परन्तु यह सब दोष होते हुए भी इन ट्रस्टों ने नगरपुनर्निर्माण में काफी लाभदायक काम स्वास्थ्य तथा सफाई की दृष्टि से किया है।

**वैण्टूनमैण्ट बोर्ड**—कुछ ऐसे नगर हैं जहाँ बि फौज की छावनों हैं। ऐसे नगरों में छावनी का क्षेत्र म्यूनिसिपैलिटी के अधिकार से बाहर रहता है। इन क्षेत्रों का प्रबन्ध वैण्टूनमैण्ट बोर्ड करता है। यह बाड़ रोशनी, पानी स्वास्थ्य तथा सफाई का प्रबन्ध करता है। इस प्रकार उगाव काम करीबन म्यूनिसिपैलिटी का ही हो रहा है। वैण्टूनमैण्ट बोर्ड के कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं तथा कुछ निर्वाचित। अधिकतर मनोनीत सदस्यों की ही संख्या अधिक होती है। उन्ना अध्यक्ष एक ऊँचा फौजी अफसर होता है। ये बोर्ड राज्य-सरकार के नियंत्रण में न होकर भारत के सेना विभाग के नियंत्रण में काम करते हैं।

**पोर्ट ट्रस्ट**—य उन नगरों में स्थापित है जो बड़-बड़ बन्दरगाह हैं जैसे कलकत्ता बम्बई मद्रास। पोर्ट ट्रस्ट का काम उन समस्याओं को हल करना है जो कि बन्दरगाहों की विशेषताएँ हैं। इसलिए इन नगरों में कारपोरेशन तथा इन्क्यूबमैण्ट ट्रस्ट के अतिरिक्त पोर्ट ट्रस्ट भी है।

पोर्ट ट्रस्ट में कुछ सदस्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तथा कुछ कारपोरेशन द्वारा भेजे जाते हैं। कुछ सदस्य व्यापारिक संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं। साधारणतः मनोनीत सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों से अधिक है। परन्तु कलकत्ते के पोर्ट ट्रस्ट में निर्वाचित सदस्यों की ही संख्या अधिक है। इनके सदस्यों का कमिशनर या ट्रस्टी बना जाता है। पोर्ट ट्रस्ट के निम्नलिखित मुख्य काम हैं माल का लादना तथा उतरवाना माल गादामा का बनवाना तथा देशभाल रखना, घाट बनवाना, यात्रियों के आने-जाने तथा ठहरने की सुविधाओं का ध्यान रखना स्वास्थ्य तथा सफाई का प्रबन्ध करना तथा व्यापार के लिये

नाव तथा जहाजों का प्रबन्ध करना आदि। पोर्ट ट्रस्ट के धन के मुख्य तीन स्रोत हैं—माल की लदाई तथा उतरवाई पर कर, जहाजों पर कर लगाये गये कर तथा गोदामों के किराये।

पोर्ट ट्रस्ट अपना काम ठीक ढंग से कर सकें तथा माल की हिकाजत रत नई इसलिए उनकी अपनी धुलिन रखने का अधिकार है। इन संस्थाओं में सरकारी हस्तक्षेप अन्य स्थानीय संस्थाओं से अधिक है।

**जिला बोर्ड**—जो काम नगरों में म्युनिसिपैलिटीज या टाउन एरिया कमिटीज आदि करती हैं वही काम ग्रामीण क्षेत्रों में जिला बोर्ड करते हैं। इन बोर्डों की स्थापना भारत में १८७० ई० के परचातु हुई। जिला-बोर्डों का कार्यक्षेत्र म्युनिसिपैलिटीज आदि क्षेत्रों से अलग है। उत्तर प्रदेश में केवल जिला बोर्ड ही थे परन्तु कुछ अन्य राज्यों में जिला बोर्डों के नीचे सब-डिविजनल बोर्ड या तालुका बोर्ड भी पाये जाते हैं। वही-वही इन सब-डिविजनल बोर्डों के नीचे लोकल बोर्ड भी हैं। जिला बोर्ड मारे जिले के ग्रामीण क्षेत्र की देखभाल के लिये हैं। सब-डिविजनल बोर्ड १००-५० गांवों की देखभाल करता है। लोकल बोर्ड केवल २-४ गांवों की देखभाल करता है।

**जिला बोर्डों का संगठन**—जिला बोर्डों के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार १९४८ ई० के पूर्व केवल पोर्ड ही व्यक्तियों को या क्योंकि निर्वाचक होने के लिये धन तथा शिक्षा की योग्यताएँ रखी गई थी। परन्तु अब ये सब व्यक्ति निर्वाचक हो सकते हैं जो कि ग्रामीण विधानसभा के लिए निर्वाचक होने की योग्यता रखते हैं। अर्थात् वयस्क मतदाता अधिकार हो गया है। इसलिए कोई भी २१ वर्ष की आयु से अधिक आयु वाला भारतीय नागरिक जो उस जिला बोर्ड की सीमा के अन्दर रहता हो निर्वाचक हो सकता है। परन्तु वह पागल, दिवालिया न हो। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति ६ महीने से अधिक काल की मजरा काटे हो और इन्ने काटे ५ वर्ष पूरे न हो चुके हों, या किसी निर्वाचक सम्बन्धी अपराध के कारण अप्रयोग घोषित किया गया हो, वह भी निर्वाचक नहीं हो सकता है। निर्वाचकों के लिये यह जरूरी है कि जिला बोर्ड की निर्वाचक नामावली में उनका नाम दर्ज हो। अगर उनका नाम गलती से छूट गया हो तो उसे चाहिये कि वह निश्चित तिथि के भीतर अपना नाम दर्ज करवा ले अन्यथा वह मतदान नहीं कर सकेगा।

१. यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि १ मई १९५९ से उत्तर प्रदेश में जिला बोर्डों का काम समाप्त हो गया है और इनके स्थान पर जिला परिषदों (ग्रन्तरिम) की स्थापना कर दी गई है।

प्रत्येक निर्वाचक को अधिकार है कि वह जिला-बोर्ड की सदस्यता के लिये सम्मोदित हो सकता है। केवल नीचे लिखी अयोग्यताएँ न होनी चाहिये —

(१) सरकारी नौकर हो। (२) जिला बोर्ड की नौकरी में हो। (३) गैर के किसी ठेके आदि में उसका हिस्सा हो। (४) वह अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा न जानता हो। (५) सरकारी नौकरी पान के अयोग्य हो। (६) नकारात्मक करने में रोक दिया गया। (७) पिछले वर्ष का कर न दिया हो।

जिला बोर्ड का कार्यकाल ३ वर्ष रहता है। परन्तु सरकार इस कार्य-काल को बढ़ा सकती है। वह साधारण चुनावों को भी स्थगित कर सकती है। कोई व्यक्ति एक बार में ही बोर्ड का सदस्य हो सकता है।

जिला बोर्ड में कई पदाधिकारी होते हैं। इनमें से कुछ तो वैतनिक होते हैं तथा कुछ अवैतनिक। कर्मचारियों में वरकें आदि के प्रतिरिक्त निम्नलिखित मुख्य हैं। मंत्री, स्वास्थ्य अफसर, इंजीनियर तथा मब-ओवरसियर, टैक्स अफसर कई शिक्षक, कुछ डाक्टर आदि।

बोर्ड का मुख्य कर्मचारी अध्यक्ष कहलाता है। मन् १९२२ के कानून के अनुसार उसका निर्वाचन बोर्ड के सदस्य करते हैं। परन्तु यह प्रथा मशायित कर दी गई है। अब उसका चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जावेगा। इस पद की अवधि ३ वर्ष रहती है। कोई भी जिला-बाड का निर्वाचक जिसकी आयु कम से कम ३० वर्ष हो इस पद के लिये खड़ा हो सकता है। इस प्रकार सीधा चुनाव रखने से बाड के अन्दर दलबन्दी कुछ मात्रा तक दूर हो जावेगी। अध्यक्ष अपने पद में इस्तीफा दे सकता है। उसके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है। अगर राज्य सरकार इस प्रस्ताव को मान ले तो अध्यक्ष का पद रिक्त करना पड़ेगा। ऐसा होने पर अध्यक्ष सरकार से बोर्ड भंग करा कर नए चुनाव की प्रार्थना भी कर सकता है। अध्यक्ष के प्रतिरिक्त सदस्यों में एक या दो अध्यक्ष चुन लिये जाते हैं। उनका कार्यकाल १ वर्ष होता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ये इसका कार्य करते हैं। अध्यक्ष का पद बहुत महत्वपूर्ण है। बाड की सफलता बहुत कुछ मात्रा तक उसके ऊपर भी निर्भर है। इसके वर्तमान निम्नलिखित हैं —

(क) वह बोर्ड की बैठक बुलाता है तथा इसमें सभापति का काम प्रथम करता है। यह बाड की कार्य-कारिणी समिति का भी सभापतित्व करता है।

बोर्ड की बैठकों में सिविल-मजिस्ट्रेट, इंजीनियर, इन्स्पेक्टर आफ् सूर्तस् आदि को परामर्श देने के लिये नियमित कर सकता है।

(ख) वह समस्त बोर्ड के शासन-प्रबन्ध की देख रेख करता है।

(ग) बोर्ड के कर्मचारियों के वेतन, उपलब्धियाँ, भत्ते, सेवा की शर्तें आदि प्रश्नों का निणय करता है।

(घ) वह बोर्ड के काम की रिपोर्ट तैयार करता है, हिमाय-विताय सम्बन्धी लेख तैयार करता है तथा गमिन्जर और जिलाबोर्ड के पान इनको भेजता है।

(ङ) अन्य के काम जो बोर्ड द्वारा इनको सौंपे जायें।

**जिला बोर्ड के कार्य:**—इनका ऐक्ट द्वारा अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बाँटा गया है। मुख्य अनिवार्य कार्य नीचे लिखे हैं:—

(१) नहरों, पुलों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत करना। इस प्रकार यातायात के साधनों की उन्नत करना। (२) नहरों के किनारे पेड़ लगाना तथा उनकी रक्षा करना। (३) औषधालय स्थापित करना तथा उनकी सहायता करना। (४) चेषक, हँजा, प्लेग आदि के टीके लगाना; (५) शिक्षा के लिये स्कूल आदि स्थापित करना। (६) अकाल से बचाव का प्रबन्ध तथा अकाल के समय सहायता करना। (७) कुएँ, तालाब, नहरों आदि का निर्माण तथा मरम्मत। (८) काँजी हीजों का प्रबन्ध करना। (९) मेलों, प्रदर्शनी आदि का लगवाना तथा प्रबन्ध। (१०) पहाव, मराय आदि का प्रबन्ध। (११) नदियों में बावों का प्रबन्ध। (१२) बाजार, पार्क, मनाषालय की स्थापना तथा प्रबन्ध। (१३) वृषि तथा पशुपालन के सम्बन्ध में शिक्षा प्रचार। (१४) हानिकारक व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाना। (१५) पीने के पानों का प्रबन्ध करना।

इन अनिवार्य कार्यों के अनिवार्य अधिक स्थिति अच्छी होने पर बोर्ड कुछ अन्य कार्य भी कर सकती है। जैसे, जनसंख्या की गणना, जन्म-मृत्यु का हिमाय रक्खना, ट्राम वेम आदि धलाना, नहरें बनवाना, नई सड़कों का निर्माण, प्रौढ़-शिक्षालयों का प्रबन्ध आदि। परन्तु माधोरण जिला बोर्ड की धार्धिक स्थिति इतनी खराब होती है कि वे अपने अनिवार्य कर्त्तव्य ही ठीक प्रकार नहीं कर सकते हैं।

**कार्य-सहृति:**—मुख्यार्थ जिला बोर्ड का काम कई कमेटियों द्वारा किया जाता है। इन कमेटियों को बोर्ड ही नियुक्त करता है तथा इनमें बोर्ड के

हा सदस्य होता है। हर कमटी में ३ या ४ सदस्य होते हैं। इन्हें मैं एक समी-  
पति चुना जाता हूँ। परन्तु कार्यकारिणी समिति का सम्भाषित बोर्ड का अध्यक्ष  
ही होता है।

जिला बोर्ड की समितियाँ मैं सबसे प्रभावशाली कार्यकारिणी-समिति कहूँगी।  
है। १९४१ ई० में पूर्व बोर्ड की एक अधि-समिति होती थी। अब इसके  
स्थान पर ही कार्यकारिणी समिति जाती है। उस समिति के सदस्य-बोर्ड का  
उपाध्यक्ष अध्यक्ष प्राड की अन्य समितियाँ व सम्भाषित तथा वाम व सदस्य  
ज्ञान वन हैं। अन्य सदस्य होते हैं। इस कार्यकारिणी समिति का सम्भाषित बोर्ड  
का अध्यक्ष होता है। बोर्ड का मंत्री ही इसका पद (ex officio) मंत्री  
होता है। यह समिति वह सब काम करती है जो कि बोर्ड द्वारा सौंपे।  
कमरे काम जा पहिले अधि-समिति करती थी अब यहाँ करती है। इसके मुख्य काम  
नीचे दिये हैं।

- (१) सदस्य के मत निश्चित करना।
- (२) किसी सदस्य के विरुद्ध दावा करना।
- (३) बोर्ड की किसी अन्य समिति में रिपोर्ट मागना।
- (४) तहसील समितियों की व्यवस्था का निश्चित करना तथा उन्हें  
अधिनियम देना।
- (५) बोर्ड के किसी कर्मचारी का ठके दान का अधिकार देना।
- (६) नए कर लगाने की योजना तैयार करना।
- (७) अन्य स्थानीय संस्थाओं में सहयोग करना।
- (८) आवश्यक कर्मचारियों के अनिवार्य अन्य कर्मचारियों का वस्तु  
तथा सन्ध्या निश्चित करना।
- (९) महका का निर्माण तथा सम्मत करना।
- (१०) बोर्ड के आय व्यय का चिट्ठा तैयार करना।

कार्यकारिणी समिति व अनिवार्य दूसरी मुख्य समिति शिक्षा-समिति है।  
इसका काम बोर्ड के शिक्षण का प्रबन्ध करना, अध्यापकों का नियुक्त करना  
प्रादि है। इसमें १२ सदस्य होते हैं। इनमें से आठ बोर्ड के सदस्य अपने में ही  
चुनते हैं। ४ बाहर से लिये जाते हैं। इन बाहर वाले सदस्यों में से ऐसे दो सदस्य  
हो सकते हैं जो कि इनके द्वारा के अनिवार्य शिक्षा विभाग के कर्मचारी हों।

बोर्ड के सदस्यों में से एक जिला बोर्ड के अध्यापको का प्रतिनिधि होगा। इस समिति का मंत्री डिप्टी-इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स होता है। यह समिति अपने सदस्यों में से एक सभापति चुन लेती है। यह अपने काम की रिपोर्ट बोर्ड के सामने रखती है। अगर यह समिति ठीक प्रकार कार्य न कर रही हो तो बोर्ड सरकार से इसकी भंग करने की प्रार्थना कर सकता है। इस समिति का कष्ट अत्यन्त उत्तरदायित्वपूर्ण है। इसलिए इसके सदस्यों को अपना काम ईमानदारी के साथ करना चाहिये।

बोर्ड जिले की विभिन्न तहसीलों में अपना कार्य ठीक प्रकार से करने के लिए तहसील कमेटियाँ नियुक्त करता है। किसी तहसील समिति में उस तहसील से निर्वाचित बोर्ड के सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त बोर्ड अगर चाहे तो उसमें अन्य सदस्यों को मनोनित कर सकता है। इन समितियों को वही अधिकार होंगे जो बोर्ड उनको देगा।

**बोर्ड की आय तथा व्यय**—जिला बोर्डों की आय के मुख्य साधन निम्न-लिखित हैं:—

(१) भवदाय—यह कर राज्य सरकार द्वारा मालगुजारी के साथ किसानों तथा जमींदारों से वसूल कर लिया जाता है तथा बाद में जिला बोर्ड को दे दिया जाता है। यह कर भूमि-कर पर उपकर है। १९४८ के संशोधन के पूर्व इसकी दर १ घाना रुपया थी परन्तु अब यह पहले से बड़ा हो गई है।

(२) जिला बोर्ड अपने क्षेत्र के अन्तर्गत रहने वाले किसी व्यक्ति या व्यापारी पर कर लगा सकती है। परन्तु उस व्यक्ति की आयवनी कम के कम २००) वार्षिक होनी चाहिये। इस कर की दर ४ पाई प्रति रुपये से अधिक नहीं हो सकती है।

(३) बाजारों, मेलों तथा नुमायश आदि पर कर।

(४) सवारियों पर टैक्स।

(५) पशुओं की विक्री पर कर।

(६) स्कूलों से फीस के रूप में आय।

(७) फैक्टोरियों पर टैक्स।

(८) पुलों तथा नावों से आय।

(९) पेड़ बेचने से आय।

(१०) भूमि बेचने से आय।

(११) दलालों, भादतियों आदि पर टैक्स।



(१२) काँजी हाउस से आय।

(१३) राज सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता।

(१४) ऋण।

इन विविध स्रोतों से हुई आमदनी को बोर्ड निम्नलिखित बातों पर व्यय करता है —

(१) सड़कों का बनाना, मरम्मत करना तथा उनसे बिनारे वृक्ष लगाना।

(२) पानी के लिये तालाब, कुओं का प्रबन्ध करना।

(३) नदियों पर पुल बनाना तथा उनकी मरम्मत करना।

(४) शिक्षालयों पर व्यय, जैसे शिक्षका का वेतन आदि।

(५) औद्योगिक तथा चिकित्सकी पर व्यय।

(६) कृषि, उद्योग आदि की उन्नति के लिये व्यय।

(७) मेन, पैठ, मूमायश आदि पर व्यय।

(८) बोर्ड के कर्मचारियों का वेतन।

जिला बोर्ड की आय उनके कामों के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कम है। यह उनके ठीक प्रकार से अपने उत्तरदायित्व को पूरा न करने का एक मुख्य कारण है। बोर्ड को अपनी आय बढ़ाने के लिये कुछ उपाय करना चाहिये उदाहरणार्थ बोर्ड को अपने क्षेत्र के अन्दर उद्योग-धंधों की स्थापना के लिये लोगों को उत्साहित करना चाहिये तथा उनकी सहायता देनी चाहिये। इनसे कर रूप में आमदनी होगी। बोर्ड अपनी आय बढ़ाने के लिये डेरी, पोल्ड्री फार्म आदि खोल सकते हैं। मले, पैठ प्रदर्शनियों से भी आमदनी बढ़ सकती है; बस रेल तथा अन्य सवारी के साधनों से भी आय बढ़ेगी। इनके अतिरिक्त राज्य-सरकार को अपनी आर्थिक सहायता में कुछ और वृद्धि कर देनी चाहिये।

सरकारी नियन्त्रण — स्थानीय संस्थाएँ यद्यपि अपने क्षेत्र के अन्दर स्वायत्त अधिकार का प्रयोग करती हैं तथापि इनके साथ साथ वे सरकारी नियन्त्रण से स्वतन्त्र भी नहीं हैं। नगर-पालिकाओं तथा जिला बोर्ड दोनों ही सरकारी नियन्त्रण में हैं। कमिश्नर तथा कलेक्टर को नगरपालिकाओं के कार्यों में हस्तक्षेप का अधिकार है। अधिकार इन कर्मचारियों को हमलिये दिये गये हैं ताकि स्थानीय संस्थाएँ अपने कामों को ठीक ढंग से करें। नगरपालिकाएँ समय समय पर जिलाधीश को अपने कामों की रिपोर्ट भेजती हैं। विवादग्रस्त मामला पर जिलाधीश अपनी राय दे सकता है। उसको इनके साथ व्यय पत्र पर भी परामर्श देने का अधिकार है। वह इनके कार्यों के सम्बन्ध में एक वार्षिक रिपोर्ट भी देता है।

जिला बोर्ड पर भी सरकारी नियन्त्रण है। कुछ सरकारी अधिकारियों को बोर्ड की बैठकों में शामिल होने का अधिकार है, जैसे कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, जिले के स्वास्थ्य विभाग का अधीनस्थ आदि। इनके प्रतिरिक्त प्रादेशिक अधिकारियों को बोर्ड के विभिन्न विभागों के निरीक्षण का अधिकार है। उदाहरणार्थ, शिक्षा विभाग का सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्वास्थ्य विभाग का प्रादेशिक अधिकारी निरीक्षण कर सकते हैं। इनके अलावा कमिशनर तथा मुख्यतः जिलाधीश को बोर्ड के कामों पर नियन्त्रण का अधिकार है।

उत्तर-प्रदेश की सरकार जिला बोर्डों की समस्याओं तथा उन साधनों और उपायों पर विचार कर रही है जिन्हें अपनाकर वह आय के प्रतिरिक्त साधनों की व्यवस्था कर सके। इस सरकार द्वारा नियुक्त दोनों समितियों अर्थात् स्थानीय विकास महापठार्थ अनुदान समिति (Local Bodies Grants-in-Aid Committee) तथा स्थानीय वित्त-समिति (Local Finance Enquiry Committee) ने इस विषय का अध्ययन किया और उनकी सिफारिशों उत्तर प्रदेशीय सरकार के विचाराधीन हैं। जिला बोर्डों के पुनर्गठन तथा उनकी आय के साधनों में वृद्धि में सुधार रखने के लिये एक उच्च स्थानीय समिति को नियुक्त की गई है। इसकी रिपोर्ट इस वर्ष के अन्त तक आ जावेगी।

**जिला परिषद्**—उत्तर प्रदेश में १ मई, १९५८ से जिला बोर्डों का विघटन कर दिया गया है। इनके स्थान पर एक अन्तरिम व्यवस्था की गई है और इसे हेतु एक अध्यादेश जारी किया गया है। यह “उत्तर प्रदेश अन्तरिम जिला परिषद अध्यादेश १९५८” कहलाता है। इसके अनुसार १ मई, १९५८ से उत्तर प्रदेश के मगसत जिला बोर्डों, (जिनके अन्तर्गत, मधोही का उप-जिला बोर्ड भी है) तथा इन बोर्डों की समस्त कमेटियों ने एक मई, १९५८ से अपने काम समाप्त कर दिया है। इन बोर्डों का नाम, इनके स्थान पर अन्तरिम जिला परिषदों की स्थापना तक, जिले के कलेक्टर द्वारा किया जायगा परन्तु जब जिलों में अन्तरिम जिला परिषदों का निर्माण हो गया है। इन परिषदों का सघटन निम्नलिखित है।

इस परिषद में निम्नलिखित सदस्य हैं—

- (१) जिले की जिला नियोजन समिति के सब सदस्य;
- (२) पाँच सदस्य जो कि उन व्यक्तियों के निर्वाचक-गण द्वारा निर्वाचित हैं, जो ३० अप्रैल, मन् १९५८ की मृतपूव जिला बोर्ड के सदस्य तथा प्रेसीडेंट थे अथवा जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट हों;

(३) वाराणसी के जिला परिषद में दो सदस्य भदोही के उपाजिहा वार्ड के सदस्य द्वारा भी निर्वाचित होकर भेजेगे ।

सरकार द्वारा बल्लेक्टर को आन्तरिक जिला परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है और वही इसका बैठकों का सभापतित्व करेगा । जिला बोर्ड का प्रेग्रीडेंट जिला परिषद का उप-सभापति होगा ।

ये जिला परिषदें जिला नियोजन समिति के मार्ग को समाहित करनी । आन्तरिक जिला परिषदों का कार अधिकारी जिले का जिला नियोजन अधिकारी होगा ।

जिला बोर्ड का बिपटन सरकार ने एक कमेटी की राय में किया जो कि इसी उद्देश्य से बिठायी गई थी । सरकार ने नियोजन के कार्य को बढ़ाने के उद्देश्य से यह पग उठाया है । इन जिला परिषदों का अन्तिम रूप क्या होगा यह अभी तब पूर्ण रूपसे ज्ञात नहीं है क्योंकि इन विषय में अभी कोई प्राथमिक नियम नहीं बना है । परन्तु यह समाचार है कि जिला कमिशन में दो सदस्य की व्यवस्था करने का विचार है । निम्नले सदन को जिला परिषद तथा उपरि सदन को जिला सदन का नाम दिया जाएगा । किन्तु चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होगा । इन वष इनके सम्पठन के सम्बन्ध में राज्य सरकार विधेयक प्रस्तुत करते वाली है ।

गौँ पचायत — भारत में पचायत व्यवस्था अत्यन्त प्रार्थित है । प्राचीन काल में तथा मध्यकाल में गाँवों में पचायत ही दैनिक जीवन के सभी प्रश्नों को हल करती थी । परन्तु अंग्रेजी राज्य की स्थापना के पश्चात् केन्द्रीयकरण की ओर अधिक ध्यान दिया गया । इसके फलस्वरूप गाँवों की स्वतन्त्रता जाती रही । गाँवों की अपने-आपके कार्य-क्रम में गाँवों को पुनः आत्मनिर्भर बनाने की ओर काफी जोर दिया । उनके प्रभाव के कारण ही कांग्रेस सरकार ने पचायतों की स्थापना की और बलम उठाया है ।

अंग्रेजी काल में भी प्रान्तों में पचायत ऐक्ट बने थे । उदाहरणस्वरूप, यू०पी० (अब उत्तर प्रदेश) में १९२० में ऐसा ऐक्ट बना था । प्रभाव में इससे पहले ही पचायत ऐक्ट बन चुका था । अन्य प्रान्तों में भी ऐसे ऐक्ट बने । परन्तु उस समय जो पचायतें स्थापित की गई थी उसकी स्वाधीनता केवल नाममात्र की थी । सरकारी कर्मचारियों का हस्तक्षेप बहुत अधिक था । इनके सदस्यों को तत्कालीन पनीनीत करना था । ऐसे अवस्था में यह स्वाभाविक था कि ये पचायतें कुछ

काम न कर सकी। जब मन् १९३७ में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल की स्थापना हुई तब सर्वप्रथम इस विचार को कार्यन्वित करने के लिये योजना बनाने का प्रस्ताव हुआ कि ग्रामों के स्वायत्तता के हेतु पंचायतों की स्थापना की जाये। परन्तु इसके पूर्व कि यह योजना बने कांग्रेस सरकार ने पद त्याग कर दिया। जब कांग्रेस फिर पदार्हूट हुई तब पंचायत स्थापना की योजना कार्यरूप में परिणत की गई। भारत के संविधान की ४०वीं धारा में यह कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिये प्रयत्न होगा, तथा उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिये आवश्यक हों। इसी को ध्यान में रखते हुये विभिन्न प्रादेशिक सरकारों ने इस दिशा में कार्य किया। इन पंचायतों का संगठन राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। पश्चिमी बंगाल के प्रतिरिक्त सभी राज्यों में तथा अधिकतर केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों में पंचायत ऐक्ट बन चुके हैं। उत्तर-प्रदेश में २७ दिसम्बर सन् १९४७ में ही पंचायत ऐक्ट पास हो गया था। पश्चिमी बंगाल तथा दिल्ली राज्य की सरकार इस प्रकार का अधिनियम बनाने जा रही हैं। समस्त देश के ५८१=१६ गाँवों में से २९४४६० अब तक पंचायत कानून के अन्तर्गत आ गये हैं। उत्तर प्रदेश के तो सभी गाँव (१२४३२३ गाँव) ३६१३९ गाँव पंचायतों के अन्तर्गत आ गये हैं।

**गाँव सभा :—**सन् १९४७ के अधिनियम द्वारा प्रत्येक गाँव में जिसकी जनसंख्या १००० या इससे अधिक थी एक गाँव सभा की स्थापना की गई थी। यदि किसी गाँव की आबादी उगमिक्रम थी तो उसे किसी पास के गाँव के साथ मिला दिया गया था। परन्तु यदि तीन मील की दूरी तक कोई अन्य गाँव न था तो उस दशा में गाँव के लिये १००० से कम जनसंख्या होने पर भी एक गाँव सभा स्थापित की गई थी। परन्तु दिसम्बर १९५४ में एक संशोधन पास किया है तथा गाँव सभाओं के संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये गये हैं। इस संशोधन के अनुसार प्रत्येक नम्बरी गाँव में अर्थात् जिसकी जनसंख्या २५० है, एक गाँव सभा होगी। जिन गाँवों की जनसंख्या २५० से कम है उन्हें निकटवर्ती गाँवों में मिला दिया जावेगा। उत्तर-प्रदेश में नम्बरी गाँवों की संख्या ५५००० से ६०,००० के बीच होगी।

**प्रत्येक गाँव का निवासी—**स्त्री तथा पुरुष—बिना किसी भेद भाव के इस सभा का सदस्य हो सकता है, भयर वह २१ वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। परन्तु निम्नलिखित व्यक्ति इसकी सदस्यता के अयोग्य हैं :

जो भारत के नागरिक न हो, जिसका अस्थायी विकृत हो तथा जो गाँव सभा क्षेत्र के साधारणतः निवासी न हो।

प्रत्येक गाँव-सभा का एक प्रधान तथा उप प्रधान होता है। गाँव सभा के पदाधिकारी तथा पचायत और न्याय पचायत के निम्नलिखित व्यक्ति सदस्य नहीं हो सकते हैं—वाड़ी, सरकारी नौकर, भीषण अपराध के लिये दण्डित अनन्मृत दिवालिये नैतिक अपराध तथा निर्वाचन मध्यगी अपराध के लिये दण्डित।  
 न का निर्वाचन के सभा के सदस्य अपने में से ही करेंगे। प्रधान की आयु कम से कम ३० वर्ष होनी चाहिये। इसका कार्यकाल २ वर्ष होगा परन्तु यह १ वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। गाँव सभा का उप प्रधान गाँव-पचायत के द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित होगा। उप प्रधान के पद की अवधि उसका चुनाव की तारीख से एक वर्ष होगी। प्रधान तथा उप प्रधान का अपने कार्यकाल में पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि विशेष रूप से बुलाई गई किसी गठक में जिसकी कम से कम १५ दिन पूर्व स नोटिस दी गई हो, उसके विरुद्ध उपस्थित तथा मत देते हुए सदस्यों के दो तिहाई बहुमत द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पाम कर दिया जावे। प्रत्येक गाँव सभा की एक कार्य-नारिणी होती है। इसको गाँव पचायत कहते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव गाँव सभा अपने सदस्यों में से करती है।

गाँव सभा की बैठक के लिये कम से कम सदस्य सभा का पाँचवाँ भाग उपस्थित होना चाहिये। वष में इसकी दो बैठकें होती हैं—एक तो रबी की फसल के बाद तथा दूसरी खरीफ की फसल के बाद। इनकी प्रथम रबी की बैठक तथा खरीफ की बैठक कहते हैं। इनके अतिरिक्त सभा की असाधारण बैठक भी बुलाई जा सकती है। यदि कुल सदस्य सभा का पाँचवाँ भाग ऐसी बैठक की माँग करेता ३० दिन के अन्दर ऐसी बैठक सभापति द्वारा बुलाई जावेगी।

गाँव सभा के निम्नलिखित मुख्य कर्तव्य हैं —

(१) ग्राम विकास की योजना बनाना उसको स्वीकार करना तथा इस काम की देख रेख करना।

(२) खरीफ की बैठक में आगामी वर्ष के आय-व्यय के अनुमानों तथा निर्माण कार्य के प्रस्तावों पर विचार करना तथा उसे स्वीकार करना। रबी की बैठक में गत वर्ष के आय व्यय के ऊपर विचार होता है।

(३) अपने प्रधान, उप प्रधान, गाँव पचायत तथा न्याय-पचायत के सदस्यों का चुनाव तथा उन्हें पद से हटाना।

(४) गाँव कोष की स्थापना करना तथा उसकी देख-रेख और वार्षिक लेखा-परिक्षण (आडिट) करना।

(५) पंचायत की कार्य के लिये अपने क्षेत्र के अन्तर्गत कर, शुल्क आदि लगाता ।

**गाँव-पंचायत**—यह गाँव समा की कार्यकारी निति है। इसका चुनाव गाँव समा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका काम गाँव-समा से सम्बन्धित दैनिक कार्यों को करना है। गाँव-समा तो साल भर में केवल दो ही बार मिलती है। इसलिए गाँव-पंचायत का हो सब काम करने होते हैं। इसके सदस्यों की संख्या गाँव की जनसंख्या पर निर्भर है। इसलिए अलग-अलग गाँवों में यह अलग-अलग होगी। गाँव पंचायत में प्रधान तथा उप-प्रधान के अतिरिक्त कम से कम १५ तथा अधिक से अधिक ३० सदस्य हों सकते हैं। गाँव-समा के नभारति ही इसके भी प्रधान तथा उप-प्रधान होते हैं। १००० जन-संख्या तक १५ सदस्य, २००० जन-संख्या तक २० सदस्य, ३००० जन-संख्या तक २५ सदस्य तथा ३००० जनसंख्या से ऊपर ३० सदस्य होंगे। गाँव समा के प्रधान तथा उप-प्रधान ही गाँव पंचायत के पहले प्रधान तथा उप-प्रधान होंगे। गाँव पंचायत के प्रधान व उसके सदस्यों के कार्य की अवधि साधारणतः ५ वर्ष होगी। परन्तु राज्य-सरकार विशेष परिस्थितियों में इसे ६ वर्ष कर सकती है। उप-प्रधान के कार्यकाल की अवधि केवल एक वर्ष ही है।

पंचायतों के लिए चुनाव समुक्त-निर्वाचन प्रणाली द्वारा होंगे। परन्तु परिणमित जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। निर्वाचन के हेतु क्रांति गाँव निर्वाचन क्षेत्रों में बाँटा जाएगा। जिलाधीन एक निर्वाचन-अवधि तथा कुछ उप-निर्वाचन अवधियों को नियुक्त करता है। इनके अतिरिक्त पोलिंग-अफसर भी होते हैं। मतदान गुप्त नहीं है परन्तु हाथ उठाकर दिया जाता है। इनको पोलिंग-अफसर गिन लेता है तथा निर्वाचन अवधि को इसकी सूचना देता है। बराबर नष्ट मिलने पर इसका निर्णय हादरी द्वारा किया जाता है।

गाँव-पंचायत की प्रत्येक नहीं के कम से कम एक बैठक होनी चाहिए। प्रत्येक पंचायत अपने सदस्यों की विविध कार्यों को करने के लिये छोटी-छोटी समितियाँ बना सकती है। इन्हें कार्य-समिति में सहायित्व रहती है। ये समितियाँ निम्नलिखित हैं—

१. शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, नफाई समिति, काम रक्षा समिति, विकास समिति तथा अन्य समिति।

२. पंचायत के कार्य :—इन कार्यों को दो भागों में बाँटा जा सकता है—  
अनिवार्य तथा ऐच्छिक।

प्रत्येक गाँव पंचायत का अपने क्षेत्र में निम्नलिखित विषयों पर अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार प्रबन्ध करना होगा। ये गाँव-पंचायत के अनिवार्य कार्य हैं —

(१) ग्राम गलियों को बनवाना, मरम्मत करना, ठीक दशा में रखना तथा उनकी सफाई और रोशनी का प्रबन्ध करना,

(२) हाइड्रो महायता;

(३) सफाई का प्रबन्ध तथा छूत की बीमारियों को फैलने से रोकने का प्रबन्ध,

(४) गाँव-सभा की इमारतों या अन्य सम्पत्ति की देखभाल करना;

(५) जन्म, मृत्यु तथा विवाह का रजिस्टर रखना;

(६) ग्राम गलियों, सार्वजनिक-स्थानों तथा सार्वजनिक सम्पत्ति पर से हस्तक्षेप (encroachments) को दूर करना;

(७) मनुष्य तथा पशुओं की छातों को फेंकने के लिये स्थान निश्चित करना;

(८) अपने क्षेत्र के अन्दर मेला, हाट तथा बाजार का प्रबन्ध करना;

(९) बालक तथा बालिकाओं के लिये प्रारम्भिक स्कूलों का प्रबन्ध करना;

(१०) सार्वजनिक-चरागाहों तथा भूमि का अपने क्षेत्र के निवासियों के हितार्थ प्रबन्ध करना।

(११) सार्वजनिक कुओं, तालाबों आदि को पीने, कपड़ा धोने तथा नहाने के पानी के लिये बनाना, मरम्मत करना तथा उन्हें ठीक दशा में रखना,

(१२) नई इमारतों के बनाने के लिये तथा पुरानी इमारतों के मरम्मत के लिये नियम निर्माण करना;

(१३) खेती, व्यापार तथा उद्योगों की महायता करना।

(१४) आग बुझाने का प्रबन्ध करना;

(१५) दीवानी तथा फौजदारी न्याय का प्रबन्ध और पंचायती अदालत के लिये पंचों को चुनना;

(१६) मनुष्यों तथा पशुओं की गणना का प्रबन्ध;

(१७) शिशु-केन्द्रों का प्रबन्ध;

(१८) खाद इकट्ठा करने लिये स्थान नियत करना;

(१९) कानून द्वारा सौंपा कोई अन्य कार्य करना;

(२०) कुमायूँ की पहाड़ी पट्टियों में वर्षा एक तथा केंसर-ए-हिन्द जंगल तथा देनाप भूमि, पानी के नालों और पनघटों का प्रबन्ध करना;

इन उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी गाँव पंचायत कर सकती है। ये इसके ऐच्छिक कार्य हैं।

(१) ग्राम रास्तों के दोनों ओर तथा सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ लगाना और उनकी रक्षा करना;

(२) पशुओं की नस्ल सुधारने का तथा उनकी चिकित्सा का प्रबन्ध;

(३) गडों को भरवाने का प्रबन्ध;

(४) स्वयं सेवक दल की स्थापना जो कि गाँव को देखभाल करेगा तथा पंचायती प्रदालत को उसके कार्यों में सहायता देगा।

(५) खेतिहरों को सरकारी ऋण लेने में सहायता करना तथा उसको उतारने में उसकी राय देना;

(६) अच्छे बीज तथा खेत के ओजार रखने के लिये भंडार बनाना तथा सहकारिता की उत्पत्ति;

(७) अकाल तथा अन्य विपत्तियों के विरुद्ध सहायता का प्रबन्ध करना;

(८) जिला बोर्ड से उन कार्यों को रोकने के लिये कहना जो कि गाँव समेत के अधिकार के बराबर हैं;

(९) प्राबादी क्षेत्र को बढ़ाना;

(१०) पुस्तकालय तथा वाचनालय को बनाना तथा उनका प्रबन्ध करना;

(११) अखाड़ा, क्लब आदि मनोरंजनार्थ स्थापित करना;

(१२) ताद तथा कूड़े के इकट्ठा करवाने तथा फेंकवाने का प्रबन्ध;

(१३) प्रायादी के २२० गज के अन्दर चमड़े की रमाई आदि ध्वन्द करना या उसको नियंत्रित करना;

(१४) विभिन्न सम्प्रदायों के बीच सद्भावना बढ़ाने के लिए संस्थाएँ स्थापित करना;

(१५) सार्वजनिक रेडियो तथा ग्रामोफोन का प्रबन्ध करना;

(१६) गाँव बालों के नैतिक या भौतिक उत्थति के अन्य कोई कार्य;

(१७) जिलाबोर्डों के अनुसार गाँव के हित में ऐसे काम करना जो जिला-बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में हैं;



(१८) कोई ऐसे अन्य कार्य करना जिन पर खर्च करने की प्रादेशिक सरकार गाँव सभाया को आज्ञा दे दे ।

१ (१९) आबारा मवेशिया, आबारा कुत्ता जंगली पशुआ और बन्दरा को पकड़ने और उनका निवर्तन का प्रवन्व करना

बिहार सरकार ने ग्राम स्तर पर प्रधानता की आधार भूत इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों को मान्यता दे दी है और उसने जिलाधीशों को प्रादेश दिया है कि स्थानीय विरास के सारे कार्य पंचायतों के द्वारा कार्यान्वित होने चाहिये । इसके अतिरिक्त बिहार राज्य सरकार ने राजस्व बसूली का कार्य भी पंचायतों के हाथ में सौंपने का निश्चय किया है । १९२५ पंचायतों को कमोशन के आधार पर यह कार्य दिया भी जा चुका है ।<sup>१</sup>

**अधिकार** — इन अनिवार्य तथा ऐच्छिक कार्यों को करने के लिए गाँव पंचायतों को कुछ अधिकार दिये गये हैं । वे निम्नलिखित हैं —

(१) गाँव पंचायत को अपने क्षेत्र के अन्दर समस्त सार्वजनिक जल तथा पल मार्गों पर अधिकार है अगर वे प्रादेशिक सरकार या जिलाबोर्ड के अधीन न हों । जल तथा पल मार्गों की रक्षा करना, मरम्मत करना या नये मार्ग बनवाना गाँव पंचायत के अधिकार में है । यह किसी रास्ते को चौड़ा करवा सकती है, यह अगर उचित समझे तो बन्द भी करवा सकती है । रास्तों पर आई हुई ताड़ियों तथा पेडा की डालियों को कटवा सकती है । इसको यह भी अधिकार है कि किसी सोने के पानी को बपटा घोलने नहाने आदि के लिये इस्तेमाल करने से रोक लगा दे ताकि पानी पीने के लिए गन्दान होने पाये ।

(२) गाँव पंचायत मफाई के लिये किसी भूमि या इमारत के स्वामी को यह आज्ञा दे कि वह अपनी भूमि या इमारत से गन्दगी को हटाये, मरम्मत करे, गालियाँ बनावे, गड्ढा को भरवाये, कुआँ को साफ करवाये या उसको भरवा दे, घास काड़ियों को कटवाये तथा कूड़ा करकट आदि को साफ करे । परन्तु इसी आज्ञा दते समय पंचायत उस मनुष्य की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखेगी तथा उसे काफी समय देगी । जिस मनुष्य को ऐसी नोटिस मिलेगी वह ३० दिन के अन्दर जिला मेडिकल आफसर से इसके विरुद्ध अपील कर सकता है जिसका नण्य इस मामले में अंतिम होगा ।

(३) बालक तथा बालिकाओं को प्रारम्भिक शिक्षा-हेतु स्कूल स्थापित करने तथा उसकी रक्षा करने का अधिकार है। गाँव वालों के स्वास्थ्य के लिये यूनानो या आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित कर सकते हैं।

(४) अगर गाँव-पंचायत अपने क्षेत्र में रहने वाले किसी यादमी से किसी सरकारी कर्मचारी, जैसे भूमीन, सिपाही, पटवारी, टीका लगाने वाले, सिंचाई विभाग के पटरोल या अन्य किसी विभाग के चपरासी, के विरुद्ध कोई दुर्बिचार की रिपोर्ट पावे तथा उसके विरुद्ध पंचायत के पास प्रमाण हो, तो वह उस कर्मचारी की निकायत उचित अधिकारी के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये कर सकती है।

(५) अपने क्षेत्र के अंदर, प्रादेशिक सरकार की आज्ञा होने पर, गाँव-पंचायत को अपने कर्तव्यों के पालन करने में सरकारी कर्मचारियों की सहायता का अधिकार है।

गाँव कोष :—प्रत्येक गाँव-सभा का एक कोष होता है। इसी में से पंचायत अपने कर्तव्यों का पूरा करने के लिये व्यय लेती है। इस कोष में नीचे लिखी रकमें जमा होती हैं।

- (१) पंचायत राज ऐक्ट द्वारा लगाये गये करों से प्राप्त रकमें ;
- (२) प्रादेशिक सरकार द्वारा गाँव सभा को सौंपी गयी रकमें ;
- (३) इस ऐक्ट के लागू होने के पूर्व की पंचायतों की बची हुई रकम ;
- (४) किसी म्यागालय की आज्ञा से इस कोष में जमा की हुई रकम ;
- (५) कृषि, पशुओं की लाशों, गोबर आदि की बिक्री से प्राप्त रकम ;
- (६) नजूल की सम्पत्ति या भूमि की धामदनी का वह भाग जो प्रादेशिक सरकार पंचायत को दे दे ;

- (७) जिला बोर्ड या अन्य अधिकारियों द्वारा दी हुई रकमें ;
- (८) ऋण या दान से प्राप्त रकम ;
- (९) प्रादेशिक सरकार द्वारा मंजूर कोई अन्य रकम ;

पंचायत राज्य अधिनियम के अनुसार गाँव सभा को अपने क्षेत्र में तीन प्रकार के कर लगाने के अधिकार दिये गये हैं : (१) गालमुजारी तथा लगान पर कर जो कास्तकार के लगान पर अधिक के अधिक एक आना प्रति रुपया है, (२) व्यापार और घरे पर कर, जिसके अनुसार ५०० रुपये से अधिक की धामदनी वाले पर एक आना रुपया लिया जा सकता है; (३) मकान कर जो उष्युक्त दोनों कर न देने वालों व्यक्तिगत से ही लिया जा सकता है। इसके

प्रतिरिक्त गाँव सभा की अपने क्षेत्र में मजदूरी तथा कपड़ा, गल्ला और चीनी के व्यापारिया और सबारिया की गाड़ियाँ रखने वालों, आदि से भी साधारण अनुमति शुल्क (लाइसेंस फी) लेने का अधिकार है।

गाँव सभाओं की आय बढ़ाने के उद्देश्य से फीस में कुछ नई मदें बढ़ा दी गई हैं। गाँव सभा के निपट्यार में चलाए जाने वाले बाजार हाट या मेले में माल बेचने वाला पर बित्री फीस लगायी जा सकेगी यदि ये व्यापार या पेशा सबंधी कर न देते हों। जानवरा की बित्री पर रजिस्ट्री फीस और कटाई छाना या लेने लगाने के स्थानों के प्रयोग की फीस भी ली जा सकती है। जिन गाँव सभाओं की ओर से पानी देने या व्यक्तिगत सौचालय या नालियों की सफाई करने का प्रबन्ध होगा वहाँ पर पानी तथा सफाई टैंक्स भी लगाया जा सकेगा। गाँवों में चलते फिन्ते सिनेमा प्रदर्शन पर भी फीस लगेगी।

गाँव-पंचायतों की आमदनी के स्रोत बहुत साधारण हैं। उनके कर्तव्यों के अनुपात से उनकी आय बहुत कम है। इससे यह होगा कि पंचायत अपने कर्तव्यों का उचित प्रकार पालन नहीं कर सकेगा। अगर वे कुछ लाभदायक काम कर सकती हैं तो यह आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रादेशिक सरकार को उनकी आमदनी बढ़ाने के माध्मन प्रस्तुत करने चाहिये। यह सत्य है कि नवीनतम संशोधन द्वारा इस दिशा में कुछ सुधार हुये हैं।

न्याय पञ्चायत — पञ्चायत राज अधिनियम द्वारा न्याय पञ्चायतों की भी स्थापना की गई है। इनका उद्देश्य यह है कि गाँव निवासी अपने छोटे-मोटे झगडा का निणय स्वयं ही कर लें। उनका व्यय तथा परेशानी बच जाय।

पञ्चायत राज अधिनियम में हुए नवीनतम संशोधनों के द्वारा जैसा हम देख चके हैं गाँव सभा क्षेत्रों में परिवर्तन कर दिया गया है। इसी कारण न्याय पञ्चायतों के क्षेत्रों में परिवर्तन कर दिया गया। संशोधन पूर्व साधारणतः तीन से पाँच गाँव सभाओं की मिलाकर एक न्याय पञ्चायत की स्थापना की जाती थी। अब साधारणतः ९ गाँव सभाओं पर एक पञ्चायत होगी परन्तु विशेष परिस्थितियों में ५ से १२ गाँव सभाओं पर एक न्याय पञ्चायत हो सकती है।

प्रादेशिक सरकार या निर्धारित अधिकारी प्रत्येक जिले को कई मण्डलों (Circle) में बाँटगा तथा इनमें से प्रत्येक में एक न्याय पञ्चायत होगी। न्याय पञ्चायतों के लिये प्रत्येक गाँव सभा अपने यहाँ से गाँव पञ्चायत के लिए निर्धारित सदस्यों के प्रतिरिक्त ५ या इससे कम जितने अधिनियम के अनुसार निर्दिष्ट किए जायें, व्यक्तियों को और निर्वाचित करगी। इसके पञ्चायत निर्धारित

अधिकारी उन निर्वाचित व्यक्तियों में से उतने पड़े-लिखे व्यक्तियों को जितने वह गांव सभा न्याय पञ्चायत के लिये भेजने की अधिकारी हैं, वह पञ्च मनो-नीत कर देगा ।

प्रत्येक न्याय पञ्चायत में पञ्चों की संख्या ऐसी रखी जायगी जो ५ से नोट जाय अर्थात् १५, २० या २५ । एक से लेकर ६ गांव सभाओं तक वृद्धि न्याय पञ्चायत के पञ्चों की संख्या १५, ७ से लेकर ९ तक की संख्या २० तथा ९ से अधिक गांव सभाओं वाली न्याय पञ्चायत के पञ्चों की संख्या २५ होगी । इस संख्या का गांव सभाओं के मध्य विभाजन इस प्रकार होगा, यदि पाँच सभाओं की न्याय पञ्चायत है तो उसमें १५ सदस्य होंगे अतएव प्रत्येक में ३-३ पच चुने जायेंगे । यदि इन सभाओं की संख्या ६ है तो प्रत्येक सभा में २-२ पच चुने जाएँगे और शेष जो ३ बचता है उसके लिये ऐसे गांव सभाओं में से एक-एक पच चुना जायगा जिनकी जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है ।

प्रत्येक न्याय पञ्चायत में एक सरपंच तथा एक सहायक सरपंच होंगा । इनका चुनाव पञ्चायत अपने में से ही करेगा । इन अधिकारियों के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें बाल्यवाहियों को लिखने की योग्यता हो । प्रत्येक पच के पद की अवधि उसके चुनाव की तारीख से ५ वर्ष है परन्तु राज्य सरकार इसे १ वर्ष बढ़ा सकती है । पच को अधिकार है कि वह इस अवधि के पूर्व पद त्याग सकता है । वह विशेष दत्ता में अपने पद से राज्य सरकार या निर्धारित अधिकारी द्वारा हटाया भी जा सकता है ।

सरपंच न्याय पञ्चायत के सामने अपने जाने वाले समस्त वादों और जाँच के निबटारे के लिए पाँच-पाँच पचों को बेंच बनाएगा । इन बेंचों का निर्माण स्थाई होगा । कोई पच, सरपंच या सहायक किसी ऐसे वाद (मामले) की सुनवाई में या जाँच में भाग नहीं लेगा जिसमें वह या उसका निकट सम्बन्धी, मालिक, नीकर, कृषी, ऋणदाता या रासी एक पक्ष में हो या जिसमें उनमें से किसी का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ हो ।

न्याय-पञ्चायतों के अधिकार —पंचायत राज्य ऐक्ट (१९८७) के ग्राम पञ्चायत ऐक्ट के नीचे पञ्चायतों के अधिकार अत्यन्त साधारण थे । परन्तु इस नये ऐक्ट द्वारा इन अधिकारों में काफी वृद्धि की गई है । न्याय पञ्चायतों के निम्नलिखित अधिकार हैं :

(१) इस ऐक्ट के अधीन पेश किया हुआ फौजदारी मुकदमा, जान्ते फौजदारी ( Criminal Procedure Code ) के किसी बात के होते

हुए भी उस सचिव के सरपंच के सामने पक्ष होगा जिसमें कि अपराध किया गया हो ।

निम्नलिखित फौजदारी मामले पंचायती अदालत में पेश हो सकते हैं —

१. फौज में न होते हुए भी फौजी पोशाक पहनने का अपराध, लड़ाई जगड़ा करना, सम्मन की तारीफ करने से छिप जाना, सरकारी कर्मचारी के प्रश्नों का उत्तर न देना, रास्ते में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना पानी की टकी या सोते को गन्दा करना आग, जानवर आदि के मामलों में प्रसावधानी, गन्दी क्रियाएँ या गाने, भूमि तथा भूकान में अनाधिकार प्रवेश करना, १० रुपये तक की चोरी इत्यादि ।

पंचायती अदालत को बंद की सजा देने का अधिकार नहीं है । यह केवल जुर्माना कर सकती है । इनका १०० तक जुर्माना का अधिकार है । पंचायती अदालत अगर यह समझे कि किसी व्यक्ति में क्षान्ति भग होने का भय है तो वह उससे १०० मजलका १५ दिन तक के लिए ले सकती है । परन्तु न्याय पंचायत पुराने अपराधियों के मुकदमों की सुनवाई नहीं कर सकती है ।

(२) न्याय पंचायत निम्नलिखित प्रकार के किसी दीवानी मुकदमे की सुनवाई कर सकती है यदि उसका मूल्य एक नौ रुपया से अधिक न हो ;

(क) कोई दीवानी मुकदमा जो अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सविदा क प्रतिरिक्त किसी अन्य सविदा पर दाय धन के लिये हो ;

(ख) किसी चल सम्पत्ति या उसकी कीमत वापसी के लिए कोई दीवानी मुकदमा ;

(ग) किसी चल सम्पत्ति की दोषपूर्ण ढंग से लेने या क्षतिग्रस्त करने के लिए कोई दीवानी मुकदमा ;

(घ) अनाधिकार पशु प्रवेश के द्वारा उत्पन्न क्षतियों के लिये कोई दीवानी मुकदमा ;

राज्य सरकार यदि चाहे तो न्याय पंचायत को ५०० रुपये मूल्य तक के दीवानी मुकदमों की सुनवाई का अधिकार दे सकती है ।

(३) माल के मुकदमों में न्याय पंचायत को निर्णय देने का अधिकार नवीनतम मसौदा द्वारा नहीं रह गया है । उन माल के मुकदमों में जो इस अधिनियम द्वारा इनके क्षेत्र के अन्तर्गत हैं, यदि उनमें कोई विरोध नहीं है

(uncontested) है, तो न्याय पंचायतों को परीक्षण (enquiry) का अधिकार है। परन्तु उन मुकदमों में जिसमें विरोध (contested) है यह अधिकार भी नहीं है।

इन अदालतों के निर्णय की अपील नहीं होती है। उनमें निर्णय बहुमत से होता है। इनके फैसलों की, कुछ विरोध दफ्तरों में मुन्सिफ या सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट, निगरानी कर सकते हैं।

**सरकारी नियन्त्रण :—**ग्रन्थ स्थानीय संस्थाओं की तरह गांव पंचायतों भी सरकारी नियन्त्रण में हैं। पंचायत ऐक्ट में यह बतलाया गया है कि प्रादेशिक सरकार का क्या नियन्त्रण है। इस नियन्त्रण का उद्देश्य यह है कि पंचायत अपने अधिकारों का दुरुपयोग न करें।

प्रादेशिक सरकार गांव सभा को संचल सम्पत्ति, भूमि, आदि का निरीक्षण कर सकती है। गांव-पंचायत के किसी कामकाज को रोक सकती है। गांव सभा, गांव-पंचायत या पंचायती-अदालत से सम्बन्धी किसी भी मामले की जांच पड़ताल भी करवा सकती है। प्रादेशिक सरकार को यह भी अधिकार है कि वह किसी गांव पंचायत या पंचायती अदालत को अधिकारों के दुरुपयोग करने पर भंग कर सकती है। इसी प्रकार इनके किसी सदस्य को भी प्रादेशिक सरकार सदस्यता से हटा सकती है। सरकार द्वारा नियुक्त उचित अधिकारियों को यह शक्ति भी है कि गांव पंचायत या पंचायती अदालत द्वारा प्राप्त किसी प्रस्ताव या आज्ञा को अगर उसमें जनता की हानि होती है तो रद्दवा दे।

सरकार ने इन संस्थाओं के निरीक्षण के लिए पंचायती इस्पेक्टर, पंचायत मजिस्ट्रेट तथा एक डायरेक्टर की नियुक्ति की है।

**भारतीय स्थानीय संस्थाओं पर एक दृष्टि** —भारत में स्थानीय संस्थाओं का कार्य अभी तक सराहनीय नहीं रहा है। सार्वजनिक सेवा की ओर कम ध्यान तथा अपने स्वार्थों की ओर अधिक ध्यान, साधारणतः इनका काम रहा है। अंग्रेजी काल में ये स्थानीय संस्थाएँ बहुत ही सीमित क्षेत्र के अन्दर काम कर सकती थीं। परन्तु इस सीमित क्षेत्र में भी इन्होंने कोई विशेष काम नहीं किया। इन संस्थाओं में आये दिन भ्रष्टाचार, घूस खोरी आदि के उदाहरण मिल सकते हैं। दलबन्दी, जातिभेद-हीनता, स्वार्थपरता आदि के कारण ये संस्थाएँ महत्वपूर्ण काम नहीं कर सकी हैं। परन्तु हमारा यह कर्तव्य है कि इन दोनों को दूर किया जावे, जिससे कि ये संस्थाएँ हमारे राष्ट्रीय जीवन में अपना पूरा भाग ले सकें। इसके लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं :—

सबसे पहिले आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा का देश में अधिक प्रचार हो। जनता अगर शिक्षित होगी तो शीघ्र बहुकावे में नहीं आवेगी। उसमें अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना जागृत होगी तथा वह सार्वजनिक कामों में उदासीन नहीं रहेगी अपितु उसमें भाग लेगी। इसका फल यह होगा कि देश में जागरूक जनमत बनेगा। इसके फलस्वरूप इन समस्याओं में वे व्यक्ति होंगे जो सार्वजनिक सेवा की ओर अधिक ध्यान देंगे तथा स्वार्थ-साधन की ओर कम।

दूसरी आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने स्वार्थों को सब से ऊपर नहीं रखें। अगर हम केवल अपने स्वार्थों का ही ध्यान रखेंगे तो समाज तथा देश की भलाई नहीं कर सकते हैं। सामाजिक जीवन के बहुत से दोष इस कारण उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने को समाज का केन्द्र समझता है। इस प्रकार की भावना सहयोग के स्थान में संघर्ष को जन्म देती है, तथा स्थान के स्थान में स्वार्थ को।

तीसरी आवश्यकता इस बात की है कि जो लोग स्थानीय समस्याओं में निराश्रित के लिए उम्मीदवार होते हैं वे संचरित हो तथा उनमें नैतिक भावना का अभाव न हो। क्योंकि नैतिक भावना का अगर अभाव होगा तो स्थान की प्रवृत्ति जाती रहेगी।

चौथी आवश्यकता यह है कि सरकार को स्थानीय-समस्याओं के क्षेत्र में, अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। अगर स्थानीय-समस्याओं की यह भावना हो जावे कि उनकी स्वतन्त्रता केवल नाम मात्र की है तो वे उत्तरदायित्वहीन हो जावेंगे।

अन्तिम आवश्यकता यह है कि इन समस्याओं के आग्रह के साधनों में वृद्धि होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सी बातें तो ये सरकारें इसी कारण नहीं कर पाती हैं क्योंकि इनके पास आवश्यक साधन नहीं हैं।

### प्रश्न

(१) म्युनिसिपैलिटीज के क्या अधिकार तथा कर्तव्य हैं? उनको क्या समस्याएँ हैं?

(२) उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों के संगठन तथा अधिकारों पर एक निबंध लिखिये। (यू० पी० १९५१)

(३) पंचायत राज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। (यू० पी० १९२४)

(४) उत्तर प्रदेश में जिला बोर्डों के क्या कर्तव्य हैं ?

(यू० पी० १९५५)

(५) स्पानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं ? अपने प्रान्त में नगर-पालिकाओं के अधिकार तथा कर्तव्यों का वर्णन कीजिये ।

(यू० पी० १९४५)

(६) स्पानीय स्वशासन शासन का क्या महत्व है ? उदाहरण सहित बताइये ।

(यू० पी० १९५६)

(७) उत्तर प्रदेश में प्रान्त-स्वराज्य की क्या व्यवस्था की गई है ? प्रान्त संघासक्त के संगठन और अधिकारों का उल्लेख कीजिये ।

(य० पी० १९५७)



## सरकारी नौकरियाँ

हमारे दैनिक जीवन में सरकार में तात्पर्य विभिन्न कार्यों के लिये नियुक्त सरकारी कर्मचारियों में हैं। प्राचीन काल तथा मध्यकालीन राज्यों में इन कर्मचारियों की संख्या उसनी अधिक नहीं थी जितनी कि हम आजकल देखते हैं। इसका कारण यह था कि उस समय सामाजिक व्यवस्था तथा जीवन शैली इतने अधिक जटिल नहीं हुए थे जितने कि आज हैं विजयपल औद्योगिक प्रगति के परिणामस्वरूप के नये वस्तुओं का सृष्टि हुई तथा इनका उचित प्रकार से करने के लिए अधिकारिक कर्मचारी नियुक्त किये गये।

इन कर्मचारियों का दैनिक शासन में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि इन्हीं के द्वारा सरकार को नीति कार्यान्वित करने में है। जनता को इन्हीं के द्वारा सरकार के सम्पर्क होता है, अतएव यह स्वाभाविक है कि शासन जनता को दैनिक जीवन में सरकारी कर्मचारी तथा सरकार में कोई भेद भी न देखे। इन सरकारी कर्मचारियों की योग्यता, कार्यकुशलता, मर्यादा तथा तत्परता पर बहुत अधिक मात्रा तक सरकारी नीति की सफलता निर्भर रहती है। इसलिये प्रत्येक आधुनिक राज्य इस बात की चेष्टा करता है कि योग्य तथा चरित्रवान व्यक्ति ही सरकारी नौकरियों में छोटे जायें।

सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियाँ हैं। छोटे-छोटे चपरासियों से लेकर बड़े बड़े विभागों के सेंट्रलरी आदि सब सरकारी कर्मचारी हैं। इनके कार्य तथा वेतन में इनके पद के अनुसार विवेक स्वाभाविक है। सरकारी नौकरियों से तात्पर्य उन कर्मचारियों में है जिनकी नौकरी की दशाएँ निश्चित हैं तथा जिनकी नौकरी पर मन्त्रिमंडल के बनने विगडने का प्रभाव नहीं होता है। चाहे कोई भी दल चुनाव में जीते सरकारी कर्मचारी अपने पद में बने रहते हैं। इनका काम मन्त्रिमण्डल द्वारा निर्धारित नीति का अनुसरण मात्र है।

भारतीय नौकरियों का औद्योगिकी काल में विकास — जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सन् १६०१ में भारत से व्यापार आरम्भ किया, तब बड़े व्यापारी इस उद्देश्य से भारत आये। इनका काम भारत में जहाँ सम्भव हो, वहाँ व्यापारिक-केन्द्र (trading posts) स्थापित करना था। इनको 'factors'

कहते थे, इसीलिए व्यापारिक-केन्द्र factories कहलाने लगे। Factor शब्द का अर्थ व्यापारिक एजेंट (commercial agent) है।

कम्पनी भारत में केवल व्यापार के उद्देश्य से आई थी और कई वर्षों तक इसने सर टॉमस रो की राय के अनुसार अपनी नीति निर्धारित की। सर टॉमस रो ने १६१६ सन् में कम्पनी को लिखा था कि इसका उद्देश्य भारत में व्यापार होना चाहिये न कि विजय।<sup>१</sup> इस समय कम्पनी के कर्मचारी व्यापारी हुआ करते थे। परन्तु कालान्तर में कम्पनी व्यापार के प्रतिरिक्त शासन भी करने लगी। इसको दीवानी अधिकार मिल गये। कम्पनी के स्वभाव में इस परिवर्तन के कारण जर्ने: जर्ने: कम्पनी के कर्मचारी व्यापारी से बदल कर शासन कर्ता (administrators) हो गये। इस प्रकार भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व सरकारी नौकरियों का जन्म हुआ।

भारत में प्राथमिक-वर्ष में सैनिक-सेवाओं (Civil Service) का जन्म वारेन हेस्टिंग्स तथा लार्ड कानिंगहम के सुधारों द्वारा हुआ। वारेन हेस्टिंग्स ने लगान वसूली प्रथा में कुछ सुधार किये। इसी प्रकार न्याय प्रथा में भी उसने सुधार किये। जब कानिंगहम भारत का गवर्नर-जनरल हुआ उसने भी सुधार किये। उसके अनुसार भारतीयों को उच्च नौकरियों में नहीं रखना चाहिये या क्योंकि "Every native of Hindostan, I really believe is corrupt." कानिंगहम की नीति के अनुसार भारतीय उच्च नौकरियों के प्रयोग बंद कर दिये गये। यद्यपि यह नीति उचित नहीं थी, और कई अंग्रेजों ने, जैसे मैल्कम, एलफिन्स्टन आदि ने भी इसको ठीक नहीं बतलाया तथापि यह सन् १८३२ तक चालू रही। उस वर्ष नया चार्टर ऐक्ट द्वारा भारतीयों को भी बड़ी नौकरियों के योग्य मान लिया गया। परन्तु भारतीय कमो भो ५०० प्रति मास से अधिक वेतन पर नहीं पहुँच पाए। सन् १८५४ से बड़ी नौकरियों में नियुक्ति योग्यता परीक्षा के द्वारा होने लगी। इसका उद्देश्य यह था कि योग्य व्यक्ति ही इन नौकरियों में चुने जाएँ। यह परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। सन् १८५८ में महारानी विक्टोरिया ने अपनी घोषणा में कहा कि नौकरियों में रंग, जाति या धर्म के कारण कोई भेद-भाव नहीं किया जावेगा। परन्तु इसने भी भारतीयों को अधिक लाभ नहीं हुआ। क्योंकि बहुत ही कम भारतीय नवयुवक चलायत जाने का

1. "Let this be received as a rule, that if you will profit, seek it at sea and in quiet trade, for without controversy, it is an error to affect garrisons and land wars in India."

2. Blunt, The I. C. S., p. 1.

व्यय उठा सकते थे। फिर धर्म की भी स्वाद थी। बहुत थोड़े से भारतीय इस मार्ग से उच्च नौकरियों में आये।

सन् १८५० में गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्ट द्वारा यह तय हुआ कि कुछ भारतीय इन नौकरियों में बिना परीक्षा में उत्तीर्ण हुए ही गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्ति कर दिये जायें। यह उपबन्ध ९ वर्ष बाद सन् १८७० से कार्यान्वित हुआ और इस प्रकार स्टैचुटरी सिविल सर्विस का आरम्भ हुआ। गवर्नर जनरल को यह अधिकार मिला कि वह जितने व्यक्ति इंग्लैंड में स्टेण्डरी और स्टैंड फार इंडिया द्वारा चुने जाते थे उनका छठवाँ हिस्सा बिना परीक्षा के भारत में नियुक्त करे। परन्तु इस प्रकार जो नियुक्ति हुए वे अयोग्य सिद्ध। अंग्रेजों के अनुसार यह इस बात का प्रमाण था कि भारतीय उच्च नौकरियों के अयोग्य हैं, परन्तु यथार्थ में कारण था कि जो व्यक्ति इस प्रकार प्रकाशित हुए वे वे योग्यता के कारण नहीं परन्तु वशसम्बन्ध आदि के कारण नियुक्त किए गए थे।

इन नियमों के विरुद्ध बहुत प्रमत्तोप था। इस कारण कमीशन मन १८८६ में नियुक्त किया गया। इसके प्रधान सर चार्ल्स एचीसन (Sir Charles Acheson) ने इस बात पर विचार किया कि भारतीय सिविल

लिए सुरक्षित किया जाय जो कि प्रान्तीय सिविल सर्विस से इसमें भेजे जायेंगे। सन् १८९२ में इस रिपोर्ट की निष्कर्षों के आधार पर नौकरियों में भर्ती के नियम बनाये गए। इसके अनुसार १०८१६ ऐसे रखे गये थे कि भारतीय नियुक्त होते, परन्तु ये घटा कर ९३ कर दिये गये और बाद को केवल ११ कर दिये गये। एचीसन कमीशन ने नौकरियों को तीन वर्गों में बाँट दिया—इण्डियन सिविल सर्विस, प्राविन्सियल सिविल सर्विस तथा सर्वोर्डिनेट सर्विस। इनमें वे प्रान्तीय तथा सर्वोर्डिनेट सर्विस में भारतीय नियुक्त होते थे।

इण्डियन सिविल सर्विस की प्रवेश परीक्षा इंग्लैंड में होती थी। सन् १८९३ में हाउस ऑफ कामस में यह प्रस्ताव पास हुआ कि यह परीक्षा भारत में भी हो। परन्तु भारत से क्रेटरी के विरोध के कारण यह सम्भव नहीं हो सका। सन् १९१२ में एक कमीशन नियुक्त किया गया। लार्ड इसलिंगटन जो कि न्यूज़ीलैंड के गवर्नर थे, इसके सभापति थे। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में अधिक भारतीयों को उच्च नौकरियों में स्थान देने का सुझाव रखा। यह रिपोर्ट सन् १९१७ में छपी। भारतीयों ने इसको असन्तोषजनक बताया।

मार्च १९१७ में ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की कि भारतीयों का शासन में अधिक से अधिक सम्पर्क, इसकी नीति है। दूसरे वर्ष मॉन्टेग्गु तथा चेम्सेफोर्ड ने अपनी संयुक्त रिपोर्ट में यह कहा गया कि इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों का अनुपात ३३% होना चाहिये तथा १२% प्रति वर्ष बढ़ाना चाहिये। इनके अनुसार सन् १९२० में यह अनुपात निश्चय किया गया। सन् १९२५ से भारत में भी इस नौकरी में प्रवेश के लिए परीक्षा होने लगी तथा यहाँ से छाटे हुए उम्मीदवार की दो वर्ष पिलायत में ट्रेनिंग के लिए जाना होता था। ताकि सब प्रांतीय तथा सम्प्रदायों का इन नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व हो, इसलिए भारतीयों के लिए सुरक्षित स्थानों में से एक तिहाई के लिये मनोनित करने का उपबन्ध किया गया।

उच्च नौकरियों के भारतीयकरण के प्रश्न तथा अन्य कठिनाइयों—जैसे भारतीय सिविल सर्विस के लिए अंग्रेज उम्मीदवारों की उदासीनता, मंत्रियों तथा इन उच्च कर्मचारियों में विरोध, आदि पर जांच करने के लिए कमीशन—*Royal Commission on the Superior Civil Services in India*—सन् १९२३ में नियुक्त हुआ। इसके सभापति लार्ड ली (Lee) थे, यद्यपि यह ली कमीशन कहलाता है। इसने निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की :—

(१) इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फारेस्ट सर्विस, तथा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस (नहर विभाग) के लिये भारत से नैटरी ही नियुक्ति करे। परन्तु अन्य अखिल-भारतीय नौकरियों जैसे, इंडियन ऐग्रीकल्चरल सर्विस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन मेडिकल सर्विस (असैनिक) आदि प्रांतीय सरकारों के अधीन कर दिये जायें। यह इसलिए किया गया क्योंकि ये विभाग हस्तान्तरित कर दिये गये थे।

(२) ली कमीशन के अनुसार भारतीयकरण की गति बढ़ा देनी चाहिये थी। इसने कहा, "In the days of the Islington Commission the question was 'how many Indians should be admitted into the Public services? It has now become what is the minimum number of Englishmen which must be recruited?' ली-कमीशन ने सिफारिश की कि इंडियन सिविल सर्विस में सन् १९३९ तक तथा इंडियन पुलिस में सन् १९४९ तक ५० प्रतिशत भारतीय हो जायें। इंडियन फारेस्ट सर्विस तथा इंडियन

इजीप्तीयन सर्विस में भी भारतीय अधिक लिये जायें। इन सिफारिशों को पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया।

(३) अंग्रेज कर्मचारियों के विषय में यह सिफारिश थी कि उनके भत्ते  $\nearrow$  दिये जायें। उन्हें overseas भत्ता मिले। कार्यकाल में ४ बार इंग्लैंड जाने का खर्च मिले। अगर किसी अंग्रेज कर्मचारी का नौकरी करते हुये देहान्त हो जावे तो उसके परिवार को इंग्लैंड जाने के लिये भारत-सरकार खर्च दे। इन कर्मचारियों की पेन्शन बढ़ा दी जावे।

(४) एक पब्लिक सर्विस कमिशन की नियुक्ति की जावे। इसमें ५ सदस्य हों। सन् १९२५ में इसकी स्थापना की गई। इसका काम नौकरियाँ में भर्ती करना तथा उनके बारे में कुछ अन्य बातों पर निश्चय करना था।

देश में राजनैतिक चेतना बढ़ती गई। स्वराज्य की माँग दिन पर दिन जोर पकड़ती गई। अंग्रेजी सरकार ने साइमन कमिशन की नियुक्ति की। इसका मुख्य काम भारत में मघ शासन स्थापित करने के विषयों में रिपोर्ट देना था। इसमें नौकरियों के भारतीयकरण पर भी विचार प्रकट किये। १९३५ ऐक्ट के द्वारा नौकरियों को प्रसैनिक तथा रक्षा सम्बन्धी इन दो भागों में बाँटा गया।

प्रसैनिक नौकरियों (civil service) के तीन वर्ग किए गए।

- (१) अखिल भारतीय सर्विस,
- (२) केन्द्रीय सर्विस,
- (३) प्रान्तीय सर्विस तथा सर्वोर्डिनेट सर्विस।

अखिल भारतीय सर्विस के सदस्य भारत-सेक्टरों के द्वारा नियुक्ति होते थे। इसमें सब से मुख्य इंडियन सिविल सर्विस तथा इंडियन पुलिस सर्विस थे। इनको security services कहा जाता था। इनमें अंग्रेजों की सहाय्य अधिक थी। ये ही दो नौकरियाँ अंग्रेजी काल में सबसे मुख्य थी। इन्हीं के ऊपर भारत में अंग्रेजी सरकार की नींव थी। इन दोनों में भी इंडियन सिविल सर्विस अधिक मुख्य थी। सब बड़े-बड़े पदों पर उसी सर्विस के लोग थे, जैसे जिलाधीश, कमिश्नर, जिला जज, प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सरकार के कौंसिलर। इस सर्विस के उच्च अधिकारी ही बंगाल बम्बई तथा मद्रास के अतिरिक्त अन्य प्रान्तों के गवर्नर होते थे। इनको बहुत अधिक वेतन तथा कई अन्य सुविधाएँ प्राप्त थीं। इस सर्विस का इतना अधिक आकर्षण था कि अगर कोई भारतीय इसमें छाँटा जाता था तो अपने को कुतुकुल्य समझता था। इसमें कोई सदेह नहीं कि इसमें योग्य व्यक्ति थे। परन्तु उनका दृष्टिकोण अमानवीय था।

केन्द्रीय सर्विस में भर्ती भारत सरकार तथा पब्लिक सर्विस के द्वारा करती थी। केन्द्रीय सेक्रेटारिएट, रेलवे, भारतीय तार तथा डाक, कस्टमन् सर्विस इस वर्ग में थे। इनका वेतन भी अच्छा था। इनमें जो काफी अंग्रेज थे।

प्रान्तीय-सर्विस में अधिकतर भारतीय थे। यह प्रान्तीय-सरकार के अधिकार में था। इसका सम्बन्ध उन मामलों में था जो कि प्रान्तीय सरकारों के हाथ में था।

सर्वोद्दिष्ट सर्विस सबने निम्न श्रेणियों की थी। इसमें वेतन कम था। इसमें सब भारतीय थे।

**स्वाधीनता के पश्चात् नौकरियों की अवस्था :—**स्वाधीनता प्राप्त के बाद सरकारी नौकरियों में कुछ परिवर्तन हुए हैं। सर्वप्रथम तो यह कि इंडियन मिडिल सर्विस के स्थान में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की स्थापना की गई। सब नौकरियों के सम्बन्ध में वे सब नियम लागू हैं जो नए संविधान के विरुद्ध नहीं हैं। वे सब सरकारी कर्मचारों जो कि अंग्रेजी काल में प्रशिक्षित भारतीय सर्विस में थे तथा स्वाधीनता के पश्चात् भी भारत सरकार के नौकरी में हैं, वेतन, भत्ते तथा पेन्शन आदि के सम्बन्ध में पुराने नियमों के अधीन रहेंगे। (धारा ३१४)। एक विशेष बात यह दृष्टिगोचर होती है कि भारत में सब नौकरियों से अंग्रेज चले गये हैं, यद्यपि भारत सरकार उनको उनके कार्यकाल समाप्ति तक रखने की प्रस्तुत थी।

नए संविधान के लागू होने पर भी सरकारी नौकरियाँ तीन वर्गों में विभाजित हैं—प्रशिक्षित भारतीय, संघीय तथा राज्यों की नौकरियाँ। (१) प्रशिक्षित भारतीय सर्विस में एडमिनिस्ट्रेटिव तथा पुलिस हैं। इनका संविधान में वर्णन है। इनके प्रतिरिक्त इंडियन फोरें सर्विस भी है। इसके कर्मचारी विदेशों में भारतीय दूतावासीयों में विभिन्न पदों पर नियुक्त होते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव तथा इंडियन पुलिस सर्विस के सदस्य राज्यों में विभिन्न पदों पर काम करते हैं, जैसे जिलाधीश, पुलिस, सुपरिन्टेन्डेंट आदि। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव के सदस्य ही राज्यों में तथा संघ में सेक्रेटरी, आदि होंगे। संघ अन्य भारतीय सर्विस की स्थापना कर सकती है अगर राज्य परिषद् दो-तिहाई बहुमत से इस बात की सिफारिश करे। (२) संघीय सर्विस में रेलवे, कस्टमन्, बॉर्डर, भारतीय डाक तथा तार, उच्चतम न्यायालय तथा भारतीय लोकसेवा आयोग के कर्मचारी आते हैं। कस्टमन् इन्फैन्ट्री तथा सेन्ट्रल एक्साइज सर्विस सब रेवेन्यू सर्विस कहलाती है। (३) राज्यों की नौकरियों में राज्यों के अधीन विभागों के सम्बन्धी विभाग हैं। जैसे, पुलिस, शिक्षा, जंगल, नहर, आवासीय आदि।

भारतीय सविन तथा मर्याद सविन व नमचारिया की नियमित भारताय  
राज्य सेवा आयोग पराक्षा द्वारा करता है। राज्या की सविन म नियमित राज्या  
क राज सेवा आयोग द्वारा की जाती है। भारतीय नौकरियों के सम्बन्ध में सम  
तथा राज्या का नौकरियों के सम्बन्ध म राज्या व विधान मण्डल को नियम  
बनान का अधिकार है। परन्तु जब तक सम या विधान मण्डल नियम का  
निर्माण न करता तब तक राष्ट्रपति या राज्यपाल का नियम बनान का  
अधिकार दिया गया है। सरकारी नमचारी राष्ट्रपति या राज्यपाल व  
प्रशासनिक अर्थन पत्र पर राज्या अर्थात् उनका वापसाल निश्चित है  
और उसके पक्ष व राज्या नमचार अथवा असमयता के कारण ही हटाए  
जा सकते हैं। विधान की ३११ की धारा म कहा गया है कि कोई भी  
व्यक्ति जो कि भारताय गया का या राज्य की सेवा का सम्बन्ध है अपनी नियुक्त  
करन दाता अधिकारी (authority) से निचर किसी अधिकारी द्वारा  
पदच्युत नहीं किया जावेगा और न पद स हटाया जावेगा। उसके विरुद्ध कोई भी  
निर्णय तब तक नहीं किया जब तक कि उसके विरुद्ध का जान वाली कायवाही  
के निम्न उमे कारण दिखान का पूरा अवसर न दिया गया हो। परन्तु कुछ  
दशाभा म यह अवसर नहीं दिया जायेगा — जब कि वह गुप्त आचार के कारण  
पदच्युत हुआ हो या निकाय गया हो जिसके विरुद्ध दोषारोप पर वह दोष  
निष्ठ हुआ हो। जबकि उम दणित करन दाता अधिकारी का यह समाधान  
है कि यह ठीक नहीं कि उम कारण विज्ञान का अवसर दिया जावे जब राष्ट्र  
पति या राज्यपाल का समा मान है कि राज्य की मर्यादा के निम्न म यह अवसर  
नहीं देना चाहिये।

सर्वोच्च सविन म कुछ पत्र पर नियमित लाइ गया आयोग के सिफारिश  
पर होती है। कुछ पत्र पर विभिन्न विभागों का सम नमचारी नियमित करन  
का अधिकार है।

## लोक सेवा आयोग

सरकारी नमचारी (Services) अपना कार्य ठीक प्रकार से कर सक  
तथा योग्य व्यक्ति हो छान पाय इस कारण इनकी नियुक्ति के विषय व्य  
वस्था की जाती है। सबसे प्रथम यह आवश्यक है कि उनकी नौकरियों की शर्तों  
कायवा उनसे नियम आदि निश्चित हो। दूसरा माय यह भी आवश्यक  
है कि उनकी नियुक्ति का अधिकार किसी निपक्ष अधिकारी को हो।  
इहीं सब कारणों से सब के विषय तथा प्रत्येक राज्य के विषय विधान द्वारा  
एक एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। परन्तु यदि दा या अधिक

राज्य चाहे कि उनका एक ही संयुक्त लोक सेवा आयोग हो। तथा यह प्रस्ताव उन दोनों राज्यों के विधान-मण्डलों द्वारा मान लिया जाये, तो संसद संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की आज्ञा दे सकती है। राष्ट्रपति की आज्ञा में यह लोक सेवा-आयोग किसी राज्य की प्राप्ति पर उस राज्य की स्वयं किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति में लिये कार्य करना स्वीकार कर सकता है।

लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति यदि वह संघ-आयोग या संयुक्त आयोग है तो, राष्ट्रपति द्वारा तथा यदि वह राज्य-आयोग है तो, राज्य के राज्यपाल द्वारा की जावेगी। इन सदस्यों में से प्राये सदस्य ऐसे व्यक्ति नियुक्ति किये जायेंगे जो कि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के प्रथम क्रम से कम दस वर्ष तक पद धारण कर चुके हैं।

लोक सेवा आयोग का भव्य पद ग्रहण की तारीख से ६ वर्ष की अवधि तक, अथवा यदि वह संघ-आयोग का है तो ६५ वर्ष आयु की प्राप्ति होने तक, तथा यदि वह राज्य आयोग या संयुक्त-आयोग का है तो, साठ वर्ष की आयु की प्राप्ति होने तक, जो भी इनमें से पहले हो, अपना पद धारण करेगा। परन्तु सदस्य अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। सेवा आयोग का कोई सदस्य अपने पद राष्ट्रपति द्वारा केवल कदाचार के कारण हटाया जा सकता है। ऐसे अवसर पर उच्चतम न्यायालय उन सदस्य के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करेगा तथा उन्हें ठीक बताने पर ही वह सदस्य पद से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जायेगा। जब तक जांच की रिपोर्ट न आ जाये वह सदस्य अपने पद से निलम्बित किया जा सकता है। नीचे लिखी बातें भी कोई सदस्य अपने पद से हटाया जा सकता है। अगर वह दिवालिया हो जाये, अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों के बाहर कोई वैयक्तिक नोकरी करता है; राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक दुर्बलता के कारण अपने पद पर रहने के अयोग्य है।

संघ आयोग तथा संयुक्त-आयोग के बारे में राष्ट्रपति तथा राज्य-आयोग के बारे में उस राज्य का राज्यपाल आयोग के सदस्यों की तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या तथा इनकी सेवाओं की शर्तों पर निश्चय करेगा। परन्तु लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् कोई ऐसा परिवर्तन न किया जावेगा जो उसके लिए अलाभकारी हो। आयोग के सदस्यों का वेतन तथा अन्य व्यय भारत तथा राज्यों के संविधान विधि में दिये जाते हैं; लोक-सेवा आयोगों की कार्यकारिणी के हस्तक्षेप से स्वतन्त्र रखा गया है ताकि वे अपना कार्य ठीक प्रकार सम्पादित कर सकें।



कोई व्यक्ति जो लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है, अपनी पदावधि की समाप्ति कर पुनः उसी पद पर नियुक्ति नहीं हो सकता है। सघ-आयोग का महापति भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य नौकरी के लिए अपात्र है। राज्य-आयोग का महापति सघ-आयोग का महापति या सदस्य भ्रष्टा किंसी अन्य राज्य-आयोग का महापति हो सकता है। परन्तु यदि अन्य सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। सघ आयोग का सदस्य इसका अर्थ कि किसी राज्य-आयोग का महापति हो सकता है, परन्तु अन्य सरकारी नौकरी के अयोग्य है। राज्य आयोग का कोई सदस्य सघ-आयोग का महापति या सदस्य तथा किसी अन्य राज्य-आयोग का महापति हो सकता है परन्तु अन्य कोई सरकारी नौकरी के योग्य नहीं है। इन प्रतिशोषों का उद्देश्य यह है कि ये सदस्य अपना काम निष्पक्ष तथा निभयतापूर्वक करें।

मेरा आयोग के कृत्य —सर तथा राज्य के लोक सेवा-आयोगों का कृतव्य क्रमशः सघ तथा राज्य को सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करना है। सघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य है कि अगर कोई दो या अधिक राज्य, ऐसी किन्हीं सेवाओं के लिए, जिनके लिए विशेष योग्यता वाले उम्मीदवार चाहिये, मिली-जुली भर्ती की योजनाओं के यानि तथा प्रवर्तन करने में सहायता माँगे तो उनकी सहायता करे। अधिधान द्वारा यह आवश्यक कर दिया गया है कि निम्नलिखित विषयों पर सघ-सरकार सघीय लोक सेवा आयोग से तथा नौकरी की सरकारें राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श लें (धारा ३२०) —

(क) प्रभेदिक सेवाओं में और प्रभेदिक पदों के लिए भर्ती की रीति में सम्बन्धित समस्त विषयों पर;

(ख) भर्तनिक सेवाओं की नियुक्ति, पदोन्नति तथा बदली तथा इस विषय पर अनुसरण किए जाने वाले सिद्धान्तों पर,

(ग) प्रभेदिक सेवाओं के अनुशासन में सम्बन्धित विषयों पर,

(घ) सैनिक पद पर काम करने वाले किसी व्यक्ति के इस दावे पर कि कर्तव्य पालन में किए गए कार्यों के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध चलाई गई किन्हीं कानूनी-कार्यवाहियों में जो खर्च उसे अपनी रक्षा पर करना पड़ा है वह सरकार द्वारा किया जाय ;

(ङ) किसी प्रभेदिक पद पर काम करने वाले व्यक्ति का अपने कर्तव्य पालन में हुई घाति के बारे में निवृत्ति वेतन (पेंशन) दिए जाने के लिए किसी दावे पर, तथा ऐसी दी जाने वाली राशि का क्या हो, इस प्रश्न पर।

इन कर्तव्यों के प्रतिरिक्त, संविधान में यह कहा गया है कि सघीय लोक सेवा आयोग के कर्तव्य संसद् द्वारा तथा राज्यों के आयोग के कर्तव्य उनके विधान-मंडलों द्वारा बढ़ाये जा सकते हैं। सघीय लोक सेवा आयोग प्रति वर्ष राष्ट्रपति को अपने वार्षिक कार्य का विवरण देगा। राष्ट्रपति इस विवरण की एक प्रतिलिपि संसद् में प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा। अगर कोई ऐसा मामला हो जहाँ कि आयोग का परामर्श स्वीकार नहीं किया गया तो राष्ट्रपति ऐसी अवस्थिति के कारणों का विवरण भी उस रिपोर्ट के साथ रखवायेगा। राज्यों में राज्यपाल विवरण को विधान-मण्डल में रखवायेगा।

अगर देश में योग्य तथा ईमानदार व्यक्ति सरकारी सेवाओं में भर्ती करना है तो कार्यकारिणी को चाहिए कि लोक-सेवा आयोग के कार्य में हस्तक्षेप न करे तथा उनके परामर्श के अनुसार व्यक्तियों को भर्ती करे। योग्य कर्मचारियों के अभाव में कोई भी सरकार ठीक प्रकार काम नहीं कर सकती है। संविधान द्वारा इस बात का प्रयत्न किया गया है कि लोक सेवा आयोग स्वतन्त्रतापूर्वक अपना काम कर सके। इनकी स्वतन्त्रता तथा निष्पक्षता बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करेगी कि इनके सदस्य भी निष्पक्ष, ईमानदार तथा निर्भीक हों। यह वांछनीय प्रतीत होता है कि राजनैतिक दलों ने सम्बन्धित व्यक्ति इनके सदस्य न नियुक्त हों।

### भारतीय सेना विभाग

अभी तक हम अखंडित सेवाओं का वर्णन कर रहे थे। अब सेना विभाग की ओर ध्यान देना चाहिए। राज्यों में प्रारम्भ से ही अपनी रक्षा की ओर सर्वदा ध्यान दिया है। सेना का काम देश को वाह्य आक्रमण से बचाना है। सेना कभी-कभी आन्तरिक अशांति से भी बचाव करती है। पुनाबी वारानिक प्रफलतून (१२७-१४७ ई० पू०) ने सैनिकों की तुलना कुत्तों (watchdogs) से की है।

अंग्रेजी काल में सेना.—अब ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारियों ने भारत में अपनी फौजदरिया स्थापित की, उन्होंने उनकी रक्षा के लिए चौकीदार (guards) तैनात किये। परन्तु औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात् भारत की राजनैतिक अवस्था का खान उखाने के लालच से अब अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों में युद्ध हुए तब अंग्रेजों ने सेना का गठन किया। सन् १७९३ में अंग्रेजी सेना में १३,००० सशस्त्र तथा ५७,००० भारतीय थे। सन् १८२४ में अंग्रेजों ने भारतीय-सेना का पुनर्गठन किया।

सन् १८५७ में कम्पनी के शासन का अन्त होने पर ब्रिटिश सरकार ने

भारत में सेनाओं का फिर से संगठन किया। सेना तीन भागों में बाँटी गई—  
बंगाल सेना, मद्रास की सेना तथा बम्बई की सेना। सन् १८९५ में इन तीन  
सेनाओं के स्थान पर ४ कमानों (commands) की स्थापना की गई—पंजाब  
सेना, मद्रास तथा बम्बई। परन्तु सन् १९०७ में लार्ड किचनर (भारत का  
मुख्य सेनापति) ने इस संगठन को असन्तोषजनक बतलाया तथा भारतीय सेना  
को दो भागों में बाँट दिया—उत्तरी सेना तथा दक्षिणी सेना। इसमें से प्रत्येक  
एक जनरल अफसर (General officer) के अधीन थी। सन् १९१८ में  
यह उचित समझा गया कि जनरल अफसरों के अधिकार बढ़ा दिये जायें। उन्हें  
शासनीय (administrative) अधिकार दे दिये गये और इस प्रकार  
आर्मी हेडक्वार्टर्स के ऊपर से कुछ बोज़ कम किया गया। सन् १९२० में फिर से  
कमानों की स्थापना की गई। प्रत्येक एक जनरल अफसर कमान्डिंग के अधीन  
रखी गई। नवम्बर १, १९३८ को पश्चिमी बंगाल ताठ दी गई।

सन् १९३८ में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना के सम्बन्ध में जाँच करने  
को एक कमिटी नियुक्त की जो कि चैटफील्ड कमिटी (Chatfield  
Committee) कहलाती है। इस कमिटी ने यह सुझाव रखा कि भारतीय  
सेना को आधुनिक ढंग से संगठित किया जावे, इसको आधुनिक अस्त्र-पस्त्रों  
की शिक्षा दी जावे, इसका काम भारत की बाह्य सुरक्षा होना चाहिये, भारत  
को गोलार्द्ध (munitions) के मामले में दीर्घ ही आत्मनिर्भर हो जाना  
चाहिये।

सन् १९४७ में जब भारतवर्ष का भारत तथा पाकिस्तान में विभाजन हुआ  
तो इसके साथ साथ भारतीय सेना भी भारत की सेना तथा पाकिस्तान सेना  
इन दो भागों में बाँट दी गई। इस काम के लिये तथा फिर से विभाजित सेनाओं  
को संगठन के लिये एक सुप्रीम कमान्ड स्थापित किया गया था। यह ज्वाइंट  
डिफेंस कौंसिल के अधीन था। इसमें दोनों देशों के प्रतिनिधि थे। यह काम  
समाप्त होने पर सुप्रीम कमान्ड नवम्बर १९४७ में तथा डिफेंस कौंसिल अप्रैल  
१९४८ में खतम हो गई।

ब्रिटिश सरकार तथा भारत की सरकार के बीच एक समझौता किया गया।  
इसमें यह तय हुआ कि भारत से अंग्रेजी फौज हटा ली जावेगी। इसका फलस्वरूप  
सन् १९४७ से ब्रिटिश फौज यहाँ से हटनी शुरू हुई तथा १९४८ के परवरी  
मास के अन्त तक सब अंग्रेजी फौज भारत से हटा ली गई थी।

अग्रणी काल में सेना का संगठन—इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी  
कि सेना के जब उच्च पदों पर अंग्रेज अफसर थे। भारतीय अफसरों की सहायता बहुत

कम थी। सेना प्रत्येक धर्म में समरतीय थी। एक लेखक के अनुसार यह केवल इसी धर्म में भारतीय थी कि इनका सर्व भारत को डराना पड़ता था।

भारतीय सेना के सेनापति को नियुक्ति मन्त्रिद् द्वारा की जाती थी। यह सेनापति के प्रतिरिक्त वाइसरॉय की कौन्सिल का सदस्य भी होता था। उसे डिफेन्स-मैम्बर (Defence Member) कहते थे। वह मल, जल तथा नम इन तीनों सेनाओं का सेनापति था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में, भारत-मैम्बेटर भारतीय सेना के लिये भी उत्तरदायी था। इस प्रकार भारतीय सेना पूर्णतः अंग्रेजी सरकार के अधीन थी। इसका मुख्य काम भारत में अंग्रेजी सरकार को बचाये रखना था। इसलिये राष्ट्रीय-मत इनके पूर्वतया विरुद्ध था।

भारतीय सेना जैसा लिखा जा चुका है चार कमानों (Commands) में बंटी थी। प्रत्येक कमान का अफसर लेफ्टिनेण्ट-जनरल होता था। प्रत्येक कमान में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होते थे। इनका अफसर मेजर-जनरल कहलाता था। इनके बाद ब्रिगेड, और ब्रिगेडों के नीचे स्टेशन (Stations) होते थे। इनके अफसर क्रमशः ब्रिगेडियर तथा कर्नल या लेफ्टिनेण्ट-कर्नल होते थे।

द्वितीय युद्ध के पूर्व हमारे हवाई तथा समुद्री बड़े बहुत ही छोटे थे। हवाई बड़े में २११ भारतीय तथा २,१७३ अंग्रेज थे। जहाजी बड़े में १८५४ भारतीय थे। परन्तु यह सब निम्न पदों पर थे। ऊँचे पदों पर सब अंग्रेज थे। इन अफसरों की संख्या १७१ थी। यल सेना के कई भाग थे—स्थायी ब्रिटिश सेना, स्थायी भारतीय सेना, रक्षित सेना, सहायक सेना, टेरिटोरियल फोर्सेज, तथा बेगी रियासतों की सेना।

वर्तमान सैनिक-संगठन :—स्वाधीनता के पश्चात् भारतीय सेना का पूर्णरूपेण भारतीयकरण हो गया है। फरवरी १९४८ तक सब अंग्रेजी फौजें यहाँ से चली गई थी। अब उच्च पदों पर, कुछ को छोड़ कर भारतीय हैं। कुछ अंग्रेज अफसर तथा टेक्नीशियन्स अभी हैं। परन्तु उनकी संख्या घटान्त न्यून है।

मन्त्रिमंडल में एक रक्षा मंत्री है। यह भारत की रक्षा नीति के लिये संसद् को उत्तरदायी है। रक्षा मंत्री का काम सेना की नीति निर्धारित करना तथा यह देखना है कि वह कार्यान्वित की जाती है। इस मंत्री के प्रतिरिक्त कॅबिनेट को एक समिति इस विभाग की समस्याओं पर विचार करने के लिये है। इसकी डिफेन्स कमिटी कहा जाता है। इन कमिटी का समापति प्रधान मंत्री ही होता है। रक्षा मंत्री तथा तीन अन्य मंत्री इसके सदस्य होते हैं। इनके प्रतिरिक्त तीनों सेनाओं के सेनापति तथा डिफेन्स मैम्बेटर भी इसकी बैठकों में भाग ले सकते हैं। रक्षा सम्बन्धी मामलों में इसका निर्णय अन्तिम होता है। परन्तु यह अपने कुछ

निर्णयों को पूरे मन्त्रिमण्डल के सामने उसका समर्थन प्राप्त करने के लिये रखती है। सेना की नीति सम्बन्धी मामलों में यह कमेटी सबसे महत्वपूर्ण है।

। इसके अतिरिक्त कई अन्य कमिटियाँ हैं। सबसे ऊपर जो कमेटी है उसका 'डिफेंस मिनिस्ट्रस कमेटी' (रक्षा मन्त्रियों की समिति) कहते हैं। इसके मध्य रक्षा मन्त्री तीनों सेनापति फाइनेन्सियल एडवाइजर तथा डिफेंस सेक्टरों होते हैं। इस कमेटी के निर्णय अन्तिम होते हैं परन्तु जहाँ पर महत्वपूर्ण नीति सम्बन्धी प्रश्न होते हैं यह उनका रेविजेंट का डिफेंस कमेटी को परामर्श हेतु भेज देती है।

डिफेंस मिनिस्ट्रस कमेटी के नीचे कई अन्य समितियाँ हैं। इनमें सबसे मुख्य तीन हैं—चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, माइनिट्रिय एडवाइजरी कमेटी तथा मेडिकल कमेटी। इन सब कमिटियों की इसलिये स्थापना की गई ताकि जब काम शीघ्रता से तथा मुबालस्य से होता रहे।

पहला नम्र जल तथा यह इन तीनों सेनाओं के लिये एक सेनापति होता था। परन्तु १५ अगस्त १९४७ से प्रत्येक का सेनापति अलग-अलग है। भारत की सरकार जल तथा नम्र सेना की वृद्धि के लिए पूर्णरूपेण समस्तशील है भारत का समुद्र तट बहुत लम्बा है, इसलिये हमारी जल सेना खूब मजबूत होनी चाहिए। ये सेनापति मन्त्रिमण्डल के सदस्य नहीं होते हैं। ये रक्षा-मन्त्री के अधीन हैं।

२. **यल सेना** —इसका सेनापति सबसे मुख्य अफसर है। उसके नीचे एक आर्मी हेडक्वार्टर है। इसमें छ विभाग हैं, जिनका काम सेना का विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना है। इनके नाम हैं जनरल स्टाफ विभाग, एडज्यूटेंट जनरल विभाग, क्वार्टर मास्टर जनरल विभाग, इंजीनियर-इन-चीफ विभाग तथा मिलिट्री सेक्टरोंज विभाग।

आर्मी हेडक्वार्टर के अधीन भारतीय सेना को तीन कमानों में बांटा गया है। इनका पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी कमान कहा जाता है। प्रत्येक कमान का मुख्य अफसर एक लेफ्टिनेंट जनरल होता है। कमानों को एरिया में विभाजित किया गया। प्रत्येक एरिया एक मेजर जनरल के अधीन है। एरिया में नीचे सब एरियाज होते हैं। प्रत्येक सब एरिया एक ब्रिगेडियर के अधीन है। यल सेना के बड़े भाग होत हैं जैसे आम्बकोर, आटिलरी, इंजीनियरिंग, इन्फैंट्री एडज्यूटेंट जनरल वार आदि, आदि। देशी रियासतों की सेना भी भारतीय सेना में मिला दी गई है। स्थायी सेना के अतिरिक्त टेरिटोरियल आर्मी तथा नेशनल वॉलेंट वार भी है।

**टैरिटोरियल आर्मी** —अधुनी काल में भारत में एक टैरिटोरियल फोर्स था। इसका उद्देश्य आवश्यकता होने पर सेना की सहायता करना था। अर्थात्

सकलकाल में यह द्वितीय रक्षा पक्ति होता था। परन्तु वह अत्यन्त मरुचित था और इसकी ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया था। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारतीय सरकार ने इनके स्थान पर टेरिटोरियल आर्मी स्थापित करने का निश्चय किया। भारतीय ससद ने सितम्बर १९४८ में इम्पियन टेरिटोरियल आर्मी ऐक्ट पास किया। टेरिटोरियल सेना पहिले से अधिक बड़ी होगी। इनमें दो तरह के दस्ते होंगे। (१) प्रान्तीय (Provincial) इनमें देहातों में भर्ती होंगी। प्रति वर्ष इसका एक कैम्प होगा, जो कि दो या तीन महीने का होगा। (२) नहरी (Urban), इसमें गन्त-सेवा में भर्ती होगी। प्रति सप्ताह इनकी ड्रिल होगी तथा प्रति वर्ष कुछ दिनों के लिये एक कैम्प होगा।

इन सेना में नव भारतीय भर्ती हो सकते हैं। अक्टूबर १९४९ में इनकी भर्ती आरम्भ हो गई है। भारत को ८ भागों में (Zones) में बांटा गया है। इन सेना का काम संकट काल में द्वितीय रक्षा पक्ति का होगा।

नेशनल कैंडेट कोरः—अंग्रेजों के काल में विद्यापियों को कुछ मैट्रिक शिक्षा देने के लिये यूनीवर्सिटी ट्रेनिंग कोर था। परन्तु १९४८ में सरकार ने इसके स्थान पर नेशनल कैंडेट कोर स्थापित किया है। सन् १९४६ में एक कमेटी १० हृदयनाथ बुंजरू के सभापतित्व में स्थापित की गई थी। इनकी रिपोर्ट के ऊपर ही नेशनल कैंडेट कोर की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भारत के नवयुवकों को कुछ मैट्रिक शिक्षा देना तथा उनमें सैनिक शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करना है। इस योजना के अनुसार लड़कियों को भी मैट्रिक शिक्षा दी जावेगी। इस कोर के भाग हैं—मीनिस्टर तथा जूनियर। मीनिस्टर भाग में यूनीवर्सिटी के विद्यार्थी लिये जाते हैं। जूनियर भाग में स्कूल तथा कॉलेजों के विद्यार्थी हैं। इनमें भर्ती के लिये कोई उम्रबंदस्ती नहीं है।

भारतीय नव सेना :—इसका मुख्य उद्देश्य नवसेना बहलाना है। इनके नीचे एन हृदयकार्टर है। १५ अगस्त १९४७ में पूर्व नवसेना भी बहुत ही नाभारण थी। अंग्रेजों ने इनके विकास की ओर नाममात्र का ही ध्यान दिया था। अंग्रेजों हवाई सेना की एक एकाई भारत में स्थित थी। परन्तु स्वतन्त्रता मिलने के बाद सरकार ने नवसेना की ओर ध्यान दिया है और इन दिशा में कुछ उन्नति हुई है। परन्तु अब भी हमारे देश की नवसेना अन्य बड़े राष्ट्रों के मुकाबले में अत्यन्त कमजोर है। इसलिये इनके विकास की ओर बहुत अधिक आवश्यकता है।

हवाई बेटे की शिक्षा के लिये कई स्कूल खोले गये हैं जैसे, जोधपुर तथा अम्बाला। कोयम्बटूर में आउटडो-ट्रेनिंग के लिये स्कूल है। भारत में टेक्निकल

ट्रेनिंग के लिये भी एक कालिज खोला गया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

/ भारतीय जल सेना —स्वतन्त्रता के पूर्व हमारी जल-सेना भी अत्यन्त हीन थी। अब इसके विकास की ओर भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है इसका प्रधान भी सेनापति कहलाता है। इसने नीचे एक ट्रेडक्वाटर्न है। इसमें ५ विभाग हैं—स्टाफ विभाग, पर्सनल विभाग तथा एडमिनिस्ट्रेशन विभाग, मॅटीरियल विभाग तथा नेवल एवियेशन विभाग।

जल सेना के लिये नवयुवकों की शिक्षा देने के लिये कोचीन, विजगापट्टम जामनगर तथा लोनाथाला में स्कूल खोले गये हैं। ग्राजुअल नौ-सेना के प्रफ़मरा की प्रारम्भिक शिक्षा नेसनल डिफेंस एकेडमी देहरादून में होती है। उच्चशिक्षा के लिए विलायत भेजा जाता है। परन्तु अफ़सरो की उच्च शिक्षा के लिये विजगापट्टम में एक कालिज खलने वाला है। भारत सरकार की जलसेना के विकासार्थ एक दसवर्षीय योजना है। इस काल की समाप्ति पर यह धारा है कि भारतीय जलसेना राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल होगी।

सैनिक शिक्षा की व्यवस्था —सेना के विकासार्थ यह आवश्यक है कि सैनिक शिक्षा का उचित प्रबंध हो। नसार के सब देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है। अमेरिका, रूस, इंग्लैण्ड में तो सैनिक-शिक्षा हेतु अत्यन्त ही उच्च कोटि के शिक्षालय हैं। बिना उच्च शिक्षा के अच्छे अफ़सरो का होना असम्भव है। हमारे देश में तो यह और भी आवश्यक है कि योग्य अफ़सरो की शिक्षा की ओर पूरा ध्यान दिया जावे। क्योंकि अंग्रेजों-काल में तो अंग्रेज ही उच्च पदों पर थे। इसलिए भारतीयों को उच्च पदों पर काम करने का अनुभव नहीं के बराबर है। योग्य अफ़सरो की कमी को पूरा करने तथा उनकी उचित शिक्षा का प्रबंध करने के लिए भारत सरकार पूना के निकट खडकवासला नामक स्थान पर एक सैनिक शिक्षालय खोल दिया है इसका नाम भारतीय रक्षा शिक्षालय (National Defence Academy) है। इसका शिलान्यास ६ अक्टूबर, १९४९ को प० नेहरू ने द्वारा किया गया था। इसमें सेना, नौ सेना तथा नभ सेना के अफ़सरो को शिक्षा दी जावेगी। इसमें मन् १९५५ से शिक्षा प्रारम्भ हो गई है। इस एकेडमी में १५०० छात्र शिक्षा पावगे। इसने निर्माण में ६५ करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

इस राष्ट्रीय एकेडमी के अतिरिक्त कई अन्य शिक्षा समस्याएँ हैं। नौसेना तथा नभ सेना के शिक्षालयों का वर्णन हम कर चुके हैं। वॉलिंगटन (नीलगिरी

पहाड़) में एक स्टाफ कॉलेज खोला गया है। रड़को में फौज के इंजीनियरों की शिक्षा का प्रबन्ध है। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य स्कूल भी हैं। परन्तु इतना होते हुए भी यह कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि सैनिक-शिक्षा में अभी हम बहुत पिछड़े हैं और इस ओर और अधिक देना चाहिये।

### प्रश्न

(१) संघीय लोक सेवा-आयोग के विधान का वर्णन कीजिये। कौन ऐसे विषय हैं जिनमें संघ सरकार के लिये उसको सम्भवि लेना आवश्यक है ?

(यू० पी० १९५१)

(२) अखिल भारतीय सेवाओं पर टिप्पणी लिखिये।

(यू० पी० १९५२)

(३) लोक सेवा आयोग में आप क्या समझते हैं ? केन्द्रीय लोक सेवा आयोग के संगठन तथा कार्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिये।

(यू० पी० १९५८)



## संघ तथा राज्यों में अधिकार विभाजन तथा सम्बन्ध

जैसा पहिले लिखा जा चुका है, प्रत्येक सघात्मक संविधान में, संघ सरकार तथा राज्यों की सरकारों के बीच अधिकार विभाजन किया जाता है। यह विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है। इस प्रकार दोनों के क्षेत्र निश्चित कर दिये जाते हैं। इस विभाजन का आधार यह होता है कि सर्वदेशीय महत्व के विषय तो संघ सरकार के अधीन रहें जाते हैं और स्थानीय महत्व के विषय राज्यों की सरकारों के अधीन। इस प्रकार यह चेष्टा की जाती है कि सम्पूर्ण देश के तथा विभिन्न स्थानों के हित, दोनों ही ठीक प्रकार से पूरे हो सकें। न्यायपालिका का यह कर्तव्य है कि वह संघ तथा राज्यों को एक दूसरे के क्षेत्र में अनाधिकार हस्तक्षेप न करने दे। न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है। संघ तथा राज्यों के मध्य अधिकार विभाजन निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है। (१) संविधान में संघ सरकार के अधिकारों का वर्णन कर दिया जाता है और शेष सब अधिकार (residuary powers) राज्य सरकारों को दिये जाते हैं। ऐसा समुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा आस्ट्रेलिया के संविधान में है। (२) संविधान में संघ तथा राज्य दोनों की शक्तियों का वर्णन कर दिया जाता है। इनके अतिरिक्त यदि कोई अधिकार और हों, जिनको अवशिष्ट अधिकार कहा जाता है, संघ को दे दिये जाते हैं। ऐसा हम कनेडा के संविधान में पाते हैं।

**विधायिनी सम्बन्ध (Legislative Relations)** — भारत के संविधान में अधिकार विभाजन कुछ विशेष रूप से किया गया है। इसका कारण यह है कि संविधान निर्माताओं ने १९३५ के Government of India Act का बहुत मात्रा तक अनुसरण किया है। अवशिष्ट अधिकार संघ को दिये गए हैं। यह कनेडा की तरह है। संविधान द्वारा समस्त विषयों को तीन सूचियों में बाँटा गया है—संघ सूची राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। संघ-सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ सरकार है। राज्य-सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों के विधान मण्डलों को है। समवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर संघ तथा राज्यों के विधान-मण्डल, दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। परन्तु यहाँ पर भी संघ का प्रधानता तथा

प्राथमिकता प्रदान की गई है। अगर संसदीय सूची में वर्णित किसी विषय पर संसद् तथा किसी राज्य द्वारा बनाये कानून में विरोध हो तो संसद् का ही कानून लागू होगा। परन्तु अगर राष्ट्रपति राज्य द्वारा निर्मित किसी कानून को अपनी स्वीकृत दे देता है जिसका कि संसद् द्वारा निर्मित किसी कानून से विरोध हो तो उन दशा में उस राज्य के अंदर विधान मंडल का बनाया हुआ कानून ही लागू होगा। अगर संसद् चाहे तो वह इस प्रकार के कानून को रद्द कर सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है। संसद् राज्य सूची में वर्णित विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। इसमें संसद् की ही प्रधानता होगी।

संविधान द्वारा इस प्रकार अधिकार विभाजन के माध्यम से संसद् को राज्यों के क्षेत्र में कई अवसरों पर हस्तक्षेप का अधिकार भी दिया गया।

(घ) अगर राज्य परिषद् दो-तिहाई उपस्थित सदस्यों के मत से यह पान कर दे कि कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का ही गया है तो संसद् उस प्रस्ताव में वर्णित विषय पर कानून बना सकती है। ऐसा प्रस्ताव एक बार में एक वर्ष तक लागू रहेगा। अगर राज्य-परिषद् द्वारा से प्रस्ताव को पान कर दे तो इस अवधि की फिर एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है। संसद् द्वारा ऐसे प्रस्ताव के मंजूर बनाया हुआ कानून, प्रस्ताव की अवधि समाप्त होने के बाद भी ६ महीने तक लागू रहेगा। (धारा २४२)

(ङ) संकटकाल की घोषणा के उपरान्त संसद् को राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार है। ऐसी अवस्था में संसद् द्वारा निर्मित कानून संकटकाल की घोषणा के समाप्त होने के बाद भी ६ महीने तक लागू रहेगा। (धारा २५०)

उपरोक्त दोनों अवस्थाओं में राज्यों के विधान-मंडलों की भी सम विषय पर कानून बनाने का अधिकार रहेगा। परन्तु संसद् के कानून से विरोध होने पर संसद् का कानून ही मान्य होगा और राज्य द्वारा निर्मित कानून अमान्य ही जावेगा।

(च) अगर दो या अधिक राज्यों के विधान-मंडल इस माध्यम का प्रस्ताव पान कर दें कि राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर संसद् ही कानून बनावे तो उन राज्यों के लिये उन विषयों पर संसद् कानून बना सकती है और उन राज्यों के विधान मंडलों को उन कानूनों में संशोधन का या उन्हें रद्द करने का अधिकार नहीं होगा। ऐसा कानून किसी अन्य राज्य में भी प्रभावी होगा, अगर वहाँ

का विधान-मण्डल भी एक प्रस्ताव द्वारा यह निश्चय करे कि इस विषय पर ससद् ही कानून बनावे । (धारा २५२)

(६) ससद् को किसी अन्य देश या देशों के साथ की हुई सन्धि या करार अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन या मन्त्रालय में किये गये किसी निश्चय के पालन के लिये भारत के सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के लिये कोई विधि बनाने की शक्ति है । (धारा २५३)

हम पहले लिख चुके हैं कि भारत का संविधान एक प्रत्यात सन्तुलित केंद्र की स्थापना करता है । देश की व्यवस्था को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया । सप को संविधान द्वारा अधिकार दिए गये हैं । सर्वश्रेष्ठ अधिकार भी सप को दिये गये हैं । समवर्ती सूची में वर्णित अधिकारों में भी सप का ही प्राथमिकता तथा प्रधानता दी गई है । इसके प्रतिरिक्त कई उपबन्ध हैं जिनके द्वारा साधारण काल में भी ससद् राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बना सकती है । संकटकाल में तो ससद् के अधिकार बहुत ही बढ जाते हैं । संसार के किसी अन्य विधान में इस प्रकार के संकटकालीन अधिकारों का उपबन्ध नहीं है ।

मध्य तथा राज्या के अधिकारों को बहुत ही विस्तृत रूप से संविधान द्वारा तीन सूचियों में वर्णित किया गया है । इस प्रकार के विस्तारपूर्वक वर्णन का लाभ यह होगा कि इनमें आपस में अंगों की कम सम्भावना रहेगी और इस कारण संविधान में कानूननियत की कमी की गई है ।

सप सूची — इस सूची में यह विषय वर्णित हैं जो सार्वदेशीय महत्व के हैं । इसमें ९७ विषय वर्णित हैं । मुख्य विषय निम्नलिखित हैं : भारत की रक्षा, भारत की जल, चल तथा नभ सेनाएँ, शस्त्रास्त्र, अणुशक्ति, दूसरे देशों सम्बन्ध युद्ध तथा शान्ति, नागरिकता तथा देखीयकरण, रेल, डाक और तार, केसार, मध्य का लोक श्रृंखला, विदेशों के साथ व्यापार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार और वाणिज्य, बीमा, अफिम की खेती, रिजर्व बैंक, मुद्रा जनपणना, निर्गम कर आदि ।

राज्य-सूची — इसमें वर्णित विषय स्थानीय महत्व के हैं । इसमें ६६ विषय वर्णित हैं । मुख्य विषय निम्नलिखित हैं : सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, न्याय प्रशासन, कारागार स्थानीय-शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, शराब और शराबान, सड़कें, पुल आदि, कृषि, वन, बाजार तथा मेले, राज्य लोक-सेवाएँ, कृषि आय पर कर आदि ।

समवर्ती सूची — इस सूची में उन विषयों को रखा है जो कि मध्य तथा

राज्य दोनों के महत्व के हैं। इसमें ४७ विषय वर्णित हैं। मुख्य ये हैं: दण्ड-विधि, दण्ड-प्रक्रिया, निवारण-निरोध, विवाह और विवाह-विच्छेद, दिवाला, न्याय और न्यायी, पशुओं के प्रति निर्दयता के निवारण आर्थिक और सामाजिक योजना, श्रमिकों का कल्याण, मृत्यु-निवन्धन, कारखाने, वाष्पमन्त्र, विद्युत्, समाचार-पत्र, पुस्तकें तथा मुद्रणालय, शरणाधिकियों की सहायता और पुनर्वास आदि।

**अन्य संघों में शक्ति विभाजन :—**अगर हम संसार के अन्य सघात्मक संविधान को देखें तो यह ज्ञात होगा कि भारत के बराबर शक्तिशाली केन्द्र प्रत्यन्त कही नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सघ सूची में ३० से भी कम विषय वर्णित हैं। अवशिष्ट अधिकार राज्यों को दिए गए हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिसके द्वारा राज्यों के अधिकार सघ के लें। कुछ विषयों में सघ तथा राज्यों के सम-वर्ती अधिकार हैं। और इन विषयों में सघ की प्राथमिकता है।

ऑस्ट्रेलिया में केन्द्र को बहुत कम अधिकार हैं। केवल ६ विषय संघ-सूची में वर्णित हैं—(१) सघ सरकार की राजधानी (seat), (२) सघ की नौकरियाँ, (३) कस्टम, आयातारी तथा निर्यात कर, (४) जहाजी मेना तथा पल सेना, (५) मुद्रा, (६) संसोधन के कुछ अधिकार। इन विषयों के प्रति-रिक्त संघ का अन्य विषयों में एकाधिकार नहीं है। राज्यों को अपना विभाग भी कुछ मात्रा तक संसोधन करने का अधिकार है। समवर्ती सूची में कई विषय हैं और इनमें संघ की ही प्रधानता है।

कैनेडा में अवशिष्ट अधिकार सघ को दिए गए हैं। सघ तथा राज्यों के विधायिनी-अधिकारों का संविधान में वर्णन है। समवर्ती सूची में केवल दो विषय हैं—कृषि तथा आवासन (Agriculture and Immigration)। कैनेडा तथा भारत के संविधान में यह समानता है कि दोनों में अवशिष्ट अधिकार केन्द्र को दिये गये हैं। कैनेडा में भी केन्द्र काफी शक्तिशाली है। वहाँ राज्यों को प्रान्त कहा जाता है। केन्द्र को प्रान्तीय विधान-मण्डल के कार्य में हस्तक्षेप करने का भी अधिकार है।

### संघ तथा राज्यों में प्रशासन-सम्बन्ध

संविधान में २५६ धारा में २६३ धारा तक इस सबय का वर्णन किया गया है। उपबन्धों द्वारा सघ सरकार को राज्यों के क्षेत्र में कुछ अवसर पर, हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया है। संविधान में यह भी कहा गया है कि अगर संघ द्वारा अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में दिए गए किन्हीं आदेशों का

पालन करने में कोई राज्य अक्षम होना, तो राष्ट्रपति यह मान सकता है कि उस राज्य में संविधान के उपबन्धों के अनुकूल शासन नहीं चलाया जा सकता है और वह उस राज्य के अधिकारों को अपने हाथ में ले सकता है (धारा ३६५)। संविधान द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होना चाहिए जिसमें समूह द्वारा बनाए हुए कानूनों का पालन सुनिश्चित रहे। राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होना चाहिए जिसमें सब की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या प्रतिस्पर्धा प्रभाव न हो। मघ को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्यों की सम्पत्ति-समय पर इन प्रयोजन के लिए आदेश दे सके। मघ राज्यों को ऐसे संचार-माध्यमों (means of communication) के निर्माण तथा बनाये रखने के लिए आदेश दे सकता है जो कि राष्ट्रीय या सैनिक महत्व के हों। मघ राज्यों को उनकी सीमाओं के अन्तर्गत रेलों की रक्षा के लिए भी आदेश दे सकता है। इन कारणों से राज्य की सरकार का जो अतिरिक्त खर्च होगा वह मघ द्वारा दिया जाएगा।

राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य की सरकार की सम्मति से उस सरकार को या उसके पदाधिकारी को ऐसे काम, जो मघ के क्षेत्र में हैं, सौंप सकता है। समूह कानून द्वारा जो भी राज्य सरकार या उसके पदाधिकारियों को ऐसे विषय पर अधिकार दे सकती है या उन पर कर्तव्य आरोपित कर सकती है जो कि राज्य सरकार के क्षेत्र के बाहर हैं। ऐसा करने पर जो अतिरिक्त खर्च होगा वह मघ द्वारा वहन किया जाएगा।

मघ की सरकार को यह अधिकार है कि वह भारत के बाहर किसी राज्य की सरकार से करार कर उस सरकार के कामों को अपने हाथ में ले सकती है।

भारत के राज्य-क्षेत्र में सब जगह मघ की और प्रत्येक राज्य की सार्वजनिक क्रियाओं (public acts), अभिलेखों (records) और न्यायिक कार्यवाहियों (judicial proceedings) को पूरा विस्मरण और पूरी गान्ध्या दी जावेगी।

समूह को यह अधिकार है कि कानून द्वारा राज्यों के भाषत में किसी नदी के पानी के ऊपर झगड़ों के समाप्ति का प्रबन्ध करे। समूह कानून द्वारा ऐसे झगड़ों को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के बाहर रख सकती है।

राष्ट्रपति आदेश द्वारा एक परिषद् की स्थापना कर सकता है जिसके नीचे लिखे कर्तव्य होंगे :

(१) राज्यों के पासतो दागदो की जाँच करना और उन पर नग्न देना :

(२) ऐसे विषयों का अनुसन्धान करना जिनमें कुछ या सब राज्यों के दा-संघ और एक या अधिक राज्यों के हित सम्बन्ध हैं।

(३) किसी ऐसे विषय पर विचारित करना ।

उही तक केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों का सम्बन्ध है उनका शासन सब न करों के अधीन है।

## संघ तथा राज्यों में वित्तीय सम्बन्ध

**भारत की वित्तीय व्यवस्था का इतिहास :—** सन् १७७३ में पूर्व भारत में बंगाल, मद्रास तथा बम्बई प्रेसीडेन्सी वित्त के विषय में पूर्ण स्वतन्त्र थी परन्तु धीरे धीरे इनकी स्वतन्त्रता कम होने लगी। सन् १८८३ में इनकी स्वतन्त्रता का पूर्णरूपेण अन्त हो गया। यह केन्द्रीयकरण की पराकाष्ठा थी। परन्तु १८७० ई० के पश्चात् पुनः विदेशीकरण आरम्भ हुआ। प्रान्तों की कुछ भाग के साधन दे दिये गये। साठे विषय तथा सग्रे कर्बन के काल में यह और बढ़ा।

प्रथम युद्ध के पश्चात् १९१९ में गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया ऐक्ट द्वारा प्रान्तों को कुछ स्वायत्त शासन के अधिकार दिए गए। इसलिए यह किना गया कि वित्त के विषय में भी प्रान्तों को केन्द्र से स्वतन्त्र रखा जाय। इस वाक्य पार्स के साधनों या केन्द्र तथा प्रान्तों के बीच विभाजन किया गया। प्रान्तों के धार के स्रोत भूमिकर, खाकरी, जंगल, ल्यान्ड, तथा रेजिस्ट्रेशन, रखे गये। केन्द्र के धार के स्रोत बल्टम, धानकर, नमक, रेल, धफीम, मिनीडरी रिस्पीट (Military Receipts) तथा डाक और तार रसे कर परन्तु इस व्यवस्था में केन्द्र की आमदनी कम हो गई। इस कारण नेल्डन एवांस द्वारा ही तय हुआ कि प्रान्त केन्द्र को सालाना १२८ लाख रुपया दे। यह १९२८-१९२९ में अन्तम हो गया।

जब १९३५ का ऐक्ट बना तो उसके द्वारा भी धार के स्रोत केन्द्र तथा प्रान्तों के बीच विभाजित किए गए : इस ऐक्ट द्वारा यह निर्दिष्ट हुआ कि धार कर म से कुछ भाग प्रान्तों को दिया जावे। जिन प्रान्तों में जूट उत्पन्न होती थी उनको जूट-निर्मात कर का कुछ भाग मिले। इसके अतिरिक्त प्रान्तों को केन्द्र द्वारा नमक कर, धानकारी आदि से हुई धार भी दी जाने वाली थी ताकि विभिन्न प्रान्त स्वास्थ्य, शिक्षा आदि पर पूरी प्रकार ध्यान दे सकें। उनको इन अनेक करों से आमदनी के अतिरिक्त केन्द्र द्वारा कुछ और सहायता दी जाने का प्रकण

हुमा। एक कमरी बंटी जिसके सम्पाति सर ओटो नेमियर व। इसने इस विषय में अपनी सिफारिश सरवार के सामने रखी। इस कमरेटी ने इस विषय में भी सिफारिश की कि आयकर तथा जूट निर्यात कर का विम प्रकार विभाजन किया जाय।

सविधान द्वारा स्थापित वित्त व्यवस्था —सविधान द्वारा सच तथा राज्यों की आय व साधना का वर्णन दिया गया है।

(१) सच की आय के साधन निम्नलिखित हैं। कृषि आय को छोड़ कर अन्य आय कर तीमा शुल्क जिसके अन्दर निर्यात शुल्क भी है। तम्बाकू पर उत्पादन कर व्यक्तियों तथा कम्पनियों के मूल धन पर कर, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति के बारे में शुल्क रेल या समुद्र या वायु नेता से आने जाने वाली वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा वर रेल के जन भाड़े पर कर, मुद्राक शुल्क ( Stamp duty ) को छोड़कर स्टॉक एक्सचेंज तथा बादा बाजार वर विनिमय पत्र चेक हुण्डो, बीमा पत्र आदि पर मुद्राक शुल्क, समाचार पत्रों के अथवा विक्रय पर तथा उनमें प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों पर कर, किमी न्यायालय में लिय जाने वाले फीमों को छोड़कर इस सूची में के विषयों में किसी के बारे में फीस।

२) स्वायत्त राज्यों की आय के साधन —अ राजस्व कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकारी के विषय में शुल्क, कृषि भूमि के विषय में सम्पत्ति शुल्क भूमि और भवनों पर कर गसद द्वारा लगाई सीमाओं के अधीन खनिज अधिकार पर कर, अफीम भाग सराय तथा अन्य नशीली वस्तुओं पर उत्पादन कर विनी लोभ में वस्तुओं के प्रवेश पर कर विद्युत कर समाचार पत्रों को छोड़कर अन्य वस्तुओं व क्रय विक्रय पर कर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों को छोड़कर अन्य विज्ञापनों पर कर, सड़को पर उपयोग के योग्य यानों पर कर पशुओं और नौकाओं पर कर पत्र पर, वृत्तियों व्यापार, धार्मिक विद्याओं और नौकरियां पर कर प्रति व्यक्ति कर, विलाम की वस्तुओं पर कर, दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी।

(३) समवर्ती आय के साधन —न्यायिक मुद्राको (Judicial stamp) द्वारा समुहोत दस्तावेजों या फीमों को छोड़कर अन्य मुद्राक शुल्क ( stamp duty ) समवर्ती सूची में के विषयों में किसी के बारे में फीस किंतु इनके अतिरिक्त किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है।

राज्य सरकारों को सच की सहायता —हम लिख चुके हैं कि १९३५ के ऐक्ट में इस प्रकार के उपबन्ध थे जिनके द्वारा प्रान्तों को सच सरकार से आर्थिक

सहायता दी जाती थी। नेमियर कमेटी (Niemeyer Committee) ने मधु द्वारा प्रान्तों की सरकारों को कितनी राशि दी जावे इसको निर्धारित कर दिया गया था। नये संविधान के द्वारा इन बातों का प्रबन्ध किया गया है मधु सरकार द्वारा राज्यों की सरकारों की वित्तीय सहायता दी जावे। यह कहना ठीक ही होगा कि नागरिकता नये संविधान द्वारा इन विषय में बना ही प्रबन्ध किया गया है जैसा कि १९३४ के ऐक्ट में था।

प्रश्न यह उठता है कि मधु द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता क्यों दी जावे? इसका उत्तर है क्योंकि राज्यों की आय इसकी नहीं है कि वे अपने विविध कर्तव्यों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य जनहित के कार्य ठीक प्रकार कर सकें। इसलिये यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि उनकी सभ्य सरकार द्वारा कुछ सहायता दी जावे। सभ्य सरकार को ध्यान हो नये ऐसी है कि उनमें आमदनी घटती ही जायेगी, जैसे आयकर, वस्तु-माध्यमिकी आदि दूसरी ओर राज्यों के कुछ साधन ऐसे हैं जिनमें आमदनी घटती जायेगी जैसे गराब पर कर, कई सरकारों ने अपने यहाँ मयनियम लागू कर दिया है। इन बातों की दृष्टि में रखते हुए यह उचित ही है कि राज्यों को सभ्य द्वारा सहायता दी जावे।

मधु तथा राज्यों में भाइयों वित्तीय-सम्बन्ध तो यह होगा कि मधु अपनी समस्त आवश्यकताएँ अपनी आय में तो पूरी कर ले तथा इसी प्रकार राज्यों के साधन उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त हो। परन्तु कार्यक्षेत्र में ऐसा होना कठिन है। तब भी इन बातों का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिये कि राज्य की सरकारें बहुत अधिक मात्रा तक मधु सरकार के ऊपर आर्थिक सहायता के लिये निर्भर न हों। क्योंकि इस प्रकार की आर्थिक-निर्भरता स्वायत्त शासन के हित में नहीं है।

सभ्य तथा राज्यों के बीच करो के वितरण के लिये संविधान में निम्नलिखित उपबन्ध हैं :—

(१) कुछ कर ऐसे हैं जो कि सभ्य द्वारा आरोपित किये जायेंगे परन्तु अपने क्षेत्र में स्वायत्त राज्यों द्वारा संग्रहीत होंगे तथा सर्व किये जायेंगे। केन्द्रीय क्षेत्रों भीतर वे सभ्य सरकार द्वारा ही संग्रहीत होंगे। इसमें ऐसे मूद्राक-शुल्क (Stamp duty) तथा औषधीय और प्रसाधन सामग्री (Medicinal and toilet preparations) ऐसे उत्पादन शुल्क हैं जो कि सभ्य-क्षेत्रों में पणित हैं। ऐसे करों की आमदनी भारत की संचित निधि का भाग नहीं होगी परन्तु उन राज्य को दी जायेगी।



( २ ) निम्नलिखित गुरू और कर भारत सरकार द्वारा चारागित और संग्रहित किया जायेगा बिन्दु राज्या का मोप लिए जायगा ।

( क ) कृषि भूमि व अग्रा अथ सम्पत्ति व उत्तराधिकार विषयक गुरू

( ग ) कृषि भूमि व अग्रा अथ सम्पत्ति विषयक सम्पत्ति गुरू

( ग ) देश समुद्र या वायु में बाहिन वस्तुओं पर या यात्रियों पर सामा कर

( घ ) रंग भाडा और वस्तु भाडा पर कर

( ङ ) स्टॉक एक्मचेंज तथा वायण बाजारा के मोदा पर स्टॉम्प ड्यूटी म आय कर

( च ) लमाचार पत्रा व नय विवर तथा उनम प्रकाशित दिनापना पर कर

इन मध्य करा से हुई आय मित्राय केन्द्राय क्षत्रा व निम्न का छोटा कर उन राज्या म व ट दी नावणी जिनम व कर उम सांग समूह है । इस बटवार के लिए मगन कामन बनावगी ।

( ३ ) कुछ कर ऐसे ह जा नि सध द्वारा लगाय जायगा तथा कमल जायग परन्तु उनकी आय सध तथा राज्या के बीच बट जावेगा —

( क ) कृषि आय व अतिरिक्त आय आय पर कर

( ग ) अगर मसद् निर्दिष्ट कर तो औपरीय तथा प्रसाधनीय सामग्रा के अतिरिक्त आय वस्तुओं पर मध्य सूची में वर्णित उत्पादन गुरू (excise duty) राज्या के बीच मसद् द्वारा निर्मित विधि व अनुसार बाटा जावेगा ।

( ४ ) अगर मसद् चाहें तो वह ऊपर वर्णित (२) तथा (३) भाग के करा म स किंगों को भी किसी समय सध के प्रयोजना के निच अधिकार (surcharge) द्वारा बढ़ा सकते हैं और इस प्रकार जो अतिरिक्त आय होगी वह केवल मध्य व सचित निधि का भाग होगी ।

आय करके बटवारा का प्रश्न — अधिधान में इस विषय में निम्नलिखित ज्ञात है आय कर व केवल गुरु आय ( net proceeds ) का ही वितरण होगा अर्थात् इस कर की वमूली में जा व्यय होगा वह इसम से पहले ही काट लिया जावेगा । इस गुरु आयम में भी वह भाग निवास किया जावेगा जा कि केन्द्रीय क्षत्रा को मित्र वाना माना जायगा तथा इसके अतिरिक्त इसमें

से संप सरकार द्वारा कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन तथा पेन्शन आदि (उपलब्धियों) का भाग भी निकाल लिया जावेगा। इसके पश्चात् जो राशि बचेगी इसमें राष्ट्रपति के आदेशानुसार स्वायत्त राज्यों को भाग मिलेगा। परन्तु जब वित्त आयोग स्थापित हो जावेगा तब राष्ट्रपति इसकी सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, आय-कर के वितरण के लिए आदेश देगा।

**संध द्वारा राज्यों को अनुदान** — इन अनुदानों को नीचे लिखे चार वर्गों में रखा जा सकता है :—

(१) संविधान में यह कहा गया है कि आसाम, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल तथा बिहार को पटसन या पटसन से बनी वस्तुओं पर निर्यात शुल्क (Export duty) के स्थान से संप द्वारा प्रति वर्ष कुछ अनुदान दिया जावेगा। जब तक भारत सरकार इन वस्तुओं पर निर्यात शुल्क वसूल करती है या संविधान प्रारम्भ होने से दस वर्ष तक, या इन दोनों में से जो भी पहले हो उसके होने तक, यह अनुदान भारत सरकार द्वारा इन चार पटसन पंदा करने वाले राज्यों को दिया जावेगा। १९३५ के ऐक्ट द्वारा भी ऐसा उपबन्ध था। इन चार प्रान्तों को निर्यात शुल्क का ६२½% भाग मिलता था।

(२) सत्तद् विधि द्वारा विभिन्न स्वायत्त राज्यों को भारत की संचित निधि में ऐसे अनुदान देने का उपबन्ध कर सकती है, जैसा कि वह उन राज्यों की सहायतायें आवश्यक समझे।

(३) अगर कोई स्वायत्त राज्य अपने अन्तर्गत अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए या अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को ऊँचा करने के लिए भारत सरकार के अनुमोदन से विकास योजनाएँ को लागू करता है तो इसमें जो खर्च होगा वह भारत सरकार द्वारा दिया जावेगा।

(४) आसाम राज्य को भारत सरकार द्वारा स्वायत्त जिलों के प्रशासन तथा उसके प्रशासन स्तर को ऊँचा करने में, जो खर्च हो वह अनुदान के रूप में दिया जावेगा। इस विषय में सत्तद् विधि निर्माण करेगी और जब तक विधि नहीं बनती है, अनुदान राष्ट्रपति के आदेश से दिया जावेगा। जब वित्त-आयोग स्थापित हो जावेगा तो राष्ट्रपति कोई आदेश इसकी सिफारिशों पर विचार किए बिना नहीं देगा।

**वित्त-आयोग** :— इस आयोग का काम राष्ट्रपति को वित्त-सम्बन्धी मामलों पर परामर्श देना होगा। राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह संविधान के प्रारम्भ से दो वर्ष के भीतर एक ऐसे आयोग की स्थापना करे। इसके पश्चात्

प्रत्येक पाँच वर्षों के पदचान् अथवा उमर पहिने में से समय पर जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे यह स्थापित किया जावेगा। इसमें एक समापति तथा चार सदस्य होंगे। दूसरी योजनाएँ समुद् विधि द्वारा निश्चित करेगी। प्रथम आयोग की स्थापना १ नवम्बर १९५१ को की गई। इसमें निम्नलिखित सदस्य थे।

(१) श्री के० मी० नियांगी (समापति)

(२) श्री बी० पी मेनन,

(३) श्री कौशल चन्द्र राय,

(४) श्री डा० बी० के० मदन,

(५) श्री लम० बी० रमचारी।

आयोग का वर्तमान निम्नलिखित खाना पर राष्ट्रपति की परामर्श देना था

(क) मघ तथा राज्यों के बीच में उन कार्यों के वितरण के बारे में जिनका विभाजन संविधान द्वारा निश्चित किया गया है तथा राज्यों के बीच उनके भाग २ बेटपात्र के बारे में।

(ख) भारत की संविधान विधि में से राज्यों की अनुदान देने में पारंपरिक सिद्धान्तों के बारे में

(ग) भारत सरकार तथा विभिन्न राज्यों की सरकार के बीच किए गए करों के उपबन्धों के पालन करने अथवा उनमें कोई बदलाव करने के लिए।

(घ) राष्ट्रपति द्वारा कोई वित्त-सम्बन्धी विषय के बारे में।

राष्ट्रपति संविधान के उपबन्धों के अधीन वित्त-आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को तथा उमर पर की कार्यवाही के विवरण को, मगद के प्रत्येक मदन के समक्ष रखवाता। राष्ट्रपति के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह आयोग के परामर्श अनुसार ही निर्णय ले। परन्तु यह आवश्यक है कि वह निगी निर्णय लेने के पछि आयोग में परामर्श अवश्य ले।

संविधान में कहा गया है कि वित्त-आयोग अपनी प्रक्रिया निर्धारित करेगा तथा अपने कृत्यों के पालन में उसे के अधिकार होंगी जो समुद् विधि द्वारा उसे दान कर।

मघ तथा राज्यों में कर-वितरण आदि का वर्तमान प्रश्न -- वित्त-आयोग स्थापित होने तक मघ तथा राज्यों के बीच आयकर किस प्रकार वितरित है इसका निश्चय करना था। इसलिये सरकार ने दो कमेटियाँ नियुक्त की।

एक के समापति श्री एन० आर० सरकार ये तथा दूसरे के श्री वी० पी० अडारकर ये । परन्तु इन दोनों की रिपोर्ट सन्तोष-जनक न होने के कारण यह कार्य श्री सी० टी० देशमुख (भूत पूर्व वित्त-मंत्री) को सौंपा गया । श्री देशमुख का निर्णय साधारण परिवर्तनों के प्रतिरिक्त वैसा ही है जैसा कि नेमियर-निर्णय था । इस निर्णय के अनुसार यह निश्चित किया गया था कि प्रायकर के शुद्ध-भाग का ५०% भाग राज्यों में निम्न प्रकार से विभक्त हो

मद्रास	१७.५%
बम्बई	२१%
बंगाल	१३.५%
उत्तर प्रदेश	१८%
पंजाब	५.५%
बिहार	१२.५%
मध्य प्रदेश	६%
आसाम	३%
उड़ीसा	३%

श्री देशमुख का निर्णय १ अप्रैल १९५० में लागू हुआ तथा ३१ मार्च, १९५२ तक लागू रहेगा यह निश्चित किया गया था ।

श्री देशमुख द्वारा ही इसका निर्णय किया गया कि पटसन के निर्यात-शुल्क के बदले में पश्चिमी बंगाल, आसाम, बिहार तथा उड़ीसा को कितना अनुदान मिलेगा ।

पश्चिमी बंगाल	१०५ लाख रुपया वार्षिक
आसाम	४० लाख रुपया वार्षिक
बिहार	३५ लाख रुपया वार्षिक
उड़ीसा	५ लाख रुपया वार्षिक

वित्त आयोग की सिफारिशें :—वित्त आयोग की रिपोर्ट १३ फरवरी १९५३ को श्री देशमुख द्वारा मन्त्रिमंडल में प्रस्तुत की गई । सिफारिशें भारत सरकार द्वारा मान ली गई तथा ये १ अप्रैल १९५३ में लागू हुई ।

मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं :—

(१) प्राय-कर के शुद्ध-भाग का ५५% भाग राज्यों में निम्न प्रकार से विभक्त होगा :—

आसाम	२.२५%
बिहार	१.७४%
बम्बई	१७.१%
हंदरावाद	४.५%
मध्य भारत	१.७५%
मध्य प्रदेश	५.४५%
मद्रास	१५.२५%
मैसूर	२.२५%
उडिसा	३.५%
पेप्पू	७.५%
पंजाब	३.२५%
राजस्थान	३.५%
सीर पट्ट	१%
त्रावनकोर-कोचीन	२.५%
उत्तर प्रदेश	११.५%
पश्चिमी बंगाल	११.२५%

(२) पटसन के निर्यात शुल्क के बदले बंगाल, आसाम, बिहार तथा उड़ीसा को निम्नलिखित वार्षिक अनुदान मिले, बंगाल १५० लाख आसाम ७५ लाख बिहार तथा उड़ीसा १५ लाख रुपये।

(३) राज्यों को सघ की कुछ एक्साइज ड्यूटीज (Excise Duties)—सम्बाबू, दिमामलाई तथा बेजीटैबिल ग्राइवुड्स—का भाग दिया गया।

(४) जिन राज्यों को आयोग उपयुक्त समझे उनको मध द्वारा कुछ अधिक सहायता दी जाय।

(५) कुछ कम उन्नत राज्यों की प्रारम्भिक शिक्षा के विकासार्थ मध द्वारा सहायता दी जाय।

**द्वितीय वित्त आयोग** —भारत सरकार द्वारा एक नवीन वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग ने राष्ट्रपति के सम्मूह निम्न विषयों में निष्कारिण की थी।

(१) केन्द्र और राज्या में आयकर का वितरण और राज्या के हितों का राज्यों में वितरण।

(२) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क इत्यादि केन्द्रीय करों का वितरण।

(३) पटसन और पटसन के माल के निर्यात शुल्क की भाय व हिस्से के बदले आसाम, बिहार, बंगाल, और उड़ीसा को कितनी रकम दी जाय ।

(४) वे मिद्वान्त जिनके आधार पर भारत की सचिव निधि में से राज्यों को अनुदान दिये जायें ।

(५) वे कौन से राज्य हैं जिन्हें अपने राजस्व में से अनुदान की आवश्यकता है । अन्य बातों के मलावा पंचवर्षीय योजना की आवश्यकताओं को देखकर तथा यह देखकर कि ये राज्य अपने साधनों से घन एकत्र करने का जिनना प्रयत्न कर रहे हैं, तय करना कि इन्हें कितनी सहायता कर दी जाय ।

(६) कृषि भूमि को छोड़कर और संपत्ति पर लगने वाले मपदा शुल्क की भाय को किम आधार पर बाँटा जाय ।

(७) १५ अगस्त, १९४७ और ३१ मार्च, १९५७ के बीच केन्द्र ने राज्य की सरकारों को जो कर्ज दिया है उसकी ग्याज दर और अदापगी की बातों में क्या किसी प्रकार के संशोधनों की आवश्यकता है ।

नये वित्त आयोग को द्वितीय पंचवर्षीय योजना तथा राज्यों के पुनर्गठन को ध्यान में रखते हुए, हर राज्य के हिस्से को नये सिर से तय करना था ।

**वर्तमान स्थिति**—वित्त आयोग ने करों के वितरण के सम्बन्ध में निम्नोक्त मुख्य सिफारशों की हैं जो वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में लागू हुई —

आयकर के शुद्ध आगम का ६०% भाग राज्यों में निम्नोक्त प्रकार में वितरित हो —

आंध्र	८.१२%	पैमूर	५.९४%
आसाम	२.४४%	उड़ीसा	३.७३%
बिहार	९.९४%	पंजाब	४.२४%
बम्बई	१५.९०%	राजस्थान	४.०९%
केरल	३.६४%	उत्तर प्रदेश	१६.३६%
मध्य प्रदेश	६.३०%	पश्चिमी बंगाल	१०.०८%
मद्रास	८.४०%	जम्मू तथा काश्मीर	१.१३%

इन राज्यों के अतिरिक्त केन्द्रीय शासित प्रदेशों को १% दिया जायगा ।

(२) राज्यों को सब की इबसाइज ड्यूटी—सम्बाकू, दियामलाई, वेजी-टेविल, प्रोडक्ट्स, चीनी, चाय, कौफी, कागज, तथा वेजीटेबिल तेल के ऊपर—का २५% भाग दिया जाय ।

(३) वित्त आयोग ने यह भी सिफारिश की पटसन के निर्यात शुल्क के बढ़ाये पश्चिमी बंगाल को १५२.६९ लाख, बिहार को ७२.३१ लाख, आसाम को ७५ लाख तथा उड़ीसा को १५ लाख रुपये का अनुदान दिया जाय।

(४) कृषि भूमि के अतिरिक्त सम्पत्ति पर इस्टेट द्यूटी का वितरण जिस आधार पर राज्यों के मध्य किया जाय इसका भी आयोग ने सिफारिश की है। ये अनुदान १०.६० सन् के अन्त में बन्द हो जायेंगे।

(५) इसी प्रकार राज्य सरकारों ने सेल्स टैक्स के स्थान पर कपड़े (textile), चीनी तथा तम्बाकू पर अतिरिक्त इक्साइज द्यूटी से जो आय होगी इसका वितरण राज्यों के मध्य किसी आधार पर हो इसके भी आयोग ने सिफारिश की है।

(६) रेलभाड़े में टैक्स से जो आयदनी होगी उसके वितरण की भी सिफारिश की गई है।

**संचित निधि** -- इस अध्याय में कई समय 'संचित-निधि' का प्रयोग किया गया है। वहाँ पर उचित प्रतीत होता है कि इसका अर्थ बतलाया जाय।

सविधान द्वारा यह व्यवस्था की गई है (धारा, २६६) कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त सब राजस्व, राजहूदिया को निकाल कर उधार द्वारा और अर्घोपाय पेशगियों द्वारा लिए सब उधार, तथा उधारों के प्रतिदान में उस सरकार की प्राप्त सब धनो की एक संचित निधि बनेगी जो भारत की संचित निधि के नाम से जाना होगी तथा राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त सब राजस्व, राजहूदिया को निकाल कर उधार द्वारा और अर्घोपाय पेशगियों द्वारा लिए गए सब उधार तथा उधारों के प्रतिदान में उस सरकार को प्राप्त सब धनो की एक संचित निधि बनेगी जो राज्य की संचित निधि के नाम से जाना होगी।

भारत की सरकार तथा राज्यों की सरकार द्वारा या और से प्राप्त अन्य सब नावर्जनिक धन यथाशक्ति भारत के या राज्य के लोक लेखे में जमा किये जायेंगे।

संचित निधि में से धन केवल विधि की अनुकूलता से या इस सविधान में वर्णित रीति से ही निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं।

संचित निधि के अतिरिक्त भारत सरकार तथा राज्यों की सरकारें एक आकस्मिक निधि की भी स्थापना करेंगी। भारत सरकार के लिए ऐसी निधि की स्थापना ससद विधि द्वारा करेगी। इसी के द्वारा यह भी निश्चय होगा कि इसमें समय-समय पर कौन सी राशियाँ डाली जायें। इस आकस्मिकता निधि

में से राष्ट्रपति मन्त्र की आज्ञा मिलने से पूर्वे व्यन कर सकता है। यह निधि राष्ट्रपति के हाथ में रखी गई है।

इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को भी एक आकस्मिक निधि होगी। इसकी स्थापना का अधिकार राज्यों के विधान मण्डल को दिया गया है। यह निधि राज्यपाल के हाथों में रहेगी और यह इनमें से विधान-मण्डल की आज्ञा से पूर्वे आकस्मिक कार्यों के लिए धन दे सकता है।

### प्रश्न

(१) संघ तथा राज्यों के मध्य संविधान द्वारा किस प्रकार अधिकार विभाजन दिया गया है? संघ तथा उत्तराखण्ड राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र का वर्णन कीजिये।

(२) वित्त आयोग के क्या कार्य हैं? इस आयोग की क्या शक्तियाँ थीं?

(३) संघ तथा राज्यों के मध्य पित्तोप सम्बन्ध पर एक टिप्पणी लिखिए?



## अनुसूचित क्षेत्रों तथा जन-जातियों के लिए विशेष प्रबन्ध

बिहार, उड़ीसा तथा प्रदेश, मद्रास राजस्थान तथा माध्याम में कई पिछड़े हुए वर्ग हैं जिनकी जनजाति वृद्ध है। सम्यता की दृष्टि से ये परान्त पिछड़ी हुई प्रदस्था में हैं। इनकी आर्थिक तथा सांस्कृतिक अवस्था भी शोचनीय है। इनकी उन्नति की दृष्टि से समीपान से इनके शासन व नियम विशेष उपक्रम हैं।

ये अनुसूचित क्षेत्र समीपान द्वारा दो भागों में विभक्त किये गये हैं तथा उनके लिये अलग-अलग शासन-व्यवस्था का प्रबन्ध किया गया है। एक भाग में तो सामान्य के जनजाति क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य राज्यों के ऐसे क्षेत्र रखे गये हैं। दूसरे भाग में सामान्य के जनजाति क्षेत्र रखे गये हैं। इनके शासन का समान परान्त क्रिया जगता।

आमाम के अतिरिक्त अन्य अनुसूचित क्षेत्रों का निर्धारण — राष्ट्रपति की समीपान द्वारा यह अधिकार दिया है कि वह राज्य द्वारा यह घोषणा कर कि विभिन्न राज्यों में कौन अनुसूचित जनजातियाँ हैं तथा कौन अनुसूचित क्षेत्र हैं। इन घोषणा में वह चाहती वेबल निम्नलिखित परिचयन कर सकता है।

(क) कि कोई सम्पूर्ण समन्वित क्षेत्र या उसका कोई उल्लिखित भाग अनुसूचित क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र का भाग न रहेगा।

(ख) किसी अनुसूचित क्षेत्र को उद्घाटन होगा। किन्तु सबक सीमाओं का सीमा कराने हो बदल सकेगा।

(ग) किसी राज्य को सीमाओं के किसी परिवर्तन पर पक्ष या मध्य में किसी राज्य के प्रवेश पर मध्य या राज्य की स्थापना पर एत किसी क्षेत्र का अनुसूचित क्षेत्र या उसका भाग पापित कर सकेगा जो पहिल में किसी राज्य में समाविष्ट नहीं है।

इनका शासन — प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका बचिर का विस्तार उसमें १ अनुसूचित क्षेत्र तक होगा। परन्तु, उन राज्य के राजधानी को जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है अतिरिक्त या जब की राष्ट्रपति चाहें, इसके शासन प्रबन्ध के बारे में राष्ट्रपति की रिपोर्ट देनी होगी। मध्य की कार्यपालिका पर यह अधिकार है कि वह राज्य की कार्यपालिका को इन दोनों के शासन के बारे में आदेश

दे सकती है। इस प्रकार राज्यों की कार्यपालिका इस विषय में सघ कार्यपालिका के अधीन की गई है। राज्यपाल यह आदेश दे सकता है कि समझ या उस राज्य ने विधान मण्डल का कोई कानून उस राज्य के अनुमूर्ति क्षेत्र या उसके किसी भाग में बिल्कुल ही लागू नहीं होगा या कुछ परिवर्तनों के साथ लागू होगा। राज्यपाल को यह भी अधिकार है कि वह ऐसे क्षेत्रों की शान्ति और सुशासन के लिये नियम बना सकेगा। वह अनुमूर्ति जनजाति के सदस्यों द्वारा भूमि के हस्तान्तरण या उसके विवरण के सम्बन्ध में नियम बना सकता है। ऐसे नियम तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि उन्हें राष्ट्रपति की अनुमति न मिल जावे। राज्यपाल ऐसे नियमों को बनाने के पूर्व उन राज्य में जनजाति मजदूरी परिषद् से परामर्श लेगा।

**जनजाति मंत्रणा परिषद्** — प्रत्येक राज्य में जिसमें अनुमूर्ति क्षेत्र है, तथा राष्ट्रपति के आदेश पर ऐसे राज्यों में भी, जहाँ अनुमूर्ति जनजातियाँ हैं यद्यपि अनुमूर्ति क्षेत्र नहीं है, एक जनजाति मंत्रणा परिषद् स्थापित होगी। इसमें बीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे। इसके सदस्यों में से जहाँ तक सम्भव हो तीन चौपाई उस राज्य की विधान सभा में से अनुमूर्ति जनजातियों के प्रतिनिधि होंगे। परन्तु अगर विधान मण्डल में प्रतिनिधियों की संख्या इस निश्चित मर्यादा से कम है तो ऐसे स्थान उन जातियों के अन्य सदस्यों द्वारा भरे जायेंगे।

इस परिषद् का कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की जनजातियों के कल्याण और उन्नति से सम्बन्ध रखने वाले ऐसे विषयों पर राय दे जो कि उनकी राज्यपाल द्वारा मीने जायें।

राज्यपाल की परिषद् के सम्बन्ध में निम्नलिखित विषयों पर नियम बनाने का अधिकार है —

(क) सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्ति तथा परिषद् के सभापति तथा पदाधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति।

(ख) परिषद् के अधिवेशनों के संचालन तथा उनकी साधारण प्रक्रिया।

(ग) अन्य सब प्रासंगिक विषयों पर।

इन क्षेत्रों के विषय में उपरोक्त वर्णित उपबन्धों को संसद् जब चाहे तब मनोपित कर सकती है। ऐसा संशोधन संविधान का संशोधन नहीं समझा जावेगा। अर्थात् संसद् साधारण विधि से ही इनमें संशोधन कर सकती है।

**आसाम के जनजाति क्षेत्र** —आसाम के जन-जाति क्षेत्रों के बारे में सविधान में अन्य राज्यों के जन जाति क्षेत्रों से अलग उपबन्ध है। इसका कारण यह है कि आसाम के जन-जाति धर्म तथा संस्कृति की दृष्टि से सर्वथा भिन्न हैं। इस कारण यह स्वाभाविक था कि उनके शासन के लिये विशेष व्यवस्था हो। तत् की अन्य जन-जातियाँ साधारणतः हिन्दू समाज के अन्तर्गत आ जाती हैं परन्तु आसाम की जन-जातियाँ अपना अलग अस्तित्व रखती हैं।

आसाम के जनजाति क्षेत्रों को दो भागों में बाँट दिया गया है—इनको क्रमशः 'क' तथा 'ख' भाग कहा जाता है।

'क' भाग में ६ क्षेत्र हैं। इनमें से प्रत्येक एक स्वायत्त क्षेत्र है। इनके नाम हैं —

( १ ) मयुक्ता खासी-जयंतिया पहाड़ी।

( २ ) गारो पहाड़ी जिला।

( ३ ) लसाई पहाड़ी जिला, (मगध ने एक विधेयक पारित कर यह निश्चय किया है कि इस जिले का नाम मिजा जिला (Mizo District) कर दिया जाय)।

( ४ ) नागा पहाड़ी जिला।

( ५ ) उत्तरी कछार पहाड़ियाँ।

( ६ ) मिबिर पहाड़ियाँ।

'ख' भाग में निम्नलिखित क्षेत्र है —

( १ ) उत्तरी-पूर्वी सीमान्त इलाका जिनके अन्तर्गत बालिपारा सीमान्त इलाका, निराय सीमान्त इलाका, अंबोर पहाड़ी जिला और मिमिम पहाड़ी जिला भी हैं।

( २ ) नागा जनजाति क्षेत्र।

राज्यपाल, राष्ट्रपति की अनुमति से, 'ख' भाग में वर्णित जनजाति क्षेत्रों का शासन उन्हीं उपबन्धों द्वारा कर सकता है जो कि 'क' भाग के लिए लागू होंगे। परन्तु जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक राष्ट्रपति इन जन-जाति क्षेत्रों का शासन आसाम के राज्यपाल द्वारा करवायेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में अपने स्वविवेक से काम करेगा। इन क्षेत्रों को स्वायत्त शासन का अधिकार इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि अभी तक भारतीय अधिकारियों को इनके कुछ भागों के बारे में पूरा परिचय नहीं है।

'क' भाग के जनजाति क्षेत्रों का शासन — इस भाग के प्रत्येक जनजाति क्षेत्र का एक स्वायत्त जिला होगा। यदि किसी जिले में भिन्न-भिन्न जन-जातियाँ हैं तो राज्यपाल इन जन जातियों के अनुसार जिले को स्वायत्त प्रदेशों (autonomous regions) में बाँट देगा। राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह दो स्वायत्त जिलों को मिलाकर एक कर दे, या एक को दो में बाँट दे, या किसी स्वायत्त जिले के क्षेत्र को घटा दे, या बढ़ा दे।

प्रत्येक स्वायत्त जिले के लिए जिला परिषद् होगी। इसमें बीबीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे। इसमें कम से कम तीन-चौथाई का वयस्क-मतदाताधिकार के आधार पर निर्वाचन होगा। प्रत्येक स्वायत्त प्रदेश के लिये एक प्रादेशिक परिषद् होगी। स्वायत्त प्रदेश का शासन प्रादेशिक परिषद् में तथा जिले का शासन जिला-परिषद् में निहित होगा। राज्यपाल जिला-परिषद् तथा प्रादेशिक-परिषद् के प्रथम गठन के लिए नियम बनायेगा। इसके पश्चात् ये परिषदें स्वयं अपने गठन के लिये नियम बना लेंगी।

इन परिषदों को चार प्रकार के अधिकार हैं — कानून सम्बन्धी, न्याय-सम्बन्धी, वित्त-सम्बन्धी तथा शिक्षा सम्बन्धी।

कानून सम्बन्धी — इन परिषदों को अपने अपने क्षेत्र के अन्दर निम्न-लिखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है —

( १ ) किसी रक्षित वन की भूमि को छोड़कर अन्य भूमि को ऐसे प्रयोग के लिये जिससे किसी ग्राम नगर निवासियों के हितों की उन्नति सम्भव हो, बाँटना (allotment), दलल, या उपयोग या प्रयोग रखना।

( २ ) रक्षित वन न होने वाले किसी वन का प्रवन्ध।

( ३ ) कृषि प्रयोजनार्थ किसी नहर या जलधारा का प्रयोग।

( ४ ) भूमि की प्रथा या अन्य प्रकार की स्थानान्तरणशील (shifting) कृषि की प्रथा का विनियम (regulation)।

( ५ ) ग्राम अथवा नगर समितियों या परिषदों की स्थापना और उनकी शक्तियाँ।

( ६ ) ग्राम या नगर प्रशासन से सम्बद्ध कोई अन्य विषय जिनके अंतर्गत ग्राम या नगर पुलिस और लोक-स्वास्थ्य तथा स्वच्छता भी हैं।

( ७ ) प्रभुत्व या मुखियों की नियुक्ति तथा उत्तराधिकार।

( ८ ) सम्पत्ति का दायभाग (inheritance)।

(९) विवाह ।

(१०) सामाजिक स्थिति ।

परन्तु इन सब विषयों पर उपरोक्त परिपदा द्वारा निर्मित कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक उन्हें राज्यपाल की अनुमति प्राप्त न हो जाय। जिला परिषद का अपने क्षेत्र के अन्दर निवास करने वाले जन-जातियों में भिन्न भागों, साहूकारी तथा व्यापार पर नियन्त्रण के लिए नियम बनाने का भी अधिकार है।

**ध्याय सम्बन्धी** — जिला परिषद तथा प्रदेस परिषद को अपने अपने क्षेत्र के अन्दर साम परिषदों या न्यायालय स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। इनमें ऐसे मामलों कायें जिनमें दोनो पक्ष इन क्षेत्रों के भीतर की जन-जातियों के हों हैं। इन साम परिषदों तथा न्यायालयों से अपील प्रदेश परिषद या जिला परिषद में होगी। सामान के उच्च न्यायालय को इसके ऊपर ऐसे अधिकार होंगे जैसे कि राज्यपाल समय समय पर आदेश दे। राज्यपाल इन परिषदों को अदालत प्रक्रिया संहिता १९०८ (Code of Civil Procedure) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता १८९८ (Code of Criminal Procedure) के अधीन कुछ शक्तियाँ प्रदान कर सकता है जैसे मृत्यु दण्ड, राजीवन बालापानी का / वष से अधिक के लिये बाराबाद। राज्यपाल जब चाहे तब इन शक्तियों को छीन सकता है या उन्हें बदलाव कर सकता है।

**वित्त सम्बन्धी** — जिला परिषद तथा प्रदेश परिषद का अपने अपने क्षेत्र के अन्दर सब भूमिों के बारे में उन सिद्धान्तों के अनुसार लगान लगाने और वसूल करने का अधिकार होगा जो साधारण सामान सरकार द्वारा माने जाते हैं। ये अपने क्षेत्र के अन्दर भूमि तथा दूसारों पर कर तथा एवं क्षेत्रों में निवास करने वाले स्थितियों पर पथ कर (Tolls) लगा सकती हैं। इनके प्रतिस्वत इनको नीचे लिखे कर लगाने तथा वसूल करने का भी अधिकार है वृत्तिमा, व्यापारिया, शारीकिकार और नौकरिया पर कर, पशुओं, यातों और ताबों पर कर, किसी बाजार में बहुरा दिवने के लिये वस्तुओं के प्रवेश पर कर तथा मावों व जाने वाले स्थितियों और माल पर पथ कर, पाठशालाओं और शालाओं या सड़कों के बनाय रखने के लिये कर। इन प्रतिस्वत जिला परिषद का अपने क्षेत्र के अन्दर जो चाहें हैं उसकी आपदनी का एक भाग दिया जायगा। इसका निश्चय सामान सरकार तथा जिला परिषद के बीच एक करार द्वारा किया जायगा। अगर इनके बारे में कोई समझा हो तो राज्यपाल उसका निश्चय करेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

प्रत्येक जिला में एक जिला निधि तथा प्रदेश में एक प्रदेश निधि होगी जिसमें कर्मचारी जिवे तथा प्रदेश द्वारा प्राप्त भव्य धनो का जमा किया जावेगा। इन निधियों के प्रबन्ध के लिये जिला परिषद् तथा प्रदेश परिषद् राज्यपाल के अनुमोदन से नियम बनायेंगे।

**शिक्षा सम्बन्धी, आदि अधिकार**—जिला परिषद् को मनने क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों, औपशाल्यों, बाजारों काबोहीत, नीवाट, मोन-जंभ (Ficheries) मडको और जल पयों की स्थापना, निर्माण और प्रबन्ध करने का अधिकार है। यह इमका भी निश्चय करेगी कि प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में दी जावे तथा किस रीति में दी जावे।

**जांच आयोग**—राज्यपाल इन जिलों के या प्रदेशों के शासन की जांच के लिये किसी समग्र भी एक आयोग नियुक्त कर सकता है। विशेषतः ऐसा आयोग निम्नलिखित बातों की जांच करेगा :—(१) शिक्षा और शिक्षता की सुविधाएँ तथा उनके प्रबन्ध, (२) इन क्षेत्रों के बारे में किसी नये विधान की प्रावश्यकता तथा, (३) इन परिषदों द्वारा बनाये गये विधियों, नियमों आदि की। यह आयोग अपनी जांच की रिपोर्टें राज्यपाल को देगा। इन बातों के प्रतिनिधित्व राज्यपाल इन जिला की सीमाओं के बारे में, नये जिले बनाने के या दो जिलों को मिलाकर एक करने के बारे में, उनके क्षेत्रों को घटाने या बढ़ाने के बारे में भी जांच करने के लिये आयोग स्थापित कर सकता है। स प्रकार के आयोगों की रिपोर्टें को राज्यपाल विधानमण्डल के सामने रखवायेगा। राज्यपाल एक मन्त्री को विशेषतया इन क्षेत्रों के कल्याण के लिये नियुक्त कर सकेगा।

**संविधान में जन जातियों तथा जनजाति क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबन्ध**

इन विशेष उपबन्धों की व्यवस्था इस कारण की गई है ताकि ये विच्छेद हुए वर्ग जल्दी से भन्व भागों के समतल हो जावें। संसद तथा विधानमंडलों में इन अनुसूचित जनजातियों को (सिवाय आसाम के 'ख' भाग के) विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह उपबन्ध संविधान प्रारम्भ होने से दस वर्ष तक रहेगा।

जिन राज्यों में ऐसे क्षेत्र हैं उन्हें इनके विकासाय तथा कल्याणाय योजनाएँ बनाने को उत्साहित किया गया है। इन योजनाओं के भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने पर उन्हें वार्यान्विन करने का पूरा खर्च भारत सरकार

सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों समझा जावे, इनका निश्चय करेगा। स्वयंसेवक राज्यों के बारे में वह इनके राज्यपाल से परामर्श करके इनका निश्चय करेगा। १० अगस्त १९५० को राष्ट्रपति ने एक आदेश द्वारा आसाम, बिहार, उड़ीसा, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला तथा पूर्वी बंगाल राज्यसंघ, हैदराबाद, भावनगर-कोचीन, राजस्थान तथा नीराष्ट्र में कौन-कौन अनुसूचित जातियाँ हैं इसकी घोषणा की। राष्ट्रपति द्वारा इन प्रकार निर्मित सूची में संसद् को परिवर्तन करने का अधिकार है।

लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिये स्थान उनकी जनसंख्या के आधार पर रक्षित रहेंगे। इसी प्रकार राज्यों की विधान सभाओं में भी उनके लिये स्थान सुरक्षित रखे गए हैं परन्तु यह व्यवस्था संविधान प्रारम्भ होने के दस वर्ष बाद समाप्त हो जावेगी। मध्य तथा राज्य की नौकरियों में भी नियुक्तियाँ करने में इन जातियों के सदस्यों के हितों का ध्यान रखा जावेगा। सितम्बर १९५० में इनके लिये केन्द्रीय नौकरियों में सुरक्षित स्थानों की संख्या निर्दिष्ट कर दी गई है।

राष्ट्रपति अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिये एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त करेगा। इसका काम संविधान द्वारा इन वर्गों के लिये जो विशेष व्यवस्था की गई है उससे सम्बन्धित बातों की जाँच करना तथा राष्ट्रपति को उसके बारे में रिपोर्ट देना होगा। राष्ट्रपति इसकी रिपोर्ट को संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। यह पदाधिकारी आंग्ल-भारतीय समुदाय तथा पिछड़े वर्गों के विषय में जाँच करेगा। इस उपबन्ध के अनुसार नवम्बर १८, १९५० को राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिये एक कमिशनर की नियुक्ति की गई। इसके अधीन ६ सहायक कमिशनर हैं। इनमें से प्रत्येक एक-एक क्षेत्र विशेष के लिये कार्य करता है। कमिशनर द्वारा अभी तक राष्ट्रपति को चार रिपोर्टें दी जा चुकी हैं।

राष्ट्रपति संविधान लागू होने के दस वर्ष पश्चात् एक आयोग की नियुक्ति करेगा जो कि अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के शान्त के सम्बन्ध में उनको रिपोर्ट देगा। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति इस काल के पूर्व भी कर सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति साम्प्रतिक तथा भविष्य की दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की दशा की जाँच करने के लिये भी एक आयोग स्थापित कर सकता है। इन आयोग की रिपोर्टें संसद के सम्मुख रखी जावेगी।

**आंग्ल भारतीय समुदाय :—**यद्यपि राष्ट्रपति यह सोचें कि लोकसभा में इस समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो वह इसके अधिक से

प्रथम दो सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इसी प्रकार राज्यों में राज्य-पाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह इस समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व न होने पर विधान सभा में जितने उचित समझे उतने इस समुदाय से सदस्य मनोनीत कर सकता है। यह विशेष व्यवस्था संविधान प्रारम्भ होने के वर्ष के पश्चात् लागू नहीं रहेगी।

अंग्रेजी सरकार ने अधीन आंग्ल-भारतीय के लिये कुछ सरकारी सेवाओं में बहुत अधिक स्थान थे जैसे रेलवे, पोस्टल, डाक सार विभाग। इस समुदाय के अधिकतर सदस्य अपनी आजीविका के लिए सरकारी नौकरी करते आए हैं। इसलिए यह उचित समझा गया है कि नये संविधान के लागू होने पर एकदम इनकी स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना चाहिये। इस लिये संविधान द्वारा यह उपबन्ध दिया गया कि हमारे प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम दो वर्षों में मध्य की रेल, पोस्टल, डाक सार सम्बन्धी सेवाओं में उस समुदाय के लोगों की नियुक्तियाँ उसी आधार पर की जावेंगी जिस आधार पर १५ अगस्त १९४७ ई० से पूर्व की जाती थी। संविधान लागू होने के प्रत्येक दो वर्ष की समाप्ति पर समुदाय के लिए रक्षित स्थानों में कम प्रतिशत कमी की जावेगी। तथा १० वर्ष की समाप्ति पर हम प्रकार के रक्षण का अन्त हो जावेगा।

आंग्ल-भारतीय समुदाय के शिक्षण के लिये विशेष अनुदानों का प्रबन्ध किया गया है। संविधान लागू होने के बाद तीन वर्ष तक इनका शिक्षण-मन्त्रालय को विभिन्न राज्यों में वही अनुदान मिलते रहेगे जैसे कि ३१ मार्च १९४८ ई० को अन्त होने वाले वित्तीय वर्ष में दिए गए थे। इस काल पश्चात् प्रति तीन वर्ष की समाप्ति पर इन अनुदानों में १० प्रतिशत कमी की जावेगी। परन्तु संविधान प्रारम्भ होने से १० वर्ष की समाप्ति पर ऐसी रियायत का अन्त हो जावेगा। परन्तु किसी आंग्ल-भारतीय शिक्षण मन्त्रालय को इस प्रकार के विशेष अनुदान तब तक नहीं दिए जायेंगे जब तक इसमें कम से कम ४० प्रतिशत आंग्ल-भारतीयों के अतिरिक्त अन्य वर्गों के विद्यार्थी प्रति वर्ष प्रवेश न पायें।

पिछड़े वर्गों के लिए कमीशन — राज्य की नीति के निदेशक भाग में यह उपबन्ध है कि राज्य जनसंख्या के पिछड़े वर्गों की उन्नति-आर्थिक तथा सांस्कृतिक — की ओर विशेष ध्यान देगा। इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान की ३४० धारा में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत-राज्य क्षेत्र के अन्दर सामाजिक तथा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की दशा की जाच करवाने के लिये एक कमीशन की नियुक्ति करेगा। यह कमीशन इस बात की



निकारित करने कि उन्नति के हेतु नष्ट तथा राज्य नरकायों को बचा करना चाहिये । तथा इस उद्देश्य में उनकी क्या अनुदान (Grants) देना चाहिये । दिसम्बर १९५२ में गृह-मन्त्री ने संसद् में यह घोषणा की कि नीचे ही इन कमीशन की नियुक्ति की जायेगी । जनवरी १९५३ में संसद्-पति ने अपने आदेश द्वारा इन कमीशन को नियुक्त किया । इसके निम्नलिखित सदस्य थे :

- ( १ ) श्री बाबा साहेब बालेलकर (समानादि)
- ( २ ) श्री एन० एन० कन्नोडकर
- ( ३ ) श्री बीका भाई
- ( ४ ) श्री सिवटान सिंह बोरसिया
- ( ५ ) श्री राजेश्वर पटेल
- ( ६ ) श्री प्रबुल कैम्पूज प्रन्सा
- ( ७ ) श्री लाला जगन्नाथ
- ( ८ ) श्री मरेप्पा
- ( ९ ) श्री बरनांगु दे

इस कमीशन के निम्नोक्त कर्तव्य थे :—

( अ ) इस बात का निर्णय करना कि किन आधार (criterion) पर किसी वर्ग विशेष अथवा जनतन्त्रों के नाम को पिछड़ा वर्ग कहा जा सकता है ।

( ब ) सम्पूर्ण भारत के लिए ऐसे वर्गों की तालिका प्रस्तुत करना ।

( स ) इनकी दशा तथा कठिनाइयों की जाँच करना तथा इस बात की सिफारिश करना कि संघ सरकार तथा राज्य सरकारों को इनकी दशा में सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए ।

इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को ३१ मार्च, १९५५ को दी । सरकार ने इस रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्गों के हित में कुछ महत्वपूर्ण पद्य उठाए हैं । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक-एक केन्द्रीय परामर्शदात्री बोर्ड का निर्माण किया गया है । अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी इसी प्रकार के एक बोर्ड की स्थापना का विचार है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कमीशन के सिफारिशों को पूरा करने के लिए अनेक योजनाएँ हैं ।

### प्रश्न

( १ ) अनुसूचित लोगों में क्या तात्पर्य है ? आन्ध्र के प्रतिनिधित्व अन्य अनुसूचित लोगों का किन प्रकार निश्चय किया जायेगा तथा वहाँ की क्या दायित्व अवस्था होगी ?

(२) आसाम के अनुसूचित क्षेत्रों के लिये संविधान में क्या विशेष व्यवस्था है ?

(३) आंग्ल-भारतीय समुदाय के हितों को किस प्रकार सुरक्षित रखा गया ?

(४) पिछड़े वर्गों के कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये ।

## अध्याय १८

### राजभाषा

स्वतन्त्रता के पूर्व भारत की राजभाषा अंग्रेजी थी। क्योंकि उस समय हमारे शासक अंग्रेज थे और यह स्वामाधिक या कि विदेशी शासक बननी ही भाषा को सरकारी-भाषा भी बनावें। नये संविधान द्वारा देवनागरी लिपि में हिन्दी राजभाषा बना दी गई है। परन्तु अंकों का रूप अन्तराष्ट्रीय ही होगा। यह इसलिये किया गया क्योंकि दक्षिण भारत के प्रतिनिधियों का कहना था कि यही अंक माने जाय। हिन्दी भाषा का प्रचार करना तथा उनका विकास करना संघ का कर्तव्य बना दिया गया है।

परन्तु एकदम से हिन्दी को सब कामों के लिये व्यवहृत कर देना उचित नहीं था। क्योंकि बहुत काल से सब काम अंग्रेजी में ही होता भाषा है। बहुत से लोगों को हिन्दी का ज्ञान नहीं है या अल्पतः स्वल्प है। तीसरे हिन्दी अभी अंग्रेजी के बराबर उन्नत भाषा नहीं है। इन सब कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए संविधान में यह उपबन्ध है कि १५ वर्ष के लिये संघ की सरकारी भाषा अंग्रेजी भाषा ही रहेगी। परन्तु राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उक्त काल के अन्दर ही आदेश द्वारा संघ के राजकीय प्रयोजनों में से किसी के लिये अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिन्दी भाषा का तथा देव नागरी अंकों का प्रयोग अधिकृत कर दे। इसके साथ ही साथ यह भी उपबन्ध है कि १५ वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर भी संसद् विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग सरकारी प्रयोजनों के लिये अधिकृत कर सकेगी। संसद् अन्तराष्ट्रीय अंकों के स्थान में देवनागरी अंकों का प्रयोग विधि द्वारा १५ वर्ष की कालावधि समाप्त होने पर करवा सकती है।

**हिन्दी भाषा के लिए आयोग :—**संविधान के प्रारम्भ के ५ वर्ष पश्चात् तथा फिर इसके १० वर्ष बाद, राष्ट्रपति आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा। इसमें एक सभापति तथा निम्नलिखित भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्य होंगे : असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, काश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगू, पंजाबी, मलयालम, मराठी तथा हिन्दी।

इस आयोग का काम यह होना कि राष्ट्रपति को सरकारी कामों में हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर अधिक प्रयोग के सरकारी कामों के लिये अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा के, तथा अन्य ऐसी विषयों के जो राष्ट्रपति इसका समर्थन करने में सिकायित करे। इस आयोग का सिफारिशों एक समिति के सामने रखी जावेगी। इस समिति में २० सदस्य लोकसभा में तथा १० राज्यपरिषद् से चने जायेंगे। इस समिति का काम भाषा आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना होगा। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् आदेश निकालेगा।

७ जून, १९५० को भारत सरकार द्वारा हिन्दी कमीशन की स्थापना की घोषणा की गई थी। यह कमीशन श्री वी० जी० खेर की अध्यक्षता में बना था। उनके अतिरिक्त इसमें २० सदस्य थे। हिन्दी के प्रयोग के विषय में अपनी सिफारिश करते हुए कमीशन का देश की औद्योगिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक प्रगति और सार्वजनिक सेवाओं में अहिन्दी जनों के निवासियों की उचित भाषा तथा हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें देती थी। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने यह निश्चय किया कि अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को राजभाषा के रूप में व्यवहृत करने में जल्द से जल्द बढना चाहिये।

**प्रादेशिक भाषाएँ** —कोई राज्य अपने में सरकारी कामों के लिये उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से एक या अधिक को या हिन्दी को विधि द्वारा अंगीकार कर सकता है। परन्तु जब तक इस बारे में कोई विधि का निर्माण नहीं किया जाता है तब तक सरकारी कामों के लिये अंग्रेजी प्रयुक्त होगी।

राज्यों के बीच में तथा उनके और संघ के बीच में संचार के लिये राजभाषा अंग्रेजी ही रखी गई है। परन्तु दो अधिक राज्य आपस में कठार द्वारा हिन्दी का प्रयोग कर सकते हैं।

घर पर किसी राज्य के अन्दर जनसंख्या की बर्पाति मात्रा यह चाहती है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा राज्य द्वारा मान ली जावे तो राष्ट्रपति आदेश दे सकता है कि वह भाषा राज्य के अन्दर में तथा किसी भाषा में सरकारी कामों के लिये मान ली जावेगी।

१ **उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा**

जब तक मसद विधि द्वारा प्रत्यक्ष न करे उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियाँ अंग्रेजी में होंगी। इसके अतिरिक्त मसद में

या किसी विधान-मंडल में पेश किये जाने वाले सब बिल, या उनके संशोधन, या सुमद् अथवा विधान-मंडलों द्वारा पान कोई अधिनियम, या कोई अध्यादेश, या कोई नियम इत्यादि के प्राधिकृत पाठ (authoritative texts) अंग्रेजी में होंगे।

राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से हिन्दी या अन्य किसी भाषा को जो राज्य के अन्दर सरकारी काम के लिये प्रयुक्त (authorise) कर सकता है। परन्तु उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय, आदेश आदि अंग्रेजी में दिये जायेंगे।

अगर किसी राज्य में बिल, ऐक्ट या अध्यादेश आदि के लिये अंग्रेजी के प्रतिरूप कोई अन्य भाषा प्रयोग की जाती है तो वहाँ यह आवश्यक होगा कि राजकीय सूचना-पत्र में इन सब का अंग्रेजी अनुवाद छपा जाय।

**इन उपबन्धों का संशोधन** — इस विषय में संविधान में यह कहा गया है कि — ~~के पन्द्रह वर्ष बाद तक कोई संशोधन नहीं पेश किया जायेगा।~~ राष्ट्रपति या समिति की राय लेंगे।

## अध्याय १६

### गर्भीय जाग्रति

जब १५ वीं शताब्दी के आरम्भ में अंग्रेज व्यापारी भारत में आए, तब यह निर्मा ने भी नहीं साधा हुआ कि एक दिन देश व्यापारियों की सन्तान भारत में शासन करेगी। परन्तु अठारहवीं शताब्दी के मध्य में भारत में अंग्रेजों व्यापारियों ने भूमि विजय प्रारम्भ कर दी तथा १९ वीं शताब्दी के आरम्भ में वे सर्वोच्च हो गए। जा चाहे वे भारतीय राज्य उनसे अधीन नही हुए थे व भी धीरे-धीरे उनके अधीन होने लगे थे। क्योंकि भारत में कोई भी राज्य इतना शक्तिशाली नहीं बचा था कि अंग्रेजों की शक्ति का पराजित कर सकना अंग्रेजों की मफूतता का सबसे मुख्य कारण यह भी था कि भारत में एकता का निराला अभाव था। भारतीय नरेश आपसी वैमनस्य के कारण निर्मल हो गए थे। इससे अनिश्चित, यह बात भी नहीं भूलना चाहिये कि अंग्रेजों की मुद्र कला भी हमसे उच्च काटि की थी। केवल भारत में ही नही परन्तु अन्य एशियाई देशों में भी जहाँ कहीं यूरोपीय पहुँचे, जैसे चीन, व अफ्रीका उच्च युद्धकला के कारण गिराए गए। उनसे अस्त्र-शस्त्र भी उच्च काटि के थे। भारत में अंग्रेजों की विजय का एक यह हुआ कि न केवल उन्होंने हमारे देश का जीता ही परन्तु हमारा उन्होंने दागता में जकड़ लिया।

अंग्रेजों विजय अफ्रीका का मध्य तथा भारतवासियों की असम्य समझने से उनमें प्रत्येक भारतीय वस्तु के लिए निरादर था। उनकी आशानोत मफूतता के कारण भारतीय भी उनसे इतना अधिक प्रभावित हुए कि प्रत्येक यूरोपीय वस्तु के लिए उनके हृदय में महान् आदर की भावना घर कर गई। इसका एक यह हुआ कि भारतीय सम्पत्ता के प्रति उनके हृदय में निरादर भर गया और उन्होंने पाश्चात्य सम्पत्ता का अनुकरण अनुकरण आरम्भ किया। भारतीयों के मन में भारतीय सम्पत्ता तथा सम्पत्ति के प्रति विरक्ति हो गई। ईसाई पादरियों ने ईसाई धर्म के प्रचार के साथ-साथ भारतीयों के धर्म-विश्वासों के ऊपर भी आक्रमण किया। इनसे अनुमान भारतीय-धर्म केवल अंध विश्वास मात्र थे। दूसरे तब पहुँचने का दीव रास्ता केवल ईसाई धर्म था। इस प्रकार हम वाद में विदेशियों ने न केवल हमारे देश का ही

जीता परन्तु उनका प्रयास हमारे मन को भी जीतने का था और इसमें भी वे काफी मात्रा तक सफल हुए थे।

परन्तु इस समय भारत में कुछ धार्मिक आन्दोलन प्रारम्भ हुए। इनका विस्तारपूर्वक वर्णन आगे किया जावेगा। इन धार्मिक आन्दोलनों ने हमारी सुप्तप्राय चेतना को पुन जगाया। बंगाल में राजा राममोहन राय (१७७२-१८३३) ने ब्रह्म समाज आन्दोलन चलाया। इसके विषय में श्रीमती ऐनी बेसेन्ट ने लिखा है कि इसने बंगाल को, जो कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सत्ता-गुल्लू कर दिया था, फिर से चेतन्य किया। उत्तर-पश्चिमी भारत में स्वामी दयानन्द सरस्वती (१८२४-१८८९) ने आर्य समाज आन्दोलन चलाया। स्वामी जी ने कहा कि हिन्दुओं का प्राचीन वैदिक धर्म सब धर्मों से ऊँचा है। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश में ग्रन्थ धर्मों की मालोचना की तथा यह दिखलाने का प्रयास किया है कि हिन्दू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। स्वामी जी का आन्दोलन यद्यपि मुख्यतः धार्मिक था, परन्तु इसके साथ-साथ यह राष्ट्रीय भी था। इसने भारत की राजनैतिक जागृति में महत्वपूर्ण काम किया।<sup>१</sup> श्री रामकृष्ण परमहंस (१८३४-१८८६) तथा उनके शिष्य स्वामी विवेकानन्द ने भी भारतीयों को जगाने में महत्वपूर्ण काम किया। इन दोनों धार्मिक नेताओं ने भारतीयों को यह ज्ञान दिया कि भारत आध्यात्मिकता की दृष्टि से संसार में सबसे बड़ा-चढ़ा है। यह सच्चे धर्म का घर है। धर्मोपदेशक समाज ने जिसका प्रारम्भ सन् १८८२ में बंगाल में हुआ, भारत को जगाने में काफी काम किया। श्रीमती ऐनी बेसेन्ट ने जो कि १८५३ ई० में भारत आयी, इस आन्दोलन में भाग लिया तथा अपने मूल्यपर्यन्त वे इसके लिए पूर्णरूपेण प्रयत्नशील रही। इन सब धार्मिक आन्दोलनों का प्रभाव यह हुआ कि भारत में एक नवीन जागृति प्रारम्भ हुई। यहाँ के निवासियों में आत्म-विश्वास तथा आत्म-गौरव के भाव जगे। यह भावना कि हम यूरोपीय सभ्यता के सम्मुख बिलकुल ही गिरे हुए हैं, दूर हुई। तथा इनके साथ-साथ सामाजिक कुुरीतियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हुआ और यह बात समस्त में घने लगी कि बिना इन सामाजिक बुराइयों को दूर किए हुए हमारा उत्थान सम्भव नहीं है। यद्यपि ये सब

1. इसके विषय में लेखक ने लिखा है कि It was "at once a religious and national revival. It sought to bring new life to India and the Hindu race." Hans Kohn, *History of Nationalism in the East*. p 62.

ग्रान्दात्मन मुक्तत धार्मिक थे परन्तु गाय-भाष इन्होंने हमारे मन्दर राष्ट्रीयता का भी मचार किया । अतएव हमारे राजनैतिक जागृति के इतिहास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है ।

इसी समय यूरोप में कई विद्वानों ने प्राचीन भारतीय सभ्यता तथा सभ्यता के ऊपर जोध-कार्य किया तथा अपनी खोजों के फलस्वरूप उन्होंने भारत के महान् अतीत को गवा के सामने रखा । उनके अनुसार भारत की सभ्यता, साहित्य तथा दर्शन सब बहुत ही उच्च कोटि के थे । इन पाश्चात्य विद्वानों में मुख्य मैक्समुलर विलयम्स, रीच वर्नाफ आदि थे । भारतीयों के ऊपर इनकी पुस्तिका का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा । अपने अतीत शौर्य के प्रति हमारे मन में सम्मान की भावना लगी । हमें यह लपने लगा कि हमारी सभ्यता के सम्मुख यूरोपीय सभ्यता कुछ भी नहीं है ।

धर्म ने राष्ट्रीयता के विकास में केवल भारत में ही नहीं परन्तु कई अन्य देशों में भी महत्वपूर्ण भाग लिया है । उदाहरणार्थ, दक्षिण-पूर्वी योरोप में भी राष्ट्रीयता की जागृति में धर्म का बहुत बड़ा हाथ रहा है । ऊपर के मक्षिप्त वर्णन में यह स्पष्ट होगा कि भारत में 'धर्म ने राष्ट्रीयता को प्रेरणा दी ।'

भारत में राष्ट्रीय-चेतना के जागृत होने में धार्मिक-ग्रान्दोलनों के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य कारण हैं —

१. **अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव** — भारतवर्ष में शासनतन्त्र चलाने के लिए उच्च अफसर तो अंग्रेज होते थे परन्तु निम्नकोटि के सरकारी कर्मचारी भारतीय ही हो सकते थे । इसलिए हमारे विदेशी शासकों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की स्थापना की ताकि उन्हें बलक मिल सके । परन्तु इस शिक्षा का प्रभाव अत्यन्त महत्वपूर्ण हुआ । एक तो यह कि इससे भारतवर्ष में एक कोने से लेकर दूसरे कोने में शिक्षित समुदाय में भाषा की एकता स्थापित हो गई । इसके फलस्वरूप जो विभिन्न भाग के निवासियों में भाषा की विभिन्नता के कारण विचारों के आदान-प्रदान में व्यवधान था, वह दूर हो गया । दूसरे, अंग्रेजी भाषा के द्वारा भारतीयों का पाश्चात्य-विचारों से परिचय हुआ । उस समय योरोप में राष्ट्रीयता, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, उदारवाद आदि जोरों पर थे । भारतीयों का भी इन विचारों से परिचय हुआ । विद्वान तथा दार्शनिक जैसे मिल स्पेन्सर, ह्यू आदि के विचारों ने भारतीयों को प्रभावित किया । इस प्रकार हमारे देशवासियों को प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों का ज्ञान मिला ।<sup>१</sup>

१. "Mr Herbert Spencer's individualism and Lord Morley's liberalism are as it were, the only battery of guns which India



बहुत से भारतीय शिक्षा या धन्य उन्हेंसों ने इकट्ठे गये। वहाँ उन्होंने देखा कि स्वतन्त्र-देश के नागरिक किस प्रकार अपने अधिकारों का उपयोग करते हैं। वहाँ उन्होंने यह अनुभव किया कि बिना स्वतन्त्रता के व्यक्ति का विकास सम्भव नहीं है। वहाँ जाकर उन्हें यह ज्ञान हुआ कि बिना स्वराज्य के जीवन का उपयोग नहीं हो सकता है। ये भारतीय जब विदेश में वापिस आए तो वहाँ के परमन्त्र वातावरण में उनकी नान घुटने लगी। अतएव उनमें अनन्त रूप स्वाभाविक था।

मैकौले ने जो कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के लिए उत्तरदायी था, वह पहले ही देख लिया था कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव भारत में राजनैतिक अधिकार को माँग करेगा।

देश में एकता की स्थापना — यद्यपि यह नितान्त नव्य है कि नाट्यतिक दृष्टि में भारत प्राचीनकाल तथा मध्यकाल में एक था तथापि यह भी उतना ही सत्य है कि राजनैतिक दृष्टि में भारत की एकता सर्वदा अस्थिर रही। अशोक, समुद्रगुप्त या बाद की अक्षवर या खीरगजेब ने भारत के एक बड़े भाग पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था परन्तु यह स्थायी नहीं हो सका। परन्तु अंग्रेजी के भारत विजय के फलस्वरूप सम्पूर्ण भारत राजनैतिक दृष्टि में एक इकट्ठी हो गया। इन प्रकार भारत में पहली बार स्थायी रूप से राजनैतिक एकता स्थापित हुई। इस राजनैतिक एकता का फल यह हुआ कि स्थानीय भक्ति का स्थान सम्पूर्ण देश के प्रति भक्ति ने ले लिया। यह एकता की भावना, हम लिय चुके हैं कि अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप दृढ़ हुई। इनके अतिरिक्त अंग्रेजों ने समस्त देश में रेल तथा सड़कों का जाल-बिछा दिया। यात्रायान के साधनों के सुविधा के कारण देश के एक भाग से दूसरे भाग में जाना सरल हो गया। अतएव यह स्वाभाविक था कि देश के विभिन्न भाग एक दूसरे के अधिक सम्पर्क में आए और इससे एकता की भावना और अधिक दृढ़ हो गई। अंग्रेज-शासकों ने भारत में यात्रायान के साधनों में उन्नति, धार्मिक-शोषण तथा सैनिक दृष्टि में की थी। परन्तु परोक्ष में उससे यह लाभ हुआ कि एकता की भावना संगठित हो गई।

आर्थिक कारण — बहुधा यह प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेज शासक समुद्र पार से भारत में क्यों आए ? इसका कारण कुछ विदेशियों ने खोज की प्रवृत्ति बनाया है तथा किन्हीं ने विजय की इच्छा। परन्तु सार्थक कारण यह है कि

अंग्रेज भारत में व्यापार करने आये। परन्तु जब इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति हुई उसके पश्चात् उत्पादन व्यवस्था में आमूल-परिवर्तन हो गया। इंग्लैण्ड में कारखाना की बच्च माल की अधिकाधिक आवश्यकता होने लगी तथा उनकी आवश्यकता यह थी कि इन कारखाना में बना हुआ सामान बेचा जाय। न बचने हुए माल के सामने छोटे छोटे गृह उद्योगों द्वारा बनाया हुआ माल अधिक महंगा होगा। इसलिए जब भारत में अंग्रेजी माल आने लगा और विदेशी मालको ने इसके ऊपर कोई चुनौती नहीं लगाई ना इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि भारत में उद्योग धंधे चौपट हो गए रेकारी बड़ी तथा अधिकाधिक लाग और कोई माधन न होने के कारण रस्ती की कार झुब। अंग्रेजों की आदिक नीति यह थी कि भारत का आदिश-आपण इंग्लैण्ड के पूँजीपतियों के हित में हो। उन्हें भारत को परवाह नहीं थी। भारत की अवस्था का अनुमान इसमें लगाया जा सकता है कि सन् १९३४ में लार्ड चेम्बेर्लैन ने लिखा *The misery hardly finds a parallel in the history of commerce The bones of cotton weavers are bleaching the plains of India*

अंग्रेजी काल में खेती की बाई उन्नति नहीं हुई। इसका कारण यह था कि भूमि के सम्बन्ध में अंग्रेजी सरकार कोई प्रगतिशील नीति नहीं अपनाती थी। जमींदारी प्रथा के कारण बहुत से लोग भूमिहीन हो गये थे। पंच दश में बड़ उद्योग-धंधा के स्थापित करने के लिए भी तैयार नहीं थे। १७७० ई० में दश में मयानक अकाल पड़ा। परन्तु सरकार ने इससे उत्पन्न कठिनाइयों का दूर करने की कोई विशेष चिन्ता नहीं की। इसी समय द्वितीय प्रफगान युद्ध में भारत का कराइरा रुपया बबाद किया गया। सन् १८८० में सर विलियम हण्टर ने कहा कि भारत में ४ करोड़ व्यक्ति केवल एक समय खाते हैं। तीसरी शताब्दी के प्रारम्भ में एक अंग्रेज अफसर के अनुसार भारत में ७ करोड़ व्यक्ति भरपेट खाना नहीं पाते थे।

सरकारी नौकरियों में सब उच्च पदा पर अंग्रेज आसीन थे। भारतीयों को केवल निम्न काटि की नौकरियां सेही सतोष करना पड़ता था। यद्यपि सन् १८३३ में यह कह दिया गया था कि नौकरियों में भेद भाव नहीं किया जायगा। तथापि यह भेद भाव बना रहा। शिक्षित भारतीयों में इस कारण शोभ होना स्वाभाविक था। सन् १८५८ की महारानी विनोदिया

१. शिक्षित भारतीयों की सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के शब्दों में यह भावना हो गई थी कि "They are the helots of the land, the hewers of wood and the drawers of water . ."

की घोषणा में भी यह भावना उत्पन्न थी कि नौकरियों में योग्यता के अनुसार नियुक्ति होगी परन्तु कार्यरूप में यह सिद्धान्त कभी भी पूरी तरह लागू नहीं हुआ।

इण्डियन सिविल सर्विस परीक्षा में सन् १८६९ में श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी पाम हुए लेकिन वे नौकरी में नहीं लिए गये। इससे बंगाल में बहुत असंतोष हुआ बाद को सरकार ने उनको सन् १८७१ में नौकरी में ले लिया किन्तु दो वर्ष बाद वे नौकरी से हटा दिये गये। श्री बनर्जी ने विलायत जाकर बैरिस्टर पाम का। भारत लौटने पर उन्होंने सन् १८७६ में 'इण्डियन एसोसिएशन' नामक मन्था की स्थापना की। जब आई० सी० एस० में उम्र २१ से घटाकर १९ कर दी गई तो भारतीयों के लिये इसमें बैठना असम्भव हो गया। भारत में अत्यन्त आश्रय हुआ। इण्डियन एसोसिएशन ने देश में इस कार्य के विरुद्ध जनमत संगठित किया। कलकत्ते में २४ मार्च सन् १८७७ को एक बृहत् सभा हुई। इसके पश्चात् कई अन्य नगरों में भी सभाएँ हुईं, जैसे लाहौर, प्रमृतनगर, मेरठ, इलाहाबाद, अहमदाबाद, सूरत, बम्बई, मद्रास आदि। इन सभाओं से देश में राजनैतिक चेतना बढी तथा भारतीयों ने संगठन का महत्व समझा।

**समाचार-पत्र.**—राष्ट्रीयता के विकास में भारतीय समाचार-पत्रों का भी बड़ा हाथ रहा है। देश की दुर्दशा की ओर इन्होंने जनताघारण का प्लान खींचा, ब्रिटिश नीति के दुष्परिणामों से इन्होंने लोगों को अवगत कराया तथा इनके कारण देश में ब्रिटिश विरोधी जनमत संगठित हुआ। भारत में जो समाचारपत्र अँग्रेजी के थे वे सरकारी नीति के समर्थक थे। भारतीय पत्र सरकारी नीति के आलोचक थे। इसलिये समय-समय पर ब्रिटिश सरकार ने इनकी स्वतन्त्रता पर कई नियम बनाकर कुठाराघात किया। परन्तु इससे सरकार की शान कम हुआ और हानि अधिक, क्योंकि भारतीय जनमत इन कारणों से अधिकाधिक अँग्रेजों का विरोधी होता चला गया।

**साहित्य:**—भारतीय भाषाओं में जो साहित्य का सृजन हुआ उसने भी राष्ट्रीयता के विकास में सहायता दी। कुछ सीमा तक यह राष्ट्रीय भावना का फल यह था जो कुछ सीमा तक राष्ट्रीय भावना इसकी फल थी। बंगाल में इस समय जिस साहित्य की सृष्टि हुई उसने जनता में नए चेतना का संचार किया, बकिम दास के उपन्यासों में सर्वत्र स्वतन्त्रता की महिमा गाई गई है। बन्धुमातरम् नामा उनके उपन्यास आनन्दमठ से लिया गया है। हिन्दी में भी इस समय राष्ट्रीयता के विचार लेखों आदि द्वारा प्रवृत्त किए जा रहे थे।

अंगरेजों की भारतीयों के प्रति घृणा — भारत में सन् १८५७ से पूर्व अंगरेजों का व्यवहार भारतीयों के प्रति अत्यन्त था वे भारतीयों के साथ मिलकर रहते थे। कई अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ विवाह किया। परन्तु १८५७ के विद्रोह पश्चात् वह अवस्था नहीं रही। अंग्रेज भारतीयों को सदेह की दृष्टि से बने लग गये। उनका व्यवहार इतना अधिक बुरा हो गया था कि वे भारतीयों को मनुष्य ही नहीं समझते थे। वे अलग रहते थे। भारतीयों से उनका कोई सम्पर्क नहीं था और न वे उनसे सम्पर्क स्थापित ही करना चाहते थे। वे भारतीयों को बुरा तथा जंगली समझते थे।

इस समय अंग्रेजों का जो व्यवहार भारतीयों के प्रति था वह इतना बुरा तथा घृणित था कि किसी भी सम्यक् समाज को उसके ऊपर लज्जा होनी चाहिए। अंग्रेजों के लिए भारतीयों की हत्या करना साधारण बात हो गई थी। ऐसे कई उदाहरण हैं। इन सब घण्टियों के लिए उन्हें या तो कोई सजा नहीं मिलनी थी या बहुत साधारण सी सजा मिलनी थी। सन् १८९० में भारतीय सिविल सर्विस के एक अंग्रेज सदस्य ने लिखा था कि, "It is an ugly fact which it is no use to disguise that the murder of the natives by Englishmen is no infrequent occurrence" इस बात में अंग्रेजों का व्यवहार तीन विद्वानों पर आघात है।

( १ ) यूरोपियन का जीवन कई भारतीयों के जीवन से अधिक मूल्यवान् था।

( २ ) भारतीय बकाय भय समझता है, और कुछ नहीं।

( ३ ) अंग्रेजों का काम भारत में आकर आनन्द करना है न कि वहाँ के निवासियों का हित-साधन।<sup>१</sup>

अंग्रेजों के व्यवहार के कारण भारतीयों में भी उनके प्रति घृणा अवस्था तथा शोभ की भावना जागृत हुई।

लार्ड लिटन का शासन — लार्ड लिटन ने अपने वाइसरॉय काल में कई ऐसे काम किए जिससे भारत में अमनोप और बढ़ा। महोप में वे निम्न-लिखित थे उसने सन् १८७७ में दिल्ली में दरबार किया जब लाखों

भारतीय भूत में सड़प-सड़प कर मर रहे थे । परन्तु इसका एक अच्छा फल यह हुआ कि देशवासियों के मन में भी घबिला भारतीय कांग्रेस स्थापित करने का विचार पैदा हुआ ।

उनने द्वितीय मजिपान मुद्दे में भारत का करोड़ों रुपया व्यय किया

उनके समय में भारतीय भाषा के समाचार-पत्रों पर कई प्रकार की रजा-वटें लगाई । इन ऐक्ट को नागरिकता 'बन्धन ऐक्ट' कहते हैं ।

इसने इंग्लैंड के कपड़ों को जिनमें के साज के लिए भारत में रुई के निर्यात पर से कर उठा लिया ।

उमने एक ग्राम्स ऐक्ट पाम करवाया । इसके द्वारा कोई भी भारतीय बिना लाइसेन्स के हथियार नहीं रख सकता था, परन्तु यह ऐक्ट अंग्रेजों पर लागू नहीं था ।

**इलबर्ट-बिल :—**भारतीय मैजिस्ट्रेट तथा जजों को अंग्रेजों के मुकदमे करने का अधिकार नहीं था । सन् १८८७ में जब लार्ड रिपन ने एक बिल द्वारा यह भेद-भाव दूर करने का प्रयत्न किया तो इस बिल के विरुद्ध भारत में अंग्रेजों ने एक तुफान सहा कर दिया । अंग्रेजों के विरोध के कारण यह बिल रद्द हो गया । परन्तु इसने भारतीयों ने दो बातें सीखी : एक तो यह कि किसी संगठित रूप से आन्दोलन किए उनकी मांगें पूरी नहीं हो सकती हैं तथा दूसरी यह कि अंग्रेजों से न्याय की मांग करना व्यर्थ है ।

उपरोक्त कारणों से भारत में राजनैतिक चेतना दिन पर दिन बढ़ती गई । देशवासियों का आत्म-विश्वास तथा आत्म-शौर्य इस कारण और भी जाग्रत हुआ क्योंकि इस समय कुछ पूर्वीय देशों ने करघट बढ़ाई । सबसे महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि जापान ने पश्चिमी देशों की देसा-देसी अपने देश में राजनैतिक तथा आर्थिक परिवर्तन किए । इसने उसकी शक्ति प्रत्यन्त बढ़ी । यहाँ तक कि कुछ वर्ष पश्चात् वह रुस को मुझ में हराने में सफल हुआ ।

**राजनैतिक आन्दोलन का विकास :—**भारत में अंग्रेजों की हुनौति के कारण काफी असन्तोष उत्पन्न हो गया था । इलबर्ट बिल की प्रतिक्रिया के कारण भारतीयों में नई जान घाई और उन्होंने संगठितरूप से कार्य आरम्भ किया । सन् १८८२ ई० में कलकत्ते में इण्डियन एसोसिएशन की मंभा हुई, इसमें ममसा बंगाल के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे । सन् १८८४ में मद्रास

में महाजन मना की एक प्रांतीय बैठक हुई। बम्बई में मन् १/८५ ६ प्रथम मास में बम्बई एसोसियेशन की स्थापना हुई। परन्तु ये सब प्रांतीय थे।

सन १८८६ में कुछ लोगोंने एक अखिल भारतीय मन् की स्थापना का प्रचार किया। इसमें सब से मर्य भाग श्री० ए० ओ० ह्यूम ने लिया। श्री १. स्त्रीय मिचिल-मिचिल ने एक अवकाश प्राप्त मदस्य थे। इन्होंने इस मन् की स्थापना में पूर्वं भारत में वाइमराय लार्ड डफरिन से सलाह ली थी। वाइमराय ने उन्हें इस प्रकार के मन् की स्थापना में लिए उत्साहित किया। यह निश्चित हुआ कि इस मन् की प्रथम बैठक २८, २९, तथा ३० दिन म्बर को होगी। यह सरकार का ध्यान आगन की बुराई की ओर आकर्षित करेगी। यह मन् हुआ कि इस मन् की प्रथम बैठक २८, २९, तथा ३० दिन म्बर को होगी। पहले यह बैठक पूना में होने वाली थी, परन्तु वहाँ हुआ फैसले के कारण यह बम्बई में हुई। इसके प्रथम सभापति श्री उमेशचन्द्र बनर्जी थे।

इस सम्मेलन में ७० प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इनमें से केवल दो मुसलमान थे। यही सत्वा भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस नाम से प्रसिद्ध हुई। जिस समय काँग्रेस की प्रथम बैठक हुई करीबन उसी समय बलकत्ते में राष्ट्रीय कांग्रेस का एक बैठक हुई। इसमें भी भारत के कई प्रांतों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुये थे। परन्तु दूसरे वर्ष से राष्ट्रीय कांग्रेस काँग्रेस में ही मिल गई।

काँग्रेस शब्द में केवल भारतीय शिक्षित तथा मध्य वर्ग की सत्वा थी। प्रति वर्ष इस मन् के प्रतिनिधि एक बार एकत्रित होते थे तथा अंग्रेजी सरकार के नामने कुछ मांगें रखने थे जैसे कि नीकरिया में अखिल भारतीयों की लिया जाने तथा उन्हें आगन में अखिल भाग लेने का अरसर हो। उन समय इसकी मांग स्वराज्य नहीं थी यह तो बाद की हुआ। काँग्रेस के जन्म के विषय में कुछ विद्वानों का यह कहना है कि श्री ह्यूम ने इसकी स्थापना इस कारण की क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध इतना अखिल अगमनीय हो गया था कि यह भय था वही एक विद्रोह कर न कर पड़े। इसलिये यह प्रयत्न किया गया कि भारतीय आन्दोलन वैधानिक रूप ले। इसको 'Save the British Empire' मिदात कहा जाता है। लाला लाजपत राय का काँग्रेस के जन्म के बारे में यही विचार था।<sup>१</sup> इस विचार में मन् का एक अंश

१. "But one thing is clear that the Congress was started more with the object of saving the British Empire from danger than with that of winning political liberty for India"—  
Lala Lajpat Rai, Young India, p. 126

प्रवर्ध है। परन्तु यह पूर्णतया सत्य नहीं। कांग्रेस का जन्म जिस कारण भी हुआ हो, धीरे-धीरे यह राष्ट्रीयता के सपना में प्रमुख संस्था हो गई तथा इसका ध्येय भारत की स्वतन्त्रता हो गया।

सन् १८८५ में कांग्रेस की पहली बैठक में इसके सभापति ने इसके प्रमुख उद्देश्य बतलाये थे —

(१) साम्राज्य के विभिन्न भागों में बसे हुए भारतवासियों के बीच सम्पर्क तथा मैत्री स्थापित करना।

(२) देश के नमस्त प्रेमियों के बीच में जाति, धर्म तथा प्रांतीयता की भावनाओं को दूर करना।

(३) मुख्य-मुख्य समस्याओं पर शिक्षित भारतीय वर्ग के विचारों का स्पष्टीकरण।

(४) आगामी वर्ष के लिए लोकनेत्री कामों की बतलाना।

इस प्रकार से सन् १९०६ तक कांग्रेस के ये ही उद्देश्य रहे। उस वर्ष प्रथम बार कांग्रेस के सभापति पद से श्री दाना भाई मौरोजी ने यह कहा था कि कांग्रेस का उद्देश्य भारत में स्वराज्य प्राप्त करना है। परन्तु स्वराज्य का अर्थ उस भाति का राज्य था जैसा कि इंग्लैंड के राज्य उपनिवेशों में स्थापित था। इन उद्देश्यों के प्रतिरुद्ध कांग्रेस ने देश की चबूती हुई गरीबी के विरुद्ध भी आवाज उठाई, यह मांग की कि भूमि पर कर कम किया जावे। कांग्रेस ने अपने दसवें अधिवेशन में सरकार की औद्योगिक नीति के विरुद्ध भी आवाज उठाई। इसने अपने अधिवेशनों में प्रवासी भारतीयों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की भी निन्दा की। इन कामों के साथ-साथ कांग्रेस ने भारतीयों के अधिकार तथा स्वतन्त्रता के लिए भी मांगें रखी।

कांग्रेस के आदर्शवाद का यह फल हुआ कि सन् १८९२ में दंडिया कौन्सिल ऐक्ट पास हुआ। इसका उद्देश्य शिक्षित भारतीयों की कुछ मांगें पूरी कर उनके विरोध को दूर करना था। परन्तु इसमें शिक्षित वर्ग को सन्तोष नहीं हुआ।

कांग्रेस इस काल में केवल उच्च वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करती थी। इसके नेताओं का जनता के साथ सम्पर्क नहीं था। इनका अंग्रेजी सातन पर परा विश्वास था और वे अंग्रेजी छत्रछाया में रह कर ही राजनैतिक अधिकार चाहते थे। परन्तु धीरे-धीरे कांग्रेस के अन्दर एक उपद्रव पैदा होने लगा जो

कि इस नरम-दली नृति से असन्तुष्ट था। इस उग्रदल के पैदा होने का मुख्य कारण यह था कि भारत में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध अग्रन्तोप बढ़ता ही जा रहा था। इसके कई कारण थे। सन् १८९७ में एक भोपण प्रकाल पड़ा जिसके फलस्वरूप कई लाख व्यक्ति मरे। सरकारी सहायता अग्रन्तोपजनक थी। तभी समय बम्बई में बड़े से जोरों के साथ प्लेन फैला। इसमें भी सरकारी सहायता अग्रन्तोपजनक थी। सरकार के विरुद्ध भावना ने इतना उग्र रूप धारण कर लिया था कि पूना में दो नवयुवकों ने दो अंग्रेजी अफसरों को गोली मार दी। इस घटना पर सरकार ने महाराष्ट्र के लोगों से बस कर बदला लिया। श्री बाल गंगाधर तिलक को १८ महीने के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। सरकारी नीति के फलस्वरूप अग्रन्तोप और बढ़ा। सन् १८९८ में बंगाल में राखपुर नामक स्थान में तीन गोरा ने श्री सुरेशचन्द्र सरकार नामक एक डाक्टर का मार डाला। परन्तु इनको मृत्युदण्ड न दिया जाकर केवल ७ वर्ष के कठोर कारावास दण्ड दिया गया।

लाड कर्जन के काल में सरकार की नीति से भारत में क्रोध तथा असन्तोष बढ़ता गया इन काल में सरकार ने कई ऐसे कानून पास किए जिनको देश का अल्पसंख्यक भाग अत्यन्त ही प्रतिश्रियावादी समर्थता था। लाड कर्जन उन साम्राज्यवादियों में से था जो निःशर्तता को अत्यन्त हीन दृष्टि से देखता था। सन् १९०५ में लाड कर्जन ने बंगाल के दो भागों में विभाजित करने की योजना स्तुत की। यह अक्टूबर में लागू की गई। इस योजना का बंगाल में भार विरोध किया गया। सारे देश में इसने विरुद्ध आवाज उठाई गई। बंगाल विभाजन का उद्देश्य राजनैतिक आन्दोलन को अशक्त करना तथा हिन्दू और मुसलमानों के बीच विरोध पैदा करना था। सरकार के विरोध में देश में स्वदेशी आन्दोलन चला। यह देशवासियों ने चीन से सीखा जहाँ कि इस समय अमेरिकन माल बायकाट किया जा रहा था। सरकार ने दमननीति को अपनाया। सरकारी नीति के कारण कांग्रेस के अन्दर उग्र-दल शक्तिशाली होने लगा। इनके नेता तिलक, विपिन चन्द्र पाल तथा लाला लाजपत राय थे। सन् १९०५ में जब सूरत में कांग्रेस हुई वहाँ नरमदल तथा उग्रदल अलग अलग हो गए और कांग्रेस में फूट पड़ गई। कांग्रेस नरमदल के हाथ में रही, दूसरा दल इसमें से निकाल दिया गया।

इसी समय बंगाल, पंजाब तथा महाराष्ट्र में एक आतंकवादी आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। इसका नाम सरकार की दमन नीति का उत्तर गोली बम से देना था। देश में कई आतंकवादी दल थे। देश के बाहर भी कुछ आतंककारी



संगठन थे। इनका उद्देश्य साहज से हिंसाधारित आदि भेदना था। सरकार ने इस आन्दोलन को कुचलने में नृशमता तथा बर्बरता का पुनः उपयोग किया। उपद्रवीय क्रान्तियों को भी सरकार ने नहीं छोड़ा। तिलक को दमन में बंद कर भेज दिया गया। साधु राजपतराय को हिन्दुस्तान से निकाल दिया गया तथा विपिन चन्द्र पाल को कठोर कारावास का दण्ड दिया गया। सरकार ने कई दमनकारी कानून पास किए। उदाहरणार्थ १९०८ में Criminal Law Amendment Act तथा Newspapers Act, १९१० में Press Act, सन् १९११ में Seditious Meetings Act आदि। इन सब कानूनों का उद्देश्य आतंकवादी तथा उपद्रवी आन्दोलन को कुचलना था। इस दमन नीति के साथ साथ दूसरी ओर सरकार नरमदलीय कांग्रेसियों को यह आश्वासन दे रही थी कि वह भारत में शीघ्र ही कई सुधार लागू करने वाली है। तीसरी ओर सरकार मुसलमानों को प्रोत्साहित कर रही थी कि वे अपना अलग संगठन बनावें तथा हिन्दू आन्दोलनकारियों से कोई सम्पर्क न रखें।

**मुसलमानों का संगठन:**—घपने शासन के आरम्भिक-काल में अंग्रेजों ने मुसलमानों की तथा उनके हितों की उपेक्षा और हिन्दुओं के उत्तर विरोध किया। क्योंकि उस समय अंग्रेजों की नीति मुसलमानों को प्रभावित करने की थी। मुसलमानों की सेवा में या सरकारी नौकरियों में स्थान पाने का कोई प्रयत्न सर नहीं था। मुसलमान अधिकतर अंग्रेजी शिक्षा से अव्यभिज्ञ थे। इसलिए वे भी समाज में पिछड़े गए।

१८ वीं शताब्दी के अन्त में मुसलमानों में कुछ-कुछ अपनी दशा का ज्ञान होने लगा। सम्यद अहमद इलदी ने भारत में मुसलमानों में एक धार्मिक सुधार आन्दोलन प्रकाशित किया। परन्तु मुसलमानों की राजनैतिक जागृति में सबसे अधिक हाथ सर सम्यद अहमद खान (१८१७-१८९८) का रहा है। उनका विचार था कि उनके सम्प्रदाय वालों को अंग्रेजी शिक्षा की ओर अधिक से अधिक धरना चाहिए। सन् १८५५ में उन्होंने प्रलोख मोहम्मद कोलिज की स्थापना की। उनका विचार था कि मुसलमानों को अंग्रेजों के साथ मिलकर रहना चाहिये और इसी में उनका कल्याण है। इसलिए जब

1. Sir William Hunter ने लिखा, "We believed that their exclusion was necessary to our safety." Indian Musalmans p. 163

सन् १८८५ में काँग्रेस को स्थापना हुई तब मैसूर अधिसूचना ने इसका विरोध करने का वनागम के राजा शिरप्रसाद के साथ एक दूतग मण्डन स्थापित किया। अधिसूचना ने जब देखा कि काँग्रेस अधिकाधिक राष्ट्रीय तथा सरकार विरुद्ध होने लगी जा रही है तो उन्होंने मुसलमानों को साम्प्रदायिक-मण्डन बनाने में तुरंत सहायता दी। सन् १८९० में एक विशेष समामेलन नामक मुसलमानों सम्मेलन स्थापित हुई। इसका उद्देश्य मुसलमानों में राजभक्ति का प्रचार करना तथा उनका काँग्रेस से अलग रखना था।

बीसवीं शताब्दी में मुसलमानों साम्प्रदायिकता को उपासने के लिये विशेष प्रयत्न किए गये। वनाग के विभाजन के पीछे भी उद्देश्य यह था कि हिन्दू और मुसलमानों में वैमनस्य बढ़ जावे। पूर्वी बंगाल का मुसलमानों गुला कहा गया। सन् १९०६ में बांग्ला ली वाइसराय के पास एक मुस्लिम लिटमसल लेकर पहुंच और यह प्रार्थना की कि मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व दिया जावे। इस लिटमसल ने पीछे अंग्रेजों का शय स्पष्ट था। उनका प्रयास था कि हिन्दू तथा मुसलमानों के बीच बिना प्रचार ही एक गार्ड बना दी जावे और इसमें वे अलग में सफर करें। वाइसराय ने लिटमसल को अस्वामन दिया कि उनकी मांगों का भरिय में सुनारा के समस्त ध्यान गया जावेगा।<sup>१</sup> इस दिन के बारे में (अक्टूबर १, १९०६) वाइसराय ने लिखा 'This has been a very eventful day as someone said to me an 'epoch in Indian history' "

१० दिसम्बर सन् १९२६ में दाका व तबाय सुलीमउल्लाह ने मुस्लिम मोग की स्थापना की। इनके निम्नलिखित उद्देश्य थे :

१) भारतीय मुसलमानों में अंग्रेजी सरकार के प्रति राजभक्ति बढ़ाना।

( २ ) भारतीय मुसलमानों व राजनैतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना और मांगों का सरकार के समक्ष रखना।

( ३ ) मुसलमान तथा अन्य सम्प्रदायों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बढ़ाना।

१ वाइसराय ने लिटमसल में कहा, "You justly claim that your position should be estimated not only on your numerical strength, but in respect to the political importance of your community and the service it has rendered to the Empire"

**मिण्टो-मॉर्ले सुधार तथा प्रथम महायुद्ध** —सरकार ने देखा कि सब उपाय करने पर भी घमन्तोप में किन्हीं प्रकार की कमी नहीं आ रही है तो उसने १९०९ में मिण्टो-मॉर्ले सुधारों की घोषणा की। इनका वर्णन हम पहले अध्याय में कर चुके हैं। इन सुधारों का उद्देश्य भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन स्थापित करना नहीं था और न उनका उद्देश्य भारतीयों के हाथ में यथायुक्त शक्ति देना था। उनका उद्देश्य नरमदल को बस में करना तथा हिन्दू मुसलमानों के बीच खाई को गहरा करना था। इसलिये इसके द्वारा जहाँ एक ओर लेजिस्लेटिव कोसिलो में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई वहाँ दूसरी ओर साम्प्रदायिक-प्रतिनिधित्व प्रणाली को मान लिया गया। उदाहरण इस समय नेतृत्व-बिहीन था; उसके सब नेता जेलों में थे। सन् १९१० के बाद सरकार की नीति में परिवर्तन होने लगा क्योंकि योरोप में युद्ध के बादल दिन पर दिन अधिकाधिक घने होते जा रहे थे। १९११ में मन्नाट जॉर्ज पञ्चम भारत आये और बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। सन् १९१२ में नीकरियों ने अधिक भारतीयों को भर्तों के सम्बन्ध में एक रायल कमीशन नियुक्त किया गया। इस समय मुसलमानों में राजनैतिक चेतना बढ़ी। मुस्लिम लीग के अन्दर एक उग्रशक्त का जन्म हुआ। इसके नेता मौलाना मोहम्मद अली थे। सन् १९१३ में लीग ने भी स्वराज्य (Self-government) को अपना उद्देश्य बतलाया। लीग तथा कांग्रेस में इस समय काफी सहकारिता थी। परन्तु इस समय देश में अँग्रेजों के विरोध में कोई आन्दोलन नहीं हुआ।

प्रथम महायुद्ध में भारत ने इंग्लैंड की सहायता की। अँग्रेजों ने कुछ इस प्रकार के आश्वासन दिये कि युद्ध के पश्चात् भारत की स्वतन्त्रता प्रदान की जावेगी। लाखों भारतीयों ने मित्र-राष्ट्रों के लिए युद्ध में अपने प्राण दिये और करोड़ों रुपया भारत ने दिया। इस समय देश में फिर आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। १९१४ में कांग्रेस के सम्मेलन श्री भूषेन्द्रनाथ बसु ने अपने सम्भाषण पद से कहा कि भारत के शासन में आमूल परिवर्तन होने चाहिये। ऐनी बेसेंट ने कहा कि भारत स्वतन्त्रता चाहता है। इस समय लोकमान्य तिलक जेल से छूट गये थे। सन् १९१५ में श्री गोखले तथा श्री फिरोजशाह मेहता की मृत्यु से नरमदल को आपात पहुँचा। सन् १९१६ में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस में दोनों दल मिल गए। इस अधिवेशन के बाद भारत में 'होम रूल' आन्दोलन ऐनी बेसेंट तथा तिलक के नेतृत्व में प्रारम्भ हुआ। सरकार ने ऐनी बेसेंट को नजरबन्द कर दिया (१९१७)। इससे देश में होम रूल आन्दोलन

और बढ़ा। परन्तु कुछ काल बाद ऐनी बेमेट रिहा कर दी गई। होम रुल आन्दोलन अधिकतर वैधानिक हो रहा।

युद्धकाळ में मुसलमानों तथा कांग्रेस में सहयोग बढ़ता ही गया। मई १९१६ में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। इनके एक स्वल्प इन दोनों दलों ने सुधारों की एक समुचित योजना स्वीकार की। इसको साधारणतः कांश्म-लीग पैक्ट कहा जाता है। इस समझौते के द्वारा मुसलमानों के नेताओं ने स्वराज्य की माँग को मान लिया और हिंदुओं ने साम्प्रदायिकता निर्वाचन पद्धति को स्वीकार कर लिया।

मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों वैधानिक रूप से कार्य करने में विश्वास करती थी। इनके प्रतिरिक्त भारत में आतङ्कादियों तथा क्रांतिकारियों के हल भी थे तथा देश के बाहर भी इनके संगठन थे। इन भयानकों का जमना तथा टका न अंगरेजों के विरुद्ध उकसाया। इनके पास बाहर से कुछ हथियार भी भेजे गये परन्तु घगोल, पंजाब तथा उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत तीनों स्थानों में जहाँ क्रांतिकारियों ने अंगरेजों के विरुद्ध वगावत की चेष्टा की थी वे असफल रहे। भारतीय जनता की यद्यपि इनके प्रति सहानुभूति थी परन्तु भारतीय नेता इनके प्रति विरक्त थे और वे वैधानिक उपायों से अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाहते थे।

अगस्त १९१७ में भारत मंत्री ने ब्रिटिश सरकार की भारत के प्रांत नीति को एक घोषणा द्वारा स्पष्ट किया। नवम्बर १९१७ में भारत मंत्री मि० मोण्टेग्यू भारत प्रायें और १९१८ में मोण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड योजना से भारत में उपवादियों को न शोध नहीं हुआ। उन्होंने इसको निरासाजनक बतलाया।<sup>१</sup> परन्तु नरमदन वालो ने इस योजना को समीपजनक बतलाया जो कि क्रमशः उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना की ओर प्रगतिरहीगी। अगस्त १९१८ में कांग्रेस का सम्मेलन में एक अधिवेशन हुआ। परन्तु नरमदन वालो ने इसमें भाग नहीं लिया और नवम्बर १९१८ में अपनी मूल्य बार्थेन्स को। इस प्रकार भारतीय लिबरल फेडरेशन का जन्म हुआ। बाद को दिसम्बर १९२० में लिबरल पार्टी ने १९१९ के ऐक्ट के अधीन नए चुनावों में भाग भी लिया।

१ 'य मनी ऐनी डमन्ट न बहा, The scheme is ungenerous for England to offer and unworthy for India to accept'

गान्धी युग तथा जन आन्दोलन — सन् १९१९ के पश्चात् भारत में कांग्रेस का आन्दोलन केवल समाज के निहित तथा उच्चवर्गों तक ही सीमित नहीं रहा परन्तु यह जन आन्दोलन हो गया। इसका ध्येय मराना गांधी की है। गांधी ने दक्षिणी अफ्रीका में गिरा की भारतीय-विरोधी नीति का मफलातपूर्वक विरोध किया था। उनका रुख अमहयोग था और उनका नारा अहिंसा तथा सत्य था। अफ्रीका में भारतीयों की बहुत दुर्दशा थी और धाज भी भारतीय वहाँ के गिरे आनकों के कारण तथा उनकी सकुचित क्षमोक्ति के फलस्वरूप नागरिक व अधिचारों से बचित हैं। गांधी जी ने इस नीति के विरुद्ध वहाँ जन आन्दोलन चलाया था। दक्षिणी अफ्रीका की सरकार की भारतीय विरोधी नीति के कारण भारत में बहुत असन्तोष बढ़ा। इस काल में अंग्रेजी के विरुद्ध जो भारत में आन्दोलन हुआ उसका एक कारण प्रवासी भारतीयों की दुर्दशा भी थी। दक्षिणी अफ्रीका से वे भारत आ गए थे क्योंकि उन्होंने यह देख लिया था कि प्रवासी भारतीयों की दशा में तब तक कोई सुधार सम्भव नहीं है जब तक भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र नहीं हो जाता है।

युद्ध के पश्चात् भारतीयों की भाषा के विरुद्ध अंग्रेजी सरकार ने स्वराज्य तथा स्वतन्त्रता के बदले भारत में दमनकारी नीति को अपनाया। सरकार का यह विचार था कि रुत तथा अफगानिस्तान के एजेंट भारतीयों को भड़का रहे हैं। इसलिए मार्च १९१९ में युद्ध कानून पास किया गया जिसके द्वारा नागरिकों की स्वतन्त्रता का मूल्य कुछ नहीं रहा। इनको साधारणतः रोलट बिल (Rowlati Bills) कहते हैं।

इन बिलों के विरुद्ध देश-व्यापी आन्दोलन हुआ। इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। सरकार ने दमन के द्वारा आन्दोलन को कुचलना चाहा परन्तु इसमें वह सफल न रही। गांधी जी ने जनता से हड़ताल करने की अपील की थी। भारतीय जनता ने इसमें पूर्ण रूप से भाग लिया। पंजाब में फातल अनाब होने के कारण आधिक अश्रुता सराब थी। इनके साथ साथ युद्धतोर मोमारियों के कारण भी जनता का कष्ट बढ़ गया था। ऐसी दशा में वहाँ असन्तोष स्वाभाविक था। युद्ध में पंजाब के ग्रामों से हजारों की संख्या में नवयुवक सेना में भर्ती हुए थे। परन्तु युद्ध के बाद सरकार वहाँ के प्रति उदासीन थी। ३ अप्रैल १९१९ को अमृतसर में २०,००० जनता की सभा के ऊपर फौज ने तब तर गोली चलाई जब तक कि उनकी गोलियाँ समाप्त न हो गईं। वह गोलीकाण्ड अत्यन्त नृशस्नानूर्ण था। इसके फलस्वरूप

**असहयोग-आन्दोलन** -- गांधी जी ने देश के सम्मुख यहिनामक असहयोग आन्दोलन का कार्यक्रम रखा। इस विषय में कांग्रेस में कई मत थे। परन्तु सितम्बर, १९२० में ऋषभदेव के विशेष अधिवेशन में बहुमत ने गांधी जी का साथ दिया। इस अधिवेशन में गांधी जी ने अपने व्याख्यान में कॉमिटल प्रवेश का विरोध किया तथा मन् १९१९ के सुधारों में प्रत्याग्रह को नहीं क्योंकि वे स्वराज्य की ओर नहीं ले जा रहे थे। सितम्बर १९२० में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के विचार पूर्णतः स्वीकार कर लिये गये। इस अधिवेशन में ही यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकृत किया गया कि कांग्रेस का ध्येय स्वराज्य है।

इस अधिवेशन के पश्चात् देश में उत्तरांग आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। इस आन्दोलन के कारण नई हजार व्यक्ति जेल गए, विद्यापियों ने बहुत बड़ी संख्या में स्कूल तथा कॉलेज छोड़ दिए, दफ्तरों ने बन्दन छोड़ दी, उपाधिशालाओं ने सरकारों को छोड़ दिया। इनके साथ-साथ देश में स्वदेशी का प्रचार हुआ तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। सरकार ने पूरी शक्ति से आन्दोलन को कुचलने का प्रयास किया, परन्तु मन् १९२१ में आन्दोलन और बढ़ा। प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत यागम पर कांग्रेस ने उनका बॉयकाट करने को कहा। जहाँ-जहाँ मुवजब गया जनता ने हड़ताल में उनका स्वागत किया।

आन्दोलन जोरों पर था, परन्तु ४ फरवरी १९२२ को चोरी-चोप नामक एक छोटे से शहर में कथेवन :००० के जलूस ने, २१ पुलिस-वालों को तथा एक पानेदार को पाने में ही जला दिया। इस घटना का गांधी जी पर अत्यन्त प्रभाव पड़ा और उन्होंने आन्दोलन का स्थगित कर दिया ( १२ फरवरी )। अंग्रेजी सरकार ने इसके बाद ही गांधी जी को पकड़ लिया। गांधी जी के मतदाग्रह स्थगित करने के कारण उनकी लोक-प्रियता में कुछ कमी अवश्य हो गयी थी। आन्दोलन के प्रारम्भ में गांधी का नारा था 'एक-रूप में स्वराज्य'। लोगों ने जब इसकी प्राप्ति के लिए इतना त्याग किया और जब वे समझते थे कि मकदुदा सन्निकट है, गांधी जी ने आन्दोलन वापिस ले लिया। गांधी जी की ६ वर्ष के कारावास का दण्ड मिला।

1. गांधी ने स्वराज्य की परिभाषा देते हुए कहा, "It means a state such that we can maintain our separate existence without the presence of the English. If it is to be a partnership, it must be a partnership at will."

2. "We were angry when we learnt of this stoppage of our

साम्प्रदायिक दंगे —आन्दोलन स्थागित हो गया। धार्मिक का स्थान गिराया ने ले लिया। लोग नहीं समझ पाये कि क्यों आन्दोलन आरम्भ हुआ तथा क्यों वह स्थगित किया गया। आन्दोलन स्थगित होने से हिन्दू तथा मुसलमानों के बीच पुनः मतभेद उत्पन्न होने लगा। अली बन्धु तथा श्री जिन्ना कांग्रेस से बिल्कुल अलग हो गये। कुछ काल के बाद खिलाफत आन्दोलन भी बन्द हो गया क्योंकि टर्की में कमाल पाशा ने अपना शासन स्थापित कर लिया था। खलीफा के लिये वहाँ कोई स्थान नहीं रह गया था। इसी समय हिन्दू महासभा की पुनः स्थापना की गई। इस प्रकार देश का वातावरण दूषित होना लगा था। फलस्वरूप देश में १९२१/१९२६ तथा १९२७ में साम्प्रदायिक दंगे हुए। श्री जवाहरलाल नेहरू के अनुसार आन्दोलन स्थगित हो जाने के कारण जनता की गद्दी हुई हिंसा वृत्ति इन साम्प्रदायिक दंगों के रूप में फूट पड़ी।

स्वराज्य पार्टी —कदाचित् जनता के सम्मुख कोई अन्य कार्यक्रम नहीं था तथा देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे इसलिए यह स्वाभाविक था कि कुछ लोग फिर से कौंसिल में प्रवेश की सोचें। इस मत के लोग में मुख्य श्री० सा० आर० दास०, श्री मोतीलाल नेहरू, श्री बिट्ठल भाई पटेल आदि थे। इन लोगों का विचार था कि ये सरकार का धारा सभाओं के मन्दिर से उलटें। वे सरकार के प्रत्येक काम का विरोध करेंगे। कौंसिलों के मन्दिर के प्रसहयोग का नारा था, क्योंकि कौंसिलों के बाहर प्रसहयोग असम्भव था।

सन् १९२३ में स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई। निर्वाचनों में कई प्रान्तों में इस दल को अच्छी सफलता मिली। इसी वर्ष फरवरी में गांधी जी रिहा कर दिए गये थे। दिसम्बर १९२४ में गांधी जी ने स्वराज्य पार्टी के कार्यक्रम को मान लिया। स्वराज्य पार्टी ने उनके रचनात्मक कार्यक्रम का स्वीकार कर लिया—बर्खास्त जमींदारों तथा हिन्दू मुस्लिम एकता का प्रयत्न। स्वराज्य

struggle at a time when we seemed to be consolidating our position and advancing on all fronts" J. Nehru, Autobiography p. 81

"1. The drift to sporadic and futile violence in the political struggle was stopped, but the suppressed violence had to find a way out, and in the following years, this perhaps aggravated the communal trouble" Autobiography p. 86

पाटी ने कॉमिलो के अन्दर अस्त्रा काम किया, परन्तु ये सरकार को अपने कार्य-क्रम से विचलित नहीं कर सके। इन पाटी के पीछे अपना सन्निधि भी सी० आर० दास थे। जून १९२५ में देगदगु का देहान्त हो गया। इससे स्वराज्य पार्टी की दहूँ बड़ी हो गई। इस समय स्वराज्य पार्टी के अन्दर भी मत भेद पैदा हो रहा था। एक भाग सरकार से उन्होंने काम की नीच रहा था। इन सबका फल यह हुआ कि स्वराज्य पार्टी अशक्त होने लगी और १९२६ के निर्वाचनों में पहुँचे की तरह सफल नहीं रही।

साइमन कमीशन.—जब देश में एक प्रकार की नाराजगी फैली हुई थी तथा विदेशी-सरकार के प्रति किसी प्रकार का आन्दोलन नहीं था उस समय ब्रिटिश सरकार ने एक कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की। १९१९ के ऐक्ट के अनुसार १० वर्ष बाद (अर्थात् १९२९) एक कमीशन इस बात की जाँच करने को नियुक्त होता कि नया ऐक्ट कार्यरत में बितना नफ़्त हुआ। परन्तु इंग्लैंड की सरकार ने दो वर्ष पूर्व ही एक कमीशन नियुक्त कर दिया। इसके समाप्ति पर जोन साइमन थे। अतएव यह साइमन-कमीशन कहलाता है। इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। इस कारण देश में प्रत्येक दल ने (सिक्ख मजदूर के अतिरिक्त दल तथा असलमानों के छोटे दलों के) इसका विरोध किया। श्री जिन्ना ने कहा कि किसी भी आत्मसन्मानी भारतीय के लिए इस कमीशन के दहिष्कार के अतिरिक्त अन्य कोई मूर्ख नहीं है। अंग्रेजी सरकार ने कहा कि भारत में हिन्दू तथा मुसलमान सम्प्रदाय में मतभेद न होने के कारण कमीशन में किसी भारतीय को सम्मिलित करना सम्भव न था। कमीशन के विरोध में विभिन्न सम्प्रदाय तथा राजनीतिक दल एक थे। केंद्रीय एसेम्बली में फरवरी, १९२८ को कमीशन के विरुद्ध एक प्रस्ताव पास किया गया।

साइमन कमीशन का सर्वत्र हड़ताल तथा काले झंडों द्वारा स्वागत किया गया। सम्पूर्ण भारत में हजारों काले झंडे लहराए जा रहे थे 'गोदीक'। सरकार ने सब जगह प्रदर्शनकारी पर लठी-प्रहार किया। लाहौर में लाला लाजपत राय पुलिस की लाठीचार्ज के शिकार हुए। लखनऊ में ५० नेहरू तथा ५० पन्त की लाठीचार्ज की चोटें सहनी पड़ी।

सन् १९२८ में भारत भर में फिर से एक आन्दोलन फैल गया। नवयुवकों में एक नया उत्साह आया। स्थान-स्थान पर नवयुवकों की समितिें स्थापित हुईं। इसी समय देश में मजदूर आन्दोलन ने भी जोर पकड़ा। मजदूरों की हड़तालें हुईं। किसानों में भी एक नयी जागृति आयी। नवयुवकों में भी एक नयी चेतना का संचार हो रहा था। भारत के पूर्वाजापति तथा व्यापारी



मा प्रिटिस नीति के विरुद्धी हा रहे थे। देश में अन्तर्गत फिर उभड़ा। लाहौर में तिस गुणित अफगन ने न्याय लाजस्वय पर बार किया था उसको गोला मार दा गई। सगतमिहू तथा श्री ५० दत्त ने अगम्यलो में बम फेका तथा 'इन्'दाय जिन्दाबाद का नारा लगाया।

★ नेहरू रिपोर्ट —अंग्रेजी सरकार का कहना था कि भारतीय सम्मिलित रूप में कार्य विधान बना ही नहीं सकते हैं। इसी बात पर दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। ५० मानीलाल की अध्यक्षता में एक कमेटी स्थापित हुई। इसने अंग्रेजी रिपोर्ट में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स की मांग रखी। यह सम्मेलन १९२८ में लन्दन में एक सर्वदलीय सम्मेलन के सम्मुख रखी गयी। नेहरू रिपोर्ट को कांग्रेस ने मान लिया परन्तु लीग ने इसे नहीं माना—श्री जिन्ना कुछ बातें मनमाना चाहते थे। कांग्रेस के अन्दर भी एक छोटे से वर्ग ने इस रिपोर्ट से इस कारण असन्तोष प्रकट किया क्योंकि इसने पूर्ण-स्वतन्त्रता छोड़ गयी तथा यह। ब्रिटिश-सरकार ने इस रिपोर्ट पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया।

समिन्धय अपिज्ञा आन्दोलन —मार्च १९२९ में भारत में बेकारी तथा गरीबी बढ़ रही थी। मजदूरों की दसा शोचनीय थी क्योंकि वस्तुमा के मूल्य बहुत बढ़ गए थे। मध्यवर्ग भी असन्तुष्ट था। देश में कई स्थानों में मजदूरों की हड़तालें हुईं। सरकार ने मजदूर आन्दोलन को कुचलने के लिये कम्प्युनिस्ट पार्टी के मुख्यायों वरसाओ का पकड़ा तथा उन पर मुहदमा चलाया। यह मेरठ-पटवन्ध केस कहलाता है।

इंगलैंड में मजदूर दल की सरकार बन गई थी (मई, १९२९)। परन्तु भारत के मामल में इस दल तथा अन्य दल की नीति में भाषा के प्रतिस्वित पन्थ कोई भेद नहीं था। भारत के वाइसराय इंगोड गए तथा वर्ग से लौट कर लार्ड इ विन ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत तथा रियासतों की एक वा फ्रेण्ड बुलायेगी परन्तु समिन्ध ने इसमें भाग लेना शक्य समझा।

दिसम्बर १९२९ में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पास किया गया तथा मौफी जी ने अंगरेजी सरकार से कहा कि अगर ३१ दिसम्बर तक भारत का स्वतन्त्रता प्रदान न की गई तो वे समिन्ध प्रस्ताव जिन्दाबाद नाराज करगे। २६ जनवरी १९३० को देश भर में स्वाधीनता की प्रतिज्ञा पढ़ी गई। (तब से ही यह दिवस स्वाधीनता-दिवस के नाम से हर वर्ष मनाया जाता है।) कांग्रेस के सदस्यों ने घायलवाओ से इंगोडा

दे दिया। गांधी जी ने १८ मार्च को दांडी की ओर प्रस्थान किया और ६ अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। देश भर में आन्दोलन चला। गांधी जी ५ मई को पकड़ लिए गए। सरकार ने दमनचक्र पूरी शक्ति से चलाया। कई स्थानों पर गोलीयाँ चलाई, निहत्थे तथा अहिंसात्मक सत्याग्रहियों पर लाठियों की बर्षों की गई। करोड़ों एक लाख व्यक्ति जेलों में भर गए। सरकार को डूब नौति से असंतुष्ट और बड़ा। इसी समय आइमन कमिशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसने भाग में भी काम किया। परन्तु इस आन्दोलन में उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त के अनिर्दिष्ट, मुन्थनाता ने भाग नहीं लिया।

**गोलमेज सभा तथा गांधी इरविन समझौता:**—नवम्बर १९३० में प्रथम गोलमेज सभा की बैठक इंग्लैंड में हुई। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया क्योंकि इसकी मांगें सरकार द्वारा अस्वीकार कर दी गई थी। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने एक घोषणा भारत के सम्भावित विधान के बारे में की। जनवरी, १९३१ में गांधी जी तथा कॉम्रेन के १९ अन्य प्रमुख सदस्य छोड़ दिने प्राकि वे इस घोषणा पर विचार विनिमय कर सकें। गांधी जी ने कॉम्रेन की ओर से लाहं इरविन से मार्च १९३१ को एक समझौता किया। सरकार सत्याग्रहियों को रिहा करने को तैयार हो गई, कांग्रेस ने आन्दोलन बन्द कर दिया। कॉम्रेन ने दूसरी गोलमेज सभा में भाग लेने का वचन भी दिया।

द्वितीय गोलमेज सभा का अधिवेशन सितम्बर से दिसम्बर १९३१ तक हुआ इसमें कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने भाग लिया। परन्तु यह सभा भारत के विषय में कुछ निर्णय नहीं कर सकी। इनका कारण यह था कि विभिन्न भारतीय समुदायों की मांगें एक दूसरे से इतनी भिन्न थी कि आपस में कोई समझौता असम्भव था। अंग्रेजी सरकार ने इन प्रतिस्पर्धावादी दलों को खूब उकसाया। फल यह हुआ कि गांधी जी इंग्लैंड में गाली हाथ बापिम लौट आए।

४ जनवरी १९३२ को भारत सरकार ने गांधी जी की गिरफ्तार कर लिया। इसका कारण यह था कि ब्रिटिश-सरकार समझौते की नीति के स्थान में दमन की नीति का अनुसरण करना चाहती थी। गांधी जी के गिरफ्तार होने से देश में आन्दोलन फिर आरम्भ हुआ। सरकार ने गोली तथा इन्डों ने

1. गांधी जी ने इस विषय में कहा था, "It is with deep sorrow and deeper humiliation, that I have to announce utter failure to secure an agreed solution of the communal question."

इसका दवाना चाहा पुलिस का अत्याचार चरम सीमा पर पहुँचा। परन्तु आन्दोलन चलता रहा। विदेशी माल का बहिष्कार बहुत सफर हुआ। सरकार ने कामा में मुस्लिम लोग न भी म्हायता पहुँचाई। बम्बई में भीषण हिन्दू मुस्लिम दंगा हुआ। मुसलमानों ने विदेशी माल का बहिष्कार का साथ दिया।

मैकडोनाल्ड एयाह तथा पूना पैक्ट — ८ अगस्त १९३२ को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने भारत में साम्प्रदायिक प्रश्न का हल करने के लिए एक निर्णय दिया जो मैकडोनाल्ड एयाह कहलाता है। इन निर्णय के द्वारा साम्प्रदायिक-प्रतिनिधित्व बना रहा। इसके माध्य-साय अछूता का हिन्दुओं से अलग करने के लिए उन्हें भी अलग निर्वाचन अधिकार दिए गये। गांधी जी ने जेल में ही इसके विरुद्ध आन्दोलन-प्रदर्शन किया। पूना में हिन्दुओं तथा अछूतों के कुछ नेताओं के बीच समझौते की वार्ता चली। इसके फलस्वरूप एक 'पैक्ट' पर दोनों ने हस्ताक्षर कर दिये जो कि पूना पैक्ट कहलाता है। इस पैक्ट द्वारा यह तय हुआ कि हरिजनता के लिए प्रांतीय तथा केन्द्रीय धारा गमा में कुछ स्थान रखे जायें तथा उन्हें सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाये। इस वदे में अछूतों ने पृथक निर्वाचन की माँग त्याग दी। सरकार ने इस पैक्ट को मान लिया, इसलिए गांधी जी ने पूना उपवास तोड़ दिया। गांधी जी के उपवास का फल यह हुआ कि दश में अज्ञात आन्दोलन जारी न चला।

तीसरी गोली मेज़ सभा — इसका अधिवेशन नवम्बर-दिसम्बर १९३२ हुआ। इसमें कांग्रेस न भाग लिया। इस अधिवेशन की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने एक ध्वेन-पत्र प्रकाशित किया। इन माँगनाओं से भारत में कोई सन्तोष नहीं हुआ।

आन्दोलन का अन्त और कीमिल प्रवेश — इस में आन्दोलन घीमा पड़ रहा था। गांधी जी ने १९३३ में फिर से हरिजनों के उद्धार के लिए २१ दिन का अनशन करने का निश्चय किया। वे ८ मई को जेल से छोड़ दिए गए। गांधी जी ने सामूहिक आन्दोलन के स्थान पर व्यक्तिगत आन्दोलन की राय दी। माघ, १९३४ में कांग्रेस ने आन्दोलन वापिस ले लिया।

इसी बीच कांग्रेस ने फिर से कौंसिल प्रवेश कार्यक्रम को मान लिया था। कांग्रेस के अन्दर एक भाग था जो कि कांग्रेस की इस नीति से असन्तुष्ट था। दश में साम्यवादी दल भी इससे असन्तुष्ट थे। सन् १९३३ के चुनावों में कांग्रेस की अच्छी सफलता प्राप्त हुई।

१९३५ का ऐक्ट — इस ऐक्ट का दर्पण हम पहले अध्याय में कर चुके हैं। कांग्रेस के अन्दर दक्षिण पक्षियों को यद्यपि इस ऐक्ट में पूर्ण मन्तोप नहीं था तथापि वे इसके अन्तर्गत होने वाले चुनावों में भाग लेने को उत्सुक थे। कामपत्ती नेता इस कार्यक्रम से सन्तुष्ट नहीं थे। परन्तु कांग्रेस ने चुनावों में भाग लेने का निश्चय किया। १९३७ के चुनावों में कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली।

कांग्रेस ने मन्त्रिमण्डल बनाने से पूर्व यह आश्वासन चाहा कि गवर्नर उनके बानों में अनुचित हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह बात वाइसराय तथा गांधी जी के बीच एक समझौते द्वारा तय हुई। इसके पदचार् ६ प्राप्ति में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बना। दो शक्तों में कांग्रेस ने समुक्त मन्त्रिमण्डल बनाया।

कमिश्न में मतभेद :—कांग्रेस में दो विचार धाराएँ हो गई थी। एक तो वे गांधीवादी। इसके प्रतिनिधि पुराने नेता थे, जैसे सरदार पटेल, श्री राजेन्द्रप्रसाद, श्री आचार्य कृपलानी, राजा जी, श्री गोविन्द वल्लभ पन्त आदि। दूसरी और कांग्रेस के अन्दर एक जोशीली दामनमय विचार धारा पैदा हो गई थी। इस समय इसका नेतृत्व श्री मुन्नाखन्द बोस कर रहे थे। श्री नेहरू इन दोनों दलों के बीच में थे। श्री बोस अंग्रेजों के विरुद्ध एक आन्दोलन चाहते थे जो कि आत्मसत्ता पढ़ने पर हितात्मक भी हो सकती था। उनको समाजवादियों तथा साम्यवादियों का महयोग प्राप्त था। सन् १९३९ में जब श्री सुभाष बोस गांधी जी के विरोध करने पर भी पट्टाभि सीतारामैया को हटाकर दुबारा राष्ट्रपति चुने गये तब इनको कांग्रेस दक्षिण पक्षियों ने पसन्द नहीं किया। गांधी जी ने कहा 'पट्टाभि की हार मरी हार है'। त्रिपुरी कांग्रेस (१९३९) में इन्होंने श्री बोस के विरुद्ध एक प्रस्ताव पारित किया। बोस ने कांग्रेस छोड़ दी और अपना एक अलग दल बनाया। इसका नाम Forward Bloc रखा।

द्वितीय महायुद्ध—नवम्बर, १९३९ में द्वितीय महायुद्ध प्रारम्भ हुआ। अंग्रेजी सरकार ने बिना भारत की अनुमति के इसको युद्ध में सम्मिलित कर दिया। इसके विरोध स्वरूप कांग्रेस मन्त्रिमण्डली ने परतना कर दिया।

1- इस ऐक्ट तथा इसकी बाद की घटनाओं के लिए पृष्ठ २ अध्याय देखिए।

(अक्टूबर १९३५) । मुस्लिम लीग ने भारत भर में इस अवसर पर मुक्ति दिवस मनाया ।

पश्चिमी याराय की फामिल संताया न कुछ महीन व अन्तरही रोंद दिया । प्रजातन्त्रीय दशा की स्थिति चिन्तनीय थी । कांग्रेस की कार्यकारिणी में एक प्रस्ताव डाला यह कहा कि अगर भारत-भरदार को केन्द्रीय विधान मण्डल व प्रति उत्तरदायी बना दिया जाय तो कांग्रेस मुद्राकारीन सहयोग व लिए तैयार थी । इस उत्तर में वाइसराय ने अगस्त ८, १९४० को एक पारणा की । यह अंग-तापजनक थी और कांग्रेस ने व्यक्तिगत उत्प्राप्ति प्रारम्भ किया । (नवम्बर १९४०) ।

गत् १९४१ में मुद्रा व सम्पत्ति म दा महत्वपूर्ण बाने हुई । प्रथम ता यह कि जून १९४१ में जमनी ने रूम पर आप्रमण कर दिया । दूसरी बात यह हुई कि दिसम्बर के महीने में जापान ने भी मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । जय दिसम्बर १९४१ में भारतीय कांग्रेस का बारदोती अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस ने उन सब देशों में अपनी महानुभूति प्रकट की जो कि अपनी स्वतन्त्रता के लिए पातित्व के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे । परन्तु कांग्रेस ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि केवल एक स्वतन्त्र भारत ही देश की रक्षा के लिए समुचित प्रवृत्ति बन सकता है । जापान ने दक्षिणीयुर्वी, शिया को बहुत लोभ विजय कर लिया । अंग्रेजों का इस अवसर पर भारत के पूरा सहयोग की आवश्यकता हुई । इसलिए ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ने शक्रम और पॉन्स में यह ऐलान किया कि सर स्टुफोर्ड क्रिप्स भारतीय नताया से बात चीन करने भारत जायेंगे वचिन् ने यह भी कहा कि मुद्रोपरान्त भारत को औपनिवेशिक-स्वराज्य प्रदान किया जावगा ।

क्रिप्स मिशन गपन नहीं हुआ । इसी अवसरता के कारण का हम यणन कर चुके हैं । इससे पश्चात् कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया कि अंग्रेज भारत छोड़ें और ० अगस्त १९४२ का नए अध्याय का प्रारम्भ हुआ ।

कांग्रेस व नेताया के पकड़े जाने पर देश में क्षाम, असन्ताप तथा गुस्सा फैला । लोग ने आ कुछ ठीक समझा वह किया । रेलवे स्टेशन, गवणाने, पुलिस चौकियाँ, गैर-हो की मस्या में जग दिया । रेल की पटरियाँ उखाड़ दी तथा तार काट दिये । परन्तु अंग्रेजी सरकार इस आन्दोलन को कुचलने के लिये तैयार बंठी थी । अमानुषिक ध्वंशना में सरकार ने दमन

प्रारम्भ किया। सरकार के अनुसार कांग्रेस, जर्मनी तथा जापान से मिली हुई थी परन्तु यह नितान्त प्रगत्य था। कांग्रेस की सहानुभूति प्रजातन्त्रीय राष्ट्रों से थी। गांधी जी का विचार था कि भारत से अंग्रेजों सेनाएँ हटा ली जावें तो जापान फिर आक्रमण नहीं करेगा और करेगा भी तो भारत अपनी रक्षा ठीक ढंग से कर सकेगा।<sup>1</sup>

कांग्रेस सरकार ने भारत छोड़ो प्रस्ताव के बाद भी समझौता की बात चलाना चाहती थी। परन्तु सरकार ने नेताओं को पकड़ लिया और इस कारण से देश में क्षोभ उत्पन्न हुआ। गांधी जी का कहना था जो कुछ जनता ने किया उसका उत्तरदायित्व सरकार पर है। इस आन्दोलन में भी मुस्लिम लोग शामिल रही। इसने हमको हिन्दुओं का आन्दोलन बतलाया।

**आजाद-हिन्द-सेना** — इसका आरम्भ सितम्बर १९४२ में हुआ। जब जापान ने मलाया, सिंगापुर विजय किये तब एक बहुत बड़ी सख्या में भारतीय सैनिक तथा अफसर कैदी बना लिये गये थे। इन्हीं में से आजाद हिन्द सेना का संगठन किया गया। इस सेना में भारतीय सेना के सैनिकों के प्रतिरिक्त दक्षिण-पूर्वी एशिया में रहने वाले कई अन्य भारतीय भी भर्ती हुए। इसका उद्देश्य भारत को अंग्रेजों की दासता से मुक्त करना था।

— सन् १९४३ के जुलाई मास में श्री सुभाष चन्द्र बोस ने इस सेना का संचालन अपने हाथ में लिया। श्री बोस भारत से सन् १९४१ में प्रत्योप गये। वे वहाँ से अफगानिस्तान होते हुए जर्मनी पहुँचे और वहाँ से बाद को आजाद फौज के संगठन के लिए आये। उनको इस सेना ने नेता जी कहना प्रारम्भ किया। वे इसके मुख्य सेनापति थे। उनके अनुसार यह सेना पूर्णतया भारतीय थी और इनका उद्देश्य भारत की स्वतन्त्रता थी। जर्मनी और जापान से इस कार्य के लिये सहायता लेना वे अनुचित नहीं समझते थे। उनका कहना था कि आधुनिक इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जहाँ कि किसी देश ने बिना विदेशी सहायता के स्वतन्त्रता प्राप्त की हो।<sup>2</sup>

1. "The presence of the British in India is an invitation to Japan to invade India Their withdrawal removes the bait. Assume, however, that it does not, free India will be better able to cope with the invasion. Unadulterated non-co operation will then have full sway."

2. "I have yet to find one single instance in modern history where an enslaved nation has achieved its liberation without

मन् १९४२ से ६१ तक आजाद फौज न जगजा न मिद्ध व पछा म भाग गिया । परन्तु हमका आश्रित मकाना नही मिली । तथापि व निम्नद कि हमन वनी बहाली म गजरा म भाचा गिया ।

श्री सभाप लोग न एक अस्थायी सरकार की भी स्थापना का सा । हमरा जागान जमना आदि दगा न मान गिया था ।

७१ की अस्थायी - भारत छात्र आन्दोलन के स्वल्प में समय हम म एक वान में दूसर वान तक उत्तरेता का रह गये । परन्तु कुछ समय बाद जब आन्दोलन धीमा हो गया तब तक के उपर कई निपटिया आदि । उनमें सबसे मुख्य बंगाल का स्थिति था (१६११४४) । इस स्थिति का उत्तरदायित्व अंग्रेजी सरकार पर था का गण मिनिस्टर तथा वनी के व्यापारी बग पर ह । यह बहुत म बार्ड मराच १९४५ में व्यापारी गण न अपने स्वाध के सम्मुख था व निता का गौण समता । यह भाग्यवतता प्राप्ति के पता उत्तरी मनायति म बार्ड पत्रिकन नया हुआ । यह स्थिति के स्वल्प में अन्तमा गवाया जाता है कि जात गले म अधिक प्रतिम म पद प्राप्त था । ७१ भर म ७२ समय अन्तर्गत वस्थ का मरत व

नताभा का रिहाइ तथा पालन अन्तर्गत म ७२ म पद का अन्त था । भारत म भाग्यवत अन्त था वीक्षण के नतीजा का था पद गये । गांधी का सो १९४४ म गान्धी का गये व । कि म मयपान के प्रयत्न थे । गांधी जी तदा जिता गान्धी म गता ह । परन्तु यह प्रयत्न रत्ना । ज १९४५ म गान्धी का न वृत्त मनाय था । ७२ वर्ष विचार विनिमय अनु गिमरा में एक का फल गान्धी ग । यह गाम का जात व कारण अमर रत्ना ।

७२ म नय चनाय के फलस्वरूप मजदूर का शिरोय हुआ । मितवर १९४४ म बरत न पर थापणा का जिनर फलस्वरूप भारत म भाग चनाय हुआ । शीघ्र न भी भाग गिया । ८ शान्त म वीक्षम गवागमभाय म बहुमत था । इन मर दाता म यन् स्पष्ट हो गया था कि अन्त म सरकार भारत के साथ पर समन्वित वरना चाहती ह ।

निम्न सरकार न ग्या कि भारत म न गतिर्या पद हो रहा था । ७२ म मयपद व वात भारतय जनता का बहुत निता तब गामता म नता

foreign help of some sort And for en laved India it is much more honorable to join hands with enemies of the British Empire than to curry favour with it should be a moral part

रखा जा सकता था। आजाद-फौज के मामले को लेकर देश के एक कोने से दूसरे कोने तक हलचल मच गई। सरकार को यह आशा नहीं थी कि समस्त देश इस प्रकार आजाद फौज का साथ देगा। अंगरेजी सरकार ने सोचा था कि वह सेना के कुछ अफसरों पर मुकदमा चलावेगी, तथा उन्हें कठोर नज़र देकर भारतीयों के सम्मुख अपनी शक्ति का एक दृष्टान्त रखेगी। परन्तु इसको लेने के देने पड़ गए।

देश में असन्तोख केवल जमता तक ही सीमित नहीं रहा परन्तु सेना में भी धीरे-धीरे फैलने लगा। फरवरी, १९४६ में बम्बई में भारतीय नौ सेना के सैनिकों ने हड़ताल थी। उनकी माँग यह थी कि सब सैनिकों से एक प्रकार का ही बर्ताव हो चाहे वे मजदूर हो या भारतीय हों। सब राजनैतिक कैंदी तथा आजाद सेना के कैदों छोड़ दिये जायें। यह हड़ताल बम्बई के प्रतिरिक्त अन्य स्थानों में फैली। इन हड़तालियों तथा अंगरेजी सेना में सघर्ष भी हुआ। देश में नौ सेना के हड़तालियों के साथ पूरी सहानुभूति थी। बम्बई में मजदूरों ने हड़ताल कर दी। बम्बई के रास्तों में जमता तथा अंगरेजी फौज में टकराई।

इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि अंगरेजी सरकार ने यह स्पष्ट रूप से देखा लिया कि अगर भारत से समझौता नहीं किया गया तो घबड़ाहट फैलने लगेगी। यह यथार्थ में एक मुद्दा होगा। इस कारण वे समझौते की तैयारि हुई।

**कमिनेट मिशन तथा अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना :—**अंगरेजी सरकार ने कमिनेट मिशन को भारत भेजा। क्योंकि कांग्रेस तथा लीग में कोई समझौता नहीं हो सका अतएव इस मिशन ने ही एक योजना भारतीय नेताओं के सामने रखी। इस योजना को कांग्रेस तथा लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। विधान तथा के लिए चुनाव हुए। इनमें लीग ने भी भाग लिया।

अगस्त १९४६ में एक अन्तर्कालीन सरकार की स्थापना हुई। इसमें लीग सम्मिलित नहीं हुई। लीग ने देश भर में 'वाइसेरेंट ऐक्शन डे' मनाया जिसके फलस्वरूप कई स्थानों में भीषण साम्प्रदायिक दंगे हुए। यह कहने में कोई गलती नहीं होगी कि लीग का आन्दोलन अंगरेजी सरकार के विरुद्ध नहीं कर हिन्दुओं के विरुद्ध था। बंगाल में इस समय लीगी अभियान चल रहा था। बंगाल

1. इन सब का प्रथम परिणाम में विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है।



में लीग को हिन्दुओं के विरुद्ध जेहाद करने का अच्छा अवसर मिला। इन दलों की प्रतिनिधियाँ देश के अन्य भागों में भी हुई।

अक्टूबर माह में लीग अन्तर्कालीन सम्मेलन में सम्मिलित हुई। इसका काम कांग्रेस के मार्ग में रोड़े अटकाना था। वाइसराय ने लीग को इसलिये सरकार का स्थान दिया ताकि इनके और कांग्रेस के मतभेद के कारण देश में कुछ भी गति न हो सके। ए० नेहरू ने कहा कि वाइसराय लीग के शामिल होने के बाद एक एक कर कॅबिनेट के पहिए निकाल रहा है। जिन्ना ने कहा था कि लीग सरकार से पाकिस्तान प्राप्त करने के लिये सम्मिलित हो रही है। लार्ड बेंबेल ने लीग को सरकार में सम्मिलित कर लिया परन्तु लीग ने संविधान सभा में भाग लेना स्वीकार नहीं किया था। इस प्रकार सरकार साम्प्रदायिकता को उत्साहित कर रही थी।

लन्दन कांफ्रेंस तथा १९४७ का ऐक्ट — मुस्लिम लीग के अन्तर्कालीन सरकार में सम्मिलित होने में कांग्रेस की कठिनाईयाँ और बढ़ गई। लीग ने सरकार में सम्मिलित होते समय भी इस प्रकार का वरार नहीं दिया था कि बट कॅबिनेट मिशन योजना का पूरी तरह मान ही लेगी। लीग एक संविधान सभा के स्थान में दो संविधान सभाओं की मांग कर रही थी।

इंग्लैण्ड के प्रधान मंत्री ने कांग्रेस तथा लीग के नेताओं की एक कॉफ्रे स के लिये १० दन आमंत्रित किया। इस कॉफ्रे स का उद्देश्य कांग्रेस तथा लीग के बीच में इस प्रकार का कोई समझौता कराना था ताकि संविधान सभा ९ दिसम्बर से अपना काम आरम्भ कर सके। इस कॉफ्रे स में भी कांग्रेस तथा लीग में मतभेद न हो सके। जब संविधान सभा का अधिवेशन ९ दिसम्बर को हुआ तबमें लीग के सदस्य अनुपस्थित रहे। देश में इस समय साम्प्रदायिक दंगे हुए।

२० फरवरी १९४७ का ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि सन् १९४८ तक ब्रिटिश सरकार भारत में भाग लेना को ही शक्ति सौंप देगी। इसी दिन यह भी ऐलान किया गया कि लॉर्ड माउंटबैटन भारत के नए वाइसराय होंगे।

लार्ड माउंटबैटन २३ मच को नई दिल्ली पहुँचे। उन्होंने कांग्रेस तथा लीग के नेताओं से वार्ता की और इसके पल्लवरूप ३ जून को एक नई योजना

रखी। इस माउण्टबेटन योजना के अनुसार भारत का दो क्षेत्रों में विभाजन निर्दिष्ट हो गया।

इन योजना के अनुसार बंगाल तथा पश्चाद का भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन करने के लिये सीमा-कमीशन नियुक्त किये गये। गिल्टहड ग्रा जिला पूर्वी बंगाल में मिला दिया गया।

१४ अगस्त १९४७ को भारत तथा पाकिस्तान, ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत इन दो नए उपनिवेशों का जन्म हुआ। देश के विभाजन के फलस्वरूप स्वतन्त्रता प्राप्त हुई। परन्तु विभाजन के बाद भी देश में छद्म युद्ध रहा। हिन्दू तथा मुसलमानों ने जो कुछ किया, वह अक्षयणीय है। लाखों निर्दोष तथा निर्दोशी के प्राण गये, लाखों की सम्पति नष्ट हुई और लाखों की मरणा-पर-दार छांटना पड़ा। यह ब्रिटिश-नीति का बटुल्लू था।

भारत उपनिवेश २६ जनवरी १९५० ने स्वतन्त्र राष्ट्र हो गया। परन्तु यह राष्ट्र-बंध का सदस्य बना रहा। संघर्ष में यह भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास है।

## परिशिष्ट

(क) देशी-रियासतों में राष्ट्रीय जागृति :—आर के वर्ग में हमारे देशी रियासतों में जो जागृति हुई उसका वर्णन नहीं किया है। देशी राज्यों में जनता ब्रिटिश-भारत की जमात के मुकाबले में अधिक पिछड़ी हुई थी। इसका कारण यह था कि वे रियासतें एक प्रदेस से मध्य-युग में थीं। न इनमें शिक्षा ने प्रगति की थी और न उद्योग धर्म ने। परन्तु कुछ रियासतें इन मामलों में उन्नत थी, जैसे मैसूर तथा ग्वाल्हेर। राजनैतिक जागृति रियासतों में ब्रिटिश भारत से बाद प्रारम्भ हुई। इन सब रियासतों में जनता की किसी भी प्रकार के राजनैतिक अधिकार नहीं थे। इसलिए यह स्वाभाविक था कि इनमें जनता का आन्दोलन इन अधिकारों की मांग करे। सर्वप्रथम सन १९२७ में एक मण्डल की स्थापना हुई। इसका नाम देशी राज्य लोक-परिषद् रखा गया। इसका उद्देश्य इन रियासतों के निवासियों के लिये राजनैतिक अधिकारों की मांग करना था। आरम्भ में कांग्रेस ने इन रियासतों के मामलों में कोई ध्यान नहीं दिया। परन्तु कुछ काल बाद कांग्रेस ने इनमें भी उत्तरदायी शासन की मांग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सन् १९३१ में लोक-परिषद् का उद्देश्य यह था कि देशी रियासतों के निवासियों को वे सब अधिकार—राजनैतिक तथा सामाजिक—प्राप्त हों, जो कि ब्रिटिश भारत के

निवासियों का नये विधान व अन्तर्गत दिये जायेंगे तथा गिराफ्तार भारतीय सभ में शामिल हो ।

ज्या ज्या रियासतों में जागृति बढ़ती गई तथा-तथा लाख परिपक्व व तत्वावलोकन से विभिन्न रियासतों में जनता ने वहाँ अत्याचारी शासन व विरुद्ध आन्दोलन लिये । गरगा ने इन आन्दोलनों को बचन में गव उपाय धरनाये । रियासतों के निवासियों ने भी गालियाँ मारी तथा लाठियाँ मारी । उन्होंने भी अपने अधिकारों के लिए प्राण बलिदान दिये । देशी रियासतों व आन्दोलन में कांग्रेस ने प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया तथापि इसकी मदद पराजित रूप में सहानुभूति मिलती रही । देशी रियासतों का उन्नीसवाँ व सत्तावादी शासन का ही एक भाग है । इस प्रकार यद्यपि यह दो समस्याएँ व विषय एक ही अंगरेजी साम्राज्यवाद तथा इसके विरुद्ध आन्दोलन में हैं ।

( ४ ) साम्यवाद का जन्म — प्रथम महायुद्ध तक भारत में शायद ही कोई अपने को साम्यवादी कहता था । परन्तु सन् १९१३ में रूसी क्रांति ने पहिली बार भारतीयों का इस नई विचारधारा से परिचित कराया । पहिली बार भारतीयों ने यह सुना कि रूस में आर (Tsar) की अत्याचारी सरकार का स्थान में एक मजदूर तथा किसानों की सरकार स्थापित हो गई । भारत में भी इसका प्रसार हुआ तथा भारतीय नवयुवक इस नयी विचारधारा की ओर आकर्षित हुए । इस समय तक भारत में भी मजदूर-आन्दोलन का आरम्भ हुआ तथा मजदूर सभाओं की स्थापना हुई । इनका उद्देश्य मजदूरों के हितों का संरक्षण था । मजदूरों की दशा अत्यन्त खराब थी । इस कारण मजदूर सभाओं ने कई हड़तालें मगलित की ।

कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग साम्यवादी विचार धारा में प्रभावित हुए थे । पं० जवाहरलाल नेहरू तथा श्री सुभाष चन्द्र बोस अपने-अपने समयों में साम्यवाद (Socialist) कहते थे और भारत में इस प्रकार के समाज की स्थापना की बातें करते थे । इनके अतिरिक्त आचार्य नरेंद्र दत्त, श्री जयप्रकाश नारायण आदि भी कांग्रेस के अन्दर साम्यवादी थे । कांग्रेस ने इस विचार धारा में प्रभावित होकर अपना लक्ष्य भारत में वर्ग-विहीन समाज की स्थापना रखा ।

### प्रश्न

( १ ) मसौदा में सन् १८८५ से १९२१ तक के राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास लिखिये ।

( २ ) गान्धी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास लिखिए ।

( ३ ) भारत में राष्ट्रीय जागरूकता के क्या कारण थे ? उनका विस्तार-पूर्वक वर्णन कीजिए ।

( ४ ) १९०९ से १९३५ तक देश में नजबत की क्या नीति थी ? इस पर प्रकाश डालिए । (यू० पी० १९४०)

( ५ ) देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन के सन् १९१६ से सन् १९२९ तक के इतिहास का सूक्ष्म में वर्णन कीजिए । (यू० पी० १९५८)

## भारत में राजनैतिक दल

राजनैतिक दलों का महत्त्व — प्रजातन्त्र में राजनैतिक दलों का महत्त्व महत्व है। सामान्यतः यह सभी स्वीकार करना है कि बिना इन दलों के प्रजातन्त्रवाद सम्भव ही नहीं है। इन दलों के द्वारा जाता जो राजनीति की शिक्षा मिलती है। प्रत्येक राजनैतिक दल कुछ उद्देश्यों का लेकर चलता है और चाहता है कि सरकार उन उद्देश्यों की पूर्ति करे। इसलिये प्रत्येक राजनैतिक दल सरकार पर अधिकार करना चाहता है। प्रजातन्त्र में यह निर्वाचनों के द्वारा होता है। एक निश्चित समय के बाद निर्वाचन होता है। इसमें जनता प्रतिनिधियों को छांटती है और वे प्रतिनिधि जनता के नाम में शासन करते हैं। जिस दल का बहुमत होता है वही सरकार बनाता है।

भारत में भी कई राजनैतिक दल हैं। उनमें से कुछ बहुत छोटे हैं तथा उनका यहाँ के जनजीवन में कोई प्रभाव नहीं है। एक दल के अतिरिक्त, अन्य मुख्य मुख्य दलों का संक्षेप में वर्णन दिया जायगा।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस — गांधीजी ने भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास तथा कांग्रेस का इतिहास एक ही है। यह सच है कि कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य दलों ने भी इस आन्दोलन में भाग लिया तथापि कांग्रेस का ही वास्तव में महत्वपूर्ण रहा है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस उस समय एक दल न होकर स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाले सब दलों का संयुक्त मोर्चा थी। स्वतन्त्रता के बाद कांग्रेस से समाजवादी दल अलग हो गया है। इसके पूर्व कांग्रेस से साम्यवादी दल निकाल दिया गया था।

कांग्रेस की स्थापना सन् १८८५ में हुई। आरम्भ में कई वर्षों तक यह केवल उच्च मध्यवर्ग की संस्था थी। प्रति वर्ष इसका एक अधिवेशन किसी बड़े नगर में होता था और यह कुछ प्रस्ताव पास कर साल भर के लिये फिर निर्वाजित हो जाती थी। इससे आरम्भ इसलिये हुआ कि यह मध्यवर्ग की मांगों को जैसे शासन में भाग लेने का अवसर मिले या सरकारी नौकरियों में भारतीयों को अधिक पद दिये जायें, इत्यादि, सरकार के सामने रखे। इस

प्रकार इसका काम अंग्रेजी सरकार से प्रार्थना करना था। कई वर्षों तक इसका यही काम रहा। परन्तु जने जने, इनके स्वभाव में परिवर्तन होने लगा। इन सब कारणों का हम शिल्प-अभ्यास में वर्णन कर चुके हैं। वग-भग के कारण देश में जो अमनोभाव उत्पन्न हुआ उसने कांग्रेस के स्वभाव में और अधिक परिवर्तन हुआ। महापुरुष के बाद देश में राजनैतिक चेतना बढ़ी। गान्धी जी ने मद्रप्रथम कांग्रेस को आधार में जनता का संगठन बनाया। उन्होंने कहा कि हम अपना युद्ध तत्पक्ष ग्रहिणा के अगुओं से लड़ेंगे। कांग्रेस ने तदा ग्रहिणात्मक मार्ग का अवलम्बन किया। देश में कई लोग इनकी ग्रहिणात्मक नीति को पसन्द नहीं करते थे। उनके अनुसार यह प्रान्ति का मार्ग न होकर ब्रिटिश सरकार से समझौते का मार्ग था। हालाँकि को का कहना था कि जब-जब जन-मान्दोलन प्रान्तिकारी होने लगा तब-तब कांग्रेस ने उसको दन्द कर दिया। ग्रहिणात्मक-मार्ग के अनुयायियों का कहना था कि केवल इसी प्रकार स्वतन्त्रता प्राप्त ही सकती है। हिसात्मक तर्कों को अपनाते के अर्थ यह होगा कि ब्रिटिश सरकार अपनी पूरी शक्ति में ऐसे आन्दोलन को कबल देगी क्योंकि दारुद की उसके पाल कमी नहीं है। प्रताप केन्द्र नैतिक गर्वित द्वारा ही उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है।

कांग्रेस के अन्दर कुछ लोग यदा में ही ऐसे रहे जो कि केवल वैधानिक उपायों का ही अवलम्बन करना चाहते थे। इनके अनुसार स्वराज्य ऐंग्लो-इण्डियन के अन्दर में जीता जा सकता था। ऐसे विचार के लोगों ने स्वराज्य पार्टी को स्थापना की थी तथा चुनवाओं में भाग लिया और ऐंग्लो-इण्डियनों में गद। परन्तु इनको स्वराज्य नहीं प्राप्त हुआ।

कांग्रेस के इतिहास में सन् १९१९ के बाद यह दिखलाई देता है कि आन्दोलन की नीति तथा वैधानिक नीति बारी-बारी ने अपनाये गये हैं।

सन् १९२७ तक कांग्रेस ने अपना उद्देश्य औपनिवेशिक स्वराज्य रखा। यद्यपि लोकमान्य तिलक ने 'स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है' का नारा लगा दिया था, तथापि सर्वप्रथम सन् १९२७ में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य अपना लक्ष्य बनाया। इनके पश्चात् सन् १९२८ में कांग्रेस ने पुनः औपनिवेशिक स्वराज्य को अपना उद्देश्य बतलाया। परन्तु जब ब्रिटिश सरकार ने यह भी नहीं दिया तो फिर ने सन् १९२९ में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना उद्देश्य बनाया।

सन् १९३० के आन्दोलन के पश्चात् दूसरी गोलमेज सभा में कांग्रेस

ने भाग लिया परन्तु उसका हाथ केवल अमफरना आयी। दश में फिर आन्दोलन हुआ जा कि मन १०५४ में बन्द हुआ। मन १०३५ के तैयार क प्रान्ता में लागू होने पर कांग्रेस ने चुनाव के पश्चात् ८ प्रान्ता में अपने मन्त्रिमण्डल बनाये।

द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होने पर जब अग्रणी सरकार ने भारत को बिना भारताया का राय के उसमें सम्मिलित कर दिया तब कांग्रेस-मन्त्रिमण्डल ने इसके विरुद्ध-रूप पद त्याग कर दिया। इसके बाद कांग्रेस ने मन् १९४० में व्याक्तिगत आन्दोलन जोर मन १९४० में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' चलाया। मन १९४१ में मन समझौते की जाने हुई तथा अगस्त १९४३ का भारत की शीतलविक्रम अगस्त प्रान्त हुआ तथा २६ जनवरी १९४० का भारत एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो गया।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् कांग्रेस ने विधान सभाया तथा सदन में बहुमत होने के कारण प्रान्तीय तथा केंद्राय सरकारें बनाई। १९४२ में निर्वाचनों के पश्चात् भी कांग्रेस का ही उत्थान रहा। उस समय कांग्रेस ही मताधिकार है।

कांग्रेस के विरोधियों के अनुसार इसमें अनेक घुसाइया आ गई हैं। इसके अवस्था में मेवा तथा त्याग का भाव नहीं रह गया है। वे स्वायत्त-साधन में अधिक रत हैं। कांग्रेस जब एक सरकार सम्प्राप्त हो गई है तथा इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार आगमन पर अधिकार रखना है। इसके अन्दर एकता भी नहीं है। दलबन्दी हो गई है। गांधी जी के आदेशास पर दूर दूर चला गया है। कुछ आलोचकों का कहना है कि कांग्रेस पूँजीपतियों के प्रभाव में है और इसके द्वारा देश का कल्याण सम्भव नहीं है। इनके अनुसार ता स्वतन्त्रता के पश्चात् देश में कुछ भी उत्थान दृष्टिाचर नहीं होती है। जाने तथा कपड़े का प्रदन हल नहीं हुआ है। कांग्रेस सरकार की यात्राएँ बबल बागजी है। अत्रिहार में उन्हें सफलता नहीं मिली।

परन्तु कांग्रेस के समर्थकों का कहना है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् कांग्रेस ने देश के लिये जो कुछ सम्पन्न किया है उससे अधिक सम्भव नहीं था। आर्थिक अवस्था पहले से सुधार रही है। गल्ले का प्रदन ता हल ही हो गया है। अभी कठिनाइयाँ तथा समस्याएँ हैं। परन्तु इनके लिए कांग्रेसी सरकार प्रयत्नशील है। पञ्चवर्षीय योजना, सामुदायिक योजनाएँ तथा ग्राम-विकास की योजनाएँ शीघ्र ही देश की अवस्था को सुधार देंगी। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की प्रतिष्ठा बढ़ गई। ५० नेहरू का दम तथा अन्य साम्यवादी देशों में जो भव्य स्वागत हुआ वह इस बात को सिद्ध करता है।

कमिंस के उद्देश्य :—कांग्रेस का राजनैतिक उद्देश्य स्वतन्त्रता की प्राप्ति या और वह एक प्रकार से पूरा हो चुका है। इस कारण से लोगो का कहना है कि अब कांग्रेस का काम पूरा हो चुका है और इसे अब भंग कर देना चाहिए। कांग्रेस देश में प्रजातन्त्र शासन की स्थापना चाहती है। इसमें किसी प्रकार का धार्मिक भेद-भाव नहीं होगा तथा धर्म और गरीब को बराबर अधिकार मिलेंगे।

आर्थिक क्षेत्र में कांग्रेस एक धर्म-रहित समाज की स्थापना अपनी उद्देश्य बतलाती है। इसमें आर्थिक शोषण नहीं होगा। व्यक्ति की स्वतन्त्रता बनी रहेगी। इस बात का प्रयत्न किया जायगा कि मजदूरों को दशा में सुधार हो, देश में बेकारी न हो। सब लोग अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें।

इस वर्ष प्राचादी अधिवेशन में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि कांग्रेस का उद्देश्य देश में समाजवादी समाज की स्थापना है। कांग्रेस ने अध्यास (श्री ठेकर) के अनुसार अपने निम्नलिखित उद्देश्य हैं : (१) समाज के हित में उत्पादन के साधनों का समाजीकरण, अर्थात् ये किसी की व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं रहेंगे। (२) राष्ट्र की सम्पत्ति, भूमि तथा साधनों का ग्याप्तपूर्ण वितरण। (३) समाज के प्रत्येक भाग को भवित्त की समानता प्रदान करना।

कांग्रेस ने कुछ मास पूर्व अपने नागपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि देश में सरकार द्वारा मजदूरी इषि व्यवस्था लागू होनी चाहिये। पं० नेहरू कहा कि इसके अतिरिक्त देश की खाद्य स्थिति सुदृष्टाने का अन्य कोई साधन नहीं है। परन्तु कांग्रेस के अन्दर तथा बाहर अनेक व्यक्ति इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। उनके अनुसार समाजवादी व्यवस्था तथा सहकारी इषि दोनों ही व्यक्ति का स्वतन्त्रता के लिये घातक हैं।

सामाजिक क्षेत्र में कांग्रेस का उद्देश्य हरिजनोद्धार तथा साम्प्रदायिकता को हटाना है। यह मध्य-निषेध के पक्ष में है तथा अन्य सामाजिक पुराणों को

1. कांग्रेस-विधान की प्रथम धारा में यह कहा गया है कि—

“The object of the Indian National Congress is the well-being and advancement of the people of India and the establishment of a   
 tive comm   
 political,   
 and fellowship.”



हटाना चाहती है। शिक्षा-प्रचार तथा हिन्दी का प्रचार भी कांग्रेस अपना उद्देश्य रखती है।

गांधी जी ने सदा इस बात पर जोर दिया कि भारतवर्ष गाँवों का देश है और यहाँ की समस्या तब तक नहीं सुधर सकती है जब तक कि गाँवों का उन्नयन न हो। कांग्रेस अभी तक गाँवों की उन्नति को—शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, कुटीर-उद्योग आदि को—अपना कार्यक्रम में स्थान देती है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कांग्रेस सब देशों के साथ मैत्री-पूर्ण सम्बन्ध रखना चाहती है और सदस्य रहना चाहती है। कांग्रेस के कुछ विराधियों ने इस सदस्यता की नीति का केवल एक धोखा कहा है। उसके अनुसार कांग्रेस का स्थान अमेरिका तथा इंग्लैंड की ओर अधिक है। परन्तु अब ५० नेहरू की सदस्यता की नीति की वजह से, चीन आदि देशों ने भी सराहना की है। अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई है। इसका श्रेय ५० नेहरू तथा उनकी नीति को है।

कांग्रेस दल के नेता अब यह देखने लगे हैं कि सत्ताशुद्ध होने के पश्चात् इस दल में कई प्रकार की बुराइयाँ आ गई हैं। पद लोभ, लालच, गृहव्यथी, साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार आदि दोष इसमें भर गए हैं। इसके सदस्यों तथा प्रत्येक शाखाओं में भी यह आत्मत्याग नहीं रह गया है जिसके कारण कांग्रेस का इतना विकास हुआ। पण्डित नेहरू ने भी यह निश्चय किया था कि वे प्रधान-मंत्री-पद को त्याग दें तथा कांग्रेस के पुनर्संगठन की ओर ध्यान दें। उन्होंने यह विचार अपने सहयोगियों के समक्ष से छोट दिया परन्तु अब कांग्रेस के उच्च पदस्थ नेता कांग्रेस की उन दोषों से मुक्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं जिनके कारण कांग्रेस की प्रतिष्ठा दल में गिर रही है।

**प्रजा समाजवादी दल (Praja Socialist Party)** — इस राजनैतिक दल का निर्माण दिसम्बर १९५२ में हुआ। यह भारतीय समाजवादी तथा वृषक-भजदूर प्रजा पार्टी के संयुक्तीकरण से बना, अतएव इसका नाम प्रजा समाजवादी दल बन गया।

भारतीय समाजवादी दल का आरम्भ सन् १९२६ में पटना में हुआ था। कई वर्ष तक यह दल कांग्रेस के ही अन्तर्गत रहा। यद्यपि कई महत्वपूर्ण विषयों में, जैसे आर्थिक उद्देश्य, इसमें तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मतभेद था, तथापि समाजवादी इससे पृथक् नहीं हुए। परन्तु सन् १९४७ के पश्चात् समाजवादीयों तथा कांग्रेस में मतभेद बढ़ता ही गया और सन् १९४८ में यह दल कांग्रेस

में प्रलय हो गया। इनके पूर्व इनका नाम कांग्रेस नवोद्योगी दल था परन्तु प्रलय होने पर इसने अपने नाम के आगे में कांग्रेस शब्द हटा दिया।

कृपक पार्टी का मंगल आचार्य कृपलानी ने किया। आचार्य जी तथा अन्य कई कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं का यह विचार हुआ गया कि भारतीय कांग्रेस अपने आदर्शों के अनुसार काम नहीं कर रही है। यह जनता की सेवा से विमुख हो गई है तथा पूँजीपतियों के हितों को ही मुख्यतः ध्यान में रख रही है। यह गांधी जी के मार्ग से विचलित हो गई है। इसने अत्याचार बढ़ा दिया है। सरकार भी जनता की सेवा के विमुख हो गई है। इन्हीं कारणों से कृपलानी जी ने मई १९५१ में इन दल को नीव डाली।

जब मई १९५२ में भारत में आम चुनाव हुए उस समय नवोद्योगी दल तथा कृपक पार्टी दोनों ने ही अपने अपने क्षेत्रों में निर्वाचनों में संघर्ष तथा प्रादेशिक विद्रोह-मनाफों के लिये जड़े किए। इन दोनों दलों का यह कहना था कि कांग्रेस के स्थान पर वे सरकार बना सकते हैं। परन्तु निर्वाचनों में कांग्रेस को ही बहुमत प्राप्त हुआ तथा इन दलों को प्रत्यन्त ही सीमित सफलता प्राप्त हुई। मन्त्रालय में कृपक पार्टी ने भारतीय साम्यवादी दल के साथ संयुक्त मोर्चा बनाया था।

परन्तु इन दोनों दलों के नेताओं के अन्दर यह भावना घोर-घोर काम करने लगी है कि कांग्रेस के विरुद्ध विपक्षी दलों को एक संगठन बनाना चाहिए तभी सफलता मिलेगी। साम्यवादी दल के साथ इस दोनों का सिद्धान्त रूप में मेल नहीं था और वे साम्यवादी दल के विरोधी थे। अतएव यह स्वभाविक था कि ये दोनों दल मिलाकर एक नया दल बनाते। इस उद्देश्य से इन दोनों दलों के नेताओं के मध्य बातचीत हुई तथा अन्त में दिसम्बर (ता० २६, २७) में बम्बई में एक संयुक्त सम्मेलन हुआ तथा प्रजा-नवोद्योगी दल का निर्माण हुआ।

इस दल के विरोधियों का कहना है—विरोधकार साम्यवादियों का—कि यह एकता केवल अवसरवाद पर आधारित है। इसका कोई सैद्धान्तिक आधार नहीं है। क्योंकि नवोद्योगी दल का आधार मार्क्सवाद है तथा कृपक पार्टी का आधार गांधीवाद तथा स्वतंत्रता की नीति है। परन्तु प्रजा-नवोद्योगी दल के नेताओं का कहना है कि सैद्धान्तिक दृष्टि से इन दोनों दलों में कोई विशेष भेद नहीं है। अतएव इस एकता का आधार सैद्धान्तिक है।<sup>१</sup>

१. आचार्य कृपलानी ने बम्बई में २६ दिसम्बर को अपने भाषण में कहा: The new Party "is not formed in terms of any rigid political

इस देश का नाति यह है कि वैधानिक उपायों में यह कार्यक्रम का मन्त्रालय का स्थान में अपना सरकार स्थापित करेगा कि इसके अनुसार कार्यक्रम का नाति पूजापनियों का हित साधन करना है न कि जनता का। देश के सम्मुख वा गमस्याएँ हैं उनमें न कार्यक्रम एक का भा है न रतन में प्रथम है। यह कार्यक्रम मन्त्रालय का नाति म भा अनन्तर है।

इस देश के निर्माणविषय उद्देश्य है

( १ ) भारत में वष विहान तथा वष हान समाज का वापना करना ।

( २ ) देश में किसान-वच पन तथा मजदूर-मन्त्रालय का मगठन करना । यह माहिदा मर वग युद्ध का प्रजातन्त्र काय प्रजाता के अन्तर्गत मानना है ।

( ३ ) मुख्य उद्योग घघा तथा विज्ञान व्यापार का राष्ट्रीयकरण ।

( ४ ) यह अन्तराष्ट्रीय मन्त्र मन्त्रालय का नाति का मानना है । इस देश के अनुसार भारत का अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतन्त्र नाति का प्रवर्धन करना चाहिए तथा विराधा तन्त्र का म वापन करना चाहिए ।

( ५ ) यह सामन्तवादा व्यापार के विरुद्ध है।

प्रजा समाजवाद का यह अन्तराष्ट्रीय साधन का प्रभाव है रहता है जा कि किमा का सफलता के लिए आवश्यक है। देश के जनता में उत्पन्न तथा तन्त्रि मन्त्रालय भद है। यह का मन्त्रालय तथा कार्यक्रम का नाति म काड मन्त्रालय नही दक्षिणाचार होता है। इनमें पर्यन्त मन्त्रालय का औचित्य भा नही दाखला है।

समाजवाद का लक्ष्य — १। गममन्त्रालय गतिता न मन १० ५ म मन्त्रालय वादा का स्थापना वा। २। गतिता प्रजा समाजवाद का म पत्रक है गय वाकि तन्त्र अन्तर्गत प्रजा समाजवाद का द्वारा भाति म समाजवाद का स्थापना मन्त्रालय नही मन्त्रालय। शासनकार म मन १०५५ म वहा की प्रजा समाजवाद मन्त्रालय न मजदूर पर गतिता च गति। इस पर डा० गतिता न कहा कि इस गतिता का जाच (Judicial inquiry) होना चाहिए तथा इस पत्रालय का मन्त्रालय चाहिए। परन्तु प्रजा समाजवाद का लक्ष्य की कार्य समिति न डा० गतिता म सहमति नही प्रवर्त वा। इसा वान पर १। गतिता

creed orism It is based upon identity of certain basic principles of a common goal and major socio-economic policies. Both parties have accepted the idea that social change must be accomplished through peaceful means.

ने पृथक दल बनाने का निश्चय किया। उनका कहना है कि ७ वर्ष में उनका दल भारत में सत्तारूढ़ हो जायगा।

**वामपंथी समाजवादी** — समाजवादी दल के अन्दर एक प्रामत्त ही छोटा भाग ऐसा था जो कि दल की नीति से सन्तुष्ट नहीं था। इन लोगों का यह कहना था कि समाजवादी दल क्रान्तिकारी दल नहीं रह गया है वरन् यह दक्षिणी-पन्थी हो गया है। इसकी नीति मानसवादी नहीं रह गई है। श्रीमती अरुणा आसफ़अली ने कहा कि कोई भी मन्ना समाजवादी इस दल के अन्दर नहीं रह सकता है। अभी इस दल का विघेप प्रभाव नहीं है।

**साम्यवादी दल (Communist Party of India) :—** इसका जन्म सन् १९२४ में हुआ था। परन्तु करीबन बीस वर्षों तक यह दल प्रबंध रहा। इस कारण इसको खल कर काम करने का अवसर सन् १९४३ के पूर्व नहीं मिला। सन् १९४७ में स्वतन्त्रता के पश्चात् इस दल ने श्री पी० सी० जोशी के नेतृत्व में नेहरू सरकार का स्वागत किया तथा यह नारा दिया कि इस सरकार से सहयोग करो। परन्तु कुछ समय बाद इसकी नीति में परिवर्तन हो गया। श्री एणबिबे इसके नए मन्त्री चुने गये। उनके काल में दो वर्षों तक साम्यवादी दल ने सरकार का सर्वत्र विरोध प्रारम्भ किया। इस काल में रेलगाना में इस दल के नेतृत्व में सरकार के विरुद्ध खल कर विरोध किया गया। परन्तु यह सभर्ष की नीति असफल रही। इसके फलस्वरूप देश में इसका प्रभाव और भी कम हो गया। दल की नीति में पुन परिवर्तन हुआ तथा श्री अजय घोष इसके नए मन्त्री निर्वाचित हुए तथा अभी तक है।

साम्यवादी दल का चरम उद्देश्य भारत में पूँजीवादी व्यवस्था का पूर्ण रूपेण उन्मूलन करना है। इस प्रकार एक वर्ग-विहीन समाज की स्थापना होगी जिसमें मनुष्य का मनुष्य द्वारा शोषण का अन्त हो जायगा। उत्पादन में सब साधनों पर समाज का अधिकार होगा। इस उद्देश्य के पूर्ति के लिये साम्यवाद के प्रवर्तकों के मतानुसार, शान्तिपूर्ण या हिंसात्मक किसी भी प्रकार के मार्ग का अवलम्बन किया जा सकता है। भारतीय साम्यवादी दल का भी यही दृष्टिकोण था। परन्तु इस दल ने अमृतसर अधिवेशन के पश्चात् स्पष्ट रूप से यह घोषणा की है कि यह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति केवल वैधानिक तथा शान्तिपूर्ण उपायों से करेगा। इस दल ने प्रथम तथा द्वितीय निर्वाचनों में पूरा भाग लिया तथा दूसरे निर्वाचनों के पश्चात् केरल प्रदेश में इस दल द्वारा मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया गया है।

साम्यवादी दल का नीति-प्रोग्राम मध्य मध्य प्रजातन्त्रीय स्तर का था। उस समय यह दल में एक साम्यवादी सरकार की स्थापना न करके मध्य मध्य प्रजातन्त्रीय सरकार की स्थापना करना मुख्य बतलाते हैं। उस सरकार का मुख्य काम गरीबों की समस्या को हल करना होगा। अन्तराष्ट्रीय स्तर पर उस दल का उद्देश्य अमेरिका की नीति का विरोध करना है। यद्यपि इसके अनुसार मगार की शांति का सबसे बड़ा भय धर्मगर्भीय साम्राज्यवाद से है। देश के छे दस यह विभिन्न राष्ट्रीय वर्गों की अपने मासुहृतिक तथा आर्थिक उद्योग के लिए प्रत्येक प्रकार की स्वतन्त्रता का समर्थक है। उस दल के विरोधियों के अनुसार यह प्रजातन्त्र की स्थापना नहीं अपितु एक तिरकूट शासन की स्थापना करना चाहता है जिसमें कि केवल एक वर्ग होगा और कोई नहीं। वायस तथा प्रजा समाजवादी दोनों ही साम्यवादी दल के विरोध हैं।

अन्य धामपक्षी दल — ये मध्य छोटे छोटे दल हैं जो कि समाजवादी (Socialist) विचार धारा से प्रभावित हुए हैं। परन्तु इन दलों का प्रभाव बहुत कम है। इन छोटे दलों में सबसे मुख्य फारवर्ड ब्लाक है। उनकी स्थापना श्री सुभाषचन्द्र बोस ने कांग्रेस से घलग होने के बाद की थी। उस दल का प्रभाव सीमित है। उस समय दूसरा उद्देश्य भारत में एक समाजवादी सरकार की स्थापना है जो कि जनसाधारण के हित में तत्पर होगी। उसके अंदर दो विचारधाराएँ दृष्टिगोचर होती हैं। एक ही मार्क्सवादी है और दूसरी को हम प्रांतिकारी उदारवादी (Radical Liberalism) कह सकते हैं।

अन्य धामपक्षी दल के नाम य हैं — सोशलिस्ट पार्टी रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी, वक्म एंड पीपुल्स पार्टी रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आदि।

लिबरल पार्टी — लिबरल पार्टी का जन्म सन् १९१८ में हुआ। उस समय तक लिबरल पार्टी की कोई बलम सत्ता नहीं थी क्योंकि उदारवादी नेता कांग्रेस के ही अन्तर्ग थे। जब यह शुरू में प्रारंभ बनी थी तब यह यथाय म उदारवादिया का ही मस्या थी और यह वैधानिक उपाया के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर औपनिवेशिक स्वराज्य प्राप्त करना चाहती थी। परन्तु शनैः शनैः कांग्रेस के दृष्टिकोण में परिवर्तन होने लगा। लाइ कन्न के समय का म भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति घस-तोष और बढ़ा। बहुत नेताओं ने वैधानिक उपाय का छोड़कर अन्य उपायों को अपनाने पर जोर दिया। औपनि-

शिक स्वराज्य के स्थान में कुछ लोग पूरे स्वराज्य को अपना उद्देश्य बनाने लगे। पहले-पहल तो कांग्रेस के मन्दिर नरम दल वालों का ही जोर रहा परन्तु बाद की नरम दल वालों का अल्पमत हो गया। सन् १९१८ में ये नरम दल वाले कांग्रेस में अलग हो गये।

लिबरल पार्टी का प्रथम अधिवेशन सर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ। इस नई पार्टी का नाम इण्डियन लिबरल फेडरेशन रखा गया। लिबरल फेडरेशन का लक्ष्य महा औपनिवेशिक स्वराज्य रहा है। यह दल इस उद्देश्य की प्राप्ति वैधानिक उपायों से ही करने का पक्षपाती रहा है। इसीलिए जब-जब कांग्रेस में विदेशी शासन के प्रति आन्दोलन चलाने उदारवादी रुढ़ि से अलग रहे।

वर्षा में लिबरल पार्टी का जनता में कभी भी सम्पर्क नहीं रहा। एक तरह से यह पार्टी खोही नहीं। इनमें नेता ही नेता थे। इनके नेताओं में भारत के प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं, जैसे सर सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, सर तेज बहादुर सप्रू, डा० जयकाद, श्री चिन्तामणो, डा० कुंजल आदि।

प्रति वर्ष लिबरल पार्टी अपना अधिवेशन करती है। इनमें देश की विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श किया जाता है। राष्ट्रीयता के इतिहास में इस दल विरोध महत्व नहीं रहा है। काजल इस दल का अंग हो चुके, गया है।

**स्वतन्त्र दल.**—श्री राजगोपालाचारी ने इस दल की अभी एक मास पूर्व स्थापना की है। इस दल के प्रमुख नेताओं में राजा जी, श्री मनानी तथा श्री० रंगा हैं। इस दल का उद्देश्य देश में सनातनवाद, सहकारी खेती तथा राज्य के बढ़ते हुए प्रभाव-क्षेत्र का विरोध कर व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा करना है। स्वतन्त्रता दल के घोषणा-पत्र को देखने से यही प्रतीत होता है कि यह केवल एक अनूदार दल नहीं है अपितु एक प्रतिक्रियावादी दल है। इस दल का नविष्य क्या होगा यह कहना कठिन है। यह सम्भव है कि यह अन्य प्रतिक्रियावादी दलों तथा दलों के साथ मिलकर देश में एक संयुक्त प्रतिक्रियावादी विरोध-पक्ष बनाने का प्रयत्न करे।

**साम्प्रदायिक दल:**—यद्यपि जिन राजनैतिक दलों का वर्णन किया गया है वे किसी सम्प्रदाय-विरोध के या धर्म-विरोध के ऊपर आधारित नहीं हैं। परन्तु इसके विपरीत वे राजनैतिक तथा आर्थिक कार्यक्रम को लेकर चलते हैं। इस लिये उनकी सदस्यता भी किसी विशेष सम्प्रदाय या धर्मानुयायियों तक ही

ही सीमित नहीं है। श्रत्येक भारतीय जाना कि उनके कायक्रम तथा सिद्धान्तों में विश्वास करता है उनका मद्ध्यम हासिल होता है। इन दलों के प्रतिरिक्त देश में कुछ अन्य दल भी हैं जो कि साम्प्रदायिक हैं। उदाहरणार्थ, हिन्दू महासभा, मुस्लिम लीग तथा मूस्लिम लीग। भारतवर्ष के विभाजन के पश्चात् भारत में मुस्लिम लीग की सक्ति क्षीण हो गई है तथा यह समाप्तप्राय सी ही है। मुख्य मुख्य साम्प्रदायिक दलों का वर्णन नीचे किया गया है —

**हिन्दू महासभा** — इस सताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में जब अंग्रेजी सरकार की नीति के फलस्वरूप मुसलमानों के नेता मुस्लिम लीग की स्थापना कर रहे थे उसी समय हिन्दू हिता के रक्षार्थ हिन्दू महासभा का जन्म हुआ। यह दल प्रारम्भ में राजनैतिक नहीं था। परन्तु इसका उद्देश्य हिन्दुओं के सामाजिक तथा सांस्कृतिक हिता की रक्षा करना था। इस दल में हिन्दू जनता इनकी ओर बाई विशेष आकर्षित नहीं हुई क्योंकि बापेस का अत्यधिक प्रभाव था। परन्तु जैसे जैसे मुसलमानों में साम्प्रदायिकता का भावना फैलती गई वैसे-वैसे हिन्दू महासभा का प्रभाव बढ़ा। परन्तु इनका होने पर भी हिन्दू महासभा कभी भी हिन्दुओं में अधिक जनप्रिय नहीं पाई। इसका कारण यह है कि हिन्दू जनता का यह विज्ञान रहा है कि बापेस उनके हिता का रक्षण ठीक प्रकार से कर रही है। इसके प्रतिरिक्त एक बात यह थी कि अंग्रेजी सरकार ने मुस्लिम लीग का मुसलमानों की प्रतिनिधि-मन्त्रा माना परन्तु हिन्दू-महासभा के इस दाव का कभी भी स्वीकार नहीं किया कि यह हिन्दुओं की प्रतिनिधि संस्था है। इससे बढ़ते अंग्रेजी सरकार सदा बापेस की ही हिन्दुओं की प्रतिनिधि मानती आई यद्यपि बापेस ने सदा सारे देश का प्रतिनिधि होने का दावा रखा। हिन्दू-महासभा के नेताओं में प्रमुख नाम लाला लाजपत राय, पं० मदन मोहन मालवीय, स्वामी श्रद्धानन्द, डा० मृ० जे० आदि हैं। वर्तमान समय में इसका नेता वीर सावरकर, श्री आशुतोष ठाकुर, श्री भापनकर आदि हैं। इस समय भी हिन्दू महासभा के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक नहीं है।

हिन्दू महासभा देश की अखण्डता में विश्वास करती है। इसलिए इसका प्रथम मुख्य उद्देश्य यह है कि देश के विभाजन का अन्त हो और भारत तथा पाकिस्तान के स्थान में अखण्ड भारत की स्थापना हो। इसका कहना है कि देश का विभाजन बापेस की ही नीति का परिणाम है। इससे प्रतिरिक्त महासभा के अन्य मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं —

(घ) यह देश में प्रजासत्ताक की स्थापना करना चाहती है जिनमें कि किसी भी प्रकार की जाति, वर्ण आदि का भेदभाव नहीं होगा। इस प्रजातन्त्र का आधार भारतीय सभ्यता होगी। देश के अन्दर एक न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना होगी।

(ब) देश की सैनिक शक्ति को बढ़ाना और इससे स्वतः स्वस्थ नागरिकों को सैनिक शिक्षा देना।

(स) देश की आर्थिक, सांस्कृतिक तथा भौतिक उन्नति करना। देश में उद्योग-पेशों की स्थापना करना।

(द) हिन्दू धर्म की रक्षा करना।

(ध) अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सब अन्य देशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखना तथा विश्व-शांति के लिए प्रयास करना।

अगर हिन्दू-महासभा सामाजिक क्षेत्र तक ही अपने को सीमित रखती तो शायद अधिक लाभदायक काम कर सकती। परन्तु राजनैतिक क्षेत्र में इसकी नीति प्रतिक्रियावादी है। यद्यपि यह एक प्रगतिशील आर्थिक कार्यक्रम को अपना ध्येय बतलाती है, परन्तु इसके अन्दर जमींदार, पूँजीपति आदि को देखने से लगता है कि इस क्षेत्र में इनका काम विशेष रहित की रक्षा ही होगी।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ.—संघ की स्थापना मन् १९२५ में डा० हेडगेवार द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य हिन्दू संस्कृति, हिन्दू धर्म तथा हिन्दू राज्य की स्थापना था। इस दल का प्रारम्भ महाराष्ट्र में हुआ था तथा अनेक वर्षों तक इसका प्रभाव उसी प्रदेश में सीमित रहा। परन्तु धीरे धीरे संघ का काम अन्य प्रदेशों में भी फैला। भारत के विभाजन के पश्चात् साम्प्रदायिक दंगों के फलस्वरूप जो वैमनस्य का वातावरण उत्पन्न हुआ उसमें संघ के विचारों तथा प्रभाव की प्रसारित होने का अवसर मिला। इस समय संघ के नेता श्री गोलवलकर हैं। संघ का उद्देश्य इसके अनुयायियों के अनुसार हिन्दू सभ्यता का पुनरुत्थान है। यह अपने को राजनैतिक दल नहीं बतलाता न इसके राजनैतिक उद्देश्य ही हैं। संघ का सबूतन धर्म सैनिक संगठन है। इसका प्रभाव अधिकतर विद्यार्थियों तथा छोटे दुकानदारों में है।

भारतीय जनसंघ :—भारतीय जनसंघ वास्तव में भारतीय न होकर एक हिन्दू साम्प्रदायिक राजनैतिक दल है। इसकी स्थापना मन् १९५१ में स्वर्गीय डा० व्यासप्रसाद मुखर्जी द्वारा की गई थी। यह वास्तव में राष्ट्रीय



स्वयं सबका मध्य का हूँ। राजनीतिक दल हैं। जनसंघ एक प्रतिनिध्यावादी दल है तथा सभी प्रगतिशील आर्थिक तथा सामाजिक सुधारों का व्यक्ति स्वातन्त्र्य तथा भारतीय संस्कृति के नाम पर विरोधी है।

(इस दल के निम्नान्वत मुख्य उद्देश्य हैं—(१) भारत की प्रगतिशीलता की स्थापना (२) भारत का राष्ट्रमण्डल से पृथक्करण, (३) भारत का आर्थिक विकास तथा औद्योगिक उन्नति (४) समाजवादी व्यवस्था तथा सरकारी श्रेणी का विरोध, (५) जातीयता का प्रश्न समुचित राष्ट्रमण्डल से वापिस लिया जाय, तथा (६) देश में अल्पसंख्यकों के हितों का समुचित संरक्षण।

देश के कुछ भाग में विशेषतः दिल्ली तथा पंजाब में जनसंघ का प्रभाव बढ़ रहा है।

सिखों के दल — सिखा के अन्दर एक भाग तो ऐसा है जो कांग्रेस में है तथा उस विचार का अनुयायी है कि कांग्रेस राष्ट्रीय मस्था है तथा किसी साम्प्रदायिक मस्था की मित्व शिता व विरोध रक्षार्थ आवश्यकता नहीं है। परन्तु इस विचारधारा का अनुयायियों के अतिरिक्त सिखा में दो दल हैं। एक तो अकाली दल है। इसके नेता मास्टर तारासिंह हैं। यह दल साम्प्रदायिक भावना से ओत प्रोत है। यह कांग्रेस का विरोधी है। इसकी माँग मुस्लिमों में यह है कि मित्व-शिता के रक्षार्थ यह आवश्यक है कि सिख साम्प्रदाय की एक अलग मस्था हो। इसको सबसे अधिक सन्तोष नव होगा जब कि एक मित्रिस्तान बन जाय। अकाली दल मुख्यतः राजनैतिक है। इसकी राजनीति का आधार धर्म है। दूसरा दल के नेता महाराजा पटियाला हैं। इस दल का कार्यन्वय राजनैतिक नहीं है। इसका प्रमुख उद्देश्य सिखा की सांस्कृतिक उन्नति है।

मुस्लिम लीग तथा अन्य मुस्लिम दल — हम पिछले अध्याय में यह बतला चुके हैं कि किस प्रकार सन् १९०३ में लीग का जन्म हुआ। लीग आरम्भ से ही एक प्रतिनिध्यावादी तथा अराष्ट्रीय मस्था रही है। इसका उद्देश्य सदा साम्प्रदायिक रहा है। इसका जन्म भारतीय राष्ट्रीयता के विकास में रोड़ पटकाने के हेतु अंग्रेजों की कृतनीत द्वारा किया गया था। कोई भी विदेशी शासन अधिक दिना तक किसी देश को दासता में नहीं रख सकता है अगर वहाँ के निवासी एक हाथ पर उसके विरुद्ध हो जायें। इसलिए अत्यन्त प्राचीन काल से ही सर्वत्र विदेशी शासकों ने फूट डालने की नीति

को अपनाया है। रोम के शासकों ने अपने साम्राज्य में इसी नीति को अपनाया था। इसको Divide and Rule की नीति कहते हैं। अंग्रेजों ने भी भारत में इसी नीति को अपनाया और इसमें कोई संदेह नहीं कि वे इसमें अत्यन्त सफल हुए बन्त में जब वे यहाँ से चले भी गये हैं, तब भी हम उनके प्रभाव से मुक्त नहीं हो सके हैं।

लीग ने स्थापना के पश्चात् सरकार के सम्मुख इस प्रकार की माँग रखी, जैसे कि मुसलमानों के हितों का सुरक्षण ठीक प्रकार में हो, उन्हें नीतिगतों में अधिक स्थान दिये जाय, मुसलमानों के लिये अलग निर्वाचन-क्षेत्र या निर्वाग हो इत्यादि। क्योंकि सरकार मुसलमानों को राष्ट्रीय आन्दोलन में अलग रखना चाहती थी, इसलिए सन् १९०९ में कार्ल लिप्पी मुघार द्वारा साम्प्रदायिक निर्वाचन का प्रारम्भ हुआ। परन्तु इस काल में देश में कई प्रसिद्ध मुसलमान नेताओं ने लीग का साथ नहीं दिया। कुछ प्रगतिशील विचार के नेताओं ने यह चेष्टा की कि लीग तथा कांग्रेस में मेल हो जावे। कुछ सीमा तक इसमें सफलता रही। सन् १९१५ में लखनऊ में कांग्रेस-लीग बैठ हुआ। इसके द्वारा लीग ने स्वतन्त्रता की माँग को धन्य भी उद्घोष स्वीकार कर लिया तथा कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को मान लिया।

जब दुष्ट के पश्चात् देश में अतन्त्रिय बड़ा तथा कांग्रेस का आन्दोलन और खिलाफत आन्दोलन हुए, तबका लीग ने विरोध नहीं किया। परन्तु इस काल में लीग में अधिक प्रभाव जमावत-उद-उत्कर्ष हिन्दू का हो गया था।

जैना पहले दिखाया जा चुका है सन् १९२३ से भारत में करीबन चार वर्षों तक कई स्थानों में हिन्दू मुस्लिम दंगे हुए। इन दंगों का सबसे उत्तरदायित्व अंग्रेजी सरकार पर है।<sup>१</sup> इनका अन्तर यह हुआ कि जो हिन्दू तथा मुसलमानों के बीच सन् १९१९ से एकता बली भा रही थी वह टूट गई तथा मुस्लिम लीग पुनर्गठित हो गई। परन्तु इन समय भी लीग के धन्दर को

---

1. पं० जवाहरलाल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'The Discovery of India', में लिखा है, "I cannot excuse or forgive the British authorities for the deliberate part they have played in creating disruption in India. All other injuries will pass; but this will continue to plague us for a much longer period."

विचारधाराएँ थी। एक तो कुछ मात्रा तक राष्ट्रीय था परन्तु दूसरी पूर्णतया साम्प्रदायिक थी। जब सन १९२७ में साइमन कमीशन का आगमन का थापणा हुई उस समय साम्प्रदायिक भाग ने अपना एक अलग अधिवेशन किया तथा कमीशन के स्वागत में एक प्रस्ताव पाम किया। इस समय उन्माथा भी माप्रदायिकता की भावना रही और उन्होंने नहरू रिपोर्ट का विरोध किया। "म रिपोर्ट में मंगल निराकरण मात्रा के अनमोदन किया गया था। परन्तु उन्माथा ने एक मांग रखी कि पत्रक निर्वाचित क्षेत्र हान चाहिये। लोग के अन्तर प्रतिक्रिया-सदिया का प्रभाव बढ़ना ही गया और अन्त में यह हुआ कि राष्ट्रीय विचार का असर मग हुआ।

मुम्तस नाम साम्प्रदायिकता बढ़ना म और इसका कारण अंग्रेजी सरकार का इस विचार धारा का प्रोत्साहन देना था। सन १९२९ में श्री मोहम्मद जली जिनान ने जो कि अपना राजनैतिक जीवन के आरम्भिक वर्षों में राष्ट्रीयता के समयक था लोग के लाहीर आइजगन में अपनी प्रसिद्ध १४ मांग रखी जो कि **Fourteen points** कहलाती ह। ये मांग नहरू रिपोर्ट की सिफारिशों का पूर्णतया विरोधी ह। इनमें में मुख्य निम्नलिखित थी —

(१) भारत का भाषी विधान सभात्मक हो तथा अयशिष्ट अधिकार शासकों के पाम हो। प्रांतों की स्वायत्त शासन का अधिकार हो।

(२) सब विज्ञान मण्डलों में अल्पसंख्यकों के नियम स्थान सुरक्षित हो। क्षेत्रीय विज्ञान मण्डलों में समानता के नियम एक तिहाई स्थान परक्षित हो।

(३) पत्रक निर्वाचन प्रणाली हो।

(४) मंत्र नीतिरिया में मुसलमानों के नियम उचित स्थान हो।

(५) समानता के धर्म मर्यादा भाषा आदि के संरक्षण का विधान मांग उचित प्रवृत्ति हो।

गोमज सभाओं में मुस्लिम लोग ने पूरी तरह से अंग्रेजी सरकार का साथ दिया। इसका फल यह हुआ कि अंग्रेजी सरकार ने राष्ट्रीय मांगों को यह कह कर ठुकरा दिया कि समानता इसके विरुद्ध है। अंग्रेजी सरकार ने पूरा प्रयत्न किया कि हिंदू तथा मुसलमानों में समझौता न हो पाय।

सन् १९३२ में ऐक्ट द्वारा भान्त में साम्प्रदायिकता को और प्रोत्साहन मिला। जब कांग्रेस ने ऐक्ट के अन्तर्गत चुनावों के बाद कई प्रान्तों में परम्परा दिया तथा मुस्लिम लीग की इन मांगों को कि सचरत मजि-मदल बनाये जाय, स्वीकार नहीं किया तो लीग ने मुसलमानों ने कहा कि देश में हिन्दू राज्य स्थापित हो गया है तथा मुसलमानों का धर्म, भाषा तथा संस्कृति सभी गण-  
में है। इस काल में देश भर में लीग का प्रभाव बढ़ा। अधिकाधिक मुसलमान इसमें आने लगे। जब कांग्रेस ने पद-त्याग किया तब लीग ने देश भर में मुक्तिदिवस मनाया।

इस काल में लीग की मांगें उत्तरोत्तर दृढ़ी हुई। लीग नेताओं के भाषणों में राष्ट्रीयता के विरुद्ध विष बटता ही गया। उन्होंने कहा प्रारम्भ किया कि हिन्दू तथा मुसलमान मिल कर नहीं रहे सकते हैं। सन् १९४० में श्री जिन्ना ने लीग के सभापति पद में भाषण देते हुए लाहौर में कहा था कि हिन्दू तथा मुसलमान दोनों की सम्प्रदाय, संस्कृति, भाषा और धर्म सब पूरक पूरक हैं। इसलिए यह भाषा करना व्यर्थ है कि वे दोनों मिलकर एक राष्ट्रीयता को जन्म दें। उनका इतिहास भिन्न है, उनकी प्रेरणा के स्रोत भिन्न हैं।<sup>1</sup> इस प्रकार हम देखते हैं कि लीग अधिकाधिक राष्ट्रीयता की राह छोटी जा रही थी। इसको मंजूर नहीं करती जा रही थी। अब यह केवल विशेष प्रतिनिधित्व या नौकरियों में अधिक स्थानों की ही मांग कर खड़ा न थी परन्तु अब यह कहने लग गई थी कि मुसलमान एक अलग राष्ट्र हैं। इसके बाद यह स्वतन्त्रादिक या कि दूसरा ब्रह्म यह होता कि मुसलमानों का एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो। लाहौर अधिवेशन में ही लीग ने यह प्रस्ताव पाम किया कि देश के वे भाग जिनमें मुसलमानों का बहुमत है स्वतन्त्र राज्य माने जाय।

संवैधान्त सन् १९३० में लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग की थी। इसमें उनके अनुसार पंजाब, उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्त प्रवेश, सिन्ध तथा बलूचिस्तान सम्मिलित होने चाहिये थे। तीन वर्षों बाद इंग्लैंड में कुछ मुसलमान विद्वानों ने एक पुस्तिका में यह सुझाव रखा कि उपरोक्त प्रान्तों का एक अलग राज्य

1. Islam and Hinduism "are not religions in the strict sense of the word, but are in fact different distinct social orders, and it is only a dream that Hindus and Muslims can ever evolve a common nationality.. The Hindus and Muslims have different religions, philosophies, social customs, literature."

है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान को "समृद्धि, शान्ति और विकास" तथा आर्थिक और हितों के लिए भारत के साथ सहयोग के लिए है।

इस प्रकार पाकिस्तान की भाग न ले मलिया। परन्तु १९४७ में यह  
एक अस्पष्ट विचार था। गीर वीर भाग न लेना ही भारत के मन्त्रियों  
की रणनीति का हिस्सा था। गीर वीर ने उन दिनों हमारा तारा लगाया।  
तायारण मुताबिक इतना शक्तिशाली प्रभावित हो कि वह और गीर रूठ भू  
गया। सन् १९४७ में मद्रास अधिराज्य में भाग न ले पाकिस्तान में अपना  
उद्देश्य स्वीकार किया। जब सन् १९६२ में भारत का आतंकवादी आतंक  
काग ने मुगलमान जाना में बला वि हमारा उद्देश्य भारत में हिन्दू राज्य  
स्थापित करना है हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें  
म अलग ही है।

मा १ ८० ग १९६६ तक कृषिगत राश व साधन समीक्षा के लिये  
कई बार योजनाय की वस्तु मरणा प्राप्ति न हुई। राजा जी ने भूतभाई  
दगार्द तथा अन्त में गांधी जी सभी धनपत्र रह ।

जब सन १८६१ में 'बंकिम' मिशन भारत में था तब मस्तिष्क में न उभर सामने यह सोच रखी कि उत्तर-पश्चिम में पंजाब उत्तर-पश्चिमी सीमा प्राप्त मिथ तथा बलुचिस्तान और पूर्व में यथा तथा आसाम पाकिस्तान में मस्तिष्क में नियो आर्य। पंजाब में तापय कासीर त भी था। गीग यह जाननी था कि 'तना' एव मित्रता अस्तमय है। परन्तु दगरी आर य भी स्पष्ट हो गया था किना गीग का मत्तु नियो भारत की ऐथानिक समस्या में नष्टी होनवता है। लाग अथी स्विटि म किगी भा प्रकार स्टन का तयार नहों था। परन्तु कश्मि विभाजन के नियो प्रस्ता नही थी। परन्तु धीरे धीरे उमरे अन्वयम्भावी या स्वीकार कर लिया। जब 'तुगद' १०८७ में प्रिटिन पालिया-मण्ड न भारतीय रथा अता एवट पाग किया नर भारतवष में दा उपनिवेश की स्थापना की गई—भारत तथा पाकिस्तान।

दृग्बल पक्षपात यन्म्याभाविन या वि जीय व सख नता दारिद्र्यतान धरे  
जाय । भारत मे आग का प्रवट प्रभाव कम हुआ गया । वर नता न न यह प्रयत्न  
हिया या वि मस्यमाना या फिर स नए रूप में मगटा किया ताए ताकि उनसे  
राजपतिर जीर मास्त्रनिक अधिकार गुरुगिर रह पम्नु अधिपति निधित  
मस्त्रिम वग विगी एक अलग दल की स्थापना व पम् म नदी है ।

नाम ए अनिर्विकल भारत म समग्रमाना न वल्लभय दग्भा रहे है।  
ब्रिटिश युग म मस्मिम जनता न ऊपर इगका प्रभाव लग का मपभा प्रत्यत

कम था। ये दल मद्रास में राष्ट्रीय विचारों के रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस का मद्रास शाखा दिया और विभाजन का विरोध किया। स्वतन्त्रता के बाद भारत में मुस्लिम जनता के ऊपर इनका प्रभाव पहले से कुछ बढ़ गया है। इन दलों में मुख्य तमील-उच्च-उत्तम हिन्दू, महाराष्ट्र दल, मोगल दल तथा सिंध दल हैं।

हमारे देश में चाहे हिन्दुओं के साम्प्रदायिक दल हों अथवा मुसलमानों के, दोनों के लिए कोई स्थान नहीं है। साम्प्रदायिकता केवल राष्ट्रीयता के ही विकास में बाधक नहीं है बल्कि यह देश में प्रगतिशीलता की भी गन्तु है। धर्म के नाम से प्रत्येक लुभार का विरोध करना साम्प्रदायिक दलों का काम रहा है। इसलिए अगर भारतीय जनता अपने बड़ना चाहती है तो उसे इन साम्प्रदायिक दलों की ओर से मुँह मोड़ लेना चाहिए।

### प्रश्न

- (१) कांग्रेस के क्या उद्देश्य हैं? संक्षेप में इनका इतिहास लिखिये।
- (२) प्रजा समाजवादी दल का किस प्रकार जन्म हुआ तथा इनके क्या उद्देश्य हैं?
- (३) साम्प्रदायिक दलों के ऊपर एक निबन्ध लिखिए। भारत में इनका क्या भविष्य है?
- (४) साम्प्रदायिक दल पर एक निबन्ध लिखिये।

(२० पी० १९५३)

## अध्याय २१

### धर्म तथा धार्मिक आन्दोलन

धर्म तथा जीवन में इसका महत्त्व —साधारणतः धर्म शब्द का तात्पर्य किसी विशेष प्रकार से किसी देवी देवता या ईश्वर की उपासना करना समझा जाता है। इस मय में यह व्यक्ति तथा ईश्वर के मध्य सम्बन्ध है। परन्तु व्यवहार जगत में धर्म इसका कहीं अधिक व्यापक अर्थ रखता है। धर्म से तात्पर्य न केवल एक विचार प्रकार की पूजा विधि या उपासना का हम ही मनष्यता चाहिए परन्तु वह यथायथ में एक जीवन का ढंग (a way of life) भी है। प्रत्येक देश में अलग अलग जीवन की दशाएँ होने के कारण अलग अलग धर्मों उचित या अनुचित समझी गई हैं। धर्म से तात्पर्य इन सब बातों से समझा जाता है। इस प्रकार धर्म जीवन में एक प्रकार का नियन्त्रण है। यह सिखाता है कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए। यह कुछ नैतिक नियमों का पालन आवश्यक बताता है। ये सदाचार के नियम प्रसन्नता प्राप्त के साधन हैं परन्तु इनके पालन से न केवल हम सत्कार में परमपौराणिक भी सुख प्राप्त होता है।

धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई? हम धर्म का विवर्धन करना यहाँ हमारा उद्देश्य नहीं है। कुछ विद्वानों के अनुसार धर्म का जीवन में अस्तित्व महत्त्व है। वह हमें सदाचार की ओर प्रेरित करता है। वह मनुष्यों के मध्य सामाजिक सम्बन्धों को सुदृढ़ करता है।

धर्म ही की देन है।

इन विचारों में सत्य का बड़ा अंग है। इस दृष्टि से सत्कार के सभी धर्मों में मूल बातें एक ही हैं इसलिए उनमें यथायथ में कोई भेद नहीं है। कोई भी धर्म यह नहीं सिखाता कि अत्यन्त भाषण करो। कोई भी धर्म दया के स्थान में निन्दितता नहीं सिखाता है। हम प्रकार सभी धर्म धर्मों को उन गुणों की प्राप्ति करने को कहते हैं जो कि सफल सामाजिक जीवन के लिए

अविच्छेदक है। प्रत्येक धर्म किसी न किसी रूप में एक अर्थोक्ति तथा अमानवीय शक्ति में निस्वास्त रहता है। यह शक्ति सर्वोच्च सव्यक्तिमाली, जगत् का यदि कारण मानी गई है। इसके रूप के विषय में प्रत्येक धर्म में अलग-अलग विचार है। धर्मों में आपस में उपामना की विधि के विषय में भी भेद है। परन्तु विभिन्नताओं के होते हुए भी उनमें बहुत अधिक मात्रा तक समानता है।

धर्म के कारण समाज में जहाँ एक ओर अस्पृश्यता आती वहीं दूसरी ओर कठोर घृणाइयाँ भी आती हैं। विभिन्न धर्मों के अनुयायियों ने एक दूसरे के विरुद्ध जो कुछ किया है वह अचर्चनीय है। योरोप में वैश्वीय धर्मावलम्बियों ने प्रोटेस्टेण्टों को आग में जिन्दा जलाया। मुसलमानों ने धर्म के नाम में अन्य धर्म के मानने वालों को तलवार के घाट उतारा, ईसाइयों ने इसी प्रकार के अत्याचार किए। सभी धर्मों ने दूसरे धर्मों के नमस्कार पर जब अस्वभाविकता कुछ न कुछ अत्याचार किए हैं। हमारे ही देश में, हमारे ही जीवन में, धर्म के नाम में हिन्दू तथा मुसलमानों ने जो कुछ एक दूसरे के विरुद्ध किया वह विदित है।

धर्म समाज की प्रगति में बड़े अवनयन पर बाधक सिद्ध हुआ है। यूरोप में जब पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी में वैज्ञानिक-ज्ञान (Scientific Knowledge) फैल रहा था, धर्म ने इसका विरोध किया तथा इसके अधार्मिक बतलाया। इसी प्रकार सब देशों में धर्म किसी भी प्रकार के परिवर्तन के विरुद्ध रहा है। धर्म के नाम में समाज में सुधारों का विरोध किया गया और आज भी हमारे समाज में सुधारों का विरोध किया जाता है। आज भी हमारे हमारे समाज में बड़े लोग हस्त्रिजनों को अथवा स्त्रियों की अधन्या में किसी प्रकार के सुधार के विरोधी हैं क्योंकि उनके अनुसार यह हमारे धर्म के विरुद्ध है। धर्म अत्यविज्ञान का जन्मदाता है। यह मानसिक दासता को जन्म देता है तथा विचारों की स्वतन्त्रता का शत्रु है। धर्म का आधार विज्ञान है, न कि बुद्धि। हमारे समाज में बाल-विवाह, पुनर्विवाह, पर्दा-प्रथा सब धर्म के नाम में उन्नित बतलाये जाते हैं। धर्म के ही नाम में विधवा-विवाह, मिथ्यों की शिक्षा, उनको अधिकार प्रदान करना आदि का विरोध किया जाता है। भारत में कुछ वर्ष पूर्व तक समुद्र यात्रा करना पाप समझा जाता था। बहुतों ने इसी कारण विदेश यात्रा ही नहीं की। जिन्होंने की भी उनमें ने बहुत न लोगों ने भारत आकर प्रार्थित किया। धर्म सरीर्णता का स्रोत है।

धर्म समाज को विभिन्न वर्गों में बाँट देता है। इन प्रकार साम्राज्य एकता नष्ट हो जाती है। हिन्दू-समाज में वर्ण-व्यवस्था ने समाज को अत्यन्त



दिया जाता, यद्यपि पुरुष मन्त्र में अधिक विवाह वर्ण वर्णना है। धर्म के नाम से पण्डित तथा पूजारी और नृपत्य जीव मौलवी भोग-माप्ति जनता को सृष्टे हैं। मध्म में, धार्मिकता कोई बुरी बात नहीं परन्तु धार्मिकता का अर्थ आदर्शवादी तथा कृष्णकार नहीं होना चाहिये।

भारत के मुख्य धर्मों का वर्णन दिया जाता है —

**हिन्दू-धर्म:**—भारत में जनता का अधिकतर भाग हिन्दू धर्म का अनुयायी है। इसमें शास्त्र धर्म कहा जाता है। इन धर्म में यह छेक है कि आत्म जितने भी धर्म प्रचलित हैं उनमें यह सबसे प्राचीन है। इनके अनुयायियों को नृत्याश्रमों में है। कर्तव्य मनार की जननस्थता का पाँचवाँ भाग इनकी मानता है।

हिन्दू धर्म के अन्दर कई मतमनान्तर हैं। इन कारण इनकी परिभाषा करना असम्भव है क्योंकि इनके अन्तर्गत ही कई विभेद हैं। इसका कारण यह है कि समय की गति के साथ-साथ मौलिक हिन्दू-धर्म में कई बातें जुड़ी चली गईं।

हिन्दू धर्म का शांत केंद्र है। ये चार हैं—सूर्यदेव, सूर्यदेव, मानदेव तथा अग्निदेव। हिन्दुओं का विश्वास है कि केंद्र किसी मनुष्य की वृत्ति नहीं परन्तु भाग्य के मूल में प्रकट हुए हैं। अर्थात् ये देव उन स्मृतियों के मध्य है जिनके द्वारा आर्य लोग अपने देवताओं की उपासना करने थे। आर्य प्रकृति-पूजक थे। वेदों में सूर्य, इन्द्र, वरुण, अग्नि वायु आदि की स्तुति है।<sup>1</sup> यह स्वभाविक है कि कृषि-प्रधान देश में प्रकृति की इन शक्तियों की उपासना की जावे। आर्य लोग इनको प्रशन्न करने के लिये यज्ञ करने थे। आरम्भ में आर्यों का विचार था कि मन्त्र की देवताओं ने ही सृष्टि की है। आर्य इन विविध देवताओं की उपासना इसलिए करते थे ताकि उन्हें मन्त्र में मूल मिले और नृत्योपरास भी उन्हें कष्ट न हो: इन समय यह विचार हो गया था कि करने के बाद पुष्पात्मा व्यक्ति तो स्वयं को जाते हैं और दुरात्मा नरक में जाते हैं।

1. "In this religion the various powers of nature like fire (agni), wind (vayu) and the sun (surya), amidst which man lives and to whose influence he is constantly subject, are personified. They are looked upon as higher beings, whom it is man's duty to obey and to propitiate." *Hiriyana, Essential, of Indian Philosophy*, p. 10.

धर्म धर्म आर्षा म इम विचार का आविर्भाव हुआ कि इन विविध दृष्टताओं में पीछे एक सबभ्रष्ट जगत् है और अथ सब सन्तिया उगी व विविध रूप है। उनका एकस्थान पर तन एकम कहा गया है। यह सर्वोच्च जगत् परमभू है और मारी गृष्टि म्मा म जगती है।

यहने-यहने अथ अपन देवताओं का प्रसन्न करने व लिय उह प्रसन्न तथा धी चढ़ाने थे। परन्तु कालान्तर म पूजा का इम आविर्भाव जगत् हो गया। यह-यहने यज्ञ होने लग। इनका वरन व लिय विषय पुण्डित वग का भी जन्म हुआ। इम प्रकार कम काटा की वृद्धि हुई। इम काल म यह विश्वास भी उत्पन्न हो गया था कि यज्ञ व दान जो कुछ चाहा वह कराया जा सकता है।

अथ आर तो कमवाण की वृद्धि हो रही थी परन्तु दूसरी ओर इमने प्रतिश्रिया-स्वरूप उपनिषद् के विचारों का जन्म हुआ। उपनिषद् का अथ गुप्त विद्या या रहस्य म है। यह विद्या सबमाधारण व लिए नहीं थी परन्तु गुप्त द्वारा देवता उन्हा को दी जाती थी जो कि इमक वाग्य समझ जात थे। उपनिषद् में कमवाण के ऊपर बोट महत्त्व नहीं दिया गया है। य मुन्यत दशन (philosophy) व अथ है। इतम मुन्य विचार यह है कि ब्रह्म ही चरम सत्य है। उपनिषद् की चरम शिक्षा है कि मैं ही ब्रह्म हूँ।

उपनिषद् व विचारों का साधारण जीवन म अविश्व प्रभाव रहा हुआ और कमवाण बढ़ता ही गया। नए-नए यज्ञ निरन्तर और उनका वरन भी नई विविधता पुरोहितों की निरन्तर। यज्ञ म दानदान बहुत होत लग। इम प्रकार बाह्याङ्ग पर अधिष्ठान और दिया गया। हिन्दू धर्म का तभी अवस्था देखकर इनमें सुधार के उद्देश्य ग जैन तथा बौद्ध धर्मों का जन्म हुआ। (इनका वरन बाद का दिया गया है)। इन दो नए धर्मों के प्रभावस्वरूप हिन्दू धर्म म कई परिवर्तन हुए। य इम कारण भी किए गए ताकि लोग पुराने धर्म का विलुप्त हो छाड़ न दें। इसीलिए हिन्दू धर्म म नए देवताओं की गृष्टि की गई—शिव विष्णु तथा देवी। इन तीनों व अनुयायियों ने अलग अलग मत चलाए। परन्तु इमक साथ ही साथ यह नती 'भूलन' चाहिये कि य सब नए मत हिन्दू धर्म की शाखा मात्र है। यों व स्थान म भक्ति की महिमा बढ़ने लगी। स्वयं प्राणि का माधन इन देवी देवताओं की प्रसन्नता हो गई।

हिन्दू धर्म की दो विशेषतायें हैं एक तो यह कि कोई एक व्यक्ति इस धर्म का सम्यक् नहीं कहा जा सकता है तथा दूसरे प्रत्येक हिन्दू एक ही मिश्रान्त

का माने पर अन्वय नहीं है। परन्तु कुछ गेनी माने हैं जिनकी प्रत्येक हिन्दू मानता है—वेदा की श्रेष्ठता, आत्मा की अमरता ईश्वर की सत्ता तथा ब्रह्मवाद में विश्वास। इनके साथ साथ सभी हिन्दू पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। एक विशेष देवता का भक्त होने हुए भी वे अन्य देवताओं का प्रति श्रद्धा रखते हैं। वे यह भी मानते हैं कि सब देवी-देवता एक ही परम-शक्ति के विभिन्न रूप हैं।

**जैन धर्म**—यह वैदिक धर्म की एक शाखा नहीं है। मानव उत्तर वैदिक-काल में इसका आरम्भ हुआ। परन्तु ई० पू० छठी शताब्दी में महावीर द्वारा इसकी पुनर्जीवित किया गया। महावीर जैनो के सादि गुरु नहीं हैं। वे चौबीसवें तीर्थंकर माने जाते हैं। महावीर का जन्म करीबन ५४० ई० पू० में हुआ था और उनकी मृत्यु करीबन ४८८ ई० पू० में हुई। उनका जन्म राजपराने में हुआ था परन्तु उन्होंने करीबन तीस वर्ष की आयु में सब कुछ त्याग दिया तरह-वर्ष की तपस्या के पश्चात् उनको मान प्राप्त हुआ और वे 'जिन' हो गए। इनका धर्म आत्म-विज्ञान में है। इसी में जैन धर्म निबन्धा है। जैन धर्म का भारत के बाहर किसी भी देशों में प्रचार नहीं हुआ और भारत में भी यह काले बौद्ध धर्म की तरह लोक-प्रिय नहीं हुआ। कालान्तर में जैनियों के दो भाग हो गए—श्वेताम्बर तथा दिगम्बर। श्वेताम्बरों के माधु केन्द्र श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। उनकी मूर्तियाँ भी सफेद बस्त्रों में ढँकी रहती हैं परन्तु दिगम्बर जैनियों के माधु वस्त्र हीन रहते हैं, क्योंकि उनका यह विश्वास है कि किसी भी वस्तु का अपने पान होना निषेध-प्राप्ति के मार्ग में बाधक है।

जैन धर्म जीव (spirit) तथा अजीव (matter) में विश्वास करता है। परन्तु इसका हिन्दुओं की तरह ईश्वर में विश्वास नहीं है। जीव शाश्वत है। यह पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है और इनके साथ-साथ ब्रह्मवाद की भी मानता है। जीव की धारण करने वाली के अनुसार अच्छे या बुरे फल भोगने पड़ते हैं। जैन धर्म अहिंसा पर बहुत अधिक जोर देता है। छोटे से छोटे जीव की हानि भी महापाप<sup>1</sup>। जैनियों के अनुमान नगर में किसी बात का भी लगाव नहीं होना चाहिये। अगर जीवन का चरम उत्प्रेत्य प्राप्त करना है तो

1. "Its chief doctrine is that there are souls in every particle of earth, air, water and fire, as well as in man, animals and plants; and its first ethical precept is "Do not destroy life."

Encyclopaedia—Modern Religious Movements in India, p. 321.

सैराग्य का रास्ता अपनाना चाहिये। केवल दृष्टी मार्ग में आत्मा को वैवल्यज्ञान की प्राप्ति होगी। यह वह अवस्था है जब आत्मा प्रत्येक दृष्टि में पूरा हो जाती है। इस अवस्था का निर्वाण कहा गया है। इसके लिये तीन चीजें आवश्यक बतलाई गई हैं—सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान तथा सम्यक् चरित्र। सम्यक् दर्शन आत्यय रूप धर्म की शिक्षाओं में पण विद्वांस में है। सम्यक् ज्ञान का अर्थ ग्रीक ज्ञान में है और सम्यक् चरित्र का अर्थ महाचार में है। इन तीनों को विरक्त कहा जाता है। इनके पालन करने में जीव' कर्म व बन्धना में नष्ट हो जावेगा और उनको निवाण की प्राप्ति होगी।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन धर्म न वेदा का मानता है, न इसमें यज्ञ व लिये स्थान है और न यह हिन्दू समाज की वर्ण-व्यवस्था का ही मानता है। प्रसी तब भाग्यवर्ष में बड़ी लाम इस धर्म का मानन है परन्तु उनकी मर्यादा प्रतिक नहीं है।

**बौद्ध-धर्म** —इस धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उनका जन्म कपिल-रस्तु में ई० पू० ५६३ में हुआ था। उनका जन्म भी राजघराने में हुआ था १६ वर्ष की आयु में उनका विवाह एक सुन्दरी राजकुमारी के साथ कर दिया गया। इसमें उनके एक पुत्र भी हुआ। परन्तु गौतम ससार में विरक्त हो गए और एक दिन उन्होंने चुपचाप रात को गृहत्याग कर दिया। पहले उन्होंने जंगल में जाकर घोर तपस्या की। परन्तु इससे शरीर के प्रभक्त हो जाने के प्रतिरिक्त और कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने इस प्रकार की शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या का छोड़ कर ध्यान का मार्ग अपनाया और इस बार इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध हो गए। बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार प्रारम्भ किया। उनकी शिक्षा भी कमकाण्ड के विरुद्ध है। बुद्ध का धर्म बहुत सरल था। उन्होंने नैतिकता पर विशेष जोर दिया। उनके बहुत से अनुयायी हो गए। उनके जीवन का में ही उनके धर्म का बहुत विस्तार हुआ। बुद्ध का तो यह भारत के बाहर कई देशों में फैला। चीन, तिब्बत, जापान, लावा, बर्मा तथा मध्य एशिया में यह धर्म फैला। भारत के अन्दर भी इसका सूब प्रचार हुआ। बुद्ध की महाधीर की तरह वर्ण-व्यवस्था में विद्वांस नहीं करते थे। उनकी शिक्षा बना किसी भेद भाव के सत्ता के लिये थी। यथार्थ में जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म सुधार-आन्दोलन थे। उस समय हिन्दू धर्म में कई बुराईयाँ आ गई थी और वे बुराईयाँ को दूर करने के लिये ही ये दो धर्म चले थे। उस समय यज्ञों में बहुत अधिक बलिदान की प्रथा चल गई थी। इन दोनों धर्मों ने इसका निरोध किया और ब्राह्मणों को परम धर्म बनलाया।

बुद्ध ने ध्यान द्वारा चार मुख्य मत्स्यों का ज्ञान प्राप्त किया और जनसाधारण के हितार्थ इनका ही उपदेश लोगों को दिया। वे निम्नलिखित हैं—

(१) जीवन दुःखमय है।

(२) इन दुःख का कारण अविद्या है।

(३) यह दुःख दूर किया जा सकता है। क्योंकि अगर इनके कारणों को नाश कर दिया जावे तो यह दुःख भी नष्ट हो जावेगा। निर्वोण के लिये जन्म तथा मृत्यु के चक्र में छुटकारा पाना चाहिये।

(४) दुःख को हटाने का उपाय सम्यक् ज्ञान (प्रज्ञा) प्राप्त करना है।

बुद्ध की शिक्षाओं में सदाचार को प्रमुख बतलाया गया है। इसकी प्राप्ति के लिये शरीर को बलेग या दुःख नहीं देना चाहिये परन्तु बुद्ध ने दुःख दूर करने के लिये आठ बातें बतलाई हैं। इनको अष्ट-मार्ग (Eightfold path) कहते हैं। ये आठ बातें निम्नलिखित हैं: सौल या सदाचार, प्रज्ञा या सम्यक् ज्ञान, समाधि या सम्यक् ध्यान, सम्यक् वाक्, सम्यक् आजीविका, सम्यक् प्रदान, सम्यक् विचार तथा सम्यक् विद्वान्।<sup>१</sup>

बुद्ध का देहान्त ई० पू० ४८३ में ८० वर्ष की अवस्था में कुशीनारा नामक स्थान में हुआ।

कालान्तर में बौद्ध धर्म कई सम्प्रदायों में बँट गया। इनमें से प्रमुख हीनयान तथा महायान हैं। इन दो मत्स्यों के ठीक अर्थ के विषय में मन्देह है। शान्त हीनयान से सात्वत नीचा और महायान से उच्च का होगा। हीनयान वर्ग के अनुयायी बुद्ध को न ईश्वर का अवतार मानते हैं और न उनकी पूजा करते। वे बुद्ध को एक मनुष्य मानते हैं जिनमें कई दैवी गुण थे। परन्तु महायान वर्ग वाले बुद्ध की पूजा करते हैं और उन्हें ईश्वर मानते हैं। इस पूजा के फलस्वरूप वे सोचते हैं कि निर्वाण की प्राप्ति होगी। महायान के ऊपर हिन्दू धर्म का प्रभाव अत्यन्त है। एक विद्वान् के अनुसार इनमें भक्ति के मार्ग का प्रभाव दृष्टिगोचर है।

इस्लाम धर्म:—भारत के मुसलमानों का धर्म इस्लाम कहलाता है। यह धर्म भारत में पैदा नहीं हुआ परन्तु बाहर से भारत में आया। इसकी स्थापना अरबों हजरत पैगम्बर द्वारा की गई थी। पैगम्बर का नाम मोहम्मद

१. सुविधा के लिए इनका अंगरेजी अनुवाद यह है: Right conduct, right knowledge, right concentration, right speech, right livelihood, right effort, right mindfulness, right resolve.

था। उनका जन्म ५७० ई० में हुआ था। उनका देहान्त ६३२ ई० में हुआ। छाटी उम्र से ही मोहम्मद माह्व की एकान्त में रहने और साधन की आदत थी। वह अपनी माधिया में बहने थे मनष्य कबल खल्ल-बूद में समय नष्ट करने लिये नहीं परन्तु अथ उच्च बातों के लिए बनाया गया है।<sup>१</sup>

इस समय अरब में सब तथा शांति का नाम न था। अरब की जनसंख्या कई कबीलों (Tribes) में विभाजित थी। ये आपस में लड़ते रहते थे। इन बड़ाइया में जो लोग पकड़ जाते थे उनको दास बना लिया जाता था। जीरता की अवस्था भी अच्छी नहीं थी। लड़कियाँ को मार डालने का रिवाज था। शराब पीने का रिवाज खूब प्रचलित था। अरब इस समय मूर्ति-पूजक थे। प्रत्येक कबीले के अलग अलग देवता थे। इनकी कल सख्या कई हजार होगी। अरब के कुछ भागों में यहूदी धर्म तथा ईसाई धर्म प्रचलित थे। इन दो धर्मों के आयायी भी आपस में लड़ते थे और एक दूसरे को नष्ट करने की मत्तन चेष्टा में रहते थे। संक्षेप में कहा जा सकता है कि मोहम्मद माह्व ने देखा कि उनके शत्रुवासी अधर्माचार में डूबे हैं उनमें न एकता और न मान और इसलिए वह सब शांति में भी बर्चित है। उनका उद्देश्य इन बड़ाइया को दूर करना था।

पैगम्बर की शिक्षाओं में तीन मुख्य महत्वपूर्ण हैं। उनका हर्म इस्लाम धर्म का निचाड कह सकते हैं। ये निम्नलिखित हैं —

(१) ईश्वर एक है। कुरान में लिखा है उस अल्लाह के नाम में जा रहमान (मैं की मी मुहब्बत में भरा हुआ) और रहोम (दयावान) है कह दो कि अल्लाह एक है और सब कुछ उसी अल्लाह के सहारे है न वह खुद कभी जन्म गता है और न किसी का जनता है कोई उस-जसा नहीं है। वह आप ही अपनी मिमाल है। कुरान में बार बार कहा गया है एक के अतिरिक्त दूसरा खुदा नहीं है।

(२) कुरान में दूसरा मुख्य विचार यह पाया जाता है कि सब आदमा एक है। पैगम्बर ने इस बात पर विचार जोर दिया कि आदिमिया में किसी भी प्रकार का भेद भाव नहीं होना चाहिए। अमीर गरीब स्वामी दास ऊँच नीच में सब भेद भाव निरर्थक है। आन्धी बड़ा छोटा इस प्रकार नहीं होता है। वर न भवता बराबर बनाया है। बड़ा वह है जो कि अच्छे काम करता

हैं। कुरान में कहा गया कि, "यद्यपि मैं तुम सब व्यक्ति एक ही उम्मत (Community) हूँ, मैं तुम सब का पालने वाला हूँ, तुम सब मेरी ही पूजा करो।"

(३) कुरान में इस बात पर भी बार-बार जोर दिया गया है—मत्तार में सब धर्मों के प्रति आदर करो क्योंकि सब धर्म सच्चे हैं। इसलिए कुरान में कहा गया है कि "हमने सगार के सब उम्मतों (Communities) में समुल भेजा जिसका उपदेश यही था कि ईश्वर की पूजा करो और बुराई से बर्षो।"

ऐगम्बर ने अपनी शिक्षाओं के द्वारा अरबों को सम्य बनाने तथा उनमें ज्ञान का प्रचार करने की चेष्टा की। उनकी शिक्षाएँ लोगों के हृदय में धर कर गईं और बहुत धीघ्रता से इनका प्रचार होने लगा। थोड़े ही समय में समस्त अरबवासी इस नये धर्म के अनुयायी हो गए। अरब में यह धर्म दूसरे देशों में फैला। इनके अनुयायियों ने अपना धर्म तलवार के बल पर फैलाया। भारत में भी इसका आगमन मुसलमान आक्रमणकारियों के साथ हुआ।

इस्लाम के अनुसार प्रत्येक मुसलमान को नीचे लिखे कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक मुसलमान को प्रतिदिन कलमा पढ़ना चाहिए। कलमा यह है—'ईश्वर एक है और मोहम्मद उसका रसूल है।' मुसलमान प्रति दिन पाँच बार नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज पढ़ते समय मुसलमान अपनी मुह्र भक्के की ओर करने है। जीवन में एक बार कम से कम प्रत्येक मुसलमान को हज करना चाहिए अर्थात् भक्के की तीर्थयात्रा करनी चाहिए। प्रत्येक मुसलमान को अपनी आमदनी का एक हिस्सा दान में देना चाहिए। रमजान के गहीने भर मुसलमानों की रोजा रखना चाहिए।

इन कर्तव्यों की मूची देखने में स्पष्ट हो गया होगा कि मोहम्मद नाहब का उद्देश्य अपने देशवासियों का बुराई से उधार करना था। इसमें वे बहुत मात्रा तक सफल रहे। अरबों ने मूर्ति-पूजा को त्याग कर एक ईश्वर की प्रार्थना आरम्भ की। उनके फलस्वरूप उनमें एकता बढी। इसी एकता तथा सगठन के कारण अरब वाले हमारे देशों को विजय तथा इस्लाम का प्रचार कर सके।

मुसलमानों में ऐगम्बर की मृत्यु के कुछ काज बाद दो सम्प्रदाय हो गए—शिया तथा सन्नी। शिया मुसलमानों की मख्या मन्त्रियों की अपेक्षा बहुत कम

हैं। शिया केवल कुरान को मानते हैं तथा पैगम्बर के बाद उनके दामाद अली को ही (जो कि चौथा खलीफा था,) खलीफा पद का न्यायपूर्ण अधिकारी मानते हैं। सुन्नी कुरान के अतिरिक्त इस्लाम की पुरानी प्रथाओं (सुन्नत) को भी मानते हैं तथा पैगम्बर के बाद अबूबक, उमर तथा उसमान को भी खलीफा पद का न्यायपूर्ण अधिकारी मानते हैं। शिया इन तीनों को खलीफा नहीं मानते हैं। शिया हसन के शहीद होने की स्मृति में मोहर्रम मनाते हैं तथा ताजिये निकालते हैं।

मुसलमानों का ही एक सम्प्रदाय सूफी कहलाता है। सूफी सम्प्रदाय भक्तिमार्गी है। इसमें तथा हिन्दू अष्टवैदान्त में काफी साम्य है। सूफी भी एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। वे अवतारवाद तथा पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं। ईश्वर तक पहुँचने का रास्ता प्रेम का है। भारत में कई प्रसिद्ध सूफी हुए हैं।

**सिख धर्म**—इस धर्म के प्रवक्ता गुरु नानक थे। वे पंजाब के रहने वाले थे। उनका जन्म सन् १४६९ में हुआ और उनकी मृत्यु सन् १५३८ में हुई। गुरु नानक का उद्देश्य हिन्दू धर्म में जो बहुत सारे आडम्बर तथा झूठी प्रथाएँ सम्मिलित हो गई थी उनका दूर करना था। उनकी शिक्षाओं का उद्देश्य हिन्दुओं के धर्म में सुधार करना था। इस दृष्टि से सिख धर्म हिन्दू धर्म की ही एक शाखा कहला सकता है।

गुरु नानक, कबीर अन्य भक्तिमार्गी साधुओं की शिक्षा से प्रभावित हुए थे। उनकी शिक्षाओं में वेदान्त तथा मुसलमानी धर्म का भी प्रभाव परिलक्षित होता है। उनकी शिक्षा यह थी कि ईश्वर एक है। इस ईश्वर तक पहुँचने का माय तीर्थयात्रा गंगा-स्नान आदि न बतलाकर उन्होंने चित्त की शुद्धि पर जोर दिया। मूर्ति-पूजा के भी वे विरोधी थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर के नाम का जाप करना चाहिए। यह नाम 'थी सत' है। ईश्वर उनके अनुसार सर्वव्याप्त तथा सर्वशक्तिशाली है। वह दयालु भी है। मर उसकी दृष्टि में समान हैं। इस कारण सिख धर्म जाति-पाति में विश्वास नहीं करता है।

नानक ने यह भी कहा कि सब धर्मों के तथा उनके महात्माओं के प्रति आदर करना चाहिए। गुरु नानक ने इस बात पर भी जोर दिया कि बिना ईश्वर के ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सिख धर्म में गुरु की महिमा है। सिख कर्मवाद तथा तथा पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं।



गुरु नानक के बाद सिक्खों के नौ गुरु और हुए। मिकखों के पांचवें गुरु ने गुरु नानक तथा कई अन्य महात्माओं के धार्मिक पद्यों का संग्रह एक पुस्तक के रूप में कर दिया। यह 'आदि-ग्रन्थ' कहलाता है। गुरु गोविन्द सिंह ने इसमें कई और बातों का समावेश किया। यह नई पुस्तक 'ग्रन्थ साहिब' कहलाती है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके मरने के पश्चात् कोई अन्य गुरु की नियुक्त न की जावे तथा सिक्ख 'ग्रन्थ-साहिब' को ही अपना गुरु मानें। इसी कारण उनके पश्चात् कोई अन्य गुरु नहीं हुए।

गुरु गोविन्द सिंह ने मुगल सम्राट् औरंगजेब से अपने धर्मानुयायियों की रक्षा करने के लिए उन्हें एक सेना के रूप में संगठित कर दिया। यह खालसा सम्प्रदाय कहलाया। इस सम्प्रदाय के प्रत्येक सदस्य का उद्देश्य धर्म के रक्षार्थ प्राणों को उत्सर्ग कर देना तथा प्रत्येक अन्य सदस्य को अपना भाई समझना था। इस प्रकार गुरु गोविन्दसिंह ने सिक्ख धर्म की रक्षा की। प्रत्येक खालसा सिक्ख पांच बिन्दुओं को धारण करता है, जो कि गुरु गोविन्दसिंह द्वारा नियत कर दिए गये थे—केश, कंघा, कृपाण कच्छ तथा कड़ा।

**ईसाई धर्म:**—इसके प्रवर्तक ईसा मसीह थे। उनका जन्म जेरुसलम में हुआ था। उस समय जेरुसलम रोमन साम्राज्य के अन्तर्गत था। ईसा के विचार शासक-वर्ग द्वारा ठीक नहीं समझे गए और ईसा को उन्होंने मूली पर चढ़ा दिया। पर धीरे-धीरे उनके विचार फैलने लगे। कालान्तर में रोम के सम्राट् ने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का धर्म बना दिया। इसके फल-स्वरूप ईसाई-धर्म बहुत तीव्रता से योरोप में फैलने लगा। योरोप में यह अन्य देशों में भी जहाँ-जहाँ यूरोपीय पहुँचि, फैला। आज यह समार के प्रमुख धर्मों में से एक है। समार के प्रत्येक देश में इस धर्म के अनुयायी थोड़ी-बहुत संख्या में प्रत्यक्ष ही मिल जावेंगे।

ईसा का धर्म प्रेम का धर्म है। उन्होंने यह सिखलाया कि सब जीवों के प्रति प्रेम का व्यवहार करो। उनका विचार था कि सब प्राणों परमात्मा की सन्तान हैं। उनका उद्देश्य मनुष्य समाज का नैतिक उत्थान करना था। उन्होंने कहा कि विनयशील व्यक्ति ही अन्त में समार के स्वामी होंगे (The meek will possess the land)। उनके अनुसार ईश्वर केवल मनुष्यों का राजा नहीं है परन्तु वह उनका पिता है। ईश्वर को प्रसन्न करने का उपाय यह है कि दोन-दुनियाँ की गहायता करो।

ईसा की शिक्षाएँ विनयेत, नैतिक हैं। इनमें चार मुख्य सिद्धान्त हैं। पहला सिद्धान्त प्रेम है। ईसा ने कहा कि अपने पड़ोसी के प्रति प्रेम रखो।

पडासी में उनका अथ मानव मात्र में था। उनका दूसरा मित्रान्त्र मत्त्व है। हम कारण उद्धान झूठी गवाही देना लागे को छाना तथा हम प्रकार के अथ यामा की अथन्त्र निन्दा की है। नीमरा मित्रान्त्र विनयशीलता है। मनुष्या को विभी भी प्रचार का गव नहा होना चाहिए। ईसा स्वयं ही विनयशीलता की नेति थ। विनयी व्यक्ति के लिए स्वयं ने द्वार खुले हैं। चौथा मित्रान्त्र यह है कि मनुष्य में वृद्धिमत्ता होनी चाहिए।

दूसरा ममोह भी मुखारब्ध थ। उद्धाने अथनी गि राजा के द्वारा यहूदी समाज में जो प्रचलित राइया थी उनको दूर करने की भ्रष्टा की। उन्हान यह कहा कि निधना के निध स्वयं में म्यान है। धनो वहाँ कोई स्वान नहीं पावग। चाहे एन उँन मुई के छद में मे निवन्त्र जा। परन्तु एक धनी स्वयं के द्वार में मे नहा घुग मरना है।

भारत में कहा जाता है कि गवप्रथम हम धर्म का प्रचार मन्त्र टामस ने किया था। चौथी शताब्दी में मीरिया के कुछ ईसाई भाग कर यहाँ आए थे और कारामण्डल तट में बस गए। अभी तक उनकी मतानें यहीं रहती है। ईसाई धर्म का प्रचार १६वीं शताब्दी से हुआ जब कि पुनगालवासिया न यहाँ अपना धर्म फैलाना आरम्भ किया। विगपकर निम्न वय के लोग हम धर्म की ओर आकर्षित हुए। बाद का कुछ उच्च वय के लोग भी ईसाई हो गए। ईसाइया न भारत में अँग्रेजी शिक्षा के प्रचार में अच्छा काम किया है। उद्धाने समाज के निम्नवर्गों तथा आदिवासिया की दशा मरारन का भी प्रयत्न किया।

**पारसी धर्म** — भारत में कुछ लोग हम धर्म के भी मनुष्यायी है। इनको पारसी कहते हैं। ये लोग अधिकतर बम्बई तथा गुजरात में हैं। पारसी सम्प्रदाय बड़ा उन्नतिशील है। यह पाश्चात्य शिक्षा तथा मम्यता में बहुत अधिक प्रभावित है। पारसी नाम पारस में भारत में आया। हमका कारण यह था कि जब पारस अरबों द्वारा जीत लिया गया तथा वहाँ विजिताआ न इस्लाम धर्म फैलाया ना जित लागे न हम नग धर्म का स्वीकार नहीं किया उनमें में बहुत में पारस में दूसरे देशों का भाग। भारतीय पारसों पारस व पुरान धर्म का अनुयायी है।

पारस व पुरान धर्म के प्रवक्ता का नाम जोरोआस्टर (Zoroaster) था। इसी धार्मिक पुस्तक का नाम जन्द अवेस्ता है। पारसी लोग का मन्त्र में बड़ा नेवता अहुरमज्द कहलाता है। हमका अथ महान देवता है।

इस धर्म के अनुयायियों को अग्निपूजक (fire worshipper) भी कहते हैं। क्योंकि अग्नि या सूर्य अहुर-मन्द के ही रूप हैं। पारसी भी आत्मा को अमरता पर विश्वास करने हैं। इस धर्म में तथा हिन्दू धर्म में कई बातों में समानता है।

**धार्मिक सुधार-आन्दोलन** — उन्नीसवीं शताब्दी में भारत में कई धार्मिक सुधार-आन्दोलन चले। इन आन्दोलनों का उद्देश्य धर्म के नाम में जो कुरीतियाँ पैदा हो गई थी, उनको दूर करना था। हम यहाँ पर केवल हिन्दू धर्म तथा इस्लाम में सम्बन्धित सुधार-आन्दोलनों का वर्णन करेंगे।

प्रत्येक धर्म में कालान्तर में कई बुराईयाँ पैदा हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि समय तथा परिस्थिति के परिवर्तन के साथ-साथ धर्म में परिवर्तन नहीं होता है। धर्म मुख्यतः एक अनुदार शक्ति (Conservative force) है। भारतीय धर्मों में भी, विशेषतः हिन्दू-धर्म में, इस प्रकार की अनेक बुराईयाँ भर गई थी और लोग इन्हीं को यथाथे धर्म माने हुए थे जैसे, स्त्री-प्रथा, वर्ण व्यवस्था, बच्चों की हत्या करना इत्यादि। जब विदेशी-शासन के स्थापित होने के फलस्वरूप ईसाइयों ने अपने धर्म का प्रचार करना आरम्भ किया तो उन्होंने हिन्दू-समाज की इन बुराईयों की ओर ध्यान देकर यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि भारतीय-धर्म असम्भव है। इस समय भारतीय नवयुवकों में अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित वर्ग पाश्चात्य दर्शन तथा सम्प्रदाय में अत्यन्त प्रभावित हो गया और उन अपने देश के माहिद्वय, दर्शन, धर्म में केवल अंधकार के और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। जब देश की ऐसी अवस्था थी उन समय इन धार्मिक सुधार-आन्दोलनों का प्रारम्भ हुआ। ये आन्दोलन हमारी राष्ट्रीय जागृति के प्रथम फल हैं। धर्म के रूप में हमारी राष्ट्रीय चेतना सर्वप्रथम प्रस्फुटित हुई। हमारे समाज के ऊपर पाश्चात्य गन्धता का प्रभाव इन धार्मिक आन्दोलनों का मुख्य-कारण है।

इन सब धार्मिक आन्दोलनों का उद्देश्य हिन्दू समाज में प्रचलित बुराईयों को हटाना था। वे जाति-पाँति के विरुद्ध थे तथा छुआछूत में विश्वास नहीं करते। सब अनुसूचित एक ही ईश्वर की सन्तान हैं, इसलिए सब भाई-भाई हैं। इन सब आन्दोलनों ने मूर्ति-पूजा का भी विरोध किया और निराश्रय ब्रह्म की उपासना की शिक्षा दी। इनके अनुसार सब धर्मों में कुछ सत्य का अंश है। अतएव इतको ग्रहण कर लेना चाहिए। इन धार्मिक आन्दोलनों ने हिन्दुओं के प्राचीन धर्म-ग्रन्थों—वेद तथा उपनिषदों से प्रेरणा ली। ये आन्दोलन धार्मिक

तथा सामाजिक उद्देश्य को लेकर चले और इसके माध्यम से देश की राज-  
राजनैतिक जागृति में भी उनका महत्वपूर्ण हाथ रहा है।

**ब्रह्म समाज** —उन्नीसवीं शताब्दी के धार्मिक आन्दोलन में, ब्रह्म समाज का सबसे मुख्य स्थान है। इस आन्दोलन के प्रवर्तक राजा राममोहन राय (१७७२-१८३३ ई०) थे। राजा राममोहन हिन्दू धर्म में उन सब ऋद्धियों तथा कुरीतियों का दूर करना चाहते थे जो कि कालान्तर में धर्म में धर कर गई थी। वे ईसाई धर्म से भी कुछ सीमा तक प्रभावित हुये थे। उनका जन्म एक धार्मिक परिवार में हुआ था। उनके पिता वैष्णव तथा माता शाक्त थी। १० वर्ष की अवस्था में वे अध्ययन के लिए पटना भेजे गये। वहाँ वे मकी धर्म से प्रत्यन्त प्रभावित हुए। कुछ काम पढ़ाया बनागम में उन्होंने सम्पूर्ण का अध्ययन किया तथा १७१६ में ग्रेगोरी पटना प्रारम्भ किया। उन्होंने इस काल में ही विविध पर्यों का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। मन् १८०५ में उन्होंने ईस्ट इण्डिया कम्पनी में नौकरी कर ली और १८१४ तक वे इसमें रहे। यहाँ में व्यवसाय ग्रहण करने पर उन्होंने अपने धार्मिक विरक्तियों का प्रचार करना प्रारम्भ किया।

राजा राममोहन राय केवल धार्मिक मुद्धार ही नहीं चाहते थे पण्डु के समाज-सुधार भी करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सभी प्रकार की सामा-  
जिक कुरीतियों का विरोध किया। इस प्रकार वे वेद होने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। धर्म के मामले में वे हिन्दू धर्म के प्राचीन धर्म को पुनर्न्यपित करना चाहते थे। इसलिये वे उन ग्रन्थ-विज्ञानों के शत्रु थे जो कि हिन्दू-धर्म में प्रवेश कर गये थे। वे बहु-विवाह के भी विरोधी थे।

मन् १८०८ में उन्होंने कुछ मित्रों के साथ एक सङ्गठन की स्थापना की जो कि 'ब्रह्म समाज' कहलाया। इसकी प्रति शनिवार को संध्याकाल में ७ से ९ तक बैठक होती थी, जिसमें कि भगवान की प्रार्थना की जाती है। जनवरी मन् १८१० में समाज के लिए प्रथम मन्दिर की स्थापना की गई। वर्षावर् १८१० में राम-  
मोहन बिलासत को खाना हुये और वही मन् १८३३ में उनका देहान्त हो गया। वे केवल धार्मिक मुद्धारक ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने समाज तथा शिक्षा की उन्नति के लिए भी बड़ा ही महत्वपूर्ण काम किया है।<sup>१</sup>

१ "Ram Mohan Roy is the pioneer of all living advance, religious, social and educational in the Hindu community during the century."

सन् १८४२ में श्री देवेन्द्र नाथ टैगोर (श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर के पिता) ब्रह्म-समाज के सदस्य हो गये। वे अपनी मृत्यु-पर्यन्त इसके प्रचार के लिए प्रयत्नशील रहे। वे भी उस प्राचीन हिन्दू-धर्म को जो कि उपनिषदों में मिलता है पुनः स्थापित करना चाहते थे। परन्तु वे राजा राममोहन की तरह ईसाई-धर्म में प्रभावित नहीं हुये थे। कुछ वर्षों बाद सन् १८५३ में श्री केदावचन्द्र सेन ब्रह्म-समाज में सम्मिलित हुये। आरम्भ में श्री देवेन्द्रनाथ तथा उनमें बहुत मेल रहा परन्तु बाद को उनमें मतभेद हो गया। इसके कारण यह था कि श्री केदावचन्द्र सेन ईसाई धर्म में बहुत ही अधिक मात्रा तक प्रभावित थे। उन्होंने एक ब्रह्म समाज का संगठन किया जो कि भारतीय ब्रह्म-समाज कहलाया (सन् १८६६)। कुछ वर्षों के पश्चात् इसमें भी दो दल हो गये। एक तो केदावचन्द्र के अनुयायी तथा दूसरे उनके विरोधी। सन् १८७८ में उनके विरोधियों ने एक नया संगठन स्थापित किया जो कि भाषारण ब्रह्म समाज कहलाया। इस प्रकार ब्रह्म समाज की तीन शाखाएँ हो गईं।

ब्रह्म समाजियों के अनुसार केवल एक ईश्वर है। उनों ने इन गूटि की रचना की है तथा वही इसका संरक्षक है। वह प्रीति, शक्तिशाली तथा सर्व-व्यापक है। बिना ईश्वर की कृपा के मोक्ष संभव नहीं है। उनकी उपासना प्रेम तथा मत्स्य में होनी चाहिए। आध्यात्मिक उन्नति के लिये प्रार्थना करना चाहिए। ईश्वर परम पिता है। सब मनुष्य आपस में भाई-भाई है। ईश्वर पुण्यात्माओं तथा पापियों को उनके कर्मों के अनुसार पत्र देता है। आत्मा अमर है और अपने कर्मों के लिये ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है। सब धर्मों में मत्स्य को ग्रहण करना चाहिए। ईश्वर मानकर किसी वस्तु आदि की पूजा नहीं करनी चाहिए।

**प्रार्थना समाज:**—ब्रह्म समाज के ही प्रभाव में सन् १८६७ में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख सदस्यों में श्री रामाडे, सर आर० जी० नरहरकर तथा नारायण चन्द्रावरकर थे। इस समाज के उद्देश्य जातिप्रथा का भन्त, विधवाओं का पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा की प्रोत्साहन तथा बाल-विवाह का बन्द करना था। धर्म के विषय में इसके तथा ब्रह्म-समाज के विचार मुख्यतः एक ही हैं।

**आर्य समाज:**—आर्य समाज आन्दोलन सन् १८७५ में बम्बई में आरम्भ हुआ परन्तु कुछ वर्षों के पश्चात् यह पंजाब और उत्तरप्रदेश में विशेष कर फैला। इसके प्रवर्तक दयानन्द भरस्वती थे। उनका जन्म सन् १८२४ में काठियावाड़ में धमीर ब्राह्मण घराने में हुआ था। उनका वास्तविक नाम

मूलशक्ति या। वचन स ही वे सम्भीर प्रवृत्ति के थे। १८४६ में वे धर्म भाग निकले। अपने धर्म में कई मातृ-मन्त्राभ्यास तथा यागिया के सम्भव म आये। उन्होंने मन्त्र का सम्भीर अध्ययन किया। दयानन्द के ऊपर अंग्रेजी सम्प्रदाय तथा ईसाई धर्म का प्रभाव विस्मृत नहीं पडा। वे अंग्रेजी भाषा में 'नमो' व। उनका उद्देश्य पुनर् हिन्दू धर्म का फिर म स्थापन था। हिन्दू-धर्म में जो दुर्गद्वारा था गई थी उसी के निवारण चाहत थे। उन्होंने अपना प्रचार-कार्य सन १८६६ म आरम्भ किया। अपने भाषणा में उन्होंने मूर्ति-पूजा का विरोध किया और ईश्वर के विरुद्ध बताया। वे अपने व्याख्याता में हिन्दी का प्रयोग करने थे न कि मन्त्र का। सन् १८७४ में उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'मत्स्याय प्रमाण' की रचना की। इसमें धर्म के ऊपर उनकी विचारों स्पष्टीत हैं तथा धर्म का आलोचनात्मक विवरण है। वे यह सिद्ध करना चाहत थे कि वैदिक धर्म ही मन्त्रोद्धार है। सन् १८७५ में धर्म म आधुनिक समाज की स्थापना हुई। दो वर्ष पश्चात लाहौर में इसकी स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त अन्य कई स्थानों में भी धर्म समाज मन्दिरों का स्थापना की गई।

श्री दयानन्द की शिक्षाओं के निम्नलिखित आधार हैं।

(अ) ईश्वर एक है और पूजा मूर्तियों के द्वारा नहीं हो सकती है।

(ब) वेदा म सब कुछ सत्य है व ईश्वर व ही शक्ति है।

(ग) वेद धर्म तथा आधुनिकता का सिद्धान्त सिद्ध करने है।

(द) धर्म समाजों नीचे लिखे धर्म नियमों म विद्वान् रहते हैं।

(१) ईश्वर ही ज्ञान का परम कारण है। आधुनिकता के अधुना से सुदृष्टता पाता ही मोक्ष है।

(२) ईश्वर मन्त्र-चित्-आनन्द है। इसका कोई अकार नहीं है। वह व्यापक तथा दयावान् है। सर्वव्याप्त तथा सर्वशक्तिशाली है। वह अजन्मा तथा अमर है। केवल उसी की उपासना करनी चाहिए।

(३) वेद सत्य विद्या के भण्डार हैं। प्रत्येक धर्म को इनका अध्ययन, मनन तथा प्रचार करना चाहिए।

(४) प्रत्येक व्यक्ति सत्य ग्रहण तथा अमत्य त्यागने को तत्पर रहे।

(५) प्रत्येक काम उचित अनुचित के विचार से करना चाहिये।

(६) समाज का उद्देश्य मानव-उन्नति की नैतिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति कर संसार का भला करना है।

(७) प्रत्येक के साथ उनके गुणों के अनुसार प्रेम तथा स्वातंत्र्य व्यवहार करना चाहिये।

(८) भविष्य का नाग तथा विद्या का प्रचार करना चाहिए।

(९) प्रत्येक को सर्वनाधारण की उन्नति में ही अपनी उन्नति देखनी चाहिए।

(१०) व्यक्तिगत मामलों में प्रत्येक मनुष्य को आचरण की स्वतंत्रता होनी चाहिए, परन्तु सामाजिक मलाई में सम्बन्धित विषयों में सब नेतों को भुला देना चाहिये।<sup>१</sup>

स्वामी दयानन्द द्वारा संस्थापित धर्म-समाज आन्दोलन न केवल धार्मिक आन्दोलन ही था अपितु यह एक सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक आन्दोलन भी था। इसने देश में एक मशीन चेतना पैमाने तथा हिन्दुओं की आत्म-सम्मान की भावना को जगृत किया। इसने यह दिखाया कि हिन्दू धर्म तथा संस्कृति अन्य धर्म तथा संस्कृतियों से उच्च है। धर्म-समाज ने अंग-व्यवस्था के विरुद्ध प्रचार किया और इस प्रकार हिन्दू-समाज की एकता को दृढ़ किया। स्वामी दयानन्द एक सुधारक तथा नेता थे। उनका उद्देश्य देश और समाज की नैतिकीय उन्नति करना था।<sup>२</sup> उनके शिष्यों ने उनके काम को जारी रखा। सन् १८८३ में स्वामी जी का देहान्त हुआ।

**थियोसोफिकल समाज :-** इस समाज की स्थापना पहले पहले न्यूयार्क में एक स्त्री महिला—मदाम ब्लेवान्सकी तथा एक अमेरिकन बनेल फाल्वाट द्वारा की गई थी (सन् १८७५)। सन् १८७९ में वे दोनों स्वामी दयानन्द द्वारा निर्मित किया जाने पर भारत आये। भारत में इन्होंने अपने विचारों का प्रचार किया। इन्होंने भारतीयों को बताया कि उनका धर्म उच्च कोटि का है तथा उनमें सत्य निहित है। परन्तु इनमें कई कुरीतियाँ भी गई हैं और इनको दूर करना चाहिये। सन् १८८२ में मद्रास प्रान्त में मद्रास नामक स्थान में इस समाज की स्थापना की गई। देश में इसी शीघ्रता से इनके विचार फैले तथा कई अन्य स्थानों में इसकी शाखाएँ खुलीं। सन् १८९६ ई० में

1. Farquhar, Modern Religious Movements in India, p. 114.

2. "Pandit Dayanand Saraswati was a man of large views. He was a dreamer of splendid dreams. He had a vision of

श्रमता गनायक मन्त्रा मन्त्र्य हो गए। उन्होंने इसके प्रचार में उन काम किया। व दायरलेख की निवासिनी या पत्नी भारत में आवर उन्होंने हिन्दू धर्म का स्वीकार कर लिया था। उन्होंने अपने भाषणा तथा सेवा द्वारा हिन्दू धर्म का समर्थन किया। इस धर्म में अन्तर का वरीनिष्ठा या गर्द या उनको भी उन्होंने उचित बताया। विद्वानोंपि इस समाज का हिन्दू धर्म के पुनर्दान में काफी योगदान। इसके अनिरिक्त उन्होंने दान प्रवर्द्धि गिरी-सम्पन्न स्थिति की। मत् १८०० में ली चीन में न कानी में गन्त हिन्दू वाग्न का स्थापना की। उन्होंने वहाँ इसका उद्देश्य हिन्दू धर्म को हिन्दू धर्म मिश्रणता द्वारा। यही वाद का यह वर हिन्दू विचारविचार है। यथा। सामाजिक समाज का जो भी इस समाज में हिन्दू धर्म का ध्यान आकर्षित किया। स्थिति का अधिवाग का भी समर्थन किया गया। जाति-भेद के अन्तर्गत में यह समाज का विकास नहीं है। सभी ईश्वर की भक्त हैं इसी धर्म का वरदान है जो सभी पर ईश्वर की समान कृपा है।

विद्वानोंकी वर यह धर्मों का श्रद्धा का दृष्टि में स्थित है। विनयत हिन्दू धर्म तथा बौद्ध धर्म का गन्धी विद्या का आचार मानत है। मन्त्र्य व्यवसायी का धर्म था कि तिब्बत में गन्त वाग्न वर महान माधुम्य के द्वारा उनका धर्म प्रविष्टि हुई है परन्तु यह निरिक्त नहीं है कि व सभी स्थिति भी गर्द थी। उनका कहना था कि तिब्बत में जो महाना है वे श्रम ह मया व हा मन्त्र का संचालन करत है। उन्होंने व्यवसायी का विनय रूप में अपनी गिरीय वनान को रीति। उनमें यह वा नाम महाना मारवा था। इसके अनिरिक्त यह महात्मा भी व। इनमें एक का नाम वनदूमा था।

विद्वानोंका यह क्या मन्त्र है मया यह धर्मस्थ है। हमारा हम निधन नहीं करना है। मन्त्र यह उद्देश्य स्वयं यह दिखाना है कि यह धर्मोद्धार के द्वारा रीति प्रकार हिन्दू धर्म में एक नई बनना का संचार हुआ और गिरीय हिन्दू

India purged of the superstitions filled with the fruits of science welcoming one God suited for self rule having a place in the sisterhood of nations and restored to her ancient glory. All this was to be accomplished by throwing overboard the accumulated superstitions of the centuries and returning to the pure and unperverted teachings of the Vedas

Dr. Griswold quoted in Social and Religious Movements, by Sri N. S. Chatterjee



वर्ग के अन्दर यह भावना बहुत मात्रा तक दूर हो गई जि उनका धर्म केवल अत्यविश्वासी का समझ है। विद्योगोपी ने यह निश्चिन्ता कि ईसाईयों द्वारा हिन्दू धर्म पर लगे गये आक्षेप निराधार तथा असत्य है।

**रामकृष्ण मिशन** — इस मिशन की स्थापना अपने घर के नाम में स्वामी विवेकानन्द द्वारा की गई थी। उन्होंने कलकत्ते के निकट बेनुर नामक स्थान में तथा अम्बोडे के पास मायावती में मठ भी स्थापित किये। इन मठों का नाम रामकृष्ण मिशन के लिये प्रचारक तैयार करना था।

स्वामी विवेकानन्द के गुरु का नाम श्री रामकृष्ण परमहंस था। परमहंस जी का जन्म २० फरवरी सन् १८३४ को बंगाल के हुगली जिले में हुआ था। वे जति के ब्राह्मण थे। उन्होंने बचपन में ही धार्मिक पुस्तकों तथा कृत्यों में प्रेम था। उनका वास्तविक नाम गदाधर चटर्जी था। उनको किसी प्रकार की शिक्षा नहीं मिली। भक्तएव न उनको अंगरेजी का ज्ञान था और न संस्कृत का। यहाँ तक कि वे साहित्यिक बंगला में भी अनभिज्ञ थे। वे अपने बड़े भाई के साथ एक मन्दिर में पुजारी का काम करने थे। उन्हें इस काम में बीच-बीच में समाधि प्राप्त हो जाती थी। क्योंकि वे अपने पुजारी-पद के कामों को ठीक प्रकार नहीं करते थे इसलिए उन्हें मन्दिर छोड़ देना पड़ा और वहाँ ही एक जंगल में रहने लगे। वहाँ उन्हें एक सन्यासिनी तथा बाद को एक सन्यासी ने निशि प्राप्त करने में सहायता दी। गदाधर चटर्जी सन्यासी हो गये और उनका नया नाम रामकृष्ण परमहंस पड़ा। परमहंस जी ने बाद को इम्दाम तथा ईसाई धर्म का परिचय प्राप्त किया। उनका यह विश्वास था कि सब धर्म सत्य हैं। वे एक ही लक्ष्य पर पहुँचने के लिए अलग-अलग मार्ग हैं।

परमहंस जी के अनुसार ईश्वर निराकार है तथा अनप्य के ज्ञान और पहुँच के परे है। परन्तु प्रत्येक वस्तु में ईश्वर वर्तमान है और जो कुछ संसार में होता है वह ईश्वर द्वारा ही किया जाता है। सब देवता एक ही ईश्वर के विविध रूप हैं।

परमहंस जी के शिष्यों में सबसे मुख्य स्वामी विवेकानन्द हुए। उनका वास्तविक नाम नरेन्द्र नाथ दत्त था। उनका जन्म ९ जनवरी १८२९ को हुआ था। पहले ये नास्तिक थे परन्तु परमहंस जी के संसर्ग में धार्मिक हुए। जब सन् १८८६ में रामकृष्ण परमहंस का देहान्त हुआ तो नरेन्द्र नाथ ने सन्यास धारण कर लिया। करीबन ६ वर्षों तक वे एकान्त में भारतीय धर्म तथा दर्शन का अध्ययन करते रहे। सन् १८९२ में उन्होंने दक्षिण भारत में अपने गुरु की शिष्याओं का प्रचार किया। सन् १८९३ में निकारा में जो

मध-धर्म सम्मेलन (Parliament of Religions) हुआ उसमें उन्होंने हिन्दू धर्म को व्याख्या की। उनका व्यक्तित्व तथा व्याख्यान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। किन्तु उन्होंने धर्मश्रद्धा में प्रचार कायं किया और वहाँ से रंगमंडल हाव हुए भारत लौट। भारत में उन्होंने रामकृष्ण मिशन का पुनर्गठित किया।

स्वामी विवेकानन्द की शिक्षा का निम्नलिखित चार भागों में रखा जा सकता है —

(१) प्रत्येक व्यक्ति का अपने ही धर्म में रहना चाहिए क्योंकि प्रत्येक धर्म सच्चा तथा अच्छा है।

(२) ईश्वर निराकार है। वह मनुष्य की बुद्धि से परे है। वह सर्व-व्यापक है। आत्मा ईश्वरीय है।

(३) क्योंकि हिन्दू सभ्यता सबसे प्राचीन तथा श्रेष्ठ धर्म में निस्सृत है अतएव यह सत्य है शिव है तथा सुन्दर है। हिन्दू राष्ट्र गमार् का शिक्षक रहा है तथा भविष्य में भी रहेगा।

(४) प्रत्येक हिन्दू का अपनी शक्ति भर अपने धर्म तथा सभ्यता की पाश्चात्य सभ्यता तथा विचारों में रक्षा करनी चाहिए। पाश्चात्य सभ्यता आध्यात्मिक न होकर भौतिक तथा स्वायत्त है। परन्तु हिन्दुओं का पाश्चात्य शिक्षा तथा काम करने के ढंग का अपनाना चाहिए। बिना इसके उनका उत्थान नहीं हो सकता है।

स्वामी विवेकानन्द ने हिन्दुओं का इस बात की बार-बार याद दिलाई कि उनका धर्म तथा सभ्यता उच्च काटि के है। उन्होंने हिन्दुओं में कहा तुम्हें अपने आध्यात्म तथा दर्शन से समार का विजय करना है।

रामकृष्ण मिशन ने समाज सुधार के मिलमिट में अच्छा काम किया है। इसने दीना तथा दुखिया की सहायता की है तथा बाल और अकाल के समय भी अच्छी सेवा करते हैं।

अन्य आन्दोलन — हिन्दू समाज में ऊपर वर्णित मुख्य आन्दोलनों के अतिरिक्त कुछ और आन्दोलन भी हुए परन्तु उनका क्षेत्र इतना व्यापक नहीं था। इन शेष आन्दोलनों में राधास्वामी सत्यग का नाम उल्लेखनीय है। इसकी स्थापना आगरा में श्री विवेकदाल ने मन् १८६१ में की थी।

उनका कहना था कि ईश्वर ने स्वयं उनको गुरु पद प्रदान किया है। राधा-स्वामियों के चौथे गुरु ने आगरा के पास दयालबाग बसाया तथा वहाँ कई उद्योग स्थापित किए। इस मत के मानने वाले गुरु को मन्ने पूज्य तथा ईश्वर-प्राप्ति का मार्ग समझते हैं। ये लोग जानि-पानि में भी दिव्याम नहीं करते हैं।

एक दूसरा आन्दोलन देव-भमाज है। इनकी स्थापना ५० शिवनागपुर, अग्निहोत्री द्वारा की गई थी। श्री अग्निहोत्री पहले ब्रह्म-भमाज में थे। उन्में अलग होने पर उन्होंने देव-भमाज की स्थापना की। अपने अन्तिम दिनों में ये नास्तिक हो गए थे। इसलिए देव-भमाज भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। उनका देहान्त मन् १९२९ में हुआ।

दक्षिण-भारत में कई लघु सुधार-आन्दोलन हुए। परन्तु उनका वर्णन यहाँ स्पष्ट है।

**मुस्लिम-सुधार आन्दोलन:**—इस्लाम में भी कई ऐसी बातें आ गई थी जो कि वास्तविक धर्म के प्रतिकूल थीं। इसका एक कारण तो यह था कि शिक्षा के मामले में मुसलमान बहुत पिछड़े हुए थे। अतएव धार्मिक कुरीतियाँ उनमें स्वभावतः ही धूम गईं। इनके गाय-भाप बहुत से हिन्दुओं ने इस्लाम-धर्म ग्रहण कर लिया था। धर्म परिवर्तन के बाद भी वे पूर्णतया हिन्दू-प्रभाव में मुक्त न हो सके। उन्होंने इस्लाम के मतों की पूजा आरम्भ कर दी। इस प्रकार इस्लाम में मूर्ति-पूजा होने लगी। धार्मिक कुरीतियों को दूर करने तथा मुसलमान सम्प्रदाय को सामाजिक उन्नति के लिए कुछ धार्मिक आन्दोलन हुए जो कि लाभ-माय सामाजिक भी थे। इनमें से प्रमुख आन्दोलनों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है।

(अ) बहायी आन्दोलन.—१८ वीं शताब्दी के अन्तिम काद में अरब में बहायी आन्दोलन आरम्भ हुआ। भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा। राय-खरेली के मयद अहमद खेलवी (१७८६-१८३१) इस आन्दोलन के नेता थे। उन्होंने देश-वात का प्रयत्न किया कि इस्लाम में जो बहुत भी कुरीतियाँ आ गई थी उनको निकाल दिया जाय। उनका काफ़ी प्रभाव फैला। बंगाल में इन आन्दोलन के फलस्वरूप बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लाम को स्वीकार किया। पंजाब में बहावियों ने मित्रों के विरुद्ध युद्ध किया। जब पंजाब को अंग्रेजों ने जीत लिया, तो उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। अंग्रेजी सरकार ने इस आन्दोलन को पूरी तरह दबाया। यह आन्दोलन साम्प्रदायिक था। इसका उद्देश्य मौलिक इस्लाम का प्रचार करना था।

(ब) अलीग आन्दोलन — यह आन्दोलन सैयद अहमद खा (१८१७-१८९८) के नाम से संयुक्त है। हर सैयद अपने महधर्मिया की दगा में सुधार करना चाहते थे। उन्होंने देखा कि मुसलमान शिक्षा की दृष्टि में बहुत पिछड़े हैं तथा पाश्चात्य शिक्षा का नहीं ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने उनको पाश्चात्य शिक्षा ग्रहण करने को उत्साहित किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन कालिज की स्थापना की। यह बाद को मुस्लिम विन्वविद्यालय हो गया। उनका विश्वास था कि अगर मुसलमान अंग्रेजी शिक्षा को अपनावेंगे तो उनकी सर्वांगीण उन्नति होगी। अपनी योरोपीय यात्रा के पलम्बरूप के पाश्चात्य मध्यता से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे।

सर सैयद अहमद का विचार था कि मुसलमानों को अंग्रेजों के साथ सहयोग में रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने पूरा प्रयत्न किया कि मुसलमान धर्म में अलग रहें। उन्होंने राजा जिव प्रसाद के साथ मिलकर पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की।

मुसलमानों की जागृति में सर सैयद अहमद ने महत्वपूर्ण काम किया। उन्हीं के प्रयत्न के पलम्बरूप मुसलमानों ने अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया।

(स) अहमदिया आन्दोलन — इसने संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद (१८३८-१९०८) थे। पंजाब के मुल्तासपुर जिले में कादियान गाँव में पैदा हुए थे। उनका कहना था कि वे ईसाइयों के मसीहा, मुसलमानों के मेहदी तथा हिन्दुओं के अन्तिम अवतार थे तथा ईश्वर के द्वारा तीनों धर्मों के पुनरुत्थान हेतु भेजे गए थे। लोभा ने उनकी शिक्षाओं को अधिक महत्व नहीं दिया। पंजाब में उनके अनुयायी थोड़ी गहरी में हैं। मिर्जा साहब अपने विचारों में प्रतिभ्यावादी थे।

गल्प में यह मुख्य-मुख्य धार्मिक आन्दोलनों का वर्णन है। इन आन्दोलनों ने हिन्दू तथा मुसलमान समाजों पर बहुत प्रभाव डाला। इस कारण इनका काफी महत्व है।

### प्रश्न

(१) धर्म का नागरिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? भारतीय दगाओं को विशेष रूप से ध्यान में रख कर इस विषय पर विवेचन कीजिए।

(यू० पी० बोर्ड, १९५२)

(२) ग्रीक तथा जैन धर्मों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।

(३) टिप्पणियाँ लिखिए बहावी आन्दोलन, स्वामी विवेकानन्द, दियो-  
नोफिजल सोसायटी, ब्रह्म समाज। (यू० पी० १९५३, १९५४)

(४) भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार-आन्दोलनों का राष्ट्रीय  
जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? (यू० पी० १९५३)

(५) देश की सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक जागृति के प्रति निम्न  
लिखित किन्हीं दो तत्त्वों को देने का वर्णन कीजिये।

(१) ब्रह्म समाज, (२) आर्य समाज, (३) रामकृष्ण मिशन।

## भारतीय समाज को समस्याएँ तथा उनके सुधार

मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है। मनुष्य ने इतर जानवरों में भी सामाजिक भावना पाई जाती है। समाज से तात्पर्य मनुष्य का मनुष्य से सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध का स्वरूप स्थायी होता है। इस प्रकार छोटे से छोटा समाज-कुटुम्ब है तथा सबसे बृहद् समाज समस्त मानव जाति है। साधारण दोलचाल की भाषा में समाज में तात्पर्य मभस्त देश के निवासियों के पारस्परिक सम्बन्ध से होना है। परन्तु हमारे देश में धार्मिक विभेदों के कारण एक समाज के स्थान में कई समाज माने जाते हैं। बहुधा यह कहने सुना जाता है कि यह बान हिन्दू समाज के योग्य नहीं यद्यपि अन्य समाजों में प्रचलित है। इस आधार पर भारत में हिन्दू समाज मुसलमान समाज, ईसाई समाज पारसी समाज आदि हैं। यहाँ पर समाज से तात्पर्य धर्म धर्मों के अनुयायियों से है। कभी-कभी समाज शब्द इससे भी सङ्घटित अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे क्षत्रिय समाज में यह नहीं होना चाहिए या ब्राह्मण समाज में मदिरा-पान वर्जित है इत्यादि। यहाँ पर समाज से तात्पर्य विभिन्न वर्ण अथवा जातियों और उनमें प्रचलित प्रथाओं से है।

भारत में अभी तक व्यक्ति के जीवन में धर्म का बहुत अधिक प्रभाव है। जन्म से मृत्यु तक साधारण भारतीय के जीवन में प्रत्येक महत्वपूर्ण अवसर पर किसी न किसी रूप में धर्म का हाथ रहता है। जन्म के अवसर पर, यज्ञोपवीत के अवसर पर विवाह तथा बच्चों के जन्म के अवसर पर तथा अन्त में मृत्यु होने पर पुरोहित के बिना काम नहीं चलता है। साधारणतः बहुधा यह कहने हुए सुना जाता है कि हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण धर्म से प्रभावित है। इस कारण हम अन्य देश के निवासियों से भिन्न हैं। हमारी मान्यताएँ तथा नैतिक धारणाएँ हमारी सम्यक्ता तथा मस्तिष्क हमारी राजनीति सत्त्व में हमारे सामाजिक जीवन के आधार ही अन्य देशवासियों से न केवल भिन्न है परन्तु उनसे उच्च भी है। कुछ विदेशियों ने भी इस दृष्टिकोण की पुष्टि की है।

साधारणतः धर्म से तात्पर्य विविध सामाजिक रीति-रिवाजों से लिया जाता है। परन्तु क्या धर्म केवल यही है? धर्म से तात्पर्य मनुचित अर्थ में व्यक्ति

का देवी-शक्ति ने सम्बन्ध हो सकता है। परन्तु अधिक व्यापक धर्म में धर्म से तात्पर्य सामाजिक जीवन को नियमित करने वाली मनमन्य शक्तियों से है। इनके लिए अंग्रेजी में **Social Ethics** शब्द है। जहाँ तक धर्म का पता चलता है उनमें एक नम है। वह यह कि वही हम यह न समझने से कि प्रत्येक सामाजिक नियम उचित है।

आज भारतीय जीवन में माधारणतः धर्म का धर्म समाज में प्रशस्ति कटियों तथा कुम्हारों से है। यह कहना कि भारत के गाँवों में आज भी प्राचीन आदर्शों के अनुसार जीवन चलता है, सुनने में अच्छा लगता है परन्तु सत्य नहीं। क्योंकि भारत में अधिकांश के कारण जनसंख्या का बहुत भाग धार्मिक कुरीतियों और अन्धविश्वासों को मानने में ही जीवन की मापकता समझता है। इन दृष्टि में आज धर्म हमारे मार्ग में बाधक हो गया है। सत्य है कि धर्म का धर्म यह नहीं होना चाहिए। परन्तु यह भी सत्य है कि माधारण जनता इसी को धर्म मान बैठी है।

इसलिए हममें अधिक दुःख नहीं करना चाहिए कि पाश्चात्य सभ्यता के संस्करण में आज हमारे जीवन में धर्म का महत्व यौन होता जा रहा है। हमें यह देखना चाहिए कि हम मनुष्य या मनुष्य के रूप में आदर करें। हमारी मान्यताएँ अपने पर आधारित न हों। अगर हम प्रत्येक मनुष्य में देवी जैसा वेदते हैं तो हम अपने धर्म से नहीं हट रहे हैं। जहाँ तक प्राचीन सामाजिक प्रथाओं में परिवर्तन का प्रश्न है, कोई भी समझदार व्यक्ति इन बातों में मन्देह नहीं करेगा कि काल की गति के साथ-साथ जीवन की दशाएँ बदलनी जानी हैं। अगर हम सामाजिक दशाएँ भी परिवर्तित होनी चाहिए।

इन धर्मों में संक्षेप में भारतीय समाज की विविध समस्याओं का वर्णन किया जायेगा। यद्यपि हिन्दू समाज तथा मुस्लिम समाज में कई विषयों पर एकता है। उनकी कई समस्याएँ एक हैं, तथापि उनका अलग-अलग वर्णन किया गया है। हिन्दू समाज में निम्नलिखित मुख्य बातों पर दृष्टिपात करना चाहिए—वर्ण व्यवस्था, हरिजनों की स्थिति, मृतक कटम्ब प्रथाएँ, विवाह की समस्या तथा स्त्रियों का स्थान और उनकी समस्याएँ।

**वर्ण-व्यवस्था.**—इनमें तात्पर्य हिन्दू समाज की जाति-व्यवस्था से है। वर्ण का अर्थ रंग है, परन्तु यह यहाँ पर जाति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हिन्दू समाज में मुख्यतः ४ जातियाँ हैं—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। परन्तु इनके अन्तर्गत कई उपजातियाँ हैं। इनकी संख्या तीन हजार से ऊपर है।

मवप्रथम यह दखना चाहिए कि जातियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इस विषय में तीन सिद्धान्त हैं। इनमें से कोई भी पूर्णरूप से सन्तोषजनक नहीं है।

१. एक सिद्धान्त यह है कि वर्णों की उत्पत्ति तब हुई जब कि प्रायः अनाथों के साथ सम्पर्क में आए। समाज में प्रायः सबके ऊपर थे। सबसे नीचे अनाथ थे। इन दोनों के बीच में वर्णमकर थे। दूसरे सिद्धान्त के अनुसार जातियों की उत्पत्ति जना (tribes) से हुई। इनका सबूत यह है कि जातियों में आपस में दान पान, विवाह आदि पर कई प्रकार के प्रतिबन्ध हैं। तीसरा सिद्धान्त यह है कि विभिन्न जातियों की उत्पत्ति अलग-अलग पेदा के कारण हुई। इनमें से प्रत्येक सिद्धान्त में मृत्यु का एक अर्थ है।

पूर्व वैदिक काल में मुख्य भेद ब्राह्मण तथा अनाथों में था। अनाथों में दो विशेष वर्ग थे ब्राह्मण तथा राजा (राजन्व)। इनके प्रतिरिक्त अन्य लोग विक्षा बहलात थे। उत्तर वैदिक-काल में क्षत्रिय का वर्ण और हो गया था। ये वे अनाथ थे जो कि अनाथों के समाज में प्रवेश पा गए थे। इस काल में वर्णों में कठोरता (rigidity) आ गई थी। इसी काल में सर्वप्रथम वर्णों के मवव में यह सिद्धान्त बना कि इनकी उत्पत्ति देवी है। ऋग्वेद के पुरष सूक्त में कहा गया है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से क्षत्रिय वाहुधा से वैश्य नाभि से तथा शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए। बृहद् के काल में इन चार वर्णों के प्रतिरिक्त कई उपजातियाँ उत्पन्न हो गई थीं।

सर्व प्रथम वर्णों का आचार कम था। ब्राह्मणों का काम शिक्षा तथा पुरोहिती था। क्षत्रियों का काम युद्ध तथा शासन था। वैश्य कृषि, व्यवसाय आदि काम करते थे। क्षत्रियों का काम अपने से ऊपर वर्णवाला की सेवा करना था। आरम्भ में यह वर्ण-व्यवस्था कठोर नहीं थी। एक वर्ण के लोग दूसरे वर्ण में जा सकते थे। उदाहरणार्थ विश्वामित्र तपस्या के प्रभाव से क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए थे। परन्तु कालांतर में वर्ण-व्यवस्था कठोर हो गई। एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाना सम्भव नहीं था। कर्म के स्थान में जन्म सिद्धांत प्रचलित हो गया। बौद्धमतवाल्गवियों ने कर्म के सिद्धांत को ही माना। कुछ ब्राह्मणों ने भी इस सिद्धान्त को माना परन्तु साधारणतः जन्म सिद्धान्त ही स्वीकृत किया गया। धर्म शास्त्रों में वर्णों को जन्म के ऊपर रखा गया है।

आज कर्म का सिद्धान्त कोई नहीं मानता। वर्ण-व्यवस्था हिन्दू समाज में जन्म के ऊपर ही आधारित है। ब्राह्मण के घर में उत्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण ही है चाहे वह निरक्षर भटाचाय होवे। इसी प्रकार शूद्र के घर में उत्पन्न



व्यक्ति शुद्ध है चाहे वह कितना ही बड़ा विद्वान क्यों न हो। हिन्दू-समाज में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी जाति में पैदा होता है। वह जन्म भर उसी जाति का सदस्य रहता है चाहे वह उसे छोड़ना ही क्यों न चाहे। यद्यपि जातियों का निश्चय जन्म से ही होता है तथापि आज भी योड़ी-सी सीमा तक अलग-अलग जातियों के पेशे निर्दिष्टनमे हैं। प्रत्येक जाति के लोगों को कुछ निश्चित नियमों का पालन करना होता है। अगर ऐसा न करें तो उनका जाति से बहिष्कार कर दिया जावेगा। अपनी जाति के बाहर शादी करना मना है। इसी प्रकार खान-पान के संबंध में भी नियम हैं। यद्यपि निम्न वर्ग में अब इन नियमों की धक्केलना होने लगी है परन्तु जनसाधारण इनका अब भी पालन करते हैं।

वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध बहुत लोग हो गए हैं। परन्तु आज भी इस व्यवस्था के कई समर्थक हैं। उनके अनुसार इस व्यवस्था के निम्नलिखित लाभ हैं :—

जाति-व्यवस्था के कारण ही हिन्दू-समाज हजारों वर्षों के बाद आज भी जीवित है। अगर समाज इस प्रकार भगटित नहीं होता तो कभी छिन्न भिन्न हो गया होता। बाहर से कई आक्रमणकारी भारत में आए। इनमें से कुछ को तो हिन्दू समाज ने अपने में मिला लिया। जो हिन्दू समाज में नहीं मिले जैसे मुसलमान, उनके प्रभाव ने समाज में विभूत्वलना नहीं माने पाई। जाति-व्यवस्था ने सामाजिक परम्परा को जीवित रखा। नसार में कई अन्य प्राचीन जातियों का आज पता भी नहीं है, परन्तु हिन्दू समाज आज भी जैने का तैसा है। आक्रमणकारियों ने भारत का तन जीता परन्तु उनका मन नहीं जीत पाये।

क्योंकि जाति-व्यवस्था धर्म-विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित था, इसलिए प्रत्येक जाति अपने विशेष कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती थी। बचपन से ही लोग अपने-अपने विशेष कार्य में लग जाते थे। पिता का कार्य उसके पदचात् पुत्र करता था। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपने काम को अच्छी प्रकार समझ जाता था और उसे उचित रीति से करता था।

आज का विविध वर्गों में अलग-अलग कामों के अनुसार विभाजन, समाज की एकता बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी था। विभिन्न वर्गों में आपस में प्रतियोगिता नहीं होती थी। अब अपना-अपना निर्दिष्ट काम करते थे। जेटो ने अपने आदर्श राज्य में भी तीन वर्गों की स्थापना की है। प्रत्येक वर्ग अपने विशेष काम करेगा।

प्रत्येक वर्ण अपने सदस्यों के दुःख-मुक्त में काम आते थे। ग्राम में एक ही वर्ण के लोगो में सहानुभूति, गौहार्द्र तथा प्रेम स्वाभाविक है। प्रत्येक वर्ण के अन्दर महारिता का मिथ्या अफनाया जाता था। इससे यह लाभ था कि आवश्यकता के समय व्यक्ति अकेला नहीं रहता था परन्तु उसे दूसरा की सहानुभूति उपलब्ध होती थी।

प्रत्येक जाति के अन्दर सब लोग समान समझे जाते थे। इस प्रकार प्रत्येक जाति का एक जनतन्त्रात्मक समूह बन गया। धनी-निर्धन का भेद भाव नहीं था। जाति का यह कर्त्तव्य समझा जाता था कि वह अपने अन्दर के निर्धन सदस्यों तथा अनाथ परिवारों की सहायता करे। इससे यह लाभ था कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोई न कोई साधन समूह द्वारा जुटा दिया जाता था। जीवन तब सामूहिक था न कि आजकल की तरह व्यक्तिगत।

जाति-व्यवस्था के जिन गुणों का ऊपर वर्णन किया गया है वे वर्तमान काल में नहीं पाये जाते हैं। आजकल तो जाति प्रथा दोषों का समूह है। इसलिए समाज सुधारकों का कहना है कि अगर हिन्दू-समाज अपनी उन्नति चाहता है तो यह आवश्यक है कि वर्ण-व्यवस्था को अन्त कर दिया जावे। इस प्रथा के नीचे लिखे मुख्य दोष हैं —

जाति-व्यवस्था के कारण हिन्दू-समाज एक इकाई के रूप में काम नहीं कर सका है अपितु अनेक वर्णों में विभाजित हो गया। हमारी भक्ति मुख्यतः समाज के प्रति न होकर अपने जाति-विशेष के लिए होती है। इससे हमारी एकता की भावना घटकर हो गई। एक जाति के लोग दूसरी जाति में न विवाह कर सकते हैं, न अन्य प्रकार के सामाजिक सम्बन्ध उनसे स्थापित कर सकते हैं। पान-पान में भी प्रतिवन्ध है। वे सब बातें एकता के स्थान में पृथक्ता का बढाती हैं। इस भावना का फल यह हुआ कि हिन्दू समाज विदेशियों का कभी भी एक हाथ मारना नहीं कर पाया। इसी कारण राष्ट्रीय एकता की भावना भी मृदुल नहीं हो पाई।

जाति-व्यवस्था के कारण हिन्दू-समाज का दृष्टिकोण अत्यन्त ही मर्यादित हो गया है। यह व्यवस्था प्रगतिशीलता की विरोधी है। इस कारण इससे समाज की उन्नति में बहुत बड़ी रोकट डाली है। कुछ समय पहले तक बहुत से लोग इस उर में विदेश-यात्रा नहीं करते थे कि वे जाति से परिचित कर दिए जायेंगे।

जाति-व्यवस्था मूलतः अप्रजातन्त्रिय है। समानता के स्थान में यह असमानता को प्रोत्साहित करती है। इसके कारण समाज ऊँच तथा नीच में विभाजित हो गया है। इस ऊँच-नीच का आधार कर्म या योग्यता न होकर जन्म है। बहुत से मनुष्य केवल इस कारण समाज में अपने को दूसरों से उच्च समझते हैं क्योंकि वे ब्राह्मण हैं या क्षत्रिय हैं चाहे कर्म की दृष्टि से वे अत्यन्त हीन कोटि के हों। समाज के एक बहुत बड़े भाग को इस व्यवस्था के कारण कभी भी उन्नति करने का अवसर नहीं मिला। कितने दुःख तथा लज्जा की बात है कि समाज के एक-सौभाग्य भाग को हमने मनुष्यों की तरह रहने नहीं दिया। इसीलिए हमारे देश में सच्चे प्रजातन्त्र की स्थापना में जाति-व्यवस्था एक बहुत बड़ा रोड़ा है। इसके कारण चुनावों के अवसर पर बहुत से लोग धार्मिक या राजनैतिक कार्यक्रम पर ध्यान न देकर उम्मीदवारों की जाति का ध्यान में रख मतदान करेंगे। इससे यह भय भी है कि कहीं जाति पर आधारित दल न बन जाएँ। कुछ सीमा तक कम्युनिस्ट-पैलिटियों, जिला-बोर्डों, विश्वविद्यालयों के अन्दर इस प्रकार के विभाजन दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे ब्राह्मण-जनपद, या ब्राह्मण क्षत्रिय आदि। सच्चे प्रजातन्त्र की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि इस प्रकार की संकुचित मनोवृत्ति समूल नष्ट कर दी जावे।

जाति-व्यवस्था के कारण समाज की आर्थिक-प्रगति में भी बाधा पहुँची है। क्योंकि बहुत से व्यक्ति स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी पसन्द का काम नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक जाति का पेशा निश्चित है। अगर कोई अपनी जाति के बाहर का पेशा अपनाता है तो जाति उसकी ठीक नहीं समझती है। बिना स्वतन्त्रता के आर्थिक उन्नति में स्वभावतः ही कमी हो जावेगी इसके साथ ही साथ यह भी दिखाई देता है कि समाज में इस व्यवस्था के कारण बहुत से लोग कठिन परिश्रम के परदास भी अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं जबकि दूसरी ओर कुछ लोग बिना किसी प्रकार का काम किए ही घराम से जीवन बिताते हैं।

जाति-व्यवस्था स्त्रियों के अधिकार की शत्रु है। हमारे समाज में स्त्रियों की शक्ति बहुत सीमा तक इसी व्यवस्था का परिणाम है। विवाह के मामले में स्त्रियों को यह किसी प्रकार के अधिकार प्रदान नहीं करती है। अन्य क्षेत्रों में भी यह स्त्रियों को पुरुष का समकक्ष बनाने की विरोधी रही है।

उपरोक्त वर्णित दोषों को देखने से यह स्पष्ट हो गया होगा कि जाति-व्यवस्था को बनाए रखना हिन्दू समाज के हित में नहीं है। हजारों-लाखों

व्यक्तिगत ने जाति व्यवस्था के कारण तथा हिन्दू समाज में अपने साथ पशुतुल्य व्यवहार होने के कारण दूसरे धर्मों को अंगीकार कर लिया। आजकल शिक्षा-मन्त्र के कारण यह व्यवस्था पहले से अधिक तो घबघा रही है परन्तु अब भी इसका प्रभाव अशिक्षित वर्ग में पूर्व की ही तरह है। जितना शिक्षा का प्रचार होगा उतना ही इस व्यवस्था के दुर्युक्त लोगो की संख्या में घटि जावेगी। देश में औद्योगीकरण के प्रसार से भी इस व्यवस्था को भारी आघात पहुँचेगा।

उन्नीसवीं शताब्दी में ही कई मधारका ने इस व्यवस्था विरोध किया था। ब्रह्म-समाज धर्म-समाज धियोसोपिकल-समाज आदि ने इस व्यवस्था का अनुमोदन नहीं किया।

बीसवीं शताब्दी में भी इस व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई गई। महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति ने इस प्रथा को दापपूर्ण तथा हानिकारक बतलाया। इतना होने पर भी यह अभी प्रभावहीन नहीं हुई है। यद्यपि पहले से अब जाति-व्यवस्था कम बढोरा जा गई है तथापि अब भी यह पूर्णतः प्रभावहीन नहीं हुई है। अब खान-पान में शिक्षित वर्ग के नवयुवक कम परहेज करते हैं। अन्तर्जातीय विवाह भी कुछ-कुछ होने लगे हैं। परन्तु अभी भी पुर्णतः मन्कारा का इतना प्रभाव है कि इस व्यवस्था के विरुद्ध शिक्षा तथा प्रचार की बहुत अधिक आवश्यकता है।

अछूतों की समस्या — हिन्दू समाज का चौथाई भाग अछूत कहलाता है। सर्वत्र हिन्दुओं का विचार है कि अछूत को छूत मात्र से ही महापातक होगा। कुछ स्थानों में उनकी छाया के छूने से भी अस्वस्थ होने का डर रहता है। हमारे समाज में अछूतों की समस्या जाति-व्यवस्था का ही कुरिणाम है। ब्रह्मा के पैर से इनकी उत्पत्ति बनलाई जानी है। शत्रु की उत्पत्ति शायद अन्याय जातियाँ से हुई है। परन्तु बाद का इनमें समाज द्वारा मत्ताएँ हुए कई अन्य वर्ग भी मिल गए, होंगे।

हिन्दू समाज में अछूतों की दशा अन्यन्त ही शोचनीय है। यद्यपि अब पहले से कुछ सुधार अवश्य है। परन्तु अब भी बवल पहला कदम ही उठाया गया है। संक्षेप में अछूतों को समाज द्वारा सब प्रकार के अधिकारों से वंचित किया गया था। उनका कतव्य सर्वत्र हिन्दुओं की सेवा बनलाया गया। इस प्रकार इनको उन्नति का अवसर ही नहीं दिया गया। अछूतों का सर्वत्रों की बस्ती के प्रन्दर रहने का अधिकार नहीं था और अब भी वे इन बस्तियों

के बाहर ही रहने हैं। उनके स्वास्थ्य तथा शिक्षा का कभी भी प्रबन्ध नहीं किया गया। वर्तमान समय में तो उनमें शिक्षा का प्रसार हो रहा है। इनमें बाल-वृद्ध भी शिक्षालयों में जाते हैं यद्यपि अब भी उनकी नब्ब्या अल्पित नून है। परन्तु पहले तो उनको इस अधिकार का उपयोग करने का अवसर ही नहीं था। शिक्षा प्राप्त करना उनका काम नहीं था। पहले यह कहा जाना पड़े कि अगर कोई अछूत वेद मूल ले तो उसे दण्ड देना चाहिए। अछूतों के वाले सब उन्नति के मार्ग बन्द थे। एक ओर जब हमारे धर्मशास्त्रकार यह निम्नता रहे थे कि सब जीवों में देवी अंग हैं, दूसरी ओर अपने ही समाज में इतने बड़े भाग को वे पशुओं के स्तर में ऊँचा नहीं उठने देना चाहते थे। गता-द्वियों के इस व्यवहार का फल यह हुआ कि अछूत न प्रापिक उन्नति कर पाए और न सांस्कृतिक। अधिक क्षेत्र में, न वे व्यापार-वाणिज्य कर करने में और न शिक्षा के अभाव में अच्छी नौकरियाँ पा सकते थे। उनके लिए केवल ऐमें ही काम बचे, जैसे मोची, कुम्हार लुहार आदि। राजनीति के क्षेत्र से भी वे दूर रहे। और सबसे बड़ा बुरा यह हुआ कि उनका नैतिक पतन भी हो गया। उनमें कई बुराइयाँ आ गई, जैसे, गराव पीना, अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन आदि। परन्तु इस अवस्था का उत्तरदायित्व ऊँचे वर्ग के हिन्दुओं पर है। उन्होंने अछूतों को कहा यह बतलाया कि अछूत पशुओं में अछूटे नहीं हैं। इसमें कोई गन्दह नहीं कि अस्पृश्यता हिन्दू-समाज का सबसे बड़ा बुराई है। संसार में ऐसा छुआ-छूत का विचार अन्य किसी देश में नहीं पाया जाता है। कुछ-कुछ इसी प्रकार का व्यवहार अमेरिका में गौरी जनता हस्तिनों के साथ करती है।

**हरिजन सुधार-आन्दोलन :-** अछूतों को हरिजन नाम गांधीजी ने दिया। इनकी अवस्था सुधारने का प्रयत्न मण्डित रूप से उन्नीसवीं शताब्दी में आरंभ हुआ। परन्तु इसके पूर्व भी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब धार्मिक-सुधारकों ने अस्पृश्यता को निरोधार टहराया। उदाहरणार्थ, महावीर तथा गौतम बुद्ध जाति-व्यवस्था में विरोध नहीं करते थे। मोक्ष का द्वार उन सबों के लिए समान रूप में खुले हैं जो उनको प्राप्त करने के लिए नैतिक जीवन अत्यंत करें, यह इनकी शिक्षाओं का सार था। परन्तु इन धार्मिक सुधारकों का प्रभाव स्थायी नहीं रहा क्योंकि जब इन धर्मों का हम हुआ और पुराना हिन्दू धर्म पुनः बलशाली हुआ तो जाति-व्यवस्था भी पुनः मण्डित हो गई। यथार्थ में इस काल में इसकी जटिलता और कठोरता और भी बड़ गई। इसके पश्चात् मध्यकाल तक फिर कोई आन्दोलन इस व्यवस्था के विरुद्ध नहीं चला। मध्य-काल में कई महात्मा तथा संतों ने इस व्यवस्था को नहीं माना। ये संतनक्ति-

मार्गी थे। उन्होंने महा का ईश्वर की भक्ति का अधिकारी बनाया और मर जाति के लोग का अपना धर्म बनाया। उदाहरणार्थ, १४वीं शताब्दी में स्वामी रामानन्द ने न केवल मर वर्णों के हिन्दुओं का परन्तु कई मुसलमानों का भी अपना धर्म बनाया। बाद का कबीर नानक नृवागम आदि भक्ति मार्गी मर। १५ वीं शताब्दी का नर भाना। कबीर स्वयं जाति के ऊपर थे। परन्तु इन मरों के प्रयत्न में जाति-व्यवस्था में बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। यह मरों की सेवा करनी रही। यथाथ में दूसरी शताब्दी और बड़ा मर। यही व्यवस्था बाद में चली आई। इसी मर में भारत में मुसलमान आ गये थे मर उन्होंने यहाँ अपना धर्म स्थापित कर लिया था। परन्तु १५ वीं शताब्दी के बाद ईसाई भी भारत में आ गये थे। इन दोनों धर्मशास्त्रों ने अपने धर्म का प्रचार किया। इन दोनों धर्मों में ऊँच-नीच का भेद मर नहीं है। इसलिए यह स्वाभाविक था कि धीरे-धीरे हिन्दू-समाज की बनायी हुई जातियाँ इन धर्मों का स्वीकार कर लें। इनमें कोई भी मदद नहीं है कि जिन लोगों ने हिन्दू-धर्म का छाँवर सम्झा था ईसाई धर्म का स्वीकार किया उनमें बहुतों का हिन्दू-समाज के अन्तर्गत की है।

१५वीं शताब्दी ने राजा राम साहित्य मर न जाति-व्यवस्था के विरुद्ध प्रचार किया। धर्म समाज ने भी जाति भेद का नहीं माना। स्वामी दयानन्द ने कहा कि वेद इस व्यवस्था का समर्थन नहीं कर रहे हैं। धर्म-समाज ने अन्तर्गत की गिनती तथा सामाजिक उत्थान की मर ध्यान दिया परन्तु इसका प्रभाव अल्पमेव सीमित रहा।

धीमरी शताब्दी में अन्तर्गतदार का गांधी जी ने प्रयत्न महत्व दिया। भारत आने के बाद ने ही उन्होंने जनता का ध्यान इस मर आकर्षित करना आरम्भ कर दिया। कबीर ने गांधी जी के प्रभाव में अन्तर्गतदार का अपने कार्य-क्रम में रखा लिया। गांधी जी ने बार-बार यह कहा कि हिन्दू-समाज का इन मरों का मर करना चाहिए। कई मर उन्होंने यह भी कहा कि मर अन्तर्गत-दार के स्वर्गाय धर्मभव है। जब दूसरी शताब्दी मर के बाद ब्रिटिश प्रचलन मरों ने अपनी धारणा द्वारा अन्तर्गत को हिन्दू सम्प्रदाय में, अलग सम्प्रदाय माना मर गांधी जी ने जनजन किया। इसका मर यह हुआ कि मिनम्बर १९३८ में पूना रैक्ट हुआ और हरिजन हिन्दू-समाज में पूवर् सम्प्रदाय नहीं माने गये।

मर १९३३ में गांधी जी ने हरिजन मेवर् मर की स्थापना की। इस मर ने इस दिशा में अच्छा काम किया है। गांधी जी ने अपने धारणा तथा

लेखों द्वारा हिन्दू समाज की सुष्ठु चेतना को जगाना चाहा और उन्हें यह समझाना चाहा कि वे ब्रह्मों के ऊपर सदियों से कितना प्रत्याचार कर रहे हैं। गांधी जी के प्रयत्नों के फलस्वरूप हरिजनों के प्रति सर्व हिन्दुओं का व्यवहार कुछ सीमा तक बदला। कई स्थानों में उन्हें मन्दिरों में प्रवेश करने को आजा मिल गई। हरिजनों में भी चेतना का संचार हुआ और उन्होंने अपने बुराईयाँ जैसे नगीली वस्तुओं का सेवन आदि, छोड़ने की ओर पग उठाया। उनमें शिक्षा का भी प्रसार हुआ।

नवीन संविधान द्वारा यह घोषणा कर दी गई है कि राज्य की दृष्टि में बिना किसी प्रकार भेद-भाष के सब व्यक्तियों को समान अधिकार हैं। मद्य प्रभूत बिना रोक-टोक मन्दिरों में जा सकते हैं, छालाबो तथा कुओं से पानी भर सकते हैं, स्कूलों में भर्ती हो सकते हैं। संक्षेप में विधि द्वारा उन्हें वे सामाजिक, धार्मिक तथा राजनैतिक अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं जो कि राज्य के मन्दर नागरिकों को प्राप्त हैं। क्योंकि ब्रह्म समाज के पिछड़े हुए वर्ग हैं इसलिए संविधान में उनके लिये कुछ विशेष उपबन्ध हैं, जैसे विधान मण्डलों में उनकी जनसंख्या के अनुसार उनके लिये स्थान सुरक्षित रखे जायेंगे। संविधान द्वारा संसद् में ६० स्थान मछूतों (scheduled castes) के लिये सुरक्षित रखे गये हैं। राज्यों के विधान मण्डलों में ४८३ स्थान उनके लिये सुरक्षित हैं। सरकारी नौकरियों में भी कुछ काल तक उनकी विशेष सुविधा दी जावेगी। इस प्रकार संविधान द्वारा यह प्रयत्न किया है कि हरिजनों के साथ असमानता का व्यवहार न हो। परन्तु केवल अधिकारों के इस प्रकार प्रदान करने से ही कुछ न होगा। आवश्यकता इस बात है कि समाज का यह उत्पीड़ित अंग अपने अधिकारों को समझे तथा उनका उपयोग कर सके। इसके लिये उनमें शिक्षा-प्रचार की अत्यन्त आवश्यकता है। इसकी ओर भी सरकार ने ध्यान दिया है। परन्तु और अधिक काम की आवश्यकता है। शिक्षा द्वारा ही उनकी सांस्कृतिक तथा धार्मिक उन्नति सम्भव है। इस दिशा में भी भारत सरकार का कार्य सराहनीय है।

१५ मार्च, १९४५ को संसद् में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था जिसका उद्देश्य समस्त भारत में छमाछूत को घोरतः प्रोत्साहित करना था। यह विधेयक मछूतों को मन्दिरों में प्रवेश तथा पूजा का अधिकार, छालाब, कुओं, नदी नालों तथा सार्वजनिक नलों के प्रयोग का अधिकार, बिनी सार्वजनिक मार्गें, मुद्राघाट, जहाज, होटल, नौजनालय आदि में प्रवेश करने का अधिकार, किसी भी पेशे को करने का अधिकार आदि प्रदान करता है। यदि कोई उनकी इन

उपयुक्त अधिकारों से वंचित करे तो उस ६ महीने की सजा या ५०० रुपया दण्ड तक ही सकता है। यह विधेयक मई १९५५ में कानून हो गया है।

१. अज्ञानता का स्वयं भी अपनी उन्नति की ओर अग्रसर होना चाहिये। इसके लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि उनमें यह भावना जमकर बैठ जाये कि वे अन्य किसी भी वर्ण से नीचे नहीं हैं। वे भी मनुष्य हैं। इसी भावना का सुदृढ़ हो जाने पर वे स्वयं भी अपने अन्दर फली हुई गन्दगी का हटाने की चेष्टा करेंगे। उन्हें अपनी बुरा आदती को छोड़ देना चाहिए। उन्हें अपने अन्दर के ऊँच-नीच के भाव को हटा देना चाहिए। उन्हें समाज के अन्य वर्गों से अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए। संक्षेप में, उन्हें स्वयं भी इस बात की चेष्टा करनी चाहिए कि वे अपने अधिकारों का ठीक प्रकार से उपभोग कर सकें।

संयुक्त प्रणाली कुटुम्ब — यह कहने में कोई अत्युक्त नहीं होगी कि भारतीय समाज की इसी व्यक्ति न होकर कुटुम्ब है। हिन्दुओं में कुटुम्ब में नास्त्य केवल पति पत्नी और बच्चा में ही नहीं है। पाश्चात्य देशों में कुटुम्ब का यही अर्थ है। हिन्दुओं में संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली प्रचलित है। संयुक्त कुटुम्ब में अर्थ यह है कि एक ही परिवार में पति-पत्नी और उनके बच्चों के अतिरिक्त दादा दादी, चाचा-चाची, भाई भतीजे पुत्र और उनकी पत्नियाँ सब रहने हैं। कभी कभी एक परिवार में तीन तीन पीढ़ियाँ तक एक साथ ही रहती हैं। ऐसे कुटुम्ब की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं

(अ) इसके सदस्यों की मर्यादा बैयकिनक-कुटुम्ब की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। तीस-चालीस होना साधारण बात है। कभी कभी एक एक कुटुम्ब में गौतम व्यक्ति होयें हैं।

(ब) ऐसे कुटुम्ब की सम्पत्ति सम्मिलित होती है। कुटुम्ब के सदस्य जितना भी कमाते हैं वह सब सम्मिलित रूप से कुटुम्ब के उपर व्यय होता है। कुटुम्ब में सेवा के लिये सम्मिलित भोजन की व्यवस्था होती है।

(ग) सबसे वयोवृद्ध पुरुष कुटुम्ब का मुखिया होता है। उसी का अनुयायन सेवा को मानना पड़ता है। अर्थात् कुटुम्ब पितृ प्रभाव होते हैं।



संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली हिन्दू समाज की विशेषता है परन्तु भारत में मुसलमानों में यह प्रणाली कुछ मात्रा तक प्रचलित हो गई है, यद्यपि उनमें यह हिन्दुओं के बराबर कठोर नहीं हुई है।

**साम :**—संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली के निम्नलिखित लान हैं —

क्योंकि सम्मिलित कुटुम्ब में कई वैयक्तिक कुटुम्ब साथ साथ मिलकर रहते हैं इसलिए इसे बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि इसके सदस्यों में परस्पर एक दूसरे के प्रति सहयोग, स्थाय तथा सहानुभूति की भावना वर्तमान हो। इसका फल यह होता है कि बच्चे भी धारम्य से इन गुणों की शिक्षा पाते हैं। ये ही गुण अच्छे नागरिक में भी आवश्यक हैं। संयुक्त कुटुम्ब नागरिकता की शिक्षा के लिये केवल प्रथम ही नहीं परन्तु प्रमुख पाठशाला भी है।

संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली का दूसरा लाभ यह है कि इसमें उन व्यक्तियों का भी जो कि कुपटता, बीमारी, बूढ़ाया या अन्य किसी कारण से अपना तथा अपने बाल-बच्चों का भरण-पोषण नहीं कर सकते हैं, उनके बच्चों का भी पालन हो जाता है तथा उनकी आवश्यकताओं की एक बड़ी मात्रा तक पूर्ति हो जाती है। प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम जीवन निर्वाह का प्रबन्ध हो जाता है, जो कि, एक लेखक के शब्दों में भाषिक प्रगति के लिये आवश्यक है। अनाथ बच्चों तथा विधवाओं की भी ऐसी प्रणाली में अच्छी प्रकार देखभाल हो जाती है। कुटुम्ब के सदस्य दुख सुख में एक दूसरे का साथ देते हैं।

संयुक्त कुटुम्ब के आय के साधन भी अधिक होते हैं। प्रत्येक सदस्य कुछ न कुछ कमाता है। इसका फल यह होता है कि कुटुम्ब की भाषिक समस्या अच्छी रहती है। समाज में कुटुम्ब की प्रतिष्ठा रहती है। भाषित के समय सारा कुटुम्ब एक इकाई की तरह काम करता है।

संयुक्त कुटुम्ब होने के कारण कई खर्च के मदों कमी हो जाती है। जैसे अगर परिवार के सदस्य अलग अलग खाना बनाये तो उसमें अधिक खर्च होगा परन्तु संयुक्त परिवार में सारे कुटुम्ब का खाना साथ ही साथ बनता है। इसी प्रकार कई अन्य खर्च संयुक्त रूप से रहने के कारण कम हो जाते हैं।

उपर्युक्त वर्णित लाभों को देखते से यह लगता है कि यही व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है तथा यह चालू रखनी चाहिये। परन्तु कई विद्वान तथा सुधारकों का कहना है कि इस प्रणाली में दोष अधिक है। इसमें नीचे लिखे मुख्य दोष हैं :—

(१) क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का भावना रहती है कि बिना उसके हाथ पर दिये हुए ही उसका जीवन की मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो ही जायगी अर्थात् उनमें आत्मिक तथा काम न करने का इच्छा पैदा हो जाती है। इसका फल यह होता है कि बटुम्व का गारा भार घाड़ से उन लोगों को ही हट करवा पड़ता है जो कि परिश्रम करने हैं इसका दो परिणाम होते हैं। एक तो यह कि बटुम्व में कुछ लोग निष्क्रिय तथा उत्तरदायित्वहीन हो जाते हैं। दूसरे यह कि जो लोग काम करने हैं उनमें कुछ लोग बाद में भावना पैदा होना स्वाभाविक है कि काम तो वे कर और मीत्र दूसरे लोग कर।

(२) एक बटुम्व में घर का संचालन क्याकि एक ही व्यक्ति के कंधों पर होता है इससे प्रत्येक मनुष्य को म आत्मनिर्भरता का अभाव हो जाता है। यह सभी जानते हैं कि बिना आत्मनिर्भरता के अधिकांश उत्पत्ति अशुभ है। इससे साथ साथ अधिकांश स्वतंत्रता भी नष्ट हो जाती है।

(३) यह बटुम्व में आपत्ति में मनोमार्जित्य पैदा हो जाता है। छोटी छोटी बातों में घर का शांति नष्ट हो जाती है यह अशांतिमय वातावरण बच्चों के ऊपर बुरा प्रभाव डालता है। अशांति के कारण बच्चे का मन लटका रहता है और जीवों में उत्साह नहीं रहता।

(४) समय पर बटुम्व प्रणाली में व्यक्ति के विकास का कम भवत्तर रहता है। प्रत्येक मनुष्य कई विषयों का अधीन रहता है। विषयों पर नियंत्रण की शक्ति अच्छी नहीं रहती। उनका सारा समय घर के ही कामों में व्यतीत होता है। यद्यपि वातावरण का अभाव ही नहीं कर सकती है।

(५) साम्प्रतिक सम्पत्ति व्यवस्था होने के कारण लोगों में अधिकांश स्वायत्तता की इच्छा का ह्रास हो जाता है। यह भी अधिकांश उत्पत्ति के लिये अहितकर है।

(६) समुक्त बटुम्व प्रणाली बहुधा निरुत्पत्ता की ओर ले जाती है। उन मनुष्यों को अवस्था विपरीत से साधनाय हो जाती जिनमें श्रम का कम होने पर लालच अधिकांश होता है। यह सब ज्यादा होता है।

I Self reliance—the great virtue without which no economic progress is possible — is discouraged Banerji, Indian Economics p 36 6th ed

(७) सम्मिलित सम्पत्ति होने के कारण जब कभी इनका बंटवारा होता है तब मुकदमेबाजी की नीबत आ जाती है ।

भविष्य —संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली भी जाति-व्यवस्था की तरह दिन पर दिन टूटती जा रही है । इसका एक कारण तो मनुष्यों में वैयक्तिक भावना की वृद्धि है । प्रत्येक व्यक्ति यह सोचने लगा है कि उसका वर्तमान केवल अपने बोधी-बच्चों तक ही है । पश्चात्य देशों के उदाहरण का प्रभाव भी नगण्य नहीं कहा जा सकता । इसके साथ-साथ यातायात के साधनों में वृद्धि होने के कारण लोग नौकरियों की खोज में दूर-दूर तक जाने लगे हैं । धार्मिक कठिनाइयों के कारण भी यह व्यवस्था टूटती जा रही है । औद्योगीकरण के बढ़ने के साथ-साथ यह व्यवस्था टूटती जायगी ।

क्या इस व्यवस्था का टूटना अच्छा है ? इसका उत्तर बहूतों ने यह दिया है कि संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली भारत में वही काम करती है जो कि अन्य देशों में सामाजिक-बीमा (social insurance) की प्रथा करती है ।<sup>1</sup> परन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि धार्मिक जीवन की जटिलता तथा औद्योगीकरण की वृद्धि दोनों ही संयुक्त कुटुम्ब प्रणाली के विरुद्ध हैं ।

स्त्रियों की समस्या —सर्व-प्रथम हमें हिन्दू समाज में विवाह-प्रथा के ऊपर दृष्टिपात करना चाहिये । हिन्दुओं में विवाह केवल एक शारीरिक सम्बन्ध नहीं है, परन्तु यह दो भारमाओं का सम्बन्ध है । विवाह का आधार भी धर्म है । यह जीवन के मुख्य संस्कारों में से एक है । इसी कारण हिन्दू धर्म के अनुसार पति-पत्नी का एक दूसरे को त्याग कर दूसरा विवाह करना अनुचित समझा जाता है । अन्य समाजों में तलाक प्रचलित है परन्तु हमारे यहाँ धर्म तक इसे उचित नहीं समझा जाता है । विवाह के लिये एक ही जाति का होना आवश्यक है । परन्तु गोत्र भ्रमण-भ्रमण होना चाहिए । जातियों के अन्दर उप-जातियाँ हैं । इसलिये इस दृष्टि से भी समानता होनी चाहिए । पुण्य को एक पत्नी के मर जाने पर दूसरे विवाह का अधिकार है और अधिकतर लोग ऐसा करते हैं । परन्तु सर्वथा हिन्दुओं में विधवा को पुनर्विवाह का अधिकार नहीं है ।

1. "In a country where neither the Government nor any other institution makes arrangements for social insurance... the disruption of joint families may lead to many practical difficulties"—Banerji, *Ibid.*, p. 37.

विवाह के सम्बन्ध में निम्नोक्त विज्ञेय समस्याओं पर ध्यान देने चाहिये —

(१) बाल विवाह — यह बहुत अधिक प्रचलित है। शिक्षित वर्ग में तो अब मातापिता इसका चलन नहीं हैं परन्तु अशिक्षित वर्ग में तथा गांवों में अभी तक इसका प्रचलन है। बाल विवाह का प्रारम्भ क्या हुआ इस विषय में निश्चित रूप में कुछ नहीं कहा जा सकता है। शायद विंसी शताब्दी के आरम्भ में प्रारम्भ हुआ हो। जिस कारण भी यह प्रथा चली हो यह पुष्ट नहीं है। (यद्यपि मैं बालक तथा बालिका) दोनों के लिये प्रसक्त हूँ। १९ वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज तथा आर्य समाज ने इसका विरोध किया। एक समय श्री माताजी ने इसके विरुद्ध एक पुस्तिका प्रकाशित की। इन सब का फल यह हुआ कि एक ऐक्ट द्वारा यह पास हुआ कि १५ वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं किया जा सकता था। बड़ीदा राज्य में १९०१ में एक ऐक्ट द्वारा भी बालिका का विवाह को कम से कम आय १२ वर्ष रखी गई। परन्तु इन नियमों का अधिकतर पालन नहीं किया जाता था। सन १९३० में भारत-ऐक्ट पास हुआ। इससे द्वारा यह निश्चित हुआ कि १४ वर्ष से कम आय की बालिका तथा १८ वर्ष से कम आय के बालक का विवाह करना अपराध माना जायगा तथा उक्त लिये दण्ड मिलेगा। जैसा हम लिये रहे हैं बाल विवाह प्रथा अब भी प्रचलित है। इसलिए यह आवश्यक है कि हमने विरुद्ध यह प्रचार दिया जाये।

(२) बहु विवाह — यद्यपि हिन्दुओं को एक से अधिक विवाह करने का अधिकार है परन्तु समाज में बहु विवाह अधिक प्रचलित नहीं है। पहले धनी लोग या जमींदार और राजे महाराजे एक से अधिक विवाह करते थे, और कुछ अभी भी करते हैं। परन्तु सब साधारण में बहु विवाह का प्रचलन अभी भी अधिक नहीं था।

(३) दहेज प्रथा — इससे यह प्रतीय है कि लड़के वाले लड़की वाले का विवाह कराने समय पैसा माँगते हैं। इससे कई दंग हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छा नौकर है, अतएव इतने हजार रुपए दो, कुछ कहते हैं लड़का आगे पढ़ना चाहता है उसका धन उसको, कुछ लोग कहते हैं हमारे लड़के के लिये मोटर खरीदा। सभ्य में लड़की वाले का अपनी लड़की के हाथ पीठे करने में हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अमीर पिता तो यह सब कर सकता है परन्तु साधारण वर्ग के माता पिता को एक एक

लड़की के विवाह में कब के बोझ में दौहरा हो जाना साधारण बात है। यह प्रथा अत्यन्त हीन है। इसका शोधोपशोध अन्त होना चाहिये। अभी तक इस प्रथा के विरुद्ध अधिक आवाज नहीं उठाई गई है। यह आवश्यक है कि इसके विरुद्ध खूब प्रचार हो गया सरकार किसी भी रूप में दहेज लेने या देने के विरुद्ध नियम बना दे।<sup>1</sup> इसी प्रकार गरीब माता-पिता बच सकते हैं।

(४) विधवा विवाह :—वैदिक-काल में विधवाओं को पुनर्विवाह की आज्ञा थी।<sup>2</sup> परन्तु कालान्तर में विधवाओं का फिर से विवाह करना साम्प्रदायिक विरुद्ध समझा जाने लगा। मध्य काल में तो ऊँचे वर्गों में सती-प्रथा प्रचलित हो गई थी। विधवाओं की अवस्था दिन पर दिन खराब होती चली गई। बाद की तो यह होने लगा कि पति के मृत्यु के बाद पत्नी को बलपूर्वक उसी के साथ जला देते थे। यह अमानुषिक प्रथा बड़ी गौरवपूर्ण समझी जाती थी। खैर यह है कि आज भी कुछ लोग इसको हमारे नारी जीवन का सबसे महान् आदर्श समझते हैं। सन् १८२९ में लार्ड बेंट्लिक ने सती-प्रथा को अवैध कर दिया।

विधवा की अवस्था हिन्दू धर्म में अत्यन्त शोचनीय है। साधारणतः यह समझा जाता है कि वह अपने ही वर्गों के कारण विधवा हुई। इसलिए सुबह-सुबह उसका मुँह देखना भी कहीं-कहीं पर खराब मनसा जाता है।<sup>3</sup> अवसरों पर विधवाओं को अलग रखा जाता है। साम्प्रदायिक-दृष्टि से भी कुछ-कुछ में विधवाएँ भार-स्वरूप समझी जाती हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार का उत्साह नहीं रह जाता है। जब कि पुरुषों को एक के बाद दूसरी शादी या अधिकार है, स्त्रियों को पति की मृत्यु हो जाने पर सतीत्व तथा नारीत्व के आदर्श के नाम में एकान्त जीवन व्यतीत करने को समाज बाध्य करता है।

श्री ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने सर्व प्रथम इस बात का आन्दोलन किया कि विधवाओं का पुनर्विवाह का अधिकार होना चाहिये। सन् १८५६ में भारत सरकार ने ऐक्ट द्वारा विधवा-विवाह को वैध मान लिया। ग्रन्थ समाज तथा धर्म समाज ने भी विधवा-विवाह के पक्ष में प्रचार किया। शिक्षा के प्रचार तथा पाश्चात्य विचारों के प्रभाव ने कई समाज सुधारकों का ध्यान इस ओर

1. अब केन्द्रीय सरकार ने एक दहेज विरोधी बिल पास कर दिया है।

2. An Advanced History of India, by Majumdar, Raychaudhury and Dutta, p. 31.

आवृत्त हुआ। २० वीं शताब्दी में इस दिशा में और अधिक उन्नति हुई। सन् १९२७ में एक नियम द्वारा विधवाओं को सम्पत्ति में भाग मिलने लगा है।

देश में विधवाश्रम असाहाय विधवाओं की सहायतायें शुरू गए हैं। इन दिशा में भी धर्म-समाज, देव-समाज आदि ने अच्छा काम किया है। यद्यपि हिन्दू समाज में कुछ माया तक विधवाओं के पुनर्विवाह के प्रश्न पर दृष्टिकोण बदला है और विधवाओं की स्थिति कुछ सुधरी है तथापि अब भी कुसत्कारों का प्रभाव समाज के अधिकतर भाग के ऊपर है। इन दिशा में अभी और प्रचार तथा शिक्षा की आवश्यकता है क्योंकि पुरानी रुढ़ियाँ बड़ी कठिनाई से उन्मूलित होती हैं।

(५) वृद्ध-विवाह — अब भी बहुधा कई माँ बाप अपनी वय अवस्था की लड़कियों को बूढ़ी को ब्याह देते हैं। वह प्रत्येक दृष्टि में अनुचित है। इनका कारण एक बहुत बड़ी माया तक तो दहेज प्रथा है। वृद्ध पुरुष बहुत कम दहेज में विवाह कर लेगा। दूसरी बात यह भी है कि बहुत से माता-पिता कन्यादान का पुण्य कमाने को अलक्षित रहते हैं और सोचते हैं कि लड़की का भविष्य उनके ही भाग्य पर निर्भर है। समाज में इस प्रकार के विवाहों के विरुद्ध भी विचार बढ़ रहा है।

हिन्दू-समाज में विवाह के सम्बन्ध में रुढ़िवादी विचार कुछ माया तक पहले की अपेक्षा प्रशस्त हो गए हैं। परन्तु अब भी इस दिशा में बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। अभी तक भी बहुत थोड़े से लोग अन्तर्जातीय विवाह करने को प्रस्तुत होये। यद्यपि ऐसे विवाह हुए हैं तथापि उनकी संख्या अत्यन्त कम है। परन्तु जाति का बन्धन स्थिर हान के साथ-साथ इस दिशा में प्रगति होगी। विभिन्न सम्प्रदायों के बीच में तो बहुत कम विवाह होते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ ऐसे विवाह हुए हैं परन्तु साधारणतः उनका बड़ा विरोध है। जो लोग हिन्दू-समाज के अन्दर दस विषय में सब कुरीतियों को हटाना चाहते हैं वे दस प्रकार के विभिन्न सम्प्रदायों के बीच विवाह को उचित नहीं समझते हैं।

अब विवाह-सम्बन्ध में लड़के-लड़कियों का भी मत जानने की चेष्टा की जाती है। शिक्षित वर्ग में तो बिना लड़के-लड़कियों की अनुमति के विवाह बहुत ही कम होते हैं। परन्तु अब भी लड़कियों के मत की कम महत्व दिया जाता है। शिक्षित वर्ग में अभी भी विवाह अभिभावकों के द्वारा ही तथा

किया जाता है। सुखी कौटान्बक जीवन के लिये विवाह के पूर्व लड़के-लड़कियों का गत अवस्था जान लेना चाहिये।

**समाज में नारी का स्थान** — यद्यपि मनुस्मृत में एक उक्ति है कि 'नारी नारियों की पूजा होती है, बड़ा दयालु स्मरण करने है' तथापि वास्तव में हिन्दू समाज में साधारण नारी का स्थान अत्यन्त ही निम्न है। प्राचीन काल में स्त्रियों की अवस्था इतनी हीन नहीं थी। यद्यपि वे पुरुषों के दरावर कभी भी नहीं समझी गईं तथापि उनका घर तथा समाज दोनों में सम्मान था। उनकी शिक्षा दी जाती थी और विवाह वही होने पर किया जाता था। स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। विश्वामित्र, घाता, अश्वला, गार्ग्यो, मैत्रेयी, विदुषी महिलाएँ थीं। परन्तु धीरे-धीरे स्त्रियों का दशा बिगड़ने लगी। उनकी स्वतन्त्रता कम होने लगी। गुप्त काल तक सती प्रथा समाज 'उच्च-वर्गों' में काफी प्रचलित हो गई थी। परन्तु इनका सब होने पर भी स्त्रियों की अवस्था बहुत खराब नहीं थी।

मध्यकाल में मुस्लिम आक्रमणों के परिणामस्वरूप इन दिशा में और अवगति हुई। उस समय की अवस्थाओं के कारण पर्दा-प्रथा का आरम्भ हुआ। स्त्रियों का स्वेच्छ केवल घर के अन्दर समझा जाने लगा। सती-प्रथा बहुत प्रचलित हो गई। शिक्षा की ओर भी कम ध्यान जाने लगा। मध्य काल में स्त्रियों की दशा दिगम्बर ही चली गई। कन्या का जन्म दुःख का अवसर माना जाने लगा। धीरे-धीरे यह प्रथा चल गई कि कन्या का जन्म होते ही उसे भार दिया जाता था। यह प्रथा विशेषकर राजपूतों में बहुत ही प्रचलित थी। लॉर्ड वेल्सली ने इन अन्यायिक प्रथा को काट करने की ओर प्रयत्न पत्र उठाया था।

यह कहने में कोई अतिशय नहीं होगी कि हिन्दू समाज में यद्यपि काफी जागृति हो गई है तथापि आज भी स्त्रियों की दशा कोई अच्छी नहीं है। विवाह के सम्बन्ध में जो कुप्रथाएँ प्रचलित हैं उनका वर्जन हम कर चुके हैं। शिक्षा तथा गठकृति की दृष्टि से भी स्त्रियों की अवस्था दयनीय है। सब भी बहुत से मौलवाय अर्थात् लड़कियों को शिक्षा में वचित रखते हैं। गाँवों की अवस्था तो इस विषय में बहुत खराब है। धार्मिक दृष्टि से भी स्त्रियों का स्थान अत्यन्त नीचा है। साधारणतः वे हर मामले में पुरुषों के ऊपर निर्भर हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। पर्दे का व्यवस्था बहुत प्रचलन है। यद्यपि पहले से स्थिति में बहुत सुधार हो गया है तथापि अब भी अन्य अन्य देशों की अपेक्षा हमारे यहाँ का नारी-समाज अत्यन्त ही पिछड़ा हुआ है।

मुधार-ग्रान्दोलन — १० वीं मताब्दी में ब्रह्म-समाज तथा धाय समाज ने स्त्रियाँ की दशा मुधारन के विषये आवाज उठाई। राजा राममोहन राय का काम काफी महत्वपूर्ण है। उन्हीं के कारण अंग्रेजी-सरकार ने सती प्रथा को खत्म कर दिया। आ कश्यपचन्द्र मल्ल ने विधवा विवाह का प्रश्न उठाया। सन् १६ में विधवाओं का पुनर्विवाह वैध मान लिया गया। धाय-समाज ने बाल-विवाह र विच्छेद तथा विना-विवाह के पक्ष में आन्दोलन किया। स्त्रियाँ की दशा में ग्रियस मुधार राजनैतिक आन्दोलन के बढ़ने से सन् १९२० के बाद हाना आरम्भ हुआ। इनके फल स्त्रियाँ स्वयंश्रमिणी होने दशा को मुधारन में अधिक प्रयत्नशील नई थी। जय हार-मल्ल आन्दोलन (१९१४-१९१७) आरम्भ हुआ तब भागीय महिलाओं ने सर्व-प्रथम धाय अधिकारों के बारे में मोक्षता आरम्भ किया। जब गांधी ने दण्डवानतुल्य लिया तो इस विषय में और प्रगति हुई। उनसे तत्पश्चात् राजनैतिक आन्दोलन में स्त्रियाँ ने भी पुण्या के साथ भाग लिया। उन्होंने लाठिया तथा गोलीयों महा और जेल गईं। इनका फल यह हुआ कि स्त्रियाँ के आन्दोलन स्पष्ट रूप से चेतना का आधार हुआ। उनका श्रमिणी होने दशा का भाव हुआ और इस कारण सन् १९२० के पश्चात् स्त्रियाँ की दशा में शीघ्रता से साथ मुधार होने आरम्भ हुआ।

स्त्रियाँ ने राजनैतिक अधिकारों की माँग की। दिसम्बर १८ १९१७ को १ म मी० माल्टा—जो कि भारत मन्त्री थे—से अखिल भारतीय-महिला का मिष्ट-मण्डल मिला और उसने स्त्रियों के लिये राजनैतिक अधिकारों की माँग की। सन १९१७ के एक्ट के द्वारा ३,१५,००० स्त्रियों को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। सन १९-२३ में स्त्रियाँ ने सर्वप्रथम प्रांतीय धाय-समाजों के चुनावों में भाग लिया। जब एम्दन में गोलेमय सभाएँ हुईं उनमें भारतीय स्त्रियाँ के प्रतिनिधियाँ ने भाग लिया। सन १९२५ के एक्ट द्वारा स्त्रियाँ के राजनैतिक अधिकारों में वृद्धि हुई। करावन ६० लाख स्त्रियों को मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। कन्दाय धायसभा के उपरी सदन में स्थान तथा निचले सदन में स्थान उनसे लिये सुरक्षित किये गये—सदन में ८, बम्बई में ६, बंगाल में ५, यू० पी० में ६ पंजाब में ४, बिहार में ८, मध्य भारत में ३ वगैरह में १, मित्र तथा उडामा प्रत्येक में २।

जब ये भारत में तथा मविधान लागू हुआ है इसके अधीन स्त्रियों का अधिकार दिये गये हैं जो कि पूर्णता का प्राप्त है। राजनैतिक तथा सामाजिक अधिकारों में उनमें तथा पुण्यों में अब कोई भेद नहीं रहा। वे नौकरों के समान हैं। उ हें समान कार्य के लिये पुण्यों के समान ही वतन मिलेगा।



चुनावों में उन्हें मत ना दिये जाते हैं। वे विधान-मण्डलों की सदस्यता के लिये खड़ी हो सकती हैं। वे मन्त्री, स्पीकर, ऐम्बेसेडर हो सकती हैं।

आज स्त्रियों की स्थिति पहले से बहुत अच्छी है। शिक्षा का प्रचार उनमें तेजी से हो रहा है। वे बड़े सेबों में नौकरों कर रही हैं। डाक्टर, नर्स, मिड्वी, वकील, बालक आदि, सभी प्रकार की नौकरियाँ वे करती हैं। मिला ७ फीटर्सियों में भी वे काम करती हैं। पैसे की प्रथा खत्म हो रही है। विद्वत् के मानके में भी पहले से अधिक स्वतन्त्रता है। अन्तर्राष्ट्रीय, अन्तर्-राष्ट्रीय तथा कुछ-कुछ दल-पक्ष सम्प्रदायों के बीच भी विश्वास होने लगे हैं। स्त्रियाँ अब धर्म के दावा पर नहीं हैं। पाकों में धूमती है तथा अन्तर्जन के स्वार्थों में जाती है। वे समाज में शान्त प्रसार के कार्य करने लगी हैं। विद्वत् तथा मूनि-शिष्य बौद्धों में भी महिलाओं के लिये स्थान सुरक्षित है। हमारे समाज में स्त्रियों ने सन् १९२० के पश्चात् प्रचण्डीय प्रगति की है। परन्तु अभी तो केवल समाज के ऊपरी भाग में यह सब हुआ है। जो स्त्रियाँ आज विधान-सभाओं में हैं, या जैसी नौकरियों में हैं, या स्कूल और कॉलेज में प्रधानाध्यापिकाएँ हैं, वे सब समाज के उपरी वर्ग की हैं। समाज के निचले वर्गों में स्त्रियों की दशा पूर्ववत् है। वे घर के बाहर किसी काम में भाग नहीं लेती हैं, इसका कारण एक तो उनकी प्रतिभा है तथा दूसरा कारण उनकी शैक्षणीय व्यापक दशा है। इसमें कोई संशय नहीं कि स्त्रियों को यथार्थ स्वतन्त्रता समाज में तभी मिल सकती है जब वे व्यापक-शिक्षा में स्वतन्त्र हों। जब स्कूल, पुस्तकों के उपर अपनी दैनिक-आवश्यकताओं के लिये निर्भर हैं, पूरी स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती है।

स्त्रियों की प्रमुख समस्याएँ:—बैचे तो देश में इस समय कई समस्याएँ हैं जो कि क्षेत्र में काम कर रही हैं, परन्तु सबसे मुख्य तीन समस्याएँ हैं :

भारतीय स्त्री संघ (Women's Indian Association):—इसकी स्थापना १९१७ में हुई थी। इसका उद्देश्य स्त्रियों में शिक्षा प्रचार तथा सुधार और उनके लिये राजनैतिक अधिकारों की मांग रहे हैं। यह अभी तक काम कर रहा है। इसी के सत्वाधान में स्त्रियों का निपटनम्बल सन् १९१७ में नाथ-भन्नी से मद्रास में निष्ठा था।

भारत में स्त्रियों की राष्ट्रीय कांसिल (National Council of Women in India):—इसकी स्थापना सन् १९२५ में हुई थी। इसने विशेषकर समाज-सुधार की ओर ध्यान दिया है।

**ग्रामिल भारतीय महिला सम्मेलन (All India Women's Conference)** —यह मस्या सत्रम प्रपय है । इसकी स्थापना सन् १९२६ में हुई थी । इस मस्या ने स्त्रिया म सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों में काम किया है गया कर रही है । इस अनिवार्य इसन स्त्रिया क वास्ते सम्पत्ति के अधिकारों म परिवर्तन की माँग की है । इसने अस्पृश्यता तथा जातिरथा के विरुद्ध भी काम किया है । इसका बाधिक अधिवेशन होने है । उनम स्त्रिया की विभिन्न समस्याओं पर विचार विनिमय तथा प्रस्ताव पास किये जाने है । इस मसम इसकी दश म करीबन २०० शाखाएँ तथा २०,००० मे कुछ अधिक सदस्य है । यद्यपि इस मस्या ने स्त्रिया की दशा सुधारने म गराहनीय कार्य किया है तथापि यह काने म कोई दोष नहीं होगा कि इसकी मददयता केवल शिक्षित, उच्च वर्ग की महिलाओं तक सीमित है । सम्मेलन समाज के निचले स्तर की महिलाओं का नहीं छू मका है । सन् १९४४ में सम्मेलन द्वारा कई माँग रखी गई थी ।

**स्त्रियों की भागें** —इन भागा का उद्देश्य महिलाओं के लिए सामाजिक तथा आर्थिक सुविधाएँ प्राप्त करना ।

स्त्रिया की शिक्षा की उचित व्यवस्था की जाव शिक्षा इस प्रकार की हो ताकि लड़कियाँ भी लड़कों की ही तरह प्रत्येक क्षेत्र में काम सकें और नौकरी कर सकें ।

पारिवारिक जीवन को सुखी बनाने के लिए तथा अतृप्तता की समस्या हल करने के लिए लड़के तथा लड़कियों को परिवार सम्बन्धी शिक्षा भी स्कूल कॉलिजा में देनी चाहिए ।

स्त्रिया के लिए दश भर में जच्चा-घर तथा गिशु घर खोले जायें । इसका आयाधिक आवश्यकता है । हर वर्ष कई हजार बच्चे तथा माताएँ इसके अभाव के कारण मर जाने हैं । गभवती स्त्रिया के लिए कन्द्र स्थापित किए जायें ताकि उनकी ठीक प्रकार से देखभाल हो सक ।

केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेश की सरकारों द्वारा समाज सेवा म लगे हुए मस्याओं के कामों का संचालन तथा देख-भाल होना चाहिए । इसके लिए एक Ministry of Social Affairs हो । इसकी स्थापना म समाज सेवा का कार्य उचित रूप से हो सकेगा ।

स्त्रियों के विषय में जो कानून है उनमें शोषिता ने परिवर्तन किये जायें जिससे स्त्रियों की अवस्था सुधार सकें।

**हिन्दू कोड बिल** — भारतीय महिलाओं ने इस बात को मांग को कि उनके सम्बन्ध में जो कानून है उनमें सुधार किये जायें। इन सुधारों की आवश्यकता देश में प्रति दिन अधिकाधिक लोगों को जात हो रही है। सन् १९३७ में एक नियम द्वारा स्त्रियों को सम्पत्ति के कुछ अधिकार दिये गए थे। चार वर्ष बाद एक कमेटी की स्थापना की गई—राय कमेटी जिसका काम हिन्दू लों में सुधार सुझाने का था। इस कमेटी ने अपनी सिफारिशों को बिल के रूप में रखा। इनको हिन्दू कोड बिल कहते हैं। इसके मुख्य उपबन्ध निम्नलिखित हैं :

( १ ) लड़कियों को जो पिता की सम्पत्ति पर लड़कों की तरह उत्तराधिकार हो।

( २ ) पत्नी तथा पुत्री को अपनी सम्पत्ति पर पूरा अधिकार हो। वे उन्हें बेच सकती हैं या किसी को दे सकती हैं या जो चाहे कर सकती हैं।

( ३ ) पुरुष या स्त्री पहले विवाह की पत्नी या पति के रहने इलाका विवाह नहीं कर सकते हैं।

( ४ ) तलाक (divorce) का अधिकार कुछ निश्चित सीमाओं के अन्दर मान लिया जाय।

( ५ ) स्त्री को गोद लेने के मामले में स्वतन्त्रता प्राप्त हो।

इस बिल की धाराओं को देखने से स्पष्ट है कि हमारे समाज में स्त्रियों की दशा सुधारने के लिये इनका पास होना आवश्यक है परन्तु देश में कई रुढ़िवादी ऐसे हैं, और उनकी संख्या कम नहीं है, जो कि इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उनके अनुसार यह बिल हिन्दू-समाज की जड़े काट रहा है। यह शास्त्र विरोधी है। हमारे विचार में इस प्रकार के बिल को नितान्त आवश्यकता है। बिना स्त्रियों को इस प्रकार के अधिकार दिए हुए उनकी स्थिति में पूरा सुधार होना असम्भव है।

देश में हिन्दू कोड बिल का अत्यन्त विरोध किया गया। अतएव वाइस सरकार ने यह उचित समझा कि ऐसे बिल को जिसका कि इतना विरोध हो पास न किया जाय। उसका विचार सन् सन् स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन

करना है। इसी उद्देश्य से दिसम्बर १९५० में हिन्दू विवाह विधेयक संसद में पेश किया गया।

१९५४ में यह विधेयक अधिनियम बन गया। इस अधिनियम के अनुसार राज्य सरकार विवाह विधेयक के अन्तर्गत निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर विवाहों की रजिस्ट्री करेगी—  
चाहे तो इस अधिनियम के अन्तर्गत विवाहों का प्रदान किया गया है। यह स्त्री-सुधार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण पग है।

स्त्री सुधार के विरोधी साधारणतः यह करने हैं कि भारतीय नारी का आदर्श पाश्चात्य नारियाँ में सर्वथा भिन्न है। यही बात माविनी का उदाहरण देते हैं। पश्चिम में उनसे विचार में नारियों का नैतिक चरित्र अत्यन्त पतित है। सुधारों के द्वारा हमारा यहाँ भी ऐसा ही हो जायगा। ऐसी बातें कुछ तो अज्ञान की उपज हैं। दूसरे से सभ्य के विरोधी यह नहीं देखते कि सुधारों का यथार्थ उद्देश्य यह है कि स्त्रियाँ भी समाज की सेवा की प्रकार कर सकें जिस प्रकार पुरुष करते हैं। यह कहना कि स्त्रियों का धर्म केवल घर के भीतर ही सर्वथा अनुचित है। न यही सोचना चाहिए अगर स्त्रियाँ घर के बाहर के जीवन में भाग लेंगी तो घर के कर्त्तव्यों से विमुख हो जावेंगी। हमें घर तथा समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करना होगा।

अन्य सम्प्रदायों का सामाजिक जीवन — देश में छोटे छोटे धार्मिक सम्प्रदायों का जीवन जैसे सिख जैन आदि, हिन्दुओं की ही तरह है। पारसियों का सामाजिक जीवन भिन्न है क्योंकि उनमें पाश्चात्य सभ्यता का बहुत अधिक प्रभाव है तथा वे शिक्षित हैं। उनमें स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी है। वे पढ़ी-लिखी होती हैं तथा उन्हें तलाक का अधिकार भी है।

मुसलमानों का सामाजिक जीवन एक प्रकार से हिन्दुओं से भिन्न कहा जा सकता है क्योंकि उनमें और हिन्दुओं में धार्मिक विभिन्नता है। परन्तु दूसरी ओर उनमें समाज में कोई समस्याएँ हिन्दुओं की ही तरह हैं।

इस्लाम के अनुसार सब अनुग्रह बराबर है और उनमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं है। परन्तु मुसलमानों में भी हिन्दुओं के सम्पर्क के कारण कुछ भाषा तथा जाति-भेद दिखाई देता है। यह उनका बहोर नहीं कि जितना हिन्दु समाज में है। उनके यहाँ सबसे ऊँचे मर्याद और श्रेष्ठ समझ जाते हैं। विवाह के समय इन भेदों का ध्यान रखा जाता है। इससे अतिरिक्त मुसलमान शिया

तथा सूची इन भागों में बँटे हैं। इनमें भी आपस में भेद है। परन्तु इतना होने पर भी मुसलमानों में छूपाछूत का प्रश्न किसी भी रूप में नहीं है। उनमें बहुत बड़ी एकता की भावना है।

मुसलमान स्त्रियों की स्थिति हिन्दू स्त्रियों से इस धर्म में अच्छी है किन्तु उन्हें विवाह तथा सम्पत्ति के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में उनसे अधिक अधिकार हैं। मुसलमानों में विधवाओं के पुनर्विवाह की भावना है। उच्च-वर्ग में यह बहुत कम प्रचलित है। कुछ अवस्थाओं में स्त्रियों को तलाक देने का भी अधिकार है। परन्तु साधारणतः पुरुष के लिए इस अधिकार का प्रयोग सुगम है। मुसलमान स्त्रियों को अपने पति तथा पिता की सम्पत्ति का भाग मिलता है।

मुसलमानों में एक पुरुष को चार विवाह करने की भावना है। परन्तु हिन्दुओं की तरह इनमें भी इसका बहुत अधिक प्रचलन नहीं है। मुसलमानों में पदों की प्रथा हिन्दुओं से भी अधिक प्रचलित है। विद्या के क्षेत्र में भी उनकी प्रगति हिन्दुओं की अपेक्षा कम है।

हिन्दू स्त्रियों में जैसा हम लिख चुके हैं, राजनैतिक भाग लेने के कारण एक नई चेतना संचरित हुई है। परन्तु मुसलमान स्त्रियाँ इससे पूर्णतः अलग हो रही हैं। इस कारण उनमें अभी तक अपने अधिकारों के बारे में वैसी चेतना नहीं उत्पन्न हो पाई। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन अमान्यतादिक संस्था है। कुछ मुसलमान स्त्रियाँ भी इसमें हैं परन्तु अधिकतर मुसलमान स्त्रियाँ इन सुधार संस्थाओं से अलग रहती हैं। उनमें थोड़ा शिक्षा का प्रचार पहले से बढ़ रहा है। हम यही आशा कर सकते हैं कि मुसलमान महिलाएँ भी अपनी हिन्दू बहिनी की तरह उन्नति और प्रगति का मार्ग अपनावेंगी।

### प्रश्न

- (१) भारतीय समाज की प्रमुख समस्याओं का संक्षेप में वर्णन कीजिये।
- (२) वर्ण-व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसके क्या गुण तथा दोष हैं? (यू० पी० १९५४)
- (३) स्त्रियों की समस्या के ऊपर विचार प्रकट कीजिये। किस प्रकार भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा में सुधार सम्भव है? (यू० पी० १९५२)
- (४) संविधान में दलित वर्गों के हितों के संरक्षण के लिये क्या विशेष प्रबन्ध हैं? (यू० पी० १९५२)

(१) 'अस्वस्थता हमारे समाज का बहुत बड़ा अभिन्न है' व्याख्या कीजिये। कन बीस वर्षों में इस अभिन्न का दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये ? (यू० पी० १०५०)

(६) मलिन टिप्पणी जिसमें हिन्दू का विचार (यू० पी० १९५१)

(७) देश का प्रमुख सामाजिक कुरीतियों पर प्रकाश टाँकिए। इनका दूर करने के क्या उपाय हो रहे हैं ? (यू० पी० १९५८)

(८) समुच्च कुटुम्ब प्रणाली में क्या गम तथा शून्यता है ? इस प्रणाली का हमारे समाज में क्या महत्व है कारण सहित लिखिये। (यू० पी० १९५७)

## भारत की आर्थिक अवस्था

किसी भी देश का सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन वहाँ की आर्थिक अवस्था पर, बहुत अधिक मात्रा में, निर्भर रहता है। गरीब देश के निवासियों के जीवन की समस्याएँ समृद्ध देश के नागरिकों की समस्याओं से भिन्न होंगी। इसलिए उन दोनों के जीवन के प्रति दृष्टिकोण में भी भेद होगा। इनही कारणों से यह आवश्यक है कि भारत की आर्थिक-अवस्था का अध्ययन किया जावे।

गरीबी :—सर्वप्रथम प्रश्न यह उठता है कि क्या हमारा देश आर्थिक दृष्टि से समृद्ध है, यथवा गरीब है ? इसका उत्तर देने के लिये कोई अधिक भूमिगत पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो कई ऐसी बातें दिखाई देंगी जो कि इन बात की ओर इंगित करती हैं कि हमारा देश आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त पिछड़ा हुआ है। किसी भी मगर या गाँव को देखिये, बापको पग-पग पर ऐसी बातें दिखाई देंगी। इन आर्थिक दुरवस्था के कई कारणों का होते हैं। हम में से अधिकांश व्यक्तियों का स्वास्थ्य खराब हो गया है। क्योंकि भारत में जनसंख्या के एक बड़े भाग को पेट भर खाना नहीं मिलता है। जनता का एक बड़ा भाग स्वास्थ्यकार मकानों में रहता है। आर्थिक दुरवस्था के कारण मातृ में अधिकांश व्यक्ति किसी भी प्रकार का सांस्कृतिक-जीवन नहीं बिता सकते हैं। उनका मारा समय की समय के लिये भोजन इकट्ठा करने में ही लग जाता है और दुत की बात यह है कि तब भी यह प्राप्त नहीं होता। गरीबी के कारण बहुत से लोगों के लिये जीवन में प्रसन्नता के स्थान में दुःख तथा दुःख है। जीवन एक बरदान न होकर भार हो गया है।

भारत के प्राकृतिक साधन :—सर्वप्रथम हमें अपने देश के प्राकृतिक साधनों पर ध्यान देना चाहिये। प्रकृति ने भारत को अत्यन्त दृष्टि से समृद्ध बनाने का प्रयत्न किया है। यह बात भारत के प्राकृतिक साधनों पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाती है :

(१) भूमि :—भारत एक विशाल देश है। इसकी लम्बाई २००० मील तथा चौड़ाई १५०० मील है। इसका क्षेत्रफल १२,६९, ६४० वर्गमील है।





**कोयला** :—वार्षिक उत्पादन लगभग ३८० लाख टन है, जब कि संसार का वार्षिक उत्पादन लगभग १२२५० लाख टन है। विनोदजी के अनुसार भारत में ४०० करोड़ टन कोयला होने की संभावना है।

**पेट्रोल** :—भारत में पेट्रोल बहुत कम पाया जाता है। परन्तु विनोदजी का अनुमान है कि आनाम, पञ्जाब पश्चिमी तट पर कच तथा खम्भात में पर्याप्त पेट्रोल मिल जायगा।

**जलविद्युत** :—हमारे देश की कोयला तथा पेट्रोल में स्थिति सजोषजनक नहीं है परन्तु जल बिद्युत में भारत की स्थिति अच्छी है। यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत में ३५० लाख किलोवाट जल-विद्युत बनित उपायन करने की क्षमता है।

उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि भारत प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से अधिक पिछड़ा नहीं है यद्यपि यह अमेरिका या रूस की तरह सम्पन्न भी नहीं है।

जनसंख्या की दृष्टि से देश की स्थिति, हमारी पिछड़ी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अच्छी नहीं कहा जा सकती। हमारे देश की जन-संख्या सन् १९५१ में लगभग ३५७ करोड़ थी। हमारे देश का जन्म-दर बहुत अधिक है। यह लगभग ३५-३६ है। इसके अधिक होने के कई कारण हैं। जैसे, धार्मिक तथा सामाजिक विचार, भाल-विवाह, गरीबी, जनसंख्या निरोध सम्बन्धी ज्ञान का अभाव, आदि। भारत की जनसंख्या अधिक है और यह देश की आर्थिक भ्रष्टाचार तथा निर्धनता का एक प्रमुख कारण है। यह कहना असंगत है कि जितनी अधिक जनसंख्या होगी उतनी ही अधिक देश आर्थिक उन्नति कर सकता है। भारत जैसे देश में जनसंख्या का निरोध आवश्यक है।

**भारत की निर्धनता के कारण** :—हम देश के प्राकृतिक साधन देख चुके हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इन साधनों के होते हुये भी भारत में निर्धनता क्यों है? संक्षेप में हमारी निर्धनता के निम्नोक्त मुख्य कारण हैं :

(१) हमारा देश करोड़ों डेढ़ सौ वर्षों तक पराधीन रहा है। विदेशियों ने भारत के उद्योग-धंधों को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी रखी। भारतीय गृह-उद्योगों का अंग्रेजी शासन में पूरी तरह नाश किया गया है। नये उद्योग-धंधों की भी विदेशी-शासन ने उन्हाहित नहीं किया। जो उद्योग

धने देश में है उनमें से भी बहुतों में अभी तक विदेशियों का अधिकार बना हुआ है ।

(२) जनता का अधिकांश भाग भूमि पर निर्भर है । कृषि का ढग भी पिछड़ा हुआ है सिंचाई आदि की व्यवस्था सतोष जनक नहीं है इसलिए यह स्वाभाविक है कि लोगों की आय बहुत कम हो ।

(३) भारत की जनसंख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है, और क्योंकि नौकरी के अन्य कोई रास्ते नहीं हैं तथा उद्योग-धंधों की भी उन्नति नहीं हो रही है इसलिए भूमि के ऊपर ही अधिकाधिक भार बढ़ रहा है ।

(४) भारत की अधिकांश जनता अशिक्षित है । इससे एक ओर तो यह अभी तक कई सामाजिक कुरीतियों में फंसी हुई है, दूसरी ओर इसके कारण देश में योग्य टेक्नीशियन, इंजीनियर आदि का अभाव है । अशिक्षा के ही कारण हम लोग भाग्यवादी हो गये हैं ।

(५) हमारे देश में लोग मुकदमेवाजी तथा शादी-अप्राह आदि उलमबो के समय व्यर्थ का खर्च करते हैं । इससे उनके ऊपर खर्च का एक बोझ लद जाता है ।

(६) हमारे देश में औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा का समुचित संबंध नहीं है । इसके साथ ही साथ जनता को धर्मशास्त्र के मिथ्यान्तों का भी ज्ञान नहीं है । जो कुछ शिक्षा हमें उपलब्ध है वह वास्तव में व्यर्थ है । क्योंकि उसके बाद बचल दफ्तर में नौकरी करने के और कोई मार्ग खुला ही नहीं रह जाता है ।

(७) देश की की ग्रामिक समस्या का सबसे बड़ा कारण वृत्तीवादी व्यवस्था है । इसके कारण राष्ट्रीय आय का वितरण इस प्रकार होता है कि एक बहुत छोटे से वर्ग के हाथ में करीबन आलीस प्रतिशत भाग चला जाता है । कृषि की उन्नति के लिये जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और औद्योगिक उन्नति के लिए उद्योगों का राष्ट्रीयकरण अत्यन्त आवश्यक है । राष्ट्रीय सरकार ने जमींदारी उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है ।

उपरोक्त कारणों से हमारा देश निर्यंत है । अतएव अगर हम इस निर्यंतता का दूर करना चाहते हैं तो हमें इन गरीबी के कारणों को दूर करना चाहिये । इसके लिए आवश्यक है कि कृषि का वैज्ञानिक ढग अपनाया जाय, उद्योग-धंधों की वृद्धि हो, टेक्निकल शिक्षा का प्रबन्ध, नये व्यवसायों का

मोल्ना तथा शिवा का प्रसार किया जाय । इनके अतिरिक्त जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा गृह-उद्योगों का विकास भी आवश्यक है । नतीज में भारत की निर्धनता का कारण उत्पत्ति का नीमित होना है । इसलिये निर्धनता दूर करने का उपाय यह है कि उत्पत्ति को बढ़ाया जाय और यह देखा जाय कि इसका उचित प्रकार से विवरण होता है ।

### ( अ ) कृषि

हमारा देश कृषि-प्रधान है । जनता का अधिकतम भाग गांवों में रहता है तथा कृषि में लगा है । हमारी जनसंख्या का लगभग ७० प्रतिशत भाग खेती पर निर्भर है । गांवों की जनसंख्या का ९० प्रतिशत भाग खेती पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर है । हमारी राष्ट्रीय आय का ८८ प्रतिशत कृषि से अर्जित होता है ।

भारत की भूमि काफी उपजाऊ है । माल में दो मुख्य फसलें होती हैं—खरीफ की फसल तथा रबी की फसल । खरीफ की फसल वसन्त शुरू होते ही बोई जाती है और सितम्बर से नवम्बर के बीच में काट ली जाती है । रबी की फसल जाड़ों की फसल है । यह अक्टूबर-नवम्बर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में सँवार हा जाता है ।

यद्यपि हमारी भूमि उपजाऊ है और हमारे किसान परिश्रमी हैं तथापि हमारे देश में प्रति एकड़ उपज अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है । नीचे दी गई तालिका से यह स्पष्ट हो जायगा :—

देश	गेहूँ	चावल	ईला	कपास
जर्मनी	२०१७	—	—	—
इटली	१३८२	४४६८	—	१७०
जापान	१७१३	३४४४	४७५३४	९६६
अमेरिका	८१२	२१८५	४३२७०	२६८
चीन	९८९	२४३३	—	२०४
भारत	६६०	१२४४	३४९४४	८९

यदि भारत में प्रति एकड़ उपज बढ़ जाय तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ जायेगी और हमारे किसान खुशहाल हो जायेंगे । यह कहा जाता है कि यदि भारत में केवल गेहूँ का उत्पादन प्रति एकड़ फाँट

कराकर हो जाय तो देश की आय १०० करोड़ पौण्ड प्रतिवर्ष बढ़ जायगा। इसी प्रकार यदि प्रत्येक वस्तु का उत्पादन बढ़ जाय तो अनुमान लगाइये देश की आय कितनी अधिक बढ़ जायगी। इसमें हम इस महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारत के कृषक की निधनता का मुख्य कारण प्रति एकड़ उत्पादन बहुत ही कम होना है। अतएव सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इतनी कम उपज का क्या कारण है ?

उस उपज के कारण — विद्वानों के अनुसार भारत में कम उपज का मुख्य कारण निम्नलिखित है —

( १ ) कृषि का अवैज्ञानिक ढंग — संसार के अन्य सम्य तथा उन्नत-शील देशों में जैसे इंग्लैण्ड, रूस, अमेरिका आदि खेती पूर्णतः वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। खेती मशीनों की सहायता से होती है, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मक्कादन। इस कारण एक तो थम का अपव्यय नहीं होता है, दूसरे समय बच जाता है। तीसरे उपज अधिक होती है। इसका साथ-साथ बहारा पर पैदावार बढ़ाने के लिये अच्छी खाद का प्रयोग किया जाता है। अच्छे बीज बोए जाते हैं। परन्तु अगर हम अपने देश में देखें तो यहाँ भी यहाँ १० प्रतिशत खतिहर धर्म ही खेती करते हैं जैसे कि दस हजार वर्ष पूर्व उनके पुरखे करते थे। इससे यह स्वाभाविक है कि उपज कम है। पाश्चात्य देशों में पैदावार बढ़ाने के लिये गति धर्म नई नई विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। वहाँ हमारा अनुसन्धान गणराज्य में इस विषय में काय होता है। परन्तु हमारे देश में इस प्रकार की प्रगतिशीलता का तथा प्रयोगशाळाओं का नितान्त अभाव है। जो कुछ पैदावार होती है उसका एक भाग बीड़ मक्खड़े चूहे टिड्डियों आदि नष्ट कर देते हैं। इनका नष्ट करने का भी अभी तक ठीक प्रबंध नहीं हो पाया। हर वर्ष कई हजार टन अन्न इस प्रकार नष्ट हो जाता है।

( २ ) पैतों का छोटा होना — दूसरा दोष भारत में यह है कि खेत बहुत छोटे-छोटे होते हैं तथा य भी एक ही स्थान में न होकर अलग-अलग बिखरे होते हैं। इससे कई हानियाँ होती हैं। सिंचाई का ठीक प्रबंध नहीं हो सकता है, प्रापस में झगड़े तथा मुकदमे बढ़ते हैं, वैज्ञानिक ढंग प्रयुक्त नहीं किये जा सकते हैं, थम तथा समय नष्ट होता है।

( ३ ) किसान का अशिक्षित होना — भारतीय किसान अशिक्षा का कारण इन प्राथमिक ढंगों से प्रभावित है। वह समझता है कि अगर जमीन में उपज कम है तो यह उसका भाग्य का दोष है। शिक्षा के कारण वह अपना

घन ध्वंस के रीति-रिवाजों तथा विवाह आदि में नष्ट करता है। अधिकांश के कारण वह आधुनिक ढंगों को अपनाने में ही सितकता है।

(४) किसान का ऋण-ग्रस्त होना — अधिकांश से भी बड़ी कठिनाई किसान के भाग में उसका ऋण-ग्रस्त होना है। अधिकतर किसान ऋण के चंगुल में फसे रहते हैं। इसके लिये उन्हें बहुत ऊँचा ब्याज देना होता है। परिणाम-स्वरूप उनकी आमदनी का बड़ा भाग साहूकारों के पास चला जाता है। गाँवों में साहूकारी सस्थाएँ नहीं हैं जो उचित ब्याज की दर पर किसानों को ऋण दें। इस निर्धनता के कारण किसान एक ओर तो आधुनिक साधनों का प्रयोग नहीं कर सकता है और दूसरी ओर निर्धनता के कारण ही उसका जीवन-स्तर अत्यन्त ही नीचा होता है जिसका उसके स्वास्थ्य पर अनिष्टकारी प्रभाव पड़ता है।

(५) लगान तथा मालगुजारी प्रथा :— अभी तक हमारे देश में जमींदारी प्रथा भी दृष्टि की दृष्टि में बाधक थी। क्योंकि विविध रूपों में किसान की आमदनी का एक बड़ा भाग इनकी जेब में चला जाता था। जमीन के ऊपर किसान का कोई स्वामित्व न होने के कारण वह उसके सुधार के ऊपर अधिक ध्यान नहीं देता था। उनमें उत्साह (incentive) की कमी हो जाती है। परन्तु राष्ट्रीय सरकार द्वारा जमींदारी का उन्मूलन कर दिया गया है। इससे आशा है कि स्थिति में सुधार आरम्भ होना।

(६) सिंचाई की उचित व्यवस्था का अभाव :— हमारे देश में सिंचाई की भी अभी तक अनुचित व्यवस्था नहीं है। इसलिये किसानों को अधिकतर बाढ़ों के सहारे रहना पड़ता है। कभी-कभी सूखा पड़ जाता है और कभी-कभी बहुत पानी बरस जाता है। दोनों बचावों में खेती का अधिक हानि पहुँचती है। इसलिये किसान को ऋण लेना पड़ता है और उसकी निर्धनता बढ़ जाती है।

(७) भूमि संरक्षण :— बरसात का पानी जब तेजी से खेतों में से बहता है तो यह अपने साथ-साथ मिट्टी के तत्वों को भी बहा ले जाता है जिसके फलस्वरूप भूमि का उपजाऊपन कम हो जाता है। इसके साथ ही हमारे देश में किसानों की यह भावना है कि वे बरसात के आरम्भ होने से पूरे खेतों में खाद जमा कर देते हैं और उनका यह विचार है कि बरसात का पानी इसे खेत भर में फैला देगा। परन्तु होता यह है कि पानी इसके भी तत्वों को बहा ले जाता है। इसलिये यह आवश्यक है कि खेतों में बरसात के पहले ऊँची मेड़ बना दी जाय जिससे बरसात के पानी के बहाव से उन्हें हानि न पहुँचे।

(८) किसानों का बुरा स्वास्थ्य — यद्यपि एक भारतीय कवि ने लिखा है कि "ग्रहा ग्राम जीवन भी क्या है !" परन्तु वास्तव में हमारे गाँवों का जीवन अनेक कारणों से, जैसे निचैतना, अशिक्षा, बीमारी, गंदगी आदि से उना खराब हो गया है कि उसमें 'ग्रहा' कहने की कुछ भी नहीं बचा है। इसका यह है कि हमारे कृषकों का स्वास्थ्य अत्यन्त ही गिर गया है और इसके फलस्वरूप वे उतना परिश्रम नहीं कर सकते हैं जितना कि अन्य देशों के किसान कर सकते हैं। इसका स्वाभाविक फल यह है कि पैसावार गिरती जा रही है।

(९) पशुओं की बुरी दशा — किसानों के साथ-साथ उनके पशुओं की दशा भी अत्यन्त ही गिर गई है। पशुओं की दशा में इस गिरावट का मुख्य कारण नारे की कमी नष्ट में सुधार न होना, बीमारी, अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रहना, आदि है। जनसंख्या बढ़ने से चराई की भूमि दिन प्रति दिन कम होती जा रही है। ऐसे पशु किसान को खेतों में ठीक प्रकार से सहायता दे सकते हैं।

(१०) अच्छे बीजों तथा खाद की कमी — किसानों के पास अच्छे बीजों का अभाव है वे बाजार से सस्ते बीज खरीद कर बो देते हैं। इन बीजों से अफल बहुत ही कम होती है। सरकार ने स्थान स्थान पर बीज मंडार खोले हैं। किसानों को इन्हीं में से बीज खरीदने चाहिये। बीजों के लिये सहकारी बीज समितियाँ भी स्थापित करनी चाहिये।

अच्छे बीजों के साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि किसान अच्छी खाद प्राप्त करने की भी चप्टा करें। यह स्पष्ट है कि बिना अच्छी खाद से अच्छी फसल नहीं हो सकती है। हमारे किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वह खेतों में डालने के लिए खाद खरीदे तथा वैज्ञानिक खाद का प्रयोग करे। वह गोबर की खाद डालता है। परन्तु गोबर सुखा कर जलाने के काम में अधिकतर लाया जाता है। इससे खेतों के लिये कम अच्छता है। उपज बढ़ाने के लिये अच्छे खाद का प्रबन्ध आवश्यक है।

अच्छे बीजों तथा खाद के अभाव के साथ-साथ प्राकृतिक

हम देखते हैं कि

उ प्रदेशों में पूर्णत

हो सुखा पड़ जाता है। इससे फसल को अत्यन्त हानि पहुँचती है। इसके साथ साथ टिड्डियों का आक्रमण, कीड़े-मकोड़ों से हानि, चूहों का उत्पात आदि भी

खेती को बहुत हानि पहुँचाते हैं। इन समस्याओं पर अभी तक हमारे देश में उचित प्रकार से ध्यान नहीं दिया गया है।

(१२) यातायात तथा विपणन की कठिनाइयाँ — किसान को अपनी उपज बाजार ले जाने तथा वहाँ में अपनी आवश्यकताओं को धन्यु लाने के लिए उचित यातायात के साधन होने चाहिये। परन्तु हमारे देश में यातायात के साधन अभी बहुत पिछड़ी अवस्था में हैं। गाँव को सड़कों में समाप्त में चलना असम्भव हो जाता है। इसलिए किसानों को अपना सामान से जाने या लाने में बहुत कठिनाई होती है। इसके फलस्वरूप वे गाँव में ही अपनी फसल महाजन को बेचने को बाध्य हो जाते हैं और उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता है। यदि वे मण्डी भी पहुँचते हैं तो वहाँ भी बे ठगे जाते हैं। मण्डियों में उनके सामान को खतिरों में रखने की भी सुविधा नहीं होती इससे भी उनका कष्ट बढ़ जाता है। इस कठिनाई का सबसे अच्छा हल यह है कि किसान सहकारी समितियों की सहायता लें।

सुधार के उपायः—स्वतन्त्र भारत के सम्मुख प्रथम समस्या भ्रष्ट की थी। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् यह समस्या अत्यन्त ही गम्भीर रूप में उपस्थित हुई। भारत सरकार को लाखों टन धन बाहर से मँगाना पड़ा और हमारा करोड़ों रुपया विदेशी को इस कारण चला गया। इस समस्या का हल करने के लिये सरकार ने "अधिक भ्रष्ट उपजाओं" आन्दोलन चलाया। नई नृमि को हल के नीचे लाया गया। अच्छे बीज तथा उत्तम खाद का प्रवर्धन भी सरकार ने किया। किसानों को खेती के बारे में बतलाने के लिये भी कुछ काम किया गया।

राष्ट्रीय सरकार ने खेतों की विभाजन तथा उप-विभाजन को रोकने के लिये कानून बनाए हैं। खेतों की चकबन्दी के लिये कई प्रादेशिक सरकारों ने अधिनियम बनाए हैं उदाहरणार्थ, बम्बई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली आदि। इसी प्रकार सरकार ने सहकारी कृषि को प्रोत्साहित करने की दिशा में भी पग उठाया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि 'निम्न तथा मध्य वर्ग के किसानों को राज्य सरकारों द्वारा प्रोत्साहन तथा सहायता मिलनी चाहिये जिससे वे सहकारी कृषि समितियाँ बनायें।' दिल्ली मद्रास, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के राज्यों में इस दिशा में कुछ काम हुआ है। सन् १९५३ में दिल्ली में भारत के विभिन्न प्रदेशों के कृषि मन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ था तथा उसमें इस प्रश्न के ऊपर विचार किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में २४३ करोड़ रुपये तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३५० करोड़ रुपये कृषि सुधार तथा उत्पत्ति के लिए रखा गया है।

कृषि की उन्नति के लिये भूमि क्षरण ( Soil Erosion ) की समस्या को भी हल करना आवश्यक है। यह समस्या इतनी गम्भीर हो गई है कि कुछ विशेषज्ञों के अनुसार भूमि क्षरण भारत में कृषि का प्रमुख शत्रु है। अनुमानत ११ करोड़ एकड़ भूमि को इससे द्वारा क्षति पहुँच रही है। भारत की सरकार इस समस्या पर ध्यान दे रही है। एक भूमि संरक्षण बोर्ड स्थापित किया गया है। भारत सरकार द्वारा १९५४-५५ में कुछ योजनाओं को इससे लिए चालू करने की आज्ञा दी गई है। रेगिस्तान को रोकने के लिए जंगल लगाने के कार्य को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत के कई राज्यों में भी इस समस्या का संज्ञान के लिये काम हो रहा है।

सरकार द्वारा सिंचाई की उचित व्यवस्था का भी प्रबन्ध किया जा रहा है। नहर काले सलाबा के अतिरिक्त इस समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार ने कई बहु-उद्देशीय योजनाएँ बनाई हैं। ये कई उद्देश्यों को पूरा करेंगी जैसे सिंचाई, बाढ़ रोकना बिजली पैदा करना आदि। ये योजनाएँ निम्नलिखित हैं।

योजना का नाम	मीचा जाने वाला क्षेत्र	बिजली का उत्पादन (किलोवाट)
१—दामोदर घाटी	७,६०,०००	३,५०,०००
२—मोर योजना	६,००,०००	४,०००
३—बोसी योजना	३०,००,०००	१८,००,०००
४—महानदी योजना	२५,००,०००	५,००,०००
५—रेहण्ड योजना	६,३५,०००	१,७०,०००
६—नमदा योजना	३७,००,०००	१०,००,०००
७—ताप्ती योजना	७,००,०००	४८,०००
८—चम्बल योजना	२,००,०००	२००,०००
९—भाकरा योजना	४५,००,०००	१,६०,०००
१०—रामपद सागर योजना	१६,००,०००	७५,०००
११—तुंगभद्रा योजना	३,००,०००	८०,०००
१२—गोडी कोटा योजना	१,००,०००	—
१३—लोघर भवानी योजना	२,००,०००	—
१४—भद्रा योजना	१,८०,०००	१७,०००
१५—जवाई योजना	१,१०,०००	४,५००
१७—नीयर योजना		१,००,०००



प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भी सिंचाई के लिए काम किया गया। मार्च १९५४ तक २८ लाख एकड़ से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई है।

किसानों को साख की सहायता भी सरकार द्वारा दी गई है। इसके लिये अनेक उपाय किये गये हैं। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि सम्बन्धी अल्प-कालिक साख का प्रबन्ध प्रायः प्रादेशिक सरकारों तथा सहकारी समितियों द्वारा हुमा है।

कृषि की उन्नति के लिए तथा किसानों की समस्या में सुधार के लिये जमींदारी उन्मूलन भी आवश्यक था। प्रादेशिक सरकारों ने इस दिशा में प्रशंसा योग्य काम किया है। बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, आन्ध्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, मध्य भारत, पेश्व, सौराष्ट्र, भोजाल तथा दिण्ध्य-प्रदेश में जमींदारी प्रथा की समाप्ति पूर्णतः या आंशिक रूप में की जा चुकी है।

कृषि की उन्नति के लिये यह भी आवश्यक है किसानों की कृषि सम्बन्धी शिक्षा तथा साधारण शिक्षा देने का प्रबन्ध हो। उन्हें वैज्ञानिक ढंग से खेती करने की उत्साहित किया जाय। उनके स्वास्थ्य में सुधार हो तथा जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो।

## गाँवों का जीवन तथा उनकी समस्याएँ

इस स्थल पर यह उचित प्रतीत होता है कि हम अपने गाँवों की दशा का अवलोकन करें। भारत कृषि-प्रधान देश होने के कारण गाँवों का देश है। कार्य-शील जनसंख्या का ६८ प्रतिशत भाग खेती पर निर्भर है। हमारी जनसंख्या का अनुमानतः तीन-चौथाई भाग गाँवों में रहता है। भारत की आत्मा गाँवों में रहती है। बहुधा यह कहा जाता है कि आधुनिक भौतिक-सभ्यता से परे भारत के गाँव आदर्श जीवन के चित्र हैं। परन्तु वास्तव में गाँवों की दशा शोचनीय है। बीसवीं शताब्दी में भी ये अज्ञान में डूबे हैं। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रत्येक दृष्टि से वे पिछड़े हैं। शिक्षा तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उनकी समस्या अच्छी नहीं है। गाँवों का सुधार अत्यधिक आवश्यक है। अंग्रेजी शासन के पूर्व गाँवों की इतनी दुरवस्था नहीं थी। परन्तु अंग्रेजी काल में जब गाँव भी साम्राज्यवादी-शोषण की चक्की में पिसने लगे तो उनकी आर्थिक समस्या प्रतिदिन विगड़ती गई। उनके गृह-उद्योगों का नाश हो गया। परन्तु अंग्रेजी सरकार ने इनके पुनर्स्थापन की ओर ध्यान नहीं दिया।

जब गांधी जी ने भारतीय राजनैतिक-आन्दोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लिया तो उन्होंने यह देखा कि गांधी जी चेतना का संचार हुये बिना भारत की स्वाधीनता प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिये उन्होंने बारम्बार गांधी की स्वच्छा सुधारों पर जोर दिया। उन्होंने गृह-उद्योगों की पुनर्स्थापना पर जोर दिया ताकि गांधी स्वयंलम्बी हो सके। उन्होंने प्राचीन-व्रतों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य की ओर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। गांधी में भी राजनैतिक चेतना बढ़ी और हजारों किसानों ने आन्दोलन में भाग लिया।

अंग्रेजी सरकार ने सन् १९३४-३५ में १ करोड़ रुपया गांधी के विकासार्थ मजूर किया। जब सन् १९३७ में कांग्रेस ने पद-ग्रहण किया तो हमन गांधी की दशा सुधारने की ओर विशेष ध्यान दिया। कांग्रेस मन्त्रिमण्डल ने गांधी की आर्थिक तथा सांस्कृतिक उन्नति को चेष्टा की। परन्तु इस दिशा में यह केवल पहला पग था। अगर कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बने रहते तो इस दिशा में और प्रगति होती। परन्तु सन् १९३९ में कांग्रेस ने युद्ध प्रारम्भ होने पर पद त्याग कर दिया। अंग्रेजी सरकार इस काल में युद्ध के प्रतिरिक्त किसी अन्य बात की सोच ही नहीं रखी थी। इसलिए सन् १९४७ तक ग्रामसुधार की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

जब मे कांग्रेस ने फिर कार्य भार संभाला है इस दिशा में फिर प्रगति आरम्भ हो गई है। यद्यपि यह मरम है कि जितना सुधार का डोल पीटा गया है उसकी तुलना में काम का हुंसा है। तथापि फिर भी कुछ तो प्रवृत्ति ही हुआ है। प्रादेशिक सरकारों ने अपने अपने प्रदेशों में ग्रामोत्थान के लिये चेष्टा की है। गांधी वालों की शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्न सम्बन्धी कठिनाइयाँ, अच्छे बीज तथा खाद, आदि बातों की ओर ध्यान दिया जा रहा है। जमींदारी उन्मूलन की दशा में भी प्रगति हुई है। सहकारी समितियों की भी स्थापना की जा रही है। पंचायतों की भी स्थापना की जा रही है। इनसे दो लाभ होंगे। एक हा यह कि गांधी वालों के बहुत से मुकदमे बड़ी गर तप हो जायेंगे और उनका समाधान नष्ट होने से बच जायगा। दूसरा यह कि गांधी वाले अपनी समस्याओं को सलझाने में सक्रिय भाग लेंगे। पंचायतों के विविध कार्यों का वर्णन पहले किया जा चुका है।

गांधी के निवासियों को दो भागों में बाँट सकते हैं—बिस्वाम तथा भूमिहीन श्रमिक (landless labourers)।

प्रायःकल यह बहुधा कहा जाता है कि किसानों की समस्या पहले से बहुत अच्छी हो गई है और वे मालामाल हो गये हैं। क्योंकि साक्षर-कर्मियों तथा अन्य

फसलों के भी दाम ही बड़ गये हैं। प्रत्येक वस्तु जैसे गेहूँ, चावल, चना, दाल, गन्ना आज बहुत महँगे हो गए हैं। इसमें नत्थ का एक बड़ा है। जिन किसानों के पास इतनी भूमि है कि वे उत्तम अपनी आवश्यकता से अधिक अन्न उत्पन्न करते हैं, उनकी प्रवृत्ति पहले की अपेक्षा अच्छी है। क्योंकि वे अतिरिक्त पैदावार को ऊँचे दामों में बेच सकते हैं। परन्तु जिन किसानों की भूमि से उनकी आवश्यकता को पूरा करने योग्य मात्र अन्न नहीं उत्पन्न होता है उनकी दशा और बिगड़ गई है क्योंकि उन्हें महँगे दामों में गल्ला खरीदना पड़ता है। ऐसे किसानों की समस्या कम नहीं है। जो किसान अतिरिक्त गल्ला पैदा करते हैं उनकी भी उत्तम साम नहीं हुआ जितना कि होना चाहिये क्योंकि वह अपना माल उपयुक्त स्थानों पर नहीं पहुँचा पाते हैं, और जमींदार या साहूकार को बेच देते हैं जो कि उन्हें उपयुक्त कीमत नहीं देते हैं। जब हम भूमिहीन श्रमिक की ओर इष्टिपात करते हैं तो उसकी प्रवृत्ति और भी खराब पाते हैं, क्योंकि उसकी भाय का साधन दूसरे के खेतों में मजदूरी करना है। इस कारण से वे केवल आधे साल ही काम कर सकते हैं और बाकी समय उन्हें कोई काम नहीं रहता है।

उपरोक्त बातों (facts) को ध्यान में रखते हुए यह कहना असंगत नहीं होगा कि भारतीय किसान निषेध है। संक्षेप में उनकी निषेधता का कारण यह है कि खेती में उनकी पर्याप्त भाय नहीं होती है। खेती की पिछड़ी दशा के कारणों का वर्णन हम कर चुके हैं। किसान को सारी कठिनाई यह है कि वह अपनी पैदावार को उचित दामों में नहीं बेच सकता है। यातायात की असुविधाओं के कारण बहुधा वह इनकी मण्डियों तक न ले जाकर गाँव में ही जमींदार या साहूकार के हाथ बेच देता है। वे कभी भी उचित दाम नहीं देते हैं। वर्ष भर में किसान कई महीने बेकार रहता है। फसल कट जाने के बाद उसकी काम नहीं रहता है। खाली दिनों को वह व्यर्थ नष्ट करता है। क्योंकि गाँव में कोई अन्य उद्योग न होने के कारण यह समय बेकार नष्ट हो जाता है। शिक्षा के कारण किसान को अरुने समय का ठीक उपयोग ही नहीं मालूम है। इसी कारण वह अपने धन को उचित प्रकार से व्यय नहीं करता है। साल भर वह सूखी रोटी खाता परन्तु शादी-ब्याह के अवसर पर बर्बादों रुपया व्यय करने को देता है। इसके लिए वह ऋण लेने से भी नहीं चूकता है। और एक समय ऋण लेकर वह कई वर्षों तक साहूकार के चंगुल से नहीं छूट सकता है। मुकदमों में भी किसानों का बहुत सा धन भ्रष्ट हो जाता है। खेती के अतिरिक्त किसानों की भाय का दूसरा स्रोत पशुपालन है। परन्तु इनने भी किसान पूरा लाभ नहीं उठा सकता है। उसके पशु चारे के बर्बाद के कारण भ्रष्ट हो जाते

है। बीमारी के कारण बहुत से पशु नष्ट हो जाते हैं। शिक्षा के कारण किसान उनकी नस्ल सुधारने की चेष्टा नहीं करता। मच तो यह है कि वह अपना जीवन तथा माय-साध अपने पशुओं का जीवन भाग्य के हाथों में छोड़ देता है। भारत में पशुओं की संख्या कम नहीं है। परन्तु उनसे पूरा लाभ नहीं उठाया जा रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का किसान न अपने खेत में और न अपने पशुओं में ही पूरा लाभ उठा सकता है। इन सबों के उपर यह धड़नाई है कि जो कुछ उसकी आय होती है उसका एक बड़ा भाग साहूकार या जमींदार हूट लेता है। सरकारी लगान भी किसान के लिये बहुत भारी है।

**सुधार के उपाय --** किसानों की अवस्था में सुधार आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित सुधार करने चाहिए

( १ ) किसानों को इस बात के लिये उत्साहित करना चाहिए कि वे सहकारी खेती (co operative farming) के लिये तैयार हों। बड़े बड़े खेतों में मशीनों के द्वारा खेती हो सकती है। सरकार उनकी मदद देकर स्टेशन खोलकर, अच्छे बीज तथा खाद के वितरण का प्रबन्ध कर, तथा उनको खेती के बारे में शिक्षा देकर कर सकती है।

( २ ) किसानों को साहूकारी के चंगुल से मुक्त करने तथा उनकी उपज का उचित दामो में बिकवाने के लिये सहकारी समितियों की अधिक से अधिक संख्या में स्थापना की जाय। सहकारी समितियों के द्वारा ऋण व्याज की सस्ती दरों में मिल जाता है। क्योंकि किसान स्वयं सहकारी समिति का सदस्य होता है इसलिए दोनों ओर से एक दूसरे के प्रति सौहार्द की भावना रहती है। ऋण देने का उद्देश्य व्याज कमाना न होकर किसान की सहायता करना होता है। ये सहकारी समितियाँ किसान को पैदावार को भी उचित दामो में खरीदेगी। जो कुछ लाभ इस प्रकार समिति को होगा उसका किसान भी हिस्सेदार होगा।

( ३ ) सरकार की ओर से किसानों के पशु धन में सुधार के लिए भी भरमक प्रयत्न होना चाहिये। किसानों में इस विषय का ज्ञान फैलाना चाहिए तथा पशुओं के अस्पताल खोलने चाहिये। किसानों को यह भी बतलाना चाहिए कि पशुओं से जीवन अवस्था में तथा मरने के बाद भी क्या क्या लाभ उठाए जा सकते हैं।

(४) जमींदारी का पूर्ण रूप से तन्मूलन करना चाहिये। इसमें विनानों का कोई प्रकार के लाभ होंगे। भूमिहीन श्रमिकों को भी भूमि देने का प्रयत्न करना चाहिये। विनोबा जो का भूमि-दान आन्दोलन इस दिशा में एक पग है।

(५) सरकार को गांवों में गृह-उद्योगों की स्थापना की ओर ध्यान देना चाहिये। इसमें किसान गाली मसम में भी बंकार बैठ न रह कर कुछ काम करता रहेगा। गांवों में शहर बिजली का प्रवन्ध हो जाये तो इन छोटे छोटे गृह-उद्योगों को चलाने में बड़ी सहूलियत होगी।

(६) गांवों में शिक्षा की उन्नति तथा स्वास्थ्य की उन्नति के लिये भी पूर्णरूपेण प्रयत्नशील होना चाहिये। हमारी सरकार ने इस दिशा में काम आरम्भ किया है। शिष्यों को भी उपयोगी शिक्षा देनी चाहिये।

(७) देश में औद्योगिकीकरण की वृद्धि होनी चाहिये। जितना अधिक उद्योगों का विकास होगा उतना ही भूमि पर भार कम होगा। इस समय जब ६८ प्रतिशत कार्यशील जनसंख्या का भाग कृषि पर निर्भर है, औद्योगिक व्यवसायों में केवल १४ प्रतिशत भाग लगा है। कम से कम ऐसा होना चाहिये कि कृषि तथा उद्योगों पर निर्भर जन-संख्या में घुसने से अधिक का भेद न हो।

**भूमि-दान आन्दोलन** — जैसा कि इस पक्ष ने ज्ञात होता है भूमि-दान का अर्थ है कि स्वेच्छा से भूमि का दान किया जाय। यह आन्दोलन देश में आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाया गया है। इसका जन्म १८ अप्रैल १९५१ को हुआ। इसके जन्म का प्रत्यक्ष कारण यह था कि भूतपूर्व हैदराबाद राज्य के तेलंगाना जिले में किसान आन्दोलन ने हिमात्मक रूप धारण कर लिया था। किसानों ने जमींदारों की भूमि पर बलपूर्वक अधिकार कर लिया था। सरकार ने उस प्रवृत्ति काय को बस प्रयोग द्वारा रोक दिया। इससे जन-धन की हानि हुई। यह आन्दोलन भारतीय साम्यवादी दल द्वारा चलाया गया था। आचार्य भावे ने इस जिले का दौरा किया और यही पर उन्हें यह विचार आया कि भारत में भूमि की समस्या को गांधी जी के अहिमात्मक सिद्धान्त के अनुसार हल करना चाहिये।

इस आन्दोलन के उद्देश्यों के विषय में आचार्य विनोबा भावे ने कहा है, “समाज के न्यायोचित संगठन में भूमि पर सबों का अधिकार होना चाहिये। यही कारण है कि हम दान की भीषण नहीं मांगते हैं, लेकिन भूमि में उस भाग को मांगते हैं जो कि न्यायोचित रूप से निर्दोशों पर गण्य है।” इस आन्दोलन

का ध्येय जो समान में भूमि का अन्यायपूर्ण वितरण है उसे शान्तिपूर्ण रूप में बदलना है।

आचार्य विनायक भाव ने अपने ग्रान्दोलन को चलाने के लिये देश के कई भागों को पद यात्रा की है। प्रत्येक राज्य में उन्हें कुछ न कुछ भूमि प्राप्त हुई है जिसे कि भूमिहीनों के मध्य वितरित कर दिया जाता है। विमम्बर १९५७ तक उन्हें ४०८० लाख एकड़ भूमि प्राप्त हो चुकी थी। इसमें से ६५४ लाख एकड़ भूमि विनश्वित कर दी गई थी। इस वितरण से दो लाख से अधिक कुटुम्बों को लाभ हुआ है।

यदि यह ग्रान्दोलन अपने उद्देश्यों में सफल हो जाय तो एक महान प्रयोग सफल हो जायगा। भारत सरकार ने इस ग्रान्दोलन को पूरी पूरी सहायता दी है। भूदान के साथ साथ ग्रामदान, सम्पत्ति-दान, जीवन दान, बुद्धि-दान तथा श्रमदान भी विनोबा जी द्वारा प्रारम्भ कर दिये गये हैं।

मार्च १९५७ के अन्त तक भारत के विभिन्न प्रदेशों में विनोबा जी को ३५४३ ग्रामों का दान मिल चुका है। इसका विवरण निम्नलिखित है।

आसाम	७७		
आंध्र	२७०	मैसूर	१५
बिहार	९७	उड़ीसा	१९३३
बम्बई	३८०	राजस्थान	१४
केरल	४५१	उत्तर प्रदेश	६
मद्रास	२४८	पश्चिमी बंगाल	८
मध्य प्रदेश	६४		

यदि ग्रामदान ग्रान्दोलन को व्यापक सफलता मिली तो इससे देश का पुनर्निर्माण तथा ग्रामोत्थान के कार्य में अत्यन्त सहायता प्राप्त होगी। ग्रामदान द्वारा एक नवीन सामाजिक व्यवस्था की जो कि समानता तथा सहकारिता पर आधारित हो, स्थापना होने का समाधान है।

### (व) उद्योग-धन्धे

भारत आज ससार के प्रमुख औद्योगिक देशों की कौटि में नहीं है, परन्तु प्राचीन काल तथा मध्य काल में भारतीय उद्योग धन्धे बहुत उन्नति की अवस्था में थे और उस समय भारत इस दृष्टि से भी ससार के देशों में अग्रणी था। उस समय हमारे देश में गृह-उद्योग बहुत ही उन्नति कर चुके थे और यहाँ की

बनी वस्तुएँ बाहर के देशों में विक्रयी थी। उस समय यहाँ चातु की नाना प्रकार की वस्तुएँ, तथा विविध प्रकार के रेशमी और सूती कपड़े बनने लगे थे। यहाँ की बनी वस्तुएँ योरोप में राजाओं तथा भूमिदारी की अवश्यकताओं की पूर्ति करती थी। मध्यपूर्व के देशों से भी भारत के व्यापारिक सम्बन्ध थे। यह दशा अठारहवीं शताब्दी तक रही। जब धीरे-धीरे यहाँ यूरोपीय व्यापारी आये उनका उद्देश्य यहाँ की बनी वस्तुएँ ले जाकर यूरोप में मूल्य दोगुने में बेचना था कि वहाँ की बनी वस्तुएँ हमारे देश बेचना।

अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप छोटे-छोटे कारखानों के स्थान में बड़े-बड़े कारखाने स्थापित हुए। इनमें मशीन माल से चलने लगी। इन मशीनों के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में वस्तुएँ पैदा की जाने लगी। परन्तु भारत में इस प्रकार का कोई परिवर्तन वस्तुओं के उत्पादन में नहीं हुआ। इस कारण जब विदेशियों ने अपना माल भारत में बेचना शुरू किया तो वे अपनी चीजों को बहुत सस्ते दामों में बेच सकते थे। इस कारण भारत के उद्योग पेशों को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी। इसके प्रति रिचर्ड ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारतीय उद्योग पेशों को नष्ट करने का पूरा प्रयत्न किया। कम्पनी के कर्मचारियों के अत्याचार से हजारों कारीगर तबाह हो गये। विलायत में यहाँ की सरकार ने भारत की बनी चीजों पर बहुत ही अधिक कर लगाया। भारत के बने रेशमी तथा सूती कपड़े पर मसूर में लेकर मसूर प्रतिशत तक कर लगाया और बाद को उनका भागा ही बन्द कर दिया। इस समय भारत में भी रहन-सहन में पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण परिवर्तन हो रहा था। विदेशी सामानों की देखादेखी यहाँ के पश्चिमी सभ्यता के प्रभावित वर्ग ने भी विदेशी माल को अपनाना आरम्भ कर दिया। देश में राजाओं तथा रियासतों के नाश हो जाने से भी उद्योग-पेशों को बहुत हानि उठानी पड़ी।

1. "The gossamer muslin of Dacca, beautiful shawls of Kashmere and the brocaded silks of Delhi adorned the proudest beauties at the courts of the Caesars. When the barbarians of Britain were painted savages, embossed and filigree metals, elaborate carvings in ivory, ebony and sandal wood; brilliant dyed chintzes uniquely set pearls and precious stones, embroidered muslins, and the like, were the only articles of dress, excellent in their kind, and in their use. In the reigns of the Caesars, the most beautiful of the world was known to the world."—

इन चीजों का परिणाम यह हुआ कि उद्योगवी जनान्दी में भारतीय उद्योग धंधे पूरन नष्ट हो गये और भारत केवल रतितर देश हो गया। भारत से बच्चा माड इग्लैंड जान लगा और वहाँ से बनी वस्तुएँ (finished goods) भारत में आने लयी।<sup>1</sup> और आयात की सुविधाओं में उन्नति के कारण इग्लैंड में अधिनाधिक माड भारत में आने लगा। सन् १८५३ में इग्लैंड से भारत में म ८०२४००० पाँड का माल भेजा गया। इसमें ५२२०००० पाँड का वषडा था। अन्य प्रकार का विदेशी माल जैसे लोहे, तंबे, पीतल के बरतन चडियाँ चाय कैंची तथा सीसा आदि भी इतनी अधिक मात्रा में भारत में आने लगे कि यहाँ के प्राचीन कारीगरो का रोजगार लभ हो गया। इसका फल यह हुआ कि अधि आधिक व्यक्ति भूमि पर निर्भर होते चके गये। सरोप में अंग्रेजों की औद्योगिक तथा व्यावसायिक नीति का फल यह हुआ कि हमारे देश में उद्योग धंधा का पुराना संगठन तो नष्ट हो गया परन्तु उसके स्थान में नया तथा उत्तम श्रेष्ठ संगठन नहीं बना।

**भारत में उद्योग धन्धों का विकास** — सन् १८५० के बाद भारत में मशीना के उद्योग स्थापित होन शुरू हुए। सन १८५०-१८५५ के बीच पहिली कपडे की मिल स्थापित हुई। इसी समय पहली रल की लाइनें भी बिछाई गई। सन १८७५ में भारत में ५१ कपडे की मिलें हो गई थी। सन् १८९० में ये वहाँ जूट की मिलें टाल गई थी। इस प्रकार १९वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में धीरे-धीरे भारत में नये उद्योग धन्धा की बीज पड रही थी। परन्तु इसी समय भारत अधिकाधिक बच्चा माल इग्लैंड से भज रहा था तथा बरले में वहाँ की बनी चीजें सरीद रहा था। २०वीं शताब्दी में भारत में लोहे तथा कागज के कारखाने गये। पहले इनका उत्पादन बहुत कम था परन्तु यह धीरे धीरे बढ़ता गया। देश में राजनितिक आन्दोलन के बढ़ने के साथ-साथ स्वदेशी की भावना बढी तथा हमारे परिणामस्वरूप भारत का औद्योगिक विकास प्रविष्ट हुआ। सन १९१४ में भारत में २६४ कपडे की मिलें तथा ६४ जूट की मिलें हो गई थी। कोयले का उत्पादन भी बढ रहा था। यह करीबन एक

1 In the 19th century, India became a country growing raw product to be shipped by British agents in British ships to be worked into fabrics by British skill and capital and to be re-exported into India by British merchants to their corresponding British firms in India and elsewhere "Ranade—Essays in Indian Economics, p 106



करोड़ अट्ठावन लाख टन हो गया था। सन् १९१८ में १२४,००० टन फौलाद भारत में पैदा होने लगा था। मशेष में हमारी औद्योगिक उन्नति हो रही थी।

गांधी जी ने देश में गृह-उद्योगों की पुनर्स्थापना की ओर ध्यान दिया। उन्होंने खहर का प्रचार किया। वे बड़े उद्योगों के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने प्रामोद्योग संघ की स्थापना की। इस काल में गृह-उद्योगों ने उन्नति की यद्यपि वह कई कारणों से मूलोपजनक नहीं हुई। द्वितीय महायुद्ध के काल में भारत ने नये उद्योगों की स्थापना हुई। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् हमारी सरकार ने इन ओर भी ध्यान दिया है। देश की उन्नति के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनाई है। परन्तु अभी इस दिशा में अधिक गफ़लत नहीं मिली है। देश में इन समय एक आर्थिक-संकट छा गया है। आशा है धीरे-धीरे अवस्था में सुधार होगा।

नीचे उद्योग-वर्गों की समस्याओं का वर्णन किया जायगा। उद्योग-पक्षों को दो कौटियों में विभाजित किया जायगा—गृह-उद्योग तथा बड़े पैमाने के उद्योग। दोनों का क्रमशः वर्णन किया जायगा।

## गृह उद्योग

भारत में बड़े-बड़े कारखाने केवल ०.६ प्रतिशत जनता को काम देते हैं जब कि गृह उद्योगों में ९६ प्रतिशत जनसंख्या लगी हुई है। इन आँकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में मो वष की औद्योगिक उन्नति के पश्चात् भी गृह उद्योगों की ही प्रधानता है। इस समय यह अनुमान है कि लगभग २.१ करोड़ व्यक्ति गृह-उद्योगों में लगे हैं।

विस्तृत अर्थ में गृह-उद्योगों में तात्पर्य सब छोटे पैमाने वाले (small scale) उद्योगों में है। परन्तु मरुचित अर्थ में इसका तात्पर्य उन उद्योगों से है जिनकी कारीगर अपने घर में या घर से गरी निमोणशालाओं में एक दो सहायकों की सहायता से करता है।<sup>१</sup>

१. "The cottage industries are defined as industries where no power is used and the manufacture is carried on in the home of the artisan." Wadia Merchant, Our Economic Problem, p. 492, f.n.

जैसा पहले लिखा जा चुका है गृह-उद्योग का उन्नत करने की सबसे बड़ी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये किसानों के गृहायक आमदनी का स्रोत है। किसानों को अधिकतर अपने समय खर्चीला रहना है। यह समय व्यर्थ नष्ट होता है। अगर हम समय का किसी प्रकार ठीक उपयोग हो सके तो किसान को बड़ा लाभ है। इसके लिए ऐसी गृह उद्योगों की उन्नति करना चाहिए जिनसे कि किसान अपने ही गाँव में रोज़गार अवकाश के समय कर सकता है। हमें उद्योग निम्नलिखित हैं हाथ की बनाई तथा बुनाई गूँड़ बनाना, टोकरियाँ तथा चटाई बुनना, रस्सी बनाना पट्टे पान्ना तैल पेरना आदि। बहुत से व्यक्ति गाँवों से शहरों में जाना पसंद नहीं करते। क्योंकि शहरों में खर्च अधिक होता है तथा वहाँ रहने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी रोज़गार अपने समय का उचित उपयोग विभिन्न प्रकार के गृह उद्योगों द्वारा कर सकते हैं। हम उनका काम मिल जायगा तथा जीवन की समस्या हल हो जायेगी। हम गृह उद्योग स्वयंसेवकों के रूप में किए जाने चाहिये, जैसे चमड़े का काम, धातु का काम मिट्टी का काम दरी या कम्बल बुनना आदि। इनके प्रतिरिक्त अन्य कई गृह उद्योग हैं जिनके लिए पुरस्ती आवश्यकता है और जो गाँवों तथा शहरों में विशेष यहाँ द्वारा किए जाते हैं। गृह-उद्योगों का एक लाभ यह भी है कि औरतें घर बैठे माली समय में लाभदायक काम कर सकती हैं। जहाँ-जहाँ में दियासलाई बनाने का उद्योग इसी प्रकार से किया जाता है। हम औरतें इस प्रकार का काम करने लगेंगी तो हमसे घर की आमदनी बढ़ जायगी तथा जीवन-स्तर ऊँचा हो जायेगा। आजकल जो बड़े-बड़े कारखाने हैं उनमें हजारों व्यक्ति काम करते हैं तथा वहाँ का वातावरण धूल, गर्मी तथा शोर व कारण अत्यन्त दुषित हो जाता है। परन्तु गृह-उद्योगों में हम प्रकार के दुषित वातावरण का सामना नहीं करना पड़ता है।

## कुछ मुख्य गृह-उद्योग

सूत कटाई तथा बुनाई — भारतवर्ष में यह उद्योग बहुत ही पुराना है। सूत बनाना तो अब लाभदायक उद्योग नहीं रह गया है क्योंकि मित्रों का बना सूत हाथों से बने सूत से अधिक मजदूर तथा पतला होता है। चर्मी आन्दा लन में सूत बनाने का उद्योग कुछ बड़ा अवश्य परन्तु इसकी उन्नति मित्रों के मुकाबले में अत्यन्त कठिन है। परन्तु कपड़ा बुनने का उद्योग अभी तक प्रचलित है तथा इसमें और उन्नति हो सकती है। हाथ से कपड़ा बुनने के उद्योग तथा मित्रों में कोई प्रत्यक्ष प्रतियोगिता नहीं है। क्योंकि हाथ से अधिकतर विशेष प्रकार का कपड़ा बुना जाता है—अत्यन्त महीन या अत्यन्त मोटा। इस

प्रतिरिक्त हाथ ने कपड़ा बुनने का उद्योग मिलों में मृत पर ही निर्भर है। यह कहा जाना है कि अब भी देश में जितने कपड़े की तपत है उसका चौपाई हाथ का बना कपड़ा होता है। भविष्य में जब देश में कपड़े की मिलें बहुत से जावेंगी तब हाथ के बुने कपड़े की मागद मांग न रहे या बहुत घट जावे, जावे, परन्तु इस समय इसको पुनर्नव्यक्ति करने से किसानों में अत्यन्त लाभ होगा। भारत की सरकार तथा प्रादेशिक सरकारें दोनों ही इन उद्योगों को बढ़ाने का प्रयत्न कर रही हैं।

**गुड़ बनाने का उद्योग**—देश में यद्यपि चीनी बहुतायत में पैदा होती है तथापि यह समस्त देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके प्रतिरिक्त इसके नाम भी काफी बड़ गये हैं। इसलिये गुड़ बनाने के उद्योग को प्रोत्साहित करना चाहिये। इससे किसानों की घामदानी बढ़ेगी और लोगों को शक्कर के स्थान में कच्चे दानों में गुड़ उपलब्ध हो जावेगा। इन उद्योगों का भविष्य बहुत अच्छा है। परन्तु एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो बनाया जाय वह नाक हो। सरकार ने इन उद्योगों में सुधार करने की ओर ध्यान दिया है।

**टोकरी बुनना तथा चट्टाई बुनना**—टोकरों बुनने का काम अधिकतर बनारस तथा इलाहाबाद के जिलों में होता है। चट्टाई बुनना मद्रास तथा कासाम में अधिक प्रचलित है। इन उद्योगों के द्वारा भी किसान अपने गाली समय को व्यर्थ न कर अपनी आय बढ़ाने का उपाय कर सकता है इस उद्योग को देश के अन्य भागों को भी अपनाया चाहिए। औरतें घर बैठे-बैठे ये काम कर सकती हैं।

**पशु-पालन**—पशुओं में कई लाभ हैं—एक तो यह कि इनके गोबर की खाद बनती है जो कि खेतों के लिए आवश्यक है, दूसरे यह कि इनसे घी, दूध, मखन की प्राप्ति होती है जिनकी दंग में बहुत माँग है, दूसरे और इससे किसान को अच्छा लाभ हो सकता है। तिसरे यह कि पशुओं के मरने के बाद उनका चमड़ा बेचा जा सकता है, आदि। हमारे देश में पशुओं को नस्ल में सुधार करने, उनके स्वास्थ्य की जाँच करने, यदि बातों की ओर कुछ तो किया गया है परन्तु यह अत्यन्त

---

1. प्रसिद्ध अमेज अर्थशास्त्री Cole ने लिखा है, "Gandhi's campaign for the development of the home-made cloth industry—khaddar—is no mere fad of a romantic eager to revive the past, but a practical attempt to relieve the poverty and uplift the standard of the Indian villager." A Guide to Modern Politics, p. 234.

में हुई है उमंगें बं भ्रान्तिभिन्न हैं। इस कारण जो माल बे वनाते हैं वह नये प्रकार का न होकर वैसा ही होता है जैसा कि उनके पूर्वज वनाते थे। उमंगें किसी प्रकार की नवीनता का अभाव होता है। दूसरी कठिनाई यह है कि इन कारीगरों को ठीक दम का कच्चा माल आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। चूँकि कच्चा माल नहीं मिलता है इसलिए गृह-उद्योगों में निर्मित वस्तुएँ स्वभावतः ही बहुत अच्छी नहीं होंगी। तीसरी कठिनाई यह है कि कारीगरों को रुपये की कठिनाई है। इस कारण माल नहीं खरीद सकते हैं और बुरे माल से ही काम चलाते हैं। जो कुछ रुपये वे उधार लेते हैं उसमें उन्हें बहुत अधिक व्याज देना पड़ता है। जीवन भर वे अपने ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं। चौथी कठिनाई यह है कि गृह उद्योगों में निर्मित वस्तुओं के ठीक प्रकार से प्रचार की व्यवस्था नहीं है। इस कारण उनके लिए माँग नहीं बढ़ रही है।

घर में गृह-उद्योगों को उन्नत करना है तो इन कठिनाईयों को दूर करना चाहिये। इसलिये कारीगरों की शिक्षा का उचित प्रबन्ध करना चाहिए। टेक्निकल शिक्षा की उनके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। इसका लाभ यह होगा कि वे नए-नए डिजाइन की वस्तुएँ बना सकेंगे। इन वस्तुओं की अच्छी बिक्री होगी। इस निम्न के साथ कारीगरों को पुराने औजारों के स्थान में नये औजारों का प्रयोग करने के लिए उत्साहित करना चाहिए। इसलिये सरकार को औद्योगिक शिक्षण मस्थाएँ तथा निर्माणशालाओं की स्थापना करनी चाहिए। जहाँ नए औजारों का प्रयोग कारीगरों को सिखलाया जा सके। दूसरी बात यह है कि ईमा प्रबन्ध करना चाहिए जिससे कारीगरों को अच्छा कच्चा माल उचित दामों में मिलता रहे। इसके साथ-साथ उनको सहकारी समितियों की स्थापना करनी चाहिये। तीसरी इन वस्तुओं की विप्री यजाने के लिए इनका उचित प्रकार से प्रचार करना चाहिए। सरकार के उद्योग-विभाग को विज्ञापन, नोटिस, छोटी-छोटी पुरितकाओं द्वारा इन वस्तुओं का प्रचार करना चाहिए। देश में ही नहीं परन्तु विदेश में भी इस प्रकार की बिक्री हो सकती है। सरकार की तरफ से या सहकारी-समिति की ओर से स्थान-स्थान पर ऐसे भंडार (Emporiums) खोलने चाहिए जहाँ कि गृह-उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं का प्रदर्शन तथा बिक्री का प्रबन्ध हो। गृह-उद्योगों की उन्नति के लिए यह भी आवश्यक प्रतीत होता है कि सरकार विदेशों से बड़ी सख्या में छोटी मशीनें खरीदे तथा उन्हें प्रयोग करने के लिए लोगों को उत्साहित किया जाय। सरकार ने जापान से कुछ इस प्रकार की मशीनें मँगाई थी। परन्तु वे बहुत घड़ी थी। इस प्रकार की मशीनों को चलाने के लिए सस्ती बिजली का भी प्रबन्ध:

हाना चाहिये। अगर गाँवों में बिजली पहुँच जाय तो इसमें गृह उद्योगों का बहुत लाभ होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना में गृह उद्योगों की निम्नलिखित समस्याओं पर मुख्यतः विचार किया गया है—(१) संगठन (२) पूँजी (३) कच्चा माल (४) शोध (५) तकनीक तथा श्रम (६) औजार तथा शक्ति की उपस्थिति (७) विपरीत तथा राज्य की इनके प्रति नीति।

गृह व्यवसायियों का यह मत है कि आधुनिक वातावरण में गृह उद्योगों का अधिक महत्त्व देना उचित नहीं। क्योंकि यह उद्योगों के सामने गृह उद्योग अधिक दिन नहीं चले सकते हैं। इनमें व्यय में पैसे तथा श्रम की बर्बादी है। इन उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुएँ महँगी होती हैं। इसलिए गृह उद्योगों को बढ़ाकर देना चाहिये। परन्तु एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिये कि यह उद्योग धंधों की वृद्धि तथा उत्पादन प्रथा में नए नए सुधारों के कारण दिन प्रति दिन कम मजदूरी की आवश्यकता होगी। उदाहरणार्थ जितना कोयला पत्र १५१२ व्ययित होकर था उसका अब १२६ आदमी खाते हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति यह उद्योग धंधों में से बहार हटने के गृह उद्योगों में लग जावेगा, वह उद्योग धंधों की स्थापना का एक दुष्परिणाम यह भी हुआ है कि जो व्यक्ति तो समाज में पूँजी के स्वामी हो गए हैं जब कि समाज का एक बड़ा भाग आर्थिक दृष्टि से दयनीय दशा में प्राप्त हो गया है। हमारे अमीर तथा गरीबों में इनका अधिक भेद औद्योगिक शक्ति के बाद ही हुआ है।

एक जगह से लिखा है कि *The association of poverty with progress is the great enigma of our time* इस कारण से प्रतिष्ठित यह उद्योग इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि वह समाज में नहीं बनाई जा सकती हैं जैसे कारखाने वस्तुएँ या ऐसी वस्तुएँ जिनमें श्रम बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है जैसा कि अमीर के व्यक्तिगत या बहियावासी या ऐसी वस्तुएँ जिनमें वैयक्तिक रुचि (Individual taste) का अनुसार भिन्नता होगी। हमारे देश की वर्तमान अवस्था में गृह उद्योगों की उन्नति की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अभी तो हमारे यहाँ यह उद्योग धंधे इस पैमाने में नहीं चल रहे हैं कि वे बकारी की समस्या का हल कर दें तथा भूमि पर निर्भर व्यवसायों को बढ़ावा दे सकें।

‘The existence of cottage industries and handicrafts by side with factory industries may not only absorb the population displaced by machines, but save them from degradation which idleness supported by unemployment doles involve’ Wadia and Merchant *Our Economic Problem*, p 504

कम कर दें। ऐसी व्यवस्था में गांवों की आर्थिक समस्या को सुधान्न के लिए गृह-उद्योग अत्यन्त आवश्यक हैं।

बड़े उद्योग-धन्धों की स्थापना में कई तमिल तथा सामाजिक दृष्टिकोण से हैं। हजारों लोगों को अपनी अपनी हार्दिक बन्धनों में गहरा पड़ना है। इनमें स्वाभिमानी तथा चरित्रदोषों पर ही अन्धता प्रभाव नहीं पड़ना है। गृह-उद्योगों की स्थापना में यह अर्थ नहीं है। गृह-उद्योगों में प्रत्येक कारीगर लोगों का निर्माण करने में एक आनन्द का अनुभव करता है, परन्तु बड़े-बड़े कारखानों में वह भी मशीन का ही एक अंग हो जाता है।

**कार्षी समिति**—जून १९५५ में योजना आयोग द्वारा श्री कार्षी की सम्पदा में एक समिति सम्मिलित स्थापित की गई कि वह द्वितीय योजना में ग्राम तथा कृषि उद्योगों के सम्बन्ध में नीति बनाए। इन समिति ने निम्नलिखित मुख्य सुझाव दिये :—

(१) राज्य सरकारें सहकारी समितियों को बित्त तथा अनुदान देकर ग्राम उद्योगों की महत्त्वता दें।

(२) ग्राम उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का ग्युलान मूल्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट कर दी जाय।

(३) बड़े उद्योगों द्वारा उत्पादित इन वस्तुओं की, जिनकी प्रतिस्पर्धिता ग्राम-उद्योगों तथा गृह-उद्योगों की उत्पादित वस्तुओं में होती है, अधिकतम उत्पादन भागा सरकार द्वारा सीमित कर दिया जाय।

(४) केंद्रीय मन्त्रि-मण्डल में गृह उद्योगों के लिये एक दृष्टक नहीं हो।

(५) बड़े उद्योगों पर एक कर लगाया जाय और इन भाग को गृह-उद्योगों की महत्त्वता पर लगाया जाय।

(६) द्वितीय योजना काल में २६० करोड़ रुपये गृह-उद्योगों के विकास पर कम दिये जाय।

**द्वितीय योजना तथा गृह उद्योग**—द्वितीय योजना काल में गृह उद्योगों पर २०० करोड़ रुपये व्यय होगा। इनमें से २५ करोड़ रुपये भारत सरकार तथा १७५ करोड़ रुपये राज्य सरकारें देंगी। इसका विवरण इस प्रकार है :—

उद्योग

अनुदान बजेट रुपये में

हाथ करपा	५९.५०
खादी तथा ग्रामोद्योग	५५.५०
छाट उद्योग	५५.००
दस्तकारियाँ	९.००
रेशम के कीड़े का पालन	५.००
नागियाँ जटा उद्योग	१.००
प्रसामन शान्त कार्य, आदि	१५.००
योग	२०० करोड़

इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वितीय योजनाविधि में १८ करोड़ रुपये निर्वाहना के पुनर्व्यवस्थापन पर खर्च करेगी जिसमें में ११ करोड़ रुपये गृह तथा मन्त्रालयों उद्योगों पर तथा ७ करोड़ रुपये उनके औद्योगिक प्रशिक्षण में खर्च होगा।

## बड़े उद्योग धन्ये

भारत का हम समार व प्रमग औद्योगिक देश की कटि में नहीं रख सकत हैं। औद्योगिक अवर्तन का कारण यह नहीं है कि भारत में प्राकृतिक साधनों (Natural resources) की कमी है। विद्वानों का कहना है कि हम तथा अमेरिका के बाद भारत तथा चीन दो ही ऐसे देश हैं जो कि स्वावलम्बी हो सकते हैं। हमारे देश के प्राकृतिक साधनों को देखने हुए यह निष्कर्ष कहा जा सकता है कि गति बाल में तथा युद्ध काल में भी अगर हमारे साधनों का ठीक दग में उपयोग हो तो भारत को अन्य देशों का मुह नहीं ताकना होगा। आर्थिक दृष्टि में भारत का भविष्य अन्यत्न उज्ज्वल है।<sup>१</sup>

भारत की वर्तमान अवस्था प्रकृति की कृपणा का फल नहीं परन्तु मनुष्य-कृत है। भारत के आर्थिक साधनों को देखने में यह स्पष्ट है कि यहाँ औद्योगिक विकास सम्भव है। हमारे देश का चौथाई भाग बना में टका हुआ है। बना का

१ "India possesses large reserves of most of the important industrial minerals—coal, iron, several of the ferro-alloys which make good steel, and the subsidiary minerals—in ample quantity to make her a powerful and reasonably self-sufficient industrial nation" Prof. C. H. Behre, Foreign Affairs. (Oct. 1942).

आधिक-दृष्टि से अत्यन्त महत्व है। इनसे सड़की, जलाने के लिए ईंधन (fuel) और पशुओं के लिए चारा (fodder) प्राप्त होता है। इनके अतिरिक्त बई तरह की घास में कागज बनाया जाता है। वनों में ही तारपीन (Turpentine), लाख तथा वानिज की प्राप्ति होती है। वनों में देश की भाव-हवा तथा वर्षा पर भी बड़ा प्रभाव होता है। देश में कपास होती है। विभाजन के कारण कपास के उत्पादन में काफी बमी हो गई है। परन्तु इनका उत्पादन बढ़ाया जा है। सरकार इसकी पैदावार को बढ़ावा दे रही है। विभाजन के पूर्व मसार का ९७ प्रतिशत जूट भारत में ही पैदा होता था। परन्तु अब मुख्य-मुख्य जूट के क्षेत्र पाकिस्तान में हो चले गये हैं। सरकार इस बात का पूर्ण प्रयत्न कर रही है कि भारत में इसकी पैदावार बहुत बड़ जावे। देश में चाय तथा तम्बाकू की भी बहुत पैदावार होती है। पशुधन भी भारत का अत्यन्त विशाल है, परन्तु उनकी नस्ल में सुधार की आवश्यकता है। भेड़ों में ऊन की प्राप्ति होती है। इस दिशा में और अधिक उप्रति हो सकती है।

खनिज पदार्थों में भी भारत निर्धन नहीं है। सर टॉमन हॉर्नैड भूतपूर्व डाइ-रेक्टर जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, के मतानुसार भारत करीब सभी प्रकार के खनिज पदार्थों में भरा है। वेबल डम दिशा में काम करने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण खनिज कोयला है। सन् १९४७ में करीबन ३ करोड़ टन कोयला निकाला गया था। यह मात्रा बहुत कम है। परन्तु यह नई-नई कोयला खानों की मशीनों को प्रयोग करने से बढ़ाई जा सकती है। यह अनुमान है कि भारत में सब मिलाकर ४०० करोड़ टन कोयला होगा। लोहे में भी हमारा देश बहुत धनी है। विद्वानों का अनुमान है कि भारत में उतना ही लोहा होगा जितना कि संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका में। भारतीय लोहे में मिलावट बहुत कम है। इस दृष्टि से भारत अमेरिका से भी बड़ा है। भारत में मैंगनीज तथा अलस्क भी प्रचुर मात्रा में है। इन दोनों खनिज पदार्थों में हमारा देश अत्यन्त धनी है। इन पदार्थों के अतिरिक्त भारत में सोना, टिन, ताँबा, तथा अन्य कई खनिज पदार्थ भी हैं।

औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् मनुष्य या जानवरों के बढते कोयला तथा पानी से मशीनें चलाई जाती है। परन्तु अब आप के बदले दिन पर दिन अधिक-आधिक बिजली का प्रयोग मशीनें चलाने में किया जाता है। भारत में कोयले की कमी नहीं है। पानी भी बहुत है। इसलिए मशीनें चलाने के लिए संचालन-शक्ति की कोई कमी नहीं है। कोयले की तरह पेट्रोल (Petroleum) भी संचालन शक्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में घरों में रोशनी के



लिए भी उनकी आवश्यकता है क्योंकि अभी तक विजली बहुत जगह नहीं पहुँची है। पेट्रोल में हमारा देश गनी नहीं है।

ऊपर के वर्णन से इतना तो स्पष्ट हो गया होगा कि औद्योगिक विकास के लिए भारत में कच्चा माल है तथा शक्ति के साधन भी हैं। अब यह देयता चाहिए कि इतना सब होने हुए भी औद्योगिक विकास क्यों नहीं हुआ।

**भारत की औद्योगिक अवनति के मूल कारण** — इसका सबसे मुख्य कारण भारत पर अंग्रेजी साम्राज्यवाद का अधिकार था। भारत करीबन १५० वर्षों तक इंग्लैंड का दाम रहा। इस दामना के काल में यहाँ बड़े उद्योग-धंधों का विकास तो क्या होता था छोटे-छोटे उद्योग-धंधे से उनका भी अंग्रेजों में तट कर डाला। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत का अधिक से अधिक आर्थिक शोषण करने का था। इसलिए उनकी नीति सदा यही रही कि भारत कच्चा माल निर्यात करे तथा वनी हुई वस्तुओं को इंग्लैंड में आयात करे। साम्राज्यवाद ने सब जगह यही नीति बरती क्योंकि साम्राज्यवाद का मुख्य पहलू आर्थिक शोषण ही है।

जब यहाँ कुछ उद्योग-धंधे आरम्भ हुए तो अंग्रेजों ने इस बात का प्रयत्न किया कि यहाँ मशीना का बनाने वाले कारखाने न स्थापित हों। इसी कारण हमें आज भी विदेशों में सब मशीनें मँगानी पड़ती हैं। हमारे देश में आयातभूत उद्योगों की भी भारी कमी है। बिना इस प्रकार के उद्योगों को स्थापित किए किसी देश का औद्योगिक विकास सम्भव नहीं। जो उद्योग-धंधे भारत में हैं उनमें से कई विदेशी पूँजीपतियों के हाथ में हैं। चाय तथा जूट पर विदेशियों का पूर्ण अधिकार है। कई वपड़ों की मिलें भी उन्हीं के हाथ में हैं।

क्योंकि देश में बहुत समय तक उद्योग-धंधे स्थापित नहीं हुए इस कारण हमारे देश में टेक्निकल आदमियों की बहुत कमी है। देश में टेक्निकल इन्स्टीट्यूट्स भी उन्ने-गिने हैं। इसका फल यह है कि हमारे यहाँ कुशल-धर्म (Skilled labour) की कमी है। इस कारण भी औद्योगिक विकास में बाधा है। हमारे यहाँ के मजदूर अशिक्षित अशिक्षित हैं, इस कारण उनकी कार्य-निपुणता (Efficiency) अन्य देशों के मजदूरों की अपेक्षा बहुत कम है।

देश में पूँजी का भी अभाव है। हमारे यहाँ माह्रम की भी कमी है। लोग अपना अपना उद्योग में लगाना नहीं चाहते। उनकी यह डर लगा रहता है कि वही अपना डूब न जाय। यद्यपि पेट्रोल की अपेक्षा अब पूँजी बढ़ गई है परन्तु अब भी पूँजीपतियों के हस्त में अधिक परिवर्तन नहीं हुआ है।

भारत में सचालन-शक्ति की भी कमी नहीं है। परन्तु धन सरकार ने कई योजनाओं को आरम्भ दिया है। इनके पूरे हो जाने पर इसकी कमी नहीं रहेगी।

औद्योगिक विकास के मार्ग में जिन बाधाओं का हमने वर्णन किया है वे सब ऐसी हैं जो कि हटाई जा सकनी हैं। इसलिए हमारे देश को समार के अन्य बड़े देशों की तरह उन्नति करनी है तो अपने औद्योगिक विकास की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए। आधुनिक समय में बिना औद्योगिक उन्नति के देश सम्पन्न तथा शक्तिशाली नहीं हो सकता है।

**औद्योगीकरण में लाभ**—भारत में औद्योगिक-शक्ति की सबसे बड़ी आवश्यकता इसलिए है कि केवल इसी प्रकार हमारे निर्धनता दूर हो सकती है। भूमि पर निर्भर व्यक्तियों की संख्या कम हो जावेगी। इनमें किसानों की समस्या में सुधार होगा। हजारों व्यक्तियों को रोजगार मिल जावेगा। इतने बेकारी की समस्या बहुत मात्रा तक हल हो जावेगी। रूज की प्रवस्था सन् १९१७ तक बहुत मात्रा तक हमारी हो तरह थी। परन्तु आज रूज समार के शक्तिशाली तथा सम्पन्न राष्ट्रों में से एक है। सन् १८९७ के बाद जापान की उन्नति का सबसे मुख्य कारण उसका औद्योगिक विकास था। इसी प्रकार औद्योगिक विकास के फलस्वरूप हमारा देश भी उन्नति करेगा।

उद्योग-धर्मों में हमारी राष्ट्रीय धार बढ़ेगी। हमारे राष्ट्रों में हमारा जीवन-स्तर ऊँचा होगा। इस समय समार के उन्नत देशों की सामने हमारी प्रति व्यक्ति धार भव्यन्तही कम है। सन् १९४७ में भारत सरकार के गवेषणा-विभाग के अनुसार सह २५० रुपया वारिक थी। हमारे देश की निर्धनता के कारण हजारों व्यक्ति अपने परिवार का ठीक प्रकार पालन नहीं कर सकते हैं, बाल-बच्चों की उचित शिक्षा नहीं दे सकते हैं, नाना भाति की बीमारियों के निवार हो जाते हैं और समस्त आयु अचूरा हो जीवन व्यतीत करते हैं। औद्योगीकरण में निर्धनता दूर होगी। परन्तु एक बात का ध्यान रखना होगा कि बड़े बड़े उद्योगपति तथा पूँजीपति ही सब लाभ को न खा जायें। इसलिए कई विद्वानों का कहना है कि केवल औद्योगीकरण में ही कुछ न होगा। इसके साथ यह भी आवश्यक है कि उद्योग-धर्मों का राष्ट्रीयकरण हो जाय। इस प्रश्न की विवेचना बाद की गई है।

आधुनिक उन्नति के साथ-साथ औद्योगिक-विकास के फलस्वरूप भौतिक उन्नति भी होगी। हमारे देशवासी धार्मिक तथा सामाजिक सकोपता से बहुत

अधिक सीमा तक मुक्त हो जायेंगे। जानि-पाति के बन्धन मिथिल हो जावेगे तथा एक नई चेतना का संचार होगा। आर्थिक उन्नति के साथ-साथ हमारी मानसिक उन्नति भी होगी। संक्षेप में औद्योगीकरण से निम्नलिखित लाभ हैं—  
“रहन-सहन के स्तर की वृद्धि, बेकारी और अर्द्ध-बेकारी का निवारण, कृषि की अवस्था में सुधार आत्म-निर्भरता और आर्थिक-स्वतन्त्रता। राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति औसत आय की वृद्धि और आर्थिक भन्तृजन।”<sup>1</sup>

देश में प्रमुख चड़े उद्योग घन्धे-रमावे देश में निम्नलिखित प्रमुख उद्योग हैं

(१) कपड़ा — भारत में कृषि के पञ्चान् वुनार्ड का उद्योग सबसे प्रमुख है। १८वीं शताब्दी तक यह बहुत ही उन्नत अवस्था में था परन्तु बाद की अंग्रेजों की नीति के कारण इसका ह्रास हो गया। हाव की वुनार्ड का उद्योग बीमवी शताब्दी में फिर बड़ा और स्वदेशी आन्दोलन ने इसको बहुत प्रोत्साहन दिया। भारत में प्रथम वुनने की मशीन १८५४ में बम्बई में स्थापित हुई थी। १९वीं शताब्दी के अन्त तक इनकी मख्या काफी बढ़ गई थी। २०वीं शताब्दी में स्वदेशी आन्दोलन का भी इस उद्योग ने अच्छा लाभ उठाया। कपड़े की मिलों की मख्या बहुत बढ़ी। क्योंकि प्रथम महायुद्ध के समय विदेशों में कपड़ा आना बन्द हो गया था इसलिए देश में कपड़े के उद्योग को बड़ा लाभ हुआ और इसकी वृद्धि हुई। सन् १९३० में भारत सरकार ने इस उद्योग को रक्षा प्रदान की। इसमें भी प्रोत्साहन मिला। द्वितीय महायुद्ध के काल में इस उद्योग ने और उन्नति की और उद्योगपतियाँ का लाभ हुआ। सन् १९५३ में भारत में ४५१ मशीनें मिले थीं। इनमें १,१२,४१,००० तक्रे तथा २०१५०० कपड़े थे। इन मिला ने ४८० करोड़ गज कपड़ा पैदा किया। इन मिला में लगभग ६ लाख मजदूर काम करते हैं। देश के कपड़े के उद्योग के मुख्य केन्द्र बम्बई, अहमदाबाद, गोलपुर, कानपुर, नागपुर इन्दौर, मदीरी तथा कोयम्बटूर हैं।

प्रथम योजना में यह लक्ष्य रखा गया था कि इसके अन्त तक देश में ४७० करोड़ गज कपड़ा पैदा हो। योजना अन्त में देश में ५२० करोड़ गज कपड़ा उत्पादन हो गया था। अर्थात् प्रति व्यक्ति कपड़ा उत्पादन १५ गज हो गया था। द्वितीय योजना का लक्ष्य ७५० करोड़ गज कपड़ा प्रति वर्ष उत्पादन करना था। अर्थात् प्रति व्यक्ति १८ गज प्रति वर्ष। इसके अतिरिक्त प्रति वर्ष १९५ करोड़ पाँड सूत तथा रुई का ५९ लाख गॉट प्रतिवर्ष उत्पादन लक्ष्य रखा

गया है। हमारे विदेशी व्यापार में नुती वस्त्र का निर्यात महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मन् १९५५ में ८३६ करोड़ गज कपड़े का निर्यात हुआ। द्वितीय योजना के अन्त में यह बढ़ कर १०० से ११० करोड़ गज तक हो जायगा।

(२) रेशम—देश में जो रेशम का कारखाना है वह मुख्यतः गृह उद्योग तक ही सीमित है। सरकार इस उद्योग के विकास की चेष्टा कर रही है। देश में रेशम की करीबन डेढ़ दर्जन मिलें हैं। देश में लगभग ३० लाख पौंड रेशम प्रति वर्ष पैदा होती है।

(३) ऊन.—भारत में ऊन की भी कई मिलें हैं। ये मुख्यतः पूर्वी पञ्जाब मद्रास, बिहार, ईदराबाद तथा उत्तर प्रदेश में हैं। इस उद्योग में उन्नति के लिए सरकार ने एक Wool Development Committee की स्थापना की है।

(४) जूट.—भारत में इस समय ८५ जूट की मिलें हैं। देश के विमा-जन के कारण इस उद्योग को घबका पहुँचा है। पाकिस्तान में मुख्यतः दो भाग चले गए हैं जिनमें कच्ची जूट पैदा होती थी। परन्तु भारत सरकार कच्चे जूट के उत्पादन को उत्साहित कर रही है। पश्चिमी बंगाल, आसाम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा तथा दक्षिणी भारत में जूट की पैदावार बढ़ाई जा रही है। प्रथम योजना काल में जूट उद्योग तथा जूट की खेती में उन्नति की परन्तु यह गतोपश्रन नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रथम योजना के लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो सकी १९५४ में जूट जाँच आयोग ने यह निष्कारिका इस उद्योग के लिए एक विकास परिषद् स्थापित होना चाहिए। द्वितीय योजना के जूट उद्योग के विषय में लक्ष्य यह है कि १९६०-६१ में ११०० हजार टन उत्पादन हो, ९०० हजार टन निर्यात कर दिया जाय। देश में पटमन का ५० लाख गॉट उत्पादन हो।

(५) चीनी का उद्योग.—देश के प्रमुख उद्योगों में से एक है। पहले यह एक गृह उद्योग था। परन्तु विदेशी चीनी के आयात के कारण इसको बड़ा घबका पहुँचा। बाद की देश में चीनी की मिलें स्थापित की गयीं। इस उद्योग का आरम्भ पिछले तीस वर्षों में हुआ है और इसने बड़ी उन्नति की है। मन् १९२५-२६ में भारत में केवल २३ मिलें थीं। परन्तु जावा से भारत में सस्ते दामों में चीनी आती थी। अतएव भारत में चीनी का उद्योग तभी नग्न था जब कि विदेशी चीनी पर महसूल लगाया जाय। मन् १९२२ में Sugar Industry Protection Act पास किया गया। इसके बाद देश में इस उद्योग में बड़ी तेजी से उन्नति की। द्वितीय महायुद्ध के काल में इसका उत्पादन बढ़ने के बजाय कुछ घट ही गया। परन्तु युद्ध के बाद फिर उत्पादन बढ़ा है।

१९५२-५३ में १२,५००० टन चीनी पैदा हुई। भारत में इस समय चीनी की १३७ मिलें हैं और इनमें ३६,०००,००० रुपये की पूंजी लगी है। भारत में समार के उत्पादन की २६% चीनी पैदा होती है। प्रथम योजना काल में चीनी का उत्पादन १४.८% लाख टन से बढ़ कर १६.५ लाख टन हो गया। द्वितीय योजना में १९६०-६१ में उत्पादन का लक्ष्य २२.५ लाख टन रखा गया है। गर्मे के उत्पादन का लक्ष्य २२.५ लाख टन रखा गया है। भारत में चीनी की खपत बहुत शीघ्रता से बढ़ती तथा इसका निर्यात भी थकेगा यदि चीनी के कामों में पसी की जा नसे।

(६) कागज का उद्योग—भारत में आधुनिक ढंग से कागज बनाने का पहला कारखाना सन १८६७ में खुला था। भारत में १९२५ से इस उद्योग का संरक्षण प्राप्त हुआ और यह १९६७ तक रहा। इस काल में इस उद्योग में अच्छी उन्नति थी। १९२१ में देश में कागज की १७ मिलें थी और इनका उत्पादन प्रतिवर्ष १०६,००० टन था। परन्तु इनसे स हमारा काम नहीं चल सकता है। सन १९५५-५६ में भारत में २ लाख टन कागज बना। श्रवणारी कागज ४२०० टन पैदा हुआ। इस समय देश में २१ कागज की मिलें हैं। द्वितीय योजना का यह लक्ष्य है कि १९६०-६१ में ३५० हजार टन कागज और इसी तथा ३० हजार टन श्रवणारी कागज का उत्पादन हो।

(७) दियासलाई का उद्योग—भारत में दियासलाई के सबसे बड़े दो कारखाने (Wimco तथा Amco) बिदेशी पूंजीपतियों के हाथ में हैं। दियासलाई के कुछ कारखानों की मर्यादा लगभग २०० है। परन्तु इनमें से प्रत्येक इतनी छोटी है कि इन्हें कुटीर उद्योगों की श्रेणी में रखा जा सकता है। भारत में सन् १९५३-५४ में दियासलाई का उत्पादन २९३ लाख प्राप्त था। इस उद्योग में लगभग २०,००० व्यक्ति काम में लगे हैं।

(८) काँच—भारत में काँच के कारखाने पश्चिमी बंगाल, बम्बई, उत्तर प्रदेश, मद्रास और बिहार में हैं। इनमें अधिकतर बोतल, शीशियाँ, चिमनियाँ, दरवाजों और सिडकियों के शीशे ही बनते हैं। सस्तेरी की वस्तुओं, वैज्ञानिक अनुसंधानशालाओं या सेना की आवश्यकता की वस्तुओं का उत्पादन नगण्य है। प्रथम योजना में काँच उद्योग पर भी ध्यान दिया गया था। द्वितीय योजना में भी इससे विकास का प्रयत्न है।

(९) सिमेंट—भारत में इस उद्योग में लगभग २९ करोड़ रुपये की पूंजी लगी है और इसमें लगभग ३३००० व्यक्ति काम करते हैं। प्रथम योजना के

समाप्ति पर देश में सिमेंट के २७ कारखाने हो गये थे और १९५५-५६ में इसका उत्पादन ४२८ लाख टन था। द्वितीय योजना में यह लक्ष्य रखा गया है कि सिमेंट का उत्पादन १९६०-६१ में १३० लाख टन वार्षिक हो जाय।

(१०) रसायन उद्योग :—आधुनिक उत्पादन में रसायनों की आवश्यकता पग पग पर होती है। परन्तु हमारे देश में रसायन उद्योग अभी बहुत पिछले अवस्था में है। इसलिये हम रसायनों के लिये विदेशों पर निर्भर हैं।

प्रमुख रसायन-उद्योग निम्नलिखित हैं :—

(अ) गंधक-श्रृंखला :—देश में इस समय इस उद्योग में ४६ मिलें हैं। इनमें लगभग २ करोड़ रुपए की पूंजी लगी है। वार्षिक उत्पादन मात्र १५०००० टन है। प्रथम योजना में इस उद्योग के विस्तार पर ध्यान दिया गया था। द्वितीय योजना का लक्ष्य ४७० हजार टन वार्षिक है।

(ब) कौस्टिक सोडा :—गंधक श्रृंखला की ही भांति कौस्टिक सोडा भी अनेक उद्योगों के लिए आवश्यक है। इसका उत्पादन हमारी आवश्यकताओं को देखते हुये बहुत कम है। इसलिए विदेशों में इसे आयात करना होता है। पंचवर्षीय योजनाओं में इसके विकास पर भी ध्यान दिया गया है।

(स) सोडा ऐश :—सोडा ऐश या सन्जी की आवश्यकता काँच उद्योग तथा यत्न उद्योग में होती है। हमारे देश में प्रतिवर्ष लगभग ८६००० टन सन्जी का उत्पादन होता है। परन्तु हमारे देश में इससे कहीं अधिक इसकी आवश्यकता है।

उपयुक्त रसायनों के अतिरिक्त एल्मुनियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, फिट-करी, ज़िंक क्लोराइड, आदि भी देश में पाँड़ा बहुत पैदा होता है। परन्तु इस बात की तीव्र आवश्यकता है कि इनका उत्पादन सीधेता से बढ़ाया जाय और हम विदेशी आयात पर निर्भर न रहें।

(११) भारी उद्योग :—भारत में लोहे तथा कोलाइ की ध्वननाय अव्यक्त प्राचीन काल में था। आधुनिक काल में पहला लोहे का कारखाना सन् १८४७ में स्थापित हुआ। सन् १९०७ में टाटा आयरन ऐंड स्टील कम्पनी की स्थापना हुई। दिन पर दिन यह कारखाना उन्नति करता गया। आज यह एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। इसके अतिरिक्त देश में ७ अन्य बड़े कारखाने हैं। प्रथम महायुद्ध तथा द्वितीय महायुद्ध के काल में इस उद्योग ने बड़ी उन्नति की। पंचवर्षीय योजनाओं में इस उद्योग के विकास का पूरा ध्यान दिया जा रहा है। भारत सरकार ने एक स्टील बोर्ड की स्थापना की है। इस बोर्ड के

अधीन तीन बड़े बड़े कारखाने हैं—दुर्गापुर, रस्केला तथा भिलाई। इन कारखानों का प्रतिवर्षक मँगूरक कारखाने का उत्पादन भी बढ़ाया जायगा। द्वितीय योजना में उपर्युक्त तीन कारखानों पर ३१० करोड़ रुपया व्यय किया जायगा। यह धारा है कि द्वितीय योजना के अन्त तक देश में कुल उत्पादन (सरकार तथा निजी मिलाकर) ८३ लाख टन इस्पात प्रतिवर्ष हो जायगा।

(१२) अन्य उद्योग — उपर्युक्त समष्टि उद्योगों के अतिरिक्त कुछ अन्य उद्योग भी भारत में स्थापित हुए हैं। एल्युमिनियम के भारत में दो कारखाने हैं। इसका उत्पादन लगभग ४००० टन है। मोटर उद्योग की भी स्थापना हो चुकी है। अधिकतर कारखाने विदेशों में मंगाये पुर्जों को जोड़ते हैं। परन्तु दो कारखाने 'हिन्दुस्तान मोटर्स' तथा 'प्रीमियर माटोमो-बाइल्स' मोटरों का निर्माण भी करती हैं। रेलों के डिब्बों तथा इंजनों का निर्माण चित्तूरजन फैक्टरी और टाटा घायरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। जहाज बनाने के लिये बिजगापट्टम में एक कारखाना है। हवाई जहाजों का निर्माण भी होने लगा है। मशीनों के फल पुर्जे बनाने के भी भारत में कुछ कारखाने खुल गये हैं। इसी प्रकार बिजली की वस्तुओं का भी देश में थोड़ा बहुत निर्माण हो रहा है। भारत में दवाइयों बनाने के भी कुछ कारखाने खुल गये हैं। देश में घनस्पति धी के भी कई कारखाने हैं। धी बहुत महंगा होने के कारण इस उद्योग ने खूब उन्नति की है। इनके अतिरिक्त देश में कई अन्य उद्योग हैं, जैसे, चमड़ा गादुन, मोजा-बनियाइन, शराब चाय कहवा तम्बाकू नमक, फिटम कम्पनियाँ, साइकिल आदि। इन उद्योगों में भी हजारों आदमी काम करते हैं और करोड़ों की पूंजी लगी है।

श्रीयोगिक विकास की योजना — सन १९३८ में कांग्रेस ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य भारत के औद्योगिक विकास के लिये योजना बनाना था। इसने इस दिशा में उपयोगी काम किया। इस कमेटी के प्रधान श्री जवाहर लाल नेहरू थे। द्वितीय महायुद्ध के काल में इस कमेटी का काम रुक गया। परन्तु भारत सरकार ने एक प्लानिंग विभाग खोला (सन १९४४, जुलाई)। भारत के विभिन्न प्रांतों ने युद्धांतर आर्थिक विकास सम्बन्धी योजनाएँ बनाईं। इसी काल में भारत का आठ उद्योगपतियों तथा अर्थशास्त्रियों ने देश के सम्मुख एक योजना रखी जो कि श्रमिक योजना कहलाती है। श्री एम० एन० राय ने अपने दल की ओर से एक योजना प्रस्तुत की जो People's Plan कहलाती है। श्री एस० एन० प्रसाद ने जो कि वर्धा कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल थे गांधी जी के मित्रान्ता

पर आधारित एक योजना रखी जिसको **Gandhian Plan** कहा गया है। इस समय देश में योजनाओं की एक बाढ़ भी आ गई है।

सन् १९४७ में भारत एक स्वतन्त्र राज्य हो गया। परन्तु इसी काल में देश की आर्थिक घटस्था सुधरने के बजाय बिगड़ने लगी। उत्पादन कम हो गया। इसका कारण उद्योगपतियों के अनुसार मजदूरों का कम काम करना या अर्थात् मजदूरों की हड़तालें। इसके प्रतिरिक्त अन्य कारण भी थे। देश के विभाजन के कारण साम्प्रदायिक दंगे हुए। ऐसे घटस्थानि के समय उत्पादन में कमी स्वाभाविक ही थी। इसके प्रतिरिक्त जूट तथा कपास के उद्योगों के लिये कच्चे माल की कमी हो गई। उत्पादन में कमी का एक कारण यह भी था कि उद्योगपति एक प्रकार का दबाव सरकार के ऊपर डाल रहे थे कि वह राष्ट्रीयकरण का इरादा छोड़ दे। सरकार से कुछ वर्षों के लिये प्रयत्नशील है कि भारत का औद्योगिक विकास हो। वह कच्चे माल के उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। इसलिये सरकार ने विदेशी पूँजी को भी भारत में आमन्त्रित किया है। ६ अप्रैल, १९४८ की सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा अपनी औद्योगिक नीति का स्पष्टीकरण किया। यह कहा गया कि देश की सर्वांगीण उन्नति के लिए एक राष्ट्रीय प्लानिंग कमीशन की नियुक्ति होगी।

इस आयोग की नियुक्ति सरकार द्वारा मार्च १९५० में की गई। इस आयोग ने जुलाई १९५१ में प्रथम पंचवर्षीय योजना देश के सम्मुख रखी। इस योजना का उद्देश्य देश के प्राकृतिक साधनों का इस प्रकार संगठन तथा प्रयोग करना या जिनसे जनता का हित हो। इसका प्रत्यक्ष उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र में युद्धोत्तर काल में जो कठिनाइयाँ पैदा हो गई हैं, उनको हटाना तथा और बाजारी और मनाफाखोरी को दूर करना है। योजना को नीहित सफलता प्राप्त हुई। प्रथम योजना की समाप्ति पर द्वितीय योजना प्रारम्भ हो गई है। जिसका उद्देश्य देश का आर्थिक उन्नति को और आगे बढ़ाना है। यह योजना १९६१ में पूरी होगी। उसके पश्चात् तृतीय योजना का प्रारम्भ होगा। इस प्रकार यह भासा है कि सुनियोजित आर्थिक प्रगति के फलस्वरूप देश में कुछ

1, "High and rising prices, shortages of raw-materials, essential consumer goods and of housing and the relief and rehabilitation of displaced persons constitute the immediate problems for which the First Five Year Plan must provide an answer." The First Five Year Plan (issued) by the Planning Commission, p. 23.



वर्षों पश्चात् वर्तमान आर्थिक कठिनाइयाँ नहीं रहनी। परन्तु इन योजनाओं के मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं और इनके कारण योजनाओं से सीमित लाभ ही हो सकता है। जैसे, देश में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है तथा साधारण रसवासी अपना उत्तरदायित्व नहीं समझता है। अभी हम लोगों में सामूहिक हरयाण की भावना अत्यन्त ही अशक्त है। हम केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को ही देखते हैं। इसी का फल है कि व्यापारी वर्ग तथा उद्योगपति अपने लाभ (profit) के सामने देश तथा समाज को नगण्य समझते हैं। सरकारी कर्मचारियों में भी उतनी मात्रा में ईमानदारी नहीं है जितनी होनी चाहिये।

**राष्ट्रीयकरण तथा औद्योगिक नीति** — जैसा ऊपर कहा गया था केवल उद्योग धंधों को बढ़ाने से ही साधारण जनता को पूरा-पूरा लाभ नहीं होगा। क्योंकि इस प्रकार जो धन की उत्पत्ति होगी उसका अधिकांश भाग पूँजीपतियों की जेब में चला जाएगा। इसलिये कई विद्वानों के अनुसार उद्योग धंधों का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिये। राष्ट्रीयकरण से यह तात्पर्य है कि उद्योग-धंधे किसी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति न हो कर समस्त समाज की सम्पत्ति हो अर्थात् उनका नियन्त्रण सरकार द्वारा किया जाय। उदाहरणार्थ, भारत में रेलें सरकार के नियन्त्रण में हैं तथा राष्ट्र की सम्पत्ति हैं। सन् १९८७ से एक बात यह भी दृष्टिगोचर हुई है कि भारतीय उद्योगपतियों की नीति लोकहितकारिणी नहीं है। उनका उद्देश्य जनता का लोभण है। चीजों के दाम दिन प्रतिदिन बढ़त जा रहे हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि इसका कारण यह है कि मजदूरों का बतम बढ़ गया है तथा कच्चे माल का दाम बढ़ गये हैं। परन्तु यह भी नहीं भूलना चाहिये कि उनका मुनाफा भी कई गुना बढ़ गया है। कई उद्योगपतियों ने उत्पादन कम कर दिया है और इस प्रकार मुनाफा कई गुना बढ़ा लिया है। कपड़े, चीनी, मधुमेय में प्रत्येक वस्तु के दाम बढ़ गये हैं। इसलिये भी कई विद्वानों के अनुसार उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिये। राष्ट्रीयकरण से राष्ट्र का हित भरी प्रकार पूरा होगा। परन्तु कुछ लोग राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध हैं। उनका कहना है कि सरकार इन उद्योगों का अपनी अच्छी प्रकार नहीं चला सकती है जितनी अच्छी प्रकार कि उद्योगपति चलाते हैं। क्योंकि सरकारी अफसरों को इस बात का कतई भी अनुभव नहीं है। अगर राष्ट्रीयकरण किया जावेगा तो इससे उत्पादन घट जावेगा। राष्ट्रीयकरण से बहुत बर्बादी होगी। उद्योगपति तो अधिक लाभ के लिये उद्योगों को अच्छी प्रकार चलावेगे परन्तु सरकारी अफसरों को इस प्रकार का कोई उत्साह नहीं होगा।

I. पंचवर्षीय योजना तथा सामूहिक योजनाओं का वर्णन आगे किया गया है।

कांग्रेस सरकार को इन समय पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने का उद्देश्य नहीं है। स्वर्गीय सुन्दर पटेल ने एक समय कहा था कि सरकार के पास न पैसा है और न इतनी योग्यता है कि वह राष्ट्रीयकरण की नीति का अनुसरण करे। पूर्ण राष्ट्रीयकरण के लिए कहा जाता है कि अभी उचित समय नहीं आया है।

परन्तु भारत की सरकार ने कई उद्योग स्थापित किये हैं जिनको वह स्वामिनी है। उनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं :—

(१) चिट्ठी फरटिलाइजर फैक्टरी, इनकी स्थापना निम्नम्बर १९५१ में हुई।

(२) हिन्दुस्तान एयरलाइन्स फैक्टरी

(३) चित्तूरजन लोकोमोटिव वर्क

(४) नेशनल इन्स्ट्रुमेण्ट फैक्टरी

(५) रेलवे कोष फैक्टरी

(६) मैनिफेस्टो फैक्टरी

(७) हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी

(८) टेलीफोन फैक्टरी

(९) हिन्दुस्तान मेशीन टूल फैक्टरी

(१०) डी० डी० टी० फैक्टरी

(११) यूरेनियम योरिडन फैक्टरी

(१२) लोहा तथा इस्पात के करकेला, भिवानी तथा दुर्गापुर में कारखाने आदि।

१ जुलाई, १९५१ से भारत सरकार ने इम्पोरिजल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। अब इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया है। यह एक महत्वपूर्ण पग हमें उजागरा गया है। इसके प्रतिष्ठित सरकार द्वारा जीवन बीमा का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है और जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई है।

भारत सरकार ने सर्वप्रथम ६, अप्रैल १९४८ को अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा की थी। इसी नीति पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। इसके पश्चात् भारत सरकार ने यह घोषणा की कि उनका उद्देश्य एक समाजवादी समाज का संगठन है। इसके फलस्वरूप यह स्पष्ट था कि आर्थिक क्षेत्र में सरकारी उत्तरदायित्व बढ़ जायेगा। अतएव भारत सरकार ने १० अप्रैल १९५६ को अपनी औद्योगिक नीति की नये रूप से घोषणा की। इसकी मुख्य विशेषतायें निम्नांकित हैं :—

(घ) सरकार को सतोपजनक आर्थिक उन्नति के लिये आवश्यक हो जाता है कि वह अधिकाधिक विस्तृत क्षेत्र में औद्योगीकरण का उत्तरदायित्व ले। अतएव भारी तथा रक्षा सम्बन्धी उद्योगों में तथा उन उद्योगों में जिनकी स्थापना में बहुत बड़ा मात्रा में प्रारम्भिक पूँजी का विनियोग करना पड़े, सरकार को क्षेत्र में हो रखना पड़ेगा।

(ब) क्योंकि सरकार यह चाहती है कि आर्थिक प्रगति और विकास तीव्र गति से हो इसलिये सरकार निजी क्षेत्र को भी अपना योगदान करने के लिये पूर्णतः उत्साहित करना चाहती है। इसलिये उद्योगों को तीन वर्गों में रखा गया है; (१) वे उद्योग जो पूर्णतः सरकारी क्षेत्र में हैं; वे उद्योग जिनका कार्य-भार धीरे-धीरे सरकार पर पड़ेगा परन्तु जिनके विकास में निजी क्षेत्र भी भाग ले सकते हैं; (२) व सब उद्योग जो पूर्णतः निजी क्षेत्र में रहेंगे।

(स) कुटीर और ग्रामीण उद्योगों की उन्नति भी देश की आर्थिक उन्नति के लिये आवश्यक है। बड़े उद्योगों तथा कुटीर और ग्रामीण उद्योगों के मध्य एक सामंजस्य स्थापित करना है। इन लघु उद्योगों से बकायी की समस्या के समाधान में महामत्ता मिलेगी। इस प्रतिरिक्त हुपको तथा ग्रामीण श्रमिकों की आय बढ़ाने तथा आर्थिक ढाँचे की नींव दृढ़ करने में भी ये बहुत मात्रा तक म्हायक होंगे।

इस नीति की घोषणा ने यह स्पष्ट कर दिया कि शर्न शर्न आर्थिक क्षेत्र में सरकार का उत्तरदायित्व बढता जायगा। भारत के उद्योगपतियों की यह नीति यही सुझाई और व इसके, यदि खुलकर नहीं तो छिपे छिपे, विरुद्ध ही है।

इस औद्योगिक नीति के आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित मायमिकताएँ रखी गई हैं

(१) लोहा तथा इस्पात का उत्पादन, मशीनों तथा यन्त्रों का निर्माण और भारी रसायनों के उत्पादन में विकास करना ;

(२) अलमुनियम, सीमेंट, रासायनिक खाद आदि के उत्पादन में विस्तार करना,

(३) जूट, कपास, चीनी आदि के उद्योगों में नई मशीनों का लगाना;

(४) प्रत्येक उद्योग का उत्पादन दसना बढाना कि वह पूर्ण उत्पादन क्षमता तक पहुँच जाय; तथा

(५) उपभोग की वस्तुओं का भी उत्पादन बढाना।

इन प्रापन्निकताओं की सुची को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार का ध्यान इस समय विशेष रूप से नगरों को औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ाना है।

**भारतीय धर्मिक तथा उसकी समस्याएँ** — भारतीय बल वाग्दानी के स्थापित होने का महत्वपूर्ण फल यह हुआ कि भारत में एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ। यह वर्ग मिल्-मजदूर वर्ग है। भारतीय-मजदूर वर्ग शान्ति में पैदा होता है। परन्तु वर्गों से जो साधन प्राप्त न होने के कारण नगरों में नौकरी की तलाश में जा जाता है। परन्तु गाँव में उसका सम्बन्ध बना रहता है। गाँवों में भूमि पर बहुत अधिक भार होने के कारण लोग शहरों में जा जाते हैं। शहरों में मजदूरों को दत्ता शोचनीय तथा दयनीय है। उनका वेतन कम है। आनन्द-प्रमोद के साधन दुष्प्राप्य हैं। दिन मनानों में वे रहते हैं वे बिलों में प्रच्छेद नहीं। खाने-पीने को बना है। उनके बच्चों के लिये शिक्षा का प्रबंध नहीं। उनके स्वास्थ्य के लिये भी उचित प्रबंध नहीं है। इसका भी उनके चरित्र तथा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव होता है। इन सब बातों के कारण वह कार्यक्षमता में अन्य औद्योगिक देशों के मजदूरों की अपेक्षा बहुत पीछे हैं। परन्तु इसमें उनका दोष न होकर उनकी अवस्था का दोष है। साधारणतः मजदूर अशिक्षित होता है इसलिये वह नगरों की बातों की बेर में जनसत्ता है।

भारत में मजदूरों की दशा में सुधार करने के लिये मजदूर आन्दोलन का जन्म हुआ। मजदूर आन्दोलन का जन्म भारत में २०वां शताब्दी में हुआ। परन्तु प्रथम महायुद्ध के पहले यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो पाया था। युद्ध के बाद यह आन्दोलन अधिक संगठित हुआ। और मन् १९१८-१९२० के बीच में मजदूरों की कई हड़तालें हुईं। इस समय ही देश में कई मजदूर संघों की स्थापना हुई। मन् १९२१ में अखिल भारतीय मजदूर संघ (A. I. T. U. C.) की स्थापना हुई। परन्तु मन् १९२९ में जब मजदूर वर्ग पर नान्दवादिनों का प्रभाव बढ़ा तो श्री एन० एन० जंगी ने इण्डियन ट्रेड यूनियन फ़ेडरेशन की स्थापना की। इसका वापिसन साम्यवादी नहीं था। मन् १९३१ में एक नया संघ बन गया। इसका नाम आल इण्डिया रेट ट्रेड यूनियन बॉर्डर रखा गया। मन् १९३१

1. The industrial worker is not prompted by the lure of city life or by any great ambition. The city as such has no attraction for him and, when he leaves the village, he has seldom an ambition beyond that of securing the necessities of life. Few industrial workers would remain in industry if they could secure sufficient food and clothing in the village; they are pushed, not pulled to the city." Whiteley Commission's Report, p. 4.

मजदूरी का प्रयत्न हुआ और मजदूरों के मजदूरी के डेढ़ सौ प्रतिशत की स्थापना हुई। यह उसी वर्ष इण्डियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन में मिल गया। प्रथम भारतीय मजदूर सघ तथा इण्डियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन में एकता की वार्ता हुई। परन्तु एम० एन० राय ने इण्डियन फेडरेशन ऑन लबर नामक अलग सघ की स्थापना की। इसने युद्ध काल में सरकार के युद्ध-बाय को पूरी सहायता दी।

युद्ध के पश्चात् मजदूर सघ में साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव अधिकाधिक बढ़ता गया। मजदूरों की दशा में कोई सुधार न होने के कारण उनमें असन्तोष बढ़ा और हड़ताल हुई। कांग्रेस मजदूर आन्दोलन के इस स्वरूप में असन्तुष्ट थी। क्यापि साम्यवादी मजदूर आन्दोलन वर्ष युद्ध में विद्रोह रकता है। लेकिन कांग्रेस का महयोग में विश्वास करती है। इसलिये मजदूरों को साम्यवादी प्रभाव से दूर रखने के लिये कांग्रेस ने इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना मई सन १९१७ में की। इससे विरोधी कहते हैं कि यह नरप्राप्ति मर्यादा है। परन्तु हमारे समर्थकों का कहना है कि यह गांधी जी के सिद्धान्तों के अनुसार मजदूरों की अवस्था में सुधार करना चाहती है। अतः भारतीय मजदूर सघ की एकाग्रता नष्ट हो गई है। समाजवादियों ने हिन्दू मजदूर के नाम से अपना अन्त्य मधुका किया है। एक लक्ष्य के अनुसार साम्यवादियों में एकता का अभाव मजदूर आन्दोलन का बड़ा दुर्भाग्य है।

मजदूर सघों की मांगें मजदूरों में एक सूर्य की हैं। वचाहल है कि हमने में ४८ घण्टा में अधिक काम न हो। न्यूनतम वेतन (Minimum wage) निर्दिष्ट कर दिया जाय। मजदूरों के बच्चे के लिये शिक्षा का उचित प्रबन्ध हो। मजदूरों के रहने के लिये मालिकों की जगह सघों की व्यवस्था की जाय। उन्हें साल में कुछ बाँट के लिये छुट्टी दी जाय। औरत मजदूरों को बच्चा होने समय दस माह की अवकाश छुट्टी दी जाय। बाट लग जान पर मजदूरों को हर्जाता दिया जाय। उनके बीमों का प्रबन्ध हो। औरतों की जमीन के नीचे काम करने की न भेजा जाये। १४ वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम में न लगाया जाय। मजदूरों में मजदूरों का उद्देश्य ऐसी काम की दशाएँ स्थापित करना है ताकि मजदूर भी जीवन को ठीक प्रकार बिता सके।

मजदूर आन्दोलन के फलस्वरूप मजदूरों की दशा में कुछ सुधार हो गया। उनकी कुछ मांगें मान ली गई हैं। परन्तु अभी केवल पहला कदम उठाया है। सरकार का कर्तव्य है कि कानून द्वारा उद्योगपतियों को बाध्य करे कि वे मजदूरों की मांगों को मानें। सरकार ने इस सम्बन्ध में जो कानून बनाया है उसको इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य मजदूर सघों ने अतः तोषजनक बतलाया है।

भारत में मजदूर आन्दोलन पाश्चात्य देशों की अपेक्षा अत्यन्त है। इसके नीचे निम्न कारण हैं :

(१) मजदूरों में शिक्षा का अभाव । (२) मजदूरों में जाति, धर्म तथा भाषा की विभिन्नता । (३) मिलमालिकों का विरोध । (४) मजदूरों को अवकाश का अभाव । (५) भारतीय मजदूरों की बलिष्ठा (Migratory Character) । (६) मजदूर वर्गों में एकता का अभाव ।

**व्यापार :**—भारत का दूसरे देशों से व्यापारिक सम्बन्ध प्राचीन काल से बना था रहा है। आधुनिक काल में हमारा विदेशी व्यापार मुख्यतः हमारे काम के लिये न होकर इंग्लैण्ड के लाभ के लिये हुआ है। इसलिये अनेकों काल में हमारा देश कच्चा माल निर्यात करना या और पक्का माल आयात करता था। इसका फल यह है कि हमारे उद्योग-व्यो उन्नति नहीं कर सके। परन्तु अब परिस्थिति बदल गई है।

भारत का व्यापार दो प्रकार का है—आन्तरिक तथा विदेशी। आन्तरिक व्यापार को दो भागों में बाँटा जा सकता है—अन्तर्प्रान्तीय तथा तटीय व्यापार। अन्तर्प्रान्तीय व्यापार में तात्पर्य देश के विभिन्न भागों में स्थल-मार्गों के व्यापार से है। हमारे देश में इसका मुख्य बिंदु बिंदु व्यापार है त्रिगुणा बाँका गया है। इसलिये यह हमारे विदेशी व्यापार से अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें और अधिक उन्नति ही न करी है। उद्योग-व्यो तथा सेवाओं के विकास के साथ इसकी उन्नति स्वभावतः ही होगी। अभी तक रेलवे की भाँड़े सम्बन्धी नीति, बंकिंग और इन्फोरेन्स व्यवस्था विदेशी व्यापार के लिये अधिक उपयोगी रही है। तटीय व्यापार से तात्पर्य उस आन्तरिक व्यापार से है जो कि देश के विभिन्न भागों के साथ स्थल के मार्ग से न होकर बन्दरगाहों द्वारा होता है। अर्थात् लुट के किनारे-किनारे व्यापार। इसमें भी बहुत उन्नति ही सकती है अगर हमारे बन्दरगाहों में सुधार आये, नये बन्दरगाह बने तथा एक बड़ा व्यापारिक बंदर बनाया जाये।

द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् हमारे विदेशी व्यापार में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने हमारा व्यापार कुछ बढ़ गया है। पाकिस्तान बन जाने के कारण भी कुछ परिवर्तन स्वभाविक है। युद्ध के पूर्व हम अपने कुल आयात का ६४% पक्का माल अमेरिका से लेते थे। परन्तु अब यह केवल ५२% रह गया है। अब हमारे निर्यात का ६०% पक्का माल होता है। अब हमारा आयात में कच्चा माल अधिक होने लगा है। भारत के आयात का युद्ध के पूर्व रुम भाग मशीन कपड़ा था। इसके अतिरिक्त अन्य चीजें जैसे अफीम, रेशम के

इजन तथा मोटरगाड़ियाँ तेल, अनाज, धातुएँ, औजार, रंग, रासायनिक पदार्थ भी आयात होती थी। परन्तु अब आयात में प्रथम स्थान मशीनों का है। सूती कपड़ों का आयात घट गया है। इससे स्पष्ट है कि देश के अन्दर सूती कपड़ों का उद्योग बढ़ा है। भारत अन्य देशों को जूट का सामान तथा चाय भेजता है। कुछ देशों को वह सूती कपड़ा भी भेजता है। भारत अब भी अपने कुल निर्यात का २५% कच्चा माल बाहर भेजता है। आयात का ३५% कच्चा माल होता है।

भारत का विदेशी व्यापार अन्य देशों की अपेक्षा अत्यन्त कम है। इसलिये इस क्षेत्र में उन्नति करनी चाहिये। इस क्षेत्र में हमारे पिछड़े होने का मुख्य कारण विदेशी शासन काज में हमारा औद्योगिक अवनति है। उद्योग धन्धों की वृद्धि तथा कृषि में सुधार से हमारा विदेशी व्यापार बढ़ेगा। अभी तक हमारा विदेशी व्यापार अधिकतर विदेशियों के हाथ में है। इससे हमारी अत्यन्त हानि होती है। बहुत सा रुपया विदेशों को चला जाता है। जहाजी कम्पनियाँ, बैंक, बीमा कम्पनियाँ तथा विनिमय बैंक सभी अधिकतर विदेशियों के हाथ में हैं। परन्तु अब इस स्थिति में सुधार हो रहा है।

यातायात — किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए यातायात के साधनों की उन्नति आवश्यक है। आधुनिक औद्योगिक सगठन के लिये उन्नत यातायात के साधन आवश्यक हैं। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ के उद्योग-धन्धे बहुत उन्नत नहीं हैं इसलिये यहाँ बैलगाड़ियों से लेकर हवाई जहाज तक सभी प्रकार के साधन पाये जाते हैं।<sup>1</sup> परन्तु हमारे देश में अन्य उन्नत औद्योगिक देशों के बराबर यातायात में उन्नति नहीं हुई है। इसका दोष भी हमें विदेशी साम्राज्यवादी नीति के उपर ही रखना चाहिये।

भारत में यातायात के साधन उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक अत्यन्त ही पिछड़ी अवस्था में थे। रेलों का तब तक आरम्भ नहीं हुआ था और सड़कें बहुत छोटी सी थी। इनमें से भी अधिकतर सड़कें वर्षा-ऋतु में यातायात के लिए बेकार हो जाती थी। यातायात के साधनों का इतनी अवनति

1 'Cheap and efficient transport is indispensable for the economic development of the country'. In an under developed country of vast distances like India, with a majority of its population dependent on agriculture and with industries far from the main centres, all forms of transport exist from the old bullock cart to a modern motor car. — Five Year Plan, p. 169

अवस्था में होने के कारण देश को कई प्रकार की हानियाँ उठानी पड़ी हैं। इससे न केवल हमारे औद्योगिक उन्नति में ही बाधा पड़ी है परन्तु हमारी मानसिक सकीर्णता भी बनी रही। लार्ड डलहौजी ने सर्वप्रथम भारत में आधुनिक याता-यात के साधनों का प्रारम्भ किया। तब से देश में एक आर्थिक तथा सामाजिक प्रान्ति इनके फलस्वरूप हो गई।<sup>१</sup> यातायात के साधनों को हम चार भागों बाँट सकते हैं—रेल, सड़कें, नहर तथा नदियाँ जोर आकाश मार्ग।

(१) रेल —यह सबसे मुख्य आवागमन का साधन है। सन् १८४७ में सबसे पहले रेल बनाने के लिए दो अंग्रेजी कम्पनियों को टेण्डा दिया गया। परन्तु भारत में रेलों का प्रसारी बनना सन् १८५३ के बाद शुरू हुआ। इसके बाद रेलों के बनाने में बड़ी उन्नति हुई। इस समय देश में ३६,२७५ मील रेल की लाइनें हैं। इस समय देश में ९ प्रमुख रेल की लाइनें हैं। यद्यपि इनमें कोई सन्देह नहीं कि रेलों का हमारे देश में प्रारम्भ अंग्रेजी नामकों ने अपनी प्रताप-शील तथा मानिक मुविधा के लिए किया था तथा उन्होंने भाड़े की नीति ऐसी प्रस्तावी थी कि उससे देश के औद्योगिक विकास में बाधा पहुँची, तथा यह निर्दिष्ट रूप से कहा जा सकता है कि रेलों से देश को कई लाभ हुए। उन्होंने इसे एकता के सूत्र में बाँधा, देश में शान्ति स्थापित की तथा देश के व्यापार, कृषि तथा उद्योग-धंधों को लाभ पहुँचाया। हमारे देश में रेलों की और वृद्धि करनी चाहिये। हमारे यहाँ प्रति १००० मील पीछे केवल २५ मील ही रेल की लाइनें हैं। यह अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में रेलों के विकास पर ४०० करोड़ रुपया व्यय किया गया।

(२) सड़कें :—इस समय देश में २,१०,००० मील लम्बी सड़कें हैं। इनमें से ४ मुख्य सड़कें हैं। अन्य सड़कें इन्हीं की सहायक सड़कों के रूप में हैं। भारत में सड़कों की बड़ी कमी है। उनकी दशा भी सन्तोषजनक नहीं है। और सड़कें बननी चाहिये, विशेषकर जो गाँवों की नगरों से सम्बन्ध करें। इससे किसानों को बहुत लाभ होगा तथा कृषि की उन्नति होगी।

(३) नहर तथा नदियाँ :—भारत में नदियों की समस्या काफी है तथा ये काफी लम्बी लम्बी माँ हैं। परन्तु कई कारणों से इस प्रकार के यातायात का अधिक विचार नहीं हुआ है। रेलों के बनने के कारण भी जल मार्ग में यातायात को धक्का पहुँचा है।

(४) आकाश मार्ग :—हमारे देश में इसका प्रारम्भ पिछले २२ वर्षों से हुआ है। सबसे पहले १९२१ में भारत ने कुछ विदेशी कम्पनियों के जहाजों



आकाश मार्ग से जाने लगे। मनु १९३८ में टाटा ने एक कम्पनी स्थापित की। तब से कई कम्पनियाँ स्थापित हो चुकी हैं। अधिकतर आकाश मार्ग का मनुष्यो नया शक्ति साधने उपयोग किया जाता है। इन दिनों में अभी बहुत उन्नति की आवश्यकता है। पञ्चवर्षीय योजना में हमारे विकास का उपबन्ध रखा गया है। भारत सरकार ने हवाई जहाज यातायात का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। निजी कम्पनियों का प्रविकर दिया गया। हमारे स्थान पर दो निगमों का स्थापना हो गई है।

इन मध्य माधना के अतिशय मनुष्य, व्यवहार धारा गया है, प्रे-  
माणी आर्थिक व्यवस्था यातायात के माधन है।

भारत में बेकारी — इन में बेकारी का समस्या एक अत्यन्त ही भयानक समस्या है। यह समस्या केवल भारत में ही नहीं परन्तु अन्य देशों में भी कम या अधिक रूप में वर्तमान है। अनेक अवस्थाओं में अन्तर्गत यह एक समस्या है जिसका कोई एक भी नहीं निकलता है। परन्तु कुछ ऐसे देश भी हैं जिनका यह दावा है कि उन्होंने अपनी अवस्था इस प्रकार संगठित की है उसमें बेकारी के लिए कोई स्थान नहीं है और उन्होंने इन प्रकार संगठित की है कि उम्र बेकारी के लिए कोई स्थान नहीं है और उन्होंने इन समस्याओं को कर दिया है और भविष्य में भी यह समस्या नहीं उठेगी जैसा कि। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बेकारी की समस्या का किसी प्रकार एक करना ही चाहिये। लार्ड बेव्रिज (Lord Beveridge) के अनुसार बेकारी का मध्य में उठा दोष भीतिक तत्त्वों के कारण है। बिना बेकारी नहीं दिया हुआ देश की प्रगति नहीं हो सकती है। जहाँ बेकारी प्रचलित होती है वहाँ प्रा० लास्की (Prof. Laski) के अनुसार व्यक्ति अपनी स्वतन्त्रता का उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्योंकि स्वतन्त्रता का दावा पर आधारित है और जहाँ बेकारी हागा वहाँ आशा के लिये कोई स्थान नहीं रह जाता है।

हमारे देश में दो प्रकार की बेकारी है — (१) प्राथमिक बेकारी तथा (२) नगरीय बेकारी। हम इसका पथ प्रत्येक वर्णन करेंगे।

प्राथमिक बेकारी — गाँवों में बेकारी दो प्रकार की है — स्थायी तथा अस्थायी या मौसमी। प्राथमिक बेकारी का कारण यह है कि अनेक व्यक्ति भूमिहीन हैं। इन्हें भूमिहीन उपलब्ध करा जाता है। यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये कि इन किसानों का एक बड़ा भाग भी जिनके पास जमीन है पूर्णरूप से बेउत्पन्न भूमि पर ही आधारित नहीं है। उन्हें अपनी आय के लिये कुछ और काम करना पड़ता है। ग्रामों में ऐसे लोग भी हैं जो कि कारीगर बने जा सकते हैं। ये छोटे उद्योग-धंधा आदि में लगे रहते हैं। परन्तु इन्हें अपने व्यवसाय

से इतनी घाय नहीं होती कि उनका उचित प्रकार से पालन हो सके। दूसरी प्रकार की अर्थात् अस्थायी बेकारी का यह कारण है कि सात में बई महीने किसान के पास कुछ काम नहीं रहता। क्योंकि यह बारिश पर निर्भर रहता है इसलिए सात में बई महीने खेती का काम बन्द रहता है।

ग्रामीण बेकारी के निम्नोक्त मुख्य कारण हैं —

( १ ) हमारे देश की कृषि प्रणाली इतनी अधिक प्राथमिक तथा पुरानी है कि उसमें दोष ही दोष भर गये हैं। भारतीय किसान भावनान की ओर प्राथमिक रूपसे बँटा रहता है। इसलिए वह पूर्णतः मनमूल पर निर्भर रहता है। प्रति-वृष्टि तथा अनावृष्टि के समाचार हमें हर वर्ष ही मिलते रहते हैं और ये दोनों ही कृषि के लिये घातक हैं इसलिए प्रतिवर्ष ही देश के किसी न किसी भाग में बाढ़ान्तों की बनी तथा दुर्निमित्त होती हैं।

( २ ) हमारे गाँव बाज़ों के पास कृषि के प्रतिरिक्त अन्य कोई उद्योगिक संस्था नहीं है, जिससे वे अपनी आय बढ़ा सकें।

( ३ ) खेतों से उत्पादन घटता जा रहा है। इसके अनेक कारण हैं जैसे, कृषि की प्राथमिक प्रणाली, खेतों का छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट जाता विमान की निर्धनता, किसान का बुरा स्वास्थ्य, उनकी भाग्यवादिता आदि।

( ४ ) प्रतिवर्ष जनसंख्या में वृद्धि के कारण भूमि पर भार बढ़ता जा रहा है।

( ५ ) ग्रामीण गद्योग-व्यवसायों का ह्रास होता जा रहा है इनलिये उसमें लगे लोग बेकार हो रहे हैं।

( ६ ) किसान अपनी उपज को उचित दामों में नहीं बेच पाता है, अतएव वह व्यापार के कारण बहुधा अल्प-वस्तु हो जाता है। इसके फलस्वरूप वह महाजनों तथा मूदखीरों के हाथों में फँस जाता है।

ग्रामीण बेकारी दूर करने के उपाय :- गाँवों की बेकारी दूर करने के लिए निम्नलिखित मुख्य मुख्य उपाय हैं :-

( १ ) कृषि की प्रणाली में सुधार विद्या जाय जिससे उत्पादन में वृद्धि हो।

( २ ) परेड्ड उद्योग पधों की वृद्धि की जाय जिनसे किसान अपने खाली समय का उपयोग कर सकें।

( ३ ) नाभूतिक खेती को प्रोत्साहन दिया जाय।

( ४ ) मिर्चार्थ आदि व्यवस्था की जाय।

( ५ ) जनसंख्या की वृद्धि के कारण जो भूमि पर प्रतिवर्ष भार बढ़ रहा है उसे रोकना चाहिए । इसमें लिए एक उपाय तो यह है कि देश में औद्योगिक उन्नति तीव्रता से हो तथा दूसरा यह है तथा इस पर भी हमें विशेष बल देना चाहिये कि मरतति-निरोध ग्रान्दोलन को व्यापक बनाया जाय ।

नगरों में बेकारी — बड़ बकारी का प्रचार की है मध्यवर्गीय वर्गों तथा औद्योगिक क्षेत्र में बेकारी । प्रतिवर्ष हमारे स्कूल व कॉलेजों से लाखों नवयुवक डिग्री लेते हैं परन्तु इनमें से आधे को भी काम मुश्किल में मिलता है । ये बेकार नवयुवक न केवल अपने कुटुम्बों के ऊपर भार हैं अपितु समाज के लिये भी उनसे भय पैदा होता है क्योंकि निराशा उनसे घेर लेती है । राज्य तथा समाज के प्रति इस निराश्य के कारण उनका मन में बहुत उत्पन्न होती है । उनमें असामाजिक भावनाओं का जन्म होता है । उनमें ही क्रान्तिकारी भावनाएँ जागृत होती हैं । इसलिये उनसे राज्य तथा समाज के प्रतिशत्रु को भय पैदा हो सकता है । औद्योगिक क्षेत्र में भी बेकारी बढ़ रही है । प्रतिवर्ष हजारों व्यक्ति देहातो से नगरों में काम की खोज में आते हैं । उनमें से से थोड़े ही काम पाते हैं । शेष वैसे ही मारे मारे फिरते हैं । क्योंकि अभी हमारे देश में जन-संख्या का एक छोटा सा भाग ही उद्योग धंधों पर निर्भर है इसलिए औद्योगिक क्षेत्र में बेकारी भीषण नहीं हुई है ।

नगरों की बेकारी के कारण — ( १ ) प्रतिवर्ष देश में नगरों की जन-संख्या की वृद्धि होती जा रही है । इसका कारण यह है कि गाँवों से लोग काम खोजने नगरों में आते हैं । परन्तु काम केवल एक थोड़े से ही भाग को मिल पाता है ।

( २ ) हमारी शिक्षा की प्रथा दोषपूर्ण है । यह नवयुवकों को सिवाय बाबू-

1 "The remedy of the problem of rural unemployment lies thus partly in the improvement of agriculture and the development of small scale industries but mainly in the absorption of greatly increased numbers of people in large scale manufacturing industries" Banerji Ibid, p 639

2 Unemployment of this type is a more serious evil than commonly recognized Besides the individual suffering it causes a cumulative existence of a dangerous to the political stability of the state" Jathar and Baner Ibid, p. 468.

नगरी के अन्य किसी प्रकार के काम के योग्य नहीं बनायी है। इनके स्थान में टेक्निकल तथा औद्योगिक शिक्षा का प्रवर्ध होना चाहिये।

(३) हम लोग शारीरिक श्रम को घृणा की दृष्टि में देखने हैं। अतएव हमारे शिक्षित नवयुवक ऐसा काम चाहते हैं जिनमें उनके हाथ और कानडे काम न हो जाय।

(४) जाति-प्रथा के कारण लोग कई तरह का काम नहीं करना चाहते हैं। जैसे एक छात्राय या लड़का मोची का काम नहीं करेगा।

(५) बाल-विवाह तथा जनन-द्वारा की वृद्धि भी इन प्रकार की बेकारी के कारण है।

(६) समुचित कुटुम्ब-प्रणाली के कारण भी कई लोग उत्तरदायित्व विहीन हो जाते हैं।

(७) देश का उद्योग-धंधों में पिछड़ा होना इन प्रकार की बेकारी का मूल-भूत कारण है। शिक्षित नवयुवकों के लिये केवल योही नौ ही नौकरियों का द्वार खुला है। इंग्लैंड में जेना तथा मरकागो नौकरियों के प्रतिस्ति १६०० प्रकार की अन्य नौकरियां हैं। परन्तु भारत में केवल ४० ही हैं।

नगरी की बेकारी दूर करने के उपाय

(१) बेकारी को दूर करने का सबसे उत्तम उपाय देश में उद्योग-धंधों का विकास करना है। इसका फल यह होगा कि लोगों की समस्या में पड़े-लिखे नवयुवकों को काम मिल जायगा।

(२) बड़े उद्योगों के साथ-साथ छोटे उद्योगों की भी वृद्धि करनी चाहिये। इनमें भी अनेक नवयुवकों को काम प्राप्त हो जायगा।

(३) शिक्षा-प्रदा में भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों की आवश्यकता है। शिक्षित वर्ग में जो बावगीरी की भावना आगई है उसे नष्ट करना चाहिये। शिक्षा अधिकारी व्यक्तियों के लिये ऐसी होनी चाहिये कि वह उनके जीवन-निर्वाह का माध्यम हो सकें।

(४) टेक्निकल तथा औद्योगिक शिक्षा पर अधिक बल देना चाहिये। हमारे अधिकांश नवयुवक इंगलिये कालिगो तथा विन्चिघायलो में जाते हैं क्योंकि उन डिग्रियों को वे नौकरी पाने में सहायक पाते हैं।

(५) देश में प्रारम्भिक शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिये । इससे ही कई हजार नवयुवकों को नौकरी मिल जायेगी ।

(६) अन्य प्रकार की नाभाजिव सेवाओं का भी विकास करना चाहिये । इसके फलस्वरूप भी शिक्षित नवयुवकों को काम मिल जायगा ।

(७) इस प्रकार के काम पषा को भी बढ़ाना चाहिये, जैसे गृह-निर्माण, इञ्जीनियरिंग आदि ।

(८) रोजगार केन्द्र अधिकाधिक सख्या में खोलने चाहिये ।

(९) खेती की ओर शिक्षित नवयुवकों का उत्साहित करना चाहिये । यह तभी सम्भव है जब कि खेती योग्य भूमि को बढ़ाया जाय तथा खेती को वैज्ञानिक ढंग से किया जाय ।

**पंच-वर्षीय योजनाओं तथा बेकारी की समस्या का हल**

हमारी सरकार का ह्य इस समस्या की ओर उपेक्षापूर्ण नहीं है । अपने सीमित साधनों के द्वारा सरकार इस समस्या का मूलज्ञाने के लिये ध्यान दे रही है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना एक प्रारम्भिक स्तरों में कहा गया है 'जब कि पहली पंचवर्षीय योजना का आधा समय बीत चुका तब एम्प्लायमण्ट एक्चेंजो अर्थात् नौकरी दिलाने के दफ्तरी में दर्ज सख्याओं में पता लगा कि देश में रोजगार की अवस्था बिगड़ रही है । इसलिये १९५५-५६ की योजना में श्रम सम्बन्धी कुछ ऐसे कार्यक्रम सम्मिलित किए गये, जिनसे अधिक लोगों का रोजगार मिल सके । फिर भी पहली योजना की अवधि में रोजगार मिल सकने के हालात बिगड़ते ही गये । एम्प्लायमण्ट एक्चेंजो के रजिस्ट्रारों में दर्ज बेरोजगार व्यक्तियों की सख्या जो मार्च १९५१ में ३ लाख ३७ हजार थी, वह दिसम्बर १९५३ और दिसम्बर १९५५ में बढ़ कर क्रमशः ५ लाख २२ हजार और ६ लाख २२ हजार तक पहुँच गई । इन सख्याओं से बे रोजगारी का अन्दाजा एक हद तक ही लगाया जा सकता है ; इनकी वृद्धियाँ प्रायः सर्वविधित हैं । परन्तु यह अनुभव अधिकाधिक माया में किया जा रहा है कि औद्योगिक विकास का योजनाएँ तभी लोकप्रिय हो सकती हैं जब कि लोगों को रोजगार दिलाना भी इनका एक प्रधान लक्ष्य हो । इसलिये इस सम्बन्ध में सबकी सम्मति है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का एक स्पष्ट उद्देश्य लोगों को रोजगार देना ही होना चाहिये ।"

पहले योजना काल में लगभग ४५ लाख व्यक्तियों की रोजी का प्रबन्ध हुआ होगा । इसके अनिवार्य व्यापार तथा वाणिज्य के क्षेत्र में भी नए अवसर उत्पन्न हुए होंगे । परन्तु इस काल में श्रमिक सख्या की वृद्धि इतने बड़ी अरिज हुई ।

इसके प्रतिरिक्त पहली योजना का प्रभाव मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ा। वहाँ व्यक्ति के विकास और बड़ी संख्या में मकानों के निर्माण से बहुत से लोगों को पूरे समय का रोजगार मिला।

योजना आयोग द्वारा दिसम्बर १९५५ में नियुक्त एक अध्ययन समिति ने यह अनुमान लगाया है कि आगामी पांच वर्षों में १४.५ लाख शिक्षित व्यक्ति यमिनी की संख्या में और बढ जायेंगे। इसमें वर्तमान ५.५ लाख संख्या जोड देने से यह विदित हो जायगा कि द्वितीय योजना काल में २० लाख शिक्षित बेकारों को काम दिलाना होगा। यह अनुमान है कि सरकारी क्षेत्रों में १० लाख तथा निजी क्षेत्रों में १ लाख व्यक्तियों को काम मिल जायगा। सब भी ८ लाख बच जायेंगे। इसके प्रतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त बेकारी भी द्वितीय योजना काल में बनी रहनी। यद्यपि यह बिल्कुल सच है कि अनेक लोगों को काम प्राप्त होगा। इसने यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्थिति धाज से अधिक नहीं बिगड़न पायेंगी।

**भारतवर्ष के दो देशों में विभाजन का आर्थिक परिणाम :—**भारतवर्ष के विभाजन के बाद एक समस्या एकदम उड खडी हुई। वह सरणायितों की समस्या थी : लाखों गृहहीन व्यक्ति बिना किसी आर्थिक साधनों के एक देश से दूसरे देश को गये। भारत में सरणायितों की संख्या ने अत्यन्त भीषण कर धारण कर लिया था। सरकार ने अपनी ओर से पूरा प्रयत्न किया परन्तु अभी तक यह समस्या पूरी प्रकार से हल नहीं हो पाई है।

विभाजन के फलस्वरूप न भारत आर्थिक दृष्टि से स्वयंपाति हो सकता है और न पाकिस्तान। क्योंकि भारत में रईस तथा अट के उत्पादन क्षेत्र मुख्यतः पाकिस्तान में चले गये हैं। पहले हजारों देश में अनाज को कमी नहीं थी। परन्तु अब प्रति वर्ष हमें विदेशों से बहुत परिमाण में आधान मँगाने होते हैं। पाकिस्तान भी आर्थिक दृष्टि से स्वयंपाति नहीं है। वहाँ कपास तथा अट पैदा होती है परन्तु वहाँ सूती तथा अट की मिलें नहीं हैं। इसलिये पाकिस्तान को इन वस्तुओं के लिये दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस प्रकार दोनों देश आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गये हैं। कुल लोगों का कहना यह है कि अंग्रेजी कूटनीति का यह फल है। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत या पाकिस्तान शक्तिशाली देश हों।

**पंचवर्षीय योजनाएँ—**भारतवर्ष आर्थिक दृष्टि से अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ के लोगों का जीवन-स्तर अन्य देशों की तुलना में अत्यन्त निम्न है। गरीबी तथा बेकारी यहाँ के भीषण अभिशाप है। भारतवर्ष की सरकार ने देश को आर्थिक उन्नति के लिए एक योजना बनाई है जो कि बालू भी हो गई है।

इस योजना का पंचवर्षीय योजना कहत है। इस योजना का उद्देश्य जनता के जीवन स्तर को उठाना है। ताकि वे सुखा तथा सम्पन्न जीवन व्यतीत कर सक। हालाँकि जहाँ एक ओर इसका उद्देश्य देश के समस्त साधना का देश की पैदावार बढ़ाने के लिये उपयोग करना है और वहाँ दूसरी ओर इसके द्वारा आर्थिक असमानता को कम करना भी उद्देश्य है। अन्त में योजना के निर्माताओं द्वारा यह कहा गया है कि यद्यपि आरम्भ में पैदावार बढ़ाने पर ही अधिक ध्यान देना पड़ेगा तथापि अन्तिम उद्देश्य वर्तमान आर्थिक ढाँचे को बदलना ही होगा जिससे कि यहाँ के सब निवासी उत्तरोत्तर अधिक शिक्षा सुरक्षा तथा सम्पन्नता का उपभोग कर सकें।

**प्रथम पंचवर्षीय योजना** — यह पंचवर्षीय योजना वास्तव में भविष्य में अधिक शीघ्र आर्थिक उन्नति प्राप्त करने के लिये प्रथम पग मात्र है। इस योजना में सरकार २०६९ करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस खर्च करने में विभिन्न बातों का विचार ध्यान रखा जायगा।

(१) विकास की प्रथा को इस प्रकार बढ़ाना जिससे भविष्य में वह इनसे भी महत्तर काम का आधार बन सके।<sup>1</sup>

(२) देश में विश्वास के लिए उपलब्ध समस्त साधन।

(३) सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में विकास तथा साधनों की आवश्यकताओं के मध्य निकट सम्बन्ध।

(४) इस योजना से पूर्व केन्द्रीय तथा प्रदेशीय सरकारों द्वारा आरम्भ की हुई विकास योजनाओं को पूरा करने की आवश्यकता।

(५) युद्ध तथा विभाजन से उत्पन्न देश की आर्थिक अव्यवस्था को दूर करना।

1 'While in the initial stages the accent of endeavour must be on increased production because without this no advance is possible at all—our planning even in the initial stages should be confined to stimulating economic activity within the existing social and economic framework. That framework itself has to be remoulded so as to secure progressively for all members of the community full employment, education, security against sickness and other disabilities and adequate income. Five Year Plan (People's ed.) p 11

इस २०६९ करोड़ रुपये का खर्च विभिन्न मदों के द्वारा विभक्तित प्रकार से किया जायगा—

(करोड़ रुपयों में)

ग्रामीण तथा सामूहिक विकास	२२१
निर्वाह तथा बहु उद्देशीय निर्वाह	१२८
शक्ति योजनाएं	२२६
शक्ति (विजली)	१२७
जातायात तथा सड़कमरम्मत	६९७
उद्योग	१७३
सामाजिक सेवाएँ	३४०
पुनर्वास	८५
योग	५२
योग	२०६९

केंद्रीय सरकार तथा प्रादेशिक सरकारों के मध्य इन खर्च का वितरण इस प्रकार किया गया था :

केंद्रीय सरकार (रिली तहत)	१-८१ करोड़ रुपये
'क' भाग के राज्य	५१० " "
'ख' " "	१-३ " "
'ग' भाग के राज्य	२२ " "
जम्मू तथा काश्मीर	१३ " "

इन योजना की सफलता पर इसके प्रायोजकों की संदेह था। इनके अनुसार इस योजना से देश की कोई भी स्थिति होने की आशा नहीं थी। उनका कहना था कि इतना खर्च करने के बाद भी देश की आर्थिक समस्या में कोई विशेष उन्नति नहीं होगी। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार इस योजना में कृषि के ऊपर अधिक ध्यान दिया गया है। परन्तु किसी देश की वर्तमान स्थिति में उन्नति केवल तभी सम्भव है जब कि उद्योग संघों के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाय। इस योजना के सफल हो जाने पर भी, इन प्रायोजकों के अनुसार देश अन्य देशों पर आर्थिक दृष्टि से निर्भर रह जायगा। देश का colonial



status बना ही रहता। इसके अनिश्चित अन्य दृष्टियाँ स भी इस योजना को आलोचना की गई, तथा इसे अव्यवहारिक बतलाया गया। कुछ भयंशास्त्रियों के अनुसार इससे देश में मुद्रा प्रसार बढ़ने का भय है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह योजना पूरी तरह नीजरशाही द्वारा चलाई जायगी, इसकी सफलता संदेहजनक है। सरकार ने जनता के गहयोग पर अधिक ध्यान नहीं दिया है।

परन्तु दूसरे कई विद्वानों तथा राजनीतिज्ञों द्वारा इस योजना की भूरि भूरि प्रशंसा की गई। एक पयवेक्षक के अनुसार यह योजना प्रगतात्म्य देश में आर्थिक योजना का प्रथम उदाहरण है। इससे देश की महदवर्धन उत्पत्ति होगी। यह अभिप्रेत के आर्थिक विकास के लिये सुदृढ़ नींव बना देगी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रगति — प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सीमा तक सकल हुई तथा इसमें क्या कमियाँ रह गई इसका ज्ञान हमें निम्न-लिखित उद्धरण से ही जायगा।

‘अर्थ व्यवस्था पर पहली योजना की बहुत अच्छी प्रतिजिया हुई है। कृषि और औद्योगिक उत्पादन में बहुत काफी वृद्धि हुई है। मूल्य युक्ति सगत मत्त पर है। देश का वैदेशिक हिमाब-फिताव भी सन्तुलित है। पहली योजना में जो महत्वपूर्ण लक्ष्य रखे गये थे वे पूर्ण हो चुके हैं और सब तो यह है कि कई क्षेत्रों में हम उनसे भी पार कर चुके हैं। इन पाँच वर्षों में कोई १७०,००,००० एकड़ नई जमीन को सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है। बिजली उत्पादन की प्रस्थापित क्षमता २२ लाख गिलोवाट में बढ़कर ३४ लाख गिलोवाट हो गई है। रेलों के पुनर्स्थापन के सम्बन्ध में यथार्थ प्रगति हुई है। सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में कई औद्योगिक कारखानों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है। इनके विपरीत पहली योजना में लगे और दृष्टांत के एक नए कारखाने और बिजली के एक भारी कारखाने के स्थापित किए जाने की जो व्यवस्था की गई थी उसके सम्बन्ध में बहुत सीमित प्रगति के अतिरिक्त उसमें कोई उन्नति नहीं हुई। इसके अतिरिक्त सामुदायिक राजना कार्य, सामोशोय तथा छोटे पैमाने के उद्योगों इत्यादि में जितना व्यय होना था, वह नहीं हो सका। फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि कुल मिला कर हमारी अर्थ व्यवस्था काफी मजबूत हो गई। योजना के कारण दीर्घकाल से स्थिर परिस्थिति में एक नया प्रगतिशील उत्पादन आ गया है। गत ५ वर्षों में राष्ट्रीय आय में अनुमानत १८ प्रतिशत वृद्धि हुई। जब कि केवल ११ प्रतिशत बढ़ने की आशा थी। १९४१-५६ में सार्वजनिक क्षेत्र में

विकास सम्बन्धी खर्च १९५१-५२ के मुकाबले में टाई मुने में अधिक है। निजी क्षेत्र में पूँजी विनियोग आत्म के अनुरूप हुआ है। यह नारा विकास हमारी अर्थ-व्यवस्था पर किसी प्रकार का भारी दबाव या असन्तुलन पैदा किये बिना हो हुआ है। योजना ने योगदान मिला तथा तत्पश्चात् की जावना अधिक मात्रा में जानूत हुई।

प्रथम पंचवर्षीय योजना की कई दृष्टियों से मालोचना की गई है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि प्रथम योजना ने देश को कुछ लाभ हुए तथापि यह भी निश्चय है कि इस योजना में अनेक त्रुटियाँ रह गई थीं। योजना के निर्माण-कर्ताओं ने देश में उपलब्ध साधनों का पूरा-पूरा अनुमान नहीं लगाया था। इन्होंने उपलब्ध मौलिक साधनों से वित्तीय साधनों को अधिक महत्व दिया। योजना ने औद्योगिक विकास से अधिक धन कृषि पर दिया। परन्तु कृषि में देश आत्म निर्भर नहीं हो सका। परन्तु इसने यह नहीं समझना चाहिए कि इस योजना से देश को लाभ नहीं हुआ। इसका सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि इनमें एक निश्चित आर्थिक स्थिति में एक गतिशील तत्व का प्रवेश कराया।<sup>1</sup>

**द्वितीय पंचवर्षीय योजना :—**द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य प्रथम योजना के कामों को और अधिक आगे बढ़ाना है। वास्तव में द्वितीय योजना प्रथम से अधिक महत्वाकांक्षी है। राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने इस द्वितीय योजना के विषय में कहा था; “द्वितीय योजना प्रथम योजना की अपेक्षा अधिक महत्वाकांक्षीपूर्ण है। उसे कार्य रूप देने के लिये देश लोगों की पहले की अपेक्षा कहीं अधिक प्रयत्न करना होगा। समाजवाद के मूलों पर समाज की-स्थानता, राष्ट्रीय धर्म का समुचित स्तर तक विकास और देश के सभी नागरिकों के लिए समान अवसर—इन सभी बातों को पूरा करने के लिए सभी हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमारी उन्नति के आधारभूत मापदंड क्या समाज का हित और सममानता का अधिक निगमन होगा। हम अपनी योजना की एक मजिल तक कर चुके हैं। और अब एक साम्य-निर्माणिक दूसरी मजिल की ओर बढ़ने वाले हैं।”

1. “The First Plan deserves a good deal of commendation as it was the first experiment of developmental planning for uplifting the lagging Indian economy. The Indian Economy responded well to the stimulus of the Plan. The First Plan introduced a new dynamic element in a long static and stagnant situation.” Atak Ghosh—Indian Economy—Its Nature and Problems. (1958)

उपर्युक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि द्वितीय योजना की आधार-भूमि समाज का समाजवादी मगठन है। इसीलिए योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित इसकी रूपरेखा में इसके उद्देश्यों का वर्णन करने समय इस लक्ष्य पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

यह योजना निम्न मुख्य लक्ष्यों को ध्यान में रख कर बनाई गई है —

(१) राष्ट्रीय आय में इतनी वृद्धि हो कि देश के रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो सके। इससे यह तात्पर्य है कि जनता के भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की ग्यूनतम आवश्यकताएँ सतोषजनक रूप में पूरी हो सकें।

(२) मूल तथा भारी उद्योगों के विकास पर विशेष बल देते हुए देश का द्रुतगति से औद्योगीकरण हो। यह इसलिये आवश्यक है क्योंकि इसके बिना देश का भावी आर्थिक विकास सम्भव नहीं है।

(३) रोजगार सम्बन्धी सुविधाओं का और अधिक विस्तार करना, जिससे देश की बेकारी समस्या का उचित समाधान हो सके।

(४) आय तथा सम्पत्ति की विषमताओं का निराकरण तथा आर्थिक शक्ति का पहले से अधिक समान वितरण। यह स्पष्ट है कि इसके बिना समाजवादी ढंग की अर्थ व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती है।

इन उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये केन्द्र और राज्यों की सरकार मिलकर इन योजना के पाँच वर्षों में कुल ४,८०० करोड़ रुपये व्यय करेंगी। इसमें से कृषि तथा सामुदायिक विकास पर १२ प्रतिशत, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर ९ प्रतिशत, बिजली पर ९ प्रतिशत, उद्योग व खनिज पर १९ प्रतिशत, परिवहन तथा संचार पर २९ प्रतिशत, समाज-सेवा, मकान तथा पुनर्वास पर २० प्रतिशत तथा शेष अन्य मदों पर व्यय किया जायगा।

यदि हम प्रथम तथा द्वितीय योजनाओं के व्यय का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमें यह दृष्टिगोचर होगा कि द्वितीय योजना में विशेष बल औद्योगीकरण पर दिया गया है। प्रथम योजना में कृषि को अधिक महत्व दिया गया था। परन्तु इससे यह नहीं सोचना चाहिये कि द्वितीय योजना में कृषि, सिंचाई या अन्य मदों पर व्यय कम कर दिया गया है। सत्य तो यह है कि सभी मदों पर द्वितीय योजना में प्रथम की अपेक्षा अधिक व्यय किया जायगा। परन्तु तुलनात्मक दृष्टि से द्वितीय योजना में उद्योगों को अधिक महत्व दिया गया है।

प्रथम एवं द्वितीय योजना के व्यय का तुलनात्मक विवरण नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है —

प्रथम योजना		द्वितीय योजना
	कुल व्यय—प्रतिवर्ष	कुल व्यय—प्रतिवर्ष
कृषि एवं सामुदायिक विकास	—३७२ करोड़—१६	५६५ करोड़ —१२
मिचोई तथा बाट का नियन्त्रण	—३९५ " —१७	४५८ " —९
बिजली	—२६६ " —११	४४० " —९
उद्योग व श्रमिक	—१७९ " —७	८९१ " —१९
परिवहन तथा संचार	—२५९ " —२४	१३८४ " —२९
समाज सेवा, गृह-निर्माण तथा पुनर्वास	—५४७ " —२३	१४६ " —२०
विशेष	—४१ " —२	११६ " —२
योग	२,३५६—१००	४,८०० —१००

सरकारी क्षेत्र के अतिरिक्त द्वितीय योजना काल में २,३०० करोड़ रुपया निजी क्षेत्र में व्यय किया जाएगा। इस व्यय की रूप रेखा निम्नोक्त होगी :—

उद्योग और श्रमिक	—	५६० करोड़ रुपया
परिवहन, बिजली आदि	—	९० " "
कृषि एवं ग्राम उद्योग	—	२०० " "
गृह-निर्माण	—	१,०५० " "
अन्य मद	—	४०५ " "
योग	—	२,३०० " "

निजी क्षेत्र में भी उद्योगों पर एक बड़ी रकम व्यय की जाएगी। उद्योगों में मुख्यतः मूल उद्योगों में ही व्यय होगा इसका कारण यह है कि यदि देश में मूल उद्योगों की स्थापना हो जायगी तो इससे आर्थिक दृष्टि से देश की विदेशों पर निर्भरता बड़ी मात्रा में कम हो जायगी। परन्तु योजना में उपयोग

की वस्तुओं पर ध्यान दिया गया है। इसके लिए यह प्रबन्ध है कि इनका उत्पादन गृह एवं लघु उद्योगों द्वारा हो। इससे एक लाभ यह भी होगा कि देश व अनेक बेकारों का रोजी मिल जायगी।

दूसरी योजना देश में फैली बेकारी समस्या को भी कुछ मात्रा तक दूर करने में सहायक होगी। दूसरी योजना की अवधि में कृषि के प्रतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में ८० लाख नए लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। परन्तु इस काल में यह अनुमान है कि लगभग १ करोड़ व्यक्ति और रोजी की तलाश में होंगे। इस समय लगभग ४५० लाख व्यक्ति बेकार हैं। इससे यह देखने है कि द्वितीय योजना द्वारा बेकारी की समस्या का पूरी तरह हल नहीं होगा। योजना की रूप-रेखा के अनुसार इन ८० लाख व्यक्तियों को निम्नोक्त उद्योगों में काम मिलेगा

घरेलू उद्योग तथा गृह निर्माण	—	२१	लाख
बड़े उद्योग	—	८	,
छोट उद्योग	—	४५	"
सरकारी नौकरियाँ	—	४३	"
वन विभाग सामुदायिक विकास आदि	—	४२	,
शिक्षा विभाग	—	२६	,
रेल तथा अन्य यातायात के साधन	—	४३	,
समाज सेवा	—	१४	,
स्वास्थ्य विभाग	—	१२	"
व्यापार	—	२३१	"

अन्त में इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि आय तथा सम्पत्ति के विपरीतताओं का निराकरण किस प्रकार किया जायगा? योजना में सरकार को इसके लिए अनेक सुझाव दिए गए हैं। उदाहरणार्थ (१) देश भर में अधिक से अधिक नू सम्पत्ति कितना हो इसको सीधा निर्धारित कर देनी चाहिए (२) इसी प्रकार अधिकतम आय की सीमा निर्धारित करने की दिशा में भी सोचना चाहिए। (३) धनी तथा निधनों व मध्य अन्तर कम करना चाहिए। इसके लिए अनेक प्रकार के कर जैसे अधिक आयकर, मुनाफा कर आदि का सुझाव दिया गया है। (४) धर्मियों, स्त्रियों पिछड़े वर्गों की स्थिति के लिए विशेष सुविधाएँ दी जायें। (५) सामाजिक सेवाओं का विस्तार किया जाय। इत्यादि।

द्वितीय योजना में उत्पादन-वृद्धि के लक्ष्य निम्नलिखित हैं— ग्राम—८०%, रेल-इजन—७६%, मोटर कार—१४८, मल समाप्त—२२%, मोमेट—१०८%, कामज—४९०%, बिजली की मोटर—१५०%, शीशे बट्टों—५२%, कच्चा लोहा—९७%, तैयार लोहा—१३१%, एयूनीनी-यम—२३३%, रसायनिक खाद—३५८%, टॉयल इजन—१०५%, नाद-किल—१००%। उद्योगों के प्रतिष्ठित पत्र पत्र के उत्पादन में भी वृद्धि होगी। यह अनुमान है कि पत्र में १५४%, कपान में ३१%, बूट में २५%, गन्ना में २२४%, तथा तिलहन में २७.३% वृद्धि होगी।

इस योजना का कल फल यह होगा कि राष्ट्रीय आय ४ वर्ष पश्चात् १०,८०० करोड़ रुपये में बढ़कर १३,४८० करोड़ हो जायगी। प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय ८० रुपया बढ़ेगी। वर्षान्त २५० के स्थापन पर ३३० रुपया हो जाएगी।

द्वितीय योजना की कांग्रेस के विरोधियों द्वारा कड़ी आलोचना की गई है। यह कहा गया है कि इसके द्वारा समाजवाद का आदर्श कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। समाजवाद की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि अति-कारी कदम उठाया जाय। यह मत है कि विकसित के द्वारा समाजवाद की स्थापना में अधिक समय लगेगा, परन्तु शान्तिपूर्ण उपायों को हम नहीं छोड़ सकते हैं। कुछ आलोचकों का यह कहना है कि इन योजना द्वारा मुद्रा-स्फीति का भय बढ गया है और अन्त में इसी कारण समस्त देश की आर्थिक-स्थिति के लिये भीषण संकट उत्पन्न हो जायगा। इस योजना की सफलता के लिये बिल्ली अधिक पूँजी की आवश्यकता है वह देश में उपलब्ध नहीं है और इसका कोई निश्चय नहीं कि विदेशों से इस उद्देश्य के लिये हमें पूँजी प्राप्त होगी। देश में कर बढ रहे हैं, दायित्व जनता को कष्ट बढ गया है। उससे यह आशा करना गलत है कि वह योजना कार्य में उत्साहपूर्वक सक्रिय भाग लेगी।

परन्तु हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि सरकारने योजना के निर्माण में इन सब कठिनाइयों पर ध्यान दिया है। इसलिए भारतीय जनता को उत्साह-पूर्वक योजना की सफलता में योग देना चाहिये।

**सामुदायिक-योजनाएँ (Community Projects):**— देश में इन योजनाओं का आरम्भ अक्टूबर, १९५२ में हुआ। इनका उद्देश्य भारत के गाँवों की उन्नति है। यह उन्नति नवनीत होगी। साम्य जीवन के सम्पूर्ण स्तर

का वहाँ के निवासियों के सामूहिक श्रम से ही उन्नत करना इन योजनाओं का उद्देश्य है।<sup>1</sup>

इन योजनाओं की आवश्यकता के मुख्य कारण निम्नोक्त हैं

(१) ग्रामजीवन का सर्वांगीण विकास आवश्यक है। भारत मुख्यतः कृषि प्रधान देश है। यहाँ की जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामों में रहता है। ग्रामों बिना इन ग्रामों के विकास के देश का विकास सम्भव नहीं है।

(२) यह आवश्यक है कि भारतीय ग्रामीण का जीवन-स्तर ऊँचा हो तथा उनकी दृष्टि विस्तृत हो। इसलिए यह आवश्यक है कि उच्च शिक्षा की सुविधा हो। यह स्वास्थ्यकर वातावरण में रहे तथा उनमें आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की भावना जागृत हो।

(३) ग्रामों के विकास का मुख्य लाभ यह होगा कि देश की खाद्य समस्या का हल हो जायगा। इस समय हम अन्न के लिए अनुनाधिक मात्रा में विदेशों के ऊपर निर्भर हैं। इसका फल यह होता है कि प्रत्येक वर्ष देश का करोड़ों रुपया जा देश के अन्दर कई उपयोगी कामों में लगता, विदेश भेजा जाता।

सामुदायिक विकास योजनाओं का महत्व उपर्युक्त कारणों से स्पष्ट है। इनके अन्तर्गत कृषि तथा अन्य सम्बन्धित विषय, जैसे सिंचाई का प्रबन्ध, अच्छे बीजारों का उपयोग, पशुपालन आदि, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रेनिंग, रोज-गार मकान तथा सामाजिक सेवाएँ आते हैं। इन ग्रामीण जीवन की विविध समस्याओं का हल होने में देश के गाँवों की अवस्था में महान् सुधार होगा।

सामुदायिक योजनाओं का आरम्भ देश में २ अक्टूबर १९५२ को हो गया। सबसे पहले डटावा जिले के अन्तर्गत कुछ गाँवों में यह काम शुरू किया गया। दस महीने में ५५ सामुदायिक विकास योजनाओं की स्थापना की गई। प्रत्येक सामुदायिक योजना के अन्तर्गत ३०० गाँव रहते थे। इस प्रकार लगभग १६,५०० गाँवों का इस कार्यक्रम में लाभ हुआ। इस कार्य का अच्छी मफरता मिली और अक्टूबर १९५३ में ५३ सामुदायिक विकास क्लबों की भी स्थापना की गई। जब अक्टूबर १९५६ में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्थापित इस योजना का काम पूरा हुआ, तब तक सारे देश में इस विकास योजना के १२०० केंद्र

1 "The central object of the community development programme is to mobilise local man-power for a concerted and co-ordinated effort at raising the whole level of rural life." Ibid, p. 42.

स्थापित कर दिए गए थे। इन योजनाओं की प्रगति का अनुमान निम्नोक्त आंकड़ों से ज्ञात होगा।

नये स्कूलों की संख्या	—	१४,०००
प्राथमरी स्कूल जो वैश्विक स्कूल बनाये गये	—	५,१५५
वयस्क शिक्षा केन्द्र	—	१५,०००
इन केन्द्रों द्वारा शिक्षित चयम्वा की संख्या	—	३७३,०००
पक्की सड़कें	—	८,०६९ मील
कच्ची सड़कें	—	२८,००० मील
झीवालधों की संख्या	—	८०,०००

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में इस कार्य को और अधिक प्रागे बढ़ाया जायगा। द्वितीय योजना का यह लक्ष्य है कि १९६०-६१ तक ३८०० राष्ट्रीय विस्तार मेवा क्षेत्र और ११२० सामुदायिक विकास क्षेत्रों की स्थापना की जाय। इनमें लगभग ३२.५ करोड़ जनसंख्या को लाभ होगा। इस कार्य के लिये योजना में २०० करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। सामान्यतः एक राष्ट्रीय मेवा क्षेत्र पर ४ लाख रुपये व्यय होंगे और एक सामुदायिक विकास क्षेत्र पर १२ लाख रुपये होंगे। द्वितीय योजना काल में इन सामुदायिक योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये २ लाख कर्मचारी होंगे। इन कर्मचारियों की शिक्षा के लिये प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये हैं। १९६०-६१ में इन प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या ७१ हो जायगी।

**सामुदायिक योजनाओं का संगठन.**—इन योजनाओं के निरीक्षण के लिये एक केन्द्रीय समिति की स्थापना की गई है तथा एक प्रशासनिक समस्त वेग की योजनाओं के संचालन तथा निर्देशन के लिये है। उसकी सहायता एक कार्य-समिति है। योजना-कमीशन ही केन्द्रीय समिति के रूप में काम करता है।

प्रत्येक राज्य में एक राज्य विकास समिति की स्थापना की गई है। उसके सदस्य प्रधान सचिव तथा उसके द्वारा मनोनीत अन्य सचिव होते हैं। इस समिति का मंत्री राज्य विकास कमिशनर कहलाता है। यह कमिशनर राज्य की समस्त योजनाओं का निर्देशन और सहयोग (Co-ordination) करता है।

प्रत्येक जिले में वहाँ का कलेक्टर या एक ऐडिशनल जिला मजिस्ट्रेट, राज्य विकास कमिशनर के आदेशानुसार इन योजनाओं का निर्देशन करेगा। उसकी सहायता के लिये एक जिला विकास समिति होती है।



प्रत्येक योजना का संचालन तथा निर्देशन एक योजना अधिकारी द्वारा होता है। उसके अधीन कुछ निरीक्षक तथा कार्यकर्ता होते हैं। इनकी संख्या लगभग १२५ होती है।

इन योजनाओं की सफलता जन सहयोग के बिना असंभव है। वास्तव में उनकी सफलता इसी बात से जाँचनी चाहिये उन्होंने कहाँ तक ग्रामवासियों को सक्रिय कर दिया है। योजना के कार्यकर्ताओं का काम तो योजनाओं को चालू करना मात्र है तथा समय-समय पर गाँव वालों का निर्देशन करना है। योजना की आगे बढ़ाना तो गाँव वालों का काम है। अभी तक योजनाओं की प्रगति को देखने से यही निष्कर्ष निकलता है कि इस योजनाओं का उस मात्रा तक जन सहयोग नहीं प्राप्त हो सका जैसा कि होना चाहिये था। परन्तु यह निम्नकोष्ठ कहा जा सकता है जैसा कि योजना आयोग की योजना अनुमान समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि "योजनाओं के फलस्वरूप जनसाधारण का सामूहिक व्यक्तिगत विकास निर्माण की ओर लग गया है।"

### प्रश्न

(१) भारत में खेती की उन्नति के लिये आप किन-किन उपायों का सुझाव देंगे ? (यू० पी० १९५५)

(२) हमारे देश में गाँवों के जीवन को अधिक सुखी तथा समृद्ध बनाने लिये आप क्या करेंगे ? (यू० पी० १९५१)

(३) भारत के आर्थिक जीवन में कृषि का क्या महत्व है ? (यू० पी० १९५६)

(४) पञ्चवर्षीय योजनाओं का क्या महत्व है ? इस सम्बन्ध में बताइये कि इन योजनाओं द्वारा बेकारी किस प्रकार दूर हो सकेगी ? (यू० पी० १०१६)

(५) देश में बेरोजगारी के क्या कारण हैं ? इनको दूर करने के लिये क्या उपचार किये जा रहे हैं। इस दिशा में धरने भी सुझाव दीजिये। (यू० पी० १०५७)

(६) यद्यपि हमारा देश कृषि प्रधान है फिर भी हमारा यहाँ कृषि की कमी क्यों है ? देश को इस दिशा में आत्म निर्भर बनाने के लिए अपने सुझाव दीजिये। (यू० पी० १९५९)

(७) भारत में बेकारी दूर करने के लिये अपने सुझाव दीजिये। सरकार उस दिपय में क्या प्रयास कर रही है। (यू० पी० १९५९)

## शिक्षा : समस्याएँ तथा सुधार

**शिक्षा का जीवन में स्थान**—जीवन में शिक्षा का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। मनुष्य के गुणों का विकास शिक्षा के बिना असम्भव है। इसलिये शिक्षा की आवश्यकता व्यक्ति के विकास के लिये आवश्यक है। अत्यन्त प्राचीन काल में ही दार्शनिकों तथा विचारकों ने शिक्षा को अत्यन्त महत्वपूर्ण बताया है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो के अनुसार शिक्षा द्वारा आत्मा सत्य के दर्शन करती है। शिक्षा के बिना मनुष्य तथा पशु में केवल शारीरिक वनावट की ही भिन्नता रह जाती है। मनुष्य का अस्तिष्क एक पट्टे की भाँति नहीं है जिसमें शिक्षक कुछ वस्तु उड़ेल देता है। परन्तु मनुष्य के अन्दर कुछ बीज गुण रूप में वर्तमान रहते हैं। उन्हें ही शिक्षा द्वारा विकसित किया जाता है।<sup>1</sup>

**भारत में शिक्षा का इतिहास**—भारतीय शिक्षा के इतिहास को तीन कालों में बाँटा जाता है—हिन्दू काल, मुस्लिम काल तथा अंग्रेजी काल। प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन किया जायगा।

(१) **हिन्दू काल**—इस काल में शिक्षा प्रधानतः धार्मिक तथा वैयक्तिक थी। तब शिक्षा राज्य के कर्त्तव्यों में सम्मिलित न थी। यह सत्य है कि राजा कभी-कभी धन तथा भूमि का शिक्षण संस्थाओं की सहायता से दान कर देते थे। शिक्षा समस्याएँ धर्मिकों की दायीरगता पर निर्भर थी। प्रत्येक गुरु अपने ही आश्रम में कुछ विद्यार्थियों को शिक्षा देता था। शिक्षा समाप्त होने पर शिष्य अपने गुरु को दक्षिणा देकर विदा होता था। शिक्षा ऐसी थी जिसने की जीवन में लाभ हो। इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों को अलग अलग

---

1. "Education is the drawing out of a child's latent potentialities by providing them with suitable opportunities for their exercise and thorough exercise, their development and perfection." Squeers The Education of India, p. 10 (जि० २४)

प्रवार की शिक्षा दी जाती थी क्याकि जीवन में उनके क्षेत्र अलग-अलग थे। ब्राह्मण की शिक्षा का आरम्भ ८ वर्ष की आयु में, क्षत्रिय का ११ वर्ष की आयु में, तथा वैश्या का १० वर्ष की आयु में होता था। बुढ़े काल के पश्चात् देश में बड़े-बड़े विद्यालयों की स्थापना हुई। इनमें नालन्दा सबसे प्रमुख था। इस विद्यालय में चीनी यात्री हुएन चुयांग के अनुसार ४००० विद्यार्थी शिक्षा पाते थे। इसके अनतिरिक्त विजयनगिरा, तक्षशिला, उदयान्तपुरी, श्रीनगर, नव-द्वीप आदि स्थानों में भी बड़े-बड़े विद्यालय थे। हिन्दू शिक्षा में नैतिकता को विशेष महत्व दिया जाता था। यह केवल मन के ही विकास पर ध्यान नहीं देती थी परन्तु चरित्र के विकास पर भी उतना ही ध्यान दिया जाता है।

(२) मुस्लिम काल — इस काल के आरम्भिक वर्षों में शिक्षा की ओर मुस्लिम शासकों ने ध्यान नहीं दिया। जब मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण तथा इस देश की विजय आरम्भ की उस समय यहाँ पर शिक्षा काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। मुसलमान आक्रमणकारियों ने कुछ स्थानों में हिन्दुओं के पुस्तकालयों को नष्ट कर डाला। दिल्ली-सल्तनत के काल में शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला। गाँवों में मस्जिदों के साथ ही छोटा स्कूल (मक़तब) जुड़ा होता था। इसमें विशेष कर क़ुरान की शिक्षा दी जाती थी। परन्तु कुछ बादशाहों ने ऊँचे स्कूलों (मदरसों) की भी स्थापना की। फ़ीरोज़ तुग़लक़ ने कई मदरसों की स्थापना की। मदरसों में ऊँची शिक्षा दी जाती थी, जैसे इतिहास, राजनीति, कानून धर्म आदि। इसमें कोई शक़ नहीं कि इस शिक्षा का आधार धार्मिक था। मुग़ल बादशाहों ने शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। प्रक़र न इस दिशा में महान्नीय काम किया। उसने कई मसूदों की पुस्तकों का फ़ारसी अनुवाद करवाया। उसने साहित्य तथा कला को उत्साहित किया। मदरसों की स्थापना की। हिन्दू तथा मुसलमान दोनों की ही शिक्षा का बड़ा समान आदर करता था। उसने उत्तराधिकारियों ने भी कुछ सीमा तक उसकी नीति का अनुसरण किया पर औरंगज़ेब ने मुसलमानों की शिक्षा की ओर तो ध्यान दिया पर हिन्दुओं की पाठशालाओं को उसने नष्ट किया। औरंगज़ेब के पश्चात् भारत के दुश्मि आरम्भ हुए और इस काल में शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया।

(३) अंग्रेज़ी का व — भारत में पश्चिमी व्यापारियों ने आरम्भ में ही अपनी शिक्षा नीति में इस बात का ध्यान रखा कि शिक्षा के द्वारा वे अपने धर्म का प्रचार कर भारतीयों को ईसाई बना सकें। पुर्तगीज़ व्यापारियों तथा फ्रेंच व्यापारियों ने जो यहाँ स्कूल खोले उनमें धार्मिक शिक्षा पर विशेष

महत्व दिया गया। जब अंग्रेजी कम्पनी ने स्कूल खोले उनमें भी यही उद्देश्य शामिल रखा गया। यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि पाश्चात्य शिक्षालयों के पीछे धार्मिक उद्देश्य था। सन् १८३३ तक अंग्रेजी ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने अंग्रेजी शिक्षा को कोई महत्त्वता नहीं दी थी। सन् १८१३ के चार्टर ने यह निर्दिष्ट हो गया था कि कम्पनी प्रति वर्ष एक लाख रुपये अपने धर्मों में शिक्षा के लिये व्यय करेगी। सन् १८३३ तक कम्पनी ने चार विद्यालय खोले थे—कलकत्ता मदरसा (१७८१) कलकत्ता मस्जिद कनिष्ठ (१८२५) तथा दिल्ली में मस्जिद कनिष्ठ (१८२५)। कम्पनी के शिक्षालयों के प्रतिरिक्त कुछ स्कूल देश में ईसाई धर्मप्रचारकों (missionaries) द्वारा खोले गये थे। इनका उद्देश्य भी मुख्यतः ईसाई-धर्म प्रचार था।<sup>1</sup>

सन् १८१३ ने शिक्षा के इतिहास में एक नये युग का प्रारम्भ होता है। प्रथम बार कम्पनी भारतीयों के शिक्षा के लिए उत्तरदायी बना दी गई। मन्त्रों महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि शिक्षा किस भाषा द्वारा दी जावे? इस विषय में तीन मत थे—एक मत तो यह था कि शिक्षा का माध्यम संस्कृत तथा अरबी हो। दूसरा मत था कि शिक्षा का माध्यम साधुनिक भारतीय भाषाएँ हों। तीसरा मत यह था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। मन्त्रों ने तीसरे मतवालों की विजय हुई। सन् १८३५ में मेमोरेन्स में, जो कि उन समय गवर्नर जनरल की काॅमिल का कानूनी सदस्य था, अपने प्रसिद्ध लेख (minute) में यह निष्कर्ष की कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम द्वारा भारतीयों को पश्चिमी विज्ञान तथा साहित्य की शिक्षा दी जावे। उनका कहना था कि पूर्वीय विद्यालयों के शिक्षालयों को बन्द कर देना चाहिये। भारतीय अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे। अंग्रेजी भाषा मस्जिद तथा अरबी की प्रेरणा प्राप्त कर ले रहे हैं। उनका कहना था कि "a single shelf of a good European library was worth the whole native literature

---

1. The "missionaries soon realised that schools were both the cause and the effect of proselytisation and educational and missionary work had to be undertaken side by side; and it is out of this realisation that the mission schools of modern India were born." Nurullah and Naik, *A Student's History of Education in India*, p. 33.

of India and Arabia" उसका विश्वास था कि अंग्रेजी मसालों की भाँसाजी में मक्खेष्ट है। मैकाण का वास्तविक उद्देश्य यह था कि अंग्रेजी शिक्षा का फल-स्वरूप अंग्रेजी मन्त्रालय का भारत में क्या प्राप्त हो जायेगा तथा भारतीय ईस्ट-इंडिया की स्वीकार करेगा।

सन् १८३१ के पञ्चान भारत में अंग्रेजी शिक्षा फैलने लगी। इसका कारण यह था कि भारत-शिक्षा-संस्था का सरकार की महामता बन्द कर दी गई। इस काल में मिशनरियाँ न भी शिक्षा के प्रचार में भाग लीं। सन् १८३५ में जब कम्पनी के प्रान्ताध्यक्ष का नवीनकरण हुआ हाउस ऑफ कॉमन्स की एक कमेटी ने भारत में शिक्षा के विस्तार की आज्ञा की। इस आज्ञा पर आधारित कर कम्पनी के डाइरेक्टरों ने भारत में सरकार के पास एक शिक्षा-सम्बन्धी पत्र (despatch) भेजा जो कि यह था शिक्षा सम्बन्धी पत्र कहलाता है। Sir Charles Wood कम्पनी के वाइस-रॉय का सम्भाषित था। उसमें कई सुझाव रखे गए थे जैसे कि देश में विश्वविद्यालय स्थापित किये जाय, प्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा को बढ़ाया जाय, माध्यमिक शिक्षालयों को कुछ धार्मिक महामता दी जाये, टेक्निकल शिक्षा तथा स्त्री शिक्षा का प्रचार हो। शिक्षकों के लिये स्कूल खोले जाय और प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा विभाग का एक डाइरेक्टर नियुक्त हो।

इन सुझावों को भारत सरकार ने मान लिया। सन् १८५७ में भारत में तीन विश्वविद्यालय स्थापित हुए—कलकत्ता बम्बई व मद्रास। प्रान्त में एक शिक्षा विभाग स्थापित किया गया था। शिक्षा के सम्बन्धित प्रकल्पों को भी नियमित की गई। सन् १८५४ के बाद सरकार ने शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। सन् १८८२ में हर्टर कमीशन की नियुक्ति हुई। इसने यह राय दी कि प्रारम्भिक शिक्षा का विशेष रूप में उत्साहित किया जाय और धार्मिक महामता बढ़ा दी जाये। इसी वर्ष पंजाब में विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। सन् १८८७ में प्रयाग में एक विश्वविद्यालय खुला। ये सब विश्वविद्यालय सम्मिलित (affiliating) थे। इस काल में कालिजा की समस्या भी बढ़ी।

लाइवर्जन् ने सन् १९०४ में एक कमीशनरी ऐक्ट पास किया। उसमें विश्वविद्यालयों को कुछ अधिक सरकारी नियन्त्रण में लाया गया। इसका मुख्य कारण यह था कि देश में राजनैतिक चेतना बढ़ रही थी। इसलिये सरकार हमारी शिक्षा को अधिकधिक अपने नियन्त्रण में रखना चाहती थी।

सन् १९१० में केन्द्रीय सरकार के अधीन एक अलग शिक्षा विभाग खोला गया। सन् १९१९ के ऐक्ट में प्रान्तों में शिक्षा विभाग मन्त्रिमण्डल के हाथ में आ गया। इस काल के बाद देश में शिक्षा का तेजी से प्रसार हुआ। नये-नये स्कूल तथा कॉलिज खोले। लड़कियों में भी शिक्षा बढ़ी। टेक्निकल स्कूल भी खोले गये। कई नये विश्व विद्यालय खुले। सन् १९२७ के पश्चात् शिक्षा का और भी विकास हुआ। हर वर्ष विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है तथा नये-नये स्कूल, कॉलिज खुल रहे हैं। परन्तु दटना होने पर भी अभी हमारी जन-संख्या का एक-तिहाई भाग में भी कम शिक्षित है। हमारी सरकार के सम्मुख इस समय शिक्षा को दूर करने की बिकट समस्या है।

**शिक्षा विभाग का संगठन**—सविधान द्वारा शिक्षा राज्यों का विषय है। परन्तु सभ्य सरकार में भी एक शिक्षा विभाग है। इसके अधीन कुछ विश्वविद्यालय हैं—अलीगढ़, बनारस, दिल्ली तथा विश्वभारती और वे सब टेक्निकल स्कूल हैं जिनको संघ सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। यह विभाग एक मन्त्री के अधीन है। मन्त्री की सहायता के लिये एक मन्त्रि-वालय है। इस समय के० एल० श्रीवास्ती शिक्षा मंत्री हैं। प्रत्येक मध्यम राज्य (प्रवेश) में भी एक शिक्षा विभाग होता है जो कि एक मन्त्री के अधीन होता है। मन्त्री की सहायता के लिये एक सचिवालय होता है शिक्षा सचिव के अतिरिक्त एक शिक्षा विभाग का डायरेक्टर होता है। यह शिक्षा का मुख्य अधिकारी है। उसके नीचे अन्य अफसर होते हैं। कई शिक्षालय पूर्णतः सरकार द्वारा चलाये जाते हैं। कई प्राइवेट स्कूल तथा कॉलिज भी हैं। इनको सरकार आर्थिक सहायता देती है। इन पर भी सरकारी नियन्त्रण होता है। प्रारम्भिक शिक्षा संस्थाओं, नगरपालिकाओं तथा जिला बोर्डों द्वारा चलाई जाती है। ये भी सरकारी नियन्त्रण से परे नहीं हैं।

**वर्तमान शिक्षा व्यवस्था**—इन व्यवस्था के अन्तर्गत (टेक्निकल शिक्षा के अतिरिक्त) शिक्षा को तीन खेपियों में बांटा गया है। प्रत्येक का अमरा-मशिप्त वर्णन दिया जावेगा—

(१) **प्रारम्भिक शिक्षा**—प्राथमिक काल में प्रारम्भिक शिक्षालयों की स्थापना सबसे पहले बंगाल में १८८५ में की गई। इसके बाद अमरा-अन्य प्रान्तों में भी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। सन् १८८२ में एक्टर कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि प्रारम्भिक शिक्षा स्थानीय सरदारों के क्षेत्र

में कर दी जावे। नगर में नगरपालिकाएँ तथा गाँवा में जिला बोर्डें इसका प्रयत्न करते हैं। इन पर नियन्त्रण होता है। पहिले प्रारम्भिक स्कूल दो प्रकार के होते थे—लोअर प्राइमरी तथा अपर प्राइमरी। लोअर प्राइमरी केवल दूसरी कक्षा तक होत थे। अपर प्राइमरी चौथी कक्षा तक होती थी। परन्तु अब यह भेद हटा दिया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा लोकप्रिय न हो सकी। गाँवों में बहुत कम लोग अपने बच्चा को इन स्कूलों में भेजते थे। हमारे विदेशी शासकों ने प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार पर कम ध्यान दिया। परन्तु अब हमारी सरकार कम और अधिक ध्यान दे रही है। समाचार के कारण इस विद्या में सफलता सीमित हो गई।

प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था अत्यन्त दोषपूर्ण है। अब इन दोषों को हटाने की चेष्टा की जा रही है, परन्तु अभी केवल इन विद्या में पहला पग ही उठाया गया है।

इसके साथ में सबसे बड़ा दोष यह है कि यह अनिवार्य नहीं है। इसके कारण मध्य वर्ग इस का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अब सरकार ने नगरपालिकाओं के क्षेत्र में इसको अनिवार्य कर दिया है, परन्तु जिला बोर्डों के क्षेत्र में अभी तक अनिवार्य व्यवस्था नहीं हुई है। इन स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है। वह जीवन से सम्बन्धित नहीं है। इसलिये व्यावहारिक जगत में वह व्यर्थ है। गाँव के बालकों को कृषि या अन्य गृह-उद्योगों की शिक्षा नहीं दी जाती है। इसलिये ऐसी शिक्षा प्राप्त कर बालकों में वह स्वाभाविक है कि धार्मिक धर्म के प्रति घृणा हो जाये। अधिकतर बालक अपनी शिक्षा को बिना पूरा किये ही बीच में ने ही छोड़ देते हैं। इसका फल यह होता है कि उनके ऊपर व्यय किया हुआ पण बेकार बला जाता है। इस दृष्टि में प्रारम्भिक शिक्षा अत्यन्त खर्चीली है। सन् १९२९ में हारटोर्ग समिती ने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात की ओर ध्यान आर्पित किया था। जो बालक गाँवों में प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर लेते हैं उनमें से अधिकांश भागिक बट्टादगों के कारण धर्म नहीं पढ़ सकते हैं। इस दृष्टि से भी उनकी शिक्षा खूबसी ही रह जाती है।<sup>१</sup> प्रारम्भिक शिक्षा में कई दोष इस कारण भी हैं क्योंकि इस पर आवश्यकता से कम व्यय किया जाता है।

\* 1 In the primary system the waste is appalling so far as we can judge, the vast increase in numbers in primary schools produces no commensurate increase in literacy, for only a small proportion of those who are at the primary

इसका परिणाम यह है कि प्रारम्भिक स्कूल के शिक्षकों को वेतन बहुत कम मिलता है। इसने इसमें योग्य शिक्षकों का अभाव है। ये अध्यापक ठीक प्रकार से नहीं पढ़ाते हैं और न अपने काम में उन्हें रूचि हो रहती है। ये अध्यापक स्वयं ही पूरे शिक्षित नहीं हैं, इसलिए उनकी अध्यापन प्रणाली दोगुनी है। आधुनिक वैज्ञानिक-प्रथा में पढ़ाई अभी प्रारम्भ नहीं हुई है। शिक्षक स्वयं ही इस आधुनिक विद्य में अपरिचित होता है। बालकों को ठीक प्रकार से शिक्षा न देने से उनका मानसिक विकास नहीं होता। उन्हें पढ़ाई में कोई आनन्द नहीं आता। पढ़ना भी एक प्रकार का शारीरिक श्रम हो जाता है। इन स्कूलों में बच्चों के मनोविनोद की ओर भी ठीक ध्यान नहीं दिया जाता है। उनके खेल-कूद की सुविधाएँ सम्पूर्ण-जनक है।

परन्तु अब सरकार इन दोनों का दूर करने के लिए अभिनव हुई है। हमारे मविधान में कहा गया है कि सरकार १४ वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा का प्रयास करेगी। इस दिशा में कुछ काम किया गया है। परन्तु अभी पूर्ण रूप से इस उद्देश्य की प्राप्ति बहुत दूर है। प्रारम्भिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई है। सन् १९५३ के अन्त तक देश में इनकी संख्या २,३१,०८२ तथा इनमें विद्यार्थियों की संख्या १,९२,९६,८४० थी। सम्पूर्ण भारत में प्रारम्भिक शिक्षा पर वार्षिक कुल खर्च ३१ मार्च, १९५३ को ४३ ७ करोड़ रुपया था। विविध प्रदेशों में वहाँ की सरकारें प्रारम्भिक शिक्षा को फैलाने के लिये प्रयत्नशील हैं तथा उपर्युक्त दोषों को भी दूर करने का भी प्रयास कर रही हैं। प्रारम्भिक शिक्षा को वैदिक शिक्षा के सिद्धान्तों पर चलाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसीलिये श्रृंग, कनार-बुनाई, बड़ौलीरी चमड़े का काम, आदि की भी शिक्षा दी जा रही है। इन वैदिक स्कूलों के पास दो एकड़ भूमि प्रति स्कूल होगी। माना है कि कुछ वर्षों में प्रारम्भिक स्कूलों का स्थान वैदिक स्कूल ले लेंगे। केन्द्र के द्वारा प्रदेशों को इस प्रकार के लिये आर्थिक सहायता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में १९५० में प्रतिवर्ष वैदिक स्कूलों की संख्या ३१,७११ थी। सन् १९५३ में यह संख्या ३३,७३७ हो गई थी। इन शिक्षा में सबसे प्रथम तथा मुख्य आवश्यकता यह है कि अधिक व्यय किया जावे। शिक्षकों को अच्छा वेतन दिया जावे तथा इन्हें शिक्षक नियुक्त होने के पूर्व नली प्रकार से बालकों को किस प्रकार आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा देनी चाहिये, इसका ज्ञान होना चाहिये। इसलिये शिक्षकों

stage reach Class IV, in which the attainment of literacy may be expected. The wastage in the case of girls is even more serious than in the case of boys." (Hartog Committee Report).



र लिय शिक्षण समस्यां सुलनी चाहिये। देश में नि शुल्क अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा के लिये २८ लाख अध्यापकों की आवश्यकता है। इस समय देश में इनकी गख्या केवल ५ ६१ ००० ही है। परन्तु इस दिशा में उन्नति हो रही है। शिक्षकों की नियुक्ति करने समय इस बात का मववा ध्यान में रखना चाहिये कि वे योग्य तथा मन्वर्त्ति हों। क्योंकि वाठरा के उपर जिस प्रकार का प्रभाव इस समय पड़ेगा वह जन्म भर बना रहेगा। यह नहीं सोचना चाहिये कि प्रारम्भिक शिक्षा के लिये योग्य व्यक्ति नहीं चाहिये। इन स्कूला में वाठरा के गैल-बुद्ध तथा मनारिनाद का भी पूरा ध्यान रखना चाहिये। वाठरा का यह नहीं प्रतीत होना चाहिये कि पढ़ना वाई भार है। उन्हें पढ़ने के लिये म्यय द्न्दुत बनाना चाहिये। यह सभी सम्भव है जब कि स्कूला में सामूल मुद्रा बिसे जावे। स्कूला में मुद्रा का फल यह होगा कि अधिकाधिका बालक इनकी भार भावपित हाने। प्रारम्भिक शिक्षा बढ़ेगी। हमारा पूरी तरह फेगने के लिये तथा निरक्षरता का दूर करने के लिये उम शिक्षा का अनिवार्य तथा नि शुल्क कर देना चाहिये।

माध्यमिक शिक्षा—मन् १०२१ के पञ्चाव भाग में माध्यमिक शिक्षा का प्रकार काफी मजो हो हुआ। नये-नये स्कूला तथा कॉलेज खुल। ग्रामीण क्षेत्रों में तथा कला में भी माध्यमिक स्कूला खड़े। कुछ तो मरवांगी के तथा कुछ मुर मरवांगी। म्त्रिया तथा पिछड़े कर्गों की शिक्षा की भार भी ध्यान दिया गया। इस प्रगति का कारण यह था कि देश में गजर्तित जागृति के कारण ज्ञान प्राप्ति करने की दृष्टा बढ़ रही थी। देश में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति दिन पर दिन होती ग हो रही है। माध्यमिक शिक्षा मिटि स्कूला में, हाई स्कूला में तथा इंटरमीडिएट कॉलेजों में दी जाती है। ये शिक्षा समस्याएं दो प्रकार की हैं—मरवांगी तथा गैर मरवांगी। मरवांगी समस्या में मरवांगी ही शिक्षक नियुक्त करती हैं तथा उनका पूरा ध्यय बहन करती है। गैर मरवांगी मरवांगी भी मरवांगी नियन्त्रण में है। मरवांगी उन्हें जागिर आविब महायता देती है। मरवांगी इन शिक्षाओं का वाधा का निरीक्षण करने हेतु दन्त्येनर्ग नियुक्त करती है। ये कप में एक बार इन शिक्षाओं का निरीक्षण करने है।

माध्यमिक शिक्षाओं के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी, हिन्दी या अन्य प्रादेशिक भाषा इतिहास भूगोल, नागरिकशास्त्र, गणित, विज्ञान इत्यादि वस्मों तथा कई अन्य मय है। इनमें से कुछ अनिवार्य हैं तथा कुछ वैकल्पिक, जिनका विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार छान लेते हैं।

विभिन्न प्रदेशों (States) में इनका संगठन अलग-अलग प्रकार से किया गया है। कुछ प्रदेशों में ९वीं, १०वीं तथा इतर कक्षाओं के लिये एक बॉर्ड स्थापित किया गया है। छठी, सातवीं तथा आठवीं कक्षाओं का प्रबन्ध अलग संगठन द्वारा किया जाता है। कुछ प्रदेशों में माध्यमिक शिक्षा विश्व-विद्यालयों के अधीन है। इन प्रदेशों में इतर की शिक्षा विश्वविद्यालयों के द्वारा दी जाती है तथा मिटिल स्कूल तथा हाई स्कूल के लिये अलग व्यवस्था होती है।

माध्यमिक शिक्षा की श्रेणियों का वर्गीकरण भी निम्न-निम्न प्रदेशों में अलग-अलग है। कुछ प्रदेशों में पाँचवीं से सातवीं कक्षा तक की शिक्षा माध्यमिक शिक्षा कहलाती है। इन प्रदेशों में इतर शिक्षा का विश्वविद्यालयों द्वारा प्रबन्ध किया जाता है। कुछ अन्य प्रदेशों में पाँचवीं से सारहवीं तक की शिक्षा माध्यमिक शिक्षा कहलाती है। दिल्ली प्रान्त में ऐसा ही किया गया है। वहाँ इतर की कक्षा दो भागों में बाँट दी गई है। एक वर्ष हाई स्कूल में जोड़ दिया गया है। तथा एक वर्ष सी० ए० में। इन प्रकार हाई स्कूल, तथा सी० ए० में तीन-तीन वर्ष लगेंगे। कुछ अन्य प्रदेशों में माध्यमिक शिक्षा से पूर्व सातवीं से बारहवीं कक्षाओं तक की शिक्षा से है।

माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में भी कई बाँध हैं। इसका सबसे बड़ा बाँध यह है कि सब विद्यार्थियों को एक सी ही शिक्षा दी जाती है। उनकी प्रवृत्तियों तथा रुचि का ध्यान नहीं रखा जाता है। इनका फल यह होता है कि माध्यमिक शिक्षा-शक्ति के पश्चात् भी विद्यार्थी का उचित विकास नहीं हो पाता। माध्यमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें भी कई दोष हैं। वह व्यावहारिक ज्ञान नहीं प्रदान करता है। उनका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिये तैयार करना है। इसलिये माध्यमिक शिक्षा भी जीवन में अधिकारा व्यक्तिता के लिये लानप्रद मिष्ट नहीं होती है। माध्यमिक शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के लिये अभी तक कोई स्थान नहीं है। विद्यार्थियों को किसी प्रकार के कला-क्रीडा या उद्योग की शिक्षा नहीं दी जाती है। इन शिक्षा में शारीरिक परीक्षण की ओर ध्यान ही जाता है और बाकूरी करना ही जीवन का लक्ष्य हो जाता है। इनके नैतिक गुणों का भी विकास नहीं होता है। शिक्षकों को बहुत कम वेतन दिया जाता है, इसलिये उनका अपने काम में पूरी तरह रुचि न लेना स्वाभाविक है।

माध्यमिक शिक्षा में कई सुधारों की आवश्यकता है। उपरोक्त दोषों को दूर करना चाहिये। इन बातों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये कि इन शिक्षा

ए पञ्चानि तद्वत्तया भोवनं मेधां तां च अतिरिक्तं बृहत्तमं कामं भा द्वा  
यव । अस्मिन् वाच्येन सप्त मासिन्वितं न नष्टं भवति चाष्टिम् । परन्तु व्याव  
हारिक भावना चाष्टिम् । औद्योगिक तथा कृषिक गिष्ठा वा भावाच्येन  
य स्थानेन तां शक्तिं प्राप्तं प्राप्तं विद्याविद्या का अपन जातन री। माग  
मिन्वितं वस्तु म मयिन्वितं गिष्ठा वा यद्यपि एतत् मिन्वितं चाष्टिम् आ  
रम्भेन का प्रत्यक्षं नष्टं चाष्टिम् विद्या समय समय पर अपन विपक्ष व मन्त्र  
म अपनता जात उता मर ।

अत्र माध्यमिक गिष्ठा म सुधार का आरम्भेन स्थान म गता ह । गिष्ठा  
म आरम्भेन वस्तु व तां विद्यावी व अभिमान्वा का पन् निषेध करता पन्ता ह  
विद्या विद्यावी का अग्नं विद्या प्रसार का गिष्ठा गिष्ठा वा चाष्टिम् । उता  
प्रत्यक्ष यत् उता विद्या विद्या पन् म भवता चाष्टिम् ह या कदा मासिन्वित  
गिष्ठा गिष्ठा वा चाष्टिम् । अत्र वा विद्यावी का जात वत्तर एत विद्या वी  
विद्या गिष्ठा वी अत्रता ता वि भविष्य म एत काम क विद्या अपनता री।

उत्तर प्रत्यक्ष म भा मन्त्रात् न माध्यमिक गिष्ठा म वत् मन्त्रात् सुधार  
विद्या ह माध्यमिक गिष्ठा वा ता भागा ३ वाता विद्या जायता-अतिपर ह  
एतत् एतत् मन्त्रात् तथा आरम्भे व तां हाता तथा हाता मन्त्रात् स्थान  
मन्त्रात् वत्ता १ एतत् १ वी व तां हाता । इत वत् म उत्तर प्रत्यक्ष गिष्ठा  
विभाग द्वारा उता मन्त्रात् एत स्थान म ता विद्यामण अत्र म स्थानित है  
एत नदी प्रयाग धारम्भ विद्या गता ह । एत अत्रा व विद्याविद्या का हृदि वा  
धारम्भिक गिष्ठा गिष्ठा जात ता प्रत्यक्ष विद्या जायता । प्रत्यक्ष एत व  
१० एतत् मन्त्रात् ता जायता गिष्ठा विद्यावी विद्या वा व्यावहारिक गान प्राप्त कर  
मन्त्रात् एत वत् वत्ता ६ म वत् नदी वाच्येन गता गता । तीत वत् म वत्ता ८  
नदी व विद्यावा एत ता वाच्येन व अत्रमात्र गिष्ठा प्राप्त करता । उत्तर प्रत्यक्ष  
गिष्ठा गता व एत प्रयाग व मन्त्रात् मन्त्रात् एत एत गिष्ठा ह विद्या प्रत्यक्ष  
मन्त्रात् वत्ता १० प्रत्यक्ष म अत्रिन्वितं जात म वत्ता १० एतत् मन्त्रात् मन्त्रात्  
एत ह । अत प्रयाग वी वाच्येन तथा विद्याविद्या म हृदि वी गिष्ठा  
एत तथा मन्त्रात् मन्त्रात् एत प्रयाग म मन्त्रात् व परिचित करान का  
प्रत्यक्ष विद्या जायता । उता प्रत्यक्ष मन्त्रात् तथा मन्त्रात् अत्र स्थाना म स्थान  
वाच्येन तथा मन्त्रात् व अत्रमात्र अत्र उता व वत्तात् तथा  
उता मन्त्रात् एत प्रत्यक्ष विद्या जात का प्रत्यक्ष विद्या जायता । मन्त्रात् ह विद्या  
ता वाता मन्त्रात् मन्त्रात् व अत्रिन्वितं मन्त्रात् मन्त्रात् । एत उता व वाच्येन  
एत गिष्ठा तथा मन्त्रात् मन्त्रात् वी मन्त्रात् व अत्रात् मिन्वित । एत

प्रतिरिक्त सामुदायिक बायों के फलस्वरूप उनमें धर्म, प्रतिष्ठा, महकारिता तथा नमाज-सेवा के प्रति आदर उत्पन्न होगा।" हायर स्कूल में चार प्रकार के पाठ्यक्रम होंगे और विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार इनमें से एक को चुन लेंगे—साहित्यिक, कलात्मक, रचनात्मक तथा वैज्ञानिक। इन सुधारों का फल यह होगा कि प्रत्येक विद्यार्थी उसी बात की शिक्षा पावेगा जिसमें उसकी रुचि है। अन्य प्रदेशों में भी माध्यमिक शिक्षा को अधिक व्यावहारिक तथा लाभदायक बनाने के उद्देश्य में सुधार किए जा रहे हैं।

सितम्बर सन १९५२ में डा० ए० एन० मुदालियर को अध्यक्षता में एक माध्यमिक शिक्षा कमिशन की नियुक्ति गई। इन कमिशन का उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्धित प्रश्नों की जाँच करना था। उदाहरणार्थ (१) माध्यमिक शिक्षा की भारत में वर्तमान स्थिति (२) इसके पुनर्संगठन तथा सुधार के लिये विनियम: इनके उद्देश्य, संगठन आदि के विषय में, इसका प्रारम्भिक, बेसिक तथा उच्च शिक्षा में सम्बन्ध के विषय में तथा अन्य सम्बन्धित प्रश्नों के विषय में, सुझाव रखना। अगस्त १९५२ को इस कमिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसकी मुख्य निष्कर्षों निम्नोक्त हैं।

(अ) हाई स्कूल शिक्षा के प्रारम्भ के पूर्व ४ या ५ वर्ष प्रारम्भिक या बेसिक शिक्षा हो चुकी है। इसमें भाषा, सामाजिक अध्ययन, साधारण विज्ञान, हस्तकला आदि की शिक्षा हो। पाठ्यपुस्तकों के चुनाव के लिये एक उच्चप्रविकारी समिति हो।

(ब) शिक्षा माध्यम क्षेत्रीय भाषा हो। इसके प्रतिरिक्त मिडिल स्कूल में राष्ट्रभाषा तथा एक विदेशी भाषा की शिक्षा हो जानी चाहिये।

(ग) प्रारम्भिक अवस्था से ही औद्योगिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये बहुषण्ठी विद्यालय खोले जाने चाहिये।

(ङ) मैकेन्डी स्कूल के शिक्षकों तथा स्नातक (Graduate) शिक्षकों के प्रशिक्षण के अलग-अलग प्रेड होने चाहिये।

(च) कृषि, उद्योग-धन्दा, व्यापार, व्यवसाय, नागरिकता में प्रशिक्षण की प्रगति के लिये केन्द्र (centre) को चाहिये कि माध्यमिक शिक्षा के लिये वित्त का प्रवन्ध करे।

उन गिफारिदा को कार्यान्विन करने के लिये भारत सरकार ने एक योजना नंगार कर ली है। माध्यमिक शिक्षा की मुख्य समस्याओं को हल करने के लिये एन अधिनियम भारतीय ममिमि की स्थापना का प्रस्ताव है।

**विश्वविद्यालय (उच्च शिक्षा) —**भारत में वड के शिक्षा मवधी पत्र (१९१४ गन्) के पदचान् सरकारने विश्वविद्यालयों की स्थापना की ओर ध्यान दिया। मवमें पहल सन् १८५७ में तीन विश्वविद्यालय कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में स्थापित किये गए। इसके बाद सन १८८२ में पंजाब तथा सन् १८८७ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। अन्य विश्वविद्यालयों की स्थापना २०वीं शताब्दी में हुई।

इस समय देश में कुल ३७ विश्वविद्यालय हैं। उनके नाम नीचे दिए गए हैं।

आगरा (१९२७), अलीगढ़ (१९२१), इलाहाबाद (१८८७), आंध्र (१९०६), अनामलाई (१९२९), बनारस (१९१६), बडौदा (१९४९), बिहार (१९५०) बम्बई (१८५७), कलकत्ता (१८५७), दिल्ली (१९२२), दिल्हाटी (१९४८), मोरलपुर (१९५७) गुजरात (१९५०), जम्मू तथा काश्मीर (१९४९), जलपुर (१९५७) जायपुर (१९५५), कर्नाटक (१९५०), कोल (१९१७), कुरुक्षेत्र (१९५६), लखनऊ (१९२१), मद्रास (१८५७), मजरा (१९५८), मैसूर (१९१६), नागपुर (१९२५) उममानिया (१९१८) पंजाब (१९४७) पटना (१९१७), पूना (१९४८), राजम्यान (१९४७), रडकी (१९४९) सरदार वल्लभ भाई विद्यापीठ (१९५५), सागर (१९६६) एम० एन० डी० टी० स्त्री विश्वविद्यालय (१९५१) श्री बेंगलेश्वर (१९५४) उल्कल (१९४३) विश्वभारती (१९२१) तथा बिनम (१९५०), इनके अतिरिक्त दिल्ली का जामिया मिलिया (१९२१) तथा पूना का वीमेन्स यनिवर्सिटी (१९०२) दो और हैं।

(१) शिक्षक विश्वविद्यालय (Teaching Universities) — ये उच्च शिक्षा का प्रवन्ध करने हैं तथा अपने पढ़ाए हुए विद्यार्थियों की परीक्षा लेते हैं। इनके अपने अध्यापक होते हैं। विद्यार्थियों के लिये इनमें छात्रावास भी होते हैं। इसलिए इनको Residential Universities भी कहते हैं उदाहरणार्थ प्रयाग, लखनऊ आदि।

(२) परीक्षात्मक या सा

य स्वयं अध्यापन का प्रवन्ध न करते हैं। ये परीक्षाएँ देते हैं। ये तिनमें पढ़ाई होती है। ये

कालेजों का निरीक्षण करते हैं तथा इनमें शिक्षा देने वाले विद्यापियों की परीक्षा लेते हैं। उदाहरणार्थ आगरा विश्वविद्यालय।

(३) शिक्षा तथा मम्मेलक विश्वविद्यालय — कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो स्वयं भी शिक्षा देते हैं तथा अपने अन्तर्गत कालेजों के विद्यापियों की परीक्षा भी लेते हैं। उदाहरणार्थ कलकत्ता विश्वविद्यालय।

विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा देते हैं। माधारणतः प्रत्येक विश्वविद्यालय में माइन्स, फाटम, बीएस तथा लाये चार फैकल्टियों का व्यवस्था है। इनके अतिरिक्त एग्रीकल्चर मेडिसिन, इंजीनियरिंग, पूर्ण विद्या, तथा अन्य फैकल्टियों भी कुछ विश्वविद्यालयों में हैं। इनमें अनुसंधान कार्य भी होता है। और वे विश्वविद्यालय इस प्रकार के काम के लिये डाक्टरेट (मास्टर) की उपाधि प्रदान करते हैं।

**विश्वविद्यालय का संगठन:**—प्रत्येक विश्वविद्यालय को स्थापना एक Incorporation Act द्वारा की जाती है। अपने आन्तरिक क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की स्वतंत्रता (autonomy) है। उन्हें सरकार से अधिक सहायता मिलती है। कुछ रूपों में बहुतों की फीस, परीक्षा की फीस आदि से एकत्र करते हैं। भारत में अलीगढ़ बनारस तथा दिल्ली के विश्वविद्यालयों को केन्द्र से सहायता मिलती है तथा वे केन्द्रीय नियमों के अधीन हैं। विश्वविद्यालय भी इसी प्रकार का विश्वविद्यालय है। अन्य विश्वविद्यालय प्रादेशिक सरकारों के अधीन हैं और जहाँ से उन्हें सहायता मिलती है।

प्रत्येक विश्वविद्यालय का एक कुलपति (Chancellor) होता है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अन्य विश्वविद्यालय में उन प्रदेशों का गवर्नर ही उपकुलपति होता है। जैसे प्रयाग, आगरा, लखनऊ, विश्वविद्यालयों का कुलपति उत्तर प्रदेश का गवर्नर है। इसके नीचे एक उप-कुलपति (Vice-Chancellor) होता है। यही विश्वविद्यालय का वास्तव में मंचालन करता है। इसकी सहायता एक समिति (Executive Council) होती है। इनमें सब बातें सहमत हो कर होती हैं। उप-कुलपति इनके परामर्श के अनुसार कार्य करता है। इनके अतिरिक्त एक मन्त्री होता है। जिसको कुछ विश्वविद्यालयों में कोर्ट (Court) तथा कुछ में सिनेट (Senate) कहते हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय को इन बातों की स्वतंत्रता है कि वह अपने कार्य को सुचारु रूप से चलावे तथा अनुसंधान के लिए अध्यापकों की नियुक्ति और परीक्षाओं के सम्बन्ध में नियम बनावे।

**अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड** —मेटल्-कमीशन ने इस प्रकार के बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की थी। मंडलर कमीशन की स्थापना सन् १९१७ में कलकत्ता विश्वविद्यालय के ऊपर रिपोर्ट करने के लिये हुई थी। परन्तु इसकी रिपोर्ट अखिल-भारतीय महत्व की थी। भारतीय विश्वविद्यालय भी इस प्रकार के बोर्ड की स्थापना चाहते थे। ताकि शिक्षा के सम्बन्ध में संयोजन (co-ordination) हो सके। सन् १९२४ में शिमला में एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय सम्मेलन हुआ तथा अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड की स्थापना की गई। सन् १९२५ में इसकी प्रतिवर्ष बैठक होती है। इसमें प्रत्येक विश्व-विद्यालय के प्रतिनिधि होते हैं। इन बैठका में विश्वविद्यालय सम्बन्धित विषय पर विचार विमल होता है। इस बोर्ड के नीचे लिखे कार्य हैं।

(१) यह विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच सम्पर्क स्थापित करता है तथा उनके कार्यों के बीच मयाजीकरण करता है।

(२) इसमें विश्वविद्यालयों का एक दूसरे के काम के बारे में सूचना प्राप्त हो सकती है।

(३) उच्च शिक्षा सम्बन्धित अन्तराष्ट्रीय सम्मेलनों में या ब्रिटिश साम्राज्य-सम्मेलन सम्मेलनों में भाग लेने के लिये भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों को नियुक्त करता है।

(४) विभिन्न विश्वविद्यालयों में होने वाली नियुक्तियों के बाबते यह एक ब्यूरो (Bureau) का भी काम करता है।

(५) विभिन्न विश्वविद्यालयों के बीच शिक्षकों के आदान प्रदान में सहायता पहुँचाता है।

**उच्च शिक्षा में दोष तथा सुधार के उपाय** —भारतीय विद्वान तथा विचारका ने हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली के कई दोषों की आलोचना की है। सर्व-प्रथम यह शिक्षा व्यावसायिक जीवन में अधिक लाभप्रद नहीं है। अगर माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद कर्क बनने की इच्छा होती है। तो उच्च-शिक्षा प्राप्त कर लेने पर प्रत्येक नवयुवक जिलाधीश, जज या कोई और अफसर होना चाहता है। जिस शिक्षा से मनुष्य में सेवा भाव त्याग तथा तपस्या, चरित्र के प्रति प्रेम आदि उदात्त गुणों का जन्म न हो वह व्यर्थ है। अंग्रेजी शिक्षा दोष है कि हमारे कुछ शिक्षा प्राप्त नवयुवक अपने को साधारण व्यक्ति से भिन्न समझते हैं। उस प्रकार इस शिक्षित व्यक्ति तथा जनता के बीच एक

बड़ी खाई बन गई है। हमारा शिक्षित वर्ग मजबूत मनोवृत्ति वाला है। यह सब शिक्षा का ही दोष है। इस शिक्षा का माध्यम अभी तक अंग्रेजी है यद्यपि कुछ विश्वविद्यालयों ने हिन्दी को ऐच्छिक माध्यम मान लिया है। इनकी पल्लवहीता है कि हमारे विद्यार्थियों का अधिक समय तो इन विदेशी भाषा की मॉनने में लग जाता है। और अन्य विषयों पर वे पूरा ध्यान नहीं दे सकते हैं। इन शिक्षा में विद्यार्थियों के नैतिक चरित्र के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में सफलता प्राप्त करना रह जाता है। विद्यार्थी वर्ष भर केवल परीक्षा की ही सोचते हैं। और क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़कर साधारणतः पास हो ही जाते हैं इसलिए अधिकतर विद्यार्थी वर्ष में अधिकतम समय ध्यान नष्ट करते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अधिकतर विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने आते हैं केवल इसलिए आते हैं क्योंकि उनको कोई उपयुक्त नौकरी नहीं मिल पाती है। देश में बेकारी के कारण विश्वविद्यालयों में प्रतिवर्ष विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। विश्वविद्यालय में औद्योगिक तथा टेक्निकल शिक्षा का अभाव है। मैटलर कमीशन ने ३३ वर्ष पूर्व इस बात पर जोर दिया था कि विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की शिक्षा का प्रवर्धन हो।<sup>१</sup> बनारस, प्रलीगढ तथा कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की शिक्षा का प्रवर्धन है। परन्तु अन्य विश्वविद्यालय आर्थिक कारणों से इस दिशा में विशेष काम नहीं कर पाये हैं।

दूसरे कुछ वर्षों में विश्वविद्यालयों की शिक्षा का स्तर गिर रहा है। संघीय लोक सेवा आयोग ने इन समस्याओं का ध्यान आकर्षित किया था। परन्तु अभी सुधार की चेष्टा नहीं की गई है। इसका कारण यह है कि विश्वविद्यालयों के मन्दर समितियों के सदस्य आपस की दलबन्दी में इतना अधिक उलझे रहते हैं तथा अपने स्वामी हित को पूरा करने में इतना अधिक संलग्न रहते हैं कि उन्हें अन्य बातों के लिए समय का अभाव हो जाता है। जहाँ पर वीर्यता योग्यता तथा नैतिक-चरित्र केवल इन्हीं दो योग्यताओं को ध्यान में रख नियुक्तियाँ आदि होनी चाहिये वहाँ पर यह देखा जाता है कि इन योग्यताओं का कोई मूल्य नहीं और अध्यापकों की नियुक्ति में इस बात का अधिक ध्यान रखा जाता है कि वे किसके भाई-भतीजे हैं।

1. "It is an important and, indeed a necessary function of a university to include applied science and technology in its courses and to recognize their systematic and practical study by degrees and diplomas"



अगर हम अपनी उच्च शिक्षा का स्तर ऊँचा करना है तथा इसे व्यक्ति और देश के लिये लाभदायक बनाना है तो इसमें गीघ्रातिशीघ्र सुधार करने चाहिये। इसलिए शिक्षा अंग्रेजी माध्यम द्वारा न दी जाकर हिन्दी अथवा प्रादेशिक भाषा द्वारा दी जाय। विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान तथा शोध कार्य को महत्व दिया जाना चाहिये। शिक्षकों की नियुक्ति योग्यता के ऊपर होनी चाहिये न कि उनकी जाति या वंश पर। विश्वविद्यालयों को अपने यहाँ की भौट कम करने के लिये एम० ए० तथा शोध-कार्य के लिये यापे विद्यार्थियों तक ही अपने को सीमित रखना चाहिये। एम० ए० से निम्न कक्षाएँ विश्वविद्यालयों में सम्बन्धित फाकजा में होनी चाहिये। व्यावसायिक शिक्षा की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता की समस्या पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। अनुशासनहीनता में तात्पर्य केवल यह नहीं होता चाहिये जैसा कि मान्यता शिक्षा अधिकारियों के द्वारा किया जाता है कि विद्यार्थियों में उन राजनीतिक दलों का भी प्रभाव है जो कांग्रेस के विरोधी हैं। परन्तु मुख्यतः नैतिक पक्ष की ओर ध्यान देना चाहिये। यह भ्रम ही खेद का विषय है कि कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में महिला छात्रों के प्रति विद्यार्थियों का व्यवहार उद्वेगपूर्ण तथा कुछ मात्रा तक दुरलीलतापूर्ण है। इस दशा में शिक्षा अधिकारियों को पूरा ध्यान देना चाहिये जिस देश का धारदा था कि मित्रता दवियों है वहाँ के विद्यार्थियों को ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देना। यह सत्य है कि अधिकांश विद्यार्थी सम्य तथा सुमृद हैं।

**विश्वविद्यालय आयोग (University Commission) —**  
भारत सरकार ने विश्वविद्यालयों में सुधार के उद्देश्य से एक आयोग नवम्बर मने १९४८ में नियुक्त किया था। इसके अध्यक्ष सर सचपल्ली राधाकृष्णन थे। इसके अन्य सदस्य भारत तथा विदेशों के प्रमुख शिक्षा विशेषज्ञ थे। इस आयोग ने सब विश्वविद्यालयों तथा कई प्रमुख कॉलेजों का निरीक्षण करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट सने १९४९ में सरकार को दी। इस रिपोर्ट की अधिकतर सिफारिशों का २३ अप्रैल मने १९५० की बैठक में Central Advisory

‘The Universities must make provision for the efficient training of personnel needed for industrial development of the country’ Nurullah and Naisk, Ibid, p 237

। विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता के लिये दविये— विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता रखव थी हुमायूँ कबीर ।

Board ने मान लिया था। धनाहर्ष नवविषय में सम्मान इन मित्रादिगणों को लाभ करेगा। देश में कुछ लोगों ने कमीशन की रिपोर्टों को कुछ मित्रादिगणों की धारणा के रूप में ग्रहण कर लिया था। प्रमाण लक्षणों तथा विश्वविद्यालय के कई अध्यापकों ने इन रिपोर्टों की समन्वित प्रतिक्रिया दी। इसमें निम्नलिखित मुख्य मित्रादिगणों की सूची है—

(१) इंटरमीडिएट कक्षा हटा दी जावे। हायर सेकेंडरी बोर्डों तथा बी० ए० बोर्डों तीन-तीन वर्षों के हों।

(२) प्रत्येक छात्र को हिन्दी का अध्ययन कराना जाय। परन्तु जब तक हिन्दी में प्रमाणित पुस्तकों का अभाव है तब तक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहे।

(३) विश्वविद्यालय में केवल वे ही भर्ती किए जायें जिनको इन प्रकार की शिक्षा में लाभ होगा। शेष विद्यार्थी औद्योगिक तथा व्यावसायिक कालेजों में भर्ती हों। विश्वविद्यालय में सभी विद्यार्थियों को भर्ती किया जाय जब कि वे इनके पूर्व १२ वर्ष की शिक्षा समाप्त कर चुके हों।

(४) शिक्षक तथा विद्यार्थियों के बीच सम्पर्क बढ़ाने के लिये ट्यूटोरियल (Tutorial) पद्धति हो।

(५) विश्वविद्यालयों में छुट्टियों की संख्या कम कर दी जावे।

(६) किसी विषय के ऊपर किसी विशेष पुस्तक के आधार पर पढ़ाई के स्थान में शिक्षक विद्यार्थियों को उस विषय पर अधिशासित पुस्तकें पढ़ने को उन्माहित करें।

(७) ग्राम विश्वविद्यालयों की स्थापना की जावे ताकि उनमें शिक्षा प्राप्त करने के बाद विद्यार्थी गाँवों के जीवन में भाग ले सकें। यहाँ उन्हें कृषि, शिल्प, व्यापार आदि विषयों में सम्बन्धित बातों की शिक्षा दी जावेगी।

(८) अध्यापकों के वेतन में वृद्धि की जावे।

(९) इन विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाय—कृषि, व्यवसाय, शिक्षा, इंजीनियरिंग और औद्योगिक विज्ञान, विधि शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र।

(१०) सम्बन्धी सेवाओं के लिये विश्वविद्यालय की किसी आवश्यकता को नजर में रखा जाय।

टेक्निकल तथा औद्योगिक शिक्षा — इस प्रकार की शिक्षा का राष्ट्र के जीवन में विशेष महत्व होता है। पहले लिखा जा चुका है कि सैडलर समीक्षण में इस प्रकार की शिक्षा की ओर ध्यान देने पर नजर दिया था। परन्तु दस में इस प्रकार की शिक्षा देने वाली संस्थाओं की अत्यन्त कमी है। यह कहा जाता है कि हमारी औद्योगिक अवनति का एक प्रमुख कारण टेक्निकल तथा व्यावसायिक स्कूलों की कमी है। सन् १९४७-४८ में दस में निम्नलिखित स्कूल तथा कॉलेज थे जिनमें ऐसे सम्बन्धी तथा व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध था।<sup>१</sup>

	स्कूल	कॉलेज
इंजीनियरिंग तथा टेक्नोलॉजी	५१७	२९
मैडिसन तथा नैटर्नलरी	३९	४१
कृषि तथा वन सम्बन्धी	४१	२२
बानून	—	२०
शिक्षण संस्थाएँ	७१५	७१
कामगार	४११	२१

ऊपर दिए हुए रेखाचित्र में यह स्पष्ट हुआ कि भारत जैसे देश में इस प्रकार के शिक्षाया की वितनी कमी है। इसका कारण यह है कि विदेशी शासन ने इस प्रकार की शिक्षा को विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया। परन्तु अब इस प्रकार की शिक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। आशा है भविष्य में हम आरंभ अधिक ध्यान दिया जायेगा।

हमारे देश में औद्योगिक तथा टेक्निकल शिक्षा का विकास करने के लिये सन् १९३६ में एक कमेटी की स्थापना की गई थी। इन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा कि देश में कुछ जूनियर तथा सीनियर बॉयसन्स स्कूल खोले जाय तथा प्रत्येक प्रांत में प्रांतीय सरकार को परामर्श देने के लिये एक परामर्श-दात्री समिति नियुक्त की जाय। सन् १९४१ में इस कमेटी की सिफारिशों के अनुसार दिल्ली में एन पोलिटैक्निक की स्थापना हुई।

१. ये आँकड़े Hindustan Year Book 1955 p 316 से लिये गये हैं।

युद्ध काल में टेक्निकल शिक्षा में मुझाव रखने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी। इसके अध्यक्ष श्री मार्जेंट थे। इन समिति के नीचे लिये तीन प्रकार के टेक्निकल स्कूल खोलने की राय दी —

(१) जूनियर टेक्निकल या ट्रेड स्कूल—इसमें वे विद्यार्थी भर्ती होंगे जिन्होंने १४ वर्ष की उम्र के लगभग नीनियर वैनिक स्कूल पान किया है। इनका पाठ्यक्रम दो वर्ष का होगा।

(२) टेक्निकल हाई स्कूल—इनका पाठ्यक्रम ६ वर्षों का होगा। इसमें वे भर्ती होंगे जिन्होंने ११ वर्ष की उम्र के लगभग जूनियर वैनिक स्कूल पान किया हो।

(३) नीनियर टेक्निकल इम्प्रोव्जेशन—ये तीन वर्ष के पाठ्यक्रम के बाद डिप्लोमा प्रदान करेंगे। ये उन लोगों के लिये होंगे जो कि नौकरी पान में हों परन्तु इन प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। ये पार्ट-टाइम (part time) स्कूल होंगे।

सरकार अब इस प्रकार की शिक्षा को फैलाने के लिये कार्य कर रही है। बिना इसके देश के औद्योगिकरण में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

सन् १९५५ में औद्योगिक शिक्षा के लिये प्रखिल भारतीय समिति (All India Council for Technical Education) की स्थापना भागत सरकार द्वारा की गई। इसका कार्य सरकार उच्च औद्योगिक शिक्षा के सम्बन्ध में परामर्श देना है।

सरकार द्वारा चार औद्योगिक शिक्षालयों की स्थापना की जायगी। इनमें से तीन लखनपुर, कानपुर तथा बम्बई में स्थापित हो चुके हैं। चौथे की स्थापना मद्रास में की जायगी।

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल में वैज्ञानिक-औद्योगिक तथा औद्योगिक शिक्षा का एक विभाग है जो कि एक मंत्री के अधीन है।

अन्य संस्थाएँ:—देश में कुछ अन्य शिक्षा संस्थाएँ भी हैं। इनमें से कुछ राष्ट्रीय जागृति या धार्मिक जागृति के फल हैं—जैसे गुरुकुल (हरद्वार), महिला विश्वविद्यालय (बम्बई), जामिया मिलिया (दिल्ली), दारुलुलूम (देवबन्द), महिला विद्यापीठ (प्रयाग), हिन्दी विश्वविद्यालय (प्रयाग)। इसमें से प्रत्येक का अपना पाठ्यक्रम है। पहले शांतिनिकेतन भी इसी बोटि में था, परन्तु अब सरकार ने उसे विश्वविद्यालय स्वीकृत कर लिया है।

देश में कुछ अंग्रेजी या अमरिक्न मिशन के भी स्कूल हैं। इनमें मुख्यतः अंग्रेजी शिक्षा दी जाती है। देहरादून में तथा नैनीताल में अंग्रेजी पब्लिक स्कूलों की तरह के स्कूल खुले हैं परन्तु ये दोनों व्यक्तियों के वक्ता के लिये ही हैं। कुछ उच्चों के स्कूल मॉण्टेग्रेरी दम में शिक्षा देते हैं। अजमेर पर प्रया बहुत प्रचलित हो रही है।

हमारी शिक्षा की समस्याएँ — इन समस्याओं में मुख्यतः तीन हैं— (१) जन शिक्षा, (२) स्त्री शिक्षा, (३) गरिब शिक्षा। प्रत्येक का गतिवत् वर्णन किया जायगा।

(१) जन शिक्षा — १५० वर्षों के विदेशी शासन काल में हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा का कुछ विभाग तो हुआ परन्तु जनसंख्या का अधिकांश भाग अनशिक्षित ही रह गया। हमारे देश में गरीबों के अथवा गरीबों की शिक्षा अनशिक्षितों की संख्या सबसे अधिक है? अनशिक्षा के सामाजिक, सांस्कृतिक आर्थिक दुष्परिणामों का बलबूझा जा चुका है? इसलिये यह आवश्यक है कि देश में निराक्षरता को दूर किया जावे। यह समस्या नहीं है। हम ने ७० वर्षों के अन्दर अपने-बड़े में अनशिक्षा को दूर करने का प्रयास किया। प्राथमिक शिक्षा भी हमें दिया है लेकिन ये प्रगति कर रहा है। हमारी सरकार ने भी इस दिशा में बहुत उद्योग किया है। स्थान-स्थान पर नए प्राथमिक स्कूल तथा राशि पाठशालाओं की स्थापना की गई है। ऐसा तथा भाषणा द्वारा जनता को शिक्षित करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

जन शिक्षा के सम्बन्ध में दो योजनाओं का गतिवत् विवरण आवश्यक प्रतीत होता है—गान्धी जी की वर्षा योजना तथा साजेंट योजना।

(अ) वर्षा योजना — मार्च १९३८ में डा० जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में वर्षा में एक समेती की स्थापना हुई थी। उसने अपनी रिपोर्ट दी और ७ की शिक्षा का Wardha Scheme of Basic Education जाता है। यह निम्नलिखित भारत की अनशिक्षा को दूर करने की सबसे बड़ी योजना है। इस अर्थ में यह एक शान्तिकारी योजना है। सर्वप्रथम गान्धी जी ने सन् १९३७ में अपने स्वयं के देश योजना का पैसा चित्र रखा था। इसमें चार मुख्य बातें हैं —

(क) यह योजना मुख्यतः गांधी के लिये है, क्योंकि गांधी में अनशिक्षा गहरा ग अंधित्व है। परन्तु यह नगरों में भी लागू हो सकती है। इसका उद्देश्य यह बच्चा के लिये अनिवार्य तथा निश्चित शिक्षा का प्रयत्न करना है।

(ग) यह केवल प्रारम्भिक शिक्षा की योजना है। इसका पाठ्यक्रम मान दण्ड का है।

इसका उद्देश्य माध्यामिक शिक्षा के माध्यम-माध्य विनी प्रकार की दम्तकारी निखाना भी है। यह दम्तकारी ही बालक के मानसिक विकास का मुख्य माध्यन बनाई जायेगी।

(घ) इन शिक्षा के द्वारा अनन्ता के ऊपर कोई नया कर नहीं लाया जायगा क्योंकि यह शिक्षा दम्त-आत्म-निर्भर होगी। क्योंकि यह विचार था कि इन शिक्षा संस्थाओं में जो बाल बच्चों द्वारा तैयार होगा उसकी किसी में परीक्षा धनदानी हो जायेगी।

(ङ) यह शिक्षा मातृ-भाषा के माध्यम द्वारा हो जायेगी। इसमें बच्चों को शिक्षित होने में सहूलियत होगी।

वर्षा शिक्षा योजना नम खर्च में भारत में निरक्षरता को दूर करना चाहती है। इसके माथ ही माथ यह शिक्षा देना चाहती है जो कि जीवन में बालकों के लिये लाभप्रद तथा उपयोगी होगी। इसका यह उद्देश्य था कि गाँवों में जो बहनेरे निवासी नगरों को धार रहे हैं उनें रोका जान। इस योजना के प्रवर्तकों का ठीक ही विचार था कि अभी तक जैसी व्यवस्था है उसमें भारत का उद्धार तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि गाँवों की दशा में सुधार न हो।

(च) सार्जेंट स्ट योजना:—वर्षा योजना केवल प्रारम्भिक शिक्षा की योजना की परन्तु सार्जेंट योजना माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की भी योजना है। सरकार ने एक कमेटी बूझोत्तर भारत में शिक्षा विकास की योजना प्रस्तुत करने की नियुक्त की थी। इसकी रिपोर्ट मर् १९४४ में प्रकाशित हुई। इन कमेटी के अध्यक्ष मर जीन सार्जेंट थे, इसलिये यह सार्जेंट योजना कहलाई संक्षेप में इस योजना के अनुसार:—

(अ) प्रारम्भिक शिक्षा के पूर्व नर्सरी स्कूलों में छोटे-छोटे बच्चों की शिक्षा होगी। यह निशुल्क होगी। परन्तु अनिवार्य नहीं होगी। इनको पूर्व-प्रारम्भिक शिक्षा कहा गया है। इसमें २ से ६ वर्ष की अवस्था के बच्चे होंगे।

(ब) प्रारम्भिक शिक्षा निशुल्क तथा अनिवार्य होगी। इनमें दो ग्रेड होंगे—जूनियर बेसिक शिक्षा तथा सीनियर बेसिक शिक्षा। पहले में ६ से ११ वर्ष तथा दूसरे में ११ से १४ वर्ष की उम्र के बच्चे (बालक तथा बालिकाएँ) होंगे। इस क्षेत्र में माध्यामिक ज्ञान के प्रतिरिक्त कोई एक उद्योग की भी शिक्षा

दी जावेगी। इसमें मे केवल वही विद्यार्थी आये पढ़ने पा मंगेंगे जो कि उच्च शिक्षा के योग्य समझे जावेंगे।

(म) प्रारम्भिक शिक्षा के बाद हाई स्कूल की शिक्षा होगी। इसका पाठ्यक्रम ६ वर्ष का होगा। ११ वर्ष से १७ वर्ष तक। जो विद्यार्थी जूनियर वेसिक पाम करने के बाद योग्य समझे जायेंगे व हाई स्कूल में भेज दिये जायेंगे। शेष सीनियर वेसिक करेगा हाई स्कूल दो प्रकार के होंगे—एक academic और दूसरे technical। पहला विश्वविद्यालय के लिये विद्यार्थियों का तैयार करेगा और दूसरा किमी पेशे के लिए।

(द) विश्वविद्यालय में केवल योग्य विद्यार्थी ही भर्ती किये जायेंगे। गरीब तथा योग्य विद्यार्थियों का अधिक सहायता दी जावेगी ताकि वे अपना अध्ययन पूरा कर सकें। केवल इसी प्रकार शिक्षा का स्तर ऊँचा हो सकता है।

(न) इस योजना में इन बातों के अनिवार्य व्यापारिक तथा व्यवसायिक शिक्षा प्रौढ शिक्षा आदि के ऊपर भी मुद्राव था।

इस योजना के कई मुद्दाओं को अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा मान लिया गया है। मार्जेंट योजना तथा वधा योजना दोनों ही हमारे देश में निरक्षरता का दूर करने चाहते हैं। वरी योजना बहुत कम खर्चीली है। मार्जेंट योजना केवल प्रारम्भिक शिक्षा की ही योजना नहीं है। इसका अन्तर्गत व्यापक है।

(२) स्त्री-शिक्षा — जैसे पहले लिखा जा चुका है प्राचीन भारत में स्त्री शिक्षा की ओर सर्वोत्तम ध्यान दिया जाता था और कई विद्वपियाँ उस काल में ही जिनका नाम आज तक हम नहीं भूलते हैं। परन्तु समय स्त्री शिक्षा में गड़ी गई और बाद का तब केवल प्रारम्भिक शिक्षा ही उनका साधारण प्राप्त थी। मध्यकाल में देश में पढ़ाई प्रथा का बहुत अधिक प्रचलन हो गया था। और इस कारण स्त्रियों का क्षेत्र केवल घर ही रह गया था। ऐसी दशा में यह स्वाभाविक था कि उनकी शिक्षा की ओर उचित ध्यान न दिया जावे। कालान्तर में स्त्रियाँ में शिक्षा का प्रचार बिल्कुल ही नहीं रहा। परन्तु आधुनिक काल में पुन इस बात को सब विचारवान व्यक्ति समझने लग गए हैं कि बिना स्त्रियों को शिक्षित बनाये हमारे देश का उन्नयन सम्भव है। अधिष्ठित नारी अपने बाल-वच्चों का टीका प्रकार पालन नहीं कर सकती है। यह समाज की ब्यां सवा करेगी। सर्वप्रथम ब्रह्म-समाज, आर्यसमाज तथा ईसाई मिशनरियाँ

ने स्त्री-शिक्षा को ओर ध्यान दिया। सरकार ने इन दिशा में बहुत बड़ों की सहायता की। २०वीं शताब्दी में स्त्री-शिक्षा ने पहले की अपेक्षा कारी उन्नति की है। नगरपालिकाओं तथा जिन्दा बोर्डों ने स्त्रियों के प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था की है। उनकी माध्यमिक शिक्षा के लिये भी देश में शिक्षालय हैं। वे विश्वविद्यालयों में भी शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। बम्बई में एक स्त्री विश्वविद्यालय भी है। वे डाक्टरों, कानून तथा इंजीनियरिंग की शिक्षा को ओर भी बढ़ रही हैं। परन्तु इतना सब होने हुए भी हमारे देश में केवल ३% स्त्रियाँ शिक्षित हैं। यह अत्यन्त लज्जा की बात है कि हमारे समाज का धर्म हित्ता पूर्ण रूप से अज्ञान में डूबा है। जो कुछ स्त्रियों की शिक्षा का प्रचार हुआ है वह भी अधिकतर नगरों तक ही सीमित है। इन बातों की अत्यन्त आवश्यकता है कि शोधप्रतिष्ठान स्त्रियों के लिये प्रारम्भिक शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य हो जाय।

(३) सह शिक्षा :—स्त्री शिक्षा के सम्बन्ध में ही सह-शिक्षा का भी प्रश्न उठता है। सन् १९३४ में अन्तरविश्वविद्यालय बोर्ड ने इन प्रश्नों पर विचार किया था कि स्कूलों में सह-शिक्षा हो या नहीं। देश में काफी लोग इसके पक्ष में हैं। परन्तु बहुमत इसके विरुद्ध रगता है। सह-शिक्षा का प्रश्न, विश्वविद्यालयों या अन्य उच्च शिक्षा के केन्द्रों में नहीं उठता है। वहाँ तो सह-शिक्षा होगी ही। यह प्रश्न बहुत छोटी अवस्था के बालक-नारिकों के लिए भी नहीं उठता है। यह दोनों के बीच की अवस्था से सम्बन्ध रखता है। यह वह अवस्था है जब हमारे चरित्र का निर्माण होता है तथा हमारी बुद्धि का विकास होता है।

कुछ विद्वानों का कहना है कि सह-शिक्षा के कई लाभ हैं। उनके अनुसार बालक तथा बालिकाएँ एक दूसरे से स्वतंत्रतापूर्वक मिलकर एक दूसरों को भली-भाँति समझने लगते हैं और यह उनके भविष्य-जीवन के लिये अत्यन्त लाभप्रद होगा। सह-शिक्षा का एक गुण यह भी बख्शा जा सकता है कि वे एक दूसरे के गुणों को ग्रहण कर लेंगे। इससे उनका व्यक्तित्व और अधिक विकसित होगा। कुछ लोगों के अनुसार सह-शिक्षा में एक लाभ यह भी है कि बालक कक्षा में

1. "Education comprise that period of our lives in which our characters are formed and moulded and our faculties so developed and regulated by reason that we can therefore face life with equanimity. The question therefore is whether the education of boys and girls at that stage... is possible and useful." Siqueira, Ibid, pp. 132-133. -



ीक प्रकार बैठते हैं और बदनमीजी करने की हिम्मत नहीं करते हैं। परन्तु सह-शिक्षा के विरोधियों का कहना है कि यह अत्यन्त हानिकारक है। इस शिक्षा समस्याओं का वातावरण दूषित हो जाता है। स्त्रियो तथा पुरुषों के बीच अलग-अलग हैं, इसलिए उनकी शिक्षा भी अलग-अलग प्रकार की होनी चाहिये तथा उनमें अलग-अलग प्रकार के गुणों का विकास भी होना चाहिये। इनकी राय में सह-शिक्षा से भारतीय नारी को कोई लाभ नहीं होगा।

ऊपर संक्षेप में हमने भारत की शिक्षा से सम्बन्धित विविध समस्याओं का वर्णन किया है। एक बात स्पष्ट है, वह यह कि भारत में शिक्षा के प्रसार की अत्यन्त आवश्यकता है। इसके बिना हमारी उन्नति असम्भव है।

### प्रश्न

- (१) भारत में शिक्षा की मुख्य समस्याएँ क्या हैं?
- (२) उत्तर प्रदेश में १९४७ से लेकर अब तक शिक्षा में जो उन्नति हुई है उसका संक्षेप में वर्णन कीजिये। (यू० पी० १९५५)
- (३) भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या दोष है? आप उसमें धीरे-धीरे सुधार करेंगे। (यू० पी० १९५५)

## भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ

अत्यन्त प्राचीन काल से विभिन्न राज्यों के बीच में किसी न किसी प्रकार के सम्बन्ध रहे हैं। इन राज्यों ने कई अवसरों पर इस बात का प्रयत्न किया कि उनके बीच के सम्बन्ध मंजूर होने लगे और वे अपने आपसी झगड़े का शान्तिपूर्ण ढंग से निपटारा कर दें। सम्पत्ता के विकास के साथ-साथ यह भावना भी बढ़ती गई। प्राचीन युग में इस प्रकार के संघ थे। मध्यकाल में सब ईसाई यूरोपीय देशों में यह भावना थी कि वे सब एक ही धर्म के अनुयायी होने के कारण एक ही बृहद् समाज के सदस्य हैं। आधुनिक काल में १५वीं तथा १६वीं शताब्दियों में राज्यों ने एक दूसरे के विरुद्ध युद्धों में अत्यन्त ही पाशविकतापूर्ण व्यवहार किया। परन्तु सन् १६४८ के बाद यह भावना उत्पन्न हो गई थी कि सब यूरोपीय राष्ट्र एक परिवार के सदस्य हैं। उक्त काल में कई विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया। इनमें से मुख्य नाम ये हैं—मथन के राजा हेनरी चतुर्थ का मंत्री सल्ली (Sully), आबे मां पियर, रूसो, फान्ट, तथा वेन्सम। १९ वीं शताब्दी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के बड़े देशों ने एक सन्धि (नवम्बर १८१५) द्वारा यह तय किया था कि प्रति वर्ष उनकी एक बैठक होगी जिसमें वे विभिन्न समस्याओं को मुलज्जा लेंगे। इसको Concert of Europe कहते हैं। परन्तु यह व्यवस्था शीघ्र ही टूट गई। सन् १८९९ तथा १९०७ में दो कॉन्फ्रेंस हुईं जिनको हेग कॉन्फ्रेंस कहते हैं। ये भी अधिक सफल नहीं रही। सन् १९१४-१९१८ के प्रथम महायुद्ध के पश्चात् यह विचार बलवान हो गया कि एक अन्तराष्ट्रीय संगठन की स्थापना होनी चाहिये। इस संगठन को राष्ट्र-संघ (League of Nations) कहते हैं। इस संघ का उद्देश्य समार में शांति को बनाये रखना था। इसलिए हमको यह अधिकार दिया गया था कि अगर किन्हीं राज्यों के मध्य कोई ऐसी विवाद उठ सके हो जिसमें कि संसार की शांति को भय हो तो राष्ट्र-संघ दोनों देशों को शांतिपूर्ण ढंग से उस विवाद को तय करने को कह सकता था और अपने मुझाव दे सकता था। इसके सदस्यों के लिए तो यह आवश्यक था कि वे अपने सब विवाद शान्तिपूर्ण ढंग से तय करें।

राष्ट्रसंघ का दफ्तर जिनवा में था। इसके मुख्य अंग थे—महा कौमिल सचिवालय, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ तथा कई गणि नियां। राष्ट्रसंघ में जैसी आशा थी वह पूर्ण नहीं हुई। इसके संस्था ने अपने स्थायी के सम्मुख समार की शान्ति तथा सुरक्षा की परवाह नहीं की। जब जर्मनी ने वर्साई सन्धि की उल्लंघन की या इटली ने अवीमीनिया को हथ लिया जब जापान ने चीन पर आक्रमण किया तब राष्ट्रसंघ कुछ न कर सका। इसमें यह स्पष्ट हो गया कि बड़े राष्ट्र राष्ट्रसंघ की उल्लंघन कर रहे हैं। इसी का यह फल हुआ कि राष्ट्रसंघ द्वितीय महायुद्ध को नहीं रोक सका।

भारत भी राष्ट्रसंघ का सदस्य था। तब भारत परतंत्र देश था परन्तु क्योंकि इसने बर्माई की सन्धि पर हस्ताक्षर किये थे इसलिए इसको राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त हो गई थी। परन्तु भारत के प्रतिनिधि अंग्रेज सरकार द्वारा छोटे जाने थे अतएव वे इंग्लैंड के हीरोपी थे न कि भारत के हिता के प्रतिनिधि। उन सब बातों के होते हुए भी भारत ने राष्ट्रसंघ के कई कामों में महत्वपूर्ण भूमिका ली। जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ (International Labour Organization)। राष्ट्रसंघ के बारे में कहा जाता है कि राजनैतिक मामलों में (Political matters) में तो उस सफलता नहीं मिली परन्तु सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य सम्बंधी विषयों में इसने अच्छा काम किया। भारत में राष्ट्रसंघ की एक शाखा दिल्ली में थी। इसका काम राष्ट्रसंघ के बारे में प्रचार करना था। भारत की सरकार ११ नवंबर १९५१ को राष्ट्रसंघ को देती थी।

संयुक्त राष्ट्रसंघ —द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होने पर लोगों की आँखें फिर खुलीं। इससे विनाशकारी परिणामों ने स्पष्ट रूप में यह दिखला दिया कि अगर सभ्यता तथा मानवता को नष्ट होने में डूबना है तो राष्ट्रों को आपस में शान्तिपूर्ण उपायों से अपने सब मामलों को तय कर लेना चाहिए। मित्र राष्ट्रों ने मई १९४३ में यह तय कर लिया कि युद्ध की समाप्ति पर तब अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना की जावेगी जिसका प्रमुख काम समार की शान्ति रक्षा होगा। मई १९४४ में डब्लुएन ओएम में मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की एक बैठक के अध्यक्षता अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की एक योजना बनाई गई जो इसको डब्लुएन ओएम योजना कहते हैं। मई १९४५ में मून फ्रामिङको में। फिर एक मित्र-राष्ट्रों की बैठक हुई। इसमें डब्लुएन ओएम योजना पर विचार विमर्श हुआ तथा एक नया चार्टर बनाया गया। इसका नाम संयुक्त राष्ट्रसंघ का चार्टर (United Nations Charter) रखा गया। इस चार्टर पर ५१ राष्ट्रों ने हस्ताक्षर

विशेष। इस प्रकार जब संयुक्त राष्ट्रसंघ की संसद्बन्धन सन् १९४५ में स्थापना हुई तो इसके ५१ सदस्य थे।

**उद्देश्य** — संयुक्त राष्ट्रसंघ की प्रस्तावना में कहा गया है कि युद्ध के नष्ट का नष्टा के लिए काम करने को, व्यक्ति के तथा राष्ट्रों के अधिकार को रक्षा करने को, न्याय की स्थापना करने को तथा सामाजिक उन्नति और जीवन-मूल्य उन्नत करने को, इस राष्ट्रसंघ की स्थापना की जा रही है।

घाटेर की पहली धारा में निम्नलिखित उद्देश्य बतलाए गये हैं:—

(१) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा की स्थापना।

(२) राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों का विकास करना।

(३) अन्तर्राष्ट्रीय, प्रांशिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय समस्याओं को हल करने के लिए राष्ट्रों में सहयोग करना तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सम्मान उत्पन्न करना।

(४) इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये, विभिन्न राष्ट्रों के कामों को संयोजित करने के लिये, केन्द्र-रूप में कार्य करना।

धारा-२ में एक मिश्रणों का वर्णन है जिसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य करता है।

१. निम्नलिखित राष्ट्र इसके प्रथम ५१ सदस्य थे:—

आर्जेन्टिना, ऑस्ट्रेलिया, बेलजियम, बोलिविया, ब्राजील, केलिफोर्निया, कनेडा, चीन, कोलम्बिया, कोस्टारिका, क्यूबा, डेक्कलावाकिना, डेन्मार्क, डोमिनिकन रिपब्लिक, इक्वाडोर, इजीप्ट, एल सल्वदोर, इथियोपिया, फ्रांस, ग्रीस, हावैमाता, हैटी, हांगकंग, भारत, ईरान, ईराक, मेक्सिको, सल्वाडोर, मैक्सिको, नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, निकारागुआ, नीवे, पनामा, पेरू, पोलैंड, पोर्तुगल, रोमी शरक, सीरिया, टर्की, यूक्रेन, दक्षिणी अफ्रीका, हंगरी, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूगोस्लाविया, वेनिसुएला तथा युगोस्लाविया।

इन ५१ सदस्यों के पश्चात् निम्नलिखित ३० राज्य और इनके सदस्य हो गये हैं:—अफगानिस्तान, आइसलैंड, स्वीडेन, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान, सनर, बर्मा, इसरायल, हिन्दोनिशिया, मल्लानिया, म्यान्मार्, बल्गेरिया, कम्बोडिया, चीली, फिलिपिन्स, हंगरी, आयरलैंड, इटली, जॉर्डन, लाओस, नीबिया, नेपाल, पृथ्वी, रमानिया, स्पेन, मोरक्को, सूडान, टुनिशिया, जपान तथा दना।

- (ग) सदस्यों की भावभूमि का तथा
- (ब) प्रत्येक सदस्य अपने कलव्या का ठीक ढंग से प्रदर्शन करेगा।
- (स) वे अपने आगामी विवादों का शान्तिपूर्ण ढंग से फैसला करेंगे।
- (द) वे अपने अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में एक दूसरे के विरुद्ध न युद्ध करेंगे और न इसकी धमकी ही देंगे।

(घ) वे संयुक्त राष्ट्र संघ का इसकी कार्यवाही में प्रत्येक प्रकार की सहायता देंगे।

(न) संयुक्त राष्ट्र संघ किसी राज्य के आन्तरिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्रसंघ के छ मुख्य भाग (Organs) हैं साधारण सभा, सुरक्षा परिषद्, अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, आर्थिक तथा सामाजिक समिति-संरक्षण परिषद्।

**साधारण सभा** — संयुक्त राष्ट्रसंघ के प्रत्येक सदस्य राज्य का इसमें प्रतिनिधित्व होता है। इसको हम यमर की समझ कह सकते हैं। प्रतिवर्ष इसकी एक बैठक होती है। परन्तु इसकी विशेष बैठक भी बुलाई जा सकती है। साधारण निर्णय बहुमत द्वारा तथा महत्वपूर्ण मामलों में बहुमत द्वारा निर्णय लिये जाते हैं।

प्रत्येक बैठक में सुरक्षा परिषद् तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ के अन्य भाग साधारण सभा को अपने कामों की रिपोर्ट देते हैं। सत्रोत्तरी जनरल पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ के कामों पर एक रिपोर्ट देता है। साधारण सभा सुरक्षा-परिषद् के सदस्यों का तथा आर्थिक और सामाजिक समिति और संरक्षण समिति के सदस्यों का चुनाव करती है। यह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों के निर्वाचन में भी सुरक्षा परिषद् के साथ भाग लेती है तथा सुरक्षा परिषद् की सकारित्व पर सत्रोत्तरी जनरल को नियुक्त करती है।

**सुरक्षा-परिषद्** — इसमें ११ सदस्य हैं। इनमें से ५ तो स्थायी सदस्य हैं—ब्रिटिश, फ्रांस, चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। दोष ६ सदस्यों का दोष के लिए साधारण सभा द्वारा निर्वाचित होता है। सुरक्षा-परिषद् संघ की कार्यकारिणी समिति है। इसको महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय देने का अधिकार है।

सुरक्षा-परिषद् का अधिकार स्वामी रूप में होता रहता है। प्रत्येक पक्ष इसकी वृत्त से वृत्त एक के क अवश्य होती है। प्रत्येक सदस्य को एक वोट का अधिकार है। महत्वपूर्ण विषयों के निर्णय के लिये इसके प्रत्येक स्थायी सदस्य का वोट होना आवश्यक है। अगर इनमें से कोई ऐसे विषय के विषय में

मग दे दे तो फिर सुरक्षा परिषद् कोई निर्णय नहीं ले सकती है। इसको विशेषाधिकार (Veto) कहा जाता है। कार्यक्रम ने सम्बन्ध रखने वाले विषयों के लिये ११ में से ७ मत पक्ष में होने चाहिए।

सुरक्षा परिषद् मन्त्रालय में गान्ति की नरक्षक है। इसको यह अधिकार है कि अगर किन्हीं राज्यों के बीच में युद्ध की आशंका हो तो यह उनको विवाद का निर्णय गान्तिपूर्ण ढंग में करने को कह सकती है। अगर कोई राज्य इनकी सिफारिशों को न माने तो यह उसे आक्रमणकारी (aggressor) घोषित कर उसके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर सकती है। प्रत्येक सदस्य चार्टर द्वारा बचन-बद्ध है कि वह सुरक्षा परिषद् को प्रत्येक प्रकार की सहायता तथा सहयोग, जिसकी कि परिषद् मांग करे, देगा। परिषद् को सैनिक विषयों में सहायता देने के लिये सैनिक-समिति है जिसमें प्रत्येक स्थायी सदस्य का एक प्रतिनिधि है।

**अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय:**—इसकी बैठकें हेग (हालैंड) में होती हैं। इनमें १५ न्यायाधीश होते हैं, परन्तु एक राज्य में से एक से अधिक व्यक्ति इसका न्यायाधीश नहीं हो सकता है। इन न्यायाधीशों को साधारण समा तथा सुरक्षा-परिषद् निर्वाचित करती है। उनका कार्यकाल ९ वर्ष का होता है।

इस न्यायालय को राज्यों के बीच किसी विवाद के निर्णय करने का अधिकार है। परन्तु यह किसी विवाद का निर्णय तभी कर सकता है जबकि उससे सम्बन्धित दोनों दल इसके निर्णय को मानना स्वीकार कर लें। इस न्यायालय की व्यवस्था इसलिये की गई है ताकि विभिन्न राज्य अपने विवादों को गान्तिपूर्ण ढंग से तय कर लें।

**सचिवालय:**—यह अन्तर्राष्ट्रीय मिल्ड मिल्ड है।<sup>1</sup> इसके प्रत्येक सदस्य को इस बात की क्षम्य लेनी होती है कि यह संयुक्त राष्ट्र सच के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करेगा। इसमें प्रत्येक जाति तथा रंग के व्यक्ति हैं। इसका प्रधान सेक्रेटरी जनरल कहलाता है जिसका निर्वाचन सुरक्षा परिषद् की

1. "In the performance of their duties the Secretary General and the staff shall not seek or receive instruction from any government or from any other authority external to the Organisation. They shall refrain from any action which might reflect on their position as international officials responsible only to the Organisation."

मिफार्मिग पर माशरण-मभा द्वारा किया जाता है। उसको मन्त्रायक मन्त्रेदारी जनरल तथा अन्य कर्मचारी नियुक्त करने का अधिकार है। मन्त्रिवालय में आठ विभाग हैं। इनके क्रमशः ये काम हैं मुख्य परिषद् में सम्बन्धित मामल, आर्थिक मामले, सामाजिक मामले, मरक्षण तथा अधीन देशों से सम्बन्धित सूचना, सर्वजनिक सूचना कानूनी सम्मेलन तथा माधारण सेवाएँ तथा प्रशा-मनीय और आर्थिक सेवाएँ।

**आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्** — इनमें १९ सदस्य हैं जिनका निर्वाचन माशरण्य तथा द्वारा तीन वर्ष के लिये किया जाता है। इसके निर्णय बहुमत से होते हैं। इसका काम अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय समस्याओं के हल करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को उत्साहित करना है। यह इन समस्याओं में सम्बन्धित विविध विषया का अध्ययन करती है तथा समय-समय पर मन्त्र-मण्डलों के अधिवेशन बुलाती है। इसका काम मन्त्र की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नति करना है। इस परिषद् के नीचे कमीशन विविध विषया पर काम कर रहे हैं।

**संरक्षण परिषद्** — मयुक्त राष्ट्र मण्डल के कई सदस्यों के अधीन कई देश हैं। इन पराधीन देशों का भी चार्टर द्वारा ध्यान रखा गया है। इसके द्वारा इस बात की घोषणा की गई है कि जो सदस्य राष्ट्र ऐसे पराधीन देशों का शासन करते हैं वे इनके हितों का पूरा-पूरा ध्यान रखेंगे तथा प्रत्येक क्षेत्र में उन प्रदेशों के शासन के सम्बन्ध में समुक्त राष्ट्र मण्डल को समय-समय पर रिपोर्टें देंगे जिनमें कि वहाँ की स्थिति के ऊपर प्रकाश डाला जायगा। पराधीन देशों के शासन के लिए मरक्षण परिषद् की स्थापना की गई है। इसमें दस समय १२ सदस्य हैं। इस परिषद् का मुख्य काम इन पराधीन देशों की आर्थिक सामाजिक तथा राजनैतिक प्रगति के सम्बन्ध में रिपोर्टें की जाँच करना तथा समय-समय पर इन प्रदेशों में जाँच करने के लिये मिशन का भेजना है। कई राज्यों ने अपने अधीन देशों को मरक्षण परिषद् के समुक्त कर दिया है।

**विशेष एजेन्सियाँ** — मयुक्त राष्ट्र मण्डल ने कुछ विशेष अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के साथ अपने काम को मन्त्रा रूप से चलाने के उद्देश्य से मध्यस्थता कर लिया है। इन एजेन्सियों का चार्टर में कोई वर्णन नहीं है। ये मयुक्त राष्ट्र मण्डल के भाग भी नहीं हैं परन्तु इनका उद्देश्य भी विभी विशेष क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है। इनमें से मुख्य-मुख्य ये हैं—(१) अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर मण्डल—इसकी स्थापना २९ अक्टूबर सन् १९१९ में हुई थी। इस मण्डल का उद्देश्य

प्रत्येक देश में श्रमिकों की दशा में सुधार करना है। (२) खाद्य तथा कृषि संघ—जैसा कि इसके नाम में स्पष्ट है इनका उद्देश्य मसालों में कृषि की उन्नति करना है। (३) संयुक्त राष्ट्र का शिक्षा, सांस्कृतिक, तथा वैज्ञानिक संघ—इसका उद्देश्य राष्ट्रों के बीच सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा शिक्षा सम्बन्धी क्षेत्रों में सहयोग द्वारा शान्ति को बढ़ाना है। (४) अन्तर्राष्ट्रीय बैंक—यह मसालों देशों की आर्थिक उन्नति अथवा पुनर्निर्माण के कामों के लिये रुपया उधार देता है। इसके अतिरिक्त इस बात का प्रयास करता है कि राष्ट्रों के बीच व्यापार प्रवृत्ति हो।

इनके अतिरिक्त कई अन्य एजेंसियाँ हैं—अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संस्था, अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्था, विश्व डाक संघ, अन्तर्राष्ट्रीय तार-संचार संघ आदि। इन संघों का काम अपने-अपने विशेष क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है।

**भारत तथा संयुक्त राष्ट्र संघ :**—हमारा देश संयुक्त राष्ट्र के प्राथमिक सदस्यों में से एक है। आरम्भ से ही स्वतन्त्र भारत की सरकार ने इस बात की घोषणा कर दी थी कि वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शान्ति और नव राष्ट्रों में मित्रता की नीति का अनुसरण करेगी। हमारा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नोक्त संगठनों (organizations) का भी सदस्य है। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्था, खाद्य तथा कृषि संस्था, अन्तर्राष्ट्रीय तार संचार संघ, विश्व डाक संघ, विश्व स्वास्थ्य संघ, अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री परामर्श संस्था। इन संगठनों के अतिरिक्त भारत अनेक आयोगों (commissions) का भी सदस्य है। जैसे, मानव अधिकार आयोग, मादक वस्तु आयोग, यातायात तथा संचार आयोग, सुदूर पूर्व एजिपाई आर्थिक आयोग इत्यादि।

भारत ने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तटस्थता की नीति को अपनाया है। इस समय दो बातें हैं—अमेरिकन तथा रूस और उनके साथी। भारत की सरकार का कहना है कि वह इन दोनों में से किसी के साथ भी नहीं है और स्वतन्त्र नीति का अनुसरण कर रही है। सरकार के कुछ आलोचकों का कहना है कि ऐसी नीति हमारे देश के हित में नहीं है। हम इनमें न अमेरिका ने ही महात्मा की आशा कर सकते हैं और न रूस से ही।

पं० नेहरू के अनुसार संसार का दो प्रतिशतों गुटों में विभाजन शान्ति के हित में नहीं है। यदि भारत इनमें से किसी एक गुट का सदस्य हो जाय तो शान्ति



के हित में उसकी कार्य करने की स्वतन्त्रता भंग हो जायेगी। भारतवर्ष, अमेरिका तथा हम दोनों ने ही मंत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापना चाहता है। उसे इन दोनों महान देशों में बहुत-बहुत सीखना है। परन्तु वह इन देशों की नीति से पूर्णतः सहमत नहीं। इसलिए भारत सरकार की तटस्थता की नीति वास्तव में अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतन्त्रतापूर्वक शान्ति के प्रयत्न में काम करने की नीति है। भारत ने अफ्रीका तथा हम के उन नामों का समर्थन किया जिनको वह ठीक समझता था उन कामों का विरोध किया जिनके औचित्य पर उसे सन्देह था।

अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में तटस्थता की नीति अत्यन्त ही सफल रही है और अब भी व० नेहरू की नीति के विरोधी भी यह स्वीकार करते हैं कि भारत को इस क्षेत्र में अत्यन्त सफलता मिली है। आज समस्त मसाले भारत की शक्तिपूर्ण नीति की मजबूती से गिरावला कर रहा है। व० नेहरू का धीत तथा यूरोप के देशों में अग्रतत्पूर्य स्वागत हुआ। यह हमें बयान को सिद्ध करता है कि हमारी पर-राष्ट्र नीति सफल है।

प्रत्येक महत्वपूर्ण अन्तराष्ट्रीय मामले में भारत ने इस बात का प्रयत्न किया है कि मयका राष्ट्रमण्डल की मर्यादा न घटने पाए। भारत के अनुसार मसाले के राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों शान्तिपूर्वक सुलझाये जा सकते हैं। मयका राष्ट्रमण्डल हम दोनों देशों में महत्वपूर्ण भाग रहेगा है यदि हमें हमारे मदमियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो।

1 श्री चेस्टर बोल्ल (Chester Bowles) ने जो भारत में पहले मयका राज् अमेरिका में राजदूत थे अपनी पुस्तक में भारत के विषय में लिखा है, "In the United Nations, she has stood out as a militant and uncompromising foe of colonialism and a champion of the right of still subject people to independence. This position has brought her in conflict on occasion with American views that the principle of self-determination must give way to the pressure of contemporary *Realpolitik*. On the whole, however, I think it has been to our advantage to have another democratic nation stating the case for freedom, on these occasions when rightly or wrongly, we have felt we could not rather than leave this field to Communism." *The New Dimensions of Peace*, p 165.

भारत ने न केवल दूसरे देशों के विषय में परन्तु उन विषयों में भी जिनमें इनके अपने स्वार्थ निहित थे इसी नीति को अपनाया है। इनका सबसे ज्वलन्त उदाहरण काश्मीर का प्रश्न है। यह स्पष्ट रूप में ज्ञात हुआ है कि भारतीय सेना उस समय इस स्थिति में थी कि काश्मीर से आक्रमणकारियों को बल प्रयोग द्वारा पूर्णतः खदेड़ सकती थी, परन्तु हमारी सरकार ने काश्मीर की समस्या को संयुक्त राष्ट्र मंच के सम्मुख न्यायोचित रूप में हल करने के लिये प्रस्तुत किया। यह दुसरी बात है कि संयुक्त राष्ट्र मंच में कुछ राष्ट्रों ने इस प्रश्न को शीत-युद्ध में सम्मिश्रित कर दिया है और यह प्रश्न अभी तक नहीं मूलतः सचा है।

कोरिया का प्रश्न जून १९५० में अन्तर्राष्ट्रीय शांति के लिये भय-काण्क्ष हो गया था। इसे लेकर अमेरिका तथा चीन के मध्य इसनी अधिक तनातनी बढ़ी कि एक समय ऐसा प्रतीत होने लगा था (मार्च १९५२) कि यह प्रश्न एक नये युद्ध को जन्म देगा। परन्तु भारत की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र मंच के द्वारा यह प्रस्ताव पास कराया कि दोनों के मध्य युद्ध विराम हो जाय तथा दोनों पक्ष बन्दियों को लौटा दें। इसको कार्यान्वित करने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति की गई थी और भारत इसका अध्यक्ष था।

इसी प्रकार हिन्दुचीन (Indo-china) की समस्या के हल में भी भारत ने प्रमुख भाग लिया। हिन्दु-चीन में वहाँ के राष्ट्रीय दल तथा फ्रांस के मध्य क वर्षों में युद्ध चल रहा था। इसमें भी विश्व शांति को बहुत उत्पन्न हो रहा था। भारत की सरकार के प्रयास से इस समस्या को भी संयुक्त राष्ट्र मंच मूलज्ञाने में सफल हो सका। जेनेवा में एक सम्मेलन हुआ जिसके द्वारा हिन्दु चीन में युद्ध-विराम हुआ और एक आयोग की नियुक्ति की गई जो कि हिन्दु चीन में जेनेवा सम्मेलन के प्रस्तावों के कार्यान्वित होने का निरीक्षण करता। इस सम्मेलन में तीन देशों के प्रतिनिधि थे—कनाडा, भारत तथा पोलैण्ड।

स्वेड-संघट भी विश्व में तृतीय युद्ध का सूत्रपात कर सकता था। परन्तु इस संघट के मूलज्ञाने में भी भारत का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। जुलाई १९५६ में मिश्र की सरकार ने स्वेड नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अक्टूबर १९५६ में मिश्र पर इमरायल, इंग्लैण्ड तथा फ्रांस ने आक्रमण कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरक्षण परिषद् में एक प्रस्ताव इस घातक का रखा गया कि कोई भी राष्ट्र मिश्र पर शक्ति प्रयोग न करे। परन्तु इंग्लैण्ड तथा फ्रांस ने इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। संयुक्त राष्ट्र मंच में पुनः शांति के लिये प्रस्ताव पास किये गये और इन प्रयत्नों में भारत का भी प्रमुख भाग रहा। अन्त में मिश्र में एक

अन्तर्राष्ट्रीय सेना, मयूक्त राष्ट्र सघ के नीले तथा श्वेत झन्डे के नीचे भेजी गयी और भारत ने भी इसमें योगदान दिया।

अक्टूबर १९५६ में हंगरी में वहाँ की साम्यवादी सरकार के विरुद्ध एक क्रांति प्रारम्भ हुई। रूस ने इसमें हस्तक्षेप किया और क्रांति को कुचल दिया और रूस की सहायता में साम्यवादी सरकार की पुनस्थापना हुई। भारत ने हंगरी में इसी हस्तक्षेप की निन्दा की और इस प्रकार यह सिद्ध कर दिया कि भारत प्रत्येक राज्य के कार्यों का निष्पक्ष रूप में देखता है।

उपर्युक्त उदाहरणों के अतिरिक्त अनेक अन्य समस्याओं के मूलज्ञाने में भी भारत का योगदान रहा है और मयूक्त राष्ट्रसघ के कार्यों में भारत का महत्वपूर्ण भाग रहा है। संसार के सम्मुख युद्ध का भय बना है और यह सभी जानते हैं कि तृतीय महायुद्ध मानवता के लिये घातक सिद्ध होगा। इसीलिये निःशस्त्रीकरण मानवता के जीवन-मरण का प्रश्न हो गया है। भारत ने प्रत्येक अवसर पर इस बात का प्रयत्न किया है कि विश्व की सभी शक्तियों निःशस्त्रीकरण कर लें जिससे युद्ध का भय दूर हो जाय। हमारी सरकार का यह दृष्टिकोण है कि धन-शक्ति का प्रयोग मानवता कल्याण के लिए होना चाहिए न मानवता के विनाश के लिये। भारतीय नीति का आधार यह है कि जिस प्रकार एक समाज के सदस्य अपने विवाह का निगम शान्तिपूर्ण ढंग में करते हैं उसी प्रकार संसार के विभिन्न देशों को भी शान्तिपूर्ण उपायों द्वारा अपने झगडा का मूलज्ञाना चाहिये।

भारत ने मयूक्त राष्ट्र सघ में उन सब प्रस्तावों का समर्थन किया है तथा इससे उन सब कार्यवाहियों में सक्रिय भाग लिया है जो कि विश्व-शान्ति के हित में थी। भारत की सरकार का यह मत है कि मयूक्त राष्ट्र सघ को वास्तव में विश्व के राज्या तथा राष्ट्रों का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिये। इसीलिये भारत की यह नीति है कि साम्यवादी चीन का मयूक्त राष्ट्रसघ की सदस्यता से वञ्चित रखना न केवल अन्यायपूर्ण है परन्तु संसार की शान्ति के हित में भी नहीं है। साम्यवादी सरकार को भारत चीन की वास्तविक तथा वैधानिक सरकार मानता है। इस समस्या को मूलज्ञाने के लिये भारत विशेषतः प्रयत्नशील है।

भारत ने संसार में सबसे साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के विरुद्ध अपनी नीति रखी है। इसने बार बार इस बात का कहा है कि शान्ति के मार्ग में साम्राज्यवाद एक बड़ा रोड़ा रहा है। इसीलिये हमारी सरकार का यह दृष्टिकोण है कि साम्राज्यवादी देशों का कल्याण इसी में है कि वे अपने आधीन देशों को स्वतन्त्र कर दें। क्योंकि बल प्रयोग द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त को देना सम्भव नहीं है।

इसीलिये हमारी महानुभूति उनमें है जो स्वतन्त्रता के लिये प्रयत्नशील हैं। जब हिन्दुएशिया ने डच साम्राज्यवाद में मूर्खता के लिये प्रयत्न किया और डच साम्राज्यवाद ने शक्ति द्वारा हमें दबाये रक्खता चाहा तब भारत ने एशियाई राष्ट्रों का सम्मेलन दिल्ली में बुलवाया तथा हिन्दुएशिया की स्वाधीनता मार्ग को मजबूत राष्ट्र मंच के सामने रखा। उत्तरी अफ्रीका में जिन देशों ने फ्रांस में स्वतन्त्र होने का प्रयत्न किया या कर रहे हैं उनमें हमारे देश की महानुभूति है। इसी प्रकार सर्वत्र भारत की नीति साम्राज्यवाद की विरोधी रही है।

संयुक्त राष्ट्र मंच की सांस्कृतिक तथा आर्थिक कार्यवाहियों में भारत का प्रमुख भाग रहा है। आर्थिक तथा सामाजिक परिपक्व तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत ने भाग लिया है। इसी प्रकार संयुक्त राष्ट्र मंच में संबंधित प्रत्येक परिपक्व तथा संगठनों का भान्त सदस्य है और इनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिये अपनी शक्तिभर प्रयत्नशील है।

**भारत की परराष्ट्र-नीति के आधार** — भारत की परराष्ट्र-नीति अन्य राष्ट्रों के साथ शान्ति तथा मैत्री की नीति है। संसार में इस समय मुख्य प्रश्न यह है कि क्या मनुष्य तथा उसकी सभ्यता का तृतीय महायुद्ध के द्वारा अन्त हो नहीं हो जायगा। अणु-बम तथा उद्भूत बम के आविष्कारों के कारण अब नयी समस्याएँ व्यक्ति इस विचार में आयन्त हो प्रस्त हैं। शान्ति की स्थापना के लिये यह आवश्यक है कि युद्ध के कारणों को दूर किया जाय। पूँजीवादी तथा साम्यवादी राज्यों के मध्य मध्य, साम्राज्यवादी राष्ट्रों के पारस्परिक विमोह, धर्म तथा श्वेत जातियों के मध्य संघर्ष, उन्नतिवाद तथा साम्राज्यवादी देशों के मध्य विरोध तथा संसार में गरीबी, भुखमरी, अक्षता, आदि, युद्ध के मुख्य कारण हैं। यदि इन कारणों को हटा दिया जाय तो युद्ध का भय नहीं होगा। इसलिए भारत की सरकार अन्य देशों के उन सब कार्यों का समर्थन करती है जो विश्व शान्ति के पक्ष में हैं।

विश्व-शान्ति के लिये यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक देश को अपनी पद्धति के अनुसार जीवन चिताने का अधिकार होना चाहिये। उसकी सरकार किस प्रकार की हो, उसकी आर्थिक व्यवस्था क्या हो, तथा वहाँ के नागरिकों के क्या अधिकार हों, आदि बातें वहाँ की आन्तरिक बातें हैं जिनमें अन्य देशों की हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। प्रत्येक राज्य को दूसरे राज्य की संप्रभुता तथा स्वतन्त्रता का आदर करना चाहिए और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये जिससे दूसरे राज्य का अहित हो। ऐसी नीति आवश्यक रूप में शान्ति तथा सह-असन्तुष्टि की होगी।

भारत की पर-राष्ट्रनीति साम्राज्यवाद की विरोधीनी है। साम्राज्यवाद का अर्थ है एक देश पर दूसरे देश का प्रभुत्व। यह प्रभुत्व राजनैतिक या केवल आर्थिक भी हो सकता है। हम स्वयं लगभग दो सताब्दियाँ तक अंग्रेजों के अधीन थे और हमारे देश का विदेशी साम्राज्यवाद द्वारा शोषण किया गया था। हमें यह स्वाभाविक है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत की सरकार अपना यह कर्तव्य समझती है कि हमारे में सभी देश साम्राज्यवाद के शोषण में मगल हो जायें। भारत ने अजिया तथा अफ्रीका में उन समस्त देशों से अपनी सहानुभूति प्रकट की है तथा उन्हें प्रत्येक प्रकार से नैतिक बल प्रदान किया है जो साम्राज्यवाद से मुक्ति के लिये प्रयत्नशील हैं।

भारत की सरकार विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोग में विश्वास करती है। किसी देश का दूसरे देश द्वारा आर्थिक शोषण नहीं होना चाहिये। परन्तु विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक सहयोग उनकी पारस्परिक उत्पत्ति के लिये आवश्यक है। इसीलिये हमारा देश बिना किसी प्रकार के भेद-भाव के अन्य देशों से अपने आर्थिक सम्बन्ध दृढ़ करना चाहता है। हममें किसी प्रकार के राजनीतिक विभेद बाधा नहीं हो सकते। हमारे देश के प्रमखिया, दमलैड, हंग आदि सभी देशों से आर्थिक सम्बन्ध हैं। इसी प्रकार भारत के अन्य देशों से सांस्कृतिक सम्बन्ध भी हैं। हमारे देश की सरकार का यह विश्वास है कि हम प्रकार के आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोग में देशों के मध्य द्वेष, अमहिष्णुता, हिंसा आदि दूर होंगे और हमारे स्थान पर मित्रता, सहिष्णुता आदि का विकास होगा।

परराष्ट्र नीति में भारत का यह सिद्धान्त है कि राष्ट्रा के मध्य सम्बन्ध स्वतन्त्रता तथा समानता पर आधारित हो। इसलिए भारत किसी भी प्रकार के घण-भेद का स्वीकार नहीं करता। कुछ देशों में शक्ति जातियाँ अशक्त जातियों पर अत्याचार कर रही हैं। तथा उन्हें अनेक प्रकार से राजनीतिक तथा आर्थिक अधिभारों से दबिञ्चित कर रही हैं। भारत ने इस नीति का सदा स्पष्ट रूप से विरोध किया है। उदाहरणार्थ, भारत दक्षिण अफ्रीका की सरकार की अश्वेतों की जातियों के प्रति नीति का कट्टर विरोधी है।

भारत की सरकार अपनी परराष्ट्र नीति में इस सिद्धान्त पर चलती है कि विभिन्न राज्यों के मध्य जो अनेक कारणों से विभेद उत्पन्न होते हैं कि वे शान्तिपूर्ण ढंग से उठाये जा सकते हैं। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् ससार में राष्ट्रा के मध्य दो गुट बन गये हैं और इससे शीत-युद्ध का सूत्रपात हुआ। इससे कभी भी तृतीय महायुद्ध का आरम्भ हो सकता है। ५० नेहरू ने कई बार यह कहा है कि शीत युद्ध का अन्त कर देना चाहिये। अमेरिका तथा रूस के नेतृत्व में हमारे

राज्य का गुटों में बंट गए हैं। और इस गुट बन्दी के कारण इन राज्यों के मध्य इस प्रकार तनावों के सम्बन्ध हो गये हैं कि बिना सोचे-समझे एक दूसरे का प्रत्येक विषय में विरोध करते हैं। भारत इस दलबन्दी से पूर्णतः पृथक् है। हमारे प्रधान मन्त्री ने भारत की नीति को "शान्ति-धील सटस्पता" की नीति बतलाया है। हमारा देश यदि हमारी में किसी हस्तक्षेप का विरोधी है तो वह पश्चिमी एशिया में अमेरिका की नीति का भी समर्थक नहीं है।

हमारी पर-राष्ट्रनीति का एक मुख्य आधार, जैसा हम पहले लिख चुके हैं, यह भी है कि समुक्त राष्ट्र संघ की प्रतिष्ठा किसी प्रकार कम न हो तथा इसका प्रभाव व्यापक हो। यह सत्य है कि समुक्त राष्ट्र विश्व-शासन नहीं है परन्तु यह मानव जाति की संगठित आत्मा (organized conscience of mankind) कहा जाता है। यह प्रभावी दग से अपना कार्य सम्पन्न कर कर सके उसके लिये आवश्यक है कि इसमें संसार के समस्त राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व होना चाहिये। भारत की सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि कुछ शक्तिशाली राष्ट्रों की राजनीति के कारण इन संगठन में से कुछ राज्यों की बाहर रखना संध्या अनुचित है। इसलिये भारत ने सदा अमेरिका की इस नीति का विरोध किया है कि गणतंत्र चीन की समुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से वंचित रखा जाय।

संक्षेप में उपर्युक्त सध्य हमारी पर-राष्ट्रनीति के आधार है। अप्रैल, १९५४ में भारत तथा जन-राज्य चीन की सरकार के मध्य तिब्बत के सम्बन्ध में एक समझौता हुआ। यह समझौता इन्हीं उपर्युक्त सिद्धान्तों पर आधारित था। इनको पञ्चशील कहा जाता है। ये निम्नोक्त हैं:

- (१) एक दूसरे की आदेशिक अखण्डता का पारस्परिक सम्मान;
- (२) अनाक्रमण;
- (३) एक दूसरे के आन्तरिक विषयों में हस्तक्षेप न करना;
- (४) समानता तथा पारस्परिक लाभ;
- (५) शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व।

भारत की सरकार ने संसार के सभी देशों से इस बात की विज्ञप्ति की है कि वे उपर्युक्त सिद्धान्तों के आधार पर ही अपनी पर-राष्ट्रनीति चलावें। सन् १९५५ में भारत ने रूस तथा योरोप की कुछ अन्य सरकारों के साथ इन प्रकार की सम्मिलित घोषणायें की जिनमें यह कहा गया कि उनके पारस्परिक सम्बन्ध इन सिद्धान्तों के आधार पर होंगे। बाँटुंग में जो एशिया तथा अफ्रीका के राष्ट्रीय आन्दोलन हुआ उसमें यह कहा गया कि वे अपनी पर-राष्ट्रनीति में पंचशील

का ही अनुमग्न करेगे । इसमें कोई सन्देह नहीं कि इन सिद्धाता के अनुसार यदि सनार वे धिभिन्न राज्य अपनी विदेशी नीति चलायें तो उनके गध्य मुद्ध का भय सर्वथा समाप्त हो जायगा ।

**भारत के अन्य देशों से सम्बन्ध** —इसके अन्तर्गत हम भारत का प्रमुख यूरोपीय देश, समुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा एशिया के देशों के साथ अन्तराष्ट्रीय सम्बन्धों का अध्ययन करेंगे ।

**यूरोपीय देश** —यूरोपीय महाद्वीप में हमारे देश व इंग्लैण्ड के साथ अनिष्ट सम्बन्ध हैं । यह आश्चर्य की बात है कि यद्यपि हमने इंग्लैण्ड के विरुद्ध सघर्ष किया तथा इंग्लैण्ड के आधिपत्य से मुक्ति के फलस्वरूप ही स्वतन्त्रता प्राप्ति की तथा हमारे इस देश से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध बने हैं । इसका एक कारण तो यह है कि इंग्लैण्ड की अमिक दलीय सरकार ने १९४७ में सत्ता का हस्तान्तरण स्वेच्छा से किया तथा दूसरा कारण यह है कि हमारे नेताओं ने स्वतन्त्रता के पश्चात् पुरानी शत्रुता को भुला दिया । भारत जैसा हम पहले लिख चुके हैं राष्ट्र मज्जल का सदस्य है । राष्ट्रमण्डलीय देशों में हमारे प्रत्येक सदस्य से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हैं परन्तु दक्षिणी अफ्रीका का रण विभेद नीति के कारण इस देश के प्रति हमारे सम्बन्धों में एक अलग ही स्थिति है ।

**अमेरिका**

समर्थन करे । उदाहरणार्थ भारत ने स्वेज सडट (१९५६) के समय खुल कर ब्रिटेन की नीति का विरोध किया । इंग्लैण्ड के साथ हमारे आर्थिक सम्बन्ध भी अनिष्ट हैं ।

स्वरूप १९५२ में बडगगर तथा १९५४ में पांडचेरी, कारिकल, माही तथा यनम की बस्तियां भारत के अधिकार में आ गई । परन्तु अभी भी भारत में कुछ बहुत ही छोटे टुकड़े पुर्तगाल के अधीन हैं । इन बस्तियों को—गोमा, डामन, द्यू—पुर्तगाल की सरकार छाडने को प्रस्तुत नहीं है । परन्तु हमारा देश इन पर बल-वर्क अधिकार नहीं करना चाहता, परन्तु यह आशा रखता है कि पुर्तगाल का सरकार स्वयं ही इसको भारत को हस्तान्तरित कर देगी । पूर्वी यूरोप में, यद्यपि हमारा देश साम्यवादी व्यवस्था का समर्थक नहीं है तथापि हमारे रूस तथा अन्य साम्यवादी राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध हैं । भारत के प्रधान मंत्री ने रूस की यात्रा की थी (१९५५) तथा रूस के प्रधानमंत्री भारत आये

थे। हमारे रूढ़ि के सम्बन्ध 'पंचशील' पर आधारित हैं। मजबूत राष्ट्र सच में कई अवसरों पर भारत तथा रूस ने एक ही पक्ष में मतदान किया है। रूस ने भारत को कुछ सीमा तक आर्थिक सहयोग भी प्राप्त हुआ है। परन्तु भारत ने इस मित्रता के फलस्वरूप अपने स्वतन्त्र निर्णय को त्याग नहीं दिया है। उदाहरणार्थ भारत ने सोवियत रूस द्वारा हमारे में हस्तक्षेप का विरोध किया। (१९५६)।

यूरोप के राज्यों के साथ हमारे आर्थिक सम्बन्ध दो शताब्दी से भी अधिक पुराने हैं। आज भी हमारे विदेशी व्यापार में आयात तथा निर्यात दोनों में—यूरोप का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट हो जायगा।

### भारत का आयात व्यापार

मूल्य लाख रुपयों में

देश	१९५४	१९५५
इंग्लैंड	१४,६०७	१५,९०६
पश्चिमी जर्मनी	३,५२४	५,४९८
इटली	२,१२७	१,५९५
नीदरलैंड्स	१,२४०	१,३४९
बेल्जियम	१,१२५	८९४
स्विटजरलैंड	१,०२२	१,०९०
फ्रांस	९६५	१,७४०
स्वीडन	६०१	६९४

### निर्यात व्यापार

मूल्य लाख रुपयों में

देश	१९५४	१९५५
इंग्लैंड	१७,६११	१६,५५२
५० जर्मनी	१,४६५	१,५६०
नीदरलैंड्स	९९७	१,७४२
इटली	५९६	६९७
फ्रांस	५२५	६५९

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका :—संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से भी हमारे देश के सम्बन्ध ही महत्वपूर्ण सम्बन्ध हैं। भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के साथ अमेरिका ने बीच बीच में अपनी सहायता प्रकट की थी, यद्यपि यह सत्य है कि कोई ठोस कार्य हमारी सहायता के लिये नहीं किया था। स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत की



सरकार तथा अमेरिका की सरकार के मध्य सम्बन्ध—राजनीतिक तथा आर्थिक—  
 धनिल हो गये। मन् १९५१ में भारत ने / ८३२ लाख रुपये का अमेरिका  
 सामान आयात किया तथा / ९५० लाख रुपये का सामान वहाँ का निर्यात किया।  
 अमेरिका ने हमारे देश को बराने वाले की आर्थिक सहायता दी है। औद्योगिक  
 क्षेत्र में भी अमेरिका ने हमारे देश का सहायता की है। अनेक अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों  
 पर भारत तथा अमेरिका एक मत हैं। परन्तु भारत इस धनिलता के होने पर  
 भी अनेक अमेरिकी कार्यों का आलोचक रहा है। उदाहरणार्थ, मध्य एशिया में अमेरिकन  
 हस्तक्षेप नीति का भारत द्वारा विरोध किया गया है। परन्तु यह सब होने पर  
 भी दोनों देशों के मध्य सम्बन्ध मित्रतापूर्ण हैं।

भारत का एशिया के देशों से सम्बन्ध —भारत एक एशियाई देश है  
 और इसका एशिया के अन्य देशों से सम्बन्ध हमारा कर्प गुराणा है। स्वतन्त्रता  
 के पश्चात् भारत का यह एशियाई देशों से मध्य अत्यन्त धनिल तथा मित्रतापूर्ण  
 हो गया है। इन कथन का केवल मात्र पारिस्तराण एक अपवाद है। हमारे इन  
 एशियाई देशों से सम्बन्ध राजनीति, सांस्कृतिक तथा आर्थिक हैं। एशिया में  
 उत्तर में रूसी भाग को छोड़ कर भारत तथा चीन दो ही विशाल क्षेत्र हैं। चीन  
 भी आधुनिक काठ मभारत की ही भाति पश्चिमी साम्राज्यवाद द्वारा उत्पीड़ित  
 रहा है। यद्यपि मन् १९१८ में चीनी गणतन्त्र की स्थापना हो गई थी तथापि चीन  
 की पूर्ण एकता तथा एक राष्ट्रीय संगठित सरकार की स्थापना वहाँ वास्तव में १९  
 तम्बर १९४९ से हुई जब राष्ट्रपति माओ जे तुंग ने चीनी जनवादी गणतन्त्र की  
 घोषणा की। एशिया के अन्य देश भी या तो विदेशियों के अधिकार में थे या विद  
 शिवात् प्रभाव में थे। उदाहरणार्थ हिन्द एशिया के ता साम्राज्य का भाग था हिन्द  
 चीन में फ्रांसीसी आधिपत्य था बर्मा अंग्रेजों के अधीन था अन्य राज्यों में इंग्लैंड  
 तथा जापान का इतना अधिक प्रभाव था कि उनकी स्वतन्त्रता केवल नाम मात्र  
 था। अफगानिस्तान तथा पारस स्वतन्त्र व लड़ने उनका प्रभाव भीमित  
 था। परन्तु द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् जापान की पराजय होने पर मध्य एश  
 स्वतन्त्रता की लहर व्याप्त हुई। एशिया के कई देश स्वतन्त्र हो गये तथा कुछ  
 देशों में स्वतन्त्रता संग्राम प्रारम्भ हो गये। सम्पूर्ण एशिया में राष्ट्रवादी आन्दोलन  
 जागृत उठने लगे। इन आन्दोलनों के पश्चात् एशिया के राष्ट्राँ में आत्मनिरीक्षण  
 जागृत तथा वास्तव में अपनी आन्तरिक तथा बाह्य नीतियों में स्वतन्त्र रूप से  
 काम करने का दृष्टिकोण हुआ। साम्राज्यवाद इस स्थिति का तटस्थ रूप से नहीं देखा  
 गया था इसलिए इस आन्दोलन का खतरे के लिये साम्राज्यवादी देशों ने  
 प्रयत्न किये। इसके साथ ही साथ इन आन्दोलनों का एक साम्यवादी माह देने

का भी प्रयत्न किया गया। परन्तु वास्तव में ये आन्दोलन मुख्यतः राष्ट्रवादी थे यद्यपि साम्यवादियों ने इस अवसर का लाभ अपना प्रभाव-विस्तार करने के लिये किया। जिन देशों में साम्यवादियों ने स्वतन्त्रता आन्दोलन का समर्थन किया वहाँ उनके प्रभाव में वृद्धि हुई, इसमें कोई सन्देह नहीं। उदाहरणार्थ, उत्तरी वियतनाम में जो सरकार स्थापित हुई है वह साम्यवादी दल के नेतृत्व में ही है। इसी प्रकार हिन्द एशिया में भी साम्यवादी दल काफी प्रभावशील है।

भारतवर्ष ने अपनी स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् अन्य एशियाई देशों में जो मुक्ति आन्दोलन चल रहे थे उन्हें नैतिक सहायता प्रदान की। भारत जैसा हम पहले बतला चुके हैं अपनी नीति में साम्राज्य विरोधी है। हमारी सरकार के एशिया के अन्य देशों का सरकारों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध है। हमने एशिया की आजादी संगठित करने का प्रयत्न किया। भारत की यह नीति है कि एशिया के देश अपनी नीति में वदरूप रहें तथा वे किसी बड़े राष्ट्र के विछलन न हो जायें। इसलिये भारत ने एशियाई देशों में सम्मेलन भी आयोजित किये। इन सम्मेलनों का यह उद्देश्य था कि ये देश अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के ऊपर विचार-विमर्श करें। इन सम्मेलनों में सबसे मुख्य सम्मेलन बांग्देश सम्मेलन था। यह सम्मेलन अप्रैल सन् १९५५ में हिन्द-एशिया में बांग्देश नामक स्थान में हुआ। इसमें अफ्रीका के देश भी सम्मिलित थे। इस सम्मेलन के द्वारा संगठित रूप से इन राष्ट्रों की नीति संसार के अन्य राज्यों के सम्मुख रखी गयी।

संक्षेप में हम भारत के अन्य प्रमुख एशियाई देशों से सम्बन्धों का वर्णन करते हैं :—

**भारत तथा चीन :—**चीन से हमारे देश का सम्बन्ध प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। आधुनिक काल में चीन तथा भारत दोनों ही पारचात्य साम्राज्य द्वारा उत्पीड़ित राष्ट्र रहे हैं। इसलिये स्वभावतः दोनों देशों के मध्य परस्पर एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण भावना है। यद्यपि चीन की राजनैतिक तथा आर्थिक व्यवस्था हमसे भिन्न है तथा भारत की सरकार साम्यवाद का विरोध करती है तथापि उस देश से हमारे सम्बन्ध अत्यन्त ही मित्रतापूर्ण हैं। एशियाई सम्मेलनों में दोनों देशों ने मिलजुलकर काम किया है। एशिया के प्रति नीति में दोनों देशों में समानता है। दोनों देश विश्व शांति के समर्थक हैं तथा साम्राज्यवाद के विरोधी हैं। भारत के प्रधान मंत्री ने चीन की यात्रा की तथा चीनी प्रधान मंत्री भारत आ चुके हैं। दोनों देशों के मध्य केवल

राजनीतिक सम्बन्ध ही नहीं स्थापित हुये हैं, अपितु सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध भी बढ़ रहे हैं। भारत मतलब प्रयत्नशील है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ में जनवादी चीन को अपना न्यायाचित स्थान प्राप्त हो। चीन ने हमारे देश को कोई प्रतिद्वन्द्विता नहीं है। परन्तु इस वर्ष तिब्बत के प्रश्न के ऊपर दोनों देशों के दृष्टिकोणों में भेद होने के कारण उनके पारस्परिक सम्बन्धों में कुछ खिचाप आ गया है। परन्तु आशा है यह शीघ्र दूर हो जायगा।

**भारत तथा बर्मा** — बर्मा से भी भारत के सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। आधुनिक में बर्मा पर भी अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तथा यह १९३७ तक भारत का ही एक भाग था। परन्तु उस वर्ष बर्मा भारत से छलग कर दिया गया। द्वितीय महायुद्ध के काल में बर्मा में जापानी प्रवेश कर गए। महायुद्ध के पश्चात् बर्मा में स्वतन्त्रता के लिये लहर उठी तथा जनवरी सन् १९४८ में बर्मा एक स्वतन्त्र राज्य हो गया। स्वतन्त्र भारत तथा बर्मा में घनिष्ठ सम्बन्ध प्रारम्भ से ही रहे हैं। बर्मा के प्रधान मंत्री थी यू नू भारत आ चुके हैं और भारत के प्रधान मंत्री बर्मा हो गए हैं। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बर्मा भी भारत की ही भाँति तटस्थता का नीति का अनुसरण करता है तथा साम्राज्यवादी नीति का विरोधी है।

**भारत तथा हिन्द चीन** — हिन्द चीन से भी भारत के राजनीतिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। आधुनिक काल में इस प्रदेश के ऊपर फ्रांस ने अपना आधिपत्य जमा लिया। परन्तु द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् यहाँ के निवासियों ने स्वतन्त्रता के लिए कटिबद्ध होकर युद्ध किया। इस युद्ध के फलस्वरूप उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना हुई। उत्तरी वियतनाम साम्यवादी प्रभाव में है। इन स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना में भारत ने बड़ी सहायता की थी। जेनेवा सम्मेलन द्वारा इस प्रदेश में युद्ध की समाप्ति हुई थी। दोनों राज्यों से भारत के सम्बन्ध अच्छे हैं। उत्तरी वियतनाम के राष्ट्रपति डा० हो ची मिन्ह भारत आ चुके हैं। •

**भारत तथा हिन्देशिया** — दक्षिण पूर्वी एशिया के नये राज्यों में हिन्देशिया का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हिन्देशिया राज्य की रचना कुछ द्वीपों के मिलने से हुई है। इन सैंकड़ों द्वीपों में नार द्वीप मुख्य है—जावा, सुमात्रा, मेन्दीस तथा कालीमाटन हैं। हिन्देशिया के द्वीपों में डच साम्राज्यवादियों ने अपना आधिपत्य आधुनिक काल में जमा लिया था और इन द्वीपों के प्राकृतिक सधनों का उनके द्वारा शोषण किया गया। परन्तु द्वितीय महायुद्ध ने पश्चात् हिन्देशिया की जनता ने सघर्ष के फलस्वरूप अपनी स्वतन्त्रता प्राप्त की। हिन्दे-